भारतीय जनता पार्टी

1980-2005

अध्यक्षीय भाषण

(भाग-1)



पार्टी दस्तावेज

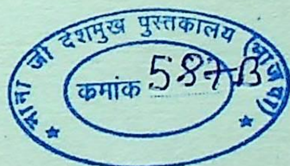
खंड-2

75

A5→R1

अध्यक्षीय भाषण

भाग-1





भारतीय जनता पार्टी



अध्यक्षीय भाषण

भाग-1

पार्टी दस्तावेज

खंड-2



भारतीय जनता पार्टी

1980-2005

प्रकाशक
भारतीय जनता पार्टी
11 अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001 (भारत)

अ.मा.पु.स. 81-89480-01-4
अध्यक्षीय भाषण (भाग-1)

संस्करण
प्रथम, 2005

मूल्य
500.00 रु. (रुपए पाँच सौ मात्र)

मुद्रक
ग्राफिक वर्ल्ड, नई दिल्ली

PRESIDENTIAL SPEECHES (PART-I)

Published by
Bharatiya Janata Party
11 Ashok Road,
New Delhi-110 001 (INDIA)



पं. दीनदयाल उपाध्याय

की स्मृति को समर्पित

अध्यक्षीय कथन

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अप्रैल 1980 में हुई। 2005 का वर्ष पार्टी का रजत जयंती वर्ष है। पार्टी के आधिकारिक दस्तावेजों का प्रकाशन इस वर्ष की बड़ी परियोजनाओं में से एक है।

देश की प्रमुख पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वह लोगों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और स्वयं इतिहास को पार्टी के विकास-क्रम का आधिकारिक विवरण दे। इन दस्तावेजों में पार्टी के विकास-क्रम के पदचिह्न देखे जा सकते हैं। उससे देश की विकासशील राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिदृश्य की झलक भी मिलेगी।

पार्टी दस्तावेज परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की गई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री इस समिति के अध्यक्ष हैं और पत्रकार व पूर्व सांसद श्री दीनानाथ मिश्र इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो दस्तावेजों के संकलन और प्रकाशन व बहुविध गतिविधियों का समन्वय कर रहे हैं।

इन ग्रंथों की प्रस्तुति के समय मुझे श्री राजेंद्र शर्मा की सुखद याद आ रही है जो दशकों तक संसदीय दल के सचिव के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने ही जनसंघ के दस्तावेजों को प्रकाशित करने की पहली बार परिकल्पना की थी। वह दस्तावेजों को बड़ी सावधानी से और व्यवस्थापूर्वक रखते थे। तब दस खंडों में जनसंघ-दस्तावेज प्रकाशित हुए थे।

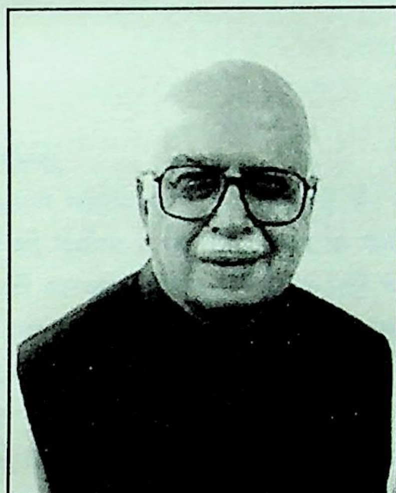
वैसे तो रजत जयंती प्रकाशनों में मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के काल पर ही दृष्टि केंद्रित होगी, लेकिन साथ-ही-साथ जनसंघ के दस्तावेजों को अद्यतन किया जाएगा और उसमें आपातस्थिति के बाद के जनता पार्टी-चरण को भी समाहित किया जाएगा, ताकि एक सातत्य बना रहे।

28 मार्च, 2005

ला॰ कृ॰ आडवाणी

(लालकृष्ण आडवाणी)
अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी

विषय-सूची



अध्यक्षीय भाषण

श्री लालकृष्ण आडवाणी

राष्ट्रीय परिषद्

नई दिल्ली 27 अक्तूबर, 2004

प्रतिनिधि बंधुओ एवं बहनो,

आज हम असाधारण परिस्थितियों में मिल रहे हैं।

18 अक्तूबर को श्री वेंकैया नायडू ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत में कहा कि वे अब पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहना नहीं चाहते। उन्होंने जो कारण बताया वे बेहद निजी तथा उच्चादर्शों से प्रेरित थे। हम सबने निरपवाद रूप से उन्हें अपने पद पर बने रहने का बहुत आग्रह किया और यह भी सुझाव दिया कि वे अपनी पारिवारिक चिंताओं के लिए पार्टी के कार्य से कुछ समय अवकाश भी ले सकते हैं। श्री नायडू ने महसूस किया कि ऐसा करना न केवल उनके अपने प्रति, बल्कि पार्टी के प्रति भी अन्याय होगा। और उन्होंने आग्रहपूर्वक स्वयं को पद मुक्त करने का अनुरोध किया।

ऐसी परिस्थिति में पार्टी के सामने और कोई रास्ता शेष नहीं रहा। पदाधिकारियों की बैठक में अत्यंत संकोच के साथ ही श्री नायडू का त्यागपत्र स्वीकार किया गया।

श्री वेंकैया का योगदान

पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने 26 महीने के कार्यकाल में श्री नायडू ने समर्पण और गतिशीलता का अनुकरणीय मानदंड प्रतिष्ठित किया। उनका उत्साही स्वभाव मन को छू जाता था और स्पष्टवादिता सबको अपना बनानेवाली थी। प्रतिकूलताओं में अडिग और सफलताओं में विनम्र रहते हुए उन्होंने हमेशा अग्रिम पंक्ति से नेतृत्व किया। चुनौतीपूर्ण समय में पार्टी को सफलतापूर्वक आगे ले जाने में श्री नायडू की भूमिका का मैं अभिनंदन करता हूँ। पार्टी आगे भी उनकी सेवाओं से लाभान्वित होती रहेगी।

चुनावी असफलता

मित्रो! भाजपा के लिए वर्तमान समय परीक्षा की घड़ी है। जब हम इस वर्ष 6 फरवरी को मिले थे तो राष्ट्रीय परिषद् में मनोबल आकाश छू रहा था। आज माहौल मंथन का है।

मई 2004 में हम वह आम चुनाव हार गए जिसे जीतने का हमें पक्का भरोसा था। निस्संदेह इससे बड़ा धक्का लगा। 1984 में लोकसभा में हमें दो स्थान मिले थे जो 1999 में बढ़कर 181 हो गए। भाजपा की लगातार हो रही बढ़त इन चुनावों में न सिर्फ रुकी बल्कि हम पीछे भी हटे और 138 सीटों तक पहुँच गए।

लोकसभा में भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी होने की अपनी स्थिति भी खो दी। भले ही भाजपा तथा कांग्रेस के मध्य लोकसभा सदस्यों की संख्या में सिर्फ आठ का अंतर हो, फिर भी इस बात का महत्त्व कम नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस हमसे आगे पहले स्थान पर पहुँच गई है।

मैं उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड में भाजपा की हार के परिणाम पर भी जोर देना चाहूँगा। इन तीनों राज्यों में हमारी हार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में पार्टी की प्रभावशाली सफलताओं का असर धो डाला।

पिछले कुछ महीनों से पार्टी ने आम चुनावों के परिणामों की समीक्षा की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हमारे गठबंधन के बहुत कम अंतर से बहुमत से पिछड़ जाने के कारण भी आत्ममंथन की यह प्रक्रिया और भी अधिक जरूरी हो गई है।

मैं आप सबसे यह भी कहना चाहूँगा कि हम असंदिग्ध रूप से जनादेश का सम्मान करते हैं। पर इसके साथ यह भी सत्य है कि मतदाताओं ने कांग्रेस नेतृत्ववाले गठबंधन को स्पष्ट स्वीकृत या जनादेश नहीं दिया है। केंद्र में सं. प्र.ग. सरकार असंदिग्ध तौर पर राजनीतिक लालसाओं तथा अवसरवाद का गठबंधन है। पर हम इस तथ्य की अनदेखी भी नहीं कर सकते कि यह गठबंधन हमारी अपनी सामूहिक कमजोरियों के कारण ही जोड़-तोड़कर बहुमत ले पाया है।

आम चुनावों में हमारे काम-काज और व्यवहार से वे कौन से मुख्य सबक हैं जो हम ले सकते हैं?

हमारा गलत आकलन

पहले तो हमारे आकलन जहाँ भी गलत साबित हुए, उसे मानना होगा। हमने सोचा कि अच्छी सरकार और चुनाव परिणामों में सीधा संबंध होता है। लेकिन यह मानना पूरी तरह से सही नहीं था। भाजपा और राजग ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेरणाप्रद नेतृत्व और सरकार में उनके यशस्वी कार्यकाल की ताकत पर चुनाव लड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों बिंदुओं पर हम गर्व कर सकते हैं।

गौरवशाली उपलब्धियाँ

6 साल की अवधि में वाजपेयी सरकार ने भारत का चेहरा बदलकर दिखा दिया।

हमने दूसरे देशों के साथ भारत की स्पर्धा की ताकत बढ़ाई तथा देश की प्रौद्योगिकी और आर्थिक आधारशिलाओं को मजबूत किया। हमने उद्यम पर लगे शिकंजे हटाने और देश को लाईसेंस परमिट कोटा राज की घातक बेड़ियों से मुक्त करने का प्रयास किया। मुद्रा स्फीति की दर रिकॉर्ड स्तर तक कम की और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड स्तर को छुआ।

भारत को परमाणु शक्ति बनाकर हमने देश की सुरक्षा को मजबूत आधार दिया; सीमा पार के आतंकवाद को काबू में लाए और इसके साथ-ही-साथ पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाए। कुल मिलाकर हमने सारी दुनिया में भारत की आवाज को महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाया।

स्वदेश में हमने लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाया। हमने संघीय शासन को एक नई तथा आपसी समन्वयवाली परिभाषा दी एवं केंद्र तथा राज्य संबंधों के रास्ते की बाधाओं को दूर किया। जम्मू-कश्मीर में पार्टीगत स्वार्थों से ऊपर उठते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लिए उपयुक्त वातावरण और सुविधाएँ दीं।

मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि आनेवाले इतिहास में श्री वाजपेयी की सरकार जवाहरलाल नेहरू के समय से आज तक की सबसे कार्यकुशल और फलदायी सरकार के नाते याद की जाएगी।

उपेक्षित पहलू

दुर्भाग्य से भारत जैसे विशाल और विविधतावाले देश में अच्छे शासन का सब जगह एक जैसा असर नहीं होता। देश के सामने एक बड़ा चित्र रखते समय हम लोगों ने छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न देने की गलती की। हम तेज बदलाव के मानवीय पहलू के बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाए। दुनिया के स्तर पर भारत को प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने की कोशिशों में हम समाज के उन वर्गों को पर्याप्त सहारा देने से चूक गए जो बाजारवाद तथा टेक्नोलॉजी के भीमकाय स्वरूप से अचानक आक्रांत हो उठे थे।

तो परिवर्तन की लहरों पर सवार होने की अदम्य इच्छा के चलते हमने उनको चोट पहुँचाई, जो इस तरह से अछूते रह गए थे। उनपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा जब हमने भारत उदय या इंडिया शाइनिंग को एक वास्तविकता बताने की कोशिश की।

अपनी इन गलतियों और भूलों की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हमें अपनी कमियों का पूरा अहसास है और मैं आज आपको यह भरोसा दिलाना

चाहता हूँ कि इन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएँगे।

मित्रो! आप भी इस बात को महसूस करते होंगे की राजनीति के हाशिये से केंद्रीय भूमिका तक की यात्रा तय करते हुए हमने अपने समर्थकों और मित्रों में अनेक उम्मीदें जगाईं, जिनमें से कुछ काफी भावनाप्रद थीं। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं कि इनमें से कुछ उम्मीदें हम पूरी नहीं कर सके।

अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर भगवान् राम के एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण एक ऐसा ही विषय रहा है।

अयोध्या का विषय

भाजपा और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तो रामजन्मभूमि आंदोलन एक निर्णायक मोड़, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हिंदू नवोदय के इस आंदोलन में हमारी भूमिका ने ही जनता की आँखों में हमारे प्रति सपने जगाए तथा पार्टी को राष्ट्रीय प्रमुखता के शिखर तक पहुँचाया।

1981 से जिन लोगों ने हमे समर्थन दिया, उनके एक बहुत बड़े वर्ग ने यह आशा की थी कि भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार अयोध्या में मंदिर निर्माण के रास्ते की बाधाओं को दूर कर देगी।

लोगों की आशाएँ गठबंधन राजनीति की सीमाओं, विपक्ष के नासमझ विरोध तथा न्यायपालिका की जटिल भूमिका से पूरी तरह असंबद्ध थी।

राजग सरकार के आखिरी साल में हमने हिंदू तथा मुसलिम धार्मिक नेताओं से बातचीत के जरिए इस समस्या के समाधान की दिशा में काफी प्रगति की थी। हम इस समस्या के समाधान में काफी आगे बढ़ सके थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि बातचीत के जरिए आम चुनावों के बाद जल्दी ही राष्ट्रीय भावनाओं के अनुरूप समाधान निकल सकेगा।

विडंबना है कि हम आगे तो बढ़े पर थोड़ा धीमी गति से, और जानबूझकर समाधान तक पहुँचनेवाली बातचीत को प्रचारित नहीं होने दिया। परिणाम यह निकला कि चुनाव के समय स्वाभाविक रूप से इस बारे में एक निराशा जैसा वातावरण बना कि हम राम मंदिर निर्माण के बारे में भी कुछ नहीं कर सके।

राजनीतिक दृष्टि से भाजपा के लिए यह एक अजीब सी परिस्थिति थी कि अधिकांश असंयम उन संगठनों की ओर से प्रकट हुआ जिन्हें हम सहगामी बंधु संगठन मानते हैं। इन विरोधों और मतभेदों ने वैचारिक फूट का दृश्य उपस्थित किया और इससे हमारे परंपरागत समर्थक भी भ्रमित हुए।

अंततः यह कहा जा सकता है कि सब जगह न तो हम अपने कार्यकर्ताओं को एक जैसे प्रेरित कर सके, न ही उत्साहित।

भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका मन और आत्मा कार्यकर्ता में बसते हैं।

यह वही कार्यकर्ता है जो अच्छे और खराब, दोनों समय में पार्टी के लिए अनथक कार्य करता है और यही वह कार्यकर्ता है जो हमें, पार्टी को सामान्य मतदाता से जोड़ता है।

जब हमारी पार्टी शासन में थी तो हमारे कुछ पदाधिकारियों के कामकाज के तौर-तरीकों और उनके व्यवहार के बारे में पिछले कुछ महीनों में मुझे बेहिसाब शिकायतें मिली हैं और निश्चित रूप से इनसे मैं व्यथित हुआ हूँ। अहंकार, रूखेपन, पक्षपात तथा केवल पैसे के बल पर ही सबकुछ काम करवाने की प्रवृत्ति ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार तक के आरोप लगे।

इस तरह का व्यवहार आमतौर पर हताशा और चिढ़ बढ़ाता है। इससे जनता में सामान्यतः फैली हुई एक भावना ज्यादा मजबूत बनती है कि यह देश स्वार्थी और लालची राजनेताओं द्वारा गिरावट की तरफ ले जाया जा रहा है।

मूल्याधारित राजनीति

मित्रो! भाजपा बाकी सबसे भिन्न विशिष्टतावाली पार्टी है। लेकिन जब तक हम अपने व्यवहार और निष्ठा से यह नहीं दिखा पाते कि हम राजनीतिक गिरावट और विकृतियों की बीमारी का हिस्सा नहीं हैं तब तक हमारा विशिष्टता का दावा कमजोर ही रहेगा। राजनेता की आज जो गंदी और विकृत तसवीर है, भाजपा उसे पूरी ताकत से बदलने की कोशिश करेगी।

भाजपा की हर स्तर पर अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से यही अपेक्षा है कि वे सम्मान, संयम तथा गरिमा के साथ व्यवहार करेंगे। हमारी राजनीति किन्हीं विशिष्ट मूल्यों पर आधारति है। हम इस बात की कभी अनुमति नहीं दे सकते कि कांग्रेस संस्कृति का आत्मकेंद्रित स्वार्थी तत्त्व हमारे संगठन को भी दीमक की तरह खोखला करने लगे।

इसलिए हम अपने निजी व्यवहार और कामकाज के मानदंड ऊँचे रखें। यह जरूरी है और अगर हमें फिर से उस नैतिक अधिष्ठान को हासिल करना है, जिसने हमें एक उदीयमान, आगे बढ़ते भारत की नई आशा के रूप में उभारा था।

इसलिए जब लोग हमारे बारे में कुछ आलोचना की बातें करते हैं, जैसाकि आम चुनावों के समय हुआ तो उसे मित्रवत् ही लेना चाहिए और उन बातों को सम्मानपूर्वक सुनना हमारा पावन कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अपनी भूलों पर ध्यान देना बहुत महत्त्वपूर्ण है। और किसी भी राजनीतिक दल के लिए जनता की आवाज को सुनना-समझना तथा उसके प्रति विनयी होना जरूरी होता है।

यह नहीं समझना चाहिए कि आत्मालोचन किसी किस्म का पराजयवाद है, बल्कि आत्मालोचन तो नए कदम उठाने का मंच और मौका देता है। इसलिए हम यह याद रखें कि हमारे आगे बढ़ते कदम तनिक ठिठके ही हैं। हमारा अभियान

न रुका है, न रुक सकता है।

पार्टी अध्यक्ष के रूप में मेरे सामने पहला काम है भाजपा को ऐसे युद्धसज्ज संगठन के रूप में खड़ा करना जो कांग्रेस तथा कम्युनिस्टों की चुनौतियों को परास्त करने में समर्थ हो। एक साथ मिलकर हम 15वीं लोकसभा में राजग का जोरदार बहुमत लाने का संकल्प व्यक्त करते हैं और उसके लिए हर संभव तैयारी की जाएगी।

हमारी विचारधारा पर आघात

भाजपा के लिए आनेवाले दिन चुनौती भरे होंगे। कम्युनिसटों के सहारे टिकी संप्रग सरकार ने हमारी विचारधारा पर केंद्रित हमले शुरू कर दिए हैं। निर्विषकरण या डिटॉक्सीफिकेशन जैसे जुमलों को उछालकर संप्रग सरकार द्वारा उन लोगों का भूतबाधा की तरह से पीछा किया जा रहा है जिन्हें राजग सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में पद और जिम्मेदारियाँ दी थीं। यह प्रक्रिया केंद्र से शुरू हुई है और अब प्रांतों तक पहुँचेगी।

वीर सावरकर जैसे हम सबके प्रेरक राष्ट्रीय नायकों को अपमानित तथा निंदित किया गया। जिन लोगों के मन में हमेशा भारत की विरासत के प्रति घृणा और अपमान रहा है उनको खुश करने के लिए इतिहास को नए सिरे से लिखा जा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अतीत में कम्युनिस्टों ने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रीय नेताओं का किस प्रकार तिरस्कार किया था और उनकी मजाक उड़ाई थी।

इस सत्तारूढ़ गठबंधन का केंद्रीय संदेश स्पष्ट है कि भाजपा तथा उसकी विचारधारा के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव को सहन नहीं किया जाना है।

हालाँकि संप्रग सरकार का यह व्यवहार हर प्रकार के लोकतांत्रिक नियम–कायदों के विपरीत है, लेकिन इस असहिष्णुता में भी एक बात ऐसी छिपी है जो हमें अपने प्रति आश्वस्त करती है। और वह बात यह है कि हमारे विरोधियों ने झिझकते हुए ही सही, पर वह बात स्वीकार की है जो हम हमेशा कहते आए हैं कि भाजपा की रीढ़ उसकी विचारधारा है।

हमारी विचारधारा की व्याख्या

यह विचारधारा ही है जो भाजपा को उसकी विशिष्ट पहचान देती है। हम एक अलग पहचानवाली पार्टी इसीलिए हैं, क्योंकि हम कुछ खास आस्थाओं और सिद्धांतों से अनुप्राणित हैं। हमारी राजनीतिक प्राथमिकताएँ, रणनीतियाँ एवं कदम भले ही तात्कालिक मुद्दों से रूपाकार लेते हों, लेकिन आधारभूत विचारधारा अपरिवर्तित रहती है।

भाजपा सबसे पहले और प्राथमिक तौर पर 'राष्ट्रहित सर्वप्रथम' वाली पार्टी

है। हमारी पार्टी राष्ट्रवादवाली पार्टी है और हमारी राजनीति की एक ही कसौटी है कि राष्ट्र के लिए क्या ठीक है, क्या वांछनीय है।

भाजपा की निष्ठा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में। हमारा विश्वास है कि भारतीय राष्ट्रीयता की जड़ें अंतर्निहित सांस्कृतिक एकात्मता में हैं। हममें से कुछ राष्ट्रीयता के इस बोध को हिंदुत्व कहते हैं, तो पं. दीनदयाल उपाध्याय ने इसी को भारतीयता भी कहा।

यह देखकर मुझे दुःख होता है कि हमारी राष्ट्रीयता के मूल स्वरूप की पहचान होने के बावजूद हिंदुत्व को एक राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। हिंदुत्व एक भावना है, जो न तो चुनावी नारा हो सकता है और न ही उसको पंथ या संप्रदाय के साथ भ्रमित करके देखना चाहिए। यह हमारी जीवन पद्धति का स्वरूप है, एक विचार है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर, 1995 को दिए अपने एक फैसले में लिखा—

"...हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू धर्म जैसे शब्दों को कोई निश्चित अर्थ नहीं दिया जा सकता। और कोई भी ऐसा सैद्धांतिक अर्थ इसे संप्रदाय की ही संकीर्ण सीमाओं, परिधि में सीमित नहीं कर सकता, जिसमें भारतीय संस्कृति और विरासत का तत्त्व समाविष्ट न हो। यह भी स्पष्ट है कि हिंदुत्व शब्द उपमहाद्वीप के लोगों की जीवन पद्धति से ज्यादा संबद्ध है। यह समझ पाना कठिन है कि किस प्रकार इन (सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती) फैसलों के प्रकाश में हिंदुत्व या हिंदू धर्म जैसे शब्द सैद्धांतिक रूप से संकीर्ण कट्टर हिंदू धार्मिक रूढ़िवाद का पर्याय माने जा सकते हैं।"

निर्णायक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है। हम इस विश्वास से निर्देशित होते हैं कि विकास को परंपरा और पर्यावरण के साथ समन्वित होना चाहिए। हमारा विश्वास है कि भारत की आर्थिक आधारशिलाएँ अति उपभोग या प्राकृतिक विध्वंस पर टिकी नहीं होनी चाहिए। हमारा विकेंद्रीकरण, विनियमन, समन्वय तथा सामाजिक न्याय में विश्वास है।

व्यक्त संदेह

पिछले कुछ वर्षों से मैं अकसर यह सुनता हूँ कि पार्टी ने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया है।

1974 में जब जनसंघ ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में शामिल होना स्वीकार किया था तो उसके बारे में भी अनेक भीतरी संदेह उभरे थे। हमारे कुछ नेताओं ने एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार

करने की बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े किए जिसके जम्मू-कश्मीर तथा नगालैंड के बारे में प्रारंभिक विचार हमसे नितांत भिन्न थे।

इसी प्रकार 1998 में जब हमने अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया तो पुनः भाजपा पर अपनी विचारधारा छोड़ देने का आरोप लगाया गया। इस बार यह आशंका इस तथ्य के कारण पैदा हुई, क्योंकि राजग के 'शासन चलाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम' में धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तथा समान नागरिक संहिता के प्रति हमारी वचनबद्धता जैसे बिंदु शामिल नहीं थे।

विचारधारा के प्रति वचनबद्ध

ये तमाम संदेह और आशंकाएँ निराधार हैं। विचारधारा किन्हीं निश्चित सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का नाम है। यही वह पहलू है जो विभिन्न राजनीतिक सवालों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। यह अलग बात है कि तात्कालिक राजनीतिक प्राथमिकताएँ कुछ अन्य कारणों से निर्णीत होती हैं तथा उनका एक संदर्भ होता है।

कांग्रेस पार्टी द्वारा 1985 में शाहबानो फैसले को जिस प्रकार पलटा गया उसने हमें छद्म सेकुलरवाद की असलियत बताने के अभियान का सूत्र दिया। यह अभियान 1989 में और मजबूत हुआ जब हम विश्व हिंदू परिषद् द्वारा प्रारंभ किए गए राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हुए। अयोध्या हिंदुओं के संबंध में तथाकथित 'सेकुलर' सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा अपनाए जानेवाले दोहरे मापदंड का नायाब उदाहरण था।

राम मंदिर बनेगा ही

14 वर्ष पहले जब मैंने सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा प्रारंभ की थी तब से बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। प्रत्यक्षतः अयोध्या में मंदिर एक ऐसी—जटिल कानूनी प्रक्रिया में उलझ गया है जो क्षोभ पैदा करती है। राजनीतिक दल अदालती फैसले की आवश्यकता का 'वाणी विलास' इसलिए करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें किसी एक फैसले पर पहुँचने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। हमारे 'प्रबुद्ध' इतिहासकारों को जब-जब बाबरी मसजिद से भी पहले वहाँ स्थित मंदिर के पुरातात्त्विक अवशेष दिखाए जाते हैं तो वे नजर घुमा लेना पसंद करते हैं।

इसके बावजूद यह कहना होगा कि जिस माहौल ने अयोध्या को स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद का सबसे शक्तिशाली जनआंदोलन बनाया, वह माहौल अब बदल गया है।

अयोध्या आंदोलन ने यह सुनिश्चित किया था कि हिंदुओं को न तो मनचाहा इस्तेमाल किया जा सकता है, न ही उनकी भावनाओं का अनादर किया जा सकता है।

अल्पसंख्यकवाद का अभिशाप

हालाँकि कांग्रेस द्वारा अभी भी अल्पसंख्यकवाद और वोट बैंक राजनीति का व्यवहार होता है, लेकिन उसका तरीका और स्वरूप बदल गया है। अब यह ज्यादा चुपचाप और अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, ताकि उसके विरुद्ध किसी प्रकार का जन प्रतिरोध न खड़ा हो सके। इसके बावजूद देश को यह पहचानना होगा कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है।

भाजपा द्वारा एक परिवार में दो बच्चों के प्रस्ताव को संस्थापित किए जाने की माँग के विरोध में जो असहज प्रतिक्रियाएँ हुई हैं वह सिर्फ एक उदाहरण है कि किस प्रकार संकीर्ण वर्ग हितों की चिंता देश की प्रगति के लिए विनाशकारी साबित होती है।

हिंदू नवोदय

अयोध्या में राम मंदिर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अडिग और अपरिवर्तनीय है। यही बात हमने दृष्टिपथ 2004 के दस्तावेज में दोहराई थी। देश बहुत आतुरता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब राम जन्मभूमि पर बने हुए अस्थायी मंदिर की जगह भगवान् राम की महानता के अनुरूप मंदिर का निर्माण होगा।

इसके साथ ही हमें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से मान्य करनी होगी कि '90 के दशक के प्रारंभ में सड़कों पर जिस हिंदू क्रोध का विस्फोट हुआ था, उसने अब नए मंदिर की धीरज के साथ प्रतीक्षा को जगह दे दी है जिसका निर्माण कोई टाल नहीं सकता।

यह मुद्दा राम मंदिर से आगे का मुद्दा है। आधुनिक विश्व के प्रति सुसंस्कृत और सुविचारित दृष्टि स्वामी विवेकानंद की कल्पना के अनुरूप एक हिंदू नवोत्थान की माँग करती है।

किसान, जनजाति और दलित

पिछले 5 वर्षों में लोगों की राजनीतिक प्राथमिकताओं में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले से अधिक युवा हुआ है। देश के एक बड़े युवा वर्ग की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने में भाजपा को अग्रणी भूमिका निभानी ही होगी और वह भी उन्हीं की भाषा और छंद में।

ऐसे सामाजिक समूह और समुदाय हैं जो अब तीव्रता से आगे बढ़कर सत्ता के ढाँचे में हिस्सेदारी चाहते हैं। उन सबको पार्टी के निर्णय लेनेवाले अवयवों में जगह देनी होगी। हमारी राजनीतिक दृष्टि निर्णायक रूप से सबको शामिल करने की भावना से प्रेरित है।

मित्रो! भाजपा सबसे पहले और अग्रणी तौर पर एक ऐसी पार्टी है जिसकी देश के गाँवों में जड़ें गहरी हैं। हमारे सांसदों और विधायकों की काफी बड़ी संख्या

ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों से ही आती है। भारत में किसानों के हितों और उनकी चिंताओं को स्वर दिए बिना हम अपनी भूमिका को सार्थक नहीं बना सकते।

भाजपा को इस बात का भी गर्व है कि उसके पास दलित तथा जनजातीय समुदायों से सर्वाधिक संख्या में सांसद हैं। हमारे विचार परिवार के साथ जुड़े संगठन जनजातियों को सशक्त बनाने के उद्‌देश्य से शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इन महत्त्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण के कार्यों में पार्टी के पदाधिकारियों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

इसके साथ ही हमें अतीत का बंदी बनकर नहीं रहना है। हमें जनता के प्रति अपनी निष्ठा, देश के भविष्य और अपनी विचारधारा का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते जाना है।

विपक्ष–धर्म

आज हम एक अग्रणी विपक्षी दल हैं। राजग के अपने घटक सहयोगियों के साथ संसद् के सदनों में हमारी काफी बड़ी उपस्थिति है। फिर भी 1998 से पहले हम जो थे उससे हम आज एक भिन्न विपक्षी दल हैं। भिन्न इस मायने में कि हम सरकार चलाने के अनुभव से समृद्ध विपक्षी दल ही नहीं हैं, बल्कि हमें प्रतीक्षारत सरकार के नाते देखा जाता है।

हमें विपक्ष के नाते अपनी जिम्मेदारियों को ताकत और तेजस्विता से निभाना होगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा व्यवहार गरिमा और जिम्मेदारीवाला होना चाहिए। जिन मुद्‌दों पर हम अपना रुख तय करें वे सुविचारित तथा समग्र होने चाहिए।

इसके साथ ही भाजपा के नेतृत्व में चल रही प्रांतीय सरकरों को अपने शासन की गणुवत्ता के बारे में विशेष ध्यान रखना होगा।

नाजुक जोड़–तोड़

संप्रग सरकार का संसद् में भले ही स्पष्ट बहुमत होगा, लेकिन वह उस प्रकार से स्थिर सरकार नहीं है जैसे कि पिछले 5 वर्षों में श्री वाजपेयी की सरकार थी। स्थिरता सिर्फ संख्या बल से नहीं आती, वह सरकार की गुणवत्ता पर भी निर्भर होती है।

श्री मनमोहन सिंह की सरकार को अभी भी अपने ही विरोधाभासों से पार पाना बाकी है। वामपंथी पार्टियों का कार्यक्रम अगर पीछे की ओर धकेलनेवाला है तो क्षेत्रीय दलों की अपनी अलग प्राथमिकताएँ हैं और कांग्रेस दो सत्ता केंद्रों के बीच झूल रही है।

यह एक स्थिर सरकार नहीं है, बल्कि ऐसा कमजोर ताना–बाना है जो या तो अपने कार्यकाल को लड़खड़ाते हुए पूरा करेगा या किसी भी समय अचानक ध्वस्त

हो जाएगा। इनमें से जो भी हो, भारत के लिए इसके परिणाम उत्साहजनक नहीं होंगे।

ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को हर तरह की आकस्मिकताओं के लिए तैयार रहना होगा। हमें राजग की एकता को मजबूती से बनाए रखते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं को समन्वित ढंग से प्रस्तुत करना होगा। यह ठीक है कि हमें एक बौखलाई हुई सरकार को चित्त करने के हर अवसर का भरपूर उपयोग करना है; लेकिन यह करते समय ध्यान रखना होगा कि लोग हमारे व्यवहार तथा प्रतिक्रियाओं को परख भी रहे हैं।

आतंकवाद और सुरक्षा

राष्ट्रीय समस्याओं की सूची में सबसे ऊपर जो दो मुख्य समस्याएँ हैं आतंकवाद तथा सुरक्षा की, उनपर ही हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मणिपुर में नागरिक जनअसंतोष तथा पूर्वांचल के अन्य राज्यों में विद्रोही गुटों की चुनौती और बँगलादेश से अवैध घुसपैठ के कारण समूचे पूर्वी भारत में हो रहा जनसांख्यिकी परिवर्तन हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है।

आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा वामपंथी आतंकवादियों के शर्मनाक तुष्टीकरण से जहाँ पड़ोसी प्रांतों में कानून व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ हुआ है, वहीं इसने नेपाल में विद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। जिस पद्धति से नक्सलवादियों को चमक-दमक बख्शी जा रही है, वह नितांत भर्त्सना योग्य है।

संप्रग सरकार जम्मू-कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ आंतरिक संवाद अगले स्तर तक ले जाने में असफल हुई है और आतंकवादियों के हमले फिर से जारी हैं।

अर्थव्यवस्था और लोग

दूसरे, देश का ध्यान अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। वाजपेयी सरकार ने संप्रग को एक स्वस्थ और प्रखर अर्थव्यवस्था सौंपी थी जो कि अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी ईर्ष्या का कारण बनी। हमें चिंता है कि यह विरासत वित्तीय अव्यवस्था, उच्च कर दर, मुद्रा स्फीति और निरर्थक खर्चों द्वारा व्यर्थ न कर दी जाए।

हम किसानों, अनौपचारिक क्षेत्र, मध्य वर्ग, बेरोजगार युवाओं तथा औद्योगिक मजदूरों की समस्याएँ उठाएँगे। आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्याओं में वृद्धि गहरी चिंता का विषय है। इस वर्ष 1 जनवरी से 15 मई के मध्य 30 किसानों ने आत्महत्याएँ की थीं, जबकि 16 मई से 20 अक्तूबर तक यह संख्या 1603 तक पहुँच चुकी है।

हमारा वैकल्पिक दृष्टिपथ

हम विनियमन के प्रति वचनबद्ध हैं, लेकिन हमारा इस बात पर आग्रह होगा कि वैश्वीकरण की शर्तें भारत के नागरिकों को किसी भी आघात के सामने कमजोर स्थिति में न छोड़ें।

तीसरे, हम लोकतांत्रिक पद्धति के प्रत्येक उल्लंघन का विरोध करेंगे। संप्रग सरकार ने वामपंथियों के उत्प्रेरण से अत्यंत असहिष्णुता का परिचय दिया है। हमें आशंका है कि इस प्रकार के दलगत भेदभाव युक्त व्यवहार से भारत के संघीय ढाँचे में विकृतियाँ आ सकती हैं।

अंत में और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम भारत की ऐसी महाशक्ति की वैकल्पिक छवि प्रमुखता से उजागर करेंगे जो अपनी राष्ट्रीयता के भाव में सुरक्षित है। चाहे आर्थिक फैसलों का क्षेत्र हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कदम उठाने हों या विदेश नीति का व्यवहार हो, भाजपा एक ऊर्जस्वी और नवोदित भारत के प्रति वचनबद्ध है। यही हमारा राजनीतिक ध्येय-वक्तव्य है।

हमारी विरासत

भाजपा के समक्ष चुनौतियाँ दुर्धर्ष हैं और पिछले कुछ दिनों में मुझसे गगनचुंबी ऊँचाइयाँ छूनेवाली अपेक्षाएँ की गई हैं। पिछले 5 दशकों से मैं उस अनुष्ठान का एक समर्पित सिपाही रहा हूँ जिसका श्रीगणेश डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने किया था, जिसे पं. दीनदयाल उपाध्याय ने पाला-पोसा और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गौरवशाली ऊँचाइयों तक पहुँचाया। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मुझे निस्स्वार्थ देशभक्ति की प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली है। इन दोनों ने मिलकर मुझे कठिनतम यात्राओं को सफलतापूर्वक पूरा करने की शक्ति और साहस दिया है।

आगे की यात्रा के बारे में विश्वास रखिए कि वह कठिन ही होनेवाली है। इसके लिए संपूर्ण लगन, समर्पण तथा कार्यकर्ताओं के सामूहिक विवेक के साथ हमारे संपूर्ण परिवार की सदिच्छा चाहिए। सबसे बढ़कर इस कार्य के लिए निस्स्वार्थ टीम भावना की जरूरत होगी।

गत चार ऐसे अवसर रहे जब आपने मुझे भाजपा अध्यक्ष पद से सम्मानित किया और मुझे पार्टी के प्रत्येक आनुषांगिक पक्ष तथा परिवार के असंदिग्ध सहयोग का सौभाग्य मिला। इस बार भी मुझे यही अपेक्षा और आशा है।

आज मैं यह जिम्मेदारी पुनः स्वीकार कर रहा हूँ तो मैं इस पथ पर मिले एक अतिरिक्त दायित्व को भी रेखांकित करना चाहूँगा।

श्री वाजपेयी

पिछले तीन दशकों से मुझे भारतीय जनता पार्टी के सबसे विराट् व्यक्तित्व

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने का मौका मिला है, जो मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा सम्मान मानता हूँ। यह संबंध अंतर्निहित विश्वास तथा पारस्परिक सम्मान पर आधारित है। हमारी शैलियाँ भिन्न होंगी और एक-दूसरे की कामनाओं से भी शायद भिन्न चले होंगे। लेकिन हमने हमेशा परस्पर एक-दूसरे का साथ निभाना चाहा। अखबारों के एक वर्ग ने हमें प्रतिस्पर्धी के नाते चित्रित किया है। लेकिन हम इसे एक साझेदारी मानते हैं, अपने वरिष्ठ नेता श्री वाजपेयी के साथ सहयोग की साँझी भावना से युक्त।

यही पारस्परिकता और साझेदारी की वह भावना है जो मैं पार्टी में भी देखना चाहता हूँ।

स्वर्णिम भविष्य

मुझे इस बात का पूरा ध्यान है कि पार्टी में स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी का दायित्व मेरे उन सहयोगियों के हाथों में पहुँचेगा जो दीप्तिमान युवा चेहरेवाले हैं, क्योंकि उम्र उनके साथ है। भाजपा एक ऐसी सेना है जो हर पीढ़ी, हर क्षेत्र और प्रत्येक सामाजिक वर्ग को अपने में समेटे हुए चलती है। यह एक ऐसी सेना है जिसे वैचारिक पाठ, प्रतिभा और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता का आशीर्वाद प्राप्त है। आज जो पार्टी में वरिष्ठ पदों पर पहुँचे हैं उनके पीछे दशकों के परिश्रम, संघर्ष और समर्पित बलिदान का पाथेय खड़ा है।

हम भविष्य के प्रति आशंकित नहीं हैं, क्योंकि इस भविष्य को सींचा, सँवारा और बुना है हमारे कार्यकर्ताओं ने। यही है हमारी विशिष्टता का मूल। यही वह बात है जो भाजपा को एक विशिष्ट, सबसे अलग पार्टी बनाती है।

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। दो महीने बाद हमारी पार्टी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगी। लोकतांत्रिक विश्व में ऐसी किसी राजनीतिक पार्टी को मैं नहीं जानता जिसने सिर्फ 25 वर्षों के अंतराल में ऐसी असाधारण बढ़त हासिल की हो।

आइए हम सन् 2005 को अपनी यात्रा का एक अविस्मरणीय यशोत्सव बनाने का संकल्प करें।

हम अपनी ताकत पर बढ़ें और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सरकार, अच्छी राजनीति और अच्छे राजनेताओं का एक आदर्श उदाहरण एवं प्रेरणा का स्रोत बनाएँ। आइए हम सब स्वयं को मातृभूमि की सेवा के लिए पुनः समर्पित करें।

वंदेमातरम्



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

रांँची 24–26 नवंबर, 2004

प्रिय बंधुओ,

मैं राँची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आपका स्वागत करता हूँ।

नई दिल्ली में 27 अक्तूबर की राष्ट्रीय परिषद् के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है।

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जबकि दो प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं तथा निकट भविष्य में तीन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होनेवाले हैं।

हाल के विधानसभा चुनावों के परिणाम

हमारे लिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के परिणाम सचमुच निराशाजनक हैं। कांग्रेस–एनसीपी गठबंधन सरकार के कार्य–प्रदर्शन के आधार पर उन्हें फिर से जनादेश प्राप्त नहीं होना चाहिए था, जैसाकि कार्य–प्रदर्शन के आधार पर निश्चित ही केंद्र में राजग को नया जनादेश मिलना चाहिए था। इस प्रकार हमें कभी–कभी लगता है कि सरकार के कार्य–प्रदर्शन अर्थात् उपलब्धियों और चुनाव परिणामों में सीधा संबंध नहीं होता है; परंतु मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसी स्थिति प्रत्येक चुनाव में होती है, हालाँकि यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिस पर गंभीर अध्ययन की जरूरत है।

मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भाजपा और हमारे गठबंधन के सहयोगी शिव सेना के बीच समुचित और सतत समन्वय का अभाव विभिन्न स्तरों पर रहा, जो चुनावों में हमारी हार का प्रमुख कारण बना। हमें आगामी चुनावों की अपनी रणनीति तैयार करते हुए इससे सही सीख लेनी चाहिए।

मैं हाल के चुनावों में अरुणाचल प्रदेश इकाई को उसकी शानदार सफलता के लिए बधाई देता हूँ। अपने ही बल पर चुनाव लड़ते हुए, हमने विधानसभा में 9 सीटें जीतीं। हमने राज्य में दोनों लोकसभा सीटों पर भी विजय प्राप्त की। इससे

पता चलता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग चाहते हैं कि भाजपा इस क्षेत्र में एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी बनकर उभरे, ताकि भाजपा राष्ट्रीय अखंडता की प्रबल रक्षक बन सके और शांति, विकास एवं सामाजिक सद्भावना की प्रतीक बन सके।

आगामी तीन निर्णायक चुनाव

आनेवाले महीनों में, हमें बिहार, झारखंड और हरियाणा में तीन महत्त्वपूर्ण चुनावों का मुकाबला करना है। इन चुनावों में हमारा लक्ष्य बिलकुल स्पष्ट है।

झारखंड : झारखंड में हमें नया जनादेश प्राप्त करने का प्रयास करना है। सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। दरअसल, सरकार ने ऐसी अनेक कठिनाइयों का मुकाबला किया जो अविभाजित बिहार की आरजेडी सरकार के कुशासन से विरासत में हमें प्राप्त हुईं। झारखंड के लोग भी इस बात को जानते हैं कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो राज्य के आदिवासियों और गैर-आदिवासियों, दोनों के हितों के प्रति दृढ़ता से वचनबद्ध है और वह इनके हितों को पूरा करने में समर्थ है तथा सद्भाव पैदा कर सकती है। हमें लोगों के मन में यह तथ्य बैठाना कि पिछली सरकार द्वारा पहुँचाई गई क्षति को सुधारने के लिए तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पाँच और वर्षों के लिए भाजपा शासन की आवश्यकता है। हमें लोगों को विशेष रूप से इस बारे में सतर्क करना होगा कि हमारे विरोधियों को जनादेश देने का मतलब होगा फिर से आतंक का शासन, सामाजिक संघर्ष, शासन का अपराधीकरण और बेलगाम भ्रष्टाचार को आमंत्रण देना।

आसुरी शक्तियों के चंगुल से बिहार को मुक्त कराएँ

मैं बिहार पर भी कुछ विस्तार से बात करना चाहूँगा कि वहाँ पर युद्ध-रेखाएँ खिंच चुकी हैं और 2 दिसंबर को पटना की विशाल रैली में इसका बिगुल बजेगा।

यह युद्धघोष केवल एक विपक्षी पार्टी की सरकार को हटा देने भर की बात नहीं है। यह वास्तव में बिहार को, पिछले 15 वर्षों से चले आ रहे जंगलराज से मुक्त कराने की बात है, क्योंकि ऐसा जंगल राज देश के किसी भी राज्य में देखने में आज तक नहीं आया है। अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ उसकी सहयोगी कांग्रेस है, जिसने राज्य को गरीबी के गर्त में डाल दिया, राजनीति और सरकार में अपराधीकरण बढ़ा है और भ्रष्टाचार इसका मूल सिद्धांत बनकर रह गया है। इस भ्रष्टाचार की लंबी दौड़ में इसके नेताओं ने जातिवाद और सांप्रदायिकता के विषैले बीज बो दिए हैं, जबकि यही अपने आप को सेक्युलरिज्म और सामाजिक न्याय के मसीहा बनने का ढिंढ़ोरा पीटते जा रहे हैं। इसमें विचित्र यह है कि यही नेता संपूर्ण छद्म-सेक्यूलर ब्रिगेड के लाडले बने हुए हैं।

मैं कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्टों तथा आरजेडी को समर्थन देनेवाले सभी सहयोगी

दलों पर आरोप लगाता हूँ कि वे बिहार को कंगाल बनाने के अपराध में जानबूझकर शामिल हैं, और एक समृद्ध तथा सुसंस्कृत राज्य को एक ऐसी लाचारी की हालत में धकेल रहे हैं कि किसी भी बिहारी–गरीब, अमीर, विद्यार्थी, औद्योगिक और कृषि मजदूर, व्यापारी, व्यवसायी–को अपने ही राज्य में अपने लिए कोई उज्ज्वल भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। इससे भी बदतर स्थिति यह है कि लोग अपने ही राज्य में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी सरकार ने ऐसे आतंकी शासन, अपराध और अराजकता की स्थिति को बना रखा है।

इसके परिणामस्वरूप, आज भारत में बिहार से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि वे बिहार पर गर्व करते हुए भी लाचार हैं। इसलिए भाजपा आरजेडी तथा उसके सभी समर्थकों पर आरोप लगाती है कि उन्होंने बिहारी गौरव को बुरी तरह से धूमिल किया है, वह गौरव जो राज्य के स्वर्णिम अतीत से जुड़ा रहा है। उसने स्वतंत्रता आंदोलन में शानदार भूमिका अदा की है। बिहार स्वतंत्रता के आरंभिक दशकों में अत्यंत सुव्यवस्थित एवं समृद्ध राज्यों में से एक राज्य रहा है और जहाँ तक बिहार के योगदान की बात है, तो बिहार के आदर्शवादी युवाओं और विद्यार्थियों ने जेपी के प्रेरणादायी नेतृत्व में लोकतंत्र की रक्षा की है।

मित्रो, आरजेडी नेतृत्व अपना हित साधने के लिए मिथ्या भ्रम का प्रचार कर रहा है कि उनकी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है और वे एक बार फिर अगले पाँच वर्षों के लिए बिहार में विजयी होंगे। उनका अनुमान है कि राज्य में जिस तरह का माफिया जनित भय का माहौल है, उससे लोग भाजपा–जेडीयू गठबंधन को वोट नहीं देंगे। हमें अपने अभियान के आरंभ में ही इस गुब्बारे की हवा निकाल देनी है। हम बिहार के लोगों को बता देंगे कि

"आप डरिए मत। हमारा गठबंधन ही वास्तविक गठबंधन है और एक मात्र विकल्प है जो बिहार को उन आसुरी शक्तियों से मुक्त कराकर रहेगा, जिन्होंने राज्य पर कब्जा कर रखा है। हमारा गठबंधन एक नए और गौरवपूर्ण बिहार की रचना करने में समर्थ है, जिसमें प्रत्येक जाति और संप्रदाय के हर नागरिक को न्याय मिलेगा और बिहार फिर से तीव्र तथा चहुँमुखी विकास के रास्ते पर चल सकेगा, और उसे समृद्ध एवं स्वाभिमानी भारत में अपना सही स्थान मिल सकेगा।"

हरियाणा : हरियाणा में हमारी पार्टी ने अपने ही बल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वर्तमान सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी ने, न तो कार्य प्रदर्शन के रूप में और न ही भाजपा के साथ अपने संबंधों के रूप में ऐसा कुछ भी किया ताकि कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जा सके। हरियाणा में हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा कि नई विधानसभा में हम अपनी संख्या का अधिकतम विस्तार करें, ताकि हम कांग्रेस पार्टी के प्रभावी विकल्प के रूप में उभर सकें।

जनांदोलन और संघर्ष की राजनीति

मित्रो, राजनीति में मेरे अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी तीन प्रकार के कार्यों के माध्यम से लोगों में अपनी छवि को मजबूत करने और उज्ज्वल बनाने में सफल हो सकती है। और मैं, उनके महत्त्व के क्रम में उनका उल्लेख करूँगा। निःसंदेह पहला और अत्यंत कारगर साधन तो चुनावों में प्रदर्शन होता है-चाहे वह चुनाव संसदीय चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या किसी स्थानीय निकाय का चुनाव। दूसरा माध्यम लोगों के हितों के प्रतीक तथा अपने राष्ट्र के हितों की प्रतिरक्षा के लिए जनांदोलन का मार्ग है। तीसरा राजनीतिक रैलियाँ करना है।

कुछ कारणों के एक साथ जुड़ने से—जिनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण यह रहा है कि हम स्वयं ही छह वर्षों तक शासन में रहे—हमारी पार्टी ने हाल के दिनों में कोई बड़ा राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया। पहले 80 के दशक में और हाल में 90 के दशक में अयोध्या मुद्दे पर हमारा जनांदोलन कार्य इस प्रकार का आखिरी प्रयास था। किंतु, मुझे आश्चर्य है कि केंद्र में कांग्रेस-नीत यू.पी.ए. सरकार के छह महीनों के अंदर एक के बाद एक ऐसे मुद्दे हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि हम जनांदोलन और सरकार विरोधी अभियान चला सकते हैं।

हाल ही में भाजपा ने दो मुद्दों पर जनांदोलन कर अपनी क्षमता प्रदर्शित की, जिसने देश में प्रत्येक देशभक्त के दिल और दिमाग को छुआ है—ये मुद्दे हैं संप्रग सरकार और कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय महापुरुष श्री सावरकर और राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे का अपमान करना।

शंकराचार्य की गिरफ्तारी, हिंदुत्व पर प्रहार

इस समय दो ऐसे मुद्दे हैं जिनपर भाजपा की ओर से दृढ़ता से जवाब देने की जरूरत है। एक मुद्दे के कारण लोगों की जेब पर असर पड़ा है और दूसरे मुद्दे ने लोगों की आस्था को गहरा आघात पहुँचाया है।

तमिलनाडु में कांची मठ के संत शंकराचार्य स्वामीजी को एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार करना भारत के आध्यात्मिक और राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व घटना है। जिस ढंग से उन्हें गिरफ्तार किया, जिस ढंग से उन्हें बंदी बनाया गया, और जिस ढंग से उनके खिलाफ राज्य की दो प्रमुख पार्टियों ने अपमानजनक अभियान चलाया, जिसमें कम्युनिस्टों और देश की हिंदू विरोधी ताकतों ने भी साथ दिया, इन सभी बातों ने आज तक के इतिहास में हिंदू समाज की आत्मा को इससे पहले कभी इतना नहीं झझकोरा था।

स्तब्ध कर देनेवाले इस घटनाक्रम में प्रमुखतः दो तत्त्वों ने योगदान दिया है। एक तत्त्व है प्रतिशोध, टकराव, दो दलों में एक से बढ़कर आगे बढ़ने की भावना

और सामाजिक विभाजन की राजनीति, जिसने हाल ही में तमिलनाडु के समाज और शासन-व्यवस्था, दोनों को ही खराब किया है। दूसरा तत्त्व है, हमारे देश में छद्म-सेक्युलरवाद का आम माहौल, जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, हिंदू की भावनाओं को आहत कर रहा है और सेक्युलरवाद के प्रति वचनबद्धता का अंतिम और सर्वाधिक एकमात्र सिद्धांत बना दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि भारत के लोग निम्न प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक सोचें :

- केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश में, 1994 में उस समय मुसलिम मदरसे से माफी क्यों माँगी थी जब आई.बी. ने संदिग्ध आई.एस. आई. समर्थित आतंकवादियों, जिनके जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों से संबंध थे, को पकड़ने के लिए मदरसे के हॉस्टल में छापा मारा। केंद्र सरकार ने दो केंद्रीय मंत्रियों को पुलिस काररवाई के लिए मदरसे से माफी माँगने के लिए भेजा।
- ऐसी स्थिति में क्या होगा यदि कोई केंद्रीय मंत्री किसी सार्वजनिक सभा में कहे कि उसे एक मुसलिम या एक ईसाई होने पर शर्म महसूस होती है?
- गरीब आदिवासियों तथा अन्य गरीब लोगों के कपटपूर्ण धर्मांतरण के प्रति आवाज उठाने को इस देश में सांप्रदायिक काररवाई क्यों माना जाता है?
- किन लोगों ने इस प्रकार का बेतुका और विकृत बौद्धिक वातावरण पैदा किया है, जहाँ हिंदू धर्म, लोकाचार तथा हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी बात को सांप्रदायिक एवं दकियानूसी माना जाता है और जब मैं 'टॉक्सिक' शब्द सुनता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है।

सेक्युलरवाद और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हिंदू लोकाचार को बनाए रखना

मित्रो, अब समय आ गया है और हम पूरी आस्था के साथ इस बात की घोषणा करें कि हिंदू लोकाचार के कारण भारत मूल रूप से सेक्युलर है। अगर हम भारत से हिंदू लोकाचार को ही निकाल दें तो फिर भारत में कुछ भी नहीं बचा रहेगा। इसके लिए हमें कोई गलती नहीं करनी है। कांग्रेस पार्टी का एक वर्ग, कम्युनिस्ट और कुछ अन्य राजनीतिक ताकतें इस देश से हिंदू लोकाचार को सुव्यवस्थित ढंग से धीरे-धीरे मिटाने के लिए षड्यंत्र रच रही हैं और ये हमारी संस्कृति तथा सभ्यता की मूल हिंदू पहचान को ही मिटाने में लगी हुई हैं।

जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता कि भारत बहुधर्मी राष्ट्र है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे देश में व्यावहारिक रूप से विश्व के प्रत्येक धर्म के अनुयायी रहते हैं तथा यहाँ प्रत्येक धर्म का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर सभी धर्मों को माननेवालों के एक समान अधिकार और

जिम्मेदारियाँ हैं। मजहब के आधार पर भेदभाव हमारी युगों पुरानी संस्कृति तथा संविधान के विपरीत है। लेकिन हमारे प्रत्येक विरोधी को समझ लेना चाहिए कि यदि कोई सेक्युलरवाद की आड़ में गैर-धार्मिक और हिंदू विरोधी राजनीति तथा शासन-तंत्र का इस्तेमाल करता है तो भारतीय जनता पार्टी उनके रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़ी हो जाएगी और हम हर प्रकार के बलिदान देने को तैयार रहेंगे।

यही कारण है कि भाजपा ने पार्टी के अंदर अच्छी तरह से विचार विमर्श करने के बाद कांची शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर सार्वजनिक रूप से उभरे आक्रोश से अपने को जोड़ने का निश्चय किया। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ तक इस मामले में उनके कथित आरोप में लिप्त होने का संबंध है, कानून को अपना काम अवश्य करना चाहिए। किंतु यह किसी एक व्यक्ति से संबंधित मामला नहीं है। इसके कहीं अधिक व्यापक आयाम हैं।

20 नवंबर को भूख हड़ताल तथा धरना प्रारंभ करके हमने रामजन्म भूमि मुद्दे की तरह एक अभियान शुरू किया है, जिसके द्वारा हम अपने वैचारिक तथा राजनीतिक विरोधियों का कड़ा मुकाबला करेंगे, इसके द्वारा हम वास्तविक सेक्युलरवाद के अर्थ को सामने रखेंगे, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेंगे तथा हम समाज एवं शासनकला में जीवन को समृद्ध करनेवाले धार्मिक मूल्यों में अपनाने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करेंगे। मैं पूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमण, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, राजग के संयोजक श्री जॉर्ज फर्नांडीज और अनेक सम्मानित साधुओं तथा संतों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

मूल्य-वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन

मूल्य-वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन एक दूसरा मुद्दा है, जिस पर पार्टी ने जनांदोलन का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके बारे में यू.पी.ए. सरकार के छह माह के शासन काल में कमर तोड़ महँगाई के विरोध में एक दिसंबर को संसद् के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव अभियान में जोर-शोर से नारा दिया था—'कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ'। किंतु सच्चाई इसके विपरीत निकली—'कांग्रेस का घात, आम आदमी के साथ'। जब कोई भी आम आदमी बाजार जाकर अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदता है, जब हर बार गृहिणी खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर खरीदती है और जब किसान अपने पंप के लिए डीजल खरीदता है तो उसे यह विश्वासघात कचोटने लगता है।

मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वे सरकार के इस विश्वासघात के बारे में लोगों को जानकारी दें तथा इसके मुकाबले वे वाजपेयी सरकार की सफलता बताएँ कि उनकी सरकार ने अपने छह वर्षों की लंबी अवधि

में मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को पूरी तरह नियंत्रण में रखा।

यू.पी.ए. सरकार की विफलताओं का जोरदार ढंग से पर्दाफाश करें

हमें आंतरिक सुरक्षा के मोरचे पर यू.पी.ए. सरकार की असफलताओं को जोरदार ढंग से उजागर करना चाहिए। इस असफलता को इससे अधिक स्पष्ट ढंग से कोई बात रेखांकित नहीं करती, जिस प्रकार से सरकार नक्सली उपद्रवों से निपटने में असफल हुई है। नक्सल उग्रवाद का विस्तार अब उन जगहों पर भी पहुँच रहा है जो अब तक इससे अप्रभावित थे। इसका एक घातक उदाहरण पिछले सप्ताह देखने को मिला, जब बनारस में नक्सलियों ने 17 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी। एन.डी.ए. सरकार ने सभी प्रभावित राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श करके भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए इस गंभीर संकट को दूर करने के लिए एक समन्वित एवं बहुआयामी रणनीति तैयार की थी। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत इस रणनीति को दरकिनार करते हुए आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वार ग्रुप पर से प्रतिबंध हटा लिया और बिना हथियारों के समर्पण के उन्हें वार्त्ता के लिए आमंत्रित कर दिया।

पंजाब के एक अत्यंत सम्मानित सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने हाल ही में दुःख व्यक्त करते हुए कहा, "यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि एक तरफ तो भारत सरकार माओवादियों द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए नेपाल सरकार को मदद दे रही है, दूसरी तरफ वहीं सरकार माओवादियों को लगभग समान शर्तों पर वार्त्ता के लिए निमंत्रण देकर उनको वैधानिकता प्रदान कर रही है।"

इसी प्रकार भाजपा कार्यकर्ताओं को सभी जगहों पर यू.पी.ए. सरकार द्वारा किसानों, कारीगरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और बेरोजगार युवकों की दुर्दशा की अनदेखी करने के विनाशकारी परिणामों का भी जोरदार ढंग से पर्दाफाश करना चाहिए।

हमें लोगों को यह भी बताना चाहिए कि हाल में प्रधानमंत्री ने अपना बहु-प्रचारित 'काम के बदले अनाज' का जो कार्यक्रम शुरू किया है, वह राजग सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम को फिर से पैकेज बनाकर प्रस्तुत किया गया है। और इसके लिए कोई विशेष अतिरिक्त संसाधन भी नहीं दिए गए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में प्रत्येक स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को वर्ष में 150 दिन का गारंटीशुदा रोजगार जुटाने का वादा भी बड़ी दूर की बात है।

राजग सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख बुनियादी संरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गति धीमी दिखाई पड़ती है, जो गंभीर चिंता का विषय है। महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,

राष्ट्रीय रेल विकास योजना अथवा वाल्मीकि-अंबेडकर आवास योजना की कहीं कोई खैर-खबर नहीं है। नदियों को जोड़ने की परियोजना तो बहुत दूर की बात बनकर रह गई है।

मैं इन बातों का उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूँ कि यू.पी.ए. सरकार का ध्यान और प्राथमिकताएँ सरकार चलाने और विकास से हटकर विपक्ष के विरुद्ध बदले की भावना और सत्तारूढ़ गठबंधन की अंतर्कलह पर केंद्रित हो गई हैं।

कश्मीर मुद्दा : राष्ट्रीय हितों पर समझौता सहन नहीं होगा

मित्रो, हाल के महीनों में कम-से-कम कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच वक्तव्य-प्रत्युत्तर देने की पर्याप्त सक्रियता दिखाई पड़ रही है। भाजपा ने कई बार इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया, जिसकी शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी, को जारी रखा जाना चाहिए। मगर यू.पी.ए. सरकार की कुछ उद्घोषणाओं और कारवाइयों से हमें इस बात की चिंता होती है कि भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के मामले में जिस प्रकार से स्पष्टता और प्रतिबद्धता की कमी दिखाई पड़ती है, उसे किस प्रकार से दूर किया जाएगा। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच सितंबर में हुई मुलाकात के बाद एक वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें भारत कश्मीर नीति के बारे में जारी दस्तावेज में सीमा पार आतंकवाद को छोड़ने की पाकिस्तान की वचनबद्धता को फिर से दोहराने का उल्लेख कराने में विफल रहा था।

17 नवंबर को श्रीनगर में प्रधानमंत्री की सार्वजनिक सभा से मात्र 200 मीटर की दूरी पर आतंकवादी हमला हुआ। यह घटना इस कड़वी सच्चाई को फिर पुख्ता करती है कि जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से आतंकवादी कारवाई निरंतर जारी है।

इसके बाद डॉ. मनमोहन सिंह ने बयान दिया कि जम्मू-कश्मीर पर बातचीत के लिए सभी विकल्प खुले हैं। जनरल मुशर्रफ ने जम्मू-कश्मीर को 7 भागों में बाँटने का विचार जाहिर किया। जनरल मुशर्रफ के अनुसार यह बँटवारा धार्मिक एवं क्षेत्रीय आधार पर होना चाहिए। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव औपचारिक तरीके से आता है तो भारत विचार कर सकता है।

प्रधानमंत्री ने श्रीगनर में अपने भाषण में कहा कि "उपमहाद्वीप में कोई भी नई रेखा नहीं खींची जाएगी।" दूसरी ओर एक बातचीत यह भी हो रही है कि एक 'पैकेज समाधान' के रूप में कुछ रेखाओं को 'मिटाया' जा सकता है।

भारतीय जनता पार्टी कश्मीर जैसे गंभीर मुद्दे पर यू.पी.ए. सरकार की

अस्थायी एवं जनता की राय जाननेवाली और तदर्थ प्रकार की योजना की भर्त्सना करती है। भाजपा यह माँग करती है कि सरकार जनता एवं संसद्—दोनों को इस मुद्दे पर विश्वास में लेकर ही कोई कदम उठाए।

अयोध्या मुद्दे पर बढ़ती आम सहमति

मित्रो, एक महत्त्वपूर्ण घटना राष्ट्रीय परिषद् एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों के बीच—10 नवंबर को एन.डी.ए. के घटक दलों की बैठक हुई। आपको याद होगा कि मैंने राष्ट्रीय परिषद् के अधिवेशन में अपने भाषण में रामजन्मभूमि मुद्दे का जिक्र किया था, जहाँ अयोध्या में रामजन्म स्थान पर राममंदिर का निर्माण करने संबंधी पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया था, वहीं मैंने कहा था कि समस्या के समाधान के दो विकल्प हैं—पहला न्यायालय का फैसला, दूसरा हिंदू एवं मुसलिमों के प्रतिनिधियों द्वारा बातचीत कर समस्या का समाधान निकालना। भाजपा, दूसरे विकल्प को बेहतर मानती है। दुर्भाग्यवश, ऐसी परिस्थितियाँ बनाने की कोशिश की गई, जिससे यह प्रतीत हो कि राजग के घटक दल मेरी प्रतिक्रिया से खुश नहीं हैं।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजग की बैठक ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बीच मतभेद फैलाने की कोशिशों पर पानी फेर दिया। राजग की बैठक में पारित प्रस्ताव में, राजग ने औपचारिक रूप से बातचीत के जरिए समाधान निकालने को प्राथमिकता दी है, यह समाधान आपसी समझ, सद्भावना और शांति के माहौल में बातचीत के जरिए निकाला जाए। मैं नहीं समझता कि कोई भी सही सोच रखनेवाला व्यक्ति इसका विरोध करेगा।

मैं इसका उल्लेख एक व्यापक महत्त्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान दिलाने के लिए कर रहा हूँ। देश में बहुत तेजी से यह मत बन रहा है कि इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने में और विलंब उचित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि 2004 के चुनावों में राजग एवं कांग्रेस, दोनों ने अयोध्या मुद्दे पर समान मत व्यक्त किया था। अब राजग इस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़कर यह घोषणा कर रही है कि हमें बातचीत द्वारा इस समस्या का हल करने का तरीका ज्यादा उचित लगता है। आज मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक से, कांग्रेस एवं अन्य दलों से आग्रह करता हूँ कि वे बातचीत के द्वारा समाधान निकालने के एकमात्र तर्क और लोगों की सुस्पष्ट इच्छा को समझें और अयोध्या मुद्दे के समाधान पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाने पर अपना योगदान दें।

प्यारे मित्रो, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं आप सभी को एक महत्त्वपूर्ण कार्य (टास्क) के बारे में स्मरण कराना चाहूँगा, जिसे हमने अपने लिए तय किया है। और यह है 'TASKS AHEAD' दस्तावेज पर केंद्र से मंडल स्तर तक व्यापक चर्चा शुरू करने के निर्णय के क्रियान्वयन की शुरुआत। इसमें पार्टी को वैचारिक,

राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत करने हेतु अनेक दायित्वों को चिह्नित किया गया है। इसके क्रियान्वयन के महत्त्व को देखते हुए मैंने इसकी जिम्मेदारी श्री वेंकैया नायडू को सौंपने का निश्चय किया है।

मैं आशा करता हूँ कि आगामी तीन दिनों की बैठक में हम सार्थक विचार करेंगे।

धन्यवाद,

वंदेमातरम्।





अध्यक्षीय भाषण

श्री एम. वेंकैया नायडू

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

हैदराबाद 11-12 जनवरी, 2004

मैं हैदराबाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में जबरदस्त सफलता के बाद आह्लादपूर्ण माहौल में हो रही है। राजनीतिक पंडितों ने इस चुनाव को 'सेमी-फाइनल' का नाम दिया था, जिसमें भाजपा ने उन चार राज्यों में से तीन राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह पराजित किया, जहाँ वह सत्ता में थी और राजग ने चुनाव में जाने वाले पाँच राज्यों में से चार राज्यों में विजय प्राप्त की। भाजपा ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकारें बनाईं। राजग के घटक मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम में सरकार बनाई।

पराजय की इस शर्मनाक घड़ी में कांग्रेस द्वारा दिल्ली की सरकार बचा ले जाना ही एकमात्र सांत्वना रही, जबकि वहाँ भी उसका बहुमत पिछली बार से कम हो गया।

सफल चुनाव रणनीति के तत्त्व

मैं चुनावी राज्यों के भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ और प्रदेश इकाइयों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने हमारी इस महान् सफलता में बड़े उत्साह से मदद की। हमने सही मुद्दों को उठाया, जो प्रत्येक राज्य में आम लोगों से संबंधित थे और इन मुद्दों पर हमने सतत और व्यवस्थित ढंग से जन अभियान चलाया। हमने सफलतापूर्वक सत्तारूढ़ कांग्रेसी सरकारों की विफलताओं को उजागर कर दिया कि उन्होंने बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के अपने वायदों को पूरा नहीं किया। इस प्रकार परिवर्तन की दिशा में कांग्रेस के विरुद्ध लोगों का आक्रोश बढ़ा।

हमने केंद्र में राजग सरकार की अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियों और पहल

को भी कारगर ढंग से प्रस्तुत किया। इस कारण लोगों को कांग्रेस की जन-विरोधी तथा विकास-विरोधी नीतियों एवं भाजपा की जन-समर्थनकारी और विकासोन्मुखी रिकॉर्ड के मध्य अंतर भी समझ में आ गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी विजय केवल सरकार विरोधी मतों के आधार पर नहीं हुई, बल्कि यह भाजपा के पक्ष में सकारात्मक मत था और केंद्र में श्री वाजपेयी की सरकार के प्रति लोकप्रिय समर्थन था।

हमारी चुनावी सफलता में अन्य निर्णायक तत्त्वों ने भी अपना योगदान दिया है। हमने लंबे समय तक कड़ा परिश्रम किया है, और इसमें हमारी सुव्यवस्थित योजना और ठीक ढंग से इसके कार्यान्वयन ने भी काम किया है। केंद्र और पार्टी की प्रदेश इकाइयों के बीच सभी स्तरों पर नेताओं के कुशल मार्गदर्शन तथा पूरी तरह से तालमेल का भी योगदान रहा है। अपने अभियान के दौरान हमें प्रत्येक स्तर पर श्री अटलजी और श्री आडवाणीजी का समुचित मार्गदर्शन मिला। तीन राज्यों में श्री अटलजी की विशाल चुनाव रैलियों ने अंतिम परिणाम को काफी हद तक प्रभावित किया।

इन अलग-अलग राज्यों में पार्टी के तीन मुख्यमंत्रियों, अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने जितना कठोर परिश्रम किया है, मैं विशेष रूप से उनके प्रति भी हार्दिक आभार प्रगट करता हूँ।

कांग्रेस पार्टी का अनिश्चित भविष्य

मित्रो, हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा और राजग की विजय कोई साधारण विजय नहीं है और न ही कांग्रेस के लिए यह कोई साधारण पराजय। इससे पहले कभी भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल इतनी बुरी तरह से क्षत-विक्षत नहीं हुआ। जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, इस स्थिति की तुलना आपातकाल शासन के बाद 1977 के आम चुनावों में उसकी बुरी तरह से हुई हार के साथ ही की जा सकती है। यह ठीक है कि उस समय की कांग्रेस का मनोबल बुरी तरह गिरा था, परंतु उसके सामने अपने भविष्य की अनिश्चितता की स्थिति नहीं थी। इसके विपरीत, आज की तरह उस समय कोई मजबूत और संगठित राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, जो भारतीय राजनीति में उसकी प्रभुता को चुनौती दे सके।

कांग्रेस के 119 वर्षों के इतिहास में पहली बार अब उसके वर्तमान नेतृत्व के अंतर्गत कांग्रेस के अस्तित्व को बनाए रखने की चिंता खड़ी हो गई है। एक बड़ी समाचार पत्रिका ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्षा के पार्टी में योगदान को एक रोचक शीर्षक देकर प्रस्तुत किया। पत्रिका के मुखपृष्ठ पर लिखा था 'हनी', आई श्रंक द कांग्रेस! जोकि एक प्रसिद्ध कॉमेडी फिल्म 'हनी, आई श्रंक द किड' की तर्ज पर था।

कांग्रेस अब ऐसी हालत में पहुँच गई है कि जहाँ उसका अपना जनाधार सिकुड़ा है, उसकी प्रतिष्ठा गिरी है, राष्ट्र के कामों में कारगर ढंग से हस्तक्षेप करने की उसकी क्षमता भी कम हुई है और उसके नेतृत्व की विश्वसनीयता में कमी आई है। आज कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है, जिसमें न तो एकता है, न स्पष्टता है, न ही योग्यता है और न ही लोगों में उसकी स्वीकार्यता है।

2003 : भारत और भाजपा के लिए एक अच्छा वर्ष

प्रिय साथियो, वर्ष 2003 देश और भाजपा के लिए एक अच्छा वर्ष रहा है। कांग्रेस से तीन बड़े राज्य हथियाने के अलावा, हमने अनेक उप-चुनावों में—विशेष रूप से सोलापुर संसदीय चुनाव और सोनगढ़ विधानसभा उप-चुनावों में—कांग्रेस को ऐसे आघात पहुँचाए हैं, जिनसे उसका आत्मविश्वास ही खत्म हो गया है। हालाँकि हमने दिल्ली में अपनी स्थिति में सुधार किया है, परंतु हम कांग्रेस को हराने में कामयाब नहीं हो सके, जो निश्चित ही निराशाजनक है। दिल्ली में हमारे सहयोगियों को इन विफलताओं के कारणों का शांत भाव से विश्लेषण करना चाहिए और शीघ्र ही इन्हें सुधारने के उपाय करने चाहिए, ताकि हम आगामी संसदीय चुनावों में फिर से शानदार प्रदर्शन करके दिखा सकें।

अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना भी वर्ष 2003 में पार्टी की उपलब्धि रही। पूर्वोत्तर में हमारा प्रभाव मजबूती से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में हमने कई मित्र बनाए हैं। हम नगालैंड सरकार में शामिल हैं। कांग्रेस तेजी से हाशिए पर जा रही है। हमारी सरकार पूर्वोत्तर में शांति एवं विकास का वातावरण तैयार करने के साथ स्थिति को सामान्य रखने में भी सफल रही है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूँगा कि वे इस क्षेत्र में बनी परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाते हुए आगामी चुनावों में भाजपा एवं सहयोगियों की संभावनाओं को उज्ज्वल बनाएँ।

एक अन्य कारण से भी वर्ष 2003 पार्टी के लिए काफी अच्छा रहा। पार्टी और सरकार के मध्य सभी स्तरों पर नियमित एवं गहन संवाद स्थापित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री एवं उप-प्रधानमंत्री ने पार्टी से जुड़े मामलों पर विचार करने के लिए हमेशा समय निकाला। उन्होंने सभी महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर पार्टी को विश्वास में लिया। सरकार में मौजूद हमारे सहयोगियों ने पार्टी से मिलने वाले सुझावों एवं 'फीडबैक' को तत्परता से स्वीकार किया। मुझे प्रसन्नता है कि पार्टी नेतृत्व एवं कार्यकर्ताओं के मध्य, केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर संवाद बेहतर हुआ है। राष्ट्रवादी, संगठनों के साथ भी हमारे संबंध मधुर रहे हैं। भाजपा एवं राजग की सहयोगी पार्टियों के बीच भी संवाद में वृद्धि हुई है। मुझे आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष इस स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाएँगे।

पिछले वर्ष मुंबई में आयोजित तीन दिवसीय चिंतन बैठक पार्टी के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना रही। इस बैठक से हमें पार्टी एवं सरकार, दोनों के प्रदर्शन का गहराई से अध्ययन करने में सहायता मिली। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी को यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूँ कि चिंतन बैठक में प्रस्तुत किए गए अधिकांश विचारों एवं सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

इसी संदर्भ में मैं वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस सप्ताह के प्रारंभ में कई साहसिक घोषणाएँ कीं, जिससे अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को लाभ पहुँचा। देश में चल रहे 'फील गुड' से भरपूर वातावारण में और वृद्धि हुई है। वित्तमंत्री पचास हजार करोड़ रुपए की आधारभूत योजनाओं, जिनमें ग्रामीण आधारभूत ढाँचा भी शामिल है, को प्रारंभ करने के लिए विशेष रूप से शाबाशी के पात्र हैं।

बाईस राज्यों में संगठनात्मक चुनाव सफलतापूर्वक कराए जा चुके हैं। चुनाव बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में एवं सर्वसम्मति से कराए गए। बाकी राज्यों में संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया अभी पूरी होनी है।

वर्ष 2003 में हमने संगठनात्मक ढाँचे को सभी स्तरों पर मजबूत करने के लिए 'समर्पण सहयोग' एव 'संवाद' जैसे नए कार्यों को शुरू किया। इनके यथेष्ट परिणाम निकले हैं। मैं देख सकता हूँ कि काम में जुटने की भावना बढ़ी है। केंद्रीय मंत्रियों ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, पार्टी के द्वारा समय माँगे जाने पर सदैव आशानुरूप सहयोग दिया।

एक तरह से हमने उस पुरानी सीख को पुनः स्मरण किया है जो सदैव भाजपा के संगठनात्मक दर्शन की बुनियाद रही है। हमारा दल कार्यकर्ताओं का दल है। वे दल के प्राण हैं। हमें उनकी चिंता करनी चाहिए, उनकी समस्याएँ सुननी चाहिए, हमें उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, हमें उन्हें रास्ता दिखाना चाहिए और उन्हें दल की गतिविधियों में पूरी तरह संलग्न होने का अवसर देना चाहिए। हम टीमवर्क में विश्वास रखने वाले दल हैं, जो पदाधिकारियों में बंधुत्व की भावना में विश्वास रखता है। हम सर्वोत्कृष्ट परिणाम तब प्राप्त कर सकेंगे जब हमारे बीच लगातार संवाद बना रहेगा। मैंने इस भावना को बढ़ाने का भरसक प्रयास किया है।

राजग सरकार के काल में भारत की शानदार प्रगति

प्रिय साथियो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वर्ष 2003 देश और दल, दोनों के लिए काफी अच्छा रहा। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हमारा यह वर्ष दल के लिए अच्छा रहा। जहाँ तक देश का सवाल है तो आप सभी जानते ही हैं कि पिछला वर्ष कितना अच्छा रहा। भारत की अर्थव्यस्था तेजी से बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था संसार की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष आए अच्छे मानसून के

बाद हम अपने परिश्रमी किसानों के बेहतर परिणाम की आशा रख सकते हैं। विनिर्माण उद्योग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी सफलताओं ने पूरे विश्व का ध्यान खींचने के साथ प्रशंसा बटोरी है। रुपया मजबूत हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार सौ अरब डालर के स्तर के ऊपर निकल गया है।

हमारी सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न विकास योजनाओं के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हम 'राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना', 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना', 'अन्त्योदय अन्न योजना', 'सर्वशिक्षा अभियान', 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना' जैसी योजनाओं के साथ दूर-संचार के क्षेत्र में हमारी शानदार सफलता है। हमने हाल ही में ग्रामीण कारीगरों के लिए एक क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, जिसका लाभ हथकरघा एवं हस्तकलाओं के क्षेत्र में काम करनेवाले करोड़ों लोगों को मिलने की आशा है। महिला सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाई गई हमारी योजनाओं की भी भरपूर सराहना की गई।

मैं बताना चाहूँगा कि विदेश नीति के मोरचे पर भारत की सफलताएँ अभूतपूर्व रही हैं। पूरे विश्व ने अटलजी को एक दूरदर्शी नेता के रूप में स्वीकारा। उनके नेतृत्व में भारत के कद को अभूतपूर्व ऊँचाई मिली। उनकी विदेश नीति से जुड़ी सफलताओं की ताजा कड़ी इसलामाबाद में आयोजित बारहवाँ 'दक्षेस' सम्मेलन रहा, जहाँ उन्होंने भारत एवं पाकिस्तान के मध्य संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान की।

यहाँ पर यह ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि जहाँ तक भारत-पाकिस्तान के रिश्तों की बात है, तो हमारी सरकार ने यह सफलता 'सीमा पार आतंकवाद' के विषय पर अपनी भूमिका पर बिना कोई समझौता किए प्राप्त की है। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान को वचन देना पड़ा कि वह भारत के खिलाफ चलने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा।

इसलामाबाद में प्रधानमंत्री की यात्रा ने भारत और पाकिस्तान तथा पूरे उप-महाद्वीप में आशा और सदाशयता का आधार बनाया है। अब सभी लोगों द्वारा यह महसूस किया जाने लगा है कि जहाँ कांग्रेस की सरकारों द्वारा कश्मीर समस्या को पैदा किया गया तथा उसे बढ़ाया गया वहीं इस समस्या का समाधान सिर्फ श्री अटलजी एवं उनकी सरकार ही कर सकती है।

यह आशा जम्मू एवं कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल होने एवं अक्तूबर 2002 राज्य में ऐतिहासिक निष्पक्ष चुनाव होने के बाद बलवती हो गई है।

पार्टी के अभियान को जन-अभियान में बदलें

अब यह पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी संप्रेषण

गतिविधियों में तेजी लाए, जिससे भारत के चहुँमुखी विकास का संदेश जन-जन तक पहुँचे। मैं पार्टी और सरकार, दोनों से चाहूँगा कि वे प्रचार-प्रसार के काम में और तेजी लाएँ। देश में 'फील गुड' तत्त्व पहले से मौजूद है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम इसे 'फील ग्रेट' में तब्दील कर सकें।

भारत के लोग अटलजी की सरकार को उसके शानदार प्रदर्शन के चलते पुनः सत्ता में लाने के इच्छुक हैं। अब हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम इस 'जनआकांक्षा' को एक दृढ़ संकल्प में परिवर्तित करें। राजनीति, धर्म, प्रदेश, जाति, वर्ग, भाषा, लिंग की सीमाओं को पार करते हुए, हमें उन वर्गों को गले लगाना है, जो अब तक भाजपा से दूर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हमें अपने 'चुनाव अभियान' को 'पार्टी अभियान' से 'जन-अभियान' में बदलना होगा।

हमें युवाओं तक पहुँचने के लिए पूरी शक्ति लगानी होगी। आइए हम समाज के सभी वर्गों में, विशेषकर युवाओं के बीच, एक वृहद विचार मंथन प्रारंभ करे, जिसका मुख्य बिंदु हो 'उनके पचास वर्ष बनाम हमारे पाँच वर्ष'। हम उनके सम्मुख एक प्रश्न रखें 'भारत अपनी प्राचीन सभ्यता, सदानीरा नदियों, उपजाऊ भूमि, परिश्रमी जनता, कुशल कामगारों, अच्छे पेशावरों, कुशाग्र मेधा और वृहद मानव संसाधन के बावजूद विकास के क्षेत्र में क्यों पिछड़ गयों? भारत क्यूं पिछड़ा, जबकि एशिया के छोटे-छोटे देश भी शानदार तरीके से आगे बढ़ गए?' कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसकी गलत प्राथमिकताओं, अस्पष्ट नीतियों, कुशासन एवं भ्रष्ट तौर-तरीकों के चलते, पचास वर्षों का समय कमोबेश नष्ट कर दिया गया। इसके विपरीत, राजग द्वारा बहुत कम समय में काफी उपलब्धियाँ अर्जित की गईं। इसलिए कांग्रेस को समर्थन देकर इस नई शुरुआत को क्यों बाधित किया जाए?

अगले पाँच वर्षों के लिए हमारी प्राथमिकताएँ

हमें आनेवाले पाँच वर्षों के लिए अपनी प्राथमिकताएँ एवं योजनाओं को स्पष्ट करना होगा। गरीबी पर जोरदार प्रहार, क्षेत्रीय विषमताओं को शीघ्रता से दूर करना, शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य अंतर को पाटना, रोजगार सृजन के साथ स्वरोजगार के अवसरों का बड़े पैमाने पर निर्माण, नदियों को जोड़ने जैसी महती परियोजनाओं पर काम शुरू कराना, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल एवं साफ सफाई को बड़े पैमान पर सुधारना, कृषि को छोटे एवं गरीब किसानों के लिए लाभदायक बनाना, लघु एवं ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग को सामाजिक न्याय एवं आर्थिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण को बढ़ाना, जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी कदम उठाना तथा पंचायती राज संस्थाओं का और अधिक विकेंद्रीकरण—हमारी प्राथमिकताएँ होंगी।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आगामी वर्षों में भारत के अल्प विकसित क्षेत्र तथा भारतीय समाज के अल्प विकसित भाग को भी उतना ही चमकाना जितना देश का विकसित भाग आज चमक रहा है, हमारी प्राथमिकता होगी।

मैं पार्टी पदाधिकारियों एवं हमारे शुभचिंतक विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ, जो आनेवाले पाँच वर्षों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी।

समाज के नए वर्गों तक पहुँचना

मित्रो, मैं आप सभी से तथा भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे राजग सरकार द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण प्रयासों एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों को देश के कोने-कोने तक ले जाएँ। हमें समाज के उस वर्ग तक पहुँचने के अपने प्रयासों को तेज करना होगा जो अभी तक हमसे दूर रहे हैं। भाजपा को समाज के नए वर्गों में समर्थन मिल रहा है यह हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में देखने को मिला, जब आदिवासियों ने कांग्रेस को नकारते हुए हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया।

इस संदर्भ में मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे अल्पसंख्यक भाई-बहनों तक पहुँच, जो कांग्रेस एवं अन्य विरोधी दलों द्वारा भाजपा के विरुद्ध दुष्प्रचार को देख चुके हैं। मैं अल्पसंख्यक बंधुओं से अपील करता हूँ कि वे संकोच की मानसिक बाधा को पार करें, भाजपा के पक्ष में मत दें एवं श्री अटलजी के नेतृत्व को मजबूत करें। हमारे विरोधियों द्वारा पैदा किए गए झूठे दावों को अस्वीकार करें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी सरकार के अंतर्गत होने वाली भारत की तीव्र एवं विस्तृत प्रगति से आपको लाभ होगा।'

भाजपा और राजग के पक्ष में लहर का निर्माण

हमें भाजपा और राजग के पक्ष में लोगों के समर्थन की जोरदार लहर का निर्माण करना होगा और निश्चय ही हम ऐसा कर भी सकते हैं। इससे हमें पुनः और पहले से कहीं ज्यादा बड़ा जनादेश पाने में मदद मिलेगी, जो हमारे 'मिशन 2004' का लक्ष्य भी है। जैसा कि श्री आडवाणीजी ने अनेक बार हमसे कहा है कि भाजपा अभी तक आखिरी सीमा तक नहीं पहुँची है। जरा पीछे पलटकर देखिए, सन् 1984 में हम कहाँ थे? तब हमारी लोकसभा में मात्र 2 सीटें थीं। इसके बाद हर आनेवाले चुनावों में अपने सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर हमने अपने विरोधियों और स्वयं को भी चकित कर डाला है। हम ऐसा फिर कर सकते हैं।

हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा नेतृत्व है। श्री अटलजी आधुनिक समय

के सबसे बड़े कद के भारतीय नेता के रूप में उभरे हैं। उन्हें 'एकजुट रखने की विद्या का माहिर' माना जाता है। गठबंधन धर्म का निर्वहण करने में उनका कोई सानी नहीं है। अपने इसी गुण के चलते उन्होंने राजग के वैचारिक विविधता के बीच राजनीतिक एकता का मॉडल बनाया। पिछले वर्षों में हमारे पास उपलब्धियों का शानदार 'ट्रैक रिकॉर्ड' रहा है। हमने एक विश्वसनीय दल के रूप में अपने सहयोगियों के मध्य पहचान बनाई है और एकजुटता बनाए रखी। हमारे पास एक विशाल संगठन नेटवर्क है। भारतीय समाज के अधिकाधिक वर्ग और हमारे विशाल देश के अधिकाधिक क्षेत्र हमारे साथ जुड़कर हमारा समर्थन करना चाहते हैं।

कांग्रेस और बाकी विरोधियों के बीच अंतर एकदम साफ है। हमारे विरोधी बिखरे हुए हैं, वे नेतृत्व विहीन हैं। इसीलिए मेरा कहना यही रहा है कि आनेवाले चुनावों में लोगों के सामने श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक प्रश्नचिह्न के बीच चुनाव करने का प्रश्न रहेगा। कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट न हो पाने के कारण और उसकी अध्यक्ष को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार मानने से इनकार करने के कारण हमारी विरोधी पार्टियाँ राजग को हराने के लिए, दो मंच बनाने के हास्यास्पद विचार में लगी हुई हैं। उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। साफ है कि इससे भाजपा और राजग को लाभ मिलेगा। हम 'ऑपरेशन 2003' में सफल रहे। आइए, हम 'मिशन 2004' को और अधिक सफल बनाने के कार्य में जुट जाएँ।

मैं सभी लोगों से हैदराबाद से यही संदेश ले जाने की आशा करता हूँ। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूँ कि 'सभी गाँवों तक पहुँचें, हर गली में जाएँ, हर दरवाजे पर दस्तक दें और हर मतदाता से बात करें।' हम सभी को प्रत्येक स्तर पर संगठित होकर काम करना होगा। हम सबको दिन-रात काम करना होगा। हमारे भीतर जीत की भावना भरी होनी चाहिए। जहाँ यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों को अपनी सरकारों के विकास कार्यों की गति बढ़ानी होगी। हमारा ध्यान नहीं बँटना चाहिए। चिड़िया की आँख पर निशाना लगाने वाले अर्जुन की भाँति हमें भी आस-पास की गतिविधियों से विचलित हुए बिना 'मिशन 2004' की सफलता पर निगाह रखनी चाहिए।

चुनाव अभियान के लिए संसाधनों का भी काफी महत्त्व है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हम एक 'चुनाव सहायता निधि' के रूप में अभियान के लिए राशि एकत्रित करें। इसके अंतर्गत 10,000, 5,000 एवं 1,000 रुपए की धनराशि दी जा सकेगी। यह धनराशि मात्र चेक द्वारा स्वीकारी जा सकेगी। पारदर्शिता लाने के लिए सभी दानदाताओं के नाम पार्टी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएँगे। मैं सुझाव रखता हूँ कि इसे एक राष्ट्रव्यापी अभियान का रूप दिया जाए।

मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी 'मिशन 2004' की कार्य योजना पर विचार करके उस पर स्वीकृति दें। मैं चाहूँगा कि सभी महासचिव चुनाव के

औपचारिक रूप से घोषित होने से पहले ही कार्यक्रम की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर लें।

आइए, हम युद्ध के लिए आगे बढ़ें विजय हमारी है!

धन्यवाद,

वंदेमातरम्



राष्ट्रीय परिषद्

नई दिल्ली

6 फरवरी, 2004

सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं उप-प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझमें अपना विश्वास एवं प्रेम प्रदर्शित करते हुए अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम प्रस्तावित किया। मैं राष्ट्रीय परिषद् एवं राज्य परिषदों के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद पर मुझे दुबारा चुना।

केवल हमारी पार्टी ही ऐसी पार्टी है, जो मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठनात्मक चुनाव नियमित रूप से कराती है। आंतरिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों को बल प्रदान करता है। यदि हमारी पार्टी लगातार मजबूत हुई है तो उसका मूल आधार पार्टी के भीतर लोकतंत्र एवं पार्टी के भीतर अनुशासन के सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता रही है।

अध्यक्ष पद पर पहली बार चुने जाने के पश्चात् 3 अगस्त, 2002 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में मैंने कहा था कि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ जो पार्टी के साथ आगे बढ़ा हूँ। मैं आज भी हृदय से एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी द्वारा मुझे दिए गए इस दायित्व की गुरुता को मैं अनुभव करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी क्षमता के साथ निभाऊँगा, साथ ही जो आदर्श और विचारधारा की विरासत हमें डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मिली है, उसे मैं अक्षुण्ण रखूँगा।

आज के दिन मैं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे को भी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जो हाल ही में हमें छोड़कर चले गए। जब मैं 18 महीने के अपने पिछले कार्यकाल पर दृष्टिपात करता हूँ तो मुझे आगे बढ़ने के लिए संतोष की अनुभूति होती है। सरकार एवं संगठन के अपने सहयोगियों के साथ हम पार्टी को मजबूत करते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रहे हैं। विशेष रूप से, ऑपरेशन 2003 की हमारी सफलता, जिसमें हमें मध्य प्रदेश,

राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में जोरदार सफलता मिली और देश की राजनीति में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई।

राष्ट्रीय परिषद् की यह बैठक आगामी लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में हो रही है, जिसे हमने 'मिशन 2004' की संज्ञा दी है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा इस ऐतिहासिक चुनावी युद्ध में विजयश्री का वरण करेगी।

मित्रो, हम आज एक गर्व और उपलब्धि की भावना के साथ एक महती जिम्मेदारी की अनुभूति करते हुए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।

पिछले छह वर्षों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश की सूरत बदलने के महत्त्वपूर्ण काम में लगी हुई है और इसी संकल्प के लिए हम सब समर्पित हैं।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के गठन के समय में हमने जनता से एक स्वाभिमानी एवं समृद्ध भारत का वादा किया था। भाजपा के हम सभी बंधुओं के लिए यह वादा एक चुनावी वादे से कहीं अधिक था। वह हमारे लिए एक लक्ष्य सरीखा था।

आज जब हम अगले लोकसभा चुनावों की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं तो मैं गर्व के साथ यह दावा कर सकता हूँ कि हम भारत की क्षमताओं को पहचानकर उसका विकास करने में सफल रहे हैं।

पचास वर्ष की निराशा और अवसरों को गँवाने के बाद भारत ने गति पकड़ी है। इसने अपनी आत्मा को पहचाना है। देश की ऊर्जा को प्रयोग में लाया जा रहा है। प्राचीन युग में भारत विश्व गुरु था और विज्ञान, कला एवं व्यापार के क्षेत्र में संसार का महत्त्वपूर्ण केंद्र था। हमने वह स्थिति गँवा दी। हमारी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास छिन गया। हम अंधकार युग में प्रविष्ट हो गए। हमारी दृष्टि सिमट गई।

आज हमने अपनी विरासत पर पुनः दावा करने के लिए तैयारी कर ली है। हमने अपने लक्ष्य बना लिये हैं और हमारे लक्ष्य काफी ऊँचे हैं—

- वर्ष 2020 तक भारत एक विकसित देश अवश्य बनना चाहिए।
- भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनना चाहिए।
- भारत पुनः जगत् गुरु के रूप में प्रतिस्थापित होना चाहिए।

श्री वाजपेयी के नेतृत्व में भारत यह लंबी छलाँग लगाने के लिए तैयार है। राजग सरकार ने भारत की रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्रीजी ने नकारात्मक मनस्थिति और निरर्थक आलोचना को नकारने का रास्ता सुझाया है।

वाजपेयीजी ने हमें बताया है कि हम दूसरी पायदान पर ही नहीं बने रह सकते। उन्होंने हमें बड़ा सोचने की प्रेरणा दी है। वाजपेयीजी ने 'मेड इन इंडिया (भारत में बने)' शब्द के साथ गर्व की भावना जोड़ी है।

देश की छवि चमकी है और विश्व बिरादरी में भारत का स्थान ऊँचा हुआ है। वर्ष 1998 में हुए संसदीय चुनावों के समय हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा था कि 'वह व्यक्ति जिसकी भारत को प्रतीक्षा है', आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अटलजी ऐसे नेता हैं जिनसे भारत अगाध प्रेम करता है और विश्व सराहना करता है।

आज हम देश के बदलते हुए मिजाज को देख और महसूस कर सकते हैं। जिस बीज को हमने छह वर्ष पूर्व बोया था, वह अब फल देने लगा है।

भारत के विकास की प्रक्रिया दिखाई दे रही है और अनुभव की जा रही है।

हमारे पास प्रसन्न होने के कई कारण हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई योजनाएँ चलाई हैं जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चलाई गई सबसे बड़ी 'काम के बदले अनाज' योजना है; ग्रामीण आवास, किसानों को उपज का पूरा मूल्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गावों को जोड़ने की विशाल योजना, साढ़े तीन करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, शीतगृहों की श्रृंखला, ग्रामीण अनाज भंडार, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक द्वारा कर्ज की राशि को 40,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70,000 करोड़ करना।

यह सब कृषि और ग्रामीण भारत के विस्तृत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की सूचक है।

पिछले पाँच वर्षों में भारत में 'जोड़ने की क्रांति' हुई है जिसके अंतर्गत राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, रेलमार्गों, हवाई अड्डों एवं पत्तनों को जोड़ा गया है। 'स्वर्णिम चतुर्भुज योजना', 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' और दूरसंचार क्रांति के प्रभावों को हम देख सकते हैं। आवास निर्माण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जो ब्याज दरों में बड़ी मात्रा में कटौती करने से संभव हो सकी है।

आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति है। पूरा विश्व हमारा सम्मान करता है। वह हमारी क्षमताओं से भयाक्रांत भी रहता है। थोड़े समय में हम ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए सुधारों, नदियों को जोड़ने तथा विश्व बाजार में कृषि पदार्थों की पहुँच के लाभ को महसूस कर सकेंगे।

हमने भारत को 'कमी के युग' से बाहर निकाल लिया है। हमने जमाखोरों एवं कालाबाजारी करनेवाले लोगों का व्यवसाय ठप्प करा दिया है। नियंत्रणों को हटाते हुए हम 'दलाल' शब्द को चलन से बाहर करने के कगार पर हैं।

हमारे खाते में कई महत्त्वपूर्ण कानून बनाने की भी उपलब्धि दर्ज है, जैसे दल-बदल विरोधी कानून, राज्यसभा में ओपन बैलेट चुनाव, मंत्रिमंडलों के आकार से जुड़ा कानून तथा सैनिकों के लिए प्रॉक्सी वोटिंग की व्यवस्था।

हमने अपने बच्चों और पोते-पोतियों के लिए एक बेहतर जीवन की नींव तैयार की है। उन्हें ऐसे अवसर उपलब्ध होंगे जिनके बारे में हम कभी सपने में

भी नहीं सोच सकते थे। हमारा विकास न केवल दिख रहा है बल्कि वह विश्वसनीय भी है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में आज भारत का महत्त्व है

भारतीय विश्व में सदैव महत्त्वपूर्ण माने जाते रहे हैं, परंतु आज भारत महत्त्वपूर्ण हो चला है।

भारत महान्ता की राह पर है। हम चाहते हैं कि यह यात्रा सुगम एवं निर्बाधित हो।

इन चुनावों में प्रत्येक भारतीय के सामने कुछ प्रश्न खड़े हैं।

- क्या आप आगे जाना चाहते हैं या आप पीछे जाना चाहते हैं?
- क्या आप निरंतरता चाहते हैं या उसमें बाधा खड़ी करना चाहते हैं?
- क्या आप महान्ता चाहते हैं या आप दोयम दर्जा पसंद करते हैं?
- क्या आप एक नेता चाहते हैं या एक प्रश्न चिह्न खड़ा करना चाहते हैं?
- क्या आप अँधेरे से भरे उन दिनों की वापसी चाहते हैं?

इन चुनावों में सिर्फ तीन मुद्दे हैं :

- विकास, विकास, विकास
- वाजपेयी, वाजपेयी, वाजपेयी
- भारत, भारत, भारत

हमारे लिए विकास एक निर्जीव आर्थिक आँकड़ा भर नहीं है। यह खाली जी.डी.पी. और बी.ओ.पी. जैसे शब्द नहीं हैं। यह अंततोगत्वा जीवन स्तर में सुधार से जुड़ा है। हम भाजपा के लोग एकात्म मानववाद के उस दर्शन के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो विकास को समग्र रूप से देख सकता है। हमारे लिए विकास कल्याण, करुणा और अच्छी नागरिकता के भाव से अलग कोई चीज नहीं है।

यह पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा है। इसमें एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया भी निहित है। इसका अर्थ भारतीयता को संबल प्रदान करना है, जिसे हम हिंदुत्व के नाम से भी जानते हैं।

पाँच दशक तक भारत कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों का शिकार रहा है। भारत को इन नीतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ी है।

कांग्रेस पार्टी की नीतियों ने हमेशा झगड़े एवं विवाद के बीज ही बोए हैं। उसने लोगों का ध्यान असली काम से हटाया है। उसने हमें पचास वर्षों तक पिछड़ा बनाए रखा। कांग्रेस का इतिहास निराशाजनक है।

- कांग्रेस ने पंचायत से लेकर संसद् तक—सभी संस्थाओं का अवमूल्यन किया।
- कांग्रेस ने भारत के संघीय ढाँचे के साथ समझौते किए। उसने केंद्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा किए। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कांग्रेस ने धारा 356 का दुरुपयोग किया।
- कांग्रेस ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया।
- कांग्रेस ने विकृत विकास को बढ़ावा दिया। विभिन्न क्षेत्रों की अनदेखी की।

शहरी और ग्रामीण इलाकों की खाई चौड़ी की। कांग्रेस का भारत को गरीब बनाए रखने में निहित स्वार्थ था।

- कांग्रेस ने भारत की रचनात्मक प्रवृत्ति को समाप्त कर डाला। उसने लाइसेंस और नियंत्रण की भ्रष्ट व्यवस्था को जन्म दिया। जनता को टैक्स के बोझ तले दबा दिया। उसने एक अजीबोगरीब समाजवाद की कल्पना की। कांग्रेस ने भारत को निम्न दर्जे के साथ जोड़ा।
- कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता की विकृत परिभाषा गढ़ी। अल्संख्यकों को कांग्रेस ने भय दिखाकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाया। कांग्रेस ने हिंदू शब्द को एक अपशब्द और उपहास का रूप दिया। कांग्रेस सामाजिक तनावों को बढ़ावा देती रही।
- कांग्रेस ने प्रजातंत्र को वंशवाद का रूप दिया। उसने भारत को एक परिवार के नाम लिख दिया।

आज की कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं है, जिसने कभी स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया था। आज की कांग्रेस लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजाजी और नेताजी सुभाषचंद्र बोस वाली कांग्रेस नहीं है।

आज की कांग्रेस पार्टी बिना किसी विचारधारा और दिशाहीन होकर बढ़ने वाली पार्टी रह गई है। इसमें भारतीयों के प्रति कोई मूल्य, कोई चरित्र और कोई विश्वास नहीं रह गया है।

राजग सरकार कांग्रेस द्वारा देश को पहुँचाई गई क्षति को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास करने में लगी हुई है। जहाँ कांग्रेस ने कई समस्याएँ खड़ी कर दी थीं, वहीं हमारी सरकार उन्हें सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है।

- हम आतंकवाद पर न केवल हावी रहे, बल्कि आतंकवाद की जड़ों से जूझे हैं। राजग के अंतर्गत कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए गए, जिसने आतंकवाद की जड़ें खोखली कर दी हैं। आज सचमुच एक आशा जगी है कि जम्मू और कश्मीर में फिर से शांति बहाल होगी। हम कश्मीरी पंडितों के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे वे अपने घरों को वापस लौटें।
- हमने कठोरता और न्यायपूर्ण ढंग के माध्यम से उत्तर-पूर्व में विद्रोहियों की समस्याओं से निपटना शुरू कर दिया है।
- प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद के खतरे को अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बना दिया है, उन्होंने अपनी राजनीतिज्ञ कुशलता से अपने पड़ोसी देशों को इस बात के लिए प्रभावित किया है कि परस्पर मित्रता ही एक मात्र सहारा है जिससे क्षेत्रीय समृद्धि लाई जा सकती है। इसलामाबाद में पिछले महीने पाकिस्तान ने पहली बार अपने क्षेत्र में किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों की अनुमति न देने पर सहमति जताई।
- राजग से अयोध्या विवाद पर शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए इसके समाधान

का प्रयास करते हुए सांप्रदायिक तनाव से निपटने की कोशिश की है। हमें आशा है कि जिस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, उनसे सार्थक समाधान निकालने में सफलता मिलेगी। हमें पूरा भरोसा है कि भारत का भविष्य इसी बात पर टिका है कि सभी समुदाय भारत माँ के प्रति समान रूप से स्नेह रखते हुए सद्भावनापूर्वक रहें।

मित्रो, आज जब हम 2004 के आम चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट है कि भाजपा ही एकमात्र भारतीय राजनीति में एक स्थिर ध्रुव है। हम एजेंडा निर्धारित कर रहे हैं, हमारे विरोधी नकारात्मक ढंग से काम कर रहे हैं।

भाजपा के लिए यह बड़ी संतोषजनक यात्रा रही है। ठीक 20 वर्ष पहले, लोकसभा में हमारे केवल दो ही सदस्य थे। 1996 से लेकर हम तीन चुनावों में लगातार देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर आए हैं

हमारा विस्तार संख्यात्मक, सामाजिक और भौगोलिक रूप में बढ़ता गया है। अंडमान से अरुणाचल तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भाजपा संपूर्ण भारत में एक बड़ी ताकत बनी है। 2003 में उत्तर-पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश में हम पहली बार सरकार में शामिल हुए। भाजपा नगालैंड सरकार में भी भागीदार बनी।

आज भाजपा के नेतृत्व में सात राज्यों में उसकी सरकारें है। इसके अलावा हम अन्य दो राज्यों में सरकारों में भागीदार हैं।

प्रवासी भारतीयों में हमारे 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' के मित्र हैं। अभी हाल में हमने सुदूर पार क्षेत्रों में पार्टी-दर-पार्टी संपर्क का कार्यक्रम भी शुरू किया है।

भाजपा निरंतर और धीरे-धीरे आगे बढ़ती चली गई है, जो हमारे समर्पित और हजारों कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम का प्रतिफल है। हमारे कार्यकर्ता हमारे राजदूत हैं, जो लोगों और पार्टी के बीच की जीवनरेखा हैं।

मात्र 24 वर्ष में ही, भाजपा ने भारत के जन-जीवन में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हम एक अलग किस्म की पार्टी के नाम से विख्यात हैं—

- हमारी एक विशिष्ट प्रकार की और राष्ट्रीय विचारधारा है।
- हमारा एक जाँचा, परखा और खरा नेतृत्व है।
- हमारे पास सक्षम, दूसरी पीढ़ी के नेता मौजूद हैं।
- लोगों की आँखों में हमारी विश्वसनीयता है।
- हम लोगों में स्वीकार्य है। भारत के लोगों ने धीरे-धीरे इस बात की पहचान कर ली है कि किस प्रकार हमारे विरोधी हमारे खिलाफ बदनामी और मिथ्या निरूपण करते हैं।

आनेवाले चुनाव हमारे लिए एक अवसर है 'जिससे सामाजिक और भौगोलिक' दोनों रूप में हमारे आधार का विस्तार हो सकेगा।

मैं एक बात पर बल देता हूँ कि भाजपा में भारतीय अल्पसंख्यकों के कुछ

वर्गों में प्रतिनिधित्व कुछ कम है। इसका कारण यही है कि ऐसे कुछ लोगों ने, जो अल्पसंख्यकों को मात्र अपना विशेष वोट बैंक समझते हैं, उनके बीच भय और आतंक का वातावरण फैला रखा है।

राजग सरकार के आचरण से भय की यह भावना समाप्त हो जानी चाहिए।

भाजपा 'सभी के लिए न्याय और किसी की संतुष्टि नहीं' की नीति पर चलने में विश्वास करती है। भाजपा सभी धर्मों के प्रति समानता बरतने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा सभी धर्मों के प्रति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सभी बकाया समस्याओं के लिए निरंतर बातचीत द्वारा समाधान करने में विश्वास रखती है।

अभी हाल में मैंने देखा है कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हमारे मुसलिम भाइयों के रवैए में हमारी सरकार और हमारी पार्टी के प्रति भारी बदलाव आया है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने शांति के लिए जो पहल की है और हमारी सरकार ने जिस तरह का सत्यनिष्ठा और दृढ़ता के साथ निपटा है, उससे अल्पसंख्यकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मैंने अल्पसंख्यकों से आह्वान किया था कि वे 'अपनी मानसिक दुविधा के अवरोधों से उबरें' और भाजपा को समर्थन दें। ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। अब यह हमारे कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनकी आशंकाओं को दूर कर, यदि कोई हों तो, अल्पसंख्यकों का समर्थन प्राप्त करें।

यही कारण है कि मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक पहुँचने में अपने प्रयासों को भी दुगुना कर दें। इससे पूर्व हमारे विरोधियों द्वारा फैलाए गए गलत प्रचार के कारण वे हमारी पार्टी से अलग रहे।

भाजपा वह पार्टी है जो भारतीयों की, भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के लिए है। हम कांग्रेस से एकदम अलग विचारधारा के लोग हैं।

- हम बढ़ते जा रहे हैं, वे सिकुड़ते जा रहे हैं।
- हमारे पास पक्का विश्वास है, वे आत्मसंशय से ग्रसित हैं।
- हम संगठित हैं, वे विभाजित हैं।
- हमारे नेतृत्व में कुशलता है, उनका नेतृत्व बोझ है।
- हमारी दृष्टि स्पष्ट है, उनकी दृष्टि अस्पष्ट है।
- हम दूर तक देख सकते हैं, वे मतिभ्रम में हैं।
- हम आगे देखते हैं, वे पीछे की ओर देखते हैं।
- हमारे सामने भविष्य है, वे अतीत में जीते हैं।
- हम विश्वास से गठबंधन बनाते हैं, वे बाध्य होकर उलझे रहते हैं।
- हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व है, वे अपने ही रिकॉर्ड को देखकर भागते फिरते हैं।

- हमारा नेतृत्व सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, उनके सामने इस बारे में बड़ा प्रश्न चिह्न लगा है।

आनेवाले चुनावों में भाजपा ने एजेंडा रखा है। हम अपने प्रधानमंत्री, सरकार में अपने प्रदर्शन और भारत को समृद्धशाली भविष्य की ओर ले जाने की अपनी योग्यता के बल पर फिर से नया जनादेश प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

हरेक चुनाव का एक प्रसंग होता है और यह चुनाव नेतृत्व और विकास के आधार पर होगा। दोनों ही मामलों में हमारा रिकॉर्ड हममें विश्वास भरता है।

पिछले पाँच वर्षों में जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, राजग उस पर खरी उतरी है। हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता हैं, जिन्होंने लोगों में विश्वास भरा है और जिन्होंने देश को संगठित किया है। प्रधानमंत्री हमारा एक प्रतीक है, भाजपा उनकी भुजा है।

आगामी चुनाव इसी के बारे में होगा। हम बिना बात के मुद्दे पर न जाएँ। कांग्रेस को मुख्य मुद्दों की तरफ से ध्यान बँटाने न दें।

कांग्रेस असफल रही है, उसके पास भारत की सफलता का कोई जवाब ही नहीं है। हमें उनकी विफलताओं को उजागर करना है, उन्हें इसी पर घेरना है।

हमें उनकी राज्य सरकारों के रिकार्डों के बारे में—कर्नाटक, महाराष्ट्र में तेलगी, केरल और पंजाब में अंतर्कलह तथा असम तथा उत्तरांचल में उनके कुशासन के बारे में—जरा याद करा दें।

कांग्रेस को इस बात की याद कराने से भी न चूँके कि बिहार में 'अंधी गुफा' के निर्माण में उन्हीं की भूमिका रही है।

कड़े प्रश्न पूछें, परंतु अपने अभियान को गरिमापूर्ण बनाए रखें।

हमें केवल लड़ाई ही नहीं जीतनी है, बल्कि अपनी राजनीतिक संस्कृति को भी बनाए रखना है। पूरे विश्व की आँखें भाजपा पर लगी हैं।

हम प्रगतिशील मंच पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के 'विजन डाक्यूमेंट' पर एक समिति कार्य कर रही है। अगले कुछ सप्ताहों में इसका विमोचन हो जाएगा।

भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने तथा धन-संपदा का निर्माण कर गरीबी से लड़ने पर हमारा विशेष बल रहेगा। भारत उदय की ओर बढ़ रहा है। हम इसकी आभा को और अधिक बढ़ाएँगे।

भाजपा के लिए यह चुनाव मील का पत्थर साबित होंगे। हमने मिशन 2004 के अंतर्गत भाजपा के लिए 300 सीट और सहयोगियों के साथ दो-तिहाई बहुमत का लक्ष्य रखा है। यह ऊँचा लक्ष्य लग सकता है। यदि हम पार्टी के अभियान को एक जन अभियान का स्वरूप दें तो यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

चुनाव अभियान में उन लोगों को शामिल करें जो परंपरागत रूप से राजनीति से बाहर रहते हैं। युवाओं को लाएँ, महिलाओं को बुलाएँ, अल्पसंख्यकों को लाएँ,

किसानों और दलितों को भी लाएँ। प्रत्येक उस भारतीय को साथ लाएँ जो भारतीय होने में गर्व की अनुभूति करता है। वह प्रत्येक भारतीय जिसे एक सुखद एहसास की अनुभूति हो रही है, उसे वाजपेयीजी का सिपाही बनने का अवसर दें, ताकि वह और बेहतर महसूस कर सके।

जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं हमें अपनी पार्टी के ढाँचे को पूरी तरह चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए।

प्रधानमंत्रीजी और उप-प्रधानमंत्री के लगातार ध्यान देते रहने के कारण पार्टी और सरकार के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। पार्टी कैडर और नेतृत्व के बीच में निरंतर संवाद की प्रक्रिया बनी हुई है।

पार्टी एवं राष्ट्रवादी परिवार के सहोदर संगठनों के बीच सौहार्द बना हुआ है।

हमारे सामने राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना है। मैं पार्टी की सभी स्तरों पर गठित इकाइयों का आह्वान करता हूँ कि कार्य विभाजन और व्यक्तियों को दायित्व सौंपने के काम तेजी से पूरे कर लिये जाएँ। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वर्तमान में चल रहे 'अटल संदेश अभियान' की सफलता सुनिश्चित करना, जिसका नारा है— 'हर गाँव पहुँचें, हर गली में जाएँ, हर दरवाजे पर दस्तक दें और हर वोटर से मिलें।'

अटल संदेश अभियान के अंतर्गत हमने देश के विभिन्न हिस्सों में सौ रैलियाँ आयोजित करने की योजना बनाई है। मैं इन सभी रैलियों की भारी सफलता सुनिश्चित करने का आपसे आह्वान करता हूँ। इन रैलियों के साथ बुद्धिजीवियों, पेशेवर लोगों के सम्मेलन भी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में आयोजित किए जाएँगे। साथ-ही-साथ मैं यह भी चाहूँगा कि आप 'चुनाव सहायता निधि अभियान' को भी पूरी गंभीरता से लेकर स्रोतों की अभिवृद्धि का प्रयास करें।

सफलता के लिए हमें टीम भावना बरकरार रखनी होगी। हम जब कभी भी युद्ध में एकजुट होकर एक टीम की भाँति उतरे हैं, हमें सफलता हाथ अवश्य लगी है।

हम युद्ध का पहला चरण पहले ही जीत चुके हैं। आइए, हम अपने कार्य को अब अंतिम अंजाम दें।

वंदेमातरम्!

भारत माता की जय!!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

मुंबई 22-24 जून, 2004

प्रिय बंधुओ,

मुंबई में हो रही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस महत्त्वपूर्ण बैठक में आप सभी का स्वागत है। चौदहवीं लोकसभा के चुनावों के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। जनादेश हमारी अपेक्षाओं के विपरीत तो रहा ही, साथ ही सत्ता में बैठे लोगों सहित सभी की अपेक्षाओं के विपरीत रहा।

स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी को सभी स्तरों पर आत्मचिंतन करना है कि आखिर क्यों हम जनादेश को फिर से पाने में सफल नहीं हो सके? हमारे पास सर्वोत्तम नेतृत्व है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुयोग्य नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का कार्य निष्पादन (परफोरमेंस) बहुत अच्छा रहा। छह वर्ष के शासन में सरकार ने देश को आगे बढ़ाने का उल्लेखनीय कार्य किया। सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और विकास कार्यों हेतु की गई पहलें इतिहास में मील का पत्थर बन गई हैं। फिर भी चुनावी नतीजे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम पराजय के कारणों का गहराई और वस्तुनिष्ठता से विश्लेषण करें तथा उन कारणों को चिह्नित करें जिनके फलस्वरूप हमें धक्का लगा है।

दो दिन पूर्व नई दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक छोटी समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। कार्यकारिणी की बैठक के अंत में मैं इस समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा करूँगा।

आत्मचिंतन के तीन सिद्धांत

मैं यह बताना जरूरी समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आत्मचिंतन और विश्लेषण की एक अलग विशिष्ट संस्कृति है, जिसे पार्टी के प्रत्येक

पदाधिकारी को समझना चाहिए। इसके लिए तीन मार्गदर्शक सिद्धांतों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ—

1. आत्मचिंतन और विश्लेषण के प्रति हमारी दृष्टि सकारात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, विश्लेषण का उद्‌देश्य सिर्फ यह जानना नहीं हो सकता कि क्या गलती हुई बल्कि इसका मुख्य उद्‌देश्य होना चाहिए कि हम अपनी कमियों पर कैसे विजय पा सकते हैं और पहले से ज्यादा विश्वास तथा दृढ़ता से कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
2. हमारी पार्टी आरोप-प्रत्यारोप और एक-दूसरे पर अँगुली उठाने में विश्वास नहीं रखती। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अधिकांश अन्य दलों की तुलना में भाजपा व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है। हम सामूहिक दायित्व के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं—हार और जीत दोनों में ही।
3. सामूहिक दायित्व में किसी व्यक्ति विशेष के उत्तरदायित्व को चिह्नित करने की जरूरत नहीं रहती। हममें से प्रत्येक अपने स्तर पर अपने निर्णयों और कार्यों को परखे और चुनावों के कुल मिलाकर आए नतीजों में अपने योगदान को तोलें।

पार्टी के अध्यक्ष के नाते न केवल अपने व्यक्तिगत कदमों अपितु समूची पार्टी के चुनावों में प्रदर्शन की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपने नेताओं और साथ ही पार्टी के सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से अपना विश्वास मुझमें जताया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दुगुनी शक्ति से काम करूँगा और मेरे कंधों पर डाली गई इस जिम्मेदारी को पूरा करने का अथक प्रयास करूँगा।

हवा न राजग विरोधी, न कांग्रेस समर्थक

मित्रो, आइए, हम नतीजों का विश्लेषण करें।

क्या देश में राजग-विरोधी लहर थी? नहीं। पूरे देश में सामान्यतया वाजपेयी समर्थक लहर और भाजपा के पक्ष में माहौल था।

क्या कांग्रेस-समर्थन हवा थी? नहीं। यह इस बात से साफ हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की तुलना में मात्र सात सीटें ज्यादा ले सकने में सफल रही। केरल में उसका खाता ही नहीं खुला। कर्नाटक में मात्र आठ सीटों पर सिमट गई। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे मजबूत गठबंधन के बावजूद कांग्रेस भाजपा-शिवसेना गठबंधन से पीछे रह गई और पहले की सीटों को ही बचा पाई। पंजाब और उत्तरांचल में केवल एक-एक सीट जीत सकी। जिन राज्यों का मैंने यहाँ उल्लेख किया वह सभी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं।

भाजपा शासित प्रदेशों—राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पहले की तुलना में और खराब हुई। उड़ीसा में भी वह कोई सफलता नहीं

पा सकी। उत्तर–पूर्व में उसकी स्थिति निराशाजनक रही। सत्ता में रहने के बावजूद यह असम में अपनी स्थिति सुधार नहीं पाई। यहाँ तक कि गुजरात में जहाँ भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हम कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीते हैं, यद्यपि यह हमारी अपेक्षाओं से कम है।

इसलिए कांग्रेस का यह दावा पूरी तरह से बेमानी है कि जनादेश उसके पक्ष में है।

यह कहा गया कि ग्रामीण जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाराज थी और उन्होंने राजग को वोट नहीं दिया। यह सही नहीं है। नतीजे दरशाते हैं कि भाजपा द्वारा जीती गई अधिकांश सीटें ग्रामीण अंचलों से हैं।

यह भी दावा किया गया कि गरीब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से खुश नहीं थे और इसलिए उन्होंने हमें वोट नहीं दिए। यह भी सत्य नहीं है। तथ्य यह है कि जहाँ हम विजयी हुए हैं, उनमें बहुत से निर्वाचन क्षेत्र गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरी कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं।

जब हम चुनावों में हार के कारणों का परीक्षण करते हैं तो ध्यान में आता है कि शायद हम परिस्थितियों के आकलन में अति–आत्मविश्वास से भरे थे। कई स्थानों पर इस अति–आत्मविश्वास ने आत्ममुग्धता पैदा की। हमारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लगा कि हम आसानी से जीत जाएँगे। भाजपा और राजग की सरकार हर हाल में बनेगी।

अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ताओं और परंपरागत मतदाताओं में आई आत्ममुग्धता से हुए नुकसान को स्थानीय परिस्थितियों ने और बढ़ा दिया। अपने सांसदों को फिर से प्रत्याशी बनाते समय हमने इस तथ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि तेरहवीं लोकसभा के अनेक सांसदों के विरुद्ध 'एंटी–इनकंबेंसी' काम कर रही है। यह हमें काफी महँगा पड़ा। हमारे लगभग पचास प्रतिशत सांसद फिर से चुने कर आने में असफल रहे। यह गंभीर चिंता का विषय है जिस पर गहन अध्ययन कर सुधारने के कदम उठाने होंगे।

हाल के चुनावों के नतीजे दरशाते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्पष्ट या एक समान पैटर्न नहीं था। मतदाताओं की पसंद राज्य–दर–राज्य बदलती रही और इतनी बदली कि ऐसा लगता है कि स्थानीय कारणों से प्रभावित राज्यों के जनादेश लोकसभा के अंतिम परिणामों पर हावी रहे।

मेरे द्वारा बताए गए इन कारणों के अलावा कुछ प्रदेशों में स्थानीय समीकरणों के चलते भी हमें नुकसान उठाना पड़ा। यह बात मैं अपने सहयोगी दलों पर आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा बल्कि तथ्य बता रहा हूँ। हमें इसका कोई मलाल नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को और अधिक मजबूत

करने तथा सहयोगी दलों से संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के पक्ष में है। यह सही है कि चुनावों से पूर्व कुछ घटक दल राजग छोड़कर गए। प्रत्येक मामले में इन दलों ने स्वयं छोड़ने का निर्णय किया। हमने अपने किसी सहयोगी को नहीं छोड़ा।

हाँ, हमें अपनी कमजोरियों को ढूँढ़कर सुधारना है। हमें अतीत से सबक सीखकर आगे की ओर बढ़ना है।

कांग्रेस पार्टी द्वारा जनादेश की स्वयं-भू व्याख्या

मित्रो, इन अप्रत्याशित चुनावी नतीजों के बाद हमारे विरोधी विशेष रूप से कांग्रेस और कम्युनिस्ट इस जनादेश को गलत ढंग से प्रचारित करने में जुटे हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसे जनादेश मिला है। मगर सांसदों की संख्या इस दावे को झुठलाती है। कांग्रेस सिर्फ 145 सीटें जीती है। कांग्रेस और उसके चुनाव पूर्व सहयोगी सिर्फ 218 सीटें जीते, जो सरकार बनाने के न्यूनतम 272 के आँकड़े से काफी कम है।

हालाँकि यह भी सत्य है कि उन्होंने जोड़-तोड़ कर सरकार बनाने हेतु आवश्यक बहुमत जुटा लिया। सत्तारूढ़ दल अपने को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) कहता है। परंतु यह संयुक्त लगने के बजाय प्रारंभ से ही बिखरा हुआ लगता है। प्रगतिशील होने के बजाय इसके अंतर्विरोध और समझौते देश को प्रतिगामी दिशा में ले जाएँगे। गठबंधन के बजाय यह सत्ता भोगने के लिए किया गया अवसरवादी समझौता ज्यादा लगता है।

मैं इसपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता कि यह सरकार कैसे बनी और पिछले एक महीने से कैसी भूलें कर रही है। क्योंकि इसपर कार्यकारिणी में रखे जाने वाले राजनीतिक प्रस्ताव में विस्तार से बताया जाएगा।

प्रतिस्पर्धात्मक छद्म-सेक्युलरवाद के खतरनाक आयाम

इस संदर्भ में सरकार में शामिल अथवा उससे जुड़े हुए दलों और लोगों की मानसिकता से चिंतित होना स्वाभाविक है। यह छद्म-सेक्युलरवाद की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृति है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सीमा पार के आतंकवाद का उल्लेख तक नहीं है, जैसे मानो यह समस्या समाप्त हो चुकी है।

नई सरकार के गठन के एक सप्ताह के भीतर ही कश्मीर में आतंकवादी हमले में सीमा सुरक्षा बल के 33 जवान और उनके परिवार वाले मारे गए। कुछ दिन पूर्व ही सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तोएबा द्वारा श्री नरेंद्र मोदी की हत्या के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। दो पाकिस्तानी नागरिकों सहित चार व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। दुःख की बात यह है कि कुछ छद्म-सेक्युलर दल और संगठन इसे भी अपने भाजपा विरोधी अभियान में उपयोग कर रहे हैं तथा इसे हिंदू

बनाम मुसलिम मुद्दा बनाने में लगे हैं। वे इसे मानवाधिकार के उल्लघंन का मामला बता रहे हैं, परंतु ऐसा करते समय वे यह भूल जाते हैं कि मानवाधिकार निर्दोष नागरिकों की रक्षा के लिए होते हैं। इनका दुरुपयोग आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधियों को बचाने में नहीं किया जा सकता। इन्हीं लोगों ने कहा था कि अक्षरधाम पर हुआ हमला 'स्टेज मैनेज' था! ये दल आतंकवादियों के बचाव में बंद आयोजित करने में अगुआ की भूमिका निभा रहे थे।

भारतीय जनता पार्टी इन छद्म-सेक्युलर दलों को चेताना चाहती है कि वे अपने तात्कालिक लाभों के लिए राष्ट्रविरोधी और आतंकवादी शक्तियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं तथा बढ़ावा दे रहे हैं। यह वही मानसिकता है जो नई सरकार को आतंकवाद के सतत खतरे की उपेक्षा कर 'पोटा कानून' को समाप्त करने का वायदा करने पर बाध्य कर रही है। यह अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और यहाँ तक कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रही है।

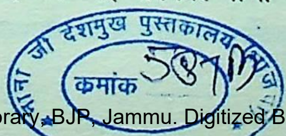
एक राष्ट्रवादी दल होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्रतियोगी छद्म-सेक्युलरवाद के परिणामों के बारे में सबको शिक्षित करें और इसके विरुद्ध जनमत तैयार करें। हम सबको झकझोर देनेवाले इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ेगी।

एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका का निर्वाह

मित्रो, हम रचनात्मक और जिम्मेदारी की भावना के साथ एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभायँगे। हमारे पास विपक्ष में बैठने का धैर्य है। हम नई सरकार के अंतर्विरोधों, बाध्यताओं, समझौतों और उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। मनमोहन सिंह सरकार में दागी मंत्रियों के विरुद्ध हमारा अभियान अभी शुरुआत है। हम शीघ्र ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के 'डिसेफराइनेज़शन' के नाम पर भारत के इतिहास से छेड़छाड़ करने के प्रयासों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे।

जहाँ राष्ट्रीय हित और लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दे होंगे वहाँ हम सरकार को पूरा समर्थन देंगे। लेकिन इसके लिए सरकार को आगे आकर हमारा समर्थन लेना होगा। यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह दिखाए कि महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने की उस परंपरा को आगे बढ़ा रही जिसकी पहल वाजपेयी सरकार ने की थी।

और जैसाकि श्री आडवाणीजी ने बताया कि इस विखंडित जनादेश, जिसमें किसी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, का सही अर्थ है कि भारत के लोग चाहते हैं कि नई सरकार सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष का सहयोग प्राप्त करे।



हालाँकि अब यह साफ हो गया है कि नई सरकार मतदाताओं द्वारा दिए गए इस संदेश का पालन करने के मूड में नहीं है। यह बदले की भावना से काम करने वाली सरकार है, जो वाजपेयी सरकार की अच्छी विरासत को जितना कर सकती है उतना समाप्त करने में लगी है। यह वाजपेयी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कदमों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर बदनाम करने की हद तक जाएगी। इसलिए हमारी पार्टी को संसद् के भीतर और बाहर ज्यादा सतर्क रहना होगा। हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों का हम जोरदार ढंग से बचाव करें। वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किए गए अच्छे कामों को पूरा करवाने के लिए हमें सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा।

यहाँ यह विशेष उल्लेख करने योग्य है कि वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई अति महत्त्वपूर्ण विकासात्मक पहलों, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वजलधारा, अंत्योदय अन्न योजना और सर्वशिक्षा अभियान का न तो नई सरकार के समान न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लेख है और न ही संसद् के संयुक्त सत्र में दिए गए राष्ट्रपति अभिभाषण में।

पार्टी की नई पहल : विषयवार समितियों का गठन

संसद् में हमारी पार्टी अनुभवी और युवाओं, सिद्ध क्षमता और संभावनाओं से भरी नई प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे बहुत से सदस्य सरकार और विपक्ष में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। हमें सौभाग्य से लोकसभा में श्री अटलजी और आडवाणीजी का नेतृत्व प्राप्त है। राज्यसभा में हमारे पास श्री जसवंत सिंहजी जैसा नेतृत्व है। इसलिए हम अपने संसदीय दल पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का भरोसा रख सकते हैं।

इस संदर्भ में हमने पार्टी संगठन के भीतर एक नई व्यवस्थात्मक श्रेणी बनाने का फैसला किया है, जिसमें हमारे सहयोगियों के सरकार और संसदीय कार्य के सघन अनुभवों का लाभ उठाया जा सकेगा। यह संसद् की स्थायी समितियों के पैटर्न पर विषय विशेष से संबंधित समितियाँ होंगी। जिनमें हमारे सांसदों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों और पार्टी से बाहर के संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इससे संसद् के भीतर और बाहर पार्टी के हमारे काम को नए आयाम मिलेंगे।

आसन्न विधानसभायी चुनावों हेतु तैयारी

प्यारे साथियो, बहुत से महत्त्वपूर्ण काम हमारे सामने हैं। 'भावी कार्यक्रम' (Task Ahead) संबंधी एक विशेष वर्किंग पेपर का प्रारूप कार्यकारिणी की बैठक में विचार-विमर्श हेतु रखा जाएगा। मुंबई के बाद भी यह चर्चा जारी रहेगी। जुलाई महीने में एक 'चिंतन बैठक' बुलाने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य इसपर

विचार करना है कि कैसे पार्टी का सामाजिक और राजनीतिक आधार बढ़ाकर जनता का विश्वास फिर से जीता जा सकता है। इस हेतु आपके और विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के सुझाव उपयुक्त रहेंगे।

हमारा तात्कालिक काम महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभायी चुनावों की तैयारी करना है, जहाँ आनेवाले कुछ महीनों में नई विधानसभाओं का गठन होना है। इस सूची में मैं उत्तर प्रदेश को भी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ देखते हुए लगता है कि समय से पूर्व चुनाव हो जाएँगे। यह सभी विधानसभायी चुनाव हमारे लिए बहुत महत्त्व के हैं।

हमारी यह बैठक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हो रही है। मैं चाहूँगा कि आप सभी अपनी महाराष्ट्र इकाई को बधाई दें कि लोकसभा के चुनावों में अनेक भविष्यवाणियों को झुठलाकर उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की। यहाँ पर उपस्थित हम सभी यह आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समय की कसौटी पर खरी उतरी उसकी सहयोगी शिव सेना मिलकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अपवित्र गठबंधन को सत्ता से बाहर करने में सफल होगी। वर्तमान प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता और आंतरिक गुटबाजी का पर्याय बन गई है। महाराष्ट्र की जनता परिवर्तन के मूड में है।

बिहार की जनता भी राष्ट्रीय जनता दल-कांग्रेस-कम्युनिस्ट गठबंधन के जंगलराज से मुक्ति की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही है। हमारी बिहार इकाई के साथियों को ताजा लोकसभा के चुनावों से सही सबक लेकर वहाँ के कुशासन को समाप्त करने की प्रभावी रणनीति बनानी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वह झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में फिर से जनादेश प्राप्त करे। यहाँ मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि हरियाणा में भी अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर हमारे सामने है।

हिंदुत्व के बारे में क्षमाप्रार्थी होने का कोई सवाल नहीं

मित्रो, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी हमारी तात्कालिक प्राथमिकता है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें पार्टी के सम्मुख उपस्थित अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान देना है।

समूचे पार्टी संगठन के सम्मुख सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काम अपनी विचारधारा और आदर्शवाद के प्रति फिर से कटिबद्ध होने का है। हमें ऊपर से नीचे तक यह विश्वास जगाना होगा कि हम एक साधारण राजनीतिक दल नहीं, अपितु एक मिशन लेकर चलने वाली पार्टी हैं। हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित एक वृहद् आंदोलन का हम एक हिस्सा हैं।

यह मिशन क्या है। और यह आंदोलन क्या है—इस बारे में हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी अवश्य ही परिचित होने चाहिए, और यह हमारी सोच, व्यवहार

और संप्रेषण में अवश्य ही अभिव्यक्त होना चाहिए।

एक बार फिर से मीडिया के एक वर्ग में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा हिंदुत्व की ओर वापस जा रही है। हिंदुत्व की ओर वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसे हमने कभी छोड़ा ही नहीं था और न कभी छोड़ेंगे।

हमारे लिए हिंदुत्व एक चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दे सामान्यतया एक चुनाव से दूसरे में बदलते रहते हैं। मगर हिंदुत्व जो कि एक जीवन पद्धति है, के साथ ऐसा नहीं है। यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिंदुत्व को भारत की मूलभूत पहचान बताया है।

भारतीय जनता पार्टी सदैव मानती है कि हिंदुत्व भारतीयता और इंडियनेस समानार्थी है। यह सब एक तथा समान है। इसलिए जहाँ तक भाजपा का संबंध है हिंदुत्व को लेकर उसके क्षमाप्रार्थी होने का कोई सवाल नहीं है, बल्कि हमें अपनी सभ्यता, दर्शन और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है।

मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि भारतीय समाज के अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों तक पहुँचने के लिए हमारे प्रयासों को छोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमने अपने राजनीतिक काम में अल्पसंख्यकों को कभी अलग नहीं माना। अल्पसंख्यक हमारे राष्ट्र का अविभाज्य अंग हैं। इस संबंध में हमारा उद्देश्य रहा है और रहेगा—'सभी को न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं'।

हमारी पार्टी उन सभी राष्ट्रवादी संगठनों, जो राष्ट्र-निर्माण के काम में लगे हैं, से अच्छे संबंध बनाएगी।

विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता कायम

मित्रो, मीडिया और राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ इस तरह की चर्चा चल रही है कि चुनावों में मिली असफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस विकास को चुनाव प्रचार अभियान का महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाया था, अब उसे छोड़ देगी। मैं यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। भाजपा की दोहरी प्रतिबद्धता है— सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास। वास्तव में यह एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। देश के सर्वांगीण और तेजी से विकास के बिना हम पुनर्जाग्रत् भारत का सपना साकार नहीं कर सकते, जो अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को न केवल फिर से पा सकता है अपितु उससे भी आगे निकल सकता है। हम आज भी यह मानते हैं कि भारत में वह संभावना है, और वह सभी आवश्यक संसाधन हैं जिनसे थोड़े ही समय में वह एक मजबूत आर्थिक शक्ति और विकसित राष्ट्र बन सकता है।

वाजपेयी सरकार द्वारा आधारभूत ढाँचे और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में विकास के लिए उठाए गए कदमों पर हमें गर्व है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और कार्यक्रम लगातार—गरीबी उन्मूलन की अत्यावश्यकता, सभी के लिए

रोजगार के अवसर, क्षेत्रीय विषमताओं को पाटना, 'पुरा' (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान) जैसे नवीन दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण-शहरी खाई को समाप्त करने, शहरों की स्लम बस्तियों की दशा सुधारने के लिए शहरी सुधार, महिलाओं का सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर तबकों के त्वरित विकास को प्रमुख रूप से उभारते रहेंगे। हमारा यह सुनिश्चित विश्वास है कि इससे समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए और राष्ट्र के एकात्म विकास में साझेदारी की भावना होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता अपनी राजनीतिक और व्यावहारिक गतिविधियों में इन मुद्दों को सर्वाधिक महत्त्व दें।

किसानों और ग्रामीण निर्धनों में भाजपा के काम का विस्तार

मित्रो, समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी गतिविधियाँ बढ़ाकर और उसे विस्तार देकर तथा समाज के जिन वर्गों में अभी भी हमारा कम आधार है, उनसे जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाकर हमें उनका विश्वास हासिल करना है।

इस परिप्रेक्ष्य में, मैं विशेष रूप से किसानों, खेतिहर मजदूरों, हस्तशिल्प कारीगरों, ग्रामीण गरीबों के अन्य वर्गों तथा शहरी क्षेत्र में असंगठित गरीबों में पार्टी के काम के विस्तार की आवश्यकता का उल्लेख करना चाहता हूँ। अब तक के अपने अनुभव के आधार पर हमने देखा है कि जब भी कभी हमने ठोस ढंग से किसानों के मुद्दे उठाए हैं, जहाँ कहीं भी पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी इकाइयाँ स्थापित की हैं और जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी अधिकारियों का नियमित जाना होता है—वहाँ के ग्रामीण लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खुले दिल से समर्थन दिया है।

इस संदर्भ में हमारे किसान मोरचा की प्रमुख जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी अकेले किसान मोरचा के पदाधिकारियों की ही नहीं है, समूचे पार्टी संगठन को अपने ग्रामीण और किसान फोकस को विस्तार देना होगा। हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं को किसानों की भाषा बोलनी चाहिए, उनकी समस्याओं और चिंताओं को प्रभावी ढंग से मुखरित करना चाहिए तथा किसान समुदाय के साथ भावात्मक संबंध स्थापित करने चाहिए।

संगठन-निर्माण : अपने मूल की ओर लौटें

प्यारे सहयोगियो, पार्टी संगठन के विस्तार और उसे ऊर्जा संपन्न बनाने के संबंध में मैं कुछ विचार आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी पार्टी के संगठनात्मक दर्शन को हम इस एक साधारण वाक्य में समेट सकते हैं—'अपने मूल की ओर लौटें' (Back to the Basics).

सबसे पहले हमें भारतीय जनसंघ के दिनों और भारतीय जनता पार्टी के

प्रारंभिक वर्षों की भाँति हमारे पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं को अपने समय का मुख्य हिस्सा पार्टी के काम हेतु अपने क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करने और लोक संग्रह के कार्यक्रमों की सुनिश्चित योजना बनाने तथा क्रियान्वित करने में लगाना चाहिए। सभी क्षेत्रों में उन्हें अपने काम के सर्वोच्च मानदंड स्थापित करने चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण है कि हममें से प्रत्येक अपने आदर्शवाद और विचारधारा से लोगों को प्रेरित करने हेतु सक्षम बन सकें।

एकदम स्थानीय स्तर से ऊपर तक हमें नियमित बैठकों, व्यवस्थित योजना, जिम्मेदारियों और काम का बँटवारा, सामूहिक समीक्षा और स्थिति का जायजा, आवश्यक सुधार जैसे काम करने के पहले के तरीकों को अपनाना होगा, ताकि भविष्य के कामों के करने के लिए हम आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार श्री अटलजी, श्री आडवाणीजी, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे और हमारे पुराने नेता काम करते थे।

इस संदर्भ में हमें फिर से अपने मूल की ओर लौटना है। व्यक्तिवाद की बीमारी से मुक्ति पानी है। हममें से प्रत्येक को यह अहसास होना जरूरी है कि आज जो हम हैं वह पार्टी के कारण हैं। हमें अपनी निजी चेतना, निजी व्यक्तित्व और निजी पहचान पार्टी की चेतना, पार्टी के व्यक्तित्व और पहचान में समाहित करनी है।

इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्र पहले, पार्टी उसके बाद और स्वयं सबसे अंत में।

जैसा मैंने उल्लेख किया कि पार्टी को फिर से ऊर्जावान बनाने की रणनीति के तहत हमें लोगों की समस्याओं और उनके मुद्दों को मुखरित करना चाहिए। इस संदर्भ में भी अपने मूल की ओर लौटना हमारे लिए प्रासंगिक रहेगा। कभी–कभी मुझे लगता है कि हमारी पार्टी भी चुनाव केंद्रित पार्टी बन गई है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे कार्यकर्ता अधिकतर तभी सक्रिय होते हैं जब चुनाव हो रहे हों, अन्य समय में कई पार्टी इकाइयों में ज्यादा गतिविधियाँ नहीं होतीं। यह एक जीवंत और प्रगतिशील राजनीतिक संगठन के लक्षण नहीं हैं।

हमें सभी स्तरों पर संगठन के कामकाज में सुधार लाना है। ऊपर से हमें पहल कर पार्टी की निचली इकाई के सामने आदर्श प्रस्तुत करना है। इसके लिए हमारा सबसे पहला काम हमारे कार्यकर्ताओं से लगातार जीवंत संपर्क रखना है।

दीनदयालजी से सीखें

एक आदर्श राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता वही है जो सप्ताह के सातों दिनो, चौबीस घंटे, साल के तीन सौ पैंसठ दिनों के चौबीसों घंटे पार्टी के बारे में सोचता है और काम करता है—आराम, न्यूनतम निजी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 'आदर्श कार्यकर्ता'

के बारे में कहा करते थे—'सबसे भाग्यशाली वह है जो सतत कार्यरत है।'

कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि हमारे समय और ऊर्जा के लिए सदैव इतना काम कहाँ है! ऐसे लोगों को और अपने को स्मरण करना होगा कि भले ही कोई छोटा काम हो, परंतु उसी से ही बड़े और छोटे संगठन बनते हैं। उदाहरण के लिए, मतदाता पर्ची बनाना, मतदाता सूची का सत्यापन, वितरण और प्रत्येक मतदाता के घर पर संपर्क करना ऐसा ही काम है। यह भले ही छोटा सा और जटिल काम है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसकी उपेक्षा की कीमत हमने हाल ही के लोकसभा चुनावों में चुकाई है।

हम जबावदेही की नई पद्धति शुरू करेंगे

मित्रो, अब आकर यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, जिसमें बहुत से लोग पार्टी के पदाधिकारी या राष्ट्रीय अथवा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य या फिर कुछ और पद चाहते हैं। लेकिन आखिर कितने लोगों को इसमें समायोजित किया जा सकता है? साथ ही संगठन निर्माण में 'एकोमोडेट' करने का सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए यह हमारे लिए महत्त्वपूर्ण है कि हम एक बार फिर से पार्टी में ऐसी संस्कृति का सृजन करें कि जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उसे निभाए और उस जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करे।

इस संबंध में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि हम शीघ्र ही जबावदेही की पद्धति बनाएँगे। जिससे सौंपा गया कार्य हम ढंग से कर सकें और पार्टी के काम को आगे बढ़ा सकें।

जिस तरह हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है उसी तरह हमारे नेताओं और पदाधिकारियों को अंतिम कार्यकर्ता तक पहुँचना चाहिए। संगठन के निचले स्तर से मिली अधिकांश शिकायतों में से एक है हमारे नेताओं और कैडर के बीच अपर्याप्त और अनियमित संवाद। हमारा कैडर उत्साही और समर्पित है। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि इनके बीच निरंतर संवाद के साथ ही प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन की व्यवस्था से हम अनेक युवा, सक्षम और संभावनाओं से भरे युवा कार्यकर्ता पा सकेंगे, जो भविष्य के हमारे नेता होंगे।

युवा नेताओं को विकसित करने की जरूरत

मित्रो, पूरे देश में पार्टी के भीतर युवा नेताओं की एक नई श्रृंखला विकसित करने की जरूरत पर मुझे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है—35 वर्ष से नीचे वालों का। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी अपने युवा और सक्षम

नेताओं पर नाज करती थी। इनमें से अधिकांश विद्यार्थी आंदोलनों या सत्तर के दशक में आपात स्थिति के विरुद्ध संघर्ष में से निकले थे। हमें एक बार फिर से योजना बनाकर सुनियोजित ढंग से समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाले युवा कार्यकर्ताओं को पहचानने और विकसित करने की योजना बनानी है, जोकि पार्टी के भविष्य के नेता के रूप में उभर सकें।

हमें अपने कार्यकर्ताओं के लिए पाक्षिक अथवा मासिक ओरिएंटेशन क्लास लगनी चाहिए जिनमें इन्हें प्रेरित करने, शैक्षणिक और कुशल विकास प्रशिक्षण की गतिविधियों से परिचित कराया जाए। इस उद्देश्य से हमने अपने पार्टी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को अन्य छह मोरचों की भाँति पूर्णरूपेण विभाग बनाने का तय किया है।

मैंने प्रो. बाल आप्टे को इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव दो महीने में बनाकर देने को कहा है। मैं चाहूँगा कि समयानुसार इस गतिविधि के लिए पार्टी स्कूल के रूप में कोई संस्थागत ढाँचा विकसित हो। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि पार्टी ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की स्मृति में भोपाल में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का फैसला किया है। मुंबई में रामभाऊ म्याहलगी प्रबोधिनी पहले से ही है।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण को मजबूत कर जातिवाद और संकीर्णता से लड़ें

प्रिय बंधुओ, एक सामाजिक-राजनीतिक प्रवृत्ति, जो मुझे इन दिनों ज्यादा चिंतित कर रही है, की ओर ध्यान दिलाकर मैं अपनी प्रारंभिक टिप्पणी समाप्त करूँगा। यह प्रवृत्ति हाल ही के लोकसभा के चुनावों में भी उभरकर आई। मैं जातीय और संकीर्ण भावनाओं के उभार की ओर इशारा कर रहा हूँ, जिसकी भारतीय राजनीति में अपील दिनोदिन बढ़ती दिख रही है। हमारी पार्टी औरों की तुलना में इस प्रवृत्ति से ज्यादा प्रभावित नहीं है। फिर भी यह देखकर दुःख होता है कि हमारी पार्टी में विभिन्न स्तरों पर इस प्रवृत्ति की शुरुआत देखने को मिल रही है।

मैं मानता हूँ कि यह एक जटिल प्रवृत्ति है। हमें विभिन्न सामाजिक समूहों, विशेष रूप से वंचित रह गए वर्गों की वास्तविक आकांक्षाओं को स्वर देते हुए एक समुचित संतुलन बनाना होगा। यद्यपि भाजपा इस दृढ़ मत की है कि जाति आधारित राजनीति न तो लोकतंत्र के लिए अच्छी है और न हीं यह राष्ट्रीय हित में। हमने देखा है कि कैसे जाति आधारित दल और संकीर्णता की ताकतें अपने वर्गीय आधार (सेक्शनल कॉन्स्टीटूएंसी) की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में असफल रही हैं। इसके बजाय उसका उपयोग निजी नेताओं के प्रोत्साहन, उनके परिवार और निहित स्वार्थ वालों के लिए किया गया।

जैसाकि मैंने कहा यह एक जटिल मुद्दा है। इसका समुचित अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमारा रुख राष्ट्रीय एकता और सामाजिक

सद्भाव की हमारी प्राथमिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। एक राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण भाजपा पर यह जिम्मेदारी आई है कि वह समाज और राजनीति में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को मजबूत करे तथा जातीय, सांप्रदायिक और संकीर्णता की ताकतों से लड़े। हमें देश की राजनीति को वृहद राष्ट्रीय और सामाजिक कल्याण से फिर से जोड़ना होगा ओर हमारे ऋषियों और संतों द्वारा बताए गए रास्ते—'सर्व जनः सुख़िनो भवन्तु' तथा 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'—की ओर ले जाएँ।

मित्रो और सहयोगियो, विधानसभायी चुनावों के अगले चरण की पृष्ठभूमि में हम मुंबई में मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग का सद्भावना और समर्थन प्राप्त है। आनेवाले महीनों में हम इसी सद्भावना और समर्थन के आधार पर अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करेंगे।

मैं चाहूँगा कि मुंबई बैठक से पूरे देश में यह संदेश जाए और हमारे विरोधी इसे ज्यादा जोर से सुन लें कि हम जनता का विश्वास पुनः हासिल कर फिर से वापस आएँगे (We will come back)। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी दृढ़ इरादे के साथ हम मुंबई आए हैं और इसी दृढ़ इरादे के साथ तीन दिनों तक सार्थक विचार-विमर्श करके मुंबई से वापस जाएँगे।

धन्यवाद,

वंदेमातरम् !



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

इंदौर 4-5 अप्रैल, 2003

मित्रो,

आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जहाँ एक तरफ राजग सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के सामने बड़ी चुनौतियाँ भी खड़ी हैं। इन अनेकानेक उपलब्धियों में श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के नेतृत्व में राजग सरकार द्वारा लगातार पाँच वर्षों का शासन पूरा करना भी शामिल है।

देश में अत्यावश्यक राजनीतिक स्थिरता प्रदान कर तथा देश को अपनी पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त करने की दिशा में ले जाने के लिए एक ठोस नींव रखकर हमारी सरकार ने देश के चहुँमुखी विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भाजपा की चुनौतियाँ प्रमुख रूप से आनेवाले निर्णायक चुनाव हैं। हमें आवश्यक सुधारों पर ध्यान देना है, जिससे पार्टी चुनावों में बाजी मार सके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसे प्रथम गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो लगातार पाँच वर्षों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे और उनके नेतृत्व में राजग ने पहले गैर-कांग्रेसी गठबंधन के रूप में इतने समय तक शासन किया। यह बात अनेक कारणों से महत्त्वपूर्ण है। इससे कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रचारित दो मिथक टूट गए। एक, केंद्र में गठबंधन सरकार स्थिर नहीं हो सकती है; और दो, भाजपा बहुदलीय गठबंधन का समुचित नेतृत्व नहीं कर सकती है तथा राजग में समर्थनकारी पार्टियाँ लंबे समय तक भाजपा के साथ जुड़ी नहीं रह सकती हैं। हम सभी के लिए यह गौरव और हर्षोल्लास का क्षण है। हमारी पार्टी ने ऐसे समय में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने में कारगर भूमिका निभाई है, जबकि इससे पूर्व केंद्र में अनेक सरकारें एक के बाद एक जल्दी-जल्दी गिर गईं, जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता के बारे में गंभीर संदेह पैदा हो गया।

हमें उस पृष्ठभूमि और उन परिस्थितियों का स्मरण करना होगा जब हम केंद्र में सत्तारूढ़ हुए थे। सन् 1998 में जब हमने शासन की बागडोर सँभाली थी तो हमें विरासत में जो कुछ मिला था वह थी टूटी-फूटी अर्थव्यवस्था, अभावों का युग, आतंकवाद का बढ़ता चला जा रहा दानव, पटरी से उतरा सुधार कार्यक्रम, ऐसा शासन, जिसमें किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, देश और राजव्यवस्था सामान्य रूप से दिशाहीन थी। इन सबसे बढ़कर एक बात यह थी कि राजग की कुशलता के बारे में प्रश्न चिह्न लगा था कि क्या वह एकजुट होकर राजनीतिक गठबंधन के रूप में खड़ा रह सकेगा। यह अत्यंत संतोष की बात है कि हम ऐसे हताशापूर्ण परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन ला सके और देश को एक विश्वसनीय, समर्थ, संशक्तिशील गठबंधन के रूप में खड़ा कर सके, जो 21वीं शताब्दी के आरंभ में अपना उचित स्थान बनाने को लालायित हैं। अब हम गौरव से उद्घोषणा कर सकते हैं कि अब न तो वे लंबी टेढी-मेढी कतारें रह गई हैं, न ही प्रतीक्षा सूचियाँ हैं, न कालाबाजारी है और न कहीं कोई कमी है—चाहे वह फोन, रसोई गैस कनेक्शन, दूध, चीनी, अनाज, सीमेंट आदि कोई भी चीज हो।

इससे पहले कि मैं अपनी पार्टी के सामने खड़े मुद्दों और चुनौतियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना शुरू करूँ, मैं भाजपा का अध्यक्ष होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री और प्रिय नेता श्री वाजपेयी के प्रति उनके दूरदर्शी तथा राजमर्मज्ञपूर्ण नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनकी सराहना और आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके ऐसे नेतृत्व में ही राजग एक हरीभरी बगिया की तरह फला-फूला है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ऐसे चार महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमों के बीच हो रही है, जिसके फलितार्थों को हम सभी अच्छी तरह जानते हैं—

1. जम्मू और कश्मीर में प्राप्त लाभ खतरे में

हाल में 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या ने एक बार फिर देश को स्तब्ध कर दिया है। अभी देशवासी इस बात पर अत्यंत संतोष प्रगट कर ही रहे थे कि राज्य विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो गए, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी स्वीकार किया गया कि तभी अब निर्दोष लोगों की बीभत्स हत्या से उस पी.डी.पी. सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न हो गए, कांग्रेस जिसकी प्रमुख भागीदार पार्टी है। 'मलहम लगाने' की नीति उम्मीद से कहीं पहले ही दुर्गति में पहुँच गई। 'मलहम लगाने' की जरूरत किसके लिए होती है? क्या इसकी आवश्यकता उन उग्रवादियों से अधिक (जिनके लिए इस नीति को लागू किया जा रहा है) सशस्त्र सेनाओं तथा सुरक्षा कर्मियों के उन संतप्त परिवारों तथा उन असंख्य निर्दोष लोगों को नहीं है जो नरसंहार में मारे गए?

हालाँकि सीमा पार से आतंकवाद निरंतर अपना सिर उठाता रहा है, फिर

भी हाल के वर्षों में स्थानीय लोगों द्वारा उग्रवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है। स्पष्ट ही जब स्थिति सुधर रही थी, तभी स्पेशल एक्शन ग्रुप को समाप्त कर दिया गया। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान तो बहुत कुछ बलिदान दे रहे हैं; परंतु उन्हें ही गलत आलोचना का शिकार बनाया जा रह है, जिससे उनके मनोबल गिरने का खतरा पैदा हो रहा है। इसीलिए यह बार-बार पूछा जा रहा है कि क्या पी.डी.पी. सरकार द्वारा अपनाई जा रही यही 'रिसीप्रोसिटी' (अर्थात् आपसी आदान-प्रदान) की नीति तो नहीं है? एक विधायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अब्दुल मजीद की हत्या हुई और कश्मीरी पंडित फिर से बीभत्स हत्याओं का शिकार हो रहे हैं। फिर से मन में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे लिए यह गंभीर चिंता का विषय है।

पी.डी.पी. की इस भूमिका के कारण घट रही ऐसी घिनौनी रहस्योद्घाटनकारी घटनाओं में कांग्रेस पार्टी की भूमिका विशेष रूप से चिंताजनक है। कांग्रेस से तो उम्मीद की जाती है कि वह कुछ हद तक विवेकपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारी से काम करेगी; परंतु दुर्भाग्य से वह तो राज्य में सफलतापूर्वक कराए गए चुनावों से प्राप्त लाभों को गड्ढे में डालने वाली पार्टी बन रही है। जिस ढंग से और जितनी बड़ी संख्या में लोगों ने चुनावों में भाग लिया, वह स्पष्ट ही इस बात का प्रमाण थे कि राज्य के लोग यहाँ की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण चाहते थे और इसके माध्यम से वे विगत से हटकर अपने भावी जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे; किंतु कांग्रेस की अल्पदृष्टि के कारण कांग्रेस राज्य के लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के विपरीत चल रही है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी कश्मीर नीति की समीक्षा करे, अन्यथा वह जम्मू और कश्मीर के लोगों को तथा राज्यों को भी बहुत नुकसान पहुँचाएगी। मैं कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर में बिगड़ती स्थिति के परिणामों की जिम्मेदारी उसी पर होगी।

2. इराक युद्ध

इराक के खिलाफ अमरीकी युद्ध से लोगों का मन उद्वेलित है। राजग सरकार और देश ने भी स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध का कोई औचित्य नहीं है। विशेष चिंता की बात यह है कि इस संपूर्ण प्रकरण में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर दी गई है। देश की विदेश नीति सदैव राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। अंतरराष्ट्रीय परिणाम वाले ऐसे मामले में सरकार की स्थिति एकदम साफ है। युद्ध जल्दी-से-जल्दी समाप्त होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को अपना दबाव डालना चाहिए और इस बात के

लिए आवश्यक काररवाई करनी चाहिए कि युद्ध समाप्त हो, ताकि नागरिकों के जीवन की और क्षति न हो।

3. स्वातंत्र्य वीरों का तिरस्कार

कांग्रेस पार्टी और उनके बने नए-नए सहयोगी दलों ने संसद् के केंद्रीय कक्ष में वीर सावरकर के तैलचित्र के अनावरण पर अनावश्यक विवाद पैदा करने का प्रयास किया है। सच तो यह है कि यह उन छद्म-सेक्युलरवादियों का चिंतन और दृष्टिकोण है, जो सदैव वोट बैंक की राजनीति को लेकर चलते हैं। वीर सावरकर एक क्रांतिकारी होने के अलावा एक कवि, इतिहासकार और समाज-सुधारक भी थे। यह अत्यंत क्षोभनीय है कि ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की छवि को अल्पकालीन राजनीतिक लाभ के लिए खराब करने की कोशिश की जा रही हे।

हमारे देश का स्वतंत्र संघर्ष विभिन्न प्रकार से विषम और पूरक आंदोलन का मिला जुला रूप था। इसमें विभिन्न प्रकार के चिंतन और दृष्टिकोण सम्मिलित रहे थे; परंतु फिर भी सभी विदेशी शासन के चंगुल से मातृभूमि को मुक्त कराने का समान लक्ष्य लेकर साथ-साथ चलते थे। स्वतंत्रता आंदोलन ने ऐसे अनेक नेताओं को आदर प्रदान किया, जिन्होंने अपूर्व बलिदान दिए। हमें अपने राजनीतिक मतभेदों के कारण उनमें से किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हर स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान किया ही जाना चाहिए। अपने देश की भावी पीढ़ियों के समक्ष महान् स्वतंत्रता संघर्ष की एकतरफा तसवीर पेश करने का अर्थ स्वतंत्रता और बलिदान के युग का अपमान करना ही होगा। वीर सावरकर के तैलचित्र पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा और हुडदंग मचा कर जिस तरह से गलत काम किया है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए।

4. हिमाचल प्रदेश और हमारा आगे का मार्ग

अगले 15 महीनों में हमें चार विधानसभाओं तथा उसके बाद लोकसभा के आम चुनावों का सामना करना है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कोई भी चुनाव एक बड़ी चुनौती होती है। आनेवाली चुनावी चुनौती को सार्थक ढंग से निपटने के लिए हमें हिमाचल प्रदेश के चुनावों से सबक लेना चाहिए और आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए।

मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने हिमाचल प्रदेश में किसी गुण-दोष के आधार पर पराजय नहीं देखी है। राजग में भाजपा सरकार के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद हम चुनावों में इसका लाभ नहीं उठा सके। मेरे विचार में हमारी पार्टी के लिए सबक सीखने का यह एक उत्कृष्ट अवसर

है, ताकि हम किसी चूक के कारण कहीं अन्यत्र पराजय का मुँह न देखें। हिमाचल इकाई में जिस तरह का अनुशासन रहा, उसके कारण पार्टी को बुरी तरह हारना पड़ा। हमारे विरोधियों ने हिमाचल प्रदेश में हमारी पराजय का अर्थ हिंदुत्व की पराजय के रूप में निकालने की कोशिश की। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो इस तरह की बात सोचता है, वह खयाली दुनिया में रह रहा है। हमारे लिए हिंदुत्व ऐसा चुनावी मुद्दा नहीं है, जिसका इस्तेमाल हम राजनीतिक युद्धक्षेत्र में करें। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी जीवन-रेखा है और हिंदुत्व भारत की आत्मा है।

हालाँकि हम हिमाचल में हार गए, परंतु उत्तर-पूर्व में हमने पर्याप्त लाभ अर्जित किया है। नगालैंड में हाल के चुनावों में भाजपा की पैठ इस बात का प्रमाण है कि हमारी पार्टी नए क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के नए क्षितिजों पर पहुँच रही है। नगालैंड में कांग्रेस का एकदम सफाया छद्म-सेक्युलरवादियों के मुँह पर लगा सही तमाचा है। नगालैंड में हमारी सफलता लोगों की इस बात की स्वीकृति का भी प्रतीक है कि वहाँ लोग वाजपेयी सरकार द्वारा ईमानदारी से शुरू किए गए शांति के पहल-प्रयासों का स्वागत करते हैं। मैं नगालैंड के लोगों, अपनी प्रदेश इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं का इस नए संदेश के लिए अभिनंदन करता हूँ।

चुनौतियाँ और सुधारात्मक उपाय

हमें भूत से भविष्य की ओर अपनी यात्रा के बारे में स्पष्ट रूप से मंथन करना चाहिए और ठोस सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। स्पष्ट है कि हमारे एजेंडा पर अनुशासन का विषय सबसे ऊपर रहना चाहिए। पार्टी को अनुशासनहीनता को रोकने के लिए पक्के तौर पर कदम उठाना आवश्यक है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ सरकार का कार्य-प्रदर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए सही लांचिग पैड है, वहीं इसकी तरफ नेताओं और कार्यकर्ताओं के अनुशासन से बहुत अंतर पड़ता है।

मैं सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान 3 अगस्त, 2002 के दिल्ली संकल्प की ओर दिलाना चाहूँगा। इस संकल्प के कठोर अनुपालन से ही समर्पण, सानुशासन, संकल्प और सक्रियता के मार्ग पर चलने में मदद मिलेगी। हमें सभी स्तरों पर आवश्यक सुधारात्मक उपाय और वह भी समय रहते करना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि कार्यकारिणी उस आचार संहिता का कठोरता से अनुपालन करने के बारे में मुझसे सहमत होगी, जिसे हमने ही तैयार किया है। यदि व्यक्ति स्वयं अपने को नहीं सुधारेंगे तो पार्टी को काररवाई करनी ही पड़ेगी।

चुनावगामी चार राज्यों में अनुकूल स्थिति

हम चुनावी समर में कूदने जा रहे हैं। जिन चार राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ हमारे प्रमुख विरोधी दल कांग्रेस का शासन है। मुझे विश्वास है कि इन राज्यों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग राज्यों में जनता की मनोदशा का पूर्ण आकलन कर लिया होगा। हमने देखा होगा कि लोगों का मोह भंग हुआ है और वे भ्रम की अवस्था से उबरे हैं। इन राज्यों में कांग्रेस का रिकॉर्ड निष्क्रिय प्रदर्शन, कुशासन, अक्षमता, भ्रष्टाचार, कमजोर वर्गों और महिलाओं पर अत्याचार, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति तथा इन सबसे बढ़कर वायदे पूरे न करने की लंबी कहानी से भरा पड़ा है। राजग सरकार ने सूखा तथा अन्य कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए बिना किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव किए उदारतापूर्वक सहायता दी, इसके बावजूद भूख से मरने की रिपोर्टें सुनकर दिल दहल उठता है। ये राज्य साक्षरता, स्वास्थ्य, आवास, स्वसहायता समूह, गाँवों को सड़कों से जोड़ने तथा निर्धनता जैसे महत्त्वूपर्ण मानदंडों पर भी राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं।

इन राज्यों में भाजपा के लिए अत्यंत अनुकूल स्थिति है और अब यह हमारे नेताओं तथा पार्टी कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे लोगों में भरे इस क्रोध तथा कुंठा को अपनी अनुकूल दिशा में मोड़ें। आवश्यकता यह है कि कांग्रेस से लोगों के इस मोहभंग को प्रभावकारी ढंग से मुखरित कर भाजपा की भारी विजय में बदला जाए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी प्रदेश इकाइयाँ एकजुट होकर संघर्ष करें। अपनी असफलताओं तथा स्थिति की गंभीरता को महसूस कर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लोगों का ध्यान हटाने के लिए गंदी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्तियाँ और तथाकथित नरम हिंदुत्व अपनाने आदि जैसी पैंतरेबाजियों का सहारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने तक का सुझाव देने की हद तक चले गए हैं, जबकि कांग्रेस हाईकमान अभी भी इस बारे में भ्रम की स्थिति में पड़ा हुआ है। कांग्रेस यहाँ तक नीचे गिर गई है कि उसने प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए कुछ पैंफलेट भी निकाले हैं। उसे बाद में ऐसी गंदी हरकतों के प्रति जन आक्रोश खड़ा होने पर इस बात से इनकार करना पड़ा है कि उसने कोई ऐसा अभियान चलाया है।

इससे भी बुरी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मतदाता सूचियों में फेर-बदल कर वैज्ञानिक ढंग से धाँधली करके अब तक के सबसे बड़े चुनावी घोटाले की योजना बनाई है। इस घोटाले का पर्दाफाश होने पर वहाँ के मुख्यमंत्री के पास कोई बचाव नहीं था तो भी उन्होंने कमजोर बचाव करने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। राज्य सरकार दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि ये अधिकारी राजनीतिक नेताओं के विशिष्ट निर्देशों के बिना ऐसी गंभीर अनियमितता नहीं कर सकते थे।

मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से यह पूछना चाहता हूँ– 'आप इस चुनावी घोटाले के बारे में चुप क्यों हैं?' मैं अपनी पार्टी की प्रदेश इकाई के सहयोगियों से भी आग्रह करता हूँ कि वे मुख्यमंत्री के विरुद्ध तब तक जन अभियान चलाते रहें जब तक इसे तार्किक परिणति तक न पहुँचा दिया जाए।

राजस्थान सरकार इस बात का बेमिसाल उदाहरण है कि कैसे एक अक्षम राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिली उदार सहायता के लाभों को भी गर्त में डाल देती है। किसी केंद्र सरकार ने आज तक राज्य सरकार को इतनी सहायता नहीं दी है जितनी राजग सरकार ने राजस्थान के मामले में दी है, ताकि वह सूखे की कठिन परिस्थिति से निपट सके। वहाँ भूख से हुई मौतों तथा बड़ी संख्या में लोगों के पलायन के समाचार मिले हैं।

कांग्रेस पार्टी प्रचार करती है कि छत्तीसगढ़ एक आदर्श राज्य है, जिसका नेतृत्व एक आदर्श मुख्यमंत्री के हाथों में है; किंतु अन्य सारे दावों की तरह सच्चाई इसके बिलकुल विपरीत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दलबदल, छल-बल तथा जोड़-तोड़ की राजनीति में दक्षता हासिल कर ली है। उनके लिए दलगत राजनीतिक लाभों के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग एक चलन बन गया है। विकासात्मक कार्य पूर्णतः उपेक्षित हैं। मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली के बारे में स्वयं कांग्रेस पार्टी में लोगों का मोह बुरी तरह टूट गया है। हाल में भाजपा द्वारा आयोजित किसान रैली में असाधारण रूप से लोगों ने भाग लिया, जो इस बात का प्रमाण है कि आगामी विधानचुनाव में लोग शासक दल को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं।

दिल्ली में कांग्रेस सरकार का रिकॉर्ड टूटे वायदों और हर क्षेत्र में असफलता की गाथा है। पानी तथा बिजली की कमी पहले से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक सुविधाओं में जो थोड़ा-बहुत सुधार दिखाई देता है यथा मेट्रो परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन, यह भी केंद्र द्वारा दिए गए ध्यान और उसकी सहायता का परिणाम है।

ये उन राज्यों की हताशाजनक स्थिति के कुछ उदाहरण मात्र हैं, जिनमें इस वर्ष के अंत में चुनाव होनेवाले हैं। इस प्रसंग में हमारी पार्टी इकाइयों को आक्रामक अभियान चलाना होगा। मैं इन चार राज्यों में अब तक हुई तैयारियों से खुश हूँ। अब हमें पूरा ध्यान देकर अभियान में जुट जाना है। मैं प्रदेश इकाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे जनता की निगाह में इन राज्यों के कुशासन को नंगा करने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करें।

हमें समझ लेना है कि अगले वर्ष आम चुनाव में हमारी पार्टी को लोकसभा की 300 सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो 'फाइनल संघर्ष' करना है, चारों राज्यों में यह लड़ाई उसका सेमी-फाइनल है। हमारी उपलब्धियों के रिकॉर्ड और विपक्षी दलों की दिशाहीनता को देखते हुए यह विजय संभव है।

कांग्रेस तथा उसका घोर विश्वासघात

चुनावों में आसन्न पराजय को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को अचानक गरीबों की याद आई है। केंद्र में अपने शासन के 47 वर्षों के दौरान उसने अमीरों को पाला-पोसा, किंतु अब कांग्रेस पार्टी को गरीबों के साथ का महत्त्व समझ में आने लगा है। लंबे कांग्रेसी शासन की कहानी 'घोर विश्वासघात' के अलावा कुछ नहीं है। इन वर्षों के दौरान बुरी तरह तिरस्कृत किए गए गरीब अब फिर से एक बार कांग्रेस से छले जाने के लिए तैयार नहीं हैं। 'अभी तक अमीर के साथ; चुनाव के मोड़ पे गरीब को हाथ, चुनाव के बाद फिर से विश्वासघात' कांग्रेस का अभी तक गरीबों के साथ यही रिकॉर्ड चला आ रहा है। कम-से-कम अब तो कांग्रेस नेतृत्व को महसूस करना चाहिए कि इस देश के लोग अब उनकी चालबाजियों को समझने के लिए होशियार हो गए हैं। कांग्रेस शासन अकेला ही क्षेत्रीय असमानताओं, बेरोजगारी, गरीबी, आतंकवाद तथा संक्षेप में उन सभी बुराइयों के लिए उत्तरदायी है जिनसे आज राष्ट्र ग्रस्त है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने अपने लंबे शासन के दौरान अमीरों के साथ ही मस्त रहकर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की अपनी लंबी गाथा को भी भुला दिया है। भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाने का श्रेय भी पूरी तरह कांग्रेस को जाता है। वेद मंत्र जपने वाले राक्षस के समान कांग्रेस घड़ियाली आँसू बहाती है, जबकि भाजपा तथा राजग हर तरह से और हर प्रकार के भ्रष्टाचार से लड़ रही है।

गत पाँच वर्ष के दौरान संसद् में विपक्ष का आचरण किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए गंभीर चिंता का विषय है जो लोकतंत्र में वस्तुतः विश्वास रखता है। विपक्षी दलों के पास सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं है तथा वे संसद् में गड़बड़ी फैलाकर बहस से कतराते हैं। उन्होंने हमेशा 'आरोप लगाओ और भागो' की नीति अपनाई है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण तथाकथित 'ताबूत कांड' के बारे में लगाए गए काल्पनिक आरोपों से मिलता है। उन्होंने संसद् की गरिमा गिरने की कोई परवाह नहीं की। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे इस सच्चाई को पचा नहीं पा रहे हैं कि भाजपा कैसे आज तक के सबसे बड़े गठबंधन को बड़े प्रभावशाली ढंग से नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम रही है। विपक्ष का कोई साझा एजेंडा नहीं है। एक दिन वे साथ-साथ फोटो खिंचवाते हैं, दूसरे दिन एक-दूसरे का विरोध करते दिखाई देते हैं। वे शाम को मिलते हैं—सुबह जुदा हो जाते हैं। वे त्रिपुरा, बंगाल तथा केरल में एक-दूसरे का विरोध करते हैं और दिल्ली में एक होने का ढोंग करते हैं।

विपक्ष व्यापक राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर दोहरा मानदंड तथा नकारात्मक रवैया अपनाकर राष्ट्र का बहुत अहित कर रहा है। कश्मीर, कारगिल, आतंकवाद, पोटा, घुसपैठ, देश की सुरक्षा, स्कूलों के पाठ्यक्रम को युक्तियुक्त बनाना,

धर्मांतरण, गोधरा तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाएँ, सुधार आदि जैसे अनेकों मुद्दे हैं, जिनपर विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय हित के साथ समझौता कर रहा है। कुछ राजनीतिक समीक्षकों से यह सुनकर मुझे दुख होता है कि देश में इससे पहले कभी ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं रहा। वे यह भी कहते हैं कि भाजपा के लिए यह अच्छी बात है। मैं उनसे इसपर सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारा विश्वास है कि लोकतंत्र को प्रभावी तथा जीवंत विपक्ष की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूँ कि वे एक भी ऐसा मुद्दा बताएँ जिसपर उसने राष्ट्रहित में रचनात्मक रवैया अपनाया है।

राजग सरकार ने अभी तक कई क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है। पार्टी खुश है कि सरकार ने 'फर्टिलाइजर सबसिडी' के मुद्दे पर उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए मैं वित्तमंत्री श्री जसवन्त सिंह का अभिनंदन करता हूँ। मैं कई राज्यों में सूखा प्रबंधन के बारे में सरकार द्वारा अनुकरणीय ढंग से राहत प्रदान करने की भी सराहना करता हूँ; किंतु मैं महसूस करता हूँ कि ब्याज माफ करने के मुद्दे पर बैंकों को स्पष्ट निर्देश देने और सूखा राहत कार्यों पर बेहतर ढंग से नजर रखने की आवश्यकता है।

पार्टी सरकार को निम्नलिखित सुझाव देती है—

- कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष पैकेज तैयार करे जिसमें उनके आवास, रोजगार, स्व-रोजगार, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा की जरूरतें शामिल हों।
- आई.एम.डी.टी. ऐक्ट को समाप्त करे, क्योंकि इससे कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है।
- गाय तथा गौवंश राष्ट्र के अमूल्य धन का एक भाग हैं, जिसे बचाने के लिए गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए।
- प्रोत्साहनों तथा निरुत्साहनों पर आधारित द्रुत जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता पर राष्ट्रीय बहस प्रारंभ करे।
- सभी भारतीय भाषाओं को उचित मान्यता तथा दर्जा प्रदान करे।

शेष 15 मासों के दौरान सरकार प्रभावशाली ढंग से और निरंतर समीक्षा करते हुए वर्तमान में चल रहे विभिन्न विकासात्मक तथा कल्याण कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन पर और अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। यद्यपि सरकार अपना भरसक प्रयास करेगी, फिर भी यह पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक और आशा बनकर उनके साथ संबंध बनाएँ। मैं भाजपा और साथ ही समर्थक दलों के विधायकों का भी आह्वान करता हूँ कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सतत सतर्क रहें कि विभिन्न जनहितकारी कार्यक्रमों का लाभ लोगों तक पहुँचे और वे लोगों से निरंतर बातचीत कर उन्हें

बताएँ कि हमें उनके हितों की चिंता है। पार्टी को निम्नलिखित मुद्दों पर सतत अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है—

- राज्य सरकारों द्वारा आतंकवाद के संबंध में प्रभावी काररवाई की आवश्यकता।
- घुसपैठ पर तीन सूत्री फॉर्मूला अपनाने की आवश्यकता-डिटेक्शन, डिलीशन और डिपोर्टेशन अर्थात्—मतदाता सूचियों में घुसपैठियों का पता लगाना, नाम हटाना और उन्हें देश से बाहर निकालना।
- एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम।
- सभी राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता।
- गो-वध पर प्रतिबंध की आवश्यकता।
- जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रभावी उपाय।

बड़ी चुनौतियाँ सामने हैं। हम उनका मिलकर प्रभावी ढंग से मुकाबला करेंगे। आइए, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। विजय हमारी है—भविष्य हमारा है।



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

रायपुर 18–20 जुलाई, 2003

भारतीय जनता पार्टी में एकता है, भारतीय जनता पार्टी में स्पष्टता है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को व हमारे सहयोगियों को और महत्त्वपूर्ण अवसर देने के इच्छुक हैं।

मुझे रायपुर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। पिछली बैठक मई महीने में इंदौर में हुई थी। इंदौर से रायपुर की यात्रा, समय और स्थान की दृष्टि से बहुत छोटी है, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी स्वप्नद्रष्टा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने इन तीन महीनों में एक लंबा रास्ता पार किया है।

चिंतन बैठक, एक दिशा निर्धारक घटना

जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, इस अवधि की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना बंबई के पास रामबाबू महलगी प्रबोधिनी के प्रांगण में एक चार दिवसीय चिंतन बैठक का आयोजन है। इस प्रकार के तीव्र विचारात्मक सत्र समय-समय पर अनौपचारिक वातावरण में आयोजित करना हमारी परंपरा है। सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को यह बताना चाहूँगा कि चिंतन बैठक सभी प्रकार से बहुत ही उपयोगी एवं रचनात्मक रही।

हमने एक संरचनात्मक तरीके से पार्टी और सरकार के सामने उपस्थित सभी प्रमुख विषयों पर खुले रूप में चर्चा की, हमने राष्ट्रीय एवं राज्य, दोनों स्तरों पर राजनीतिक स्थिति की गहराई से समीक्षा की। हमने सरकार के अनेक विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यों के निष्पादन पर चर्चा की और लोगों के लाभ के लिए नए कार्य शुरू करने पर सहमति बनाई। मुझे खुशी है कि सरकार ने पार्टी के कुछ सुझावों पर पहले से ही कार्य करना भी शुरू कर दिया है। चिंतन बैठक के सभी

प्रतिभागियों ने संतोष व्यक्त किया कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रीय संगठनों के बीच संबंध लगातार बहुत गहरे हो गए हैं।

चिंतन बैठक का मुख्य परिणाम यह रहा कि इसने हमें आगामी दो प्रमुख चुनावी ऑपरेशन 2003 और मिशन 2004 पर अपनी दृष्टि केंद्रित करने में मदद दी है। इससे साल के अंत में होने वाले पाँच राज्यों के असेंबली चुनावों में पुनः जोरदार जीत हासिल करने का हमारा संकल्प मजबूत हुआ है और यही अगले वर्ष के मध्य में होने वाले संसदीय चुनाव में हमारी अधिक बड़ी जीत का आधार होगा।

पार्टी और सरकार के बीच परस्पर संवाद

प्रिय मित्रो, आपको स्मरण होगा कि राजग सरकार के शुरू के वर्षों में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में कई सदस्यों ने यह आवश्यकता महसूस की थी कि सरकार और पार्टी के बीच और अधिक संवाद स्थापित हो। मुझे बड़े संतोष के साथ यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि सरकार और पार्टी के बीच परस्पर संवाद मेरी आशाओं से भी अधिक हो गया है। मैं प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने जब भी जमीनी स्तर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता हुई तभी उन्होंने सकारात्मक सहयोग दिया। हमारे बहुत से सुझावों और विचारों को शीघ्रतापूर्वक स्वीकार किया गया तथा कार्यान्वित किया गया इस संबंध में मुझे आपको यह सूचित करना है कि चिंतन बैठक में जो सुझाव दिए गए थे उनमें से कुछ को अविश्वसनीय गति से कार्यान्वित कर दिया गया है। इससे भी पहले वित्तमंत्री और अन्य मंत्रीगण केलकर समिति रिपोर्ट, वैट, पावरलूम क्षेत्र की समस्याएँ, लघु उद्योग क्षेत्र, टेलीफोन रैंटल्स, कर्मचारी भविष्य निधि आदि के विषय में हमारे सुझावों के प्रति पर्याप्त संवेदनशील रहे।

मुझे यहाँ आडवाणीजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है कि जब भी हमने उनसे समय और मार्गदर्शन चाहा तभी उन्होंने समय और मार्गदर्शन दिया। और वे सरकार तथा पार्टी के बीच मुख्य संपर्क सूत्र बने रहे।

मुझे इसकी भी प्रसन्नता है कि सरकार के मंत्रियों ने पार्टी कार्यालय में लगातार आकर पार्टी के कार्यकलापों में अपनी भागीदारी बढ़ाई। और उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों को देश के विभिन्न भागों तक पहुँचाया तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संपर्क बढ़ाया। ऐसा करने से मंत्रियों को पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करने में सहायता मिली है तथा अपने मंत्रालय और मंत्रालयों में कई जनहितैषी पहल करने में भी सहायता प्राप्त हुई है।

पिछले एक वर्ष में पार्टी फंक्शनरीज और कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग जैसे अभिनव प्रयोग के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक परस्पर संवाद हुआ है।

संगठनात्मक चुनाव

आप कृपया पार्टी के सभी स्तरों पर इस वर्ष के अंत तक संगठनात्मक चुनावों के बारे में अपने संकल्प का स्मरण करें। मुझे इस बारे में अब तक हुई प्रगति की आपको जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है तथा मैं आशावान हूँ कि सारी प्रक्रिया शिड्यूल के अनुसार पूरी हो जाएगी।

सरकार की उपलब्धियों का गौरवपूर्ण रिकॉर्ड

जहाँ तक राजग सरकार से संबंध है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इंदौर बैठक से बाद की अवधि में आंतरिक और बाह्य स्तर पर दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ रहीं। सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्रीजी को पहले उनकी जर्मनी, रूस, फ्रांस और बाद में चीन की यात्राओं की सफलता पर अपनी और पार्टी की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। फ्रांस की ए.वी.एन. में उन्होंने पहली बार जी–8 राष्ट्रों की शिखर वार्त्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने विकासशील देशों के लगातार और समानता के आधार पर वैश्विक विकास के मामले को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ए.वी.एन. और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, दोनों ही जगहों पर उनकी विश्व नेताओं के साथ लाभकारी बैठकों से न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं, वरन् कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद तथा अन्य विषयों पर भारत के दृष्टिकोण को अंतराष्ट्रीय सहयोग मिलने की संभावना बढ़ी है।

प्रधानमंत्रीजी की चीन की यात्रा से अनेक क्षेत्रों में नए मार्ग खुले हैं। इससे विश्व के दो बड़े एवं तेजी से विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग और रिश्तों के द्वार खुले है। भारतीय जनता पार्टी आशा करती है कि दो देशों के बीच के जटिल सीमा संबंधी झगड़ों पर बातचीत के नए द्वार, जो बीजिंग में खुले हैं, भविष्य में उसके परिणाम सकारात्मक होंगे। व्यापार और आर्थिक सहयोग पर हुए समझौते दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद देंगे। तथ्य यह है कि भारत और चीन के बीच व्यापार बहुत ही आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा है।

पाकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री के शांति के नए प्रयासों का संपूर्ण विश्व ने स्वागत और प्रशंसा की। इससे भारत की ईमानदारी और प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कटिबद्धता स्पष्ट होती है। विश्व समुदाय ने भी अब अनुभव कर लिया हैं कि सीमा पार के आतंकवाद को रोकने और वहाँ वर्षों से पल रहे आतंकवाद की जड़ों को पूर्णतया समाप्त करने का दायित्व पाकिस्तान का है। इस विषय को उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी हाल ही की अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा के दौरान जोरदार तरीके से तर्क देकर प्रमाणित कर दिया था।

इस संदर्भ में हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री की शांति की पहल के प्रति पाकिस्तान के स्थिर एवं सकारात्मक रवैए की कमी के प्रति केवल

गहरा असंतोष व्यक्त कर सकते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की यह उद्घोषणा कि वह इसलामाबाद के परंपरागत भारत विरोधी एजेंडे को बदलने के इच्छुक नहीं हैं। यह भी स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ अपने ही देश की जनतांत्रिक शक्तियों से गंभीर लड़ाई में व्यस्त हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी समाज में यह विचार पनप रहा है कि भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे सहित सभी मुद्दे द्विपक्षी वार्त्ता के द्वारा सुलझाए जाएँ। पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों, जो अभी निर्वासित हैं, ने खुले रूप से यह विचार व्यक्त किया था। यह विचार पाकिस्तान की राजनीतिक स्थापना में, जिसको जनरल मुशर्रफ के प्राधिकार का वैधता के प्रश्न पर सत्ताधारी सैनिक व्यवस्था ने मूक बना दिया है—में अभी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हुआ है। यह स्थिति अनिश्चित है और इस उठा-पटक का परिणाम भी अनिश्चित है। अतः सरकार का पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध सुधारने के प्रयासों में सतर्कता बरतने का निर्णय सही है। मेरा मानना है कि इस नीति को लोगों का समर्थन तथा सराहना मिली है। सरकार इराक में सेना भेजने के मुदे पर भी राष्टीय हितों के अनुसार कार्य कर रही है।

सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम गरीबों के पक्ष में

आंतरिक स्तर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक से अब तक की अवधि में राजग सरकार ने अनेक नए कार्यक्रम आरंभ किए एवं अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। मैं वित्तमंत्री श्री जसवंत सिंहजी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने दो महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों—वृद्ध नागरिकों के लिए 9 प्रतिशत की सुनिश्चित वार्षिक ब्याज दर वाली वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो गरीबों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बहुत आकर्षक कार्यक्रम है—को शुरू किया है। दोनों अपने प्रकार के पहले कार्यक्रम हैं जो वाजपेयी सरकार की ख्याति को जिम्मेदार एवं संवेदनशील सरकार के रूप में और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आरंभ करके इस कीर्ति को और बढ़ाया है। सरकार ने अपने एक कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह के 6 अन्य उच्च विशिष्टता से युक्त अस्पताल (देश के अल्प-विकसित क्षेत्रों में रु. 1800 करोड़ की लागत से) खोलने का निर्णय किया है। दो दिन पूर्व ही प्रधानमंत्रीजी ने ऐसे पहले अस्पताल की नींव भुवनेश्वर में रखी हैं। मैं ई.पी.एफ. पर 9 प्रतिशत ब्याज सुनिश्चित करने के लिए श्रममंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा का साहसिक पहल करने के लिए साधूवाद करना चाहूँगा। इस कदम ने सरकार की कामगार वर्ग के कल्याण के प्रति वचनबद्धता को और मजबूत किया है। ऐसा करना प्रधानमंत्रीजी व वित्तमंत्रीजी के समर्थन के बिना संभव नहीं था।

मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे इन कार्यक्रमों का क्रियाशील रूप से प्रचार करें। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के मामले में वे प्रत्यक्ष रूप से या कर्तव्यनिष्ठा वाले गैर-सरकारी संगठन द्वारा गरीब परिवारों को इस योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दें।

कुछ नए अभिक्रमों के लिए सलाह किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि ऋण

इस वर्ष देश के कई भागों में बरसात के समय पर होने के कारण फसल अधिक अच्छी होने की आशा है। अच्छी बरसात को ध्यान में रखते हुए, सरकार को किसानों का आह्वान करना चाहिए कि भरसक प्रयास करके खाद्य उत्पादन में कम-से-कम 10 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करें। यह पूर्णरूप में तब संभव होगा जब केंद्र और राज्य सरकार बैंक और उधारदाता एजेंसीज और बीज उर्वरक आदि को वितरण करनेवाले संगठनों को इसमें शामिल करते हुए बहुमुखी प्रयास करें। फिर भी, इन प्रयासों की सफलता कुछ हद तक भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्याओं के समाधान से जुड़ी हुई है। उनमें से एक है—कृषि ऋण की ऊँची दर। ग्रामीण साख समितियों की कमजोर स्थिति इसका दूसरा कारण है। मैं वित्त और कृषि मंत्रियों से अनुरोध करता हूँ कि इन मामलों की तुरंत जाँच करें और कुछ व्यावहारिक समाधान निकालें। किसानों को 9 प्रतिशत की विभेदक दर पर ऋण उपलब्ध कराने के विषय पर गंभीरता से विचार करें। ट्रैक्टर जैसे कृषि यंत्रों की खरीद के लिए ऋण पर प्रभारित ब्याज में भी पर्याप्त कमी की जानी चाहिए। भाजपा वित्त मंत्रालय से इसपर विचार करने की अपेक्षा करना चाहेगी कि वह किसानों द्वारा कृषि कुओं की डिसिल्टिंग, फिल्टर पाइंट, मोटर व पंप सैटों, कृषि भूमि के बंधों के उन्नयन को दृढ़ बनाने के लिए ऋणों पर उसी के समान ब्याज दर की व्यवस्था करेगी।

रोजगार के अवसर

योग्य नागरिकों को, मुख्यतः युवकों को उत्पादकता-रोजगार और स्वयं-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राष्ट्र के लिए एक प्रधान चुनौती है। हम सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति आभारी हैं जिनके फलस्वरूप रोजगार और स्वयं-रोजगारी के अवसर पिछले कुछ वर्षों में निश्चय ही बढ़े हैं। फिर भी आगे ये अवसर और भी बढ़ाने की आवश्यकता और संभावना है। मेरी राय में KVIC और लघु उद्योग सेक्टर इस संदर्भ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि उनपर अधिक ध्यान दिया जाए और उन्हें अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ। हाल ही में योजना आयोग ने प्रधानमंत्री को जैविक ईंधन (एथनॉल, बायो-डीजल व तथा अन्य) और बाँस (बेम्बू) के विकास पर अत्युत्तम रिपोर्ट

प्रस्तुत की है। दोनों में रोजगारी के अवसर उत्पन्न करने की आश्चर्यजनक क्षमता है, जिससे लाखों दस्तकार और किसान गरीबी रेखा से ऊपर उठें और करोड़ों रुपयों के आयात द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें। पार्टी सरकार से अनुरोध करती है कि उक्त दोनों रिपोर्टों की सिफारिशों को शीघ्र और प्रभावशाली ढंग से लागू करें।

विभिन्न आयोगों का गठन

चिंतन बैठक में सर्वसम्मत राय थी कि सरकार एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग और घुमंतू जनजातियों के लिए अलग विकास आयोग का गठन करे और इस बात के प्रति भी सहमति थी कि विभिन्न आयोग विकास और वित्तीय निगमों के कार्यकलापों की समीक्षा की जाए। मैं अनुरोध करता हूँ कि सरकार इसपर ध्यान दे।

पार्टी, सरकार से अनुरोध करती है कि यथाशीघ्र आई.एम.डी.टी. ऐक्ट को रद्द करें ताकि बँगलादेश के घुसपैठियों को जाँचने में उत्पन्न कानूनी और प्रशासनिक कमियों को दूर किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल (यूनियन केबिनेट) द्वारा स्वीकृत किए गए लोकपाल बिल को शीघ्र ही पास किया जाए। इस राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की बैठक में हम संसद् और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के आरक्षण के प्रस्ताव के प्रारूप पर चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस विषय पर अपनी टिप्पणियों को सीमित करते हुए केवल यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए नए और कार्य योग्य विचारों पर एकमत बनाना चाहेगी।

मैं सरकार से विस्थापित व्यक्तियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए आयोग की स्थापना करने का आह्वान करता हूँ। पार्टी ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की समस्याओं का और इन वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की व्यवहार्यता का अध्ययन के लिए आयोग स्थापित करने की भी सिफारिश की है।

जनजागरण अभियान—गाँव-गाँव चलो, घर-घर चलो

हमारी सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में कई अभूतपूर्व कार्यक्रम और परियोजनाओं को आरंभ किया। उदाहरण के लिए, सर्व शिक्षा अभियान, जो आजादी के उपरांत सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा प्रसार का कार्यक्रम है—अंत्योदय अन्न योजना पूरे विश्व में सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतीय राष्ट्रीय रेल विकास योजना, दूरसंचार और आई.टी. में पहल। हमारी ये सभी योजनाएँ अपने कार्यक्षेत्र और प्रभाव में अद्वितीय हैं। तो भी ऐसा लगता है कि हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों के रूप में सही सूचनाएँ नहीं दी गई हैं, उन्हें सरकार के इन कार्यक्रमों

को पूर्णतः और विश्वास के साथ जनता को बताना होगा। मेरा सुझाव है कि पार्टी को उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के लिए राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान चलाना चाहिए। और हमारी स्थानीय इकाइयाँ वर्ष के दौरान प्रत्येक गाँव तथा प्रत्येक घर का दौरा करेगी। इसे 'गाँव-गाँव चलो, घर-घर चलो' अभियान कहा जा सकता है। इस संदर्भ में मैं जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को भी अपना प्रचार कार्यक्रम और अधिक मजबूत बनाना चाहिए, ताकि लोग राष्ट्र के विकास में सहभागी बनें।

देश में सर्वत्र संतोष व्याप्त है

प्रिय मित्रो, देश की वर्तमान स्थिति को एक ही वाक्य में कहा जा सकता है कि सर्वत्र संतोष व्याप्त है, इसका मुख्य कारण श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनता ने एन.डी.ए. सरकार के कार्य को देखा, परखा और समझा है। मैंने इंदौर में भी कहा था कि प्रधानमंत्री के पद पर पाँच वर्ष रहने के उपरांत भी श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी, जितने लोकप्रिय हैं उतना और कोई नहीं। इससे विश्वास होता है कि जब कभी संसदीय चुनाव संभव होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को पुनः चुनावों में जीत ही नहीं, अधिक जनादेश मिलने की संभावना है।

जनता केवल सरकार से सकारात्मक रूप से प्रभावित ही नहीं हुई है, वरन् उसने विपक्षी दलों का तीव्र रूप से तिरस्कार भी किया है। विपक्षी दलों में मतभेद और निराशा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नेतृत्व को लेकर घोर विषमता है। हमारे पास श्री अटलजी है, जो भाजपा या राजग सरकार के नेता ही नहीं पूरे राष्ट्र के नेता हैं। दूसरी ओर कांग्रेस केवल वंश-परंपरा की शरण ले सकती है।

चिंतन और कारखाई में स्फूर्ति और मौलिकता से विहीन होकर कांग्रेस पार्टी भाजपा की नकल करने लगी। यदि हम चिंतन बैठक का आयोजन करते हैं तो वे मंथन शिविर का। 1996 के पहले ही हमने राजनीति में सहयोगी राजनीति को अपनाया, कांग्रेस को अब भारतीय राजनीति की वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए झटका खाना पड़ा और अब जब वे सहयोगी दलों को स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं तो इने-गिने दल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को अन्य पार्टियों में भी ऐसे सहयोगी कम मिलेंगे जिनके लिए भाजपा अभिशाप स्वरूप है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी को चुनौती देता हूँ कि वे चुनावों के पहले ही बंगाल, केरला और त्रिपुरा में कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा करे।

हम विकास पर कांग्रेस के साथ परिचर्चा करना चाहते हैं

अब कांग्रेस के पास सरकार के विरुद्ध कहने के लिए कोई मामला शेष

नहीं है, इसीलिए वह सांप्रदायिकता के घिसे–पिटे मुहावरे को दोहरा रही है। मैं कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देता हूँ कि वे विकास की मदों पर बात करें। कांग्रेस के 47 वर्ष के कार्यकाल के कार्यों और एन.डी.ए. सरकार के 5 वर्षों के विकासपूर्ण शासन पर डिबेट हो जाए। मगर कांग्रेस को पता है कि वे हमारे विकासपूर्ण रिकॉर्ड पर सवाल नहीं उठा सकती। कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक न्याय के हमारे ट्रेक रिकॉर्ड के साथ उनके ट्रेक रिकॉर्ड की तुलना करना समर्थनीय नहीं है।

हम धर्मनिरपेक्षता पर कांग्रेस के साथ परिचर्चा के लिए तैयार हैं

धर्मनिरपेक्षवाद पर बहस करने के लिए हम तैयार हैं; क्योंकि शिमला बैठक में कांग्रेस ने फिर से अपना सांप्रदायिकता का कुंठित और जंग लगा हथियार फेंका है और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए स्वघोषित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एकजुट होने का निमंत्रण दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी के अपने मित्रो को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एक धर्मनिरपेक्षता विरोधी पार्टी के रूप में प्रचारित करने के उनके प्रयासों से हम लेशमात्र भी चिंतित नहीं हैं। हम धर्मनिरपेक्षवाद पर खुली बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को कुछ असहजकारी सवालों का स्पष्टीकरण देते हुए कुछ मामलों पर अपने रुख को स्पष्ट करना होगा।

- कांग्रेस रामजन्म स्थान पर राम मंदिर के निर्माण द्वारा अयोध्या मामले को सुलझाना चाहती है या नहीं।
- 'हिंदुत्व धर्म की संकल्पना नहीं है', मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस दावे से कांग्रेस हाई कमान सहमत है या नहीं।
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा अपने राज्य में रामकथा के लिए मंदिर निर्माण के समर्थन को कांग्रेस हाई कमान सांप्रदायिकता मानती है या धर्मनिरपेक्षता।
- केरल के मुख्यमंत्री द्वारा मुसलिम लीग की कठोर और अनुचित व्यवहार के प्रति आलोचना को कांग्रेस हाई कमान सही मानता है या नहीं।

प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी को 'धर्मनिरपेक्षवाद के दुश्मन' के रूप में आलोचना करने वालों को मैं सलाह देता हूँ कि हाल ही में नई दिल्ली में 'डायलॉग अमंग सिविलाजेसंस' पर संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री के भाषण पर ध्यान दें। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने दृढ़ता से कहा है कि भारतीय धर्मनिरेपक्षवाद की संकल्पना सर्वपंथ समभाव को विश्व के सभी देशों को अपनाना चाहिए, ताकि सहनशीलता और आंतरिक विश्वास एवं सहयोग विश्व के आदर्श बन सके।

ऑपरेशन 2003 और मिशन 2004

मित्रो, चुनाव युद्ध की रूपरेखा बनाई जा चुकी है। हमारा पहला उद्देश्य

ऑपरेशन 2003 में सफल होना है अर्थात् राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश से कांग्रेस को हटाना है। मैं इन चार राज्यों की राज्य शाखाओं को यह उद्देश्य प्राप्त करने में उनके समर्पित प्रयास के लिए बधाई देता हूँ। मैं उक्त चार राज्यों में विशिष्ट जिम्मेदारी निभाते हुए गतिविधियों के प्रचार में भाग लेने वाले केंद्रीय मंत्रियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पार्टी संगठन के सभी स्तरों पर मिलजुलकर और लगातार काम होना चाहिए। इन चारों राज्यों की जनता में सत्ताधारी पार्टी की अक्षमता के प्रति विरोध है। हमारी जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहती है। अब यहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि इस समर्थन को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करते हुए इन चारों राज्यों से कांग्रेस को पूर्णतया हटा दें।

साथ-साथ मैं इस पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नेताओं को आमंत्रित करता हूँ कि वे मिशन 2004 के लिए तैयार रहें, सक्रिय रहें, जनता तक पहुँचकर उन्हें अपनी उपलब्धियाँ बताएँ तथा अपने पक्ष में मतदान का ठोस आधार तैयार करें। मैं अपने पहले के शब्दों को दोहराता हूँ 'चिंतन प्रगतिगामी हो, विचार ठोस हों, अभियान जुझारू हो।' जहाँ तक संभव हो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना और हमारे सहयोगियों के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त करना है यह असंभव नहीं है। यह हम कर सकते हैं। हम में एकता है, हम में स्पष्टता है और जनता हमें और बड़ा मौका देने के लिए तैयार है।

हिंदुत्व भारत की आत्मा है। हमें इसका गर्व है, किंतु यह न तो चुनावी मुद्दा हो सकता है और न ही हिंदुत्व को एक संकीर्ण धार्मिक संकल्पना के रूप में प्रक्षेपित किया जा सकता है। हमारी धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता है; किंतु हम छद्म धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के मत हथियाने के लिए तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध है।

हमें अपनी विचारधारा पर गर्व है। किसी भी मुद्दे पर अपनी स्थिति बताने में हिचक न करें, किंतु इतना भी याद रखें कि हम एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और अपने किसी सहयोगी पर अपना एजेंडा थोपे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

सभी दिशाओं से कांग्रेस को घेरा जाए। कांग्रेस को इसकी अनुमति न दी जाए कि वह अपने विगत कुशासन और वर्तमान विफलताओं से लोगों का ध्यान हटा सके। अपने एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं पर बल दिया जाए—यथा राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, सुशासन तथा विकास। इन मुद्दों पर बहस के लिए कांग्रेस को चुनौती दी जाए। हमारे अभियान के ये ही मुख्य विषय होंगे।

हम इन सभी मुद्दों पर मजबूत हैं और हमारे विरोधी कमजोर। कांग्रेस के 47 वर्षों के कुशासन और भाजपा नीत सरकार के निष्पादन के पाँच वर्षों की तुलना की जाए।

हमें लोगों को बताना चाहिए "आपने कांग्रेस को सभी स्तरों पर स्पष्ट बहुमत दिया तथा आपने देख लिया कि उन्होंने विकास के मोरचे पर क्या किया है। आपने देख लिया है कि उन्होंने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्या किया। आपने हमें सीमित जनादेश दिया, फिर भी आपके सामने पाँच वर्ष का सुशासन प्रस्तुत है। हमें भारत को और मजबूत तथा और अधिक विकसित राष्ट्र बनाने के एजेंडा पर कार्य करने के लिए और बड़े जनादेश की आवश्यकता है। अतः मिशन 2004 तथा विजन 2020 की यही पुकार है—शक्तिशाली भारत के लिए शक्तिशाली भाजपा।

भाजपा को राष्ट्र की ऐसी प्रथम पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करें, जो एक गरीब हितैषी, किसान हितैषी, युवा हितैषी पार्टी है तथा भारत के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

मैं इसी को रायपुर में आयोजित पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का प्रमुख संदेश कहना चाहूँगा।

धन्यवाद,

वंदेमातरम्



राष्ट्रीय परिषद्

नई दिल्ली 3 अगस्त, 2002

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी के अग्रणी नेताओं ने मुझे अनुगृहीत किया है। लाखों सह कार्यकर्ताओं ने इसका अनुमोदन किया और स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते समय आप सबने मुझे मन से आशीर्वाद दिया है।

आपके विश्वास और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने का मैं भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं अपनी पार्टी का नई सीमाओं, नई सामाजिक सरहदों तक विस्तार करने और साथ-ही-साथ अब तक हमें प्राप्त उपलब्धियों को समेकित करने का ईमानदारी से प्रयत्न करूँगा। यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट सदस्यों को वचन देता हूँ कि इस प्रयत्न में मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने दूँगा।

भाग-1

भूतपूर्व पार्टी-अध्यक्षों के प्रति श्रद्धा भाव

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी लघुता और पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्षों की महान्ता को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। वे सिंधु हैं तो मैं बिंदु। इसके पहले महान् नेताओं ने पार्टी का नेतृत्व किया है। मैं यहाँ 1980 से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की, यात्रा और 1951 से चली भारतीय जनसंघ की राजनीतिक और सैद्धांतिक यात्रा का उल्लेख करना चाहता हूँ। आज मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पावन स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

इस समय मैं डॉ. मुखर्जी के उन शब्दों को याद किए बिना नहीं रह सकता हूँ, जो उन्होंने भारतीय जनसंघ के 21 अक्तूबर, 1951 को आयोजित स्थापना सम्मेलन में कहे थे—

"मैं इस ऐतिहासिक सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जो भारत के इतिहास में महत्त्वपूर्ण तिथि बनकर संपन्न हो रहा है। मैं इस सत्य से अवगत हूँ कि हमारे सामने कठिन कार्य हैं। हमें कई बाधाओं को पार करना है और हमें शक्तिशाली विरोध का सामना भी करना है। जो बात हमें एकजुट करती है वह है कार्यपूर्ति हेतु स्वीकृत महान् लक्ष्य में हमारी अटल श्रद्धा, जिसके प्रति हमारी पार्टी कृतसंकल्प है और वे स्पष्ट समालोचनापरक उद्‌देश्य जो हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम सभी एकजुट व निर्भीक होकर साहस और उत्साह से आगे बढ़ेंगे और सही राह से नहीं भटकेंगे तथा जनता की सेवा और अपनी मातृभूमि के सम्मान और गोरव में वृद्धि करना ही अपना मूल उद्‌देश्य मानकर चलेंगे, तो निश्चय ही अंततोगत्वा हमें सफलता मिलेगी।"

उनमें कितना असीम आत्म-विश्वास था! वे कितने दृढ़ प्रतिज्ञ थे! और भारत माता के प्रति उनमें कितनी अटूट श्रद्धा थी!

डॉ. मुखर्जी ने ऐसी आशा और विश्वास उस समय व्यक्त किया था जब पार्टी अपनी शैशावावस्था में थी और कांग्रेस विशालकाय पार्टी थी। हम में ऐसी आशा और आत्मविश्वास तथा उसी प्रकार की अटूट वचनबद्धता क्यों नही हो सकती है जबकि हमने अपने परिश्रम द्वारा कांग्रेस का घमंड तोड़ दिया है।

मैं पार्टी के प्रतिष्ठित पूर्व अध्यक्षों के प्रति तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पुराने और सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं और अब भारत की एक अरब जनता के सबसे लोकप्रिय, सबसे प्यारे और सर्व सम्मानित नेता हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में श्री अटलजी का विशेष स्थान है जिसका उल्लेख मैं अभी करूँगा।

मैं श्री लालकृष्ण अडवाणीजी के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। वे हमारी पार्टी के शक्तिस्तंभ हैं तथा हमें राजनीतिक, सैद्धांतिक, संस्थागत और सबसे ज्यादा नैतिक शक्ति प्रदान करते हैं। बढ़ती प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बावजूद वे पार्टी के विकास में अथक और अनवरत प्रयास कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को प्रेरणा और मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

मैं परमादरणीय श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री कुशाभाऊ ठाकरे, श्री बंगारू लक्ष्मण और श्री जना कृष्णमूर्तिजी को धन्यवाद देता हूँ। मैंने इन सभी से कुछ-न-कुछ सीखा है और आशा करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहेगा।

पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से पार्टी के अध्यक्ष तक की यात्रा

आज मेरे राजनीतिक जीवन का एक विशिष्ट दिन है। मेरा हृदय भावनाओं और स्मृतियों से भरा हुआ है। पार्टी के अतीत की ओर देखते ही मैं चकित, उत्तेजित, अभिभूत होते हुए विनम्रता से भरा हूँ।

मेरा जन्म दक्षिण भारत के एक सुदूर गाँव में किसान परिवार में हुआ। अपने छात्र जीवन के दौरान मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेताओं की यात्राओं के दौरान दीवारों पर पेस्टर लगाता था, नारे लिखता था और माइक से नेताओं के आगमन का प्रचार करता था। आज उन्हीं दोनों वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पदभार मुझे सौंपा गया है। मैं समझता हूँ कि यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक कस्बे का साधारण कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यही हमारी पार्टी की शक्ति है यही उसकी विशेषता है। इसलिए हम सगर्व और सहर्ष कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग पहचान की पार्टी है।

बचपन में कबड्डी खेलने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में जाया करता था। मैंने कोई विशेष प्रयत्न तो नहीं किया, फिर भी संघ ने मुझे प्रभावित किया और मेरे मन में देशभक्ति और आदर्शवाद भर दिया। वहाँ के प्रचारक श्री भोगादि दुर्गा प्रसादजी के चुंबकीय व्यक्तित्व ने मुझे आकर्षित किया। इसी ने मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने मेरे मन में राष्ट्रीयता का बीज बोया। परिषद् ने मुझे एक सुशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में परिपक्व करने और युवा नेता के रूप में जन आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने के अवसर प्रदान किए। उन बुनियादी अनुभवों को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ।

मैं आपकी अनुमति से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता के रूप में अपने प्रारंभिक दिनों के अनुभवों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मैं तब कानून का विद्यार्थी था। उस समय अपने कुछ मित्रो के साथ गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक गाँव में सहपाठी के घर गया। उसके घर पर भरपेट खाना खाया और उसके तुरंत बाद गोदावरी के एक तट से दूसरे तट तक तैरने का निर्णय लिया। मेरा पेट इतना भरा हुआ था कि मैं नदी की आधी दूरी तक ही तैर सका। मुझे डूब जाने का भय लगा। मेरे मित्र बहुत आगे थे। मैं रक्षा के लिए चिल्लाने लगा; परंतु उस समय मेरे मस्तिष्क में यही विचार मँडराने लगा कि "मैं अटलजी को प्रधानमंत्री के रूप में देखे बिना इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ।"

परंतु नदी के दूसरे तट पर पशु चराने वाले कुछेक लोग मेरे बचाव के लिए आए और मुझे सुरक्षित तैराकर ले गए। मित्रो, यह कोरा सच है। उन दिनों मेरे जैसे परिषद् के अनेकों कार्यकर्ताओं पर अटलजी का ऐसा वशीभूत प्रभाव रहा

है कि लाखों लोग उनको प्रधानमंत्री के पद पर देखने का सपना लिया करते थे।

तदुपरांत मैंने विशाखापट्नम में अपने विश्वविद्यालय में युवाओं को संबोधित करने के लिए श्री जय प्रकाश (जे.पी.) जी को आमंत्रित किया। इसने मुझे जे. पी. आंदोलन में कूदने के लिए प्रेरित किया। हजारों लोकतंत्र समर्थकों की तरह ही आपातकाल के दौरान मुझे भी जेल भेजा गया और मैंने 17 महीने जेल में काटे। इस परीक्षण और कष्ट से भरे समय ने मुझे दृढ़ता प्रदान की और हमारी पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुझमें शक्ति प्रदान की।

भारत का हमारा स्वप्न

मित्रो! 25 साल पहले मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, उसके बाद देश के राजनीतिक माहौल में काफी परिवर्तन आया है। परंतु अपनी पार्टी के सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति हमारी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न कभी परिवर्तन होने वाला है। सत्ता हासिल करना हमारा ध्येय कभी नहीं रहा। हमारी दृष्टि में अधिकार या सत्ता महान् लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक साधन मात्र है। हमारा लक्ष्य है भारत का सर्वांगीण विकास। हमारा लक्ष्य भारत को सुरक्षित, सुदृढ, आत्मनिर्भर, सुसंपन्न और शांतिमय देश बनाना है जहाँ भुखमरी न हो, न भ्रष्टाचार हो, गरीबी न हो और विकास को अवरुद्ध करने वाली बुराइयाँ न हों। हमारा लक्ष्य भारत को एक समानतावादी देश के रूप में देखना है, जिसमें सभी देशवासियों को वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, भाषागत विभेदों के परे समान अवसर मिलें। हमारा लक्ष्य ऐसा भारत है, जो अपनी प्राचीन विरासत को पहचानकर, अपने सांस्कृतिक और कला वैभव को प्राप्त करे। हमारा लक्ष्य है, भारत पूरे विश्व में गरिमामय स्थान प्राप्त करे और वैश्विक स्तर पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। संक्षेप में, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक ही अर्थ है कि स्वर्णिम भारत का पुनर्निर्माण हो।

पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी ने एकात्म मानववाद पर दिए अपने अंतिम भाषण में इस लक्ष्य के बारे में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। यही वह लक्ष्य है जिसके लिए मैं अपने को पुनः समर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज पार्टी भी इसके लिए पुनः समर्पण करे।

पीढ़ीगत परिवर्तन : अनुभव तथा युवा शक्ति का सम्मिश्रण

बहुत से व्याख्याताओं ने मत व्यक्त किया है कि हमारी पार्टी में पीढ़ीगत परिवर्तन हो रहा है। यह सत्य भी है और सत्य नहीं भी है। हाँ, पार्टी के मेरे जैसे युवा प्रभारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब कि हमारा सौभाग्य है कि हमें अटलजी और आडवाणीजी जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं का निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग मिल रहा है। इस प्रकार अनुभवों से परिपुष्ट और ओजस्वी युवा पीढी का सुंदर समिश्रण हमारी पार्टी में दिखाई दे रहा है।

मैं राष्ट्रीय परिषद् को आश्वासन देना चाहता हूँ कि यद्यपि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं एक टीम भावना और सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत का कठोरता से पालन करूँगा। मेरा अनुचर सिद्धांत में विश्वास नहीं है। मैं सहचर सिद्धांत में ही प्रगाढ़ विश्वास रखता हूँ।

आधा रास्ता पार, मंजिल पाना शेष

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की यह बैठक उस समय हो रही है, जब देश अत्यंत नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहा है। पिछले चार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार सत्ता में है। सरकार की विभिन्न गतिविधियों के परिचालन में हमें कई अनुभव प्राप्त हुए हैं। प्रशासन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हमें स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए। स्थिति में सुधार लाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें अपनी कमियों और विफलताओं को पहचानकर उन्हें दूर करना है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, या राजनीतिक दल हो उसे सदा बड़ी ईमानदारी से अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने और अपेक्षित सुधार कर स्वयं को सक्रिय एवं सक्षम बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

हम सबके लिए यही उचित अवसर है कि हम अपनी पार्टी और सरकार के सामने आने वाली समस्याओं, वर्तमान राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए भावी कार्य प्रणाली के निर्माण पर विचार करें। इस प्रमुख मुद्दे पर विचार करना हमारा कर्तव्य है कि सत्तारूढ़ दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार की उपलब्धियाँ अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार रूपायित हुई हैं या नहीं। पार्टी और सरकार, दोनों स्तरों पर हमने, मेरी दृष्टि में, सफलता हासिल की है। इसका अर्थ यह नहीं कि इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी नहीं है। आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी और सरकार के स्तर पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाना है।

हमारा राजनीतिक रास्ता, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और एन.डी. ए. का एजेंडा

इस संदर्भ में मैं पार्टी अध्यक्ष पद स्वीकार करते समय की गई इस घोषणा को दोहरा रहा हूँ। एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और दूसरे हाथ में एन.डी.ए. का एजेंडा।

भारतीय जनता पार्टी की महत्त्वपूर्ण सफलताओं में सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न पार्टियों से एक विस्तृत संगठन का निर्माण करना। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह गठबंधन की सर्वाधिक

स्थिर केंद्रीय सरकार है। यह जनता की न्यायपरक क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण के सुंदर समन्वय को प्रति समर्पित है।

इस प्रयोग को भारतीय जनता पार्टी ने अत्यंत विचार विनिमय से अनुमोदन किया है। यह सत्ता के मोह में राजी होना नहीं है। यह देश को एक सुस्थिर और प्रयोजनकारी सरकार को देने के लिए मूल्यों के आधार पर किया गया सफल प्रयास है। हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे हितैषियों को इसके बारे में स्पष्टता से और हमारे प्रति विश्वास दिलाते हुए विवरण देना है। इसके लिए हमें शर्म या संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं।

हमारी पार्टी के मौलिक सिद्धांतों के विषय में भी हमें संकोच करने की या शरमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी पार्टी के मौलिक सिद्धांतों को हमने कभी नहीं छोड़ा है और न कभी छोड़ने वाले हैं। हमें इस विषय में सचेत होना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में हम एन.डी.ए. के एजेंडे की मूलभूत भावना से आगे बढ़ रहे हैं। अपने सिद्धांतों और आदर्शों को अपने सहयोगी दलों पर थोपने का सवाल ही नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी तथा इसके गठबंधन का प्रमुख लक्ष्य एन.डी.ए. को और मजबूत बनाना है। एन.डी.ए. के प्रयोग की सफलता केवल भारतीय जनता पार्टी की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी सहयोगी दलों की भी इसमें समान जिम्मेदारी है। यह तभी साध्य होगी जब हम सभी, गठबंधन सरकार के धर्म का सुचारु रूप से पालन करें। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एन.डी.ए. भागीदारियों के बीच निरंतर विचार-विनिमय की नितांत आवश्यकता है। विचार विनिमय द्वारा ही विभेदों को सुलझाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से ही भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं। गठबंधन सरकारों के लिए इस समय यह अनिवार्य है।

कांग्रेस पार्टी का बढ़ता गैर जिम्मेदाराना व्यवहार

भारतीय जनता पार्टी की सफलता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार की स्थिरता से विपक्षियों का मनोबल टूट गया है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और कांग्रेस की 'बी टीम' बने वामपंथी दल इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि वाजपेयी सरकार अपने पाँच साल के शासन काल को पूरा कर रही है। इसलिए संसद् में उनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बढ़ता जा रहा है। बिना किसी कारण के संसद् के कार्यकलापों में विघ्न डालना उनकी आदत बन गई है। संसद् में रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज का बायकाट न केवल प्रजातंत्र की भावना और मापदंडों के विरुद्ध है बल्कि संसद् के इतिहास में इसके पूर्व ऐसा कोई उदाहरण नहीं है।

निराशा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति गलत पूर्वग्रहों से ग्रसित होने के

कारण उनमें निम्न स्तर की नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। इसलिए उन्होंने 'पोटा' जैसे मुख्य कानून का भी विरोध किया। असल में 'पोटा' कानून तो श्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा 1986 में पारित 'टाडा' का सुधारात्मक रूप है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी एक शक्तिशाली कानून की आवश्यकता भी उनको नहीं सूझ रही है।

ऐसा गैर जिम्मेदार व्यवहार कांग्रेस के लिए नया नहीं है। मई 1998 में भारत को एक आणविक शक्ति के रूप में सन्नद्ध करने के ऐतिहासिक निर्णय का भी उन्होंने विरोध किया। कारगिल युद्ध के संदर्भ में एन.डी.ए. सरकार के प्रति कांग्रेस का विरोधी व्यवहार जनता के स्मृति पटल में अभी भी विद्यमान है और यहाँ तक उनके व्यवहार ने सीमाओं पर लड़ रहे सैनिकों के उत्साह को कमजोर करने के ढंग से प्रभावित किया है।

देश में सही सोच वाले सभी लोग इस बात से चकित रह गए कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो देश के सामने उपस्थित सभी जटिल समस्याओं को जानने का दावा करती है, क्योंकि उसके पास शासन का इतना लंबा अनुभव है क्या इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर सकती है; परंतु इस विकृति का कारण जानना कोई इतना कठिन कार्य नहीं है। एक ऐसा दल, जो प्रयोजनहीन हो गया हो, ऐसा नेतृत्व जिसके पास राष्ट्र के भाग्य के प्रति कोई दूरदृष्टि न हो, केवल ऐसा संगठन जिसने अपनी विचारशक्ति मार्क्सवाद के पास गिरवी रख दी हो इस प्रकार की हीनता और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर सकता है।

यह व्यवहार उस व्यवहार के कितने विपरीत है जो हमारे संस्थापक डॉ. मुखर्जी ने अपने कथन के द्वारा दिया, जिसका पालन हम अनेक वर्षों तक विपक्ष में रहकर करते आए हैं, उन्होंने हमें उपदेश दिया कि

"विपक्ष का अभिप्राय सभी समस्याओं के प्रति उस तर्कहीन अथवा विनाशकारी दृष्टिकोण से नहीं है जिनका सामना प्रत्येक जिम्मेदार सरकार को करना पड़ता है। अतः हमें सरकारी उपायों अथवा अधिनियमों की आलोचना करना आवश्यक हो सकता है; परंतु हमारा उद्देश्य सभी समस्याओं को रचनात्मक ढंग से हल करने की ओर होना चाहिए; जिससे जनता चेतनशील रहे और हम देश के सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए वास्तविक प्रजातांत्रिक ढाँचे के विकास में अपना विनम्र योगदान दे सकें।"

यहाँ हमारे नेता श्री वाजपेयीजी के संसदीय आचरण का उल्लेख करना उचित होगा, जो चार दशकों तक विपक्ष में बैठे।

कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में सत्ता में हो सकती है, परंतु यह हमारे देश के सम्मुख प्रमुख मुद्दों का निदान करने में और देश को महान्ता एवं गौरव प्रदान करने में अक्षम है। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है।

आज की राजनीतिक स्थिति में मेरा सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हमें कांग्रेस तथा कम्युनिस्टों की अस्थिरताकारी गतिविधियों से चौकन्ना रहना होगा। हमें कांग्रेस पार्टी का प्रभावी ढंग से सामना करना होगा और उसे निर्णायक हार देनी होगी। तभी वह वास्तविक रूप में अपने आपको बदलने का मार्ग अपनाने पर बाध्य होगी। हम अपनी सोच में प्रगतिशील हैं। अब हमें कांग्रेस तथा कम्युनिस्टों की सम्मिलित अदूरदर्शी राजनीतिक मिलीभगत का सफाया करने के लिए आक्रमणशील कार्यवाही करनी चाहिए।

धर्म निरपेक्षता का स्वरूप—सत्य और असत्य

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के प्रयोग की सफलता ने हमारी पार्टी के प्रति विपक्षियों द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार का विफल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को देश को विध्वंस करने वाली सांप्रदायिक दल के रूप में चित्रित कर इन छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने हमें देश के राजनीतिक धरातल पर अलग करने की कोशिश की, परंतु इस दुष्प्रचार में उनकी घोर पराजय हुई है।

हमें दूसरों से धर्म निरपेक्षता का सबक सीखने की जरूरत नहीं। धर्म निरपेक्ष समाज की हमारी महान् परंपरा रही है। समय की थपेड़ों से हमने अपने धर्मनिरपेक्ष स्वभाव को सदा सुरक्षित रखा। हमें सर्व पंथ समादर (सर्व धर्म सम भाव) में अटल विश्वास है। सर्व धर्म समभाव के मूल सिद्धांत भारतीयों का लहू में सदा जीवित रहा। समाज के सभी वग ों की भलाई और सभी धम ों के लोगों के कल्याण के प्रति हम कटिबद्ध हैं। हम अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति और वोट पाने के लिए किसी एक वर्ग को लालच देने में विश्वास नहीं रखते।

ज्यों-ज्यों हमारा विस्तार हो रहा है त्यों-त्यों हमारे विस्तार को पचाने में वे असमर्थ हो रहे हैं। जनता द्वारा उन्हें नकार देने से उनकी हताशा बढ़ी है। वे समाचार माध्यमों से हमारे विरुद्ध दुष्प्रचार अभियान छेड़े हुए हैं। वे झूठी बातें फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक तरफ वे यह संकेत देकर कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक एजेंडे को छोड़ दिया है, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं, दूसरी तरफ वे हमारे सहयोगी दलों तथा तटस्थ सहयोगियों को यह कहकर हमसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने छुपे हुए एजेंडे को कार्यान्वित कर रही है। इससे उनके दिवालिएपन का पता चलता है। मैं चाहूँगा कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता उनके दुष्प्रचार का राजनीतिक और बौद्धिक मंचों पर मुँहतोड़ जवाब दें। इसके लिए हमें प्रचार और प्रसार विभागों, बुद्धिजीवी वर्गों तथा सांस्कृतिक संसाधनों के द्वारा एवं व्यापक जन अभियान के द्वारा मुँहतोड़ जवाब देना होगा।

जम्मू-कश्मीर : स्वायत्तता नहीं, क्षेत्रीय अधिकारों में वृद्धि, पर हाँ

जम्मू और कश्मीर की समस्या के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि वह भारत का अभिन्न अंग है। दुनिया की कोई भी ताकत इस प्रदेश से एक इंच तक की जमीन को भी अपने कब्जे में नहीं ले सकती। यह भू-भाग भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है। पड़ोसी देश के साथ इस समस्या को लेकर एक ही बात पर विचार करना संभव है, वह है पाक द्वारा अधिकृत कश्मीर।

हम अधिकारों के विकेंद्रीकरण के पक्ष में हैं। जम्मू-कश्मीर को अधिक अधिकार देने के संबंध में भी हमारी धारणा इसी राष्ट्रीय नीति की परिधि में है। हमारे देश के अंतर्गत एक स्वायत्त राज्य कभी नहीं रह सकता है। सन् 1953 के पूर्व की स्थिति को पुनः कायम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि इसपर कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो हमारा एक ही सीधा समाधान है—नहीं, नहीं।

जब हम अधिकारों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो हम सदा जम्मू, लद्दाख और लेह प्रांतों की क्षेत्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को दृष्टि में अवश्य रखते हैं। इन तीनों इलाकों के लोगों की विभेदकारी नीतियों से संबंधित अलगाव वाली शिकायतों पर राज्य एवं केंद्र सरकार को वरीयता के ढंग से ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में किसी भी आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों का गौरवशाली इतिहास

पिछले चार सालों से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषणा-पत्र में दिए गए आश्वासनों की पूर्ति हेतु हमारी सरकार ईमानदारी से, निष्ठा से सतत प्रयत्नरत है। देश के संपूर्ण विकास के लक्ष्य को लेकर सामाजिक कल्याण के कई कार्यक्रमों की निश्चित योजनाएँ बनाकर काम करने में लगी है। मातृभूमि की सुरक्षा को कायम करने के लिए आवश्यक सभी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को और शक्तिशाली बना दिया है। इससे आंतरिक सुरक्षा की स्थिति काफी सुधरी है।

पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक आक्रमण

पाकिस्तान को विश्व मंच पर आतंकवाद का केंद्र स्थान साबित करने में हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की है। इसी कारण से अंतरराष्ट्रीय दवाब डालकर पाकिस्तान को अकेला बनाने और उसे दोषी ठहराने में हमें सफलता मिली। पाकिस्तान द्वारा अभिप्रेरित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अभियान को चलाने के लिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, उन्हीं के फलस्वरूप हमें विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। पिछले पाँच दशकों मे ऐसा कभी नहीं हुआ जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद

के मामलों में हमारा समर्थन और प्रशंसा की।

आतंकवाद मानव-जाति का दुश्मन है। भारत आतंकवाद का बुरी तरह से शिकार बना है। आश्चर्य की बात यह है कि जिन पाश्चात्य देशों ने आतंकवाद के उन्मूलन की प्रतिज्ञा की, उन्हीं देशों ने पाकिस्तान का, अपने निजी हितों के लिए, आश्रय लिया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंतकवाद का मुख्य केंद्र बन गया है। पाकिस्तान ने तालिबान में आंतकवाद का समर्थन किया और उसे आर्थिक सहायता पहुँचाई। उसी प्रकार उसने अलकायदा को शस्त्र देकर भारत के विरुद्ध युद्ध करने, उसे एक हथियार के रूप में उपयोग किया। सरकार को चाहिए कि वह निरंतर पश्चिमी देशों पर यह दबाव डाले कि वे पाकिस्तान पर, आतंकवाद को अंत करने के लिए दबाव डालें और जनता को हमें यह याद दिलाना होगा कि हमें आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई स्वयं लड़नी है तथा उसे जीतना है।

अर्थव्यवस्था : कमी से सरप्लस तक

अर्थव्यवस्था में कमी को सरप्लस में परिवर्तित कर दिया गया है, हमारे अनाज के गोदाम अनाजों से भरे हुए हैं। सार्वजानिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटनों को दुगना कर दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों को कम मूल्य पर अधिक सामान दिया जा रहा है। देश में खाद्य स्थिति पूर्णतया सुरक्षित है। अनाज के इस रिकॉर्ड उत्पादन के लिए मैं अपने मेहनतकश किसानों को धन्यवाद देता हूँ। आज भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है।

विदेशी मुद्रा के भंडार आज सर्वाधिक उच्च्च स्तर पर हैं। आज हमारा देश सगर्व घोषित कर सकता है कि 60 मिलियन टन खाद्य सामग्री और लगभग 60 बिलयन डालर विदेशी मुद्रा का भंडार है। मुद्रा स्फीति की दर सबसे कम है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से रखा गया है। नियंत्रणों को हटाने और मानव ऊर्जा के सदुपयोग से सूचना प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। ऑटो तथा दवा उद्योगो ने विश्व स्तर की गुणवत्ता प्राप्त की है। आज उपभोक्ता अपनी पसंद की, क्वालिटी की तथा लागत की वस्तुएँ खरीद सकते हैं।

अभी कुछ समय पहले की बात है, जब एक समय पर हमें टेलीफोन कनेक्शन लेने अथवा गैस का कनेक्शन लेने के लिए वष ों इंतजार करना पड़ता था। आज ये चीजें माँग पर उपलब्ध हैं। दूर संचार सेवाओं के क्षेत्र में हमारी पहले की सरकारें जो 40 वष ' में नहीं कर सकीं, उसे हमने केवल 4 वर्ष में प्राप्त कर लिया है। हमने कीमतें बढ़ने की बात तो सुनी है, परंतु यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दरों में भारी गिरावट आई है।

ग्रामीण तथा शहरी विकास

हमें इस बात पर खुशी है कि हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने के लिए बजटीय आवंटनों में वृद्धि की है। 10 हजार करोड़ रुपए के आवंटन से संपूर्ण ग्रामीण योजना शुरू की गई है। इसमें 5 हजार करोड़ रुपए के मूल्य का अनाज देने की व्यवस्था है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम के लिए अनाज तथा संपदा का सृजन करने के कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जिस पैमाने पर भवनों का गृह निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह भी अभूतपूर्व है।

किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में नियमित रूप से वृद्धि, फसल बीमा योजना आरंभ करना, लगभग 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, ग्रामीण ऋणों को 40 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपए करना—ये सभी कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता को दरशाते हैं।

दो वर्ष पूर्व हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की थी। इससे ग्रामीण भारत का दृश्य ही बदल जाएगा। वर्ष 2007 तक देश के ऐसे सभी ग्रामों को जोड़ने की हमारी योजना है जिन्हें अभी तक सड़क द्वारा जोड़ा नहीं गया है। इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति आ जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तेज गति से कार्यान्वयन के कारण भारत के राजमाग ' को बनाने के काम में भी क्रांति आई है। अगले 5 वष ' में इन दोनों सड़क परियोजनाओं पर 120,000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए जाएँगे। ये दोनों परियोजनाएँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक प्रतिष्ठित योजनाएँ हैं।

हम विकेंद्रीकरण के द्वारा पंचायती राज्य प्रणाली को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के कार्य में आम सहमति बनाने में सफल रहे हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य

प्रधानमंत्रीजी अर्थव्यवस्था की निरंतर समीक्षा करते हैं और विकास में आने वाली अड़चनों को दूर करने के बारे में मार्गदर्शन देते रहे हैं। इन उपायों में विशेष निर्यात-जोनों को बनाने की महत्त्वाकांक्षी योजना शामिल है, जो भारत को एक प्रमुख निर्यातक देश बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। डब्ल्यू-टीओ की चुनौतियों का सामना करने के लिए एंटीडम पग उपायों सहित कई उपाय करके स्वदेशी उद्योगों को सुरक्षा दी गई है। लघु उद्योगों और खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है। ऐसा पहली बार है जब सरकार ने रेलवे सुरक्षा की व्यापक योजना को कार्यान्वित करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की राशि दी है। बीमा क्षेत्र में प्रति स्पर्धा की एक नई भावना जाग्रत् हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना करने के उद्देश्य से विनिवेश की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के

साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसी के साथ-साथ सरकार ने सामाजिक क्षेत्र पर भी अपना अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर दिया है। सर्व शिक्षा अभियान, महिलाओं के लिए राज राजेश्वरी योजना, बालिकाओं के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना, असंगठित कामगारों के लिए आश्रय बीमा योजना तथा झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के लिए वाल्मीकि-अंबेडकर योजना आदि जैसी कुछ योजनाएँ इसके उदाहरण हैं।

सरकार ने चुनाव तथा न्यायिक सुधारों की दिशा में भी कुछ कदम उठाए हैं। कुछेक पुराने अधिनियमों को रद्द कर दिया गया है। एक नए सिविल प्रोसीजर को लाया गया है, जिससे न्याय में मिलनेवाले विलंब में कटौती हुई है।

पहली बार हमारी सरकार ने स्कूलों के पाठयक्रमों तथा शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम में अनेक खामियों को दूर करने का साहस दिखाया है, जो वष ' पुराने उपनिवेशवाद और साम्यवाद से प्रभावित थी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों की सुरक्षा

हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वग ' के लाभ के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। कांग्रेस समर्थित पिछली यूनाइटेड फ्रंट सरकार द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण के बारे में जारी किए गए 5 कार्यालय ज्ञापनों को संशोधित किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने तथा उनका विस्तार करने के लिए संविधान विषयक एक संशोधन लाया गया है।

उपर्युक्त सूची एक संकेत मात्र है, न कि संपूर्ण। इससे यह पता चलता है कि किस प्रकार हमारी सरकार अनेक कठिनाइयों के बावजूद जनता के साथ किए गए वायदों को पूरा करने का प्रयास कर रही है।

एन.डी.ए. सरकार का घोटाला रहित रिकॉर्ड

पिछले शासनों के घोटालों तथा घपलों के रिकॉर्ड की तुलना में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपना स्वच्छ रिकॉर्ड बनाए रखा है। समय-समय पर कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट हताशा में हमारी सरकार की छवि को खराब करने के लिए आरोप लगाते रहते हैं; परंतु उनके कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

जी हाँ, हमारी सरकार के खाते में अनेक उपलब्धियाँ हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में हमारी पार्टी काफी पीछे है और हमारी सरकार भी काफी पीछे है, वह है इन उपलब्धियों के अलावा हमारे विभिन्न नीतियों/कार्यक्रमों तथा हमारी भावी योजनाओं के बारे में जनता को प्रभावशाली ढंग से बताना। हमें इस कमजोरी से दृढ़तापूर्वक तथा गतिपूर्ण ढंग से निपटना होगा।

विकास : सुधार के लिए तेज प्रयासों की आवश्यकता

वाजपेयीजी की सरकार आर्थिक सुधारों को गति प्रदान करने के लिए बधाई की पात्र है। इसमें आगे और सुधार किए जाना आवश्यक है।

ऐसे कई अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका निवारण अविलंब किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, अनेक राज्यों में बिजली की स्थिति चिंताजनक है। निस्संदेह रूप से यह अनेक वष ' की लापरवाही तथा कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में किए गए सुधारों में रह गई आरंभिक गंभीर कमियों का परिणाम है। यह सही है कि बिजली राज्य का विषय है, परंतु इस बारे में उपचारात्मक काररवाइयाँ किया जाना भी राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। फिर भी, केंद्र सरकार को इस व्यापक समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे सभी पार्टियों की आम सहमति बन सके।

इसी प्रकार देश के अनेक भागों में सूखे की समस्या से निपटने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास करने होंगे और तत्काल राहत उपाय करने होंगे और हमारी कृषि को सूखे से बचाने के लिए स्थायी उपाय करने होंगे।

हमें काफी समय से सुधार एजेंडे में अनिर्णित पड़े अनेक मसलों, जैसे राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति सही न होने, अलाभकारी सहायता राशि न देना, चिर प्रतीक्षित श्रम सुधारों आदि के क्षेत्र में सहमति बनानी होगी, जैसाकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में उल्लेख किया गया 8 प्रतिशत की सकल उत्पादन दर को प्राप्त करने के लिए ऐसा आवश्यक है, फिर भी हमें जनता को अल्पकारी तथा अस्थायी कठिनाइयों के बारे में बताना आवश्यक है, जिन्हें उनके द्वारा हमारे दीर्घकारी विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामना करना पड़ेगा, जिससे हमारे सभी नागरिकों को लाभ होगा, जिसके लिए सरकार अपना कल्याणकारी तथा विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी।

राजनीतिक दलों से मेरी अपील

इन विकासात्मक विषयों के अतिरिक्त देश के लिए आवश्यक है कि वह राजनीति में धन-शक्ति तथा गुंडागर्दी के कुप्रभाव को समाप्त करने के लिए उपाय करे। मैं सभी राजनीतिक दलों से एक अपील करना चाहूँगा कि

"आओ, हम सब मिलकर संसद् तथा राज्य विधानसभाओं में तथा उनके बाहर राजनीतिक पतन के स्तर को ऊँचा उठाए। हमें जनता से संबंधित पहलुओं तथा जनसंख्या नियत्रंण, पर्यावरण, जल संरक्षण आदि जैसी राष्ट्र के सम्मुख चुनौतियों की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हम राजनीति के प्रति दुर्भावना की अवधारणा को दूर करें तथा आम जनता के हृदय में राजनीतिज्ञ की छवि को सुधारें। यही वह समय है जब हमें राजनीति तथा जनजीवन में नकारवाद को दूर करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा।

हमें यह याद रखना होगा कि हम एक-दूसरे के शत्रु नहीं हैं। हम इस प्रजातंत्र में मात्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं।

"बार-बार हड़तालों तथा बंद से आम जनता को असुविधा होती है तथा राजनीतिक एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से सार्वजानिक संपत्ति को हानि पहुँचाने आदि की हम सभी के द्वारा भर्त्सना की जानी चाहिए। इसके विपरीत हमारा उददेश्य अधिक उत्पादन द्वारा विकास करना होना चाहिए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु हमें अपने प्रधानमंत्रीजी के इस आह्वान—विकास, विकास, तेजी से विकास तथा संतुलित विकास—पर अमल करना चाहिए।"

भाग-2

पार्टी के सम्मुख वर्तमान चिंताएँ तथा भावी चुनौतियाँ

प्रिय प्रतिनिधियो,

जो कुछ मैंने ऊपर कहा है वह यह दरशाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के समय से ही एक लंबा रास्ता तय किया है। परंतु आत्म-संतोष के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे समाज तथा हमारी राज्य व्यवस्था के सामने अनेक प्रमुख चुनौतियाँ हैं। मैं अब उनका उल्लेख करूँगा। सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी के सम्मुख तात्कालिक राजनीतिक कार्य का उल्लेख करूँगा। संगठनात्मक काय ' के बारे में मैं कुछ समय बाद उल्लेख करूँगा।

मस्तिष्क में एक ही विचार तथा मुख में एक ही स्वर—विजय

निस्संदेह रूप से भारतीय जनता पार्टी आज भारत में प्रमुख राजनीतिक दल है। हमने बहुत पहले वर्ष 1996 में कांग्रेस को इस स्थान से खदेड़ दिया था तब से लेकर अब तक देश में दो राष्ट्रीय दलों—भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस के प्रतिनिधित्व वाली दो प्रमुख धुरी के इर्द-गिर्द राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। यद्यपि हमारी पार्टी सशक्त से सशक्त होती जा रही है तथापि हमें यह मानना होगा कि हमने कांग्रेस के पतन से उत्पन्न अवसरों का दोहन करने के पूर्ण प्रयास नहीं किए।

अतः पार्टी के सम्मुख यह तात्कालिक कार्य सर्वविदित है। सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि हम अपनी दूरदृष्टि को इस प्रकार से रखें कि गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में हम पूर्ण जनमत से जीतें और जम्मू तथा कश्मीर में भी बेहतर प्रदर्शन करें। इसके साथ-साथ हमें अगले वर्ष 9 अन्य राज्यों में, जिनमें मध्य प्रदेश तथा राजस्थान जैसे महत्त्वपूर्ण राज्य भी शामिल हैं, विधानसभा चुनावों के लिए अपने को मजबूत बनाना होगा। जिन राज्यों में आवश्यक है हम पुनर्संरचना भी कर रहे हैं।

इस वर्ष तथा आगामी वर्ष जिन राज्यों में चुनाव होंगे, मैं उन राज्यों में पार्टी

के सभी तथा प्रत्येक कार्यकर्ता से यह अपील करता हूँ कि वे अपने मन में जीत के निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें। हमारे मस्तिष्क में तथा हमारे मुख से एक ही स्वर निकलना चाहिए—विजय। तभी हम सफल हो सकते हैं।

भारतीय जनता पार्टी के विकास का दोहरा उद्‌देश्य

राज्य विधानसभा के आगामी चुनावों में विजय के लिए तैयारी करने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य के साथ-साथ हमारा लक्ष्य अपनी पार्टी का सर्वव्यापी (सभी क्षेत्रों का समावेश करके) तथा सर्वस्पर्शी (समाज के सभी वग र्ों को शामिल करके) आधार पर अपना क्षेत्रीय तथा सामाजिक आधार बढ़ाना है।

वर्ष 1951 से हमने मात्र आधी राजनीतिक यात्रा पूरी की है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम सर्वव्यापी बने और सभी तक पहुँचे, जिससे हम सुस्थिर आधार पर व्यापक जनाधार प्राप्त कर सकें। अतः हम सबके लिए आवश्यक है कि हम भारतीय जनता पार्टी को लघु भारत का रुख दें।

त्वरित क्षेत्रीय विस्तार

हमने अपने आधार में अंडमान से असम तक तथा कन्याकुमारी से कश्मीर तक विस्तार किया है; परंतु हाल के समय में हमें कुछेक उन राज्यों में धक्का पहुँचा है जहाँ हम पहले अधिक मजबूत थे। इसके लिए गहन विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। हमें देश के दक्षिणी, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना होगा।

उदाहरण के तौर पर कुछेक ऐसे राज्य हैं, जो परिस्थितियाँ अनुकूल होने के बावजूद हमारी पार्टी प्रगति नहीं कर पाई है। पश्चिमी बंगाल तथा केरल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन राज्यों में कम्युनिस्टों का आधार तेजी से समाप्त होता जा रहा है तथा कांग्रेस में भारी गुटबाजी है। जनता किसी सक्षम विकल्प की ओर आस लगाए बैठी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अवसर के अनुकूल लाभ उठाने में असमर्थ रही है। मैं इन दोनों राज्यों की पार्टी इकाइयों से यह निवेदन करूँगा कि वे ईमानदारी से अपना आत्म-विश्लेषण करें। एक नई रणनीति तैयार करें तथा आगामी कुछ वर्षों के भीतर कामयाबी पाने के लिए अपने प्रयास दुगुने करें।

त्वरित सामाजिक विस्तार

हमारा समाज विविधता लिये हुए है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दो दशकों में समाज के अनेक नए वग र्ों को अपनी परिधि के दायरे में लिया है तथापि इनमें से कुछेक वर्ग अभी भी हमारी पहुँच के बाहर हैं। हमें इन्हें अपने नजदीक लाना आवश्यक है। हमारे दल के सुस्थिर विकास तथा चुनावों में भावी सफलता के लिए दो श्रेणियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। प्रथम श्रेणी में किसान, ग्रामीण कारीगर,

बुनकर, मछुआरे तथा असंगठित कामगार; दूसरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग तथा अन्य पिछड़े वग ' में अति पिछड़े लोग शामिल हैं तथा सामाजिक दृष्टि से बहिष्कृत वग ' में यद्यपि हमारा जनाधार काफी बड़ा है तथापि इसमें और वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है।

किसान

जैसाकि अनेक राज्यों में हमारा सफल अनुभव रहा है। किसानों को अपनी पार्टी के प्रति आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम नियमित रूप से व्यापक आंदोलनों के माध्यम से ग्रामीण जनता से संबंधित मसलों को उठाएँ और सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों से उन्हें अवगत कराएँ।

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग

अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा कमजोर वग ' को अपनी पार्टी के प्रति आकर्षित करने के लिए हमें इसी प्रकार के उपाय करने होंगे। हमें सामाजिक न्याय के उनके औचित्यपूर्ण मुददों को भी उठाना होगा। उनके साथ अन्याय तथा उनपर अत्याचारों की घटनाओं पर उन्हें एकजुट करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को प्रमुख भूमिका निभानी होगी इससे उनके तथा हमारी पार्टी के बीच एक भावनात्मक रिश्ता कायम करने में सहायता मिलेगी। लेकिन ऐसा करते समय हमारे कार्यकर्ताओं को यह भी ध्यान में रखना होगा कि सामाजिक समरसता को हानि न पहुँचे।

अल्पसंख्यक

हमारे प्रतिद्वंद्वियों द्वारा गलत सूचना देने के अभियान के परिणामस्वरूप हमारी पार्टी और अल्पसंख्यकों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। हमें इसपर गहराई से ध्यान देना आवश्यक है और उनका हृदय जीतने के लिए एक कार्ययोजना बनाना आवश्यक है। इस प्रयास में हमारी सरकार के कार्यक्रम तथा अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण का हमारे कार्यकर्ता सदुपयोग कर सकते हैं।

महिलाएँ

पिछले वष ' में महिलाओं के बीच हमारे पार्टी के कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फिर भी, हमें यह मानना होगा कि हमें अपनी पार्टी संगठन में तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल करने के लिए भरसक प्रयास करने होंगे। हम पार्टी के संविधान में की गई व्यवस्था से आगे महिलाओं को चयनित निकायों में अधिक प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण से राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी के अवसरों में वृद्धि हुई है। जल्दी ही हम संसद् तथा राज्य विधानसभाओं में उन्हें

इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने से संबंधित कानून को पारित करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इससे देश में एक शांतिपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक क्रांति होगी। हमारी पार्टी को न केवल अपने आपको इस बारे में तैयार करना होगा बल्कि इस क्रांति का नेतृत्व भी करना होगा। इसके लिए हमारी पार्टी की सभी इकाइयों को समर्पित तथा सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए उत्साहित करना होगा। हमें अपने महिला मोरचा के कार्यक्षेत्र का भी तेजी से विस्तार करना होगा।

स्वैच्छिक तथा ठोस कार्य

आनेवाले वष ' में हमारी पार्टी को जिस एक नए क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना होगा, वह है स्वैच्छिक क्षेत्र तथा जल संरक्षण, वृक्षारोपण, साक्षरता अभियान, जनसंख्या नियंत्रण, ग्राम सभाओं के आयोजन में ग्रामीण जनता की सहायता करना आदि जैसे ठोस उपाय। हमारे कार्यकर्ताओं को अच्छी गैरसरकारी संस्थाओं के साथ सक्रिय संबंध स्थापित करने चाहिए और जहाँ कहीं संभव हो अपने गैरसरकारी संगठन स्थापित करने चाहिए। उन्हें सहकारी, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थाएँ, सामाजिक सुधार दल आदि स्थापित करने चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ इन सभी गतिविधियों में पार्टी के युवाओं को एकजुट करने में सहायता मिलेगी, जो ठोस ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इससे जनता के साथ पार्टी के संपर्क में वृद्धि होगी और संबंध मजबूत होंगे। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा ऐसी गतिविधियों को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

पार्टी प्रकोष्ठ

अभी हाल में हमने मौजूदा पार्टी प्रकोष्ठों की पुनर्संरचना की है और उनकी संख्या में वृद्धि की है, ताकि बुनकरों, मछुआरों, झुग्गी झोंपड़ी निवासियों, बीड़ी कामगारों, असंगठित श्रमिकों तथा विविध व्यावसायिक समूहों को इसमें शामिल किया जा सके। राष्ट्रीय मामलों में शहरी भारत की महत्ता में वृद्धि को देखते हुए हमें स्थानीय स्तर पर बेहतर शासन देने के लिए एक नए प्रकोष्ठ का सृजन करना होगा। इसी प्रकार हमें पंचायती राज्य संस्थाओं में बेहतर शासन के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करना होगा। मैं यह चाहूँगा कि हमारी राज्य तथा जिला इकाइयाँ अपने स्तर पर इस प्रकार के प्रकोष्ठों की स्थापना करें। ऐसा करते समय हमारा मूल उददेश्य यह होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को अधिक विकासोन्मुख तथा जनता के कल्याण पर ध्यान देने वाला बनाएँ।

भाग–3

आओ, हम अपनी पार्टी की एक अलग पहचान बनाएँ

मित्रो, मैंने उन विषयों को छुआ है जो कार्य हमने अभी तक किए हैं। मैंने उन विषयों को भी छुआ है जो हम अपनी प्राप्तियों को संचित करने तथा आगे बढ़ने के लिए करेंगे। अब मैं यह बताना चाहूँगा कि हम किस प्रकार यह करेंगे।

इसका उत्तर स्पष्ट है कि हमें पार्टी की एकता तथा शक्ति में विश्वास करना होगा। यह हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुशासन, समर्पण तथा सक्रियता पर निर्भर करता है। यह आदर्शवाद तथा हमारे समर्पित नेताओं, विचारधाराओं के प्रति वचनबद्धता तथा जनता को जुटाने तथा उन्हें प्रेरित करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

यही वह विशेषता है जिससे जनता यह विश्वास करती है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ की तरह ही एक अलग पहचान वाली पार्टी है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य दलों के बीच अंतर स्पष्ट दिखलाई देता है, जिनमें से अनेक दल सत्ता राजनीति का शिकार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह छवि ही हमारी पार्टी की शक्ति का प्रमुख स्रोत है और यही स्रोत आज भी विद्यमान है।

फिर भी, हमें अपने आपसे यह पूछना चाहिए कि 'क्या हम अपनी पार्टी के संस्थापकों द्वारा स्थापित आदश ' का पूर्णतया पालन कर रहे हैं?' 'क्या हम जनता की आंकांक्षाओं पर पूर्णतया खरे उतर रहे हैं?'

इन सभी प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर देने पर हमें यह स्वीकार करना होगा कि हाल के वर्षों में हमारे पार्टी संगठन में कुछेक समस्याएँ तथा कमजोरी आई हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि घटकवाद, घटकों में लड़ाई, सत्ता की लालसा, पार्टी हितों के मूल्य पर व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति जैसी कुछ अवांछनीय तथा अस्वीकार्य प्रवृत्तियाँ हमारी पार्टी में प्रवेश कर गई हैं। ये सभी विशेषताएँ कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों में विराजमान थीं। इससे कुछेक राज्यों में हमारी पार्टी को हानि हुई है।

समय की माँग—आत्म विश्लेषण

स्पष्ट रूप से सभी स्तरों पर हम सभी के लिए वह समय आ गया है जब हम कुछ गंभीर और निष्ठापूर्वक आत्म–विश्लेषण करें और तत्काल उपचारात्मक उपाय करें। पार्टी के प्रत्येक सदस्य को अपनी–अपनी कमियों को दूर करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करने होंगे। मैं बलपूर्वक यह कहना चाहूँगा कि पार्टी को ऐसी अवांछनीय प्रवृत्तियों को ठोस ढंग से दूर करना होगा। यदि पार्टी आत्म–चेतना तथा समय पर आत्म–चिंतन के इस कार्य में असमर्थ रहती है तो यह समस्या विकट रूप धारण कर लेगी। इस संबंध में आत्मसंतोष करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

अपने आत्म-मंथन की इस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का एक महत्त्वपूर्ण तरीका यह है कि हम अपने आपको यह स्मरण कराएँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिह्न कमल है, जोकि एक ऐसा महान् तथा पावन पुष्प है जो कीचड़ में उगने के बाद भी उससे अछूता रहता है।

अभी कल हमने अपने नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के लिए 'ऐसा करें तथा ऐसा न करें' के स्पष्ट संकेतों से एक आचार संहिता जारी की है। अलग पहचान वाली पार्टी के रूप में अपनी छवि में सुधार करने के लिए इस आचार संहिता पर कठोरतापूर्वक पालन करना एक नई दिशा प्रदान करेगा।

इस संदर्भ में पार्टी को पुनः सशक्त बनाने के लिए चल रहे हमारे प्रयासों में मैं कुछ विशिष्ट विचार तथा सुझाव देना चाहूँगा—

1. अधिक निष्ठा, अधिक प्रतिबद्धता तथा बेहतर संगठन

केंद्र में शासक दल होने के पश्चात् हमारे सम्मुख दायित्व में वृद्धि हुई है। इन व्यापक काय ' तथा राजनीतिक दृढ़ीकरण तथा विस्तार की पूर्ति हेतु विभिन्न स्तरों पर हमारे नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को अधिक निष्ठा तथा प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। हमें यह कार्य सुसंगठित तथा प्रणालीबद्ध तरीके से करना होगा।

तदनुसार, मैंने एक नई व्यवस्था के तहत सभी केंद्रीय पदाधिकारियों को उनकी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों का आवंटन किया है। राजनीतिक प्रबंध व्यवस्था तथा सामाजिक विस्तार का कार्य महासचिवों तथा उपाध्यक्षों में से किसी एक उपाध्यक्ष द्वारा देखा जाएगा। वे इस संबंध में राज्य इकाइयों का मार्गदर्शन करेंगे। प्रभारी केवल संगठनात्मक मामलों, संगठनात्मक तंत्र का विस्तार, पार्टी की स्थिति तथा विभिन्न स्तरों पर पार्टी तंत्र के कार्यक्रम को देखेंगे।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि राज्य की पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों तथा संबंधित राज्य के संसद् सदस्यों, प्रभारियों तथा केंद्रीय पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय होना आवश्यक है।

2. चुस्त रहो, भ्रमणशील रहो

हमारा देश विशाल है और हमने अपनी सीमाओं का विस्तार करने और नई ऊँचाइयों को छूने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। हम इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? इसका एकमात्र रास्ता यह है कि हम दिल्ली तथा अपने संबंधित राज्य मुख्यालयों से बाहर जाएँ। हमें देश के प्रत्येक कोने-कोने में जाना होगा। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने, उनकी समस्याओं तथा विकास की जानकारी लेने तथा पार्टी तंत्र को

सशक्त बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों द्वारा निरंतर दौरे करने का कोई विकल्प नहीं है। केवल एक बार दौरा करने से काम नहीं चलेगा। इन्हें नियमित रूप से करना चाहिए।

यहाँ हमें दीनदयालजी के उदाहरण पर अमल करना आवश्यक है—"एक पाँव रेल में दूसरा जमीन पर।" हमारे सम्मुख सर्वश्री अटलजी, आडवानीजी, जोशीजी तथा ठाकरेजी के प्रेरणात्मक उदाहरण है जिन्होंने थकान की परवाह न करते हुए भी देश के कोने-कोने में पार्टी का प्रचार किया और एक-एक ईंट जोड़कर पार्टी संगठन का निर्माण किया।

पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से, मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला व मंडल स्तर के हमारे सभी पदाधिकारी उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए माह में कम-से-कम 15 दिन देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करें। मेरा सुझाव है कि आगामी एक वर्ष में राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों को मिल-जुलकर देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय का दौरा करना है। आगामी एक वर्ष में राज्यों के पदाधिकारी तथा सांसद प्रत्येक मंडल कार्यालय तक पहुँचें और जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रत्येक ग्राम तक जाएँ। जहाँ तक संभव हो हम रात के समय किसी गाँव या बस्ती में ही ठहरें। यह सब पार्टी को सशक्त व मजबूत बनाने के लिए प्रस्तावित यज्ञ का एक हिस्सा है। मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि हमारी पार्टी शीघ्र ही 'गाँव चलो' नामक देशव्यापी अभियान का शुभारंभ करने जा रही है।

3. कार्यकर्ता को मान्यता और सम्मान प्रदान करें

इस अभियान में हमारे कार्यकर्ता ही हमारे सिपाही हैं। अपने कार्यकर्ता की उपेक्षा करके कोई भी पार्टी टिकी नहीं रह सकती। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच सक्रिय, सशक्त और निरंतर आपसी संपर्क बनाए रखना जरूरी है। केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को सदैव यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आज वे जो कुछ भी हैं वह अपनी पार्टी और इसके असंख्य व साधारण कार्यकर्ताओं के कारण ही हैं। अतः उन्हें भी पार्टी को अपना बेहतर योगदान देने के लिए संकल्प करना चाहिए और उन्हें ऐसा कार्यालय चाहिए जिससे कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा सके और उनकी हर संभव सहायता हो सके। कार्यकर्ताओं की पहुँच सदा उन तक बनी रहनी चाहिए और यह प्रयास रहना चाहिए कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

इसी प्रकार, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को भी जनसाधारण के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, कार्यकर्ताओं को मंत्रियों सांसदों

व विधायकों के साथ सार्वजनिक मुददों को उठाना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत स्वरूप की शिकायतों को लेकर जाना चाहिए।

4. सरकार व पार्टी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना

एन.डी.ए. सरकार के साथ चार वर्ष से अधिक के कार्यकाल के दौरान मुझे यह विश्वास हो गया है कि हमारी पार्टी का संगठन और उसके विस्तार के लिए हमारी सरकार का बेहतर प्रदर्शन ही सबसे सशक्त मंच है। तथापि, इसके लिए पार्टी और हमारी सरकार के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

इन साढ़े चार वर्षों में मैंने पार्टी तथा सरकार दोनों के साथ कार्य करने का उपयोगी अनुभव प्राप्त किया है। ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मुझे लोगों को अपनी सरकार के दृष्टिकोण, नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों से अवगत कराने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके विपरीत, इससे मुझे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन के संबंध में लोगों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाएँ सुनने का भी मौका मिला। इस प्रकार, बेहतर समन्वय से पार्टी व सरकार, दोनों लाभान्वित होंगे।

इस प्रक्रिया को अब एक प्रथा बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, मैंने यह निश्चय किया है कि हम अपने कुछ युवा एवं उत्साही सांसदों की सहभागिता से पार्टी कार्यालय में एक कार्यकुशल समन्वय केंद्र चलाएँ। यह केंद्र समूचे सुझावों और विचारों को प्राप्त करके उन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेजेगा। यह केंद्र उनकी समस्याओं व शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए मंत्रियों और नौकरशाही से भी संपर्क करेगा।

मैं सभी मंत्रियों से आग्रह करूँगा कि वे समन्वय स्थापित करने के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग दें।

5. अपने कार्यकर्ताओं की विचारधारा में परिवर्तन करना

लंबे समय से हमारी पार्टी विरोधी दल के रूप में कार्य करने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं की विचारधारा पर सहज प्रभाव पड़ा है। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका को प्रशंसनीय रूप में निभाया है। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं की विचारधारा विरोध करने, आंदोलन करने, आलोचना करने और कमियों को उजागर करने की होती है। तथापि अब पार्टी की भूमिका बदल गई है। हमारे कार्यकर्ता को अब एक अनुशासित सिपाही, उत्साही वक्ता और सरकार की सेवा में लोगों को तैयार करवाने के लिए स्वयं को नए सिरे से तैयार करना है। इस भूमिका को निभाते हुए, उन्हें उन सीमाओं और दबावों को भी ध्यान में

रखना है, जिनके दायरे में रहकर सरकार काम करती है। इनमें से कई दबाव हमारे विगत की देन है, जिन्हें तत्काल हटाया नहीं जा सकता।

इस नई भूमिका में—हमारे कार्यकर्ताओं को एक और आवश्यक कार्य करना है, वह है सरकार के कार्य निष्पादन पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ जानना, सरकार व जनता के बीच एक उपयोगी कड़ी बनना तथा एक प्रभावी पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना। उन्हें यह भूमिका उत्तेजित होकर नहीं, अपितु एक जिम्मेदार, अनुशासित तथा व्यवहारकुशल कार्यकर्ता के रूप में इस तरह से निभानी है, ताकि सरकार को उनके वक्तव्यों तथा आचरण से शर्मिंदा न होना पड़े, लोगों को किसी प्रकार की गलतफहमी न हो, पार्टी की एकता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और विपक्ष को हमारी पार्टी व सरकार की आलोचना करने का मौका न मिले।

सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा में यह भी शामिल होना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता समयबद्ध परिणामों के लिए सरकार के विभिन्न कायर्क्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की क्षमता विकसित करें, जहाँ आवश्यक हो, इस प्रकार के कार्यक्रमों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चत करें और कार्यान्वयन तंत्र के विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यकर्ता विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों के संबंध में जानकारी रखें तथा जनता के साथ प्रभावी रूप में संपर्क स्थापित करने में सक्षम हों।

आनेवाले महीनों और वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बदलाव लाने के लिए इन आवश्यक बातों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। हम निकट भविष्य में विभिन्न स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं।

6. कल के नेता तैयार करना

नेतृत्व विकास का कार्य, पार्टी को पुनः ऊर्जापूर्ण करने के हमारे प्रयास का महत्त्वपूर्ण पहलू है, तथापि हम इस आवश्यकता की ओर पर्याप्त और निरंतर ध्यान नहीं दे पा रहे है। जिस प्रकार पार्टी को बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, जो समर्पित सिपाही के रूप में कार्य करते हैं, उसी प्रकार पार्टी को विभिन्न स्तरों के सक्रिय, दृढ़, निश्चयी, योग्य और आदर्श नेताओं की भी आवश्यकता होती है। हमें विशेष रूप से युवा कार्यकर्ताओं की खोज करके उन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार व प्रशिक्षित करना चाहिए। पार्टी निर्माण का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य ऐसे करिश्माई और लोकप्रिय नेताओं का विकास करना है जो पार्टी के

आदर्शों, विचारधाराओं और आचार संहिता से जुड़े हों।

पारंपरिक रूप से, ए.बी.वी.पी. और युवा मोरचा, युवा पार्टी नेताओं को तैयार करने के आधार-स्तंभ साबित हुए हैं। नए युवा नेताओं की तलाश के लिए हमें हमेशा इनकी ओर ध्यान देना होगा। साथ-ही-साथ, मैं चाहूँगा कि विभिन्न मोरचों और केंद्रों में ऐसे महिला व पुरुषों को भी रखा जाए जिनमें नेतृत्व की क्षमता हो तथा उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपे जाएँ।

इसी प्रकार, हमारी राजनीतिक भरती प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो सामने उदाहरण प्रस्तुत करे। हमें अपनी पार्टी में ऐसे लोगों के प्रवेश को बढ़ावा देना चाहिए, जिन्होंने अपने गुणों व योग्यताओं को सिद्ध किया हो।

7. आजीवन सहयोगी योजना को सफल बनाने का संकल्प

हमारी पार्टी ने हमेशा फंड एकत्रित करने के तरीकों और पार्टी की विभिन्न वैध गतिविधियों पर खर्च करने के संबंध में पारदर्शिता रखने के महत्त्व पर जोर दिया है। पार्टी के विकास के साथ-साथ इसकी वित्तीय आवश्यकताएँ भी बढ़ी हैं। पाँच वर्ष पूर्व हमने आजीवन सहयोगी योजना के रूप में एक अद्वितीय पहल की थी, जिसके तहत आजीवन सहयोगी बनने के इच्छुक लोगों से छोटे, परंतु निर्धारित (वार्षिक) अंशदान एकत्र किए जाते हैं। निस्संदेह यह योजना प्रशंसनीय है, कुछ राज्यों में इस कार्य में शिथिलता है। कुछ एक राज्यों में पूरी क्षमता से न जुटने के कारण उन्हें सौंपे गए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई है।

मैं राष्ट्रीय परिषद् के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे आजीवन सहयोगी योजना को सफल बनाने के कार्य को व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता प्रदान करें।

निष्कर्ष

पार्टी तथा सरकार के चार 'स'

प्रिय सहयोगियो!

भाजपा को 'विशेष पहचान की पार्टी' और 'विशेष स्तर वाली सरकार' बनाने के लिए यदि मैं मुख्य आवश्यकताओं को सारांश में व्यक्त करना चाहूँ तो चार सूत्री फॉर्मूला प्रस्तुत करूँगा—

हमारी पार्टी के चार 'स' इस प्रकार हैं—
समर्पण, सानुशासन, सक्रियता, संकल्प
हमारी सरकार के चार गुणसूत्र हैं—
लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, विकास एवं सुरक्षा

यदि हम इन चार गुणसूत्रों को चरितार्थ कर लेते हैं तो निःसंदेह हमारी पार्टी और हमारी सरकार स्वयं सफलता की ओर अग्रसर होती जाएगी, जिससे देश को शक्ति प्राप्त होगी और वही ऊँचाइयों को छूएगी तथा इससे जनता में समृद्धि और सुख शांति आएगी।

राष्ट्र प्रथम, तत्पश्चात् पार्टी और अंत में स्वयं

जी हाँ, हम वृद्धि और सफलता के लिए इस गुणसूत्र को चरितार्थ कर सकते हैं। हमें स्वयं पर विश्वास, अपनी पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास, अपने बीते हुए कल पर गौरव, भविष्य पर विश्वास और आगे बढ़ने के लिए हौसला रखना होगा।

हमारे हाथ में राष्ट्रवाद और मानववाद के सिद्धांतों की मशाल है, जो हमारे हृदय को प्रेरणा प्रदान करती है और हमें रास्ता दिखाती है। इस संदर्भ में 'एकात्म मानव दर्शन' के प्रणेता स्व. दीनदयाल उपाध्यायजी के 'राष्ट्र चेतन' के वाक्यों को मैं उद्धृत करता हूँ—

"हमारा भारत समग्र रूप से एक है। इसकी जनता भी एक है और जनता को इसकी अनुभूति भी होनी चाहिए। जैसे शरीर संरचना में विषम अंगों का समावेश संभव नहीं है। एकात्म शरीर की संरचना में अंग-प्रत्यंग एक ही शरीर के अवयव हैं और वे एकात्म शरीर के अस्तित्व के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार की राष्ट्र की विभिन्न इकाइयों को भी स्वतः राष्ट्रहित के अनुकूल बनना चाहिए। विभिन्न वर्ग, भाषा और प्रांत का अपना-अपना महत्त्व है किंतु यह तब तक ही है जब तक कि वह राष्ट्रहित के अनुकूल है। यदि अनुकूल नहीं है तो राष्ट्रहित में ये त्याज्य हैं।"

हमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दक्ष नेता का आशीर्वाद प्राप्त है, जो न केवल नेता हैं बल्कि एक राजनेता हैं। वे और भी बहुत कुछ हैं। उनके नेतृत्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा, छवि और आदर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में बढ़ा है। श्री लालकृष्ण आडवाणी के रूप में हमें एक ओजस्वी और कृतसंकल्प नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनकी संगठनात्मक दक्षता बेजोड़ है और जो नैतिक रूप से हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इन दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पीछे समर्पित नेताओं का एक समूह है जिसमें योग्य और अत्यधिक होनहार दूसरी पीढ़ी है और इनके बाद तीसरी पीढ़ी के उभरते नौजवान हैं। हमारे पास समर्पित और स्वप्रेरित कार्यकर्ताओं का एक विशाल संगठन है और शुभचिंतकों का एक विशाल समूह है, जो हमारी पार्टी की शक्ति है।

हमारे देश की जनता में हमारे प्रति प्यार और स्नेह है। हमारा काम है घर-घर जाकर उन तक पहुँचना, उन्हें सीखना और उनसे सीखना। उन्हें संगठित करना तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त करना और उनके साथ कदम-से-कदम मिलाकर

कर्तव्य-पथ पर चलते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। इस यात्रा में, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता एवं कार्यकर्ता विधिवत प्रण करे कि हमारे लिए 'राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर पार्टी है और स्वयं अंत में है।

जीत हमारी ही होगी।

वंदेमातरम्!

जय हिंद!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली 23-24 दिसंबर, 2002

आदरणीय श्री अटलजी, आदरणीय श्री आडवाणीजी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेरे प्रिय बंधुओ!

मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस महत्त्वपूर्ण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह बैठक का समय हर्षोल्लासपूर्ण है, समारोह मनाने का है और हमारे सामने जो कार्य हैं, उनके प्रति निष्ठा से पुनः कार्य करने में जुट जाने का है।

आइए, हमारी इस दो दिवसीय बैठक के आस-पास घटी दो घटनाओं पर नजर डालें। अभी हाल में गुजरात विधानसभा के संपन्न चुनावों में हमारी पार्टी को फिर से मिले जनादेश की शानदार विजय के बाद हमने कल ही गांधीनगर में श्री नरेंद्रभाई मोदी के शपथ-समारोह का आह्लादकारी दृश्य देखा है।

और परसों हमारे प्रिय नेता तथा प्रधानमंत्री श्री अटलजी का 78वाँ जन्मदिवस है। हमारे लिए वस्तुतः भारत के सभी लोगों के लिए यह बहुत ही विशेष दिन है। हमारे बीच अटलजी एक महापुरुष हैं, जो इस महान् राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता, अनुभव और हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की निजी गुणवत्ता हमारी पार्टी तथा हमारे राष्ट्र की अमूल्य संपदा है।

हमारी पार्टी के संस्थापक तथा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत श्री अटलजी हमें सदैव अत्यंत प्रिय रहे हैं, हमारे लिए अत्यंत विशिष्ट रहे हैं। और हम सभी लाखों कार्यकर्ता भी उनके हृदय में विशेष स्थान रखते हैं। आखिरकार, हम सभी की तरह श्री अटलजी स्वयं भी कार्यकर्ता थे, जो परिश्रमी, समर्पित और पार्टी तथा राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध रहे हैं। इसलिए मैं अथाह स्नेहपूर्ण भाव से अपनी ओर से, आप सभी की ओर से तथा इस महान् पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

हमने इस वर्ष और भविष्य में भी उनके जन्मदिवस को 'विकास दिवस' के

रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हम इस अवसर का उपयोग उनके महान् संदेश का प्रसार करने के लिए करेंगे। आइए, 'विकास, तेजी से विकास, संतुलित विकास और सबका विकास' इस मंत्र को लेकर हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएँ।

इसके लिए मैंने महासचिवों से 25 दिसंबर से 12 जनवरी (जो स्वामी विवेकानंद जयंती है) तक के लिए एक कार्यक्रम बनाने के लिए कहा है। मैं चाहूँगा कि कार्यकारिणी के सदस्य इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने विचार और सुझाव दें।

आइए, हम गुजरात भावना को दोहराएँ

मित्रो, अब मैं हर्षोल्लास के दूसरे विषय पर आता हूँ। आज आप सभी की ओर से तथा भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों की ओर से मैं श्री नरेंद्र भाई, श्री केशुभाई, श्री राजेंद्र सिंह राणा और गुजरात इकाई के अपने सभी प्रिय सहयोगियों को विधानसभा चुनावों में पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आपकी विजय ने देश के वातावरण को आंदोलित कर दिया है और हर जगह हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान की है। आज मैं श्री अरुण जेटली, श्री संजय भाई जोशी, श्री रामदास अग्रवाल और पार्टी मुख्यालय में श्री नकवी के कार्य की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने गुजरात टीम को बढ़-चढ़कर समर्थन प्रदान किया। पूरी पार्टी ने एक टीम के रूप में कार्य किया।

आज, मैं गुजरात में पूरे चुनाव प्रचार में श्री आडवाणीजी से मिले मार्गदर्शन के प्रति भी अपना गहरा आभार व्यक्त करता हूँ; इस चुनाव प्रचार में उन्होंने स्वयं भी अथक रूप से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने चार क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी सभाओं को संबोधित किया। अनेक केंद्रीय मंत्रियों तथा पार्टी के अन्य नेताओं ने चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लिया। चुनाव प्रचार का प्रबंध, मीडिया और प्रचार प्रबंधन, सुव्यवस्था प्रबंध—इन सभी प्रबंधों को बड़े व्यावसायिक ढंग से संचालित किया गया।

इसलिए, यदि कोई हमसे पूछता है कि क्या हम अपने गुजरात 'तजुर्बे' को अन्य स्थानों पर भी दोहराएँगे, तो हमारा उत्तर यही होना चाहिए : "हाँ, हम अपना गुजरात 'तजुर्बा' अन्य स्थानों पर भी दोहराएँगे, क्योंकि गुजरात में हमने फिर से सिद्ध कर दिया है कि हमारा सामूहिक कार्य ही सफलता की कुंजी है।"

मोदी बनाम सोनिया—यह बेजोड़ मुकाबला था

आज मैं श्री नरेंद्र भाई को विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ; उन्होंने स्वयं अपने खिलाफ और हमारी पार्टी के खिलाफ फैलाई गई अभूतपूर्व बदनामी का मुकाबला करते हुए एक शेर की तरह संघर्ष किया और वोटों की गिनती के दिन विरोधियों

को मुँह छिपाते फिरने पर मजबूर कर दिया। यह चुनाव मोदी बनाम वाघेला का संघर्ष नहीं था। कांग्रेस पार्टी और वामपंथी लॉबी ने इसे 'मोदी बनाम सोनिया' का संघर्ष बना दिया। परिणामों से पता चलता है कि यह मुकाबला किस कदर बेजोड़ था।

मित्रो, यह चुनाव केवल इसलिए याद नहीं रहेगा कि इसमें हमें किस तरह की और कितनी भारी विजय मिली, बल्कि जिस तरह से भाजपा-विरोधी और हिंदुत्व-विरोधी विद्वेष को फैलाया, उसके लिए भी यह चुनाव याद रखा जाएगा, बल्कि इस बारे में बिना लाग-लपेट के स्पष्ट कहूँ तो कांग्रेस और वामपंथियों ने मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान और दुःख की बात है कि मतदान के बाद भी हिंदू-विरोधी प्रचार जारी रखा। कांग्रेस अध्यक्ष अनेक आपत्तिजनक उद्घोषणाएँ कर इस विषय में सबसे आगे रही। संभवतः उनकी सर्वाधिक आक्रामक और अशिष्ट उद्घोषणा वह थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि गांधी की भूमि गुजरात गोडसे का देश बन रहा है। यह गुजरात के लोगों की अस्मिता और आत्मगौरव पर कलंक था, जिसके कारण श्री नरेंद्र मोदी को गौरव-यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज पूरा विश्व जानता है कि गुजरात के लोगों ने इस यात्रा को कितना अधिक सम्मान दिया।

चुनाव ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व के बल पर फिर से जीवित हो रही है।

गुजरात जनादेश का वास्तविक महत्त्व

यह अत्यंत दुःख की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में अपनी जबरदस्त हार से कोई सबक नहीं सीखा है। पाँच दिन की मुँहबंद चुप्पी के बाद जरा कांग्रेस अध्यक्ष की निकली भड़ास को देखिए—"भाजपा ने विष वमन कर गुजरात में विजय प्राप्त की है।" अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि हमारी विजय के पीछे "धमकियों और डराने—'धमकाने' की राजनीति का हाथ है। अपनी हार को शालीनता से स्वीकार करने की बजाय कांग्रेस के नेताओं ने फिर से झूठ का सहारा लिया और इस प्रकार फिर से गुजरात के लोगों को अपमानित किया। इस हिंसा-मुक्त चुनाव में 90 प्रतिशत अल्पसंख्यक मतदाताओं द्वारा मतदान करने से उनका यह झूठा आरोप गलत साबित हो जाता है।

गुजरात के 62 प्रतिशत लोगों के मतदान से जो संदेश प्रकट हुआ, उसे उन कुंठित राजनीतिक ताकतों ने विकृत करने का प्रयास किया, जिन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं था कि गुजरात चुनावों में आखिरकार उनका दाँव पर क्या कुछ लगा है। जब गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया शिखर तक पहुँची तो राष्ट्रीय स्तर पर समझे जा रहे आतंकवाद, उग्रवाद और राजनीतिक अवसरवाद के मुद्दे केंद्रीय मुद्दों के रूप में स्पष्ट रूप से सामने आ गए थे। हमारे राजनीतिक विरोधियों के बारे में यह बात ठीक ही समझी गई कि वे अल्पकालीन राजनीतिक

लाभों के लिए राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करनेवाले लोग हैं। हमारे देश के लोग पिछले बीस वर्षों से आतंकवादी और उग्रवादी ताकतों द्वारा देश को लहूलुहान होते देख पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। गुजरात चुनावों ने वहाँ के लोगों को अवसर प्रदान किया कि वे इन बड़े मुद्दों पर कारगर ढंग से अपनी चिंताएँ अभिव्यक्त कर सकें, और उन्होंने देखा कि भाजपा ही एक मात्र पार्टी है जो उनकी पीड़ा और चिंताओं को समझती है तथा दृढ़ता एवं दूरदर्शिता से इनका समाधान करने के लिए कृत-संकल्प है।

गुजरात के मतदाताओं ने फिर से एक बार भाजपा में अपना विश्वास जताया, क्योंकि उनके सामने विकल्प बहुत स्पष्ट था। यह विकल्प राष्ट्रवादी और छद्म-सेक्युलरवादी ताकतों के बीच चुनाव करने का था। इसलिए भाजपा के लिए गुजरात में विजय कोई राजनीतिक विजय नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा के प्रति जनादेश है, जिसमें मूल शक्ति के रूप में राष्ट्रहित ही बसा रहा है।

हम गुजरात को 'एक आदर्श प्रदेश' बना देंगे

आज गुजरात के अपने सहयोगियों के लिए मेरे पास एक संदेश है। अब गुजरात के चुनाव पीछे रह गए हैं तथा हमारे आगे हमारे कार्य और कर्तव्य खड़े हैं। केवल गुजरात के लोग ही नहीं, बल्कि देश भर में सभी लोग बड़ी उत्सुकता से इस बात पर नजर रखेंगे कि हमारी सरकार कैसा काम करके दिखाती है। पहले की तरह ही हमें अपने विरोधियों को गलत साबित करना होगा और मुझे विश्वास है कि हम उन्हें गलत साबित करेंगे। मैं श्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने चुनाव से पहले और बाद में स्पष्ट घोषणा की कि वे गुजरात के सभी पाँच करोड़ लोगों के लिए, बिना कोई विभेद और भेदभाव किए, एकता, गौरव, कल्याण और विकास करने के लिए वचनबद्ध हैं।

भाजपा सभी को विश्वास दिलाती है कि कांग्रेस पार्टी के 'अल्पसंख्यवाद के संतुष्टिकरण और अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय' के लंबे रिकॉर्ड की तुलना में हमारा कार्य हमारे आदर्श-वाक्य 'सभी को न्याय तथा संतुष्टिकरण किसी का नहीं' को सच बनाकर दिखाएगा। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से आग्रह करता हूँ कि वे इस विषादपूर्ण खेल को समझें, कांग्रेस और अन्य छद्म-सेक्युलर पार्टियों से दूर रहें और राष्ट्रीय अखंडता तथा स्वयं अपने कल्याण के हितों को आगे बढ़ाने के वास्ते भाजपा के साथ पारस्परिक सहमति का एक नया समीकरण बनाएँ। वोट बैंक की राजनीति से अल्पसंख्यकों को असीम क्षति हुई है और समय आ गया है कि वे इस बात को पहचानें।

हमारी पार्टी ने, गोधरा में हुई हिंसा और गोधरा के बाद हुई हिंसा 'दोनों की निंदा कड़े और स्पष्ट शब्दों में की है। राज्य सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए भरसक प्रयास किया। चाहे किसी भी जाति या समुदाय के लोग हों, सभ्य समाज

में निर्दोष लोगों का खून बहाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

मैं अपने देश के लोगों को एक और विषय पर भी आश्वस्त करना चाहता हूँ। हम गुजरात को एक आदर्श प्रदेश बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। यह एक ऐसा आदर्श प्रदेश होगा, जहाँ भय नहीं होगा, जहाँ अवसर-ही-अवसर होंगे, एक ऐसा प्रदेश होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से विकास की ओर बढ़ेगी, और जहाँ विकास के लाभ प्रदेश के सभी लोगों के पास समुचित ढंग से पहुँचेंगे, बल्कि विशेष रूप से गरीबों और सभी समुदायों के अति निर्धन लोगों तक विकास के लाभ पहुँचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि गुजरात के लोग परिश्रमी और उद्यमी हैं।

'विजय पर्व' और इससे जुड़े हमारे कार्य

इस एक विजय से अब समय आ गया है कि हम और अनेक विजयों की ओर अग्रसर हों। यदि गोवा की विजय ने दिशा परिवर्तन का संकेत दिया था तो गुजरात की विजय 'विजय पर्व' का शुभारंभ है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ठीक ही इसका उल्लेख किया है। इस पर्व के बाद हमारी पार्टी की विजय उन अनेक राज्यों में होगी, जहाँ वर्ष 2003 में चुनाव होने जा रहे हैं तथा 2004 के संसदीय चुनावों में और भी बड़ा जनादेश प्राप्त कर भाजपा के सिर पर विजय का सेहरा बँधेगा।

गुजरात में हमने 1995, 1998 और 2002 में लगातार विजय प्राप्ति से हैट-ट्रिक करके दिखाई है। इसी प्रकार हम 1998, 1999 और 2004 में केंद्र में विजयी होकर हैट-ट्रिक करके दिखाएँगे। मैंने अगले लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए 300 सीटों का लक्ष्य रखा है। मैंने यह लक्ष्य यों ही अटकलबाजी लगाकर नहीं रखा है। मेरा सदा यह विश्वास रहा है कि एक दिन हमारा राष्ट्र उस विचारधारा के पथ पर चलेगा, जिस पर हम चलते रहे हैं और वह निश्चित घड़ी बहुत दूर नहीं है; परंतु नियति के साथ मिलाप करने के लिए हमें स्वयं को तैयार करना होगा और हमें अपने कार्यों को तदनुरूप ढालना होगा।

परंतु ठीक अभी, हमारा तुरंत कार्य नौ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होना है। जहाँ कहीं इन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, वहाँ उसकी हार निश्चित है, जो दीवार पर लिखी दिखाई पड़ रही है। इस संबंध में राजस्थान और असम में उपचुनाव लोगों के मिजाज और दिमाग का बेरोमीटर हैं। इसलिए आप सभी से मेरी प्रथम अपील यही है कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए सीधे कूद पड़िए, कुछ भी भाग्य पर मत छोड़िए और पहले से ही एक-एक बात का विस्तृत ब्योरा तैयार करने में लग जाइए। हमारा विशेष बल तीन प्रमुख क्षेत्रों पर होना चाहिए—

1. कांग्रेस सरकारों के निष्क्रिय-कार्य प्रदर्शन तथा कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह के बारे में प्रचार

हमें लोगों के बीच जाकर कांग्रेस-शासित राज्यों में उसकी सरकारों के निष्क्रिय कार्य प्रदर्शन, कुशासन, अकुशलता, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और वायदों को पूरा न करना, जैसे विषय, जो इन राज्यों में सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं, हमें इन विषयों को लेकर जबरदस्त प्रचार शुरू कर देना होगा। हमें इस बात का भी पर्दाफाश करना होगा कि किस प्रकार कांग्रेस के नेता बुरी तरह से अंतर्कलह में पड़े हुए हैं और उनके राज्यों में विकास तथा वहाँ के लोगों के कल्याण की बजाय सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है। अनेक उदाहरण मिलेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में भूख और भुखमरी के शिकार होकर लोग मरे हैं; हालाँकि केंद्र ने इन राज्यों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया। इस पर्याप्त खाद्यान्न के रहते मध्य प्रदेश और राजस्थान में भूख से हुई मौतों पर हर कांग्रेसी का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अन्त्योदय अन्न योजना, जो हमारे देश में पाँच करोड़ अति निर्धन लोगों के लिए अत्यंत व्यापक और सबसे सस्ती खाद्य सुरक्षा योजना है, और संपूर्ण रोजगार योजना में शामिल किए गए 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को समुचित ढंग से क्रियान्वित करे, परंतु कांग्रेस सरकारों ने इसके कार्यान्वयन में बेहद उदासीनता दिखाई है।

कांग्रेस सरकारों के शासन में महिलाओं, दलितों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार एक रोजमर्रा की बात हो गई है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को रिहा करने के अस्वीकार्य समझौते के मामले में कांग्रेस एक अकेली पार्टी है।

हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री में सिर फुटौवल हो रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के निष्क्रिय कार्यप्रदर्शन के कारण उससे लोगों का मोह भंग पूरी तरह से हो गया है। कर्नाटक में वीरप्पन को खुले घूमने देना और अपहरण करने देना और मुक्त हत्याएँ होने देना राज्य सरकार की संपूर्ण अक्षमता का उदाहरण है। केरल में सरकार के पास कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है। फिर भी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री भद्दी लड़ाई में जुटे हैं और इस प्रकार पूरे प्रशासन को पंगु बना दिया गया है। महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नियमित रूप से अपनी ही सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री और गठबंधन में भागीदार एन.सी.पी. दोनों के खिलाफ आरोपों के गोले दागते रहते हैं। असम में लगता है कि मुख्यमंत्री की जरा भी नहीं चलती है।

छत्तीसगढ़ में, एक पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री खुल्लम-खुल्ला मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहा है कि राज्य में यह आज तक की सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार है। उधर मुख्यमंत्री जोड़-तोड़ की राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष को उत्पीड़ित करने के लिए कुख्यात हैं। पंजाब में असंतोष और असहमति तेजी से उभर रही है। पंजाब में हर कोई यही कह रहा है कि राज्य सरकार के पास त्रि-सूत्री एजेंडा है—बदली, बदला और बादल। दिल्ली सरकार के पास एक-सूत्री एजेंडा है—अपनी जिम्मेदारियाँ भूलो और हर बात के लिए प्रतिदिन केंद्र को कोसो।

कांग्रेस पार्टी की धोखाधड़ी और दोहरे मानदंडों का पता भी इसी से लग जाता है कि पंजाब में चुनावों से पहले मुफ्त बिजली देने की बात कही गई और चुनावों के बाद बिजली ही नहीं दी जा रही है। अब यही पार्टी आंध्र प्रदेश में मुफ्त बिजली देने का वायदा कर रही है।

हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की चर्चा इस विषय को लेकर जोर-शोर से करनी चाहिए कि किस प्रकार इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपनी सरकार के निष्क्रिय कार्यप्रदर्शन की तरफ से ध्यान हटाने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास के पास धरने और गिरफ्तारियाँ देकर अत्यंत शर्मनाक हरकतों का सहारा लिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति इस प्रकार का अपमान नहीं किया था। परंतु इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति का कितना गहरा पतन हुआ है।

हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को झारखंड तथा राजस्थान राज्य की भाजपा इकाइयों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की बराबरी की चेष्टा करनी चाहिए, जहाँ पार्टी ने हाल के उपचुनावों में भारी विजय प्राप्त की है। मैं दोनों राज्यों के पार्टी अध्यक्षों तथा अन्य नेताओं का अभिनंदन करता हूँ।

2. छद्म सेक्युलरवाद और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के प्रति उदासीनता के खिलाफ अभियान

मित्रो, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ। हमें न तो अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में क्षमाशील होने की आवश्यकता है, न ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साझा एजेंडे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर क्षमाशील होने की आवश्यकता है। एक हाथ में बीजेपी का झंडा, दूसरे हाथ में राजग का एजेंडा—यही हमारी नीति है।

हमें अपने विरोधियों की राजनीति का पर्दाफाश दृढ़ता से करना है, जिसके अंतर्गत वे हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा को बदनाम करते हैं और ऐसे मुद्दों पर समझौता करते हैं, जिनसे राष्ट्र की सुरक्षा कमजोर होती है।

इसलिए हमारी पार्टी को छल-बल के साधनों से धर्मांतरण के खिलाफ प्रभावकारी राष्ट्रव्यापी कानून बनाने के लिए अभियान चलाना चाहिए। यह मात्र ऐसा मुद्दा नहीं है जो वैध रूप से सभी हिंदुओं के मस्तिष्क को आंदोलित कर रहा है, बल्कि यह मुद्दा राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक एकजुटता के हितों से भी जुड़ा है। यह बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि छल-बल के साधनों से धर्मांतरण को किसी देश में सहन नहीं किया जाता है। अतः सेक्युलरवाद की भ्रष्ट परिभाषा करके धर्मांतरण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पार्टी को लोगों की सुदृढ़ सम्मति तैयार कर सुनिश्चित करना होगा कि सभी राज्य सरकारें इस बारे में कानून बनाएँ।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि वह असम में आई.एम.डी.टी. को निरस्त करने पर विचार करे, क्योंकि इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाया है। भारत में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर बँगलादेशियों का प्रवेश कोई हिंदू-मुसलमान का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। हम बँगलादेश में अल-कायदा की उपस्थिति, आई.एस.आई. से जुड़े उसके संबंध और भारत के खिलाफ उसके अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नापाक इरादों की ओर से आँखें नहीं मूँद सकते हैं।

आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए 'पोटा' का इस्तेमाल आवश्यक है। जम्मू और कश्मीर की घटनाएँ आँखें खोलने वाली हैं। कांग्रेस-पीडीपी गठबंधन ने आतंकवाद में विश्वास करनेवाली ताकतों के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखने के बावजूद पी.डी.पी. के एक विधायक की हत्या कर दी। दिसंबर के उस काले दिन को संसद् पर हमले के अपराधियों के खिलाफ 'पोटा' अदालत के निर्णय से पूरे देश को राहत मिली है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विभाजनकारी तथा कुछ छद्म-सेक्युलर ताकतों की तरफ से विरोध के स्वर सुनाई पड़े हैं। यह हैरत की बात है कि यहाँ ऐसे नेता और पार्टियाँ हैं जो संसद् पर इस राष्ट्र-विरोधी हमले में शामिल षड्यंत्रकारियों का बचाव करती हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या करने में विश्वास करते हैं, उन आतंकवादियों के लिए मानवाधिकार कैसे हो सकते हैं। शांति के बिना प्रगति नहीं हो सकती है और सामाजिक तनाव, उग्रवाद आदि के माहौल में शांति नहीं हो सकती है। आतंकवाद एक चुनौती है जिसका डटकर मुकाबला करना आवश्यक है और गुजरात का यही संदेश है। आतंकवाद किसी को माफ नहीं करता है, उनको भी नहीं जो इसका विरोध करते हैं और निश्चित ही उनको तो माफ नहीं ही करता है, जो

इसपर नर्म रुख अपनाते हैं।

हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती से और बिना झुके हमारे स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों की उन विकृतियों को हटाने के लिए किए गए एन.सी.ई. आर.टी. के प्रयासों का बचाव करना चाहिए, जिन्हें कम्युनिस्टों और छद्म-सेक्युलरवादी बुद्धिजीवियों ने इन पाठ्य-पुस्तकों में डाल दिया था।

गुजरात का संदेश एकदम मुखर और स्पष्ट है। यह संदेश है कि राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित सेक्युलरवाद के नाम पर अब न तो देशवासी हिंदुओं पर प्रहार को और न ही कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मानदंडों को और अधिक सहन करने के इच्छुक हैं। हमारे लिए विकास ही एक मंत्र है और इसलिए हम शांति के वातावरण में समृद्धि लाने में विश्वास करते हैं।

आज मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ जो हिंदुत्व की बात करते हैं, परंतु उनकी उद्घोषणाओं से कभी-कभी ऐसा लगने लगता है जैसे कि वे सीमा पार जड़ें जमा चुके उग्रवाद और असहिष्णुता के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हिंदुत्व एक महान् और उदात्त अवधारणा है। भाजपा मानती है कि हिंदुत्व और उग्रवाद, दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। हिंदुत्व और असहिष्णुता भी साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा है—

"Thus it cannot be doubted, particularly in view of the constitutional bench decision of this court that the words 'Hinduism' and 'Hindutava' are not necessary understood and construed narrowly, centred only to the strict Hindu religious practices unrelated to the culture and ethics of the people of India, the way of life of the Indian people ..... considering the terms Hinduism or Hindutava per se as depicting hostility, enmity or intolerance towards other religious faiths or professing communalism, proceeds from improper appreciation and perception of the true meaning of these expressions emerging from a detailed discussion in the earlier authorities of this court."

3. राजग सरकार की असाधारण उपलब्धियों तथा अभूतपूर्व पहल-उपायों को उजागर करने का अभियान

हमें सचमुच खुशी है कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सरकार खरी उतरी और उसने कारगर ढंग से देश के अनेक भागों में सूखे की समस्या का समाधान किया। सरकार ने कुछ अत्यंत दूरगामी परिणामों की दिशा में ठोस पहल-उपाय किए, जैसे नदियों को जोड़ने की दिशा में

पहल–उपाय किए गए। इस संबंध में एक योग्य व्यक्ति के अधीन एक कार्यबल पहले ही गठित किया जा चुका है। यह बहु–प्रतीक्षित परियोजना राष्ट्र की इच्छा का प्रबल प्रतीक है। नदियों को जोड़ने का विषय 'भारत को एकसूत्र में पिरोने' के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। देश भर में और विदेशों में स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर तीव्र प्रगति का स्वागत हुआ है। 17000 करोड़ रुपए की विशेष रेल सुरक्षा निधि की स्थापना, उच्च सघनता नेटवर्क को मजबूत करने और पत्तनों को जोड़ने के लिए 15000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय रेल विकास योजना का शुभारंभ कुछ ऐसे सबसे बड़े पहल–उपाय हैं, जो स्वतंत्रता के बाद बहुत लंबे समय से उपेक्षित रेलवे के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए पहली बार किए गए हैं।

साथ ही, मैं राजग सरकार से आग्रह करता हूँ कि समाज कल्याण के क्षेत्र में भी इसी तरह के बड़े पहल–उपाय किए जाएँ। और अधिक फसलों, और अधिक क्षेत्रों तथा और अधिक किसानों को व्यापक फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए इस योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है। तीन करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और मेरा सरकार से आग्रह है कि मार्च 2004 तक सभी पात्र–किसानों को इसमें शामिल कर लिया जाए। राजराजेश्वरी, भाग्यश्री, आश्रय बीमा योजना को और अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। इन योजनाओं में लोगों को इकट्ठा करने तथा शामिल करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय रुचि लेनी होगी। सरकार ग्रामीण सड़कों को जोड़ने को विस्तार देने की अनूठी योजना—प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के समुचित कार्यान्वयन और अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार को पंचायती राज और स्थानीय निकायों को कारगर ढंग से वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए जल्दी–से–जल्दी एक नया संविधान संशोधन लाना चाहिए।

मित्रो, केंद्र सरकार कुछ ऐतिहासिक विधेयकों को संसद् से स्वीकृति प्राप्त करने में भी सफल रही है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं—इन विधेयकों का संबंध बैंक ऋण चुकता न करनेवाले दोषियों के खिलाफ जोरदार काररवाई करने, सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने, हमारे देश की भावी आशा—'बच्चों' को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने, चुनावी सुधार करने, पर्यावरण सुरक्षा आदि से है। हमें गर्व है कि हम ऐसी स्थिति पैदा कर सके हैं कि टेलीफोन कनेक्शन, गैस कनेक्शन, सीमेंट, चीनी या खाद्यान्न जैसे सभी मामलों में अब कोई प्रतीक्षा सूची, लाइन, कमी या कालाबाजारी नहीं रह गई है। मैं जिस बात को विशेष रूप से सामने रखने की कोशिश कर

रहा हूँ, वह यह है कि हमने लोगों का विश्वास प्राप्त करने का दावा करने के लिए बहुत कुछ किया है। साथ ही अभी बहुत कुछ करना शेष है और इसलिए हम कभी भी शिथिल नहीं होंगे।

दिल्ली संकल्प में निश्चित किए कार्यों का कार्यान्वयन

मित्रो, मैंने ऊपर तीन-तरफा अभियान के प्रयास की रूपरेखा प्रस्तुत की है, वह पूर्णतः बहिर्मुखी दिशा है। परंतु एक और प्रयास तेज करने की आवश्यकता है, जिसकी दिशा अंतर्मुखी होनी चाहिए। और यह हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए तथा हमारी विभिन्न प्रदेश इकाइयों, जिला इकाइयों और स्थानीय इकाइयों के कामकाज की कमियों को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में दिल्ली संकल्प में विस्तार से कार्य निश्चित कर दिए गए हैं, जिन्हें अगस्त में आयोजित राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। मैं यहाँ उन्हें पुनः दोहराना नहीं चाहता हूँ।

किंतु इस तथ्य को देखते हुए कि मैं पुनः इस विषय का उल्लेख कर रहा हूँ, जिसमें स्पष्ट है कि संगठन में बुराइयों के समाधान करने और पुनः समाधान करने का विषय हमारे तुरंत और दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा दल में घटी गंभीर घटनाओं और इससे पहले छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक की घटनाओं से गहरी निराशा हुई है और हमारे कार्यकर्ताओं तथा हमारे समर्थकों को भी दुःख पहुँचा है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से सदैव यह बात ध्यान रखने की अपील करता हूँ कि हमारी पार्टी एक अलग पहचान की पार्टी है और हमारी पार्टी सदैव एक अलग पहचान की पार्टी बनी रहेगी। पार्टी में प्रत्येक नेता को सदैव इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि उनके व्यवहार का प्रभाव पार्टी पर पड़ेगा। मैं यह बात बहुत साफ कर देना चाहता हूँ कि पार्टी उन लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करेगी जो लक्ष्मण रेखा पार करेंगे।

मैंने महासचिवों तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर अगले वर्ष जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनके संगठनात्मक मामलों की व्यापक समीक्षा के विशाल कार्य की शुरुआत कर दी है। अपने सामाजिक और राजनीतिक आधार तैयार करने और संगठन को और अधिक शक्तिशाली बनाने के प्रयास के रूप में हमने कई सफल क्षेत्रीय सम्मेलन किए हैं। जिला अध्यक्षों के साथ सीधी बातचीत हुई है और प्रदेश परिषदों की बैठकें आयोजित की गई हैं। इस समय मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 'गाँव चलो अभियान' में लोगों की अत्यधिक भागीदारी रही। चुनाव के अगले दौर से पहले प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक गाँव को शामिल करने की आवश्यकता है। मुझे यह स्वीकार करते हुए भी खुशी हो रही है कि सरकार और पार्टी के बीच, पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच तथा कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच समन्वय के कार्य में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है

और आगे कार्य करने के लिए इससे आवश्यक संवेग मिलेगा। इस प्रक्रिया को और भी अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

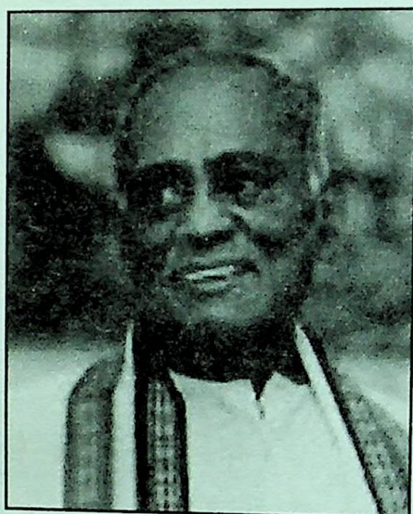
मित्रो, मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि अपने विरोधियों का राग अलापते रहना काफी नहीं है। आपको स्मरण होगा कि मेरे द्वारा पार्टी का अध्यक्ष पद सँभालने के बाद आयोजित पिछली राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में, मैंने केंद्र सरकार के कामकाज के मध्यावधि मूल्यांकन की बात कही थी ताकि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। मैंने पार्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सभी स्तरों पर आत्म-निरीक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। मैंने यह भी कहा था कि पार्टी के रूप में हमने अभी आधी दूरी तय की है और अभी कई मील आगे चलते जाना है। आवश्यक है कि हम सभी याद रखें कि प्रत्येक व्यक्ति, संस्थान और राजनीतिक पार्टी के पास आवश्यक योग्यता और ईमानदारी होनी चाहिए कि वह अपनी संकेंद्रित, सुभाषित और लाभकारी यात्रा को आगे जारी रखने के लिए अपनी कमियों की पहचान कर उनका समाधान कर सके। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि पार्टी और सरकार द्वारा किए गए आत्म-निरीक्षण और मूल्यांकन के प्रयासों के लाभ प्राप्त होना शुरू हो गए हैं। हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी अधिक शक्ति तथा प्रतिबद्धता से इन्हें आगे ले जाने की आवश्यकता है।

मैं फिर से एक बार यह बात दोहराना चाहता हूँ कि अभी हमने आधी दूरी तय की। हमारी मंजिल अभी और आगे है।

धन्यवाद!

वंदेमातरम्!





अध्यक्षीय भाषण

श्री के. जना कृष्णमूर्ति

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

गोवा 12 अप्रैल, 2002

प्रिय मित्रो,

पिछली बार हम चार महीने पहले दिसंबर में मिले थे। तब से कुछ घटनाएँ घटी हैं, जिन पर अब गोवा में हो रही इस कार्यकारिणी द्वारा विचार करना आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि गोवा में शीघ्र चुनाव कराए जाएँगे और इसलिए यह उचित ही है कि हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गोवा प्रदेश इकाई के आमंत्रण पर पणजी के इस सुंदर नगर में रखी है।

हम पहले भी इस नगर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर चुके हैं, इसलिए हमारे गोवा कार्यकर्ताओं को हमारी इस बैठक की आवश्यक व्यवस्था करने का पर्याप्त अनुभव है और मैं गोवा के सभी कार्यकर्ताओं को इस बैठक का आयोजन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

गोवा में शीघ्र ही चुनाव होने वाले हैं। श्री पारीकर के नेतृत्व में सरकार ने अच्छा कार्य करके स्वयं को जनप्रिय बनाया है; परंतु फिर ऐसी स्थिति बनी कि ताजा चुनाव कराना आवश्यक हो गया। हम आशा करते हैं कि गोवा के लोग पूरे पाँच वर्ष के लिए भाजपा सरकार को चुनेंगे।

जब हमारी बैठक पिछली बार हुई थी, तो हमें आशा थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पंजाब में भी, जहाँ हमारी सहयोगी पार्टी अकाली दल थी, हमें चुनावी सफलता मिलेगी। हमारी आशाएँ विफल रहीं। जहाँ तक हमारा संबंध है, इन सभी राज्यों में जनादेश हमारे खिलाफ रहा। उत्तर प्रदेश में हमें तीसरे स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा, जबकि पक्का विश्वास था कि हम अपने प्रथम स्थान को बनाए रख सकेंगे। परंतु एक सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हम मतदाताओं के जनादेश का सम्मान करते हैं और इसलिए हमने विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया है।

उत्तरांचल में, जो अभी लगभग एक वर्ष पूर्व तक उत्तर प्रदेश का हिस्सा था,

हम अपने संख्या बल के आधार पर शासन कर रहे थे, जिसे हमने 1996 के चुनावों में प्राप्त किया था। चुनाव अभियान के दौरान जनमत सर्वेक्षण में भी लोगों की यह सम्मति थी कि वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी; परंतु परिणाम इसके विपरीत रहे। पंजाब में हमें सबसे बुरी हार का मुँह देखना पड़ा है। वहाँ शासन-विरोधी तत्त्व तो था; परंतु इससे हमारे प्रमुख भागीदार अकाली दल से अधिक भाजपा पर कहीं बुरा असर पड़ा है।

दिल्ली नगर निगम के चुनाव परिणामों से हमारे हाथ निराशा ही आई है। निगम चुनावों में हम बुरी तरह से पराजित हुए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनमत पूरी तरह से हमारे साथ नहीं था। हमें ऐसे कुछ कारकों के कारण, जो हमारे नियंत्रण में थे और अन्य शेष कारकों के कारण, जो हमारे वश से बाहर थे, भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

लोकतंत्र में, और इसमें भी भाजपा जैसी परिपक्व पार्टी के लिए चुनावी पराजय होने पर उन कारकों पर विचार करना आवश्यक है जो हमारी चुनावी पराजय के लिए उत्तरदायी हैं, इसपर पछताने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्थिति का सार रखते हुए कहा है कि हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा।

ऐसा नहीं है कि हमें पहली बार चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। हमें सबसे बड़ा धक्का 1984 में लगा था हमें जब एक सीट आंध्र से और दूसरी सीट गुजरात से, यानी केवल दो लोकसभा सीटें मिली थीं। हमारे सर्वोच्च प्रतिष्ठावान नेता को भी चुनाव में हारना पड़ा था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से हमारे राजनीतिक विपक्षी और आलोचकों ने स्वयं पार्टी के खत्म हो जाने की भविष्यवाणी की थी; परंतु इतिहास साक्षी है कि किस प्रकार उस सतही सीमा से उबरकर हम फिर ऊपर उठे और आज हम देश में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति हैं।

हमारी शक्ति और हमारे अस्तित्व के सामने खड़ी चुनौती का सामना करने का संकल्प और इस चुनौती को स्वीकार करना ही हमारी पार्टी की ताकत तथा चरित्र का प्रमुख चिह्न है, जिससे हम अब भी स्थिति का मुकाबला करेंगे।

हमें अभी संबंधित राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिससे पता चले कि हमसे ठीक क्या गलती हुई और हमारे आकलन तथा अभियान में ठीक-ठीक हमने क्या गलती की। इसके बाद ही, यदि आवश्यक हुआ तो हम कोई सुधारात्मक कदम उठा सकेंगे। परंतु अब समय है जब हमें मिलकर और हम सभी को पार्टी संगठन में सहयोग बनाकर दुनिया को साबित कर देना है कि हाल के चुनावों में हमें जो भी हार का मुँह देखना पड़ा है, वह एक अस्थायी तत्त्व है जिसे हम अगले कुछ महीनों में ठीक कर लेंगे। पलायनवाद का रास्ता अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से भागना किसी राजनीतिक पार्टी और उससे भी कहीं बढ़कर हमारी पार्टी के दृढ़ इच्छाशक्ति रखने वाले और संकल्पशील

कार्यकर्ताओं को कभी पसंद नहीं आ सकता है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, हमें अपने राजनीतिक जीवन की कठोर यथार्थताओं से मुँह नहीं छुपाना है और न ही हमें अपनी चुनावी पराजय को हल्के ढंग से लेना है। समय आ गया है कि हम स्थिति का पुनः आकलन करें, विभिन्न मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण को पुनः निश्चयपूर्वक रखें और हम अपनी शक्ति और दुर्बलताओं का पुनः मूल्यांकन करें।

कुछ ऐसा भाव दिया जा रहा है कि हमारे बजट प्रस्तावों ने भी हमारी हार में योगदान दिया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्रीजी ने भी इसका उल्लेख किया है। यह ऐसा विषय है जिस पर बड़े ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है और यदि इस तरह का भाव सही सिद्ध होता है तो इस विषय की जाँच करना आवश्यक है कि किस तरह इस प्रतिकूल प्रभाव को ठीक किया जाए या कैसे इससे मुक्ति पाई जाए।

प्रिय मित्रो,

पिछले तीन वर्ष गुजरात के लिए कोई बहुत अनुकूल नहीं रहे हैं। हमने देखा कि वर्ष 2000 में यह राज्य अत्यधिक सूखे की चपेट में रहा। अभी यह सूखे के दुष्प्रभावों से उबरने में लगा ही था कि 2001 के आरंभ में ही जबरदस्त भूकंप ने इसे घेर लिया। यह तो राज्य सरकार के कठोर प्रयासों का प्रतिफल था कि राज्य में तेजी से पुनर्निर्माण का कार्य किया गया; परंतु इस वर्ष गुजरात गंभीर प्रकार के सांप्रदायिक दंगों की गिरफ्त में आ गया। किसी भी राज्य में निरंतर एक के बाद एक इतनी प्राकृतिक आपदाएँ और मानव-निर्मित आपदाएँ नहीं आई हैं, जितनी गुजरात में आईं। गुजरात के लोग धैर्य और दृढ़ संकल्प के लिए प्रख्यात हैं और जिस प्रकार से उन्होंने बड़ी बहादुरी से वर्ष 2000 और 2001 में सभी आपदाओं का सामना किया है, उसी तरह वे निश्चित ही 2002 की इम्तिहान की घड़ी में भी सफल होंगे। इन सभी तीन वर्षों में राज्य सरकार ने हर स्थिति का मुकाबला दृढ़ता से किया और गुजरात के लोगों तथा सरकार को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने वर्ष 2000 तथा 2001 के अपने अनुभवों को दुःस्वप्न मानकर छोड़ दिया है। वे राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे यह विश्वास भी है कि अब भी गुजरात सरकार वर्तमान कठिन स्थिति पर काबू पा लेगी और गुजरात को पुनः उत्थान और प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। मैं यहाँ अवश्य कहना चाहूँगा कि विपक्ष तथा हमारे आलोचकों की भूमिका सही मायनों में सराहनीय नहीं रही, बल्कि उनकी भूमिका भर्त्सनायोग्य है। जब भी गुजरात में कठिन स्थितियाँ पैदा हुईं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है, हमारे विरोधियों और आलोचकों ने राज्य सरकार पर कड़े प्रहार करना शुरू कर दिया और एक स्वर में मुख्यमंत्री के त्याग-पत्र की

माँग शुरू कर दी। जब लोग एक आपदा का सामना करते हैं और जब सरकार स्थिति को शांत करने के लिए जूझ रही होती है तो विपक्ष तथा विरोधियों की भूमिका उन सभी लोगों के लिए प्रयासों को मजबूत करने की होनी चाहिए, जो इस स्थिति पर काबू पाने के लिए उसमें हर तरह से जुटे होते हैं, परंतु हम देखते हैं कि हमारे विरोधियों के प्रयास उन लोगों के मनोबल गिराने तथा उन्हें बदनाम करने में लगे रहते हैं; जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। मैं उन लोगों द्वारा मचाए जा रहे हंगामे की जोरदार भर्त्सना करता हूँ जो गुजरात के मुख्यमंत्री को हटाने की माँग कर रहे हैं। राष्ट्र को ऐसी ताकतों से बचाना होगा, जिनका एकमात्र उद्देश्य भाजपा सरकार को अस्थिर करना प्रतीत होता है, जबकि वर्तमान स्थिति का तकाजा है कि इस उपद्रवग्रस्त राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रत्येक व्यक्ति अपना सहयोग प्रदान करे।

यदि देश को प्रगति की राह पर बढ़ना है तो सांप्रदायिक संघर्ष का समाधान ढूँढ़ना ही होगा। सामाजिक दुर्भावना और आंतरिक द्वंद्व से हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। सभी वर्गों के लोगों को इसपर गंभीरता से विचार करना होगा। जब समाज का प्रत्येक वर्ग सोचता है कि उसका अपना अंश ही सर्वांग है तो उसे यह अवश्य महसूस करना चाहिए कि वह मात्र सर्वांग का एक अंश है, यहाँ तक कि उसका कल्याण और समृद्धि संपूर्ण समाज के लोगों पर ही निर्भर करती है। किसी भी सांप्रदायिक संघर्ष में एक पक्ष उत्तेजना पैदा करता है और दूसरा पक्ष उससे उत्तेजित होता है। अभी तक प्रयास यही रहा है कि उत्तेजना का शिकार बने पक्ष को सलाह दी जाए और उस पर हमला किया जाए। इससे इस वर्ग के बीच कुछ ऐसी मानसिकता पैदा हुई है कि वह हर तरह से उत्पीड़ित हुआ है। यदि समाज के हर व्यक्ति के पास यह संदेश पहुँचे कि जो कोई भी किसी दूसरे को उत्तेजित करता है, और जो कोई भी उत्तेजना फैलाने या हमला करने में पहल करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, गुंडागर्दी का कोई धर्म नहीं होता है, राज्य तथा समाज उसे कड़ा दंड देने से नहीं चूकेगा तो पूरा समाज और समाज का प्रत्येक व्यक्ति आश्वस्त रहेगा कि सभी के साथ न्याय किया जाता है और किसी के साथ संतुष्टिकरण का व्यवहार नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि इस जटिल समस्या का यही समाधान है और मैं प्रत्येक व्यक्ति से, विशेष रूप से राजनीतिक दलों, सामाजिक और अन्य संगठनों, मीडिया आदि से इसपर गौर करने और सहयोग देने की अपील करता हूँ।

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि लोकतंत्र के स्वस्थ विकास के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी का रवैया जरा भी स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण नहीं है। कांग्रेस इस बात को पसंद करे या न करे, भारत के मतदाता ने केंद्र में राजग सरकार के पक्ष में जनादेश दिया है और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है।

लोगों के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और कांग्रेस को जनादेश का सम्मान करने का सबक सीखना चाहिए। विपक्षी पार्टी के रूप में सरकार की आलोचना और प्रहार करना उसका अधिकार है। हम उस अधिकार को नकारते नहीं हैं; परंतु वह सारी सीमाएँ पार कर रही है। अब 'पोटो' को ही लें। इसे संसद् में बहस के लिए रखा गया। वे ऐसे किसी भी प्रावधान का विरोध कर सकते हैं, जिस पर उन्हें आपत्ति है। वह पार्टी जो 'टाडा' लाई, वह पार्टी जिसने 'टाडा' का दुरुपयोग किया, वह पार्टी जिसके अपने शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव सभी लगभग इस बात पर सहमत हैं और चाहते हैं कि उसे उस आतंकवाद से निपटने के लिए 'पोटो' जैसे कानून की आवश्यकता है, जिसका कुरूप चेहरा हम अपने देश के अनेक भागों में देख रहे हैं, वह पार्टी ही इस प्रकार के कानून की आवश्यकता का विरोध करती है। उन्होंने आखिरी दम तक राज्यसभा में इसका विरोध किया, जिसके कारण संसद् के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा।

पिछले कुछ वर्षों से भाजपा टकराव की अपेक्षा आम सहमति की राजनीति की दिशा में बढ़ती रही है। हम अपने प्रयासों में सफल हो रहे हैं। हम एक साझा एजेंडे के आधार पर बीस से अधिक अलग-अलग पार्टियों के साथ आम सहमति तैयार कर सके हैं और इस प्रकार हमने एक स्थिर सरकार बनाकर सुशासन प्रदान किया है। हमारी इच्छा है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के साथ भी कम-से-कम प्रमुख मुद्दों पर, जैसे निर्धनता उन्मूलन, बेरोजगारी कम करने, विकासोन्मुखी आर्थिक दृष्टिकोण, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सामाजिक समरसता बनाना आदि पर आम सहमति बना लें। राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों के नाम पर मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करता हूँ कि विवेक से काम ले और जहाँ वह सहयोग कर सकती है, वहाँ उसे सहयोग करना चाहिए। परंतु यदि कांग्रेस टकराव के रास्ते पर ही अटल रहती है तो भाजपा अपना आम सहमति का मार्ग चुनने के बावजूद कांग्रेस की टकराव की राजनीति की चुनौती को स्वीकार करने को तैयार है।

मित्रो,

यदि अर्थव्यवस्था के संकट की दलदल से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध होना है तो आर्थिक सुधार के उपाए नितांत आवश्यक हैं। देश की ऐसी राजकोषीय स्थिति में, जब कि उसे विकास के कार्यों और अपने चालू व्यय को पूरा करना तो दूर, ऋण का एक हिस्सा चुकता करने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है तो हमें अपने पेट पर पट्टी तो बाँधनी ही पड़ेगी। इसके अलावा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसे सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन जुटाना भी एकदम अनिवार्य है। पार्टी सामाजिक क्षेत्र विकास के प्रति वचनबद्ध है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक समाज के एक वर्ग को विकास

के लाभों से वंचित नहीं रख सकते हैं। इसलिए राजकोषीय असंतुलन को सुधारने और सामाजिक तथा भौतिक बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि अपेक्षतया समृद्ध वर्गों को कुछ त्याग करना ही चाहिए।

परंतु इस प्रसंग में महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कहाँ तक पार्टी समाज के उस वर्ग को समझा सकती है, जो आर्थिक सुधार के उपायों-विशेष रूप से दूसरे चरण के उपायों से प्रभावित होते हैं। आर्थिक सुधारों के दौर और सिलसिले में भी हमें राजनीतिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता पर गौर करना होगा। इस मुद्दे पर विश्लेषण करने का समय आ गया है, ताकि आर्थिक सुधारों के पीछे जो आर्थिक तर्कशक्ति है और राजनीतिक प्रबंधन के लिए पार्टी की जिस क्षमता की आवश्यकता है, उसके बीच संतुलन बिठाया जा सके।

भारत जैसे देश में जहाँ हमारे पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा-व्यवस्था नहीं है, प्रायः सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अपनी वृद्धावस्था में अपने कठिन परिश्रम से अर्जित बचतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ब्याज दरों की कटौती के लिए चाहे जो भी आर्थिक औचित्य विद्यमान हो, परंतु अनेक सेवानिवृत्त व्यक्तियों को बचतों पर ब्याज से होनेवाली आय में गिरावट के कारण अचानक ही अपने आस-पास दूसरों के सहारे को देखना पड़ा है। यह विशुद्ध रूप से मानवीय विषय है। वे अपने जीवन-यापन के लिए कहाँ जाएँ?

इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह कम ब्याज दर-व्यवस्था की तरफ बढ़ने से पूर्व पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था शुरू करे, हालाँकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक विकास के लिए कम ब्याज-दर व्यवस्था आवश्यक है।

आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए लोगों का सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जहाँ कहीं भी लोगों को अपने पेट पर पट्टी बाँधनी पड़ती है, चाहे वह आयकर अधिभार का मामला हो, लघु बचत पर ब्याज दरों में कटौती हो या पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो, सभी मामलों में लोग यही उम्मीद करते हैं कि उनका त्याग राष्ट्रीय हित में हो। इस प्रसंग में सरकार द्वारा मितव्ययता अपनाने से आम आदमी की सद्भावना प्राप्त करने में बड़ी मदद मिल सकती है।

लगभग 6 करोड़ टन का सुरक्षित खाद्यान्न भंडार एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है, जबकि अगली खरीद के बाद तो यह खाद्यान्न भंडार 7.5 करोड़ टन तक हो जाने की आशा है। निःसंदेह सरकार ने पुराने भंडार को कम करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं—जैसे काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत इसका आबंटन, विक्रय मूल्यों में कमी आदि। यद्यपि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों (बी पी एल) को खाद्यान्न का आवंटन बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति माह

कर दिया है, परंतु केवल इतने भर से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की मदद नहीं हो सकती है; क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आनेवाले इनमें से अधिकांश लोग दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। पखवाड़े के आधार पर (केरल में साप्ताहिक आधार पर) वितरण की बजाय वितरण में लचीलापन होना चाहिए, ताकि मजदूरी से पैसा कमानेवाला गरीब व्यक्ति प्रतिदिन आधार पर अनाज खरीद सके। इस प्रसंग में संभवतः 'फूड कूपन' जारी करना बेहतर प्रस्ताव बन सकता है।

मैं अपने एक सुझाव को दोहराना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी दिया था। हमारे देश ने पिछले एक दशक से भी अधिक समय से उदारीकरण को अपनाया हुआ है। अब हम दूसरे चरण के सुधारों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, जैसा होना चाहिए। परंतु एक बात है कि देश एक ऐसी अवस्था में पहुँच गया है, विशेष रूप से जबकि यह दूसरे चरण के सुधारों में आ गया है, तब यह परम आवश्यक हो गया है कि प्रथम चरण के सुधारों के प्रभाव का आकलन करें कि क्या इसका प्रयोजन सिद्ध हुआ है, क्या इस बारे में अपने दृष्टिकोण, दिशा और कार्यान्वयन में कोई सुधारात्मक उपाय करना आवश्यक है। इन सभी का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि अर्थव्यवस्था को सही दिशा में चलाया जा सके। मैं महसूस करता हूँ कि देश और इसकी अर्थव्यवस्था के हित में इस प्रकार का आकलन आवश्यक है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसका अध्ययन करने के लिए सक्षम लोगों की एक समिति गठित की जाए, जो अपनी रिपोर्ट अविलंब—जैसे तीन से छह महीने में—प्रस्तुत कर दे। इससे सरकार स्वयं आश्वस्त हो सकेगी कि वह सुधार प्रक्रिया का अनुसरण सही तौर पर और निष्ठा से कर रही है।

मैं सरकार का ध्यान एक और विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कृषि के बाद कपड़ा उद्योग क्षेत्र-मिल, पावरलूम और हैंडलूम सभी को मिलाकर—ऐसा दूसरा क्षेत्र है, जहाँ लाखों परिवारों को रोजगार मिलता है। आज यह क्षेत्र अनेकानेक समस्याओं से घिरा है। कपड़ा उद्योग में हर वर्ग इस ओर ध्यान देने के लिए चीत्कार कर रहा है; सम्भव है कि उनकी कुछ समस्याएँ अन्य देशों के साथ उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण पैदा हुई हों और शायद कुछ समस्याएँ सरकारी नीतियों और यथोचित ध्यान न दिए जाने या तालमेल के अभाव के कारण पैदा हुई हों। वर्तमान स्थिति का कुल निष्कर्ष यह निकलता है कि यह उद्योग अस्त-व्यस्त हालत में है और इसकी तरफ विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा इसपर निर्भर लाखों परिवारों के बेरोजगार होकर सड़क पर आ जाने की संभावना बन जाएगी। केंद्र सरकार ने नई कपड़ा नीति अपनाई और घोषित की है। इसका मंतव्य उद्योग की सहायता करना है और इसकी बहाली में मदद करना है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि वह कपड़ा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और लघु उद्योग मंत्रालय आदि के बीच स्वस्थ परस्पर परामर्श के लिए

समन्वित प्रयास करे, जिससे पूरे उद्योग को फिर से स्वस्थ हालत में पहुँचाया जा सके तथा यह उद्योग फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसे विदेशी वस्तुओं से बड़ा कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है।

गोधरा में निर्दोष महिला और बच्चों को गाड़ी में जला डालने की भयानक घटना, जम्मू में रघुनाथ मंदिर में भक्तों पर आत्मघाती बममार हमले तथा आई. एस.आई. द्वारा चलाई जा रही नरसंहार की हाल की अनेकानेक अन्य घटनाओं से स्पष्टतः यह संदेश मिलता है कि सीमा पार आतंकवाद में भविष्य में कोई कमी होने वाली नहीं है। यह बहुत साफ है कि जनरल मुशर्रफ जेहादियों को नियंत्रित करने के इच्छुक नहीं हैं या उनमें इसकी योग्यता नहीं है।

यह भी कि 12 जनवरी का उनका भाषण अंतरराष्ट्रीय समुदाय को झाँसा देने का दिखावा था—यह बात भी अब बहुत अच्छी तरह सिद्ध हो गई है। उन्होंने डेनियल पर्ल के अपहरणकर्ताओं को भी अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया है और साफ तौर पर अमेरिका की इस सलाह को अस्वीकार कर दिया है कि वह भारत द्वारा माँगे गए बीस अत्यंत वांछित आतंकवादियों को सौंप दे, जिन्हें पाकिस्तान में शरण दी गई है। जनवरी में बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों को रिहा कर दिया गया है। जेहादी ग्रुप पहले की तरह ही अपना काम कर रहे हैं। मुशर्रफ की धोखाधड़ी अब एकदम साफ दिखाई पड़ती है। यहाँ तक कि अब तो कुछ अमेरीकी राजनीतिक टिप्पणीकार भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, हालाँकि अमरीकी सरकार अब भी मुशर्रफ की नेकनीयती में विश्वास बनाए हुए है।

जबकि यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति और मित्रता बनाकर चलने का इच्छुक नहीं है और यह भी कि हमें काफी समय तक शत्रुवत् व्यवहार करनेवाले पाकिस्तान के साथ रहना सीखना पड़ेगा, ऐसी हालत में भी जरूरत से अधिक आशावादियों की कमी नहीं है और गुमराह तत्त्व भी हैं, जो भारत सरकार से कहते रहते हैं कि उसे पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। हाल में, जैसा कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह ठीक है कि आप बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं कर सकते हैं। सीमा पार आतंकवाद के साथ दृढ़ता से निपटने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमारा विश्वास है कि हमारे सशस्त्र बल निरंतर चौकसी करते रहेंगे और देश में आई.एस.आई. नेटवर्क का भंडाफोड़ करना ही होगा और इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा।

अन्यत्र हमारे पड़ोसी देशों में कुछ सकारात्मक घटनाएँ घटी हैं। श्रीलंका सरकार और एल.टी.टी.ई. के बीच युद्ध-विराम के समझौते से आशा बँधी है कि श्रीलंका में तमिलों के दर्जे की समस्या का अंततः कोई समाधान निकल पाएगा। हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और दोनों पक्षों को श्रीलंका में स्थायी शांति लाने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करते हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा से भारत–नेपाल संबंधों को और अधिक मजबूत करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य भारतीय नेताओं के साथ उनकी चर्चा से विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से और गहन रूप में परस्पर परामर्श करने की एक रूपरेखा तैयार हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री को उन माओवादी विद्रोहियों से निपटने के लिए सभी संभावित सहायता देने का आश्वासन भी दिया है, जो हिमालय स्थित राज्य में स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।

इस महीने के आरंभ में विदेश मंत्री जसवंत सिंह की यात्रा से जनगणराज्य चीन के साथ विभिन्न स्तरों पर संरचनात्मक और निरंतर बातचीत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। चीन हमारा महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश है और हम मानते हैं कि भारत और चीन के बीच अच्छी समझ बनने से इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास की दिशा में बड़ा योगदान मिल सकता है।

मित्रो,

देश परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा है। हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर केंद्र में एक स्थिर और प्रगतिशील सरकार देने में सफल हुए हैं। राजग एकजुट है और यह एक सहयोगात्मक प्रयास भी है। साझा एजेंडे का अनुपालन और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास—ये दो तत्त्व हैं, जिनके कारण राजग सरकार सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही है। जब तक हर हालत में परस्पर विश्वास, परस्पर भरोसा और परस्पर संबंध बने रहेंगे, ये दोनों तत्त्व अविच्छिन्न बंधन में बँधे रह सकते हैं, जिससे हमारे सभी सहयोगी दल परस्पर जुड़े हुए हैं। मैं इस पहलू पर भी जोर देना चाहता हूँ और अपने सहयोगी दलों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भाजपा शेष सहयोगी दलों में यही विश्वास, भरोसा और संबंध रखती है।

मित्रो,

विपक्षी पार्टियों द्वारा हमें अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमें इससे सचेत रहना होगा। हमें सदैव याद रखना होगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को देश में एक सहमत एजेंडा के आधार पर सुशासन प्रदान करने के लिए बनाया गया था। हमें इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए। राजग का यह भी प्रयास है वह राष्ट्र की बेहतरी के लिए अधिकाधिक लोगों को साथ लेकर चले, यह प्रयास भी जारी रहना चाहिए।

परंतु इन सभी बातों के साथ, हम भाजपा के लोगों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि राजग की शक्ति पार्टी की शक्ति पर निर्भर करती है, जिसके साथ मिलकर राजग बना है। इसलिए यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि

भाजपा हर तरह से मजबूत से मजबूत बने। हाल के चुनावों में हमारी पराजय से हमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसमें सफल होने के अपने संकल्प को और पक्का करना चाहिए।

चुनावी लड़ाई में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पंजाब हमारे हाथ से निकल गए हैं। इन राज्यों में फिर से विजयी बनने के लिए हमें स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए। नई-नई चुनौतियाँ आती हैं और उनपर विजय प्राप्त की जाती है। गोवा और जम्मू तथा कश्मीर में इस वर्ष मतदान होगा। अगले वर्ष (2003) में दस राज्यों में चुनाव होंगे, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि शामिल हैं। अभी से हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी से हम चुनाव के लिए तैयार हों। हम अपने पार्टी संगठन को मजबूत बनाएँ। हम अपने काम से, अपने कार्य-प्रदर्शन से और एक संगठित संस्था के रूप में अपना कामकाज दिखाकर आम जनता में स्वयं को प्रिय बनाएँ।

हम एक मीटर की दौड़ में जरूर पिछड़ गए हैं, परंतु हमें तो आगे एक किलोमीटर की दौड़ में विजय प्राप्त करनी है। हमने भले ही एक दिन खोया है, परंतु हमें विश्वास है कि पूरा वर्ष हमारा होगा।

अतः आइए, हम आगे बढ़ें।

□

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली 24 मार्च, 2001

प्रिय मित्रो,

एक आम बात कही जाती है कि जीवन के बारे में पहले से कुछ कह पाना कठिन होता है। राजनीति पर यह बात और भी सही उतरती है। परिस्थितियों में विचित्र मोड़ के कारण सुचारू रूप से चल रहा हमारा जहाज तूफान में घिर गया और मैंने देखा कि मुझे इस तूफान में जहाज की कप्तानी करने और इसे बंदरगाह तक सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई।

जब तहलका डॉटकॉम की टेपों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दिखाया गया तो दुर्भाग्यपूर्ण और बिना बात ही ऐसी स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण हमारे अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण को पार्टी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। मुझे मालूम है कि पार्टी में कुछ लोगों ने यह अवश्य महसूस किया कि उन्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। परंतु मेरे नाम भेजा गया 13.3.2001 का उनका त्यागपत्र मुझे उस दिन मध्य रात्रि को मिला, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था—मैं उद्धृत करता हूँ—"मैं इस मामले में किसी भी जाँच का सामना करने को तैयार हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पूर्णतः निर्दोष सिद्ध होऊँगा। किंतु जाँच पूरी होने तक और भाजपा के उच्च नैतिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए मैं पार्टी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देता हूँ। मैंने यह निर्णय प्रधानमंत्री से परामर्श करने के बाद लिया है।"

इन परिस्थितियों में 14 मार्च को उपलब्ध पदाधिकारियों की बैठक में त्यागपत्र स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था और मुझसे उनके स्थान पर जिम्मेदारी वहन करने के लिए कहा गया। पार्टी का वरिष्ठतम उपाध्यक्ष होने के नाते मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि पार्टी बिना अध्यक्ष के नहीं रह सकती है। इन परिस्थितियों में आज मैं अध्यक्ष पद से आपके सामने हूँ।

हमारी पार्टी के अध्यक्ष का आसन विक्रमादित्य सिंहासन जैसा है। ऐसा कहा जाता है कि धरती के नीचे गड़े उस सिंहासन के ऊपर यदि कोई गड़रिया भी बैठता

था तो वह भी पूरा न्याय करता था। इसी प्रकार इस आसन पर आरंभ में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अत्यंत लब्ध प्रतिष्ठित नेता बैठे, जो अपनी गहन देशभक्ति, विशुद्ध राष्ट्रवाद, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के कारण हमारे देश के गिने-चुने महापुरुषों में माने जाते थे और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस आसन पर विराजमान हुए, जो हमारे मित्र, चिंतक और मार्गदर्शक रहे। भाजपा के इस पद को श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी और उनके उत्तराधिकारियों ने सुशोभित किया है। यद्यपि शायद कुछ अटपटा सा लगे कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इस उच्चतम पद तक पहुँचा दिया गया है; परंतु इससे पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिसके लिए वह अपनी स्थापना के समय से ही विख्यात है कि यही कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है और राजनीतिक शब्दावली में कहें तो कहेंगे कि यह कैडर-आधारित पार्टी है। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा कि मुझे अपनी नई जिम्मेदारी के निर्वाह में जरा भी कठिनाई नहीं होगी, चूँकि पिछले 35 या इससे भी अधिक वर्षों से मैं श्री अटलजी, श्री आडवाणीजी, श्री कुशाभाऊ आदि के साथ रह कर ही आगे बढ़ा हूँ और उन्होंने ही मुझे दीक्षित किया है।

आपने मुझे पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है, इसी से यह सिद्ध होता है कि आपको मुझ पर भरोसा है, विश्वास है, और यही नहीं, बल्कि अपनी इस विशाल पार्टी को निर्धारित लक्ष्य तक ले जाने एवं अपने साथ पूरे राष्ट्र को निर्दिष्ट गरिमा तक पहुँचाने में मुझे आपका संपूर्ण सहयोग मिलेगा। पिछले अनेक वर्षों में मुझे आपसे जो असीम समर्थन मिला है, उसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार प्रगट करना एवं अनेकानेक धन्यवाद देना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ।

मित्रो,

अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने के बाद से हमने एक लंबा रास्ता तय किया है। हम संतोष कर सकते हैं कि हमारी यात्रा सही मार्ग, सही दिशा और सही नेतृत्व के साथ आगे बढ़ती रही है। हमारे मार्ग में अनेक बाधाएँ, प्रतिरोध हास्यास्पद एवं कड़े विरोध उपस्थित हुए हैं। 1984 में हमारी पार्टी संसद् में मात्र दो सदस्यों की पार्टी बनकर रह गई थी और आज हमारी पार्टी 182 सदस्यों की सबसे बड़ी पार्टी है। 1980 के मध्य तक हमारे बारे में कहा जाता था कि यह पार्टी भारत की राजनीति में अलग-थलग पड़ती जा रही है और आज हम देखते हैं कि जिन्होंने हमें अलग-थलग करने की कोशिश की, वे स्वयं अकेले पड़ गए हैं। 20 वर्ष पहले जब हमने पार्टी की स्थापना की थी तो हमारा उद्‌देश्य तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी का विकल्प बनना था। परंतु आज हमारी परिकल्पना इससे भी कहीं आगे बढ़ गई है कि हम 21वीं सदी भारत की सदी बनाएँ। हमारा ध्येय भी कहीं स्पष्ट हो गया है और हमारा प्रयास है कि भारत अगले कुछ वर्षों में एशिया की महान शक्ति बनकर उभरे और वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी समुचित भूमिका का निर्वाह

करे। हमें अपने इस स्वप्न और उद्देश्य को साकार करना होगा।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हम अपनी वचनबद्धता का निर्वाह करेंगे। समय की माँग के साथ इसका आविर्भाव हुआ है। भाजपा श्री अटलजी के नेतृत्व में इसे सफल बनाने में कोई कोर-कसर नहीं रखेगी। भाजपा चाहती है कि राजग में हम सभी साझा गठबंधन के धर्म का पालन करें। मैं सभी से अपील करता हूँ कि हम सभी ने शासन के साझा एजेंडा से बंधे रहने की प्रतिज्ञा की है और इसी के आधार पर हमने लोगों से जनादेश प्राप्त किया है तथा हमें इसी का अनुसरण करना चाहिए एवं कहीं से भी मतभेद के स्वर सुनाई नहीं पड़ने चाहिए। जब कभी-कभी पार्टी के अंदर भी अलग-अलग राय होती है और मतभेद हुआ करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजग जैसे बहुदलीय सहयोगियों के साथ रहते हुए इसी तरह की कुछ बातें दिखाई पड़ें। किंतु अंततः सभी का उद्देश्य राष्ट्र के सर्वोत्कृष्ट हितों को पूरा करने के लिए विश्वास, सहमति और तालमेल एवं मित्रता को बनाना है, जिससे राजग में आवश्यक सौहार्द बना रहे और यह सुचारू रूप से बिना किसी विवाद के आगे बढ़ता रहे।

कम्युनिस्ट अपने पाँव देश में रखकर और अपना दिमाग देश के बाहर रख कर काम करते रहे हैं। समय और राजनीतिक उथल-पुथल ने उनके आधार को देश के अनेक भागों में क्षतिग्रस्त किया है। पश्चिम बंगाल और केरल में उनके गढ़ अपनी ही सरकार की गलतियों, राजनीति में उनकी अपनी अप्रासंगिकता तथा संगठन में पड़ी दरारों के कारण लगभग टूटने के कगार पर हैं। भाजपा कृतसंकल्प है कि आगामी चुनाव में मतदाता केरल और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में वामपंथी सरकारों को पराजित करें। इन दोनों राज्यों में हमारी रणनीति मार्क्सवादी शासन समाप्त कर दो उद्देश्यों की पूर्ति करने की होगी, जिससे राज्य में लोगों का हित और पार्टी का सर्वाधिक हित पूरा किया जा सके।

हमें तमिलनाडु, पांडिचेरी और असम इन तीन राज्यों में भी विधानसभा चुनावों का सामना करना है। इनमें से दो राज्यों—तमिलनाडु और पांडिचेरी—में हमारी प्रदेश इकाइयाँ राजग के सहयोगी दलों के साथ गठबंधन के रूप में परस्पर संतोषजनक सहमति के आधार पर चुनाव मैदान में उतर रही हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा गठबंधन लोगों का जनादेश प्राप्त कर इन राज्यों में सफल होगा।

असम में हमारी प्रदेश इकाई हमारी पार्टी के चुनाव प्रकोष्ठ द्वारा तय की गई सीटों के अनुरूप अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह अत्यंत संवेदनशील राज्य है और हमारी चुनावी रणनीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि असम और हमारी पार्टी के हित अधिक-से-अधिक पूरे हो सकें। मुझे यह देखकर खुशी है कि इसी आधार पर हमारी असम इकाई काम कर रही है।

ऐसा लगता है कि 1999 में पिछले मध्यावधि चुनावों में भारत के मतदाताओं ने जो सबक हमारे देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को सिखाया था, उसने उससे कोई

सबक नहीं सीखा है। लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी को जिम्मेदारी की भावना से काम करना चाहिए, परंतु यहाँ उसने संसद् के अंदर और बाहर नकारात्मक भूमिका निभाने की बात तय की है। वह अवसाद के वशीभूत होकर हताश हो गई है। भाजपा के प्रति अंधाधुंध विरोध, घोर घृणा, सत्ता की बेतहाशा महत्त्वाकांक्षा, लोकतांत्रिक मानदंडों और परंपराओं को धृष्टतापूर्वक उल्लंघन करने वाला गैर-जिम्मेदार नेतृत्व—ये सभी बातें कांग्रेस पार्टी की खास पहचान बन चुकी है। लोकतंत्र के प्रति भाजपा की पूर्ण प्रतिबद्धता सर्व-विख्यात है। जहाँ हमारे देश में एक सजीव लोकतंत्र है, वहीं हमारी पार्टी लोकतंत्र पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए हमें इस बात की चिंता होती है कि विपक्षी पार्टी लोकतंत्र के तकाजों के अनुसार अपनी भूमिका नहीं निभा रही है।

जिस प्रकार से तहलका डॉट कॉम द्वारा लगाए गए आरोपों पर विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष ने उन्मादकारी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वह एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता के लिए शोभा नहीं देता है। आरोप लगाए गए हैं और उन्हें अभी सिद्ध किया जाना बाकी है। पार्टी और उसके अध्यक्ष की स्वाभाविक प्रतिक्रिया और माँग यही होनी चाहिए कि अच्छी तरह पूरी जाँच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाए, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। इस स्थिति में लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए कि संसद् में जमकर बहस हो। देश इसी बात की आशा करता है और देश में लोकतंत्र को मानने वाले यही चाहते हैं। परंतु फासीवाद की हिमायती लोकतांत्रिक पार्टी माँग करती है—'हम माँग करते हैं—आप गद्दी छोड़ दो'—क्या लोकतंत्र में इसी तरह की माँग का कोई स्थान है? कांग्रेस शासन में जब कभी भी घोटाला हुआ, विपक्षी पार्टी ने जाँच की माँग की; परंतु कांग्रेस ने अपने बहुमत के बल पर इसे अस्वीकार किया। परंतु राजग सरकार बहस और जाँच कराने के लिए तैयार है, और ताज्जुब है कि कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं है। वह कहती है कि सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए और उसके बाद ही जाँच संभव होगी।

देश का कानून कहता है कि तब तक कोई दोषी नहीं होता है जब तक वह कानून की प्रक्रिया के अनुरूप दोषी नहीं पाया जाए। यहाँ कांग्रेस के कानून का नियम इसके ठीक उल्टा है। जिन पर वह आरोप लगा दें, बस वह दोषी है और उसे दंड दिया जाए। यदि हम उनसे पूछें कि सबूत कहाँ है, तो वे इधर-उधर बगलें झाँकने लगते हैं और कहते हैं कि बस इतना ही काफी है कि उन्हें दंड दिया गया है और दोष साबित हो गया। इसपर मुझे एक कहानी याद आती है, जो वर्षों पूर्व मैंने पढ़ी थी।

एक व्यक्ति दूर की गप हाँकता था कि उसने शेर को मार डाला है। लोगों को उसके दावे पर संदेह हुआ। उन्होंने उससे पूछा कि किस जगह पर तुमने शेर मारा था। उसने कहा कि मैंने एक पेड़ के नीचे मारा था। जब उससे पूछा, वह

जगह कौन सी है तो उसने पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि यह खड़ा पेड़ गवाह है।

मित्रो,

मैं प्रधानमंत्री और राजग सरकार को इस बात की बधाई देता हूँ कि उसने किसी सेवारत या सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से पूरी जाँच करने का निर्णय लिया है। ऐसा ही निर्णय लिया जाना चाहिए था। भाजपा चाहती है कि तहलका डॉट कॉम के मामले के हर पहलू की अच्छी तरह जाँच हो और सच सामने लाया जाए। दोषी को दंड अवश्य मिले।

हम सभी के मन में बड़ी पीड़ा और दुःख है कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें श्री बंगारू लक्ष्मण को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। हमारे विरोधियों ने ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की, जिसमें हमारे नेतृत्व की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर दिया जाए। श्री बंगारू लक्ष्मण ने पार्टी की सच्ची परंपराओं के अनुरूप ऐसी स्थिति में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने में जरा सी भी देर नहीं की और स्वयं को निष्पक्ष जाँच के लिए प्रस्तुत कर दिया है। हम सभी को उस दिन की प्रतीक्षा है, जो जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है, जब श्री बंगारू का कथन सही सिद्ध होगा और पता चलेगा कि वह निर्दोष हैं, उन्हें षड़यंत्रकारी ढंग से फँसाया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार अग्नि परीक्षा से निकलने के बाद फिर से उनकी सेवाएँ उपलब्ध होने पर उनके व्यक्तित्व के अनुरूप तथा पार्टी के सर्वोच्च हित में उनकी सेवाओं का संपूर्ण उपयोग किया जाएगा।

मित्रो, सरकार ने हाल में दूसरे चरण के सुधार शुरू किए हैं। आशाओं के विपरीत सभी ने बजट का स्वागत किया है। कहीं-न-कहीं से, किसी-न-किसी की ओर से कुछ आलोचना होती ही है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी बजट संपूर्ण नहीं हो सकता है। हर बजट में उस वर्ष की भूतल वास्तविकताओं तथा देश की दीर्घ और अल्पकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। पहली बार इस बात का प्रयास किया गया है कि बजट बनाते हुए देश की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। हम सरकार और वित्त मंत्री को उनके इस साहसी कदम पर बधाई देते हैं।

हालाँकि जमा राशियों पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज दर की कमी समग्र रूप से कम ब्याज दर पर ऋण देने के लिए और अधिक निवेश को ध्यान में रखकर की गई है; परंतु इससे छोटे जमाकर्ताओं में कुछ नाराजगी पैदा हुई है। लोकतंत्र में यथासंभव समाज के अधिकतर वर्गों को साथ लेकर चलना सरकार के लिए आवश्यक होता है। अतः सरकार से हमारा अनुरोध है कि वह इस बात पर गौर करे कि क्या प्रभावित लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है कि वे सरकार के बजट प्रस्तावों से राहत महसूस करें।

मित्रो,

हमने प्रगति के अपने मार्ग में अनेक बाधाओं पर विजय प्राप्त की है। अभी हमें एवरेस्ट शिखर पर पहुँचना है। संभव है हमें आगे बढ़ने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तेनजिंग नोर्गे ने कभी कहा था कि उन्हें एवरेस्ट पर्वतारोहण के समय अंतिम 100 मीटर की चढ़ाई चढ़ने में सबसे अधिक कठिनाई महसूस हुई थी। हम सब इस बात को ध्यान में रखें। हमें राजग को सुदृढ़ बनाना है। यह भी अत्यंत आवश्यक है कि हम भाजपा को आज की तुलना में कहीं अधिक सुदृढ़ बनाएँ।

हमने अपनी राजनीतिक यात्रा में अनेक संकटों का सामना किया है। भारतीय जनसंघ की स्थापना के दो वर्ष के अंदर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु, जब हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे तभी मध्यरात्रि में दीनदयालजी की हत्या, 1975 में आपातकाल का सामना, जिसमें हमारे नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया था और यह भी मालूम नहीं था कि वे कब जेल से बाहर आएँगे, जनता पार्टी से बाहर आना और फिर शुरू से अपने को खड़ा करना तथा 1984 में लोकसभा में मात्र दो सीटों तक सिमट जाना—ये संकटकाल की कुछ घटनाएँ हैं जिनका हमने सामना किया और फिर साहस तथा कृतसंकल्प के साथ उनपर विजय पाई। हाल में तहलका डॉट कॉम भी हमारे सामने एक चुनौती है, जिसके जरिए हमारी पार्टी को गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया गया है। परंतु श्री अटलजी तथा हमारी पार्टी के अन्य प्रतिष्ठित नेताओं, अपनी पार्टी के लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं और साथ ही देशवासियों के विशाल समर्थन से मुझे विश्वास है कि हम इस कठिनाई से उबर आएँगे और हमारे विरोधी पराजित होंगे। आइए, हम अपने उद्देश्य पर भरोसा कर, अपने आप पर भरोसा कर, अपने नेतृत्व पर भरोसा कर और अपने निर्दिष्ट लक्ष्य में भरोसा रखकर अपने झंडे को अपने देश के कोने-कोने में समाज के हर वर्ग तक और घर-घर में हर व्यक्ति तक ले जाने का संकल्प करें।

व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, अपने संगठनात्मक कामकाज में पारदर्शिता, अपने प्रयोजन, विचार और कार्यों के बीच एकता, अटल निष्ठा के साथ अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण, 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने का ध्येय, संपूर्ण भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोने का स्वप्न—यह सभी कुछ लंबे समय से हमारी पार्टी की पहचान रहा है। आइए, हम सब इसे अनुभव करें तथा इसे और अधिक प्रखर बनाएँ।

वंदे मारतम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली

27–29 जुलाई, 2001

मित्रो,

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में मुझे आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमने यह बैठक अगले महीने अमृतसर (पंजाब) में करने का निर्णय लिया था, और हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ बड़े उत्साह से आवश्यक तैयारी भी शुरू कर दी थी। चूँकि अगस्त के प्रथम पक्ष में कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक त्योहार आ रहे थे और हम अपनी कार्यकारिणी की बैठक को अगस्त के अंत तक स्थगित नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इस बैठक को एक बार फिर दिल्ली में रखने का निर्णय लिया। मैंने अपनी पंजाब इकाई को आश्वस्त किया है कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अगली बैठक पंजाब में अमृतसर में रखने पर अवश्य ही विचार करेगी।

मित्रो, संसद् का मानसून सत्र शुरू हो गया है। बहुत से अनिर्णीत बिलों पर विचार होना है। अन्य कई महत्त्वपूर्ण विषय भी चर्चा और बहस के लिए अवश्य ही उठाए जाएँगे। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में संसद् अत्यंत महत्त्वपूर्ण मंच होता है, जहाँ लोगों के हितों और उनकी चिंताओं पर मुक्त रूप से और विस्तार से चर्चा की जाती है। सरकार से उसकी प्रत्येक काररवाई और निर्णय के औचित्य को सिद्ध करने को कहा जाता है और विपक्ष का दायित्व होता है कि वह सरकार को इसे पूरा करने के लिए कहे। लोग संसद् से इसी बात की आशा करते हैं। परंतु दुर्भाग्य से अभी कुछ समय से संसद् को इस प्रकार से काम-काज करने नहीं दिया गया है। पिछले बजट सत्र में जो कुछ हुआ, मैं उसे स्मरण नहीं कराना चाहता हूँ। परंतु इससे प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को कष्ट पहुँचा, ऐसे प्रत्येक चिंतनशील व्यक्ति को पीड़ा पहुँची, जो चाहता है कि देश में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली ठीक ढंग से चले और इस स्थिति से उन लोगों का राजनीतिक प्रणाली से ही एक प्रकार से मोह भंग होने लगा, जिन्होंने देखा कि स्वयं

जनप्रतिनिधि ही उस संस्था की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों की भलाई के लिए सरकार की भूल-चूकों का ध्यान विशेष रूप से खींचा जा सकता है। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह सदैव एक दुःखद अध्याय के रूप में देखा जाएगा कि सार्वजनिक धन के प्रबंध के बारे में उससे जवाबदेही माँगने की बजाय क्रोध और आरोपों का दौर-दौरा रहा। यदि सत्तारूढ़ सरकार विपक्ष द्वारा बहस की माँग करने को ठुकरा देती तो हम हिचकिचाते हुए ही सही, विपक्ष द्वारा कई दिनों तक सदन की कार्यवाही को रोकने पर भी मौन सहमति देने को तैयार हैं। परंतु यहाँ तो बात ठीक इसके विपरीत है। सरकार तो पूरी और लंबी बहस कराने को तैयार थी और विपक्ष ही इससे भाग रहा था।

मैं पिछले सत्र की इस घटना को स्मरण न कराता, परंतु इस तथ्य को देखते हुए इसको स्मरण कराना पड़ा कि हमारी संसद् का एक और सत्र हो रहा है। मुझे पूरी आशा है कि विपक्ष और सरकार दोनों ही एक व्यवस्थापूर्ण और प्रयोजनशील सत्र संचालन पर सहमत होंगे, ताकि इस बार संसद् के समक्ष जो भी महत्त्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किए जाने हैं, उनपर शांतिपूर्ण ढंग से और शांतचित्त से चर्चा हो सके। इसी में संसदीय लोकतंत्र की सफलता है और भावी पीढ़ी के प्रति हमारी यही जिम्मेदारी बनती है कि हम संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को उसके उत्कर्ष तक ले जाएँ।

पिछली कार्यकारिणी की बैठक के बाद केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल और असम के पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें वामपंथियों को काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ा है और केरल में उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में भी यदि सरकार-विरोधी वोटों का विभाजन न होता तो वहाँ भी उसे अपनी लोकप्रियता का पता चल जाता। यहाँ वामपंथी चुनाव की जीत उतनी नहीं हुई है, जितना विपक्ष स्वयं हारा है। तमिलनाडु में आश्चर्य हुआ है, परंतु जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। चूँकि ए.आई.ए.डी.एम.के. की नेता द्वारा मुख्यमंत्री का कार्यभार सँभालने का मामला उच्चतम न्यायालय के सामने है, अतः मैं इसपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। परंतु मुझे विश्वास है कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय बिलकुल स्पष्ट निर्णय देगा, ताकि राज्यपाल या निर्वाचन अधिकारी कोई भी भविष्य में ऐसे विषयों में निर्णय लेने में गलती न करें। असम में सत्ताधारी पार्टी चुनाव हार गई और मुख्य विपक्षी दल सत्ता में आ गया। अब समय ही बताएगा कि असम के लोगों ने सही निर्णय लिया है या नहीं। इन सभी पाँच राज्यों में जहाँ कहीं भी भाजपा के प्रतिनिधि चुने गए हैं, वहाँ सदन में अपनी मित्र पार्टियों के साथ समुचित तालमेल बैठाकर एक विपक्ष के रूप में अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करें।

मेरा कर्तव्य है कि मैं कार्यकारिणी का ध्यान एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय की ओर दिलाऊँ जो न केवल भाजपा के लिए अपितु राजग में अन्य सहयोगी दलों

के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूँ और मुझे कहते हुए गर्व है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों में पहले से कहीं बेहतर मित्रभाव और समझ-बूझ है और राजग अधिकाधिक एक जुट हो गया है। मैं इस अवसर पर राजग में अपने सभी सहयोगी दलों में से प्रत्येक दल को उनके सहयोग और रचनात्मक भूमिका के लिए बधाई देना चाहता हूँ।

परंतु राजग में एक-दो घटनाओं पर, विशेष रूप से पाँच विधानसभाओं के समय की घटनाओं पर, ध्यान देने की जरूरत है। राजग में हमारे दो सहयोगी दलों ने अपने ही कारणों से उपयुक्त राज्यों में चुनाव होने से पहले हमारा साथ छोड़ दिया। उनके छोड़ने से राजग की छवि पर कुछ असर तो पड़ा-चाहे वह कितना ही महत्त्वहीन क्यों न हो-इतना तो हुआ ही कि इन दो दलों को छोड़ने से राजग की स्थिरता पर थोड़ी-बहुत चर्चा होने लगी। दूसरे, राजग ने ऐसा कोई उत्तेजनापूर्ण कार्य नहीं किया था, जिससे यह दल राजग को छोड़कर जाते। तीसरे, जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने राजग का साथ छोड़ा था, उसे सिद्ध कर लेने के बाद अब लगता है कि वे राजग में वापस आना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि राजग में किसी भी पार्टी को राजग को नुकसान पहुँचाने और फिर राजग से लाभ की माँग करने का हक नहीं है। भाजपा राजग का एक अंग मात्र है, हालाँकि यह ठीक है कि भाजपा इसका प्रमुख अंग है। मेरे विचार में एक बात अल्पकाल और दीर्घकाल, दोनों दृष्टियों से राजग के हित में होगी कि राजग में किसी पार्टी के प्रवेश या पुनः प्रवेश के बारे में कुछ मानदंड तय कर लिये जाएँ। मुझे आशा है कि समग्र रूप से राजग मेरे इस सुझाव पर समुचित रूप से विचार करेगा।

यहाँ तमिलनाडु में चुनाव के बाद की घटनाओं का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा। किसी भी नागरिक का, चाहे जो दर्जा हो या वह चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण माना जाता हो, यदि कोई ऐसा आधार बनता है, जिससे उसके खिलाफ कानूनी काररवाई की जानी चाहिए, तो इस बारे में राज्य सरकार के अधिकार पर कोई व्यक्ति आपत्ति नहीं करेगा। परंतु सभ्य समाज और संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार से यही उम्मीद की जाती है कि वह अच्छे मानदंड अपनाए, ताकि लोगों को भी उन्हीं मानदंडों को अपनाने की प्रेरणा मिले। संविधान में तो व्यक्तिशः नागरिकों के लिए विभिन्न स्वतंत्रताओं का प्रावधान है, परंतु यदि सत्तारूढ़ सरकार ढीठ बनकर उन प्रावधानों की अनदेखी कर देती है तो ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के पास क्या उपचार रह जाता है? किसी कागज पर 'चीनी' शब्द लिख देने भर से मीठे का स्वाद चखने को नहीं मिल जाता है। इसी प्रकार संवैधानिक अधिकार तब तक अधिकार रूप में परिणत नहीं होते हैं जब तक कि उन अधिकारों को भोगने न दिया जाए। तमिलनाडु में क्या हुआ—जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री श्री एम. करुणानिधि को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ बरताव किया, उससे पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। चाहे जो भी स्पष्टीकरण दिया

जाए, उससे संबंधित व्यक्तियों की आहत भावनाओं पर मलहम नहीं लग सकता है। हम ए.आई.ए.डी.एम.के. के नेतृत्व को बताना चाहते हैं कि सत्ता की शक्ति में अंधे होकर उसे अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध की खातिर शालीन व्यवहार के उन सभी मानदंडों को नष्ट करने का कोई हक नहीं है, जिसकी आशा उससे की जाती है। सत्ता की आड़ में कभी भी अपने किसी राजनीतिक विरोधी को अपमानित नहीं करना चाहिए। राज्य या निर्वाचित सरकार सहित किसी को भी किसी नागरिक की गरिमा को चोट पहुँचाने का हक नहीं पहुँचता है, क्योंकि मानव की गरिमा ही सामूहिक गरिमा का आधार है जिस पर समाज का निर्माण हुआ है।

मैं तमिलनाडु सरकार द्वारा इस मामले में की गई पूरी काररवाई की घोर निंदा करता हूँ। इस तथ्य को देखते हुए कि पुलिस अधिकारियों ने सभी सीमाएँ लाँघ डाली, जिससे यही सिद्ध होता है कि अधीनस्थ अधिकारी सत्ता में बैठे व्यक्तियों के मन को जानकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए किस तरह का व्यवहार करने को उत्सुक रहते हैं। कोई भी राज्य सरकार केंद्रीय मंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए बहाना नहीं ढूँढ़ सकती है। यदि ऐसी घटनाएँ होती हैं तो–जैसा कि लालू ने भी बिहार में जयललिता की नकल करने की बात कही है—देश में कोई व्यवस्थित सरकार बन ही नहीं सकती है, क्योंकि इस स्थिति में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहित कोई भी व्यक्ति देश में सुरक्षित रह ही नहीं जाएगा। किसी भी सरकार को कोई भी आड़ लेकर अराजकता की स्थिति पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे सभ्य सरकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। भाजपा इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करती है और हम कभी भी देश में इस प्रकार की अराजकता पैदा नहीं होने देंगे।

मुझे विश्वास है कि केंद्रीय सरकार भी इस बारे में कदम उठाने पर विचार कर रही होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश में अन्यत्र कहीं भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। यदि कोई भी सत्ता का केंद्र मानव-गरिमा जैसे स्वर्णिम नियम का उल्लंघन कर इस नियम का तिरस्कार करता है तो उसे परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे और तभी ऐसी स्थिति पर अपेक्षित रोक लग सकेगी।

मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घटी हैं। युद्ध विराम के विस्तार से उत्पन्न स्थिति के पीछे अधिक कारण गलतफहमी और आपसी समझ का अभाव रहा है। गलतफहमी पैदा होने का कारण यह है कि युद्धविराम को अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ाने से मणिपुर तथा अन्य कुछ राज्यों की प्रादेशिक अखंडता को खतरा हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस समझौते से न तो अभी और न ही भविष्य में कभी प्रादेशिक अखंडता पर आँच आएगी; परंतु यह स्पष्टीकरण मणिपुर में गड़बड़ी फैलने के बाद आया, जहाँ हिंसा भड़काने के लिए लोगों की भावनात्मक आशंकाओं से लाभ उठाया गया। अच्छा तो यह होता कि यदि

समझौते में ही आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिया जाता। एक बार जब जनसमूह में इस तरह की आशंकाओं पर आक्रोश भर जाता है तो चाहे जो तर्क और स्पष्टीकरण दिए जाएँ, सभी बेकार सिद्ध होते हैं। यही बात मणिपुर में देखने में आ रही है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने ही मणिपुर और अन्य राज्यों के लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। मुझे विश्वास है कि केंद्रीय सरकार मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को विश्वास दिला सकेगी कि उनकी प्रादेशिक अखंडता न केवल अभी बल्कि भविष्य में भी ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी।

इस वर्ष सूखे और बाढ़ की घटनाओं की भी पुनरावृत्ति हुई है। जहाँ हमारे देश के कुछ भागों में, जैसे राजस्थान, गुजरात आदि में सूखे की हालत से जूझना पड़ा है वहाँ उड़ीसा भारी वर्षा और बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। मुझे विश्वास है कि संबंधित राज्य सरकारें लोगों को राहत पहुँचाने के उपाय करने में अपना पूरा प्रयास करेंगी। मुझे यह भी विश्वास है कि केंद्र सरकार भी यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्रीय सहायता की कमी के कारण राहत के उपायों में कमी नहीं आएगी, मैं उन सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों से भी अपील करता हूँ, जो सदैव किसी भी राष्ट्रीय आपदा के समय प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने में आगे रहे हैं, कि वे सरकारी एजेंसियों के प्रयासों में साथ मिलकर राहत कार्यों में पर्याप्त सहायता दें। मुझे इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे देश में पार्टी की हमारी इकाइयाँ उड़ीसा इकाई को राहत कार्यों में अधिक-से-अधिक सहयोग देंगी।

सूखा, बाढ़ और चक्रवात—ये सभी प्रतिवर्ष हमारे देश में आते रहते हैं। अतः आवश्यक है कि ऐसे निरोधात्मक उपाय किए जाएँ जो इस तरह की विभीषिका को कम करने तथा राहत तंत्र को सतर्क रखने के लिए आवश्यक हों। प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और आवश्यक योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए, ताकि जान-माल की जो अपार हानि होती है, कम-से-कम हो और इस प्रकार लोगों की जो दुर्दशा होती है, उससे बचा जा सके। इस कार्य के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा आयुक्तों की नियुक्ति करने में तेजी लानी चाहिए।

केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अत्यधिक परिश्रम कर रही है। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर ले जाने के लिए अनेकानेक उपाय किए हैं। देश में अच्छी मानसून वर्षा और कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के कारण देश में खाद्यान्न का भरपूर उत्पादन हुआ है, जिससे हमारा खाद्य भंडार आवश्यकता से अधिक भर गया है। सरकार ने निर्धनतम लोगों, किसानों, महिलाओं आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक योजनाएँ शुरू की हैं, जिनकी बहुत सराहना भी हुई है। जब यह सभी योजनाएँ पूरी तरह से कार्यान्वित

हो जाएँगी तो निश्चित ही आर्थिक क्षेत्र में बहुत सुधार होगा और गरीब वर्ग के लोग निश्चित ही बेहतर स्तर का जीवन बिता सकेंगे।

परंतु इस तरह की भावना भी फैल रही है कि देश में खाद्यान्न की कमी की हालत से हटकर अब खाद्यान्न की अधिकता के कारण कुछ अपने किस्म की ही समस्याएँ खड़ी हो गई हैं, जिन्हें हम खाद्यान्न की अधिकता की समस्या कहते हैं। ऐसी एक समस्या सरकार के गोदामों में इस समय भारी भंडारण और बाजार में भी खाद्यान्न का अधिक भंडार होना है। ऐसी परिस्थितियों में किसान के पास जो भंडार पड़ा है उसे बेचने के लिए बाजार में खरीददार उपलब्ध नहीं हैं। हमारे किसान इतने समर्थ नहीं हैं कि वे खाद्यान्न का भंडार अपने पास रख सकें और अनुकूल समय पर उसे बेचने के लिए इंतजार कर सकें। सरकार के पास भी इस समय जितना भंडार है वह भी क्षमता से अधिक है और भंडारण की इतनी सुविधाएँ नहीं हैं कि वे बाजार से और भी खरीददारी कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में किसानों पर विपदा आ पड़ती है और उसे तुरंत राहत की जरूरत होती है। जरूरी हो गया है कि अनाज की मुक्त आवाजाही देश के एक कोने से दूसरे कोने तक संभव बनाई जा सके और आवश्यक वस्तु अधिनियम में समुचित संशोधन करना भी आवश्यक होगा, ताकि देश के एक भाग से दूसरे भाग तक मुक्त रूप से अनाज को लाया-ले जाया जा सके। किसानों को सलाह देने की आवश्यकता है कि वे कौन सी कृषि उपज उगाएँ। देश में अनाज की कमी को पूरा करने के लिए हमने खाद्यान्न के परिमाणात्मक उत्पादन को अपनाया, परंतु अब जब हम जरूरत से अधिक उत्पादन की स्थिति में पहुँच गए हैं तो कृषकों को अच्छे किस्म के उत्पादन करने के बारे में मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा देने की आवश्यकता है, ताकि वे इसमें सुधार कर सकें, दूसरों से सफलतापूर्वक मुक़ाबला कर सकें और अपने देश को उनकी गुणवत्ता के बारे में ब्राण्ड नाम प्राप्त हो सके।

घोषित योजनाओं में से अभी भी बहुत सी योजनाएँ और आश्वासन पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हुए हैं। लगता है कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को देने में प्रक्रियात्मक विलंब हो रहा है। गाँवों को सड़कों से जोड़ने संबंधी परियोजनाओं, लघु बिजली परियोजनाओं, विशेष रूप से आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में युगों पुराने अधिनियम, जैसे वन अधिनियम और पर्यावरण स्वीकृति लेने संबंधी नियम बाधक बनते हैं। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण बैंकों से, विशेष रूप से नाबार्ड से, कृषि क्षेत्र को पर्याप्त धनराशि नहीं पहुँच रही है।

मुझे बताया गया है कि सभी केंद्रीय योजनाओं को यथोचित रूप से कार्यान्वित करने को सुनिश्चित बनाने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास क्षेत्र, लघु क्षेत्र या अन्य किसी भी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि इस समय कोई तंत्र नहीं है, जिससे इन योजनाओं के कार्यक्रम पर नजर

रखी जा सके। मैं समझता हूँ कि इस विषय पर सरकार को यथोचित ध्यान और महत्त्व देने की आवश्यकता है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श और सहयोग से इन योजनाओं पर नजर रखने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कोई तंत्र बनाने की व्यवस्था करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन योजनाओं का यथोचित कार्यान्वयन हो और जिन वर्गों के लिए यह योजना है, उन्हें अवश्य ही इन योजनाओं का लाभ मिले। भविष्य में जब कभी भी मुख्यमंत्रियों की बैठक हो, उसमें प्रधानमंत्री राज्यों से इस विषय पर सहयोग करने की अपील कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। देश के लोगों को यह महसूस कराने में यह बहुत बड़ा कदम होगा कि योजनाएँ यों ही पड़ी रहने के लिए नहीं हैं बल्कि लोगों के लाभ के लिए इनका कार्यान्वयन होना चाहिए।

सरकार को लोगों के स्तर को सुधारने के बारे में किए जाने वाले अपने अनेकानेक उपायों के बारे में भी उन्हें जानकारी देनी चाहिए। मंत्रालयों को लोगों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए किए जा रहे अपने कार्यक्रमों के बारे में पुस्तकें आदि प्रकाशित करनी चाहिए। इनका प्रकाशन सभी भाषाओं में होना चाहिए और व्यापक रूप से वितरित की जानी चाहिए। इससे पार्टी के कार्यकर्ता और जनसामान्य को उठाए जा रहे कदमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। यह भी आवश्यक है कि संबंधित मंत्रीगण देश में व्यापक दौरे करें और समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नजर रखें तथा लोगों को जानकारी देते रहें।

हमारे प्रधानमंत्री अनेक अवसरों पर कहते रहे हैं कि इस विषय में पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने संबंधित मंत्रियों के साथ समय-समय पर बैठकें करना शुरू कर दिया है, ताकि पार्टी को सरकार के कार्यों की जानकारी मिल सके।

हमने अपने चेन्नई घोषणा-पत्र में स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि सरकार को नियामक की भूमिका न निभाकर, सुविधा-प्रदाता की भूमिका निभानी चाहिए। हमारे इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने जान-बूझकर नियामक अर्थव्यवस्था से दूर हटकर उदारीकरण की ओर जाने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है—सुविधा-उपायी अर्थव्यवस्था। इस शताब्दी के आरंभ का यह दशक उदारीकरण का दशक है। हमें उदारीकरण के मार्ग पर और आगे बढ़ना है; परंतु साथ ही हमें पिछले दशक में किए गए उदारीकरण का, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव और फलितार्थ का आकलन भी करना होगा, यदि कहीं कोई कमजोरी है तो उसकी पहचान करनी होगी। आवश्यकता हो तो उसे सुधारना होगा और फिर उदारीकरण की तरफ अपनी यात्रा पर बढ़ते हुए आगे के कदम उठाने होंगे। मैं महसूस करता हूँ कि इस प्रकार का उद्देश्यमूलक आकलन हमें सही मार्ग पर ले जाएगा।

नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और बहुत ही घनिष्ठ मित्र देश है। नेपाल में हाल की घटनाओं से हम सभी को गहरा धक्का, पीड़ा और दुःख पहुँचा है। वहाँ जो कुछ घटा है वह कभी नहीं घटना चाहिए था और जिस घटना के बारे में लोगों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, वही घटना वहाँ घटी है। स्वाभाविक है कि नेपाल के शाही निवास पर जो घटना घटी है उससे भारत के लोग बहुत अधिक चिंतित हैं, क्योंकि नेपाल और भारत, दोनों ही सस्कृति, धर्म, इतिहास और सामाजिक संबंधों के अटूट बंधनों में बँधे हुए हैं। भारत नेपाल के प्रति शुभकामनाएँ व्यक्त करता है और वर्तमान संकट की घड़ी से उबरने के लिए भारत नेपाल के लिए जो भी सहायता कर सकता है, वह सहायता देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा।

पिछले सप्ताह पूरे विश्व की निगाहें भारत पर, या कहें आगरा पर थीं। भारत-पाक शिखर वार्त्ता आगरा में संपन्न हुई। हमारे प्रधानमंत्री ने चीन सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दृष्टि से कहीं अधिक बेहतर और कारगर ढंग से साहसी पहल के उपाय किए, जो उनके पूर्ववर्तियों ने भी नहीं किए थे, साथ ही अपने देश की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए भी कदम उठाए हैं। उनकी सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधरे हैं। पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के संबंध में भी शांति के प्रयास किए। उनकी लाहौर बस यात्रा, जम्मू और कश्मीर में एकतरफा युद्ध विराम, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बातचीत के लिए भारत में आने का निमंत्रण—यह सभी कुछ उनके द्वारा की गई पहल के भाग हैं और स्वाभाविक है कि भारत ने भारत और पाकिस्तान के बीच सभी द्विपक्षी मामलों के शांतिपूर्ण समाधान के बारे में अपनी नेकनीयती सिद्ध कर दी है।

आशा के अनुरूप आगरा शिखर वार्त्ता के परिणाम नहीं निकल पाए। इसके लिए अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। आगरा शिखर वार्त्ता अपने आप में अंत नहीं है, यह तो ऐसे अनेक प्रयासों में से एक प्रयास था। भारत को पाकिस्तान से बात करने में भय क्यों हो और डरकर बात क्यों की जाए ? भारत ने एक बार नहीं, अनेक बार सिद्ध कर दिया है कि कोई भी हम पर फौजी ताकत अथवा आर्थिक उपायों की धमकी देकर धौंस नहीं जमा सकता है। राजग सरकार के अधीन और श्री अटलजी के योग्य प्रधानमंत्रित्व में भारत किसी से भी मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है और समर्थ भी।

आगरा में अटल बिहारी वाजपेयी की राजमर्मज्ञता प्रकट हुई और मुशर्रफ का सैनिक रूप सामने आया। यदि मुशर्रफ इतना समझ लेते कि वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनकर भारत आए हैं और अपने देश तथा हमारे देश के बीच बकाया मुद्दों का समाधान करने के लिए आए हैं तो आगरा में कुछ और ही बात होती। जिस ढंग से उन्होंने मेहमान देश के विचारों की उपेक्षा की और

हुर्रियत के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया और उनसे बात की, जिस तरह से उन्होंने आगरा में उनके साथ बरती राजनयिक शालीनता और सौहार्द्रता को ताक पर रख दिया एवं नाश्ते पर अनौपचारिक बातचीत को प्रेस सम्मेलन बना दिया, उससे साफ पता चलता है कि उनसे जिस प्रकार की भूमिका के निर्वाह की आशा थी, उन्होंने इसका पूरी तरह निरादर किया है। जिस तरह से पपीते को पके चावल के दाने में छुपाकर नहीं रखा जा सकता है, उसी तरह पाकिस्तान भी इस तथ्य को छुपाने में सफल नहीं हो सकता है कि वह ही सीमा पार आतंकवाद का स्रोत और आधार है। तोते की तरह कश्मीर को मूल (कोर) मुद्दा रटते रहने से किसी पर, और खास तौर पर भारत के लोगों पर, कोई प्रभाव पड़नेवाला नहीं है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति को एक बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और श्री वाजपेयी भारत के निर्वाचित और सर्वमान्य नेता हैं। भारत में कश्मीर के बारे में पूरी तरह से राष्ट्रीय आम सहमति है और मुशर्रफ को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अतः वाजपेयीजी द्वारा उनके 'एक बिंदु एजेंडा' की अस्वीकृति पूरे मंत्रिमंडल और पूरे देश की ओर से अस्वीकृति है।

बेहतर होगा कि पाकिस्तान इस बात को याद रखे कि भारत के लोगों की सच्ची प्रतिनिधि संस्था भारत की संसद् है, जिसने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है तथा इसका संपूर्ण भाग भारत का अटूट अंग है।

भारत ने इस प्रस्ताव के माध्यम से साफ कर दिया है कि भारत को ही जम्मू और कश्मीर सहित भारत के किसी भी भाग के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है और भविष्य में भी निर्णय लेने का अधिकार बना रहेगा और अन्य किसी को भी धर्म या अन्य किसी आधार पर यह हक नहीं है कि वे जिस हिस्से में रहते हैं उसके लिए अलग दर्जे की माँग करें। यदि पाकिस्तान इस बात को समझ ले तो यह भारत के साथ उसके भावी संबंधों के लिए बेहतर होगा।

विदेशी संबंधों में कूटनीतिक सौजन्यता और कूटनीतिक शालीनता आवश्यक अंग होती हैं और भारत ने सदैव इनका सम्मान किया है। परंतु जब दूसरा पक्ष अपने क्षणिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए जान-बूझकर इनका उल्लंघन करता है तो हमारे लिए भी आवश्यक हो जाता है कि अपनी सौजन्यता और शालीनता को बनाए रखते हुए हम भी अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिकारी उपाय करें। आगरा शिखर वार्त्ता से हमें यह सबक याद रखना होगा।

हम सभी प्रधानमंत्री द्वारा आगरा शिखर आयोजित करने में की गई शांति-पहल की सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री ने बातचीत के लिए पाकिस्तान के वापसी दौरे के आमंत्रण को स्वीकार कर सही निर्णय लिया है। हम वाजपेयीजी को बधाई देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ आमने-सामने अपनी वार्त्ता में दृढ़

रुख अपनाया और उन्हें समझा दिया कि न केवल जम्मू और कश्मीर को, बल्कि संपूर्ण भारत-पाक संबंधों को बिलकुल अलग परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।

मित्रो,

मैं आजकल अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के उद्देश्य से दौरा कर रहा हूँ। मैं कुछ ही राज्यों में जा सका हूँ। मैंने अपने कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखा है। मैं जहाँ कहीं भी गया, वहाँ मैंने देखा है कि हमारे सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया है। हमें अपनी प्रयासों में तेजी लानी होगी। हमारे प्राथमिक सदस्यों की एक विशाल संख्या है। जब तक हम उन्हें समुचित रूप से उत्प्रेरणा और प्रशिक्षण नहीं देंगे और जब तक वे अपने उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक हम इस विशाल संख्या को शक्ति में परिणित नहीं कर पाएँगे। हमें चाहिए कि हम अधिकाधिक प्राथमिक सदस्यों को अपने संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदार बनाएँ। जब तक नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच निरंतर आदान-प्रदान नहीं होगा तब तक यह भागीदारी संभव नहीं हो पाएगी। मैं केंद्रीय स्तर से लेकर निम्नतम स्तर तक अपने सभी पदाधिकारियों से अपील करता हूँ कि वे कार्यकर्ताओं से निरंतर बातचीत करने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करें, कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए पार्टी का संदेश उन तक पहुँचाएँ, उनके माध्यम से हम अपनी सरकार के कार्य-प्रदर्शन की जानकारी लोगों तक पहुचाएँ एवं भारत को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करें।

यही कार्य हम सभी के सामने है और हममें से सभी को इस जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए तथा इसमें हर संभव योगदान देना चाहिए।

मैं अपना भाषण विश्व प्रसिद्ध विद्वान इतिहासकार आर्नोल्ड टॉयनबी की उल्लेखनीय उक्ति से करना चाहूँगा। सन् 1952 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि संभावना है कि आज का विजित भारत कल इक्कीसवीं शताब्दी में अपने विजेताओं पर विजयी होगा। हमने अपने चेन्नई घोषणा-पत्र में संकल्प किया था कि हम 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाएँगे। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अब हम पर निर्भर करता है कि हम जितनी जल्दी हो सके अपने इस संकल्प को पूरा करें।

वंदेमातरम्।



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

अमृतसर 2-3 नवंबर, 2001

प्रिय मित्रो,

मैं अमृतसर की पवित्र नगरी में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस नगर में यह बैठक पिछली बार ही हो जानी चाहिए थी, परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण दिल्ली में बैठक रखनी पड़ी। पंजाब इकाई ने जोर दिया कि उसे यह बैठक आयोजित करने का अवसर मिलना चाहिए। मैं पंजाब इकाई को धन्यवाद देता हूँ कि दो दिन की इस बैठक के लिए उसने अत्युत्तम प्रबंध किए हैं।

अमृतसर केवल ऐतिहासिक नगर ही नहीं है, बल्कि यह भारत के अत्यंत महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। इसका एक लंबा और आह्लादकारी इतिहास रहा है, जिसमें हम सभी भागीदार हैं। इसी कारण इस बैठक का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल सत्ता में सहभागी हैं। अकाली दल स्वयं ही अपने बल पर सरकार बना सकता था; परंतु चूँकि हमारा गठबंधन लंबे समय से चला आ रहा था और दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इसलिए अकाली दल ने जोर दिया कि हम उनके साथ सत्ता में शामिल हों। अकाली दल से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और दोनों के बीच ठीक समझदारी और सामंजस्य से मुझे विश्वास है कि हमारा गठबंधन चुनाव की चुनौती को स्वीकार करेगा और सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेगा।

मित्रो,

हमारे क्षेत्र में एक युद्ध चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में और हमारे पड़ोस में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ है। हम सभी जानते हैं कि 11 सितंबर को आतंकवादी समूह द्वारा अमेरिका पर किया गया हमला उस दिन अमेरिका के लिए काला दिवस सिद्ध हुआ, इस घटना में आतंकवादी-अपहरणकर्ताओं ने

अपने दो विमान न्यूयॉर्क में दो ट्रेड टॉवरों और वाशिंगटन में पेंटागन से जा टकराए। कुछ हजार लोगों के प्राण चले गए। जान-माल के नुकसान से भी बड़ी बात यह है कि अमरीकी लोगों और सरकार को महसूस हुआ कि आतंकवादियों ने उनकी दुर्जेय तथा अनुलंघनीय स्थिति को चुनौती दी है। उस समय तक अमेरिका ने आतंकवाद को पहचानने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जो विश्व के विभिन्न भागों में और इससे भी अधिक सामान्य रूप से भारत में तथा विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में पाँव फैलाए हुआ था। अमेरिका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के हमले से अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ने को उत्प्रेरित किया, जिससे राष्ट्रपति बुश ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए अमरीकी प्रयासों में अपना समर्थन दिया। तालिबान के खिलाफ सैनिक काररवाई और अफगानिस्तान में बिन लादेन को ढूँढ़ निकालने के प्रयास पूरे जोर-शोर से चल रहे हैं।

हमें आतंकवादियों की चुनौती को स्वीकार करना होगा और इसके साथ संघर्ष करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ मुंबई में और भारत में अन्य स्थलों पर हुआ है, जो कुछ न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हुआ है, ऐसा ही सबकुछ विश्व में कहीं पर भी हो सकता है। कोई भी सभ्य देश इससे बचा नहीं रहेगा। यदि सभ्यता को आतंकवाद के खतरों से बचाना है तो मानव जाति को एकजुट होना ही पड़ेगा और इसका साहसपूर्वक मुकाबला करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार ने इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और इसीलिए उसने आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अपना पूरा सहयोग दिया है।

आतंकवाद को जीवन के अलग-अलग भागों में बाँटकर नहीं देखा जा सकता है। यह संपूर्ण है और इसको पूर्णतः समाप्त करके ही दम लेना होगा। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अमेरिका में हुए हमले को जम्मू और कश्मीर में या भारत में कहीं अन्य किसी स्थल पर अथवा विश्व में भी किसी स्थल पर हो रहे हमलों से अलग रखकर न देखा जाए, बल्कि आतंकवाद को विश्व में जड़-मूल से उखाड़ फेंका जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रत्येक देश इस बात को समझे और इस धरती से आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करे। सैन्य काररवाई कर बिन लादेन को दंड देने की अमेरिका की चिंता को हम समझ सकते हैं, जिसे तालिबान ने अपनी हिफाजत में रखकर संरक्षण दिया हुआ है। परंतु अमेरिका याद रखे कि यदि वह विश्व के अन्य भागों से भी आतंकवाद के खतरे को जड़-मूल से समाप्त करने के लिए भारत और अन्य देशों को सहयोग नहीं देता है तो अफगानिस्तान में मात्र तालिबान के आतंकवाद को समाप्त करने से वांछित परिणाम नहीं निकलेंगे। अंतरराष्ट्रीय

आतंकवाद ने अपने पाँव कई देशों में फैला लिये हैं और वह अमेरिका तथा अन्य देशों से बदला लेने के लिए किसी अन्य अड्डे से कुछ-न-कुछ करने का प्रयास करेगा। भारतीय जनता पार्टी उन सभी देशों से अपील करती है, जो इस क्रूर आतंकवाद से लड़ने के महान कार्य में सहयोग करने के लिए आगे आए हैं, कि इस कार्य में प्रयास पूर्ण होने चाहिए और किसी भी आतंकवादी संगठन को, चाहे वह विश्व में कहीं पर भी हो, बख्शा न जाए।

भारत देश के विभिन्न भागों में और जम्मू तथा कश्मीर में भी आतंकवादी हमलों का मुकाबला कर रहा है। हम इस बुराई से एक दशक से भी अधिक समय से जूझते आ रहे हैं और इसके खिलाफ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आतंकवाद का नामो-निशान नहीं मिट जाता है। 11 सितंबर को विश्व ने मिलकर आतंकवाद की निंदा की है। अब हम यह विश्व पर छोड़ते हैं कि वह आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के हमारे प्रयासों में सहयोग देता है या नहीं; परंतु हम आशा करते हैं कि विश्व इस स्थिति की गंभीरता को समझेगा और अपना सहयोग देने में दूर नहीं रहेगा। परंतु यदि किसी कारण से अफगानिस्तान में तालिबान के रूप में आतंकवाद को समाप्त करने के अमरीकी प्रयासों में सहयोग करनेवाले देश हमारे प्रयासों में सहयोग नहीं भी देते हैं तो भी मुझे विश्वास है कि इससे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सफलतापूर्वक किए जा रहे हमारे प्रयासों में कोई बाधा नहीं आएगी।

आतंकवाद को समाप्त करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमारी राजग सरकार आतंकवाद को समाप्त करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में हमारे सुरक्षा बल प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। जब तक पूरे राष्ट्र का समर्थन सरकार और हमारे सुरक्षा बलों को नहीं मिलता है तब तक उनके प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं। आतंकवाद की चुनौती पूरे देश के समक्ष एक चुनौती है, इसलिए पूरा राष्ट्र इस चुनौती को स्वीकार करता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के प्रयासों का पूरी तरह समर्थन करेगा। मैं विपक्षी दलों से विशेष अपील करता हूँ कि वे आतंकवादियों द्वारा खड़ी की गई चुनौती से लड़ने के लिए पार्टी या दलगत हितों को आड़े न आने दें। लोकतंत्र में हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं। परंतु जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाने का समय हो तो हम सभी को अपने मतभेद भुला देने चाहिए, सत्तारूढ़ सरकार को उसके प्रयासों में पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा के हित में किए जानेवाले उपायों में कोई मतभेद आड़े नहीं आने देना चाहिए।

इस प्रसंग में पाकिस्तान की भूमिका, बल्कि उससे भी अधिक राष्ट्रपति मुशर्रफ की भूमिका आशा के अनुरूप नहीं है। 11 सितंबर की घटनाओं और परिस्थितियों की विवशता के कारण पाकिस्तान को अफगानिस्तान में तालिबान

के खिलाफ अमेरिका के युद्ध-प्रयासों में सहयोग देना पड़ रहा है। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान का यह प्रयास इस स्थिति में फँसकर एक संतुलन रखने का कार्य लगता है; चूँकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान तालिबान और इसके आतंकवादियों को मदद व शह देता रहा है। विचित्र बात है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ दो मुँही बातें बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वह सीमा पार आतंकवाद को जेहाद का नाम देते हैं तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में आतंकवाद की बात को स्वीकार करते हैं। विश्व को उल्लू बनाकर अपने पक्ष में जनमत तैयार करने के प्रयासों में पाकिस्तान सफल नहीं हो सकता है। आतंकवाद तो आतंकवाद है—यह बात एकदम सीधी सी है। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त करने के बारे में अपने प्रयासों में विश्व समुदाय के साथ अपना सहयोग देने में सचमुच ईमानदार और गंभीर है तो बेहतर होगा कि वह अपनी धरती से सीमा पार आतंकवाद को बंद करे। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है बशर्ते कि वह आवश्यक शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करता है। भला पाकिस्तान अथवा वस्तुतः विश्व में कोई भी देश भारत से कैसे यह उम्मीद कर सकता है कि जब पाकिस्तान भारत के क्षेत्र में सीमा पार आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत जारी रखने के अनुरोध को स्वीकार कर ले। यदि राष्ट्रपति मुशर्रफ और पाकिस्तान पहले अपने आतंकवादी पंजों को हटा ले तो वह देखेगा कि भारत किस तरह पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है।

हमने बार-बार कहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के पक्ष में है। इसी प्रकार हम आशा करते हैं कि हमारे पड़ोसी देश भी सकारात्मक ढंग से व्यवहार करें। हमारी केंद्र सरकार अपने पड़ोसी देश बँगलादेश के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाती आ रही है। बँगलादेश में हाल में चुनाव हुए और वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है। भाजपा बँगलादेश की नई प्रधानमंत्री को बधाई देती है और उम्मीद करती है कि उनके नेतृत्व में भारत और बँगलादेश के बीच संबंध और अधिक सुधरेंगे। परंतु वहाँ पर नई सरकार द्वारा सत्ता सँभालने के बाद हाल में जो घटनाएँ हुई हैं, वे अत्यंत चिंता का विषय हैं, क्योंकि समाचार यह है कि वहाँ हिंदुओं को परेशान किया गया है। एक बार फिर बँगलादेश से शरणार्थियों की बाढ़ आनी शुरू हो गई है। भारत के सामने पहले ही बँगलादेश से आए घुसपैठियों की विकराल समस्या है और भारत में एक करोड़ से अधिक बँगलादेशियों की अवैध घुसपैठ के कारण हमारे पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में सामाजिक, आर्थिक और जन सांख्यिकीय जीवन में असंतुलन पैदा हो गया है। स्वाभाविक है कि हमारी सरकार ने भी इसपर गहरी चिंता व्यक्त की है। बँगलादेश से शरणार्थियों की बाढ़ रुकनी चाहिए। भाजपा को पूरी आशा है कि बँगलादेश की

नई सरकार इस दिशा में आवश्यक उपाए करेगी।

उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर विधानसभाओं के चुनावों की तैयारियाँ चल रही हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि इन राज्यों की इकाइयाँ इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने संगठनात्मक तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करें। अपने ढंग से राज्य विधानसभा चुनाव की एक-एक सीट का महत्त्व है। इन विधानसभा चुनावों के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी लगभग उसी समय होंगे और महाराष्ट्र में नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव भी तभी होंगे। मैं इन राज्यों के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि वे अपनी पार्टी को सफल बनाने के लिए कोई कोर-कसर न उठा रखें।

तमिलनाडु में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे। मैं तमिलनाडु इकाई को उसकी सफलता पर बधाई देता हूँ।

मित्रो,

मैंने पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने उद्‌घाटन भाषण के दौरान सरकार को सुझाव दिया था कि गरीबों को लाभ प्रदान वाली उसकी अनेक सुविचारित योजनाएँ जमीनी स्तर पर वस्तुतः कार्यान्वित नहीं हो रही हैं क्योंकि इनपर नजर रखने के लिए कोई तंत्र नहीं है। हमारे आर्थिक प्रस्ताव में भी हमने इस बात को उठाया था। इस बात से मेरा बहुत उत्साह बढ़ा है कि सरकार ने हमारे इस सुझाव पर विचार किया और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की कि आनेवाला वर्ष 'कार्यान्वयन वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा। इससे साफ पता चलता कि हमारी केंद्र सरकार किसी बात को सुनने वाली सरकार है, सुझावों पर गौर करने वाली सरकार है। एक बात और, हमने मंत्रालयों से अनुरोध किया था कि ऐसे प्रकाशन निकाले जाएँ जिनसे लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। मुझे यह स्वीकार करते हुए बड़ी खुशी है कि कुछ मंत्रालयों ने इस प्रकार के प्रकाशन निकाले हैं। इससे लोग समझ सकेंगे कि सरकार को उनकी समस्याओं के बारे में चिंता है और उन्हें यह भी मालूम हो सकेगा कि सरकार ने विभिन्न वर्गों के लोगों के हालात सुधारने के लिए कौन-कौन से उपाय किए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि वे इन प्रकाशनों की मदद से लोगों को सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से अवगत कराएँ, ताकि व्यापक रूप से लोगों को पता चल जाए कि उन योजनाओं से कैसे लाभ उठाया जाए।

इस संबंध में मैं विभिन्न सरकारों का विशिष्ट रूप से उल्लेख करना चाहूँगा जो वर्तमान संवैधानिक संघीय ढाँचे में राज्यों में शासन चला रही हैं। राज्यों को केंद्र सरकार की निर्धनता उन्मूलनकारी और रोजगार के अवसर पैदा करने वाली कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में पूरा सहयोग देना होगा। निःसंदेह,

राज्य सरकारें सहयोग प्रदान कर रही हैं। आज की स्थिति में आवश्यक है कि गतिशील सहयोग और समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि केंद्रीय योजनाओं को जल्दी-से-जल्दी और यथासंभव प्रभावकारी ढंग से पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच, विशेष रूप से केंद्र सरकार के आर्थिक मंत्रालयों और राज्यों के संबंधित मंत्रालयों के बीच परस्पर विचार-विमर्श को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कारगर ढंग से कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली तैयार कर सकें।

मैं सरकार का ध्यान सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग की मानसिक स्थिति और उनकी बदहाली की हालत की ओर दिलाना चाहता हूँ। भाजपा की अपनी कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, क्योंकि पार्टी मानती है कि ट्रेड यूनियनें स्वतंत्र होनी चाहिए और राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए; परंतु भाजपा हृदय से श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। आज जब देश सरकारी नियंत्रित अर्थव्यवस्था से हटकर उदारवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है तो कुछ समस्याएँ पैदा होना निश्चित है। यह सरकार जिन आर्थिक सुधारों को लेकर चल रही है, उनके फलस्वरूप श्रम-सुधार भी अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। यही कारण है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम और ठेका कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। संशोधन इस ढंग से किए जाने चाहिए कि इनसे निवेश प्रवाह में वृद्धि करके आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में मदद मिले। हमें रोजगार के अवसर भी बढ़ाने चाहिए। मेरे विचार से इस बात पर किसी को मतभेद नहीं होगा कि ये कदम उन लाखों युवाओं के हित के लिए अत्यंत आवश्यक हैं जो अपने जीविकोपार्जन के अवसरों के लिए व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उक्त अधिनियमों में संशोधन करने के लिए सरकार के प्रयासों को ऐसी दृष्टि से न देखा जाए कि ये संशोधन श्रमिकों के हितों के विरुद्ध हैं। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों से हार्दिक अपील करता हूँ कि वे इस प्रयास में सरकार को सहयोग दें, ताकि राजनीतिक मतभेद बेरोजगार युवाओं के हितों के लिए बाधक न बनें।

परंतु साथ ही मैं सरकार को यह सुझाव भी देना चाहूँगा कि इस संशोधन के साथ-साथ सरकार को मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को भी तीव्र गति प्रदान करनी चाहिए। श्रमिकों को भी आश्वस्त होना चाहिए कि जब उनसे राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने और बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करने की आशा की जाती है तो उनके हितों की भी रक्षा होती है। श्रमिक आर्थिक हितों के संवर्धन में हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से हार्दिक अपील करता हूँ कि वह मुआवजा राशि को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करे, जिससे प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 15 दिन की वेतन राशि

को बढ़ाकर 45 दिन की वेतन राशि के बराबर कर दिया जाए और प्रभावित मजदूरों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय पुनरुद्धार कोष (नेशनल रिन्यूअल फंड) स्थापित किया जाए। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के श्रमिकों की तरह निजी क्षेत्र के श्रमिकों को भी बीमा सुरक्षा के लाभ प्रदान किए जाएँ। निःसंदेह श्रमिकों और सरकार के एक विभाग के बीच बातचीत और पत्राचार चल रहा है, परंतु इसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश है, ताकि 'संवादहीनता' को कम-से-कम किया जा सके।

सरकार 2000 करोड़ रुपए की वाल्मीकि—अंबेडकर आवास योजना शुरू करने का निर्णय लेने के लिए बधाई की पात्र है, जिसके अंतर्गत नगर में रहनेवाले गरीबों को लाभ पहुँचेगा, जिसमें केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत की भागीदारी रहेगी। स्वाभाविक है कि इससे इस्पात और सीमेंट जैसे उद्योगों का पुनरुद्धार होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ताकि नीतिगत मंतव्यों को यथाशीघ्र यथार्थता में परिणित किया जा सके। अतः इस प्रसंग में मैं सरकार से निम्नलिखित पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ :

1. भूमि संबंधी स्वामित्व के सभी विवादों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करना।
2. भूमि संबंधी स्वामित्व की आधारभूत पंजीकरण प्रणाली को सरल बनाना और सुधार करना।
3. स्टांप ड्यूटी कम करना जिससे कर-प्रवंचना कम-से-कम हो और लागत कम हो एवं रिहायशी इकाइयों का कब्जा मिलना सुनिश्चित हो जाए।
4. ऐसी तथाकथित कृषि भूमि के परिवर्तन संबंधी सभी बाधाएँ दूर हों, जहाँ उस भूमि पर किसी प्रकार की खेती नहीं हो रही है; इस प्रकार की भूमि दिल्ली जैसे नगरों में दिखाई पड़ती हैं।

निःसंदेह हाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने के उपाय के कारण सस्ते ऋण उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे निवेश प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस प्रकार अर्थव्यवस्था का पुरुत्थान होगा। ऋण देने पर ब्याज की कम दरों का अर्थ यह भी है कि बचत राशियों पर कम ब्याज मिलेगा। हम उन लोगों की कठिनाइयों को समझते हैं जो अपनी बचत राशियों पर मिलनेवाले ब्याज से अपना जीवन निर्वाह करते हैं; परंतु आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए यह कदम अनिवार्य है।

मैं सरकार द्वारा विचारार्थ एक और सुझाव की सिफारिश करता हूँ :

जब ब्याज की दरें कम हैं तो ये दरें उन बचत खातों पर भी स्वतः लागू हो जाती हैं, जो पहले से ही खुले हुए हैं। परंतु उन ऋण राशियों पर ब्याज की वही दरें चलती रहती हैं, जिन्हें पहले प्राप्त किया जा चुका है, चाहे बाद में ऋण देने

की ब्याज दरों में कमी कर दी गई हो। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में इन विसंगतियों को लाए, ताकि ऋण देने वाली राशि बचत और राशियों के बीच जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, उसमें समानता लाने के बारे में गंभीरता से सोचा जा सके।

विश्व व्यापार संगठन की अगली बैठक दोहा में होने वाली है। मुझे विश्वास है कि सरकार अपने इस निर्णय पर टिकी रहेगी कि जब तक पहले के कार्यान्वयन कार्यक्रमों का समाधान नहीं हो जाता है तब तक चर्चा के लिए किन्ही नए मुद्दों को लाने नहीं दिया जाएगा। मैं सरकार से गंभीरता से अपील करता हूँ कि वर्तमान ढाँचे में जो विसंगतियाँ हैं, विशेष रूप से जिनका प्रतिकूल प्रभाव हमारे किसानों और लघु क्षेत्र पर पड़ता है, उन्हें दोहा सम्मेलन में ठीक किया जाए।

मित्रो,

हमने अपनी राष्ट्रीय परिषद् का विशेष अधिवेशन बुलाकर इस वर्ष 21 अक्तूबर को अपनी 'राजनीति यात्रा' की स्वर्ण जयंती की शुरुआत का समारोह मनाया था। यह अधिवेशन बहुत सफल रहा। हमने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समारोह समिति बनाई है। यह समिति तय करेगी कि किस प्रकार के कार्यक्रम तय किए जाएँ। हमारे स्वर्ण जयंती समारोहों को मनाने का ढंग और उद्देश्य यह होना चाहिए कि ये देश के कोने-कोने तक पहुँचें, हमारा संदेश न केवल हमारे समाज के छोटे-से-छोटे वर्ग तक पहुँचे, बल्कि राजग सरकार की उपलब्धियाँ और योजनाएँ तथा स्कीमों की जानकारी भी उन्हें मिले। इससे हमारे संगठनात्मक, सामाजिक और चुनावी समर्थन का विस्तार करने में हमें मदद मिलनी चाहिए। इस अवसर का उपयोग हमें अपने उन सभी पुराने वयोवृद्ध जनों को भी लाने के लिए करना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोत्तम भाग बिताकर हमें हमारी राजनीतिक यात्रा में वर्तमान स्थान तक पहुँचाने में मदद की और हम इस वर्तमान स्थान तक पहुँचे। मुझे आशा है कि यह समिति इस बारे में आवश्यक मार्ग-निर्देश देगी।

मित्रो,

मैं देश में काफी घूमता रहा हूँ और हर स्थान पर अपने कार्यकर्ताओं से मिला हूँ। हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके अनुसार केंद्र द्वारा भेजे गए नेता एक दिन में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। हम देश के लगभग 350 जिलों में यह कार्यक्रम संपन्न कर चुके हैं और नवंबर के अंत से पहले बाकी जिलों में भी इस कार्य को पूरा कर लेंगे। इस बारे में हमें इन स्थानों से जो रिपोर्टें मिली हैं वे बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक हैं। सभी संबंधित लोगों ने इसका स्वागत किया है और इससे केंद्रीय नेताओं को मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क

करने में मदद मिली है। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार प्रदेशों के नेता और जिलों के नेता आगामी कुछ महीनों में मंडल बैठकें, स्थानीय समिति बैठकें आयोजित करें। इससे कार्यकर्ताओं के साथ निकटता और संवाद बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो सदा से ही हमारे संगठन की विशेषता रही है।

हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों के कारण हम इस स्थिति तक पहुँच पाए हैं कि आज भारतीय राजनीति पर हमारा कब्जा है। हमें न केवल इस स्थिति को कायम रखने के लिए, बल्कि शिखर तक पहुँचने के लिए और भी कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। हमारा शिखर समग्र राष्ट्रीय हित में संपूर्ण राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करना है। हमारा दायित्व है कि हम अपने कठोर सेवाभाव, समर्पणशीलता तथा अनुशासन के आधार पर एक सुसंगठित राजनीतिक शक्ति का निर्माण करें और इसी के माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुँचने में सफल होंगे, जो हमने अपने चेन्नई घोषणा-पत्र में अपने सामने रखा था; यह लक्ष्य है—21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाना।

धन्यवाद!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली 29 दिसंबर, 2001

प्रिय मित्रो,

पिछली बार जब हम 2 और 3 नवंबर को अमृतसर में मिले थे तो हमारा खयाल था कि अब हम उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब आदि प्रदेशों में चुनाव के बाद ही मिलेंगे। परंतु संसद् परिसर में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में घटी घटना के बाद दिल्ली में इस विशेष बैठक को बुलाना आवश्यक हो गया। संभव है कि इससे आपमें से कुछ सदस्यों को असुविधा हुई हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस दिन आपके पास पार्टी के कुछ कार्यक्रमों की योजना थी। आप में से बहुत से सदस्यों को कार्यक्रम रद्द करने पड़े और इस बैठक के लिए आना पड़ा।

हम सभी संसद् परिसर में 13 दिसंबर की घटना से परिचित हैं। सरकार देश को सचेत करती रही थी कि आतंकवादी भारत की तरफ अपना मुँह मोड़ सकते हैं और उनकी योजना संसद् पर हमला करने की है। सरकार ने एहतियाती उपाय किए थे और 13 दिसंबर को ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध हुए, जिसके कारण आतंकवादियों द्वारा संसद् में घुसने के प्रयास को बड़ी सफलता से विफल कर दिया गया और उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। इस खतरे को निष्फल करने में हमारे सुरक्षा प्रबंध बहुत प्रभावी सिद्ध हुए। निगरानी-चौकसी और सुरक्षा के उपायों के मामले में हर तरह की तकनालॉजिकल और वैज्ञानिक उन्नत व्यवस्था के बावजूद आतंकवादी न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हमला करने में सफल रहे; परंतु हमारे सुरक्षा बलों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आतंकवादियों के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया और न केवल संसद् और इसके आदर्शों की रक्षा की, अपितु हमारे देश के संपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व को समाप्त होने से भी बचा लिया।

स्वाभाविक ही है कि राष्ट्र पर इस प्रकार के आक्रमण से पूरे देश में आक्रोश है। आतंकवाद का सफाया करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन कर लोगों ने एकजुट होकर जैसी अभूतपूर्व प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वह इस देश में अपने आप

में अद्वितीय है। जब भी स्वतंत्रता, सुरक्षा और संप्रभुता के बारे में हमारे राष्ट्र के सामने चुनौती खड़ी हुई है, हमारा राष्ट्र एक जन बनकर खड़ा होने से कभी नहीं चूका है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अपने वक्तव्य में राष्ट्र की इस भावना को व्यक्त कर दिया है। इस घड़ी में पाकिस्तान अपनी धरती से गतिविधियाँ चला रहे आतंकवादियों और उनके समूहों के खिलाफ कड़ी काररवाई करे, इस बारे में पाकिस्तान को उसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझाने के लिए सरकार ने कूटनीतिक मार्ग अपनाकर और साथ ही पाकिस्तान की धरती से हमले के खिलाफ रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाकर बहुत सही दिशा अपनाई है। हमारी सरकार ने अभी तक जो भी उपाय किए हैं, पूरा देश उनका समर्थन करता है और यह स्वाभाविक ही है कि लोग ऐसे और अनेक कदम उठाए जाने की आशा करते हैं, जिससे पाकिस्तान यह समझ ले कि यदि उसे आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई के बारे में अंतरराष्ट्रीय प्रयास में शामिल होना है तो वह अपनी धरती से आतंकवाद का समर्थन प्रदान कर इस लड़ाई की गति को मंद नहीं कर सकता है। मैं महसूस करता हूँ कि हमारे देश में ऐसी सरकार है जो न केवल देश की आशाओं के प्रति सजग है, बल्कि अत्यंत जिम्मेदार भी है। सरकार प्रतिबद्ध है कि वह भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियाँ चलने नहीं देगी, अतः इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जो भी काररवाई करना आवश्यक है, उसे सरकार पर छोड़ देना चाहिए। मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूँ कि न केवल हमारी पार्टी, बल्कि पूरा देश इस बारे में सरकार के प्रयासों में पूरी तरह उसके साथ है।

मित्रो, हम इस 21वीं शताब्दी के प्रथम वर्ष के लगभग अंत में पहुँच गए हैं। नव वर्ष का सवेरा होने वाला है। इस पूरे एक वर्ष की अवधि में जो कुछ हुआ और जो कुछ हमने उपलब्धि प्राप्त की है, इस संपूर्ण स्थिति का आकलन हमें करना होगा। हमें अगले वर्ष की योजना भी तैयार करनी होगी। हमारी पार्टी और इस देश के लोग बड़े कठिन समय से गुजरे हैं; परंतु इस वर्ष के अंत में, जब हम पूरे वर्ष का आकलन करते हैं तो महसूस कर सकते हैं कि जो कुछ हमारी योजना थी, उसमें यदि सभी बातों में नहीं तो कम-से-कम कुछ मामलों में बहुत कुछ अच्छा किया गया है। यदि हम कई मील न भी चल पाए हों तो भी कम-से-कम एक मील तो आगे बढ़े ही हैं। हम अपने मार्ग पर अडिग रहे हैं और उससे विचलित नहीं हुए हैं।

हमारी सरकार कहीं अधिक शक्तिशील और कहीं अधिक प्रभावी बन पाई है। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, परंतु इसकी गति पर्याप्त तेज नहीं है। इसके पीछे जो कारण हैं, वे हमारे बनाए हुए नहीं हैं। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व व्यवस्था से कहीं अधिक जुड़ गई है और जो कुछ भी विश्व के एक कोने में होता है, उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आज के विश्व-ग्राम में हमें अभी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अलग प्रकार की व्यवस्थाओं की खोज करना

बाकी है, ताकि बाहरी तत्त्वों से हमारी अर्थव्यवस्था पर कम-से-कम प्रभाव पड़े। आज जब हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर विश्व अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा है तो शुक्र है कि हमारी सरकार ने पर्याप्त उपाय किए हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था उसके दबाव और झटकों को सह पाई है और अपने मार्ग पर चलती रही है। देश अगले वर्ष की ओर निहार रहा और आशा करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को और तेज गति मिल सकेगी।

हमारे अधिकांश औद्योगिक उत्पाद और हमारी सामान्य अर्थव्यवस्था हमारी कृषि उपज की उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। वर्तमान ढाँचे और परिस्थितियों में जब हमारे वित्तमंत्री ने कहा है कि आगामी बजट का मुख्य केंद्र-स्थल कृषि रहेगा तो सरकार के लिए ऐसे साधन और उपाय जुटाना कठिन नहीं होगा, जिससे हमारे कृषि उत्पादों की उत्पादन-लागत नीचे लाई जा सके। ऐसा होने पर कृषि उत्पादों पर निर्भर औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन लागत भी कम होगी और निर्वाह-खर्च का सूचकांक भी कम होगा। यदि निर्वाह-खर्च सूचकांक कम होता है तो फिर महँगाई भत्ते में वृद्धि की आवश्यकता नहीं रहेगी और इससे देश को लाभ होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं केंद्र सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या सरकार के लिए कृषि आदानों और उपकरणों पर कर तथा अन्य शुल्कों को समाप्त करना उसके वश में हो सकता है, जिससे समग्र रूप से कृषि में उत्पादन लागत कम करके इसे लाभ पहुँचेगा। इस कारण से केंद्र और राज्य सरकारों को होनेवाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति महँगाई भत्ते के भुगतान से पूरी हो सकती है, जो बढ़ेगा नहीं, अपितु घटेगा। मुझे आशा है कि सरकार इसपर यथोचित विचार करेगी।

आज भारत में रेल यात्रा का सबसे सस्ता साधन है। हमारे सामने नया रेल बजट आने वाला है। रेलें आज काफी बड़ी संख्या में लोगों और काफी बड़ी मात्रा में सामान को सस्ती दरों पर देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। यदि आगामी रेल बजट में रेलगाड़ी की यात्रा और माल ढुलाई को न केवल प्रतिस्पर्धात्मक बल्कि उपभोक्ता के लिए लाभप्रद बना दिया जाए तो गरीब वर्ग के लोगों को बड़ी मदद मिलेगी और माल की आवाजाही भी अपेक्षतया सस्ती रहेगी।

मित्रो,

अगले कुछ दिनों में हम नई शताब्दी के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर जाएँगे। आइए, हम पिछले वर्ष की कटु स्मृतियों को भुलाने और अगले वर्ष को कहीं अधिक कल्याणकारी बनाने का संकल्प करें। आइए, हम सब मिलकर देश को एकजुट बनाएँ। हम यह भी संकल्प करें कि प्रत्येक नागरिक यह महसूस करे कि वह क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय या धार्मिक समूह के किसी संकीर्ण दायरे का भाग न होकर राष्ट्र तथा समाज जैसे कहीं एक बृहद आकार का अंग है। आइए, हम सब

स्वयं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से और आज सरकार के पीछे एक शक्ति के रूप में खड़े होकर यह सुनिश्चित करने का संकल्प लें कि देश में सुशासन लाएँगे, जिसमें एक पक्की सुरक्षा और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था व्याप्त होगी। हमें इस बारे में और अधिक सचेत रहना होगा कि हमारा राष्ट्र कोई 100 करोड़ नागरिकों की जनसंख्या का देश मात्र नहीं है, बल्कि 100 करोड़ संगठित और अनुशासित लोगों का महान शक्तिशाली राष्ट्र है। आइए, हम सभी भारत को एक मजबूत, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, महाशक्तिशाली भारत बनाने के लिए आगे बढ़ें, जिसका राष्ट्रों के समुदाय में एक गौरवपूर्ण स्थान हो।





अध्यक्षीय भाषण

श्री बंगारू लक्ष्मण

राष्ट्रीय परिषद्

नई दिल्ली 4–5 जनवरी, 2001

मित्रो,

मेरी शुभकामना है कि नववर्ष 2001 आप सभी के लिए सुख–समृद्धि लाए।

मुझे विश्वास है कि नववर्ष में भारत अपने हर कार्य–क्षेत्र में और भी ऊँचाइयाँ छूएगा और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुयोग्य नेतृत्व में चहुँमुखी विकास के मार्ग पर और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि नववर्ष में हमारी पार्टी अपने आधार का और अधिक विस्तार करेगी तथा पिछले वर्ष हमारे अर्जित लाभ और भी अधिक सुदृढ़ होंगे।

हम अपने लाभ सुदृढ़ करें

पिछले वर्ष, अल्संख्यकों, दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का जो आह्वान किया था—जो अभी तक हमारे प्रति बहुत उत्साहित नहीं थे—उसके बड़े अभूतपूर्व परिणाम सामने आए हैं; हम बहुत हद तक इन वर्गों और हमारी पार्टी के बीच के रिक्त स्थल को भरने में सफल हुए हैं। हमारे राजनीतिक विरोधी अपने जिस झूठे और दूषित प्रचार से इन वर्गों को हमसे अलग कर रहे थे, हमारे प्रयासों से हम इनका सफलतापूर्वक मुकाबला कर पाए हैं। हमारे प्रति उनके दिमाग में लंबे समय से जो गलतफहमियाँ चली आ रही थीं, हम उन्हें दूर कर पाए हैं। हमारे आह्वान के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अद्‌भुत रही है। जो पहले कभी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, आज हमसे बातचीत करने को तैयार हैं। देश भर में इन वर्गों के हजारों–लाखों लोग हमारे निकट आ गए हैं। उनमें से बहुत से लोग हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं और हमारी पार्टी के विस्तार तथा विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करने को तैयार हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है। नववर्ष में हमें अपने इन लाभों को सुदृढ करने के लिए और भी दुगुने प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने कार्यक्रमों को इन वर्गों तक ले जाने के लिए हमें हर तरह के उपाय

करने की आवश्यकता है। इससे भी बढ़कर हमें उनमें हमारी पार्टी के प्रति अपनत्व की भावना पैदा करना अत्यावश्यक है। मुझे पक्का विश्वास है कि नववर्ष में हम अपनी पार्टी को भारत का लघु-विश्व रूप देने के लक्ष्य की प्राप्ति में तेजी से प्रगति करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इन दो दिनों में ऐसे समुचित कार्यक्रम और रणनीतियाँ तैयार करें जिन्हें हमारे कार्यकर्ता सभी स्तरों पर पहुँचा सकें।

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में राजग सरकार के कार्य प्रदर्शन ने सिद्ध कर दिया है कि भाजपा शासन की पार्टी है। हमारी सरकार शासन के राष्ट्रीय एजेंडा को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। अयोध्या का प्रश्न उठाकर इस प्रक्रिया में बाधा डालने के प्रयास किए गए। वे सफल नहीं हो सके। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से सरकार की नीति को खुलासा कर दिया है। इसे देखते हुए मुझे विश्वास है कि राजग में हमारे सहयोगी 'गठबंधन धर्म' को निभाते हुए, जिसके प्रति हम वचनबद्ध हैं, इस अच्छे कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे।

प्रधानमंत्री द्वारा संघर्ष विराम की पहल

प्रधानमंत्री के संघर्ष विराम की पहल को प्रारंभिक सफलता मिली है। इसने कश्मीर में शांति लाने के हमारे अनवरत प्रयासों में एक नए युग का सूत्रपात किया है। पार्टी पूरी तरह से प्रधानमंत्री की पहल के साथ है। इस पहल से राज्य में हिंसा फैलाने वाले उग्रवादी संगठनों और उनके प्रायोजक पाकिस्तान का भंडाफोड़ हो गया है कि वास्तव में वे क्या हैं—आतंकवादियों के पास 'भारत से नफरत करो' की विचारधारा को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। इस पहल की सफलता पर इन ताकतों द्वारा भय खाकर जो हिंसा फैलाई जा रही है, उससे उनकी निराशा ही प्रगट होती है। स्थानीय लोगों से उनके अलग-थलग पड़ जाने से उनमें कुंठा पैदा हुई और उन्होंने इस पहल को तहस-नहस करने के हताशापूर्ण प्रयास करने शुरू कर दिए।

सीमा पार आतंकवाद के अलावा कट्टरपंथियों का आतंकवाद पूरे देश में सक्रिय है। यहाँ हमारा कर्तव्य है कि हम सतर्क रहें और समाज में फूट डालने के उनके इरादों का पर्दाफाश कर दें।

आर्थिक सुधार

सरकार आर्थिक सुधारों पर चल रही है, परंतु साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत इस दिशा में प्रमुख रूप से सरकार द्वारा की गई पहल को दरशाता है, जिससे सिद्ध होता है कि सरकार गाँवों और गरीबों की हितकारिणी है। यहाँ मैं लघु उद्योगों और किसानों की दशा का उल्लेख करना चाहूँगा। मुझे विश्वास है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम

उठाएगी कि समाज के इस महत्त्वपूर्ण वर्ग पर ध्यान दिया जाए। राजग के एजेंडा में कृषि उत्पादन के सतत विकास की कल्पना की गई है और आज हमें भंडारण और वेयरहाउसिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह अत्यंत आवश्यक है कि भंडारण के लिए बुनियादी ढाँचा तैयार करने, खाद्यान्न निर्यात करने और भूखे लोगों, गरीबों तथा बेरोजगारों के लिए खाद्यान्न का इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया जाए। मैं देश में निर्बाध रूप से प्रवेश कर रही चीन की सस्ती वस्तुओं का भी यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, जिनका हमारे देश में ढेर लगाया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि सरकार को भी सब लोगों के साथ इस स्थिति पर चिंता है और इस बारे में पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

असम की स्थिति

असम में स्थिति चौंकाने वाली है और दिनोदिन बिगड़ती जा रही है। राज्य में लोग, विशेष रूप से हिंदी भाषी लोग, निरंतर मृत्यु के भय की छाया में जी रहे हैं। पिछले दो महीनों में उग्रवादियों ने दो सौ से अधिक लोगों के प्राण ले लिये हैं। सरकार नागरिकों के जीवन की रक्षा करने के अपने मूलभूत कर्तव्य का निर्वाह करने में बुरी तरह विफल रही है। राज्य में उग्रवादी निर्विघ्न घूम रहे हैं। राज्य सरकार उनकी गतिविधियों को रोकने में असहाय सिद्ध हुई है। राज्य में परिवर्तन की जबरदस्त माँग है। हम असम के लोगों के साथ प्रतिज्ञा करते हैं। हमारी प्रतिज्ञा है कि हम राज्य में शांति बहाल करेंगे। और राज्य के लोगों को अच्छा शासन प्रदान करेंगे। असम में हमारा एक कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। हमें कमर कस लेनी चाहिए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आगामी विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

पास के मणिपुर और त्रिपुरा में स्थिति उतनी ही गंभीर है। आज वहाँ अराजकता फैली हुई है। त्रिपुरा में उग्रवादियों ने सोलह महीने पहले रा.स्व.संघ के पाँच कार्यकर्ताओं का अपहरण किया था। राज्य सरकार आज तक उन्हें मुक्त नहीं करा सकी है।

नेपाल में भारतीय समुदाय के खिलाफ हाल की हिंसा की घटनाएँ गंभीर चिंता का कारण हैं। स्पष्ट है कि इनके द्वारा भारत और नेपाल के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बिगाड़ने का जान-बूझकर प्रयास किया गया है। मुझे संशय है कि भारत और नेपाल के हितों को नुकसान पहुँचाने के लिए यह एक षड्यंत्र है। मैं नेपाल सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह प्रभावित लोगों की जान-माल की रक्षा करने के लिए कारगर कदम उठाए और अशांति पैदा करने वाली इन ताकतों के बारे में जाँच कराए और पता लगाए।

विधानसभाओं के आगामी चुनाव

इन दो दिनों में हमें तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के राज्य विधानसभा चुनावों का मुकाबला करने के लिए पार्टी संगठन को तैयार करने के लिए अपना दिमाग लगाना होगा। हमें राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करना होगा और इन राज्यों के लिए मिलकर प्रभावशाली रणनीतियाँ तैयार करनी होंगी। जहाँ आवश्यक हो, हमें संभावित सहयोगी दलों की पहचान करना भी शुरू कर देना होगा। जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें अपनी शक्ति बढ़ाने के अत्यधिक अवसर हैं और कुछ राज्यों में हम अपने बल पर या अपने सहयोगी दलों और मित्र दलों के साथ मिलकर सत्ता में भी आ सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊँचा रखना आवश्यक है, ताकि वे कारगर ढंग से चुनौती का मुकाबला कर सकें। इसके बाद से हमें अपने प्रयासों को और भी दुगुना करना होगा।

परिवर्तन का युग पहले ही शुरू हो चुका है। अटलजी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों में और भी बड़ी आशाएँ जगा दी हैं। सरकार और पार्टी को अपने सकारात्मक प्रदर्शन से इन आशाओं को पूरा करना चाहिए। आज राष्ट्र की प्राथमिकताओं का निर्धारण सुशासन और विकास की अनिवार्यताओं के आधार पर होता है। लोगों से हमारी यह प्रतिज्ञा है, जो हमें पूरी करनी है। अतः आइए, हम विवादों और झगड़ों से ऊपर उठें। आइए, हम आम सहमति बनाएँ और प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप अगले दस वर्ष पूरी तरह विकास के नाम कर दें। पार्टी सचमुच लोगों के हितों की माध्यस्थ बन जाए। आइए, हम शासन और विकास के लाभों को लोगों तक पहुँचाने के कार्य में जुट जाएँ। विकास और परिवर्तन की इस प्रक्रिया में हम लोगों को भी जोडें। पार्टी की सक्रियता से बुराइयों और पीड़ाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी और जरूरतमंदों की मदद की जा सकेगी। सक्रिय रूप से पार्टी तंत्र लोगों की इच्छा और लोगों की भागीदारी को प्रकट करता है। मैं इस गौरवपूर्ण ध्येय की पूर्ति के लिए आप सभी को अपनी शुभकामनाएँ और सक्रिय समर्थन प्रदान करता हूँ।

वंदेमातरम् !



राष्ट्रीय परिषद्

नागपुर 27 अगस्त, 2000

आज मैं अपने मन में बड़े गौरव का भाव लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पाँचवें अध्यक्ष चुनने पर मैं आपके प्रति अत्यंत आभारी हूँ, जिसे मैं शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ। आपने जो प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उससे मैं अत्यंत भाव-विह्वल हूँ।

लेकिन मैं जानता हूँ कि यह प्रतिष्ठा मेरी नहीं, बल्कि इस महान् पार्टी की है। पार्टी ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को इस उच्च पद के लिए चुना, इससे भाजपा की महानता और उसका विशिष्ट चरित्र ही प्रकट होता है। वस्तुतः मुझसे पूर्व के लब्ध-प्रतिष्ठित अध्यक्षों ने भी अपना राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन कार्यकर्ता के रूप में आरंभ किया था।

यह प्रकट करता है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं साधारण दलित परिवार से हूँ। हमारी पार्टी में जब किसी व्यक्ति पर कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उस पुरुष या महिला की सामाजिक पृष्ठभूमि कोई निषेध या रुकावट बनकर आड़े नहीं आती है। एक सामान्य कार्यकर्ता को धीरे-धीरे पार्टी की बड़ी और ऊँची जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार किया जाता है। पार्टी का नेतृत्व किसी ऐसे वंश विशेष के सदस्यों के लिए सुरक्षित और आरक्षित नहीं किया जाता है जो अपनी पार्टी और राष्ट्र का नेतृत्व करने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता हो। भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ही बताता है कि यह भारत के लोगों की पार्टी है।

मेरे पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित अध्यक्ष

मैं अब तक के पार्टी अध्यक्षों की योग्यता और उनके कद से भलीभाँति परिचित हूँ, जिनकी पंक्ति में शामिल हो गया हूँ। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हमारे अत्यंत प्रिय नेता श्री अटलजी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी गहरी

समझ, उनका विशाल ज्ञान भंडार और अनुभव, स्नेह और प्यार भरा स्वभाव, देश के सबसे कद्दावर नेता के नाते उन्होंने जो सम्मान अर्जित किया है और अंतरराष्ट्रीय धरातल में उन्हें जो प्रतिष्ठा मिलती है, यह सब हमारी पार्टी की सबसे बड़ी पूँजी रही है।

श्री आडवाणीजी के करिश्माई और गतिशील नेतृत्व में पार्टी नई ऊँचाइयाँ नापती चली गई। देश में किसी राजनीतिक पार्टी का भाजपा जैसा उदाहरण नहीं मिलेगा। जो पार्टी 1984 में भारत की संसद् में लगभग नगण्य हालत में पहुँच गई थी, वह 1996 में लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद सन् 1998 और 1999 के चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने के स्थान तक पहुँच गई। दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में शायद यह अतुलनीय उदाहरण है। हमारी पार्टी के लिए श्री आडवाणीजी का नैतिक बल और वैचारिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक मामलों का दिग्दर्शन सदैव ही शक्ति और प्रेरणा का स्रोत रहा है।

आज मैं डॉ. मुरली मनोहर जोशी तथा अपने से पूर्व के अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे के प्रति भी अपना आभार प्रगट करता हूँ। पार्टी के विकास में डॉ. जोशीजी की प्रज्ञा तथा विद्वत्ता एवं श्री ठाकरेजी के संगठन निर्माण में विपुल अनुभव दोनों की ही प्रमुख भूमिका रही है।

मैं पार्टी अध्यक्ष के रूप में पूरी निष्ठा से प्रयास करूँगा कि मैं भी अपने पिछले चारों महान् अध्यक्षों के अनुरूप स्वयं को उनका योग्य उत्तराधिकारी बना सकूँ। मुझे अपने कठिन उत्तरादायित्व के निर्वाह में उनके आशीर्वाद, निरंतर मार्गदर्शन तथा सहयोग की आवश्यकता होगी। मुझे विश्वास है कि यह भरपूर मात्रा में मुझे मिलेगा।

पार्टी के अन्य वरिष्ठ एवं युवा नेताओं ने भी जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, मैं उससे भलीभाँति परिचित हूँ। अगले तीन वर्षों तक पार्टी अध्यक्ष के रूप में मैं अपने कार्य में उनसे सहयोग और सलाह चाहता हूँ। मुझे यह भी विश्वास है कि केंद्र और राज्य में अपने सभी सहयोगियों तथा कार्यकर्ताओं से भी पूरा-पूरा सहयोग मुझे मिलेगा।

यहाँ मैं परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना करता हूँ कि वह मुझे इस पार्टी के नए अध्यक्ष पद के रूप में मातृभूमि की सेवा करने का सामर्थ्य दे, जो भारत वर्ष की महानता और गौरव को फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारी पार्टी के दो प्रकाश-स्तंभ

आज मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य स्मृति में उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। समय चक्र चलता रहेगा और पीढ़ियाँ भी

गुजरती जाएँगी; किंतु इन दोनों नेताओं के प्रति हमारी कृतज्ञता में कभी कमी नहीं होगी। भाजपा की वैचारिक और राजनीतिक यात्रा 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना से शुरू हुई थी। डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाए, परंतु उनके व्यक्तित्व में एक उत्कट राष्ट्रवाद, चरित्र और निष्ठा का धनी व्यक्तित्व तथा पार्टी के सिद्धांतों के लिए संघर्ष करने के साहस के कारण यह सुनिश्चित हो गया कि हम सब एक अलग पहचान की पार्टी और विशिष्ट राजनीतिक परंपरा के अनुयायी हैं। इस वर्ष उनकी जन्मशती मनाने में हम गर्व का अनुभव करते हैं।

पं. दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में इस विशिष्ट परंपरा की आभा निरंतर निखरती चली गई। 'एकात्म मानववाद' पर उनका शोध प्रबंध भारत के राजनीतिक विचार के विकास में एक मौलिक और गहन योगदान है। इस शोध प्रबंध में उन्होंने जो दृष्टि प्रस्तुत की है वह इतनी गंभीर और शक्तिशाली है कि वह हमारी पार्टी के लिए नई शताब्दी में दिशानिर्देश का काम करेगी।

मेरा अपना राजनीतिक जीवन जनसंघ के साथ शुरू हुआ। हमारी छोटी से पार्टी थी, परंतु भारत के राजनैतिक जीवन पर हमारा प्रभाव कम नहीं था। यह हमारे नेतृत्व की महानता का प्रतिफल था। दीनदयालजी ने हजारों युवाओं को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, राष्ट्रवादी मिशन को लेकर राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने की प्रेरणा दी। हम देखा करते थे कि किस प्रकार हमारे नेता कठोर जीवन जीते थे, उनके पास ऐसी सुविधाएँ नहीं होती थीं, जिन्हें आज साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता मानकर चलते हैं कि इतनी सुविधाएँ तो मिलेंगी ही। पुराने कार्यकर्ताओं ने देखा है कि दीनदयालजी और अटलजी दिल्ली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक साइकिल पर घूमा करते थे।

किंतु, भौतिक साधनों की कमी आदर्शवाद और विचारधारा की विपुल संपदा से पूरी हो जाती थी, जिनसे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलती थी। 'राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्राय इदं न मम्' अर्थात् मैं अपना सबकुछ राष्ट्र को समर्पित करता हूँ, अब सब कुछ राष्ट्र का है, मेरा कुछ नहीं—यह एक विचार था जिससे हमारे कार्यकर्ता और नेता प्रेरित होते थे, और उनमें अनुशासन, निष्ठा, बंधुत्व और उच्च स्तर के सहसंबंध की भावना से भर देता था।

आज भाजपा इस पुरानी परंपरा की उत्तराधिकारी है। आज हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है वह हमारी पार्टी की प्रारंभिक वर्षों की परंपरा का ही फल है। हमारा सबसे पहला उत्तरदायित्व है कि हम 'अलग पहचान वाली पार्टी' के रूप में भाजपा की इस बहुमूल्य परंपरा को पार्टी एक नए और विस्तार के विकासवाही चरण में आगे लेकर चलें। मैं इस बारे में अपने भाषण में बाद में चर्चा करूँगा।

नागपुर : तीन महापुरुषों का संगम

पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के इस अधिवेशन को नागपुर में रखने के पीछे एक विशिष्ट सांकेतिकता और महत्त्व है। यह स्थल आधुनिक भारत के तीन महान् द्रष्टाओं—महात्मा गांधी, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर और केशव बलिराम हेडगेवार—का संगम स्थल है।

दिसंबर 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने नागपुर में अपना वार्षिक अधिवेशन रखा था। गांधीजी ने एक नया पार्टी संविधान स्वीकार किया जिसे उन्होंने स्वयं तैयार किया था। इसमें 'सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज की प्राप्ति' को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया था। बाद में वह वर्धा आते-जाते प्रायः इस नगर में आया करते थे। उन दिनों उन्होंने रचनात्मक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसे प्रयोगशाला बनाया था।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का नागपुर अधिवेशन डॉ. हेडगेवार के संक्षिप्त राजनीतिक जीवन काल का महत्त्वपूर्ण स्थान था। कांग्रेस पार्टी की प्रांतीय इकाई के महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी के रूप में अधिवेशन की प्रबंध व्यवस्था में वह प्रभारी थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति छोड़ने के बाद नागपुर में ही डॉ. हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की तथा नागपुर को इसका मुख्यालय बनाया। तब से रा.स्वं.संघ देश भर में राष्ट्रवादी विचार और गतिविधियों का प्रमुख संगठन बन गया है। मैं भी अपने जन्मस्थल हैदराबाद में रा.स्वं.संघ के साथ संपर्क में आने के बाद 12 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय गतिविधियों में लग गया था।

नागपुर आधुनिक भारत के महानतम समाज-सुधारक बाबा साहब अंबेडकर की कर्मभूमि और दीक्षाभूमि है। अक्तूबर 1956 में इसी नगर में डॉ. अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म में प्रवेश किया था। इस महान् घटना के दो महीने बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया था।

गांधीजी, अंबेडकर और हेडगेवार—ये तीनों महान् विभूतियाँ थीं, सम्भव है बाहर से ऐसा लगे कि यह तीनों तीन परस्पर विरोधी विचारधाराओं और सामाजिक-राजनीतिक परंपराओं को माननेवाले थे। किंतु भाजपा को यह स्वीकार करने में गर्व है कि इन तीनों महापुरुषों ने आधुनिक भारत के निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया। हम मानते हैं कि उनके अपने-अपने विश्वासों तथा कार्यकलापों में न तो कोई विरोधाभास था और न ही टकराव था, अपितु उनके आदर्शों में गहन समानता थी।

उन्होंने अपने अलग-अलग तरीकों से इस प्राचीन एवं गौरवपूर्ण समाज को पुनः शक्तिमान बनाने के लिए संघर्ष किया, जो कभी विख्यात था, किंतु बुरे दिनों में फँस गया, कमजोर हो गया, गुलाम बन गया और इसमें हर तरह की दुःसाध्य सामाजिक बुराइयाँ पैदा हो गईं। इन तीनों के हृदय में राष्ट्रवाद की ज्वाला धधक

रही थी। ये तीनों अपने अलग अलग मार्गों पर चलते हुए 'हिंदू' शब्द के व्यापक सांस्कृतिक और सभ्यतामूलक अर्थ में इस समाज को सुधारने का प्रयास किया। डॉ. अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बारे में जो कारण बताए थे, उससे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है।

इन तीन महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तथा आज उनकी विरासत के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए भाजपा को गर्व है। वस्तुतः हमारी पार्टी ही है जो ऐसे सभी महान् पुरुषों और नारियों के योगदान को स्वीकार करती है और उन्हें प्रणाम करती है, भले ही उनकी कोई भी विचारधारा और राजनीतिक पृष्ठभूमि हो, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वातंत्र्योत्तर काल में राष्ट्र निर्माण का कार्य किया हो। हम अपने विरोधियों की तरह क्षुद्र विचार नहीं रखते हैं। हम दुराग्रही नहीं हैं और न ही क्षुद्र विचारों को लेकर चलते हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी बंगाल के उप-मुख्यमंत्री को लें, जिन्होंने कलकत्ता में बंगाल और भारत के महान् सपूत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया—वह भी तब जब प्रधानमंत्री स्वयं उस अवसर पर मौजूद थे; इस तरह का आचरण भाजपा की राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ है।

भाजपा की ऐतिहासिक जिम्मेदारी

प्रिय प्रतिनिधि बंधुओ, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक हमारी पार्टी के इतिहास और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अत्यंत महत्त्वपूर्ण समय में हो रही है। नई शताब्दी में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की यह प्रथम बैठक है।

21वीं शताब्दी के प्रथम वर्ष में केंद्र में भाजपा-नेतृत्व सरकार का सत्ता में होना समय का संयोग मात्र नहीं है। इतिहास ने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी डाली है कि हम भारत को हर तरह से पुनः शक्तिशाली बनाने और इसके पुनरुत्थान के लिए नेतृत्व प्रदान करें। नियति ने चाहा है कि इस संकट की घड़ी में देश को नेतृत्व प्रदान करें ताकि पार्टी का '21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने' का नारा जो अब राष्ट्र का नारा भी बन गया है, को साकार किया जा सके।

हमारी पार्टी के पास भारत के भविष्य के बारे में एक परिपुष्ट परिकल्पना है, क्योंकि हम भारत के भूत और वर्तमान दोनों की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। हम समस्याओं को उसके संपूर्ण और अंतरंग रूप से देखते हैं, हम उसे आंशिक अथवा खंड रूप में नहीं देखते हैं। हम समस्याओं को उनके दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और अल्प काल के लाभों से आकर्षित होकर बह नहीं जाते हैं। जब हमारे सामने अलग-अलग और टकराते हुए हितों का मामला आता है तब समन्वय दृष्टि अपनाते हैं। हम सदैव राष्ट्र के हित को समग्र रूप से ध्यान

में रखते हैं—और कोई रवैया या नीति बनाते समय तथा स्थिति का मूल्यांकन करते समय किसी श्रेणी या वर्ग को आधार नहीं बनाते हैं।

हमारी राष्ट्र-प्रथम नीति

आप सभी जानते हैं कि जब कभी समय की माँग हुई है, हमने त्याग किया है अथवा हमने अपनी पार्टी के तात्कालिक लाभ को नजरंदाज किया है और ऐसा रास्ता अपनाया है जिसे हम देश और लोकतंत्र के लिए अच्छा मानते हैं।

सन् 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की घटनाओं, सिखों की दुखद हत्याओं पर हमारा सिद्धांताधारित रवैया इस बात का अच्छा उदाहरण है। जब पंजाब में आतंकवाद छाया था तो हमने हिंदू-सिख सौहार्द बनाए रखने का जोर-शोर से प्रयास किया। इससे पहले 1977 में जब हमारे नेतृत्व ने भारतीय जनसंघ को तोड़ने का फैसला किया और जनता पार्टी में विलय किया, तब भी हमारा उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र के व्यापक हितों की पूर्ति करना था।

राष्ट्रीय जीवन के हर मोड़ पर हमने देश की बात की है और देश के लिए कार्य किया है। आगे भी हम यही करते रहेंगे। भाजपा का दिग्दर्शक सिद्धांत सदा यही था, यही है और यही रहेगा—अर्थात् राष्ट्रवाद ही प्रथम और अंतिम, छोटे-बड़े सभी मामलों में बस राष्ट्रवाद, राजनीति में राष्ट्रवाद और अर्थशास्त्र में भी राष्ट्रवाद—यही हमारा सिद्धांत है।

किंतु राष्ट्रवाद के प्रकाश में किसी मुद्दे पर अपनी नीति या रवैये के बारे में तय करते हुए हम कभी भी लकीरपंथी और हठधर्मी नहीं बने हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि शायद भारत में हमारी पार्टी अत्यंत अभिनवशील है और समय के अनुसार स्वयं को ढालती है। भाजपा जैसी ऐसी दूसरी कोई पार्टी नहीं है, जिसने इतने प्रयोग किए हों और फिर भी अपने मूल सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखी हो।

स्व-प्रतिज्ञान के माध्यम से स्व-अनुकूलन

जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और स्वयं से पूछता हूँ कि 'पिछले दो दशकों में हमारी पार्टी की शक्ति के निरंतर बढ़ते जाने के पीछे कौन सा आधारभूत तत्त्व रहा है' तो जो उत्तर मुझे अत्यंत संतोष प्रदान करता है, वह यह है कि "स्वयं का प्रतिज्ञान कर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना।" मुझे विश्वास हो गया है कि यही तत्त्व भविष्य में भी भाजपा के विकास की निरंतर प्रगति की सर्वोत्तम गारंटी बना रहेगा। आइए, मैं इस विचार को और स्पष्ट करूँ।

राजनीतिक अनुकूलन : राजनीति के क्षेत्र में भाजपा ने साँझा एजेंडा के आधार पर अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने की साहसी और कल्पनाशील रणनीति बनाई, जिससे देश और हमारी पार्टी दोनों को लाभ हुआ। अब हमारे सहयोगी दल उत्तर-पूर्व में भी हैं। एक पूर्वोत्तर राज्य में तो भाजपा

सरकार में भी सहभागी है।

हमने 'राजनीतिक अस्पृश्यता' की बेड़ियों को इतनी सफलतापूर्वक तोड़ डाला है कि जिन विरोधियों ने हमें एक किनारे करने की कोशिश की थी, वे स्वयं ही अलग-थलग जा पड़े हैं। राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने की हमारी क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं राजग का निर्माण है।

सामाजिक अनुकूलन : सामाजिक क्षेत्र में हमने सजग होकर भारतीय समाज के नए-नए वर्गों तक पहुँचने का प्रयास किया है। हमने इस कार्य को संपन्न करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की विशिष्ट चिंताओं पर ध्यान दिया और समान क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय चिंताओं की तरफदारी की। यह हम सबको जोड़ती है। परिणामतः दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों में हमारा प्रभाव पिछले दशक में काफी हद तक बढ़ा है। समाज के इन वर्गों के संसद् सदस्यों की संख्या की तुलना किसी भी बड़ी पार्टी से करें तो हम सबसे आगे हैं।

भारत एक विशाल और विविधताओं से परिपूर्ण देश है। हमारे प्रत्येक राज्य में अविश्वसनीय सामाजिक विविधता के दर्शन होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए स्थानीय और गली-मोहल्लों के मुद्दों पर संवेदनशील रहना और साथ ही संपूर्ण समाज के हितों को भी बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कुछ पार्टियाँ किसी क्षेत्र, जाति, वर्ग या समुदाय विशेष की समस्याएँ उठाती हैं। इसमें तब तक कहीं कुछ गलती नहीं है जब तक वह संपूर्ण समाज और देश के समान हितों को ध्यान में रखते हैं।

हमारी पार्टी को इस बात का गर्व है कि हम विषम सामाजिक और क्षेत्रीय चिंताओं का समायोजन करने में बहुत हद तक सफल रहे हैं। निःसंदेह हमें बड़ी विनम्रतापूर्वक यह भी स्वीकार करना होगा कि राजग के अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर हम भी अपने समाज के उन वर्गों की चिंताओं पर संवेदनशील बने हैं, जो पहले हमारी गतिविधियों के दायरे में नहीं आते थे।

आर्थिक अनुकूलन : हमारे आर्थिक दर्शन के लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल है : अपने समस्त संसाधनों का उपयोग कर अपने सभी नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए उत्पादनकारी रोजगार तैयार करना और एक समृद्ध तथा समतावादी भारत का निर्माण करना। इस लक्ष्य-प्राप्ति के लिए हमने स्वावलंबन के दिग्दर्शक सिद्धांतों को चुना है।

मैं अभी बाद में चर्चा करूँगा कि हमारे लक्ष्य वही हैं। फिर भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिन साधनों और तरीकों का प्रयोग करने की आवश्यकता है, उसके लिए बदलते समय के अनुरूप परिवर्तन करना आवश्यक होगा। कम्युनिस्टों के विपरीत हमारी पार्टी किसी हठधर्मिता की कैद में नहीं है। हम नए तथ्यों और नए अनुभवों से सीखने को तैयार हैं।

केंद्र में राजनीतिक स्थिति : स्थिर, परंतु सतर्क रहने की आवश्यकता

प्रिय प्रतिनिधि बंधुओ, अब मैं अपने देश और अपनी पार्टी के सामने की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जुड़े कुछ मोटे-मोटे मुद्‌दों पर चर्चा करना चाहूँगा।

सितंबर और अक्तूबर 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनावों में लोगों के जनादेश से केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो गई है। यह जनादेश निर्णायक था। भाजपा-नीत राजग सरकार को फिर से सत्ता सौंप दी गई। मतदाताओं ने निश्चित रूप से पदासीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। वस्तुतः 1971 के बाद से कोई भी पदासीन प्रधानमंत्री पुनः सत्ता में नहीं लौटा है। इस जनादेश में कांग्रेस पार्टी, इसकी 'बी' टीम कम्युनिस्टों तथा पिछले वर्ष मार्च में हमारी सरकार को अस्थिर करनेवालों को अच्छी तरह फटकारा गया।

लोकसभा में राजग के संख्यात्मक बहुमत से बढ़कर सरकार की स्थिरता के पीछे प्रधानमंत्री की विपुल प्रतिष्ठा और राजग के घटक दलों के बीच एकजुटता है। राजग के सहभागियों के बीच संबंध सत्ता के पहली बार से कहीं अधिक सद्‌भावपूर्ण है। गठबंधन भी पहले से कहीं अधिक प्रयोजनशील और परिणामोन्मुखी है। भाजपा अपने सभी सहयोगी दलों को पूर्ण सहयोग और समर्थन देने के लिए धन्यवाद देती है; इसी सहयोग और समर्थन के कारण अभी तक राजग केंद्रीय साझा राजनीति में सर्वोत्तम प्रयोग सिद्ध हुआ है। देश साझा सरकारों के युग में प्रवेश कर चुका है, इसलिए हमें कांग्रेस की अपनी इस स्वार्थपूर्ण भविष्यवाणी को गलत साबित करने पर गर्व है कि साझा सरकारें स्थिर नहीं रह सकती हैं और केवल कांग्रेस के एक दलीय शासन से ही स्थिरता आ सकती है।

हालाँकि राजनीतिक माहौल शांत है और न ही नई दिल्ली पर अनिश्चितता के बादल मँडरा रहे हैं, परंतु हमें आत्मसंतोष कर हाथ-पर-हाथ धरकर नहीं बैठ जाना है। कांग्रेस भारतीय राजनीति को अस्थिर करने वाली सबसे बड़ी ताकत साबित हुई है। पिछले कुछ वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी वचनबद्धता और लोगों के जनादेश का सम्मान करने की उसकी इच्छा इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि उसने पिछले दशकों में बिना सोचे-समझे अनेक गैर कांग्रेसी सरकारों को अस्थिर कर गिरा दिया।

आज कांग्रेस पार्टी हतोत्साहित है और उसका मनोबल गिरा हुआ है। उनके अपने कार्यकर्ताओं में असंतोष और विसम्मतियाँ भरी पड़ी हैं। सभी स्तरों पर पार्टी के नेतृत्व से मोहभंग हो चुका है। फिर भी वह दुःसाहसपूर्ण कार्य कर सकती है, इस बात को कम करके नहीं आँका जा सकता। कांग्रेस पार्टी के अलावा विपक्ष में अन्य असंतुष्ट शरारती तत्त्व भी मौजूद हैं।

विशेष रूप से कम्युनिस्ट अभी तक जिन तीन राज्यों में लाल गढ़ खड़ा करने

का दावा करते रहे हैं, हाल में वहाँ भी उनका आधार लगातार समाप्ति की ओर बढ़ने के कारण उनमें आतंक छाया हुआ है। पश्चिम बंगाल भी कम्युनिस्टों को आगामी राज्य विधान के चुनावों में 23 वर्षों की अकर्मण्यता के कारण उखाड़ फेंकने को तैयार है। जहाँ राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सीपीआई की मान्यता समाप्त हो चुकी है वहाँ सीपीआई(एम) भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता खोने के कगार पर खड़ी है।

भाजपा और राजग में उसके सहयोगी दलों के बीच दरार पैदा करने के सभी विपक्षी प्रयास विफल हो चुके हैं; किंतु भाजपा और हमारे सभी सहयोगी दलों को सदैव सतर्क रहना चाहिए।

राज्यों में राजनीतिक स्थिति

आज स्वतंत्रता से लेकर अभी तक भारत के राजनीतिक मानचित्र पर जितनी अधिक विविधता दिखाई पड़ती है, इससे पूर्व पहले कभी दिखाई नहीं पड़ी थी। यद्यपि अन्य किसी पार्टी की तुलना में कांग्रेस अधिक राज्यों में सत्ता में है, परंतु पार्टी का ह्रास निश्चित है। यह प्रक्रिया कभी भी उलट नहीं पाएगी; किंतु हम कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों द्वारा रिक्त स्थलों में स्वयं को प्रतिस्थापित करने में सफल नहीं हो पाए हैं।

अगले वर्ष के आरंभ में पाँच बड़े राज्यों में नए विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए मतदान होगा। तीन नए राज्यों—छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड—में से उत्तरांचल भी अपनी नई विधानसभा का चुनाव करेगा। हमें इन सभी राज्यों में स्वयं अकेले या सहयोगी दलों के साथ मिलकर विजय प्राप्त करने के सभी प्रयास करने चाहिए। हमें अभी से इसकी तैयारी जोर-शोर से शुरू कर देनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के अलावा उन राज्यों में—गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, मेघालय और गोवा—जहाँ हम पहले से ही सत्ता में हैं, वहाँ हमारी सरकारों के कामकाज में सुधार करने का प्रयास होना चाहिए। चूँकि हम केंद्र में सत्ता में हैं, इसलिए हमारी राज्य सरकारों को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें इन राज्यों में विकास कार्य को तेजी से बढ़ाने के लिए इसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए।

उन राज्यों में, जहाँ हम विपक्ष में हैं, हमारी पार्टी इकाई को जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास करना चाहिए। मैं उनसे लोगों की समस्याओं पर विचार करने तथा विधानमंडलों के अंदर और बाहर, दोनों स्थानों पर ही जोरदार राजनीतिक गतिविधियाँ चलाने का आग्रह करूँगा। सत्तारूढ़ सरकार द्वारा लोगों से किए गए वायदों को पूरा न करने पर उन सरकारों को कठघरे में खड़ा करना चाहिए। साथ ही सभी जन-समर्थन नीतियों और कार्यक्रमों में सरकारों को रचनात्मक समर्थन देना चाहिए। इन सरकारों की किसी नीति का विरोध या समर्थन

देने की एक कसौटी होनी चाहिए : "क्या इस नीति से राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी आती है या बाधा पड़ती है?"

राजग सरकार : भारत और हमारी पार्टी के लिए इसका महत्त्व

मित्रो, राष्ट्रीय परिदृश्य पर राजग के उदय से भारतीय राजनीति में एक नया सकारात्मक अध्याय आरंभ हुआ है। राजग के निर्माण में हमने पहल की और इसमें शासन के स्थिर और सफल मॉडल को तैयार करने की हमारी योग्यता साफ तौर से प्रगट हो गई है, इस प्रकार भाजपा अपने विकास के नए चरण में पहुँच गई है। हमारे लिए निश्चित ही यह आगे बढ़ा हुआ कदम है। देश के लोकतंत्र के लिए भी यह निश्चय ही आगे बढ़ा हुआ कदम है। पिछली गठबंधन की सरकारें दो कारणों से टूट गई थीं : उन्हें एकजुट रखने के लिए कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी। और उनका कोई एक स्वीकार्य नेता नहीं था। भाजपा को गर्व है कि हम इन दोनों गंभीर कमियों पर विजय पाने में राजग के लिए सहायक सिद्ध हुए।

राजग के साझा घोषणा-पत्र में ठीक ही कहा गया है कि "राजग राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आखिर राजग इस देश की बहुमुखी विविधता में एकता, भरपूर बहुलवाद और संघ का दर्पण ही तो है।" राजग सरकार के ढाई वर्ष के अनुभव से स्पष्ट हो गया है कि इसने क्षेत्रीय पार्टियों को केंद्र सरकार के कामकाज में अपनी यथोचित भूमिका का निर्वाह करने का अवसर दिया है, उनमें विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विकास करने में मदद की है। साथ ही राजग ने राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय मुद्दों और महत्त्वाकांक्षाओं के प्रति और अधिक जागरूक बनाया है।

हमें राजग को मिली अभी तक सफलताओं को आधार बनाना चाहिए और इसे लोकतांत्रिक शासन के लिए और भी प्रभावशाली साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। भाजपा और हमारे सभी सहयोगी दलों, दोनों की यह साझा जिम्मेदारी है कि हम सभी को मिलकर "गठबंधन के धर्म को और अधिक मजबूत करें, ताकि चाहे जैसा विवादास्पद मुद्दा हो, उसे निरंतर बातचीत और सलाह-मशविरों से सुलझाया जा सके।

पार्टी की पहचान का ह्रास नहीं

प्रायः हमारे कुछ शुभचिंतक भाजपा की 'एक अलग पार्टी की पहचान' के रूप में ह्रास हो जाने की आशंका इस कारण व्यक्त करते हैं, क्योंकि भाजपा ने ऐसे कुछ मुद्दों को राजग के साझा एजेंडा से बाहर रखने का फैसला किया है जो हमारे पिछले घोषणा-पत्रों में प्रमुख रूप से शामिल थे। हमारे अपने समर्थकों से अधिक तो हमारे विरोधी और आलोचक इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि यह बहस चलती रहे।

इस विषय पर संदेह और आलोचनाएँ निराधार हैं। हमारी पार्टी की बुनियादी पहचान राष्ट्रवाद के प्रति हमारी संपूर्ण प्रतिबद्धता, हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की ईमानदारी और आदर्शवाद तथा हमारे संगठन का अनुशासन और एकजुटता के कारण है। इन्हीं कारणों से भाजपा सदैव अन्य दलों से अलग रही है और बनी रहेगी।

साझा एजेंडा के आधार पर राजग का निर्माण राष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के मार्ग पर चलते रहने की हमारी योग्यता का प्रमाण है। साथ ही विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले भाजपा के सहयोगी दलों को समझाने और अपने नेतृत्व को स्वीकार कराने में भी हम सफल हुए हैं। केंद्र में राजग सरकार के ढाई वर्षों के अनुभव ने हमारे दृष्टिकोण को सही सिद्ध कर दिया है। आज कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि भाजपा को इस दृष्टिकोण को अपनाने से हानि नहीं, लाभ हुआ है।

यह कोई ऐसा समझौता नहीं है जो हमने केवल सत्ता में बने रहने के लिए किया है। बल्कि हम केंद्र में शासन के अवसर का उपयोग करते हुए राष्ट्र के अनेक बड़े हितों को साध रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता और समर्थक बिना किसी क्षमाभाव के स्पष्ट रूप से और विश्वासपूर्वक हमारे इस संपूर्ण दृष्टिकोण को लोगों को समझाएँ।

कश्मीर और हमारी राष्ट्रीय एकता तथा सुरक्षा को चुनौती

प्रिय प्रतिनिधि बंधुओं, किसी भी दूसरे मुद्दे से कहीं ज्यादा आज पूरे राष्ट्र का ध्यान जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर टिका हुआ है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक दशक से चला आ रहा छद्‌मयुद्ध अब नए भयानक चरण में पहुँच गया है। पिछले वर्ष कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की अपमानजनक हार के बाद इसलामाबाद में सैन्य विद्रोह के कारण हमारा पड़ोसी देश वह सबकुछ पाने के लिए उन्मत्त हो उठा जो वह विभाजन से अब तक प्राप्त नहीं कर सका अर्थात् वह भारत को तहस-नहस और कश्मीर को जबरदस्ती अपने साथ मिलाने में सफल नहीं हो सका। इस वर्ष मार्च में सिखों की सामूहिक हत्या के बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों और बिहार व मध्य प्रदेश से आए हुए श्रमिकों का नरसंहार किया; इसके अलावा भी प्रतिदिन हिंसात्मक गतिविधियों से हमारे अनगिनत सुरक्षा बलों और नागरिकों की हत्याएँ की जा रही हैं, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना हताश हो गया है।

इस स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी हमारी सरकार पर आई है, जिसके लिए भावी घटनाओं के बारे में स्पष्टता, रणनीति में दृढ़ता और सामरिक कार्यनीति में लचीलापन होना आवश्यक है। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा ने निश्चित रूप से भारत की शांतिप्रियता की विश्वसनीयता साबित कर

दी थी। किंतु जब पाकिस्तान ने कुछ महीने बाद कारगिल में धोखे से भारत पर आक्रमण किया तो हमारे बहादुर सैनिकों ने दुश्मन को समुचित सबक सिखा दिया। युद्ध क्षेत्र में हमारी विजय के साथ-साथ विश्व में पाकिस्तान को अलग-थलग करने में हमारी राजनयिक सफलता से यह बात स्पष्ट हो गई कि सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर पहले वाली घुटनाटेक नीति से अलग चलकर स्थिति को सँभाला।

हमारी सरकार ने करगिल में सफलता के बाद पूरे भरोसे और अच्छी तरह से सोच-समझकर कश्मीरी ग्रुपों के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करने की पहल की। प्रधानमंत्री के इस साहसी वक्तव्य से कि सरकार इनसानियत के दायरे में रहकर बातचीत करेगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों में आशा की किरण चमकी, जो शांति, सामान्य स्थिति बहाल करने और रक्तपात को समाप्त करने के इच्छुक हैं। कश्मीर घाटी में शांति की बढ़ती हुई आशाओं को देखते हुए पाकिस्तान घबरा गया। इसी कारण पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही जिन जेहादी संगठनों के नेटवर्क को लंबे समय से संरक्षण दे रहा था, उनके माध्यम से उसने भारत के खिलाफ आतंकवाद के युद्ध को और तेज कर दिया है।

आज जम्मू और कश्मीर में स्थिति नाजुक और जटिल है। यह स्थिति बड़ी तेजी से बदल रही है, जिससे चुनौतियाँ और प्रगति के अवसर दोनों ही सामने आ रहे हैं। भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के सर्वोत्तम हितों में सही दृष्टिकोण अपनाने की निर्णायक जिम्मेदारी हमारी पार्टी पर आती है। नई स्थितियों का सदैव तकाजा होता है कि व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों की उपेक्षा किए बिना नई और रचनात्मक सोच पैदा की जाए। आनेवाले महीनों में संभव है कि ऐसे अनेक मुद्दों पर पार्टी को अपनी स्थिति के बारे में बहस करनी पड़े और निर्णय लेने पड़े, जो सरकार और कश्मीरी ग्रुपों के बीच बातचीत का आधार बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार दोनों ही अवसर पर खरी उतरेगी।

उत्तर-पूर्व राज्यों में स्थिति निरंतर चिंता का विषय बनी हुई है। कुछ सकारात्मक घटनाओं के बावजूद आई.एस.आई. से सक्रिय सहायता प्राप्त कर उग्रवादी ग्रुप लूटपाट करते घूम रहे हैं। आई.एस.आई. समर्थित आतंकवादी और विघटनकारी संगठन अपने पाँव देश के अन्य भागों में भी फैला रहे हैं। नक्सलवादी हिंसा भी कई राज्यों में अविराम जारी है। पार्टी सरकार और लोगों से आग्रह करती है कि वह इन खतरों के प्रति सतर्क रहें। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और अधिक समन्वय की आवश्यकता है। आइए, हम सब मिलकर भारत को ऐसा क्षेत्र बना दे जहाँ आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता हो।

देश के सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का यह भी दायित्व है कि पाकिस्तान और इसके एजेंटों की निरंतर भड़काने वाली कारर‌वाइयों को देखते हुए शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जाए। दीनदार अंजुमन जैसे

आई.एस.आई. समर्थित संगठनों की हाल की पैशाचिक गतिविधियों से पता चला है कि पाकिस्तान सांप्रदायिक दंगे और हिंसा भड़काने पर तुला हुआ है। हम जितना अधिक उसके नापाक इरादों को विफल कर देंगे उतना ही पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ छद्मयुद्ध जारी रखना कठिन होगा।

मैं इस बात पर इसलिए जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि सांप्रदायिक शांति, आंतरिक सुरक्षा और विदेशों में भारत की छवि के बीच परस्पर गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण हिंदुओं और ईसाईयों के बीच पारंपरिक शांति और सद्भावना को धक्का लगा। हालाँकि यह मूर्खतापूर्ण अपवाद थे, परंतु मीडिया और विपक्ष ने इन घटनाओं को इस तरीके से उछाला कि इससे हमारे देश का धवल नाम कलंकित हुआ। इसी के कारण आई.एस.आई. को अपनी घृणित भूमिका निभाने का अवसर मिल गया। लेकिन इसकी भूमिका का जल्दी ही पर्दाफाश हो गया।

इस प्रसंग में हमें अपने प्रधानमंत्री द्वारा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दिए गए विवकेपूर्ण आह्वान पर ध्यान देना चाहिए : "मेरी सभी पंथ तथा जाति के लोगों से अपील है कि हम कल्पना के शत्रु खड़े न करें और अपनी तलवार से ही स्वयं को घाव पहुँचाने का रास्ता न अपनाएँ।"

अर्थव्यवस्था : उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

मित्रो, अनेक कठिनाइयों के बावजूद हमारी सरकार ने बड़े सराहनीय ढंग से अर्थव्यवस्था का प्रबंध किया है। अर्थव्यवस्था प्रगति पर है, विकास-दर बढ़ रही है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, मौसम की आँखमिचौली के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दोनों ही धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं तथा ओद्यौगिक उत्पादन भी बढ़ रहा है।

मुझे खुशी है कि यह सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और आम आदमी के हितों की सुरक्षा के बारे में समुचित उपाय करते हुए सुधार कार्यक्रम जारी रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। सरकार इस बारे में सभी प्रयास कर रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश के कारण श्रमिक वर्ग के कल्याण को कोई नुकसान न पहुँचे। हमारी नीति यह है कि विनिवेश से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल सामाजिक क्षेत्र और सरकारी ऋण की वापसी में किया जाए, जो हम पर भारी बोझ बना हुआ है।

आज जब भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रसंग में अपना पुनर्विन्यास कर रही है तो इस संक्रांति काल में छोटे, मध्यम और बड़े—सभी भारतीय उद्योगों के लिए चुनौतियाँ खड़ी होंगी। मैं सरकार से इस संक्रांति काल के लिए ठोस रणनीति तैयार करने का आग्रह करता हूँ। विश्व व्यापार संगठन के मानकों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अंतर्गत रहते हुए सरकार

को हमारे ऐसे उद्योगों को जब तक आवश्यक हो तब तक समुचित संरक्षण देना चाहिए, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता की आवश्यकता है। सरकार को उन लघु और पारंपरिक उद्यमों में लगे लोगों को पुनः प्रशिक्षित करने, उन्हें साज-सामान उपलब्ध कराने और पुनः तैनात करने में अपने प्रयास भी तेज करने होंगे, जो इस संक्रांति काल में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं या बेकार हो गए हैं।

मैं इस बात को भी अवश्य समझता हूँ कि सरकार के लिए रातोरात अर्थव्यवस्था को बदल देने का कार्य सरल नहीं है। पिछले पचास वर्षों में जो सरकारें रहीं, उनके द्वारा अपनाई गई गलत विकास और विकृत रणनीतियों के दुष्प्रभाव को दूर करना होगा। परंतु लोगों को हम से बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं। इसके अलावा वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने की हमारी दीर्घावधि रणनीति से हमें ऐसे उपाय करने होंगे, जिनसे साथ-ही-साथ एक सुरक्षा तंत्र भी तैयार किया जाए, जिससे आम आदमी, गृहिणी, छोटे किसान और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों पर बोझ काफी आसान और कम हो सके।

उनके लिए अर्थव्यवस्था को सुधारने का अंतिम पैमाना निर्वैयक्तिक नहीं है और उन्हें थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों और विदेशी मुद्रा भंडार के आँकड़ों से कुछ लेना-देना नहीं है। वे तो चाहते हैं कि जब बाजार जाएँ तो वे अपनी मासिक आय से आवश्यक वस्तुएँ खरीद सकें और उनके पास भविष्य की आकस्मिकताओं के लिए कुछ धनराशि बची रहे। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी आर्थिक नीति तैयार होनी चाहिए। यदि आम आदमी का बोझ कम नहीं होता है तो सभी अच्छे सूचकांकों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है और लोगों में यही भाव पैदा होता है कि आर्थिक सुधार केवल अमीर लोगों के लाभ के लिए हैं। मुझे खुशी है कि सरकार ऐसे अनेक उपाय कर रही है जो गरीबों और हमारे समाज के वंचित वर्गों के लाभ के लिए हैं।

तेज विकास का मंत्र

मित्रो, भारत के लोगों ने हमारी पार्टी और राजग को जो जनादेश दिया है उसके साथ वह हम पर ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी डालता है। उनको हमारी सरकार से बहुत आशाएँ हैं। विगत में जो भी सरकारें आईं, विशेष रूप से 1960 के दशक के बाद की सरकारों ने उनकी आशाओं को पूरा नहीं किया और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहीं। हालाँकि पिछले पाँच दशकों में भारत की अनेक प्रभावशाली उपलब्धियाँ हैं, परंतु आम आदमी सरकार के वायदों और कार्यक्रमों से हताश रहा है। इसका कारण यह रहा है कि लोगों की आकांक्षाओं और सरकार के कार्य-प्रदर्शन के बीच निरंतर फर्क बना रहा है।

राजग ने इस फर्क को कम करने के वायदे पर मतदाता से जनादेश माँगा था। हमें इस वायदे को पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। हमें अपने सभी नागरिकों के लाभ के लिए स्वराज को सुराज में बदलने की अपने वायदे को निभाना होगा।

हम और अधिक तेजी से व्यापक रूप में और समान रूप से आर्थिक विकास के जरिए इस वचन को पूरा कर सकते हैं। इस प्रसंग में हमारे प्रधानमंत्री ने हाल में राष्ट्र का आह्वान किया था कि अगले 10 वर्षों को विकास का दशक बनाया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने राष्ट्र के सामने अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा था। इसके लिए आवश्यक होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत से अधिक की विकास दर पर पहुँचे।

यह लक्ष्य केवल हमारी महत्त्वाकांक्षा नहीं है। यह हमारे लिए अनिवार्य फलितार्थ होना चाहिए। जब तक इतनी ऊँची दर के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं होगी तब तक हम बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पाएँगे और न ही गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत पाएँगे और न ही क्षेत्रीय तथा सामाजिक असंतुलनों को कम कर पाएँगे।

हमारे देश के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्राकृतिक, मानवीय प्रोद्यौगिकी संबंधी और प्रबंधकारी संसाधन हैं। अब भारत में ऐसा नेतृत्व भी है, जिसके पास राजनीतिक परिकल्पना और इच्छाशक्ति है, जिसकी पहले कमी थी। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्‌देश्य के कार्य में पूरे मन से सभी भारतीय लोगों की सामूहिक शक्ति लग जाए।

हमारी सरकार ने व्यापक आर्थिक सुधारों को अपनाया है, जो इस उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक तीव्र और सबसे अधिक निश्चित तरीका है। कुछ हद तक देश में आर्थिक सुधारों पर मोटे तौर पर आम सहमति पहले ही बन चुकी है। हमारी पार्टी और हमारी सरकार के लिए इस आम सहमति को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

स्वदेशी, उदारीकरण और वैश्वीकरण : सभी एक-दूसरे के पूरक

मित्रों, प्रायः हमारी सरकार द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों के अर्थ, आशय और विषय-सूची पर बहस होती है। थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा के माननेवाले लोगों से कुछ आलोचनात्मक स्वर सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी पार्टी ने लंबे समय से चली आ रही स्वदेशी के प्रति प्रतिबद्धता को भी त्याग दिया है और इन सुधारों को अपनाकर उल्टी दिशा में चलने लगे हैं। आज मैं पूरे जोर से यह बात कहना चाहता हूँ कि यह आलोचना तीन कारणों से गलत है।

एक, ऐतिहासिक रूप से भाजपा और इससे पूर्व भारतीय जनसंघ ने सदैव ही दफ्तरशाही, नियंत्रण और लाइसेंस परमिट कोटा राज को समाप्त करने का पक्ष लिया है, जिनके कारण पुरानी सभी कांग्रेस सरकारों के अधीन अनेक दशकों से हमारी अर्थव्यवस्था का गला घोंटा जाता रहा था। हमने कभी भी राजकीय समाजवाद का समर्थन नहीं किया, जिस पर विफल सोवियत मॉडल का प्रभाव था। हमारी पार्टी ने सदैव ऐसी आर्थिक प्रणाली का पक्ष लिया है जिसमें सरकार की भूमिका एक नीति निर्माता, सुविधा प्रदाता (फेसीलिटेटर) और कानून तथा नियमों के क्रियान्वयन कर्ता की रहे और वास्तविक आर्थिक गतिविधियों के चलाने का काम समाज की सृजनकारी शक्तियों पर छोड़ दी जाए।

दो, पिछली सरकारों द्वारा अपनाई गई गलत रणनीतियों और नीतियों के कारण ही ऐसा हुआ कि प्रचुर संसाधनों और क्षमताओं के बावजूद आज भी देश में भारी निर्धनता, बेरोजगारी और नगण्य विकास की स्थिति बनी हुई है। यह कठोर यथार्थ ही इस बात के लिए पर्याप्त कारण है कि हम भूतकाल के रास्ते से हटकर चलें।

तीन, पिछले दो दशकों में हमने विश्व में दूरगामी आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं। विश्व भर में सरकारें निजी और गैर-सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका की समीक्षा और संशोधन कर रही हैं। राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता कई गुणा बढ़ गई है। इसके अलावा विश्व व्यापार, निवेश, पूँजी प्रवाह और संचार में क्रांतिकारी प्रगति कंप्यूटर और इंटरनेट ने वैश्वीकरण को अनिवार्य यथार्थ बना दिया है। विश्व में व्याप्त इस नई यथार्थ ने भारत के लिए चुनौतियाँ और नए अवसर पैदा किए हैं। भारत अपने देश के लोगों के लिए अधिक समृद्धि प्राप्त करने के वास्ते चुनौतियों या अवसरों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता है।

अतः आज के प्रसंग में स्वदेशी का अर्थ आँख मूँदकर उदारीकरण या वैश्वीकरण का विरोध करना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमें वैश्वीकरण द्वारा दिए गए अवसरों से लाभ उठाकर और चुनौतियों का सामना करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए प्रभावकारी रणनीति तैयार करनी होगी। स्वदेशी कोई जड़ अवधारणा नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत ने सदैव अपने को नए यथार्थ के अनुकूल समझौता किए बिना कोई ढाला है और वही किया है जो उसके लोगों के लिए अच्छा है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि पिछली सरकारों द्वारा शुरू किए गए और हमारी सरकार द्वारा जारी रखे आर्थिक सुधारों का रास्ता समस्याओं से मुक्त है। ये सभी समस्याएँ हमारी सरकार के ढाई वर्षों के सत्ता की अवधि में सुलझाई नहीं जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, लंबे समय से कृषि खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास, लघु और कुटीर उद्योग, वस्त्र और अन्य पारंपरिक उद्योगों के प्रति जो

उपेक्षा चलती रही है उसे तत्काल उलटने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों में हमारा अधिकांश मजदूर वर्ग काम करता है और इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अतिरिक्त रोजगार पैदा करने की क्षमता भी है। बिजली, रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डों आदि के क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास को तेज करने की तत्काल आवश्यकता है।

मार्च 1998 से हमारी सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में अनेक सफलताएँ प्राप्त की हैं। उसने विशेष रूप से सूचना टेक्नोलॉजी, दूरसंचार में जो दूरगामी सुधार शुरू किए हैं उनके लाभ पहले ही दृष्टिगत होने लगे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि आनेवाले महीनों में हमारी सरकार अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देगी जिनपर अभी तक कम ध्यान दिया गया है।

गरीब गाँव और किसान : हमारी प्राथमिक वचनबद्धता

तेजी से औद्योगीकरण और नगरीकरण के बावजूद भारत प्रमुखतः गाँवों में रहता है और कार्य करता है। हमारे अधिसंख्य लोगों का काम-धंधा कृषि है। एक समृद्ध, विकसित और आत्म-विश्वास से भरे भारत के निर्माण की कल्पना ग्रामीण विकास और कृषि विकास के प्रति हमारी पक्की प्रतिबद्धता में निहित है।

दुर्भाग्य से विगत पचास वर्षों में कृषि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। हमारे परिश्रमी किसानों ने जो कुछ प्राप्त किया है—उदाहरण के लिए हरित क्रांति जैसी सफलताओं को देखकर यही पता चलता है कि सरकार द्वारा सीमित ध्यान देने पर भी हम कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सरकार को यह श्रेय जाता है कि उसने स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इसक उद्देश्य कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना है।

इसी प्रकार ग्रामीण विकास के लिए हमने अनेक वर्तमान योजनाओं को फिर से तैयार किया है, अनेक योजनाएँ शुरू की हैं और बजट में कहीं अधिक धनराशि रखी है एवं उनके कार्यान्वयन को विकेंद्रीकृत किया है।

हमारी पार्टी को ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं और नई कृषि नीति के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभानी है। मैं अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वे विशेष रूप से उन कार्यक्रमों पर सक्रिय रूप से निगरानी रखने में जुट जाएँ, जिनका उद्देश्य गरीबों में भी सबसे गरीब की दशा को सुधारना है। इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, जनश्री बीमा योजना, अन्नपूर्णा योजना और सर्वप्रिय योजना ऐसी ही योजनाएँ हैं, जिनमें हमारे कार्यकर्ता लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए उन्हें एकजुट और प्रेरित करने के काम में जुट सकते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी के साथ पक्षपात न किया जाए, किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो, और न ही गलत तरीके अपनाए जाएँ। मुझे यहाँ यह बात कहने

की आवश्यकता नहीं है कि इस सारे कार्य से हमारी पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर तक समर्थन प्राप्त कर पार्टी का विस्तार करने और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

सामाजिक न्याय हमारा दृष्टिकोण, 'आरक्षण जमा' में होना चाहिए

प्रिय प्रतिनिधि बंधुओ, सामाजिक न्याय हमारी पार्टी के लिए एक नए और नवोदित भारत की पार्टी की परिकल्पना को रेखांकित करता है। हमारे लाखों-लाख दलित आदिवासी और अन्य सुविधा वंचित समुदाय के भाइयों और बहनों पर सदियों से आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय होता आया है, जिससे हमारा समाज विकृत हुआ है। इन सभी के कारण एक तरफ भारत के महान् सांस्कृतिक और सभ्यतामूलक मूल्यों के बीच दुखद विभाजन हुआ और दूसरी तरफ हमारे ये बंधु अत्यंत दुर्दशा की हालत में जीते रहे।

यह विभाजन हमारी राष्ट्रीय चेतना पर ऐसा घाव है जिसे हम इक्कीसवीं शताब्दी में अब और जारी नहीं रख सकते हैं। इस घाव पर मरहम लगाना ही होगा अन्यथा यह हमारे राष्ट्र की प्रगति को विकृत करेगा और ह्रास की दिशा में ले जाएगा।

अभी तक सामाजिक न्याय के मुद्दे का समाधान आरक्षण की नीति के माध्यम से किया गया है। निःसंदेह इससे काफी हद तक अभिप्रेत प्रयोजन सिद्ध भी हुआ है। शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण से दलितों, आदिवासियों और उन अन्य पिछड़े वर्गों में से शिक्षित लोगों की एक पूरी नई श्रेणी तैयार हो सकी है, जिन्हें इस प्रकार के लाभ न मिलने पर शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ेपन में सड़ते रहना पड़ता। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण से इन वंचित वर्गों को लगभग शून्य के स्तर से उठकर कम-से-कम कुछ इतना लाभ तो मिला है, जो दिखाई पड़ने लगा है।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि संसद्, राज्य विधानमंडलों, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के कारण वे ग्रुप जो अभी तक निरीह अवस्था में थे, उन्हें राजनीतिक रूप से शक्ति प्राप्त हुई है। जिससे उन्हें आत्म-सम्मान, आत्म विश्वास और शासन में भागीदारी मिली है।

भाजपा ने सदैव ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की नीति का समर्थन किया है और हमारा समर्थन पहले की तरह ही अडिग रहेगा। दरअसल, हमारी सरकार की इस उपलब्धि पर हमें गर्व करना ठीक ही है कि उसने आरक्षण के प्रावधान का दस वर्षों के लिए विस्तार किया, साथ ही उसने आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने का प्रावधान किया। हालाँकि इसके लिए संविधान में संशोधन करने तक की आवश्यकता थी।

किंतु पिछले पाँच दशकों के अनुभव का वास्तविक आकलन करने पर सिद्ध

होता है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए आरक्षण शर्त है, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के भाइयों की एक बहुत बड़ी संख्या अभी तक गरीबी और अशिक्षा में रहकर जीवन व्यतीत कर रही है। उनमें से अधिकांश तो आरक्षण के वर्तमान प्रावधानों का लाभ उठाने की स्थिति में भी नहीं हैं। इनमें से अधिकांश अब भी गरीबी और निरक्षरता के हालात में सड़ रहे हैं। यह तो स्पष्ट है ही कि वे राजनीतिक आरक्षण से पर्याप्त लाभ नहीं उठा सकते हैं।

जिस गति से इस समय उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दर्जे में परिवर्तन हो रहा है, उससे तो अभी उनकी स्थिति सुधरने में अनेक दशक और लग जाएँगे और तब कहीं वह हमारे समाज के सुविधा प्राप्त तथा अगड़े वर्गों के समकक्ष आ पाएँगे। हमारी पार्टी को यह धीमी गति से हो रहा बदलाव स्वीकार नहीं है। अतः समय आ गया है कि भाजपा समाज के सभी सुविधा वंचित वर्गों का तेजी से सामाजिक न्याय, शैक्षिक उत्थान और आर्थिक प्रगति की राह पर ले जाने के लिए नया साहसिक एजेंडा सामने रखे।

सामाजिक न्याय, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच गहन संबंधों को समझने के लिए डॉ. बाबा साहब अंबेडकर के सत परामर्श का स्मरण करना हमारे लिए उपयोगी होगा :

"लोकतंत्र की आत्मा एक जन, एक मूल्य का सिद्धांत है। दुर्भाग्य से लोकतंत्र में एक जन, एक वोट के नियम को अपनाकर इस सिद्धांत को केवल राजनीतिक ढाँचे के अंदर ही लागू करने का प्रयास किया गया है···इसमें आर्थिक ढाँचे को आकार देने का काम उनपर छोड़ दिया है जो इसमें परिवर्तन करने की स्थिति में हैं। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि संविधान के अधिवक्ताओं ने···कभी यह महसूस नहीं किया कि यदि लोकतंत्र को एक जन, एक मूल्य के सिद्धांत पर टिके रहना है तो समाज के आर्थिक ढाँचे के आकार और रूप को निर्धारित करना भी उतना ही जरूरी है। समय आ गया है कि संविधान की विधि द्वारा समाज के आर्थिक ढाँचे और राजनीतिक ढाँचे, दोनों के बारे में साहसिक कदम उठाया जाए और परिभाषा की जाए···"

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम

इस प्रसंग में, मैं सामाजिक न्याय के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहता हूँ :

1. आरक्षण जारी रखना : हमें शिक्षा, रोजगार एवं राजनीतिक क्षेत्रों में जब तक आवश्यक हो, विद्यमान आरक्षण संबंधी सभी उपबंधों को तब तक जारी रखना चाहिए और सभी स्तरों पर उनके कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।

2. सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए कानूनों को कारगर तरीके से लागू करना : जाति के आधार पर होने वाले सामाजिक अन्याय एवं भेदभाव को रोकने के लिए विद्यमान कानूनी उपबंधों को कार्यान्वित करने का अब तक का रिकॉर्ड यह दरशाता है कि अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। अपराधियों को कभी-कभार ही दंडित किया जाता है। विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों एवं छोटी जातियों के प्रति किए गए अत्याचारों के दोषियों पर कभी-कभार ही मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें दंडित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप पीड़ित जातियाँ अकसर यह अनुभव करती हैं कि पुलिस, प्रशासन तथा कानूनी तंत्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। उग्रवादी गुटों ने अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक स्थानों पर इस स्थिति से नाजायज फायदा उठाया है। उदाहरणार्थ, बिहार में कभी समाप्त न होने वाली बड़े पैमाने पर की जा रही जातीय हिंसा की परंपरा आधुनिक भारत के लिए शर्मनाक है। अतः अब सामाजिक अन्याय एवं अत्याचारों के खिलाफ बनाए गए कानूनों के कार्यान्वयन की पूर्णतया समीक्षा करने का समय आ गया है।

3. सामाजिक न्याय की गारंटी के रूप में आर्थिक सुधार : अब इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण से ही वंचित समुदायों की पर्याप्त उन्नति नहीं हो सकती, उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक न्याय नहीं मिल सकता। इसके साथ ही नई नौकरियों का सृजन करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों की क्षमता अधिकाधिक सीमित होती जा रही है। अतः यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे दलित, आदिवासी तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बंधुओं को गरीबी और सामाजिक पिछड़ेपन की जंजीरों से मुक्त कराने का केवल एक ही रास्ता है कि अर्थव्यवस्था के निजी, अनौपचारिक तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में तेजी से लाखों की संख्या में रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाए। इसके लिए हमें लगातार दीर्घकाल तक अपनी आर्थिक विकास की दर को व्यापक आधार वाला बनाकर और इसकी गति को तेज करके सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की दर को लगभग दस प्रतिशत वार्षिक तक पहुँचाने की आवश्यकता है। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को तेज किए बिना इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः तेजी से किए जाने वाले आर्थिक सुधारों को दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य सुविधा से वंचित लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण सामाजिक न्याय की गारंटी के रूप में समझा जाना चाहिए।

4. सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक समरसता : अपने लोकतंत्र को

शक्तिशाली एवं और अधिक कारगर बनाने के लिए निस्संदेह वंचित जातियों एवं समुदायों को जिन्हें अब तक राजनीतिक प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है अथवा कम प्रतिनिधित्व मिला है राजनीतिक दृष्टि से अधिकाधिक संगठित करने की आवश्यकता है, किंतु राजनीतिक दलों को जाति एवं समुदायों का एकांतिक उपयोग और अतिरेकी समर्थन जुटाने में अधिकतम आत्मसंयम से काम लेना चाहिए। इस प्रकार से समर्थन जुटाने से, विशेष रूप से चुनावी लाभ के लिए, अकसर समाज में तनाव पैदा हो जाता है और लोगों में फूट पड़ जाती है जिससे अंततोगत्वा सामाजिक न्याय के लिए किए जाने वाले साझा प्रयासों में शिथिलता आ जाती है। सामाजिक न्याय का अनुसरण करते हुए सामाजिक समरसता की अनिवार्यता को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

5. साक्षरता को राष्ट्रीय औसत दर तक लाना : अगले दस वर्षों में दलितों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में शिक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़े वर्गों के साक्षरता स्तर को बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत दर तक लाने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम बनाना होगा। उस कार्यक्रम के एक विशेष भाग का उद्देश्य उन राज्यों तथा क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाकर राष्ट्रीय स्तर तक लाना होगा, जहाँ उनका साक्षरता का स्तर अत्यधिक निम्न है। इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों तथा विद्यमान शिक्षा संस्थाओं के सारे संसाधनों को एक साझा मिशन बनाकर कारगर तरीके से जुटाना होगा। साक्षरता बढ़ाने के कार्यक्रमों के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, जनसंख्या और परिवार कल्याण संबंधी शिक्षा को भी समन्वित करना होगा।

6. बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अच्छे प्रशासकों की नियुक्ति : नौकरशाही में यह चिंताजनक सोच है कि साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी विभागों और कार्यक्रमों में नियुक्तियों को 'अनाकर्षक' और 'प्रतिष्ठाहीन' समझा जाता है। वहाँ जाकर निम्न स्तर पर कार्य करना पड़ता है और दूर-दराज के तथा अल्पविकसित क्षेत्रों में नियमित रूप से जाना पड़ता है। जिन सिविल कर्मचारियों में स्वतः प्रेरणा नहीं है उनसे इस प्रकार के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आशा नहीं की जा सकती। इन कार्यक्रमों में उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार भी विद्यमान है। इसके फलस्वरूप केंद्र एवं राज्य सरकारें उनपर प्रतिवर्ष विशाल धनराशि व्यय करती हैं; परंतु उसके वांछित परिणाम नहीं निकलते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस मिशन को कार्यान्वित करने के लिए सर्वोत्तम प्रशासकों एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के सक्षम प्रबंधकों को भी नियुक्त किया जाए तथा नियमित रूप से इसकी सामाजिक जाँच होनी चाहिए।

7. गैर-सरकारी क्षेत्र पर दायित्व डाला जाए : आज गैर-सरकारी क्षेत्र आरक्षण के दायित्वों से मुक्त है। किंतु इसका कोई कारण नहीं है कि इसे सामाजिक क्षेत्र के विकास के दायित्वों से मुक्त रखा जाए। प्रत्येक गैर-सरकारी उद्यम के लिए यह आवश्यक कर दिया जाए कि वह अपने लाभ का कुछ हिस्सा ऐसी स्वीकृत गैर-सरकारी गतिविधियों में लगाने के लिए निश्चित करे जिनका उद्देश्य कमजोर वर्गों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य की देखभाल और उन्हें अन्य सुविधाएँ को प्रदान करना है। सरकार निजी क्षेत्रों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा अन्य सुविधाओं संबंधी प्रस्तावों पर विचार करते समय इस सामाजिक दायित्व को एक शर्त बना सकती है।
8. परंपरागत व्यवसायों को अधिक लाभप्रद बनाना : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकांश गरीब लोग असंगठित ही आर्थिक गतिविधियों के काम में जुटे हुए हैं। वे कला, दस्तकारी, बुनाई तथा अन्य परंपरागत व्यवसायों में रोजगार अथवा स्वरोजगार में लगे हुए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए, जो उन्हें अधिक अच्छी ऋण व्यवस्था, अधिक अच्छी विपणन व्यवस्था, अधिक अच्छे प्रबंधन तथा उपयुक्त विज्ञान एवं टेक्नॉलोजी से तथा अधिक योगदान देकर उनकी आर्थिक गतिविधियों में मदद दे। इन उत्पादों के निर्यात को इस ढंग से बढ़ावा दिया जाए जिससे प्राथमिक उत्पादकों को निर्यात से होने वाली आय का उचित हिस्सा मिले।
9. और उद्यमी तथा व्यावसायिक तैयार करना : जहाँ कहीं संभव हो सरकार को दलितों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की विशिष्ट श्रेणियों को जहाँ वे काम करते हैं वहीं के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का आंशिक अथवा पूर्णरूपेण स्वामी बनाने के लिए उपयुक्त कानून पेश करना चाहिए। उदाहरणार्थ, लाखों गरीब लोग भारत में खदानों में काम करते हैं। वे आम तौर पर छोटी जातियों के होते हैं। क्या हम ऐसा उपबंध नहीं कर सकते, जिसमें यह आदेश दे दिया जाए कि खदानों को केवल खदान में काम करनेवाले श्रमिकों की सहकारी समितियों को ही पट्टे पर दिया जाएगा और जो कोई भी यह धंधा करना चाहे उसे ऐसी सहकारी समितियों का भागीदार बनना होगा। इस प्रकार का मार्ग अन्य आर्थिक गतिविधियों, जैसे ईंट के भट्ठों, वन उत्पादों को इकट्ठा करने आदि पर भी लागू किया जा सकता है। भारत में सामाजिक न्याय के आंदोलन के अगले चरण के लिए दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों में उद्यमशीलता का विकास बहुत आवश्यक है। इन समुदायों में जितने अधिक सफल उद्यमी, व्यवसायी और प्रबंधक होंगे उतना ही इन समुदायों के अन्य सदस्यों के प्रदर्शन पर अच्छा

असर होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र तथा राज्यों में कार्यरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त निगम, पिछड़ा वर्ग आयोग आदि, निकायों के कार्य की अच्छी तरह समीक्षा की जानी चाहिए और उनमें सुधार लाना चाहिए।

10. 'अंक विभाजन' (डिजिटल डिवीजन) को कम किया जाए : सूचना टेक्नॉलोजी, बॉयो-टेक्नॉलोजी तथा ज्ञान के नए क्षेत्रों पर आधारित अन्य उद्यम धन संपदा के निर्माण के इंजन बन गए हैं। इसके साथ ही जिनके पास सूचना टेक्नोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है और जिनके पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके बीच एक नई 'अंक विभाजन' के बारे में वाजिब आशंका उत्पन्न कर दी है। भारतीय प्रसंग में इस विभाजन ने इस अर्थ में एक अतिरिक्त सामाजिक फर्क पैदा कर दिया है कि हमारे दलितों आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पास सूचना टेक्नॉलोजी की सुविधा नहीं है और वे तब तक ऐसे बने रहेंगे जब तक इसको सुधारने के लिए कारगर उपाय नहीं किया जाता। सरकार, सूचना टेक्नॉलोजी उद्योग, शेष व्यापारी वर्ग तथा शिक्षा संस्थाओं को भावी खतरे की ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए। उन्हें कम्प्यूटरों, संचार साधनों, इंटरनेट तथा सूचना टेक्नोलॉजी की अन्य सुविधाओं को इन समुदायों तक पहुचाने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए, जिससे कि सूचना टेक्नोलॉजी, सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए एक नया औजार बन सके।

सामाजिक सुधार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता

सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता का संवर्धन अकेले सरकारी कदमों से नहीं हो सकता। सामाजिक एकता लाने और पुराने रीति-रिवाजों और प्रथाओं को बदलने के बारे में नई चेतना पैदा करने के संबंध में समाज की भूमिका पर नितांत आवश्यक है।

इतिहास हमें बताता है कि आत्मसुधार सदा ही हमारे समाज की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है। स्वतंत्रता आंदोलन की विशेषता और शक्ति का अधिकांश भाग हमारे महान् नेताओं के राजनीतिक संघर्ष के साथ सामाजिक सुधार के शक्तिशाली एजेंडा था—सचेत एवं सक्रिय प्रयासों के मिलाने से पैदा हुआ। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजनीतिक गतिविधियों और सामाजिक सुधार के मुक्तिदायक एजेंडे अलग-अलग कर दिए गए।

निरक्षरता, अस्पृश्यता नर और नारी में भेदभाव, दहेज प्रथा की बुराई, वृद्धों की दशा, पर्यावरण प्रदूषण, हमारे युवा वर्ग का संस्कृतिविहीन होना—ये कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनको केवल राजनीतिक तथा सरकारी कार्यवाई के जरिए व्यापक रूप से निपटा नहीं जा सकता। इस संबंध में गैर-सरकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों

द्वारा की जाने वाली पहल एवं प्रयास प्रशंसनीय हैं; किंतु भारतीय समाज के सामने इस समय जितनी विकट समस्याएँ हैं, उन्हें देखते हुए उनके सर्वोत्तम प्रयास भी पर्याप्त नहीं हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने एजेंडा के दायरे को बढ़ाएँ और इन मुद्दों पर भी ध्यान दें तथा अपने देश को इन शर्मनाक सामाजिक बुराइयों से मुक्त करने के लिए अपना योगदान करें।

एक दलित व्यक्ति, जो अस्पृश्यता के व्यवहार और सामाजिक भेदभाव का शिकार है, पूरे मन से भारत माता का यशगान नहीं कर सकता। एक अनपढ़ व्यक्ति पूर्ण रूप से राष्ट्र के साथ अपना तादात्म्य नहीं बैठा सकता। एक नौजवान जो रोजगार का अवसर ढूँढ़ने में लगा हुआ है, उसके लिए रचनात्मक रूप से राष्ट्र की सेवा करना कठिन है। एक युवती, जिसे दहेज के लिए परेशान किया जाता है, इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती कि हमारी संस्कृति में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' को ईमानदारी से महत्त्व दिया जाता है। जब तक हम उन विवशताओं को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इन वर्गों के साथ भेदभाव किया जाता है और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, तब तक हमारी राष्ट्रीय मुख्य धारा में इनकी भागीदारी सार्थक और संपूर्ण नहीं हो सकती।

हमारी पार्टी को तत्काल चुनावी फायदा उठाने की कोशिश किए बिना इस प्रकार के सभी सच्चे प्रयासों को सक्रिय समर्थन देना चाहिए और इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी कार्यकर्ता और नेता अपने समुदाय, मौहल्ले अथवा क्षेत्र में किसी-न-किसी समाज सुधार संबंधी गतिविधि से अपने आपको जोड़ें, ताकि हम सामाजिक एवं राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को साथ-साथ चलाएँ। मैं इस मुद्दे पर अपने भाषण में बाद में आगे और चर्चा करूँगा।

पार्टी के सामाजिक आधार का विस्तार

प्रिय प्रतिनिधि बंधुओ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारी पार्टी ने नए-नए क्षेत्रों में अपना सामाजिक आधार एवं भौगोलिक दायरा तेजी से बढ़ाया है। केंद्र तथा अनेक राज्यों में चुनावी लाभ के रूप में इस संबंध में हमारी उपलब्धियाँ प्रतिबिंबित भी होती है।

तथापि 1999 के लोकसभा के चुनावों और कुछ राज्यों में हुए हाल के चुनावों के परिणाम भी एक ऐसे रुझान को प्रदर्शित करते हैं, जिस पर हमें गम्भीरता से ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी उपलब्धियाँ एक पठार पर पहुँच गई हैं। 1998 तथा 1999 के लोकसभा के चुनावों में हमारी सीटों की गिनती तथा मतदान का प्रतिशत, दोनों थोड़ा-बहुत एक जैसा ही रहा। कुछ राज्यों में जो परंपरागत रूप से हमारे गढ़ थे, हमें पराजय का सामना करना पड़ा है। कुछ अन्य राज्यों में जहाँ हमारी पार्टी गत दशक अथवा कुछ इससे

अधिक समय में तेजी से बढ़ी है और जहाँ हमें सत्ता में आने की आशा थी, वहाँ हमारा प्रदर्शन आशा के अनुकूल नहीं रहा। हमें अपनी भावी रणनीति के बारे में गंभीरता से सोचना होगा, ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि हमारी शक्ति निरंतर बढ़ती चले।

देश में कुछ राजनीतिक प्रेक्षक पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि भाजपा चुनावी दृष्टि से अपने चरम बिंदु तक पहुँच चुकी है। हमारी पार्टी तथा समग्र राजनीतिक स्थिति का यह एक गलत मूल्यांकन है। वस्तुतः इन प्रेक्षकों ने 1991 और 1996 के लोकसभा के चुनावों में भी यही निष्कर्ष निकाला था! किंतु हमने उन्हें हर बार गलत साबित किया। हमारे सामने उन्हें भविष्य में एक बार फिर गलत सिद्ध करने की चुनौती है।

मेरा विश्वास है कि इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के मामले में सबसे महत्त्वपूर्ण वह आत्मविश्वास है कि हम यह चुनौती स्वीकार करने में सक्षम हैं। हमारा अपने आप में, अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में तथा सबसे अधिक अपनी जनता में भरोसा होना चाहिए। हमने कभी नहीं माना कि हम चरम बिंदु पर पहुँच गए। इसी आत्मविश्वास भरे इनकार के कारण ही हम आगे-से-आगे बढ़ते गए।

इसके अतिरिक्त हमें उन तत्त्वों के बारे में ईमानदारी से आत्मचिंतन भी करना चाहिए जो हमारे निरंतर त्वरित विकास में बाधा डाल रहे हैं। मैं ऐसे तीन तत्त्व गिना सकता हूँ।

एक, यद्यपि हम हाल के वर्षों में दलितों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को अपनी ओर आकर्षित कर सके हैं; किंतु हमें अपने इस नए समर्थन आधार को पक्का करना होगा और संख्या एवं सामाजिक दृष्टियों से समाज के इन महत्त्वपूर्ण वर्गों में लगातार इसका विस्तार करना होगा। अपनी पार्टी की सभी इकाइयों से मेरा यह अनुरोध है कि वे दलितों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में अपने राजनीतिक एवं संगठनात्मक काम को लगातार बढ़ाने का प्रयास करें। हमें सामूहिक रूप से निरंतर उन्हें संगठित करने के कार्यक्रमों को हाथ में लेना चाहिए और जहाँ कहीं आवश्यक हो, उनसे संबद्ध महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक आंदोलन करने चाहिए। हमें उनके सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से अपने आपको संबद्ध करना चाहिए। हमें इन समुदायों के युवा, प्रगतिशील और सामाजिक दृष्टि से सम्मानित सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने तथा अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए सायास प्रयास करना चाहिए।

दो, जिन राज्यों में हमें सत्ता के लिए चुना गया था उन राज्यों में हम सामान्यतया मतदान में शासन विरोधी प्रवृत्ति को नाकामयाब करने में सफल नहीं हुए हैं। दूसरे शब्दों में, भाजपा लोगों की निगाहों में 'शासन के लिए पसंदीदा पार्टी' अभी तक नहीं बनी है। राज्यों के अपने सभी सहयोगियों से मेरा यह अनुरोध है

कि जहाँ कहीं हम मतदान में शासक विरोधी प्रवृत्ति का शिकार बने हैं वहाँ अपने लाभ-हानि की समीक्षा करें, हमें ऐसी अन्य राजनीतिक पार्टियों के सकारात्मक अनुभवों से भी सबक सीखना चाहिए, जो मतदान में शासन विरोधी प्रवृत्ति के बावजूद सत्ता में वापस आ जाती हैं।

तीन, हमारी पार्टी और मुसलिम समुदाय के बीच समीकरण की बात भी है, यह अपने आप में एक जटिल विषय है और मैं इसके संबंध में कुछ विस्तार से कहना चाहता हूँ।

भाजपा तथा भारतीय मुसलमानों के बीच संबंध को फिर से बनाना

गत पाँच दशकों की भारतीय राजनीति की एक खास बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय मुसलमान भारतीय जनता पार्टी तथा इससे पहले भारतीय जनसंघ से दूरी बनाए रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस दूरी से न तो हमारे मुसलमान भाइयों को और न ही हमारी पार्टी को कोई लाभ हुआ है। सबसे बढ़कर तो बात यह है कि इससे न तो भारत को और उसके लोकतंत्र को कोई मदद मिली है।

यह दूरी अनेक ऐतिहासिक कारणों से बनी रही है। भारत के विभाजन से भारतीय मुसलमानों के हितों को अनेक प्रकार से नुकसान पहुँचा है। उनमें से ऐसा ही एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति का है। मुसलमान देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी समुचित भूमिका नहीं निभा सके हैं। ऐसी पार्टियों ने जिनका वे समर्थन करते रहे हैं अधिकांशतया उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सांप्रदायिकता का हौवा दिखाकर भाजपा से दूर रखने की नीति पर रखा, किंतु इससे आम मुसलमान को कोई फायदा नहीं हुआ है। प्रायः राष्ट्र के विकास में न तो उनको सही हिस्सा मिला और न ही ये राष्ट्र निर्माण में अपनी समुचित भूमिका अदा करने के लिए राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हो सके।

भाजपा के हम लोगों ने विरोधियों के लगातार नकारात्मक प्रचार के कारण मुसलमानों के मन पर पड़े प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन तक पहुँचने का कोई सतत प्रयास नहीं किया। हमने किसी-न-किसी तरह यह समझ लिया है कि हमारी पार्टी को उनसे कभी कोई सार्थक समर्थन मिलने वाला नहीं है। अपनी पूर्व-परिकल्पित दृष्टिकोण को अपनाने से हमारी पार्टी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। 1999 के लोकसभा के चुनावों के परिणामों ने स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया है कि हमें जो थोड़ा-बहुत लाभ मिला है, वह हमारे नेतृत्व की योग्यता एवं प्रतिष्ठा, भाजपा के पक्ष में अत्यधिक अनुकूल वातावरण और कांग्रेस तथा हमारे अन्य विरोधियों के प्रतिकूल वातावरण के कारण संभव हुआ। हमें जितनी सफलता मिलने की आशा थी उतनी न मिलने का एक मुख्य कारण यह रहा कि हमारी पार्टी मुसलमानों के वोट प्राप्त करने में सफल नहीं रही। यह विडंबना ही

है कि यद्यपि भारतीय मुसलमान अटलजी का बहुत आदर करते हैं और वे उनमें बहुत लोकप्रिय भी हैं; किंतु फिर भी उनमें भाजपा से दूर रहने की प्रवृत्ति की इस स्थिति को बनाए नहीं रख सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी ही भावी संभावनाओं को नुकसान पहुँचाएँगे और हमारे विरोधी मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप के करते रहेंगे। इस प्रसंग में मैं अपनी पार्टी की चेन्नई घोषणा को याद कराना चाहता हूँ जिसे दिसंबर 1999 में राष्ट्रीय परिषद् के गत अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इसमें कहा गया है :

"हाल के चुनाव परिणामों से यह भी पता चलता है कि भाजपा की विकास-यात्रा की बढ़ती गति इस कठोर तथ्य पर निर्भर करेगी कि हम भारतीय समाज के उन वर्गों का समर्थन पाने में कितने समर्थ सिद्ध होते हैं जिन्हें हम कई कारणों से अभी तक प्रभावित नहीं कर पाए हैं। विशेषतः यह आवश्यक हो गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पार्टी का समर्थन बढ़ाया जाए, जो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। भारतीय राष्ट्रवाद को दृढ़ बनाने के अपने संकल्प के अनुरूप धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ वर्तमान संबंधों के बारे में पार्टी पुनरावलोकन करेगी। किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण न अपनाते हुए पूरे न्यायपूर्ण ढंग से उनकी समस्याओं को हल करने और उनके विभिन्न मुद्दों को समर्थन देने के सिद्धांतवादी आधार पर भाजपा अल्पसंख्यकों के बीच अपना समर्थन बढ़ाने के कार्य को तेज करेगी।"

पिछले दो दशकों में हमारी पार्टी दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों तक सफलतापूर्वक पहुँची है। मुसलमान भारतीय समाज का अंतिम बड़ा अछूता वर्ग है, जिस तक हमारे पहुँचने की आवश्यकता है। हमारी विचारधारा, नीतियों और कार्यक्रमों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे कोई यह अर्थ निकाले कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या हम ऐसा नहीं कर सकते। उलटे इतिहास हमारा आह्वान कर रहा है और हमसे यह माँग करता है कि हम भारत की और भारतीय मुसलमानों की और स्वयं अपनी पार्टी के हित में भी ऐसा करें।

मेरे विचार में ऐसे बहुत से अनुकूल तत्त्व हैं, जिनकी वजह से मैं आशावादी हूँ कि हम अपने इस प्रयास में सफल होंगे।

- प्रथम, अनेक मुसलमानों का उन पार्टियों की 'अल्पसंख्यकवाद' की राजनीति से पूर्णतया मोहभंग हो चुका है, जिनका वे परंपरागत रूप से समर्थन करते रहे हैं। वे समझ गए हैं कि ये पार्टियाँ ईमानदार नहीं हैं और मुसलमानों की सामान्य हालत सुधारने में विफल रही है।
- दूसरे, वे स्वयं यह भी समझ चुके हैं कि भाजपा सरकारें, चाहे वे केंद्र में हों अथवा राज्य में, दोनों ही जगह सभी समुदायों के प्रति पक्षपातरहित और भेदभाव न करने वाली रही हैं।
- तीसरे, वे इस बात को जानते हैं और उन्होंने यह अनुभव किया है कि

हमारी सरकारों के अधीन उनकी धार्मिक आजादी में न तो कोई कमी आई है और न ही कोई खतरा पैदा हुआ है।

- चौथे, पहले जो स्थिति थी, उसकी तुलना में सांप्रदायिक शांति और भाईचारा बनाए रखने का हमारा रिकॉर्ड कहीं अच्छा रहा है।
- पाँचवें, हमारी सरकार ने जो दूरगामी आर्थिक सुधार आरंभ किए हैं उनसे निश्चित रूप से चहुँमुखी विकास में तेजी आएगी, इसे सभी के लिए ज्यादा रोजगार के अवसरों और अधिक संपदा का निर्माण होगा। यह सभी के लिए होगा, जिनमें भारतीय मुसलमान भी शामिल हैं।
- अंतिम, हमारे नेताओं की ईमानदारी और उनके व्यक्तित्व के कारण मुसलमानों के मन में भी उनके प्रति उतना ही आदर और प्रशंसा के भाव पैदा करते हैं जितना बाकी के समाज में।

इन सब तत्त्वों के कारण भाजपा के विरुद्ध विरोधियों के झूठे प्रचार की पोल खुल गई है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि हम अपनी अपील और गतिविधियों को मुसलमानों के घरों और मोहल्लों तक ले जाएँ। आनेवाले महीनों में हमारी पार्टी को अपने इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हमें आम मुसलमान से संबंधित विकास संबंधी मुद्दों की जोरदार तरीके से वकालत करनी चाहिए। हमें सक्रिय रूप से इस दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि प्रभावशाली और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित मुसलमान कार्यकर्ताओं को पार्टी में लाया जा सके। विभिन्न चुनावों के उम्मीदवारों की सूची में भी हमें और अधिक मुसलमानों को शामिल करना चाहिए।

ऐसा दिसंबर 1967 के भारतीय जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में स्व. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस कथन से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था—"भारतीय समाज का हर वर्ग हमारे शरीर का एक अंग है और उनका खून हमारा खून है।"

संविधान समीक्षा : बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन नहीं

संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति हमारी सरकार का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण कदम है। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनावी वायदों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया है। कांग्रेस और वामपक्षी पार्टियाँ इस समीक्षा के बारे में अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीसियों बार संविधान संशोधन किया है। हमेशा ईमानदार उद्देश्यों के लिए किया हो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए इस बारे में सरासर झूठ बोल रही है।

इस मंच से मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि समीक्षा की युक्तिसंगतता बिलकुल सीधी-सादी है। इसका प्रयोजन भी निष्कपट है। हम यह समझते हैं कि

एक गतिशील लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि समय-समय पर संविधान की अच्छी तरह समीक्षा की जाए। यह देखना भी आवश्यक है कि हमारे राज्यतंत्र और समाज में जो दूरगामी परिवर्तन हुए उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या इसमें सुधार किया जा सकता है? संविधान निर्माताओं ने जिनमें डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर तथा तत्कालीन अनेक बड़े-बड़े विद्वान शामिल थे, उन्होंने इस दस्तावेज पर अंतिमता की मुहर नहीं लगाई।

फिर भी मैं राष्ट्र के समक्ष यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संविधान का बुनियादी ढाँचा अक्षुण्ण रहेगा। वंचितों को, जो युगों से भेदभाव के शिकार रहे हैं और जिनका सदियों तक शोषण हुआ है, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सहायता देने के उद्देश्य से उपबंध बनाए गए हैं, उनमें से किसी को भी समीक्षा की प्रक्रिया में बदला नहीं जाएगा। इस प्रसंग में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे संविधान की समीक्षा के बारे में लोगों के मन में अगर कोई आशंका है तो उसे दूर करें।

पार्टी विदेश नीति में और अधिक रुचि ले

हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक—विदेश नीति का क्षेत्र है। गत ढाई वर्षों में भारत के अंतरराष्ट्रीय दर्जे और हैसियत में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज पाकिस्तान को छोड़कर हमारे देश के संबंध विश्व के प्रत्येक देश के साथ पहले से कहीं अधिक अच्छे हैं। कुछ महाशक्तियों ने मई 1998 में परमाणु विकल्प का प्रयोग करने के बाद हमारी सरकार के साहसपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय की कठोर शब्दों में आलोचना की थी। उन्होंने भारत के खिलाफ आर्थिक एवं अन्य प्रतिबंध लगा दिए थे। हम इन बातों के बावजूद विश्व के देशों के साथ अच्छे संबंध बना सके हैं, इसका श्रेय भारत की जनता और हमारी सरकार को जाता है कि भारत ने दबावों के आगे घुटने नहीं टेके और सफलतापूर्वक इन प्रतिबंधों का सामना किया।

भारत की निंदा करने और उसे अलग-थलग करने के प्रयास बड़ी जल्दी ही विफल हो गए। प्रत्येक महाशक्ति ने जिसने हमारी परमाणु कार्यवाई की आलोचना की थी अब वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है और वैश्विक मामलों में भारत की एक शक्तिशाली एवं जिम्मेदार भूमिका को भी स्वीकार किया जाने लगा है। हमारे प्रधानमंत्री की सफल यात्राओं, अनेक क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारी सफल भागीदारी और विश्व के अनेक बड़े-बड़े नेताओं का भारत आगमन आदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योग्य नेतृत्व में भारत की बढ़ी प्रतिष्ठा और प्रभाव के जीते-जागते प्रमाण हैं।

मित्रो, अब चूँकि हमारी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है और भारतीय राजनीति में उसकी प्रमुख भूमिका है, हमें अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर पहले से अधिक ध्यान देने

की आवश्यकता है। आज विश्व में जो जटिल मुद्दे पैदा हो रहे हैं उनको गहराई से समझने के लिए अपनी पार्टी के अंदर संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी के अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रकोष्ठ को विदेश नीति के विशेषज्ञों और संगठनों के साथ अपना संबंध और अधिक प्रगाढ़ करना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि अब भाजपा के लिए विश्व की राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के साथ भाईचारे के संबंध स्थापित करने का समय भी आ गया है। हमें अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और मोरचों के पदाधिकारियों को दूसरे देशों के अध्ययन और उनके साथ परामर्श करने के लिए नियमित रूप से विदेश भेजना चाहिए। इसी प्रकार हमें विभिन्न देशों की राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित करते रहना चाहिए। इस प्रयास में हमें विश्व के विभिन्न भागों में 'ओवरसीज फ्रेंडस ऑफ बीजेपी' की भूमिका को और अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है।

भारतीय मूल के लोगों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता

मित्रो, लगभग तीन करोड़ अनिवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के लोग भारत के बाहर रहते हैं। उन्होंने विभिन्न व्यवसायों में अपनी शानदार उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं तथा उन्होंने अपने मेजबान अथवा अंगीकृत देशों के प्रति अपनी निष्ठा से भारत के लिए प्रशंसा अर्जित की है। भारत माता के साथ उनके भावनात्मक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक बंधन अटूट हैं। वे भारत में अपने वित्तीय, बौद्धिक एवं व्यावसायिक संसाधनों का निवेश करके हमारे राष्ट्रीय विकास में काफी योगदान कर रहे हैं। हम सबका और केंद्र तथा राज्यों की हमारी सरकारों का भी यह कर्तव्य है कि वे उनके आड़े वक्त में इन विदेश में रह रहे हमारे भाइयों की सहायता करें।

उदाहरणार्थ, फिजी में हाल की घटनाओं ने स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया है कि भारतीय मूल के लोगों को समय-समय पर कितने कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। श्री महेंद्र चौधरी की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी वैध सरकार की जो संवैधानिक हत्या की गई थी उसके विरुद्ध उस क्षेत्र के देशों, राष्ट्रकुल के देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के जनमत को संगठित करने के लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। फिजी में लोकतंत्र और भेदभाव रहित संवैधानिक व्यवस्था की बहाली के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। इस संघर्ष की सफलता के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन जुटाने के अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है।

इससे पहले युगांडा में भी हमारे भाइयों पर इसी प्रकार का संकट आया था। विश्व के अन्य कुछ देशों में भी उन्हें भेदभाव और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत को संकट के प्रति मात्र अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने

की बजाय विदेशों में रहनेवाले हमारे भाई-बहनों के वैध अधिकारों तथा हितों की रक्षा करने के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। जब कभी विदेशों में रहनेवाले भारतीयों को खतरे का सामना करना पड़े तो हमें भारतीय मूल के लोगों की बढ़ती आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को भारत के हित में सक्रिय रूप से संगठित करना चाहिए। साथ ही उनके हितों की रक्षा भी करनी चाहिए। संपूर्ण विश्व के भारतीय एक समुदाय हैं। हमें सबकी समृद्धि और प्रसन्नता के लिए एक-दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। इस प्रयास में हमने अब तक जितना प्रयास किया है हमारी पार्टी को उससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए।

पार्टी के समक्ष कार्य

मित्रो, हम काफी दूर आ गए हैं। अपनी वैचारिक यात्रा आरंभ करने के करीब 50 वर्ष बाद और भारतीय जनता पार्टी के रूप में 20 वर्ष की यात्रा करने के पश्चात् आज हम एक शासक दल बने हैं। हम भारत की एक प्रमुख राजनीतिक-वैचारिक शक्ति हैं। आज हमारा यह दायित्व है और अवसर भी है कि हम उन उद्देश्यों की पूर्ति पूरी तरह न भी कर पाएँ तो भी पर्याप्त रूप से पूरा करने का प्रयास करें, जिनको लेकर हमने अपनी यात्रा आरंभ की थी।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारी प्रगति चरम बिंदु तक नहीं पहुँची है। इस समय देश की राजनीतिक स्थिति हमारे पक्ष में है। हमारे पास उत्तम नेतृत्व है, जिसका न केवल हमारे मित्र, अपितु हमारे विरोधी और आम लोग भी आदर करते हैं। आज हमें वे सभी अवसर प्राप्त है, जिससे हम भारत के स्वराज को सुराज में बदलने का अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। हमें इस मार्ग पर आगे वही शक्ति ले जाएगी, जिसने आज तक हमें आगे बढ़ाया है अर्थात् हमारे कार्यकर्ताओं में एकता और अनुशासन, हमारी सोच में स्पष्टता और अटल विश्वास तथा हमारे कार्य में ईमानदारी और गतिशीलता।

अब मैं अपनी पार्टी की आज की स्थिति के बारे में कुछ साफ-साफ बात कहना चाहता हूँ। चेन्नई घोषणा-पत्र में इनका तथा अन्य मुद्दों का उल्लेख व्यापक रूप से किया गया है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से गंभीरता से इनका अध्ययन करने का अनुरोध करता हूँ।

एक अलग पहचान की पार्टी : अपने गौरव के दावे को पुनः स्थापित करना

प्यारे साथियो, हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, कि हमारे संगठन में बहुत सी विकृतियाँ और भटकाव आए है। जहाँ इनको बेरोक-टोक बढ़ने दिया गया है वहाँ हमारी पार्टी को भारी झटका भी लगा है।

गुटबाजी, आपसी मतभेद, कुछ राज्यों में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं में सत्ता हथियाने की लालसा, राज्य और जिला स्तरों पर कुछ पदाधिकारियों का निरंकुश व्यवहार, पद प्राप्त करने की लोलुपता, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जाति और संप्रदाय के आधार पर कुछ मामलों में ध्रुवीकरण, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की टिकट लेने हेतु दौड़ और कहीं कहीं पर तो अपराधी तत्त्वों के साथ मेलजोल–ये सभी विकृतियाँ भाजपा के मूल सिद्धांतों तथा हमारी गर्वपूर्ण परंपरा के विरुद्ध हैं।

मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये हमारी छोटी-मोटी भूलें हैं और हमारी पार्टी के प्रमुख लक्षण नहीं हैं। फिर भी इनसे हमारे कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा आम जनता में हमारी पार्टी से लोगों का मोहभंग होता है, इसके परिणामस्वरूप हमारे शुभचिंतक और हमारे विरोधी, दोनों ही बार-बार हमारे इस दावे को चुनौती देते हैं कि हम एक अलग पहचान वाली पार्टी हैं।

अनुशासनहीनता : हमें एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी

हमें अनुशासनहीनता की बीमारी और व्यक्तियों तथा वर्गों द्वारा पार्टी के सामूहिक निर्णयों की अवहेलना के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। यदि हमारी पार्टी अनुशासित नहीं है तो हमारी पार्टी के होने का कोई अर्थ ही नहीं है। हमें इन प्रवृत्तियों को कठोरता से दबाना होगा। मैं आज यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अनुशासनहीनता बरदाश्त नहीं की जाएगी। हमें सिर उठाने से पूर्व ही इसे कुचल देना होगा, ताकि बाद में इस रोग का उपचार करना दुसाध्य न बन जाए। इस महत्त्वपूर्ण प्रयास में मैं आप सभी के समर्थन और सहयोग की याचना करता हूँ।

हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी पार्टी में ऐसी प्रवृत्तियाँ क्यों विकसित हो रही हैं। इन प्रवृत्तियों को सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए व्यवस्था करना पर्याप्त नहीं है। इन लक्षणों से निपटने के बजाय हमें इन प्रवृतियों के मूल कारणों को दूर करना होगा और उनसे ईमानदारी एवं व्यापक स्तर पर निपटना होगा।

हमें अपने सदस्यों और संगठन की राजनीतिक और सैद्धांतिक शिक्षा को सुदृढ़ करना होगा। हमारे संगठन में निरंतर बड़ी संख्या में शामिल होने वाले नए सदस्यों को हमारी विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति को समझाने की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। हमें एक स्पष्ट आचरण संहिता बनानी चाहिए। हमें एक स्पष्ट लक्ष्मण-रेखा खींचनी होगी।

शुचिता : लोगों की धारणा हमारा मानदंड होना चाहिए

यह एक गंभीर मामला है जिस पर हमारी पार्टी को ऊपर से नीचे तक गंभीरता से विचार करना चाहिए, और शीघ्र ही उपचारात्मक उपाय करने चाहिए। हमें निरंतर यह याद रखना होगा कि भारत के लोगों ने हमें जनादेश दिया है और

उनकी हमसे बड़ी अपेक्षाएँ हैं। जहाँ हम सत्ता में हैं और जिम्मेदार हैं वहाँ वे हम से कुशल और अच्छे प्रशासन की आशा करते हैं, और जहाँ हम सत्ता में नहीं हैं वहाँ वे हम से सिद्धांतयुक्त राजनीतिक व्यवहार की आशा करते हैं। उतनी ही महत्त्वपूर्ण बात यह हे कि वे यह भी आशा करते हैं कि हम सार्वजनिक जीवन में नैतिक और सदाचारपूर्ण मूल्यों पर कायम रहें; यह भी कि हम व्यक्तिगत और वर्गीय हितों को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक शक्ति के निंदनीय प्रयोग को समाप्त करें। वे हमसे पूरी शुचिता की आशा करते हैं।

लोगों ने देखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे बड़े संगठन का भी वर्ग संघर्ष और शक्ति के दुरुपयोग के कारण पतन हो गया है। अतः उनका शंकालु होना उचित ही है। जब तक हम एक छोटी पार्टी थे या सत्ता से दूर थे तब तक हमारे लिए एक अलग पहचान की पार्टी बने रहना आसान था। वास्तविक परीक्षा तो अब है और आनेवाले दिनों में होगी।

मुझे खुशी है कि पिछले ढाई वर्षों के दौरान, जब से हम सत्ता में हैं, हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई प्रामाणिक आरोप नहीं लगा है। फिर भी इस मामले में ढिलाई बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून के प्रावधानों के आधार पर हमारी शुचिता की परख नहीं की जा सकती। हमारी ईमानदारी तकनीकी और कानूनी न होकर, इससे बढ़कर होनी चाहिए। संक्षेप में हमें अपने आचरण का आकलन जनता की धारणाओं के आधार पर करना चाहिए। कोई छोटी सी हलचल भी होती है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। हमारी छवि स्वच्छ होनी चाहिए और स्वच्छता तथा ईमानदारी दिखाई भी देनी चाहिए।

पार्टी में उच्चतम पद पर आसीन रहते हुए भी सादा जीवन व्यतीत करने का एक अच्छा उदाहरण मेरे पूर्ववर्ती श्री कुशाभाऊ ठाकरे ने प्रस्तुत किया है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी में ऐसे अनेक नेता और कार्यकर्ता हैं। वे अन्य लोगों के लिए तथा हमारी पार्टी में प्रवेश करनेवाले नए लोगों के लिए आदर्श बन सकते हैं।

पार्टी-सरकार के बीच संबंध

हमारे सामने एक महत्त्वपूर्ण कार्य है पार्टी और हमारी सरकार के बीच संबंधों को और मजबूत करना, चूँकि हम पहली बार केंद्र में सत्ता में आए हैं, यह पार्टी के लिए एक नया अनुभव है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से प्रायः यह टिप्पणी और आलोचना सुनता हूँ, कि जो लोग सत्ता में हैं, वे पार्टी की अनदेखी कर रहे हैं। इसी प्रकार सरकार में अपने सहयोगियों से भी मुझे यह सुनने को मिलता है कि पार्टी कार्यकर्ता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सरकार कैसे काम करती है, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता।

मुझे विश्वास है कि दोनों की शिकायतों में कुछ दम है। कई बार हमारे

कार्यकर्ता यह भूल जाते हैं कि हम एक सत्ताधारी पार्टी हैं और सत्ता में होने से हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। उनकी कुछ सार्वजनिक घोषणाओं और व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वे सोचते हैं कि हम अभी भी एक विपक्षी दल हैं।

कुछ कार्यकर्ताओं का यह विचार है कि अब जबकि हमारी पार्टी सत्ता में है, तो वह भी वैसे ही तरीके अपना सकते हैं जैसे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनाए, जब उनकी पार्टी सत्ता में थी। वे सोचते हैं कि व्यक्तिगत लाभ उठाना उनका अधिकार है। वे सरकारी और अर्धसरकारी निकायों में पद प्राप्त करना चाहते हैं, वे रोजगारों, नियुक्तियों और स्थानांतरणों की माँग करते हैं। मंत्रियों के ध्यान में सार्वजनिक मामलों को लाने की बजाय वे निजी स्वार्थों की प्रायः वकालत करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा सिद्धांतहीन राजनीतिक व्यवहार कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महँगा साबित हुआ। इससे लोगों के मन में यह धारणा बैठ गई कि कांग्रेसी स्वार्थी हैं और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं।

इसी प्रकार, सत्ता पर आसीन कुछ लोग तथा संसद् सदस्य एवं विधायक ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं के प्रति, जो इसकी रीढ़ की हड्डी है, उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। हमारे कार्यकर्ता को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि मंत्री उसके प्रति उदासीन है अथवा वह उससे नहीं मिल पाता है। प्रायः वे पार्टी कार्यालय में नहीं आते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। जब पार्टी के कार्यकर्ता सार्वजनिक हित के मामले उनके ध्यान में लाते हैं तो भी वे नौकरशाही ढंग से पेश आते हैं। वे अपनी निजी और शेष सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। जब कार्यकर्ता अंधकार में होते हैं या निरुत्साहित हो जाते हैं तो जनता के प्रति सरकार का रूख स्पष्ट करना उनके लिए कठिन हो जाता है।

पार्टी और सरकार के बीच घनिष्ठ तालमेल क्यों आवश्यक है, इसका एक और कारण भी है। हमारी सरकार ने जनता के हित में कई विकास की परियोजनाएँ और योजनाएँ आरंभ की हैं। इनका कार्यान्वयन एकमात्र नौकरशाहों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि जब कोई राजनीतिक दिशा–निर्देश तथा जनता का दबाव नहीं होता है तब नौकरशाही कैसे काम करती है। इन परियोजनाओं और योजनाओं को सफल बनाने में हमारी पार्टी काफी रुचि रखती है, क्योंकि हम अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी है, जिन्होंने हमें अपना जनादेश दिया है। अतः सभी स्तरों पर हमारी पार्टी इकाइयों को उनके कार्यान्वयन पर नजर रखने में समुचित रूप से दिलचस्पी रखनी चाहिए।

हमें सरकार के सामने नए विचार रखने होंगे, हमें सरकार को नई नीतियाँ बनाने के सुझाव देने होंगे, और उनके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की रचनात्मक

रणनीति तैयार करनी होगी। हमें सरकार के विरोधियों द्वारा प्रेरित और निराधार आलोचना का कारगर ढंग से विरोध करना होगा। यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि हमारी जानकारी का सरकार को लाभ हो, और जनता सरकार के अच्छे काम से लाभान्वित हो।

इसी प्रकार सरकार के विकास और कल्याण कार्यों का प्रभावी ढंग से प्रचार करने का काम सरकारी तंत्र पर नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे कार्यकर्ताओं को सरकार की कार्यसूची और उपलब्धियों के बारे में जनता को सूचना देने के लिए सभी संभव उपाय करने चाहिए, जिसमें नियमित और प्रत्यक्ष रूप से जनता के साथ संपर्क भी शामिल है।

महिलाओं का सशक्तीकरण : पार्टी के अंदर और बाहर

मित्रो, भारतीय समाज में एक मौन क्रांति हो रही है। इस क्रांति का नाम सशक्तीकरण है। नारी शक्ति, जो अब तक या तो निष्क्रिय अथवा उपेक्षित रही है, वह अब अपने आप को व्यक्त करने लगी है। हमारी बहनें और बेटियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत, अधिक शिक्षित, आर्थिक दृष्टि से अधिक उत्पादक एवं अधिक सक्रिय तथा आत्मविश्वास से भरपूर होती जा रही हैं। वे पुराने और नए, दोनों ही प्रकार के अन्यायों और पक्षपातों के खिलाफ लड़ रही हैं। वे राष्ट्र निर्माण में भी समान रूप से योगदान करना चाहती है।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण विशेष रूप से अब एक सद् इच्छा अथवा दिखावे का नारा नहीं रह गया है। आज हमारी संसद् के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है। हमें गर्व है कि भाजपा पहली ऐसी पार्टी थी, जिसने 1987 में ही वडोदरा में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संसद् तथा राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग की थी।

केंद्र में सत्ता सँभालते ही हमारी सरकार संविधान में इस क्रांतिकारी संशोधन को शीघ्रता से पारित करवाने के लिए आम सहमति बनाने के लिए जोरदार प्रयास करती रही है। दुर्भाग्यवश, अब तक यह आम सहमति बन नहीं सकी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए वह अपने प्रयासों को और तेज कर दे। यदि कतिपय राजनीतिक पार्टियों की हठधर्मिता के कारण, जो किसी भी हालत में इस विधेयक के पारित होने को रोकने की स्थिति में नहीं हैं, आम सहमति के प्रयास विफल हो जाएँ तो उसके बावजूद सरकार को अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।

जहाँ तक हमारी पार्टी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का संबंध है, हमने गत दशक में इसमें काफी प्रगति की है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यदि संसद् तथा राज्य विधानमंडलों में एक तिहाई निर्वाचित महिलाओं को प्रतिनिधि बनना है और

यदि पंचायती राज संस्थाओं की एक तिहाई सदस्याएँ पहले ही महिलाएँ है–और वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं–तो क्या हमारी पार्टी को इस अनुपात से अधिक महिलाओं को सदस्य, सक्रिय सदस्य तथा पदाधिकारी नहीं बनाना चाहिए?

मुझे इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिए सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्रिय होना बहुत अधिक कठिन है। उन्हें अपने परिवारों के अंदर तथा समाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुःख की बात है कि अकसर उन्हें पार्टी के अंदर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारा यह कर्तव्य है कि हमारी पार्टी की गतिविधियों में महिलाओं की अधिक भागीदारी के मार्ग से सभी बाधाओं को दूर कर दें। मेरा सभी स्तरों पर अपनी पार्टी की सभी इकाइयों से यह अनुरोध है कि वे हमारे महिला मोरचा की गतिविधियों को पूरी तरह प्रोत्साहित करें। हमें अपनी सक्रिय महिला कार्यकर्त्रियों को अधिक मान्यता और अधिक जिम्मेदारियाँ प्रदान करनी चाहिए। हमें विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य वंचित वर्गों की अधिकाधिक महिलाओं को नेतृत्व के पदों पर लाने की कोशिश करनी चाहिए।

महिला मोरचा की अपनी बहनों से भी मेरा अनुरोध है कि वे अपने कार्यक्रमों के दायरे बढ़ाएँ, साझे मुद्दों पर अन्य पार्टियों के महिला संगठनों के साथ निकट संपर्क में काम करें और देश भर में बहुत से मुद्दों पर सराहनीय कार्य करनेवाले गैर–राजनीतिक महिला वर्गों के साथ निकटता से कार्य करें।

युवा : हमारी पार्टी की आशा एवं ऊर्जा शक्ति

अब हम जब नई शताब्दी में अपनी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की प्रथम बैठक करने जा रहे हैं, मैं 21वीं सदी में अपनी पार्टी और अपने देश की अत्यंत महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। भारत का भविष्य युवाओं का है और स्वयं भारत एक युवा राष्ट्र बन गया है। हमारी जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग 35 वर्ष की आयु से कम के लोगों का है। एक मात्र इसी तथ्य के कारण अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने राष्ट्र की विकास प्रक्रिया को फिर से नया रूप दें जिससे प्रत्येक युवा एवं महिला लाभान्वित हो सके और इस बात को सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह इसमें भागीदार बन सकें।

आज किसी के भी सामने यह स्पष्ट है कि भाजपा एक युवा पार्टी है। हमारी पार्टी ने गत 15 वर्षों में देश की किसी भी अन्य पार्टी की अपेक्षा अधिक संख्या में युवाओं को आकृष्ट किया है। यह भारतीय युवा वर्ग के सभी वर्गों की सबसे अधिक लोकप्रिय पार्टी है–ग्रामीण एवं शहरी शिक्षित एवं कम पढ़े–लिखे सभी वर्गों के भारतीय युवा इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह आकर्षण जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग एवं प्रदेश के दायरों को भी पार कर गया है। हम सब जानते हैं

कि हमारी राजनीतिक गतिविधियों, आंदोलनों और चुनाव अभियानों में बड़ी संख्या में युवकों द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लेने के कारण ही भाजपा को भारतीय राजनीति में आज प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है।

आनेवाले वर्षों में हमें भारतीय युवाओं के साथ अपने बंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। हमें अपने युवा कार्यकर्ताओं के योगदान को और अधिक मान्यता प्रदान करनी है। इनमें से जो होनहार हों और परिश्रमी हों उन्हें और अधिक जिम्मेदारियाँ सौंपी जानी चाहिए। वरिष्ठ नेताओं को सजग और सतत प्रयास कर इन युवाओं को कल के नेता बनाने के लिए तैयार करना चाहिए।

मैं पार्टी की उन्नति में युवा मोरचा के योगदान के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मोरचा के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह दुगुने उत्साह और दृढ़निश्चय के साथ अपनी गतिविधियों को बढ़ाएँ।

संरचना : रचनात्मक गतिविधियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का समय

प्रिय प्रतिनिधि बंधुओ, 1980 में जब हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री अटलजी ने मुंबई के ऐतिहासिक सम्मेलन में पार्टी के निर्माण के लिए एक तीन सूत्री नारा दिया था। यह नारा था—संगठन, संघर्ष और संरचना। हमने बड़े प्रशंसनीय ढंग से पहले दो कामों को पूरा किया है। किंतु हमें यह मानना पड़ेगा कि हमने तीसरे काम की प्रायः उपेक्षा की है।

हमारा निरंतर प्रयास रहा कि छद्म-धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सत्तारूढ़ लोगों में भ्रष्टाचार, स्वतंत्रता के पश्चात् आनेवाली एक के बाद दूसरी सरकारों द्वारा आर्थिक विकास के गलत नमूने को अपनाने में की गई मूलभूत त्रुटियाँ जैसे विषयों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने से देश में ऐसा राजनीतिक वातावरण बना जिसके फलस्वरूप भाजपा-नीत सरकार की स्थापना हुई। फिर भी हमें केवल अपने आप को राजनीतिक शिक्षा और आंदोलनों तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है।

हमारी पार्टी एक अलग पहचान की पार्टी है। हमारे इस दावे का एक अर्थ यह है कि हम अपने समाज में क्रांतिकारी और व्यापक परिवर्तन लाने का दृढ़-संकल्प कर चुके हैं। अन्य पार्टियाँ वोट माँगने के लिए ही लोगों के पास जाती हैं और एक चुनाव व दूसरे चुनाव की मध्यावधि में उनके साथ बात भी नहीं करतीं अथवा केवल राजनीतिक प्रयोजन से ही उनसे बातचीत करती हैं। लेकिन भाजपा इस प्रकार के आचरण से संतुष्ट नहीं हो सकती है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय हित के लिए महत्त्वपूर्ण विभिन्न मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के काम में अपने आपको लगाए रखना चाहिए। उन्हें राजनीतिक स्वरूप की व्यापक रचनात्मक गतिविधियों में लगे रहना चाहिए, चाहे

इनसे हमारी पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा न हो तो भी।

स्कूल या सहकारी समिति, धर्मार्थ अस्पताल चलाने या स्वच्छता कार्यक्रम जैसे न जाने कितने प्रकार के काम हैं, जिनमें हमारे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर भाग लेने का या नेतृत्व करने का अवसर होता है। जरूरी नहीं है कि हमारे बड़े कार्यकर्ता राजनीतिक एवं सामाजिक चरित्र के बड़े पैमाने के कार्यक्रमों में ही भाग लें। हमारे समाज को व्यापक रूप से बदलने में छोटे और सूक्ष्म स्तर पर पहल की जाए तो उसकी भी हमारे समाज की कायापलट में बड़ी भारी भूमिका होती है।

हमारी पार्टी की प्रत्येक ग्राम समिति यह पक्का इरादा कर ले कि अगले कुछ महीनों में वह यह सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ उसके जन्म की जाति के आधार पर किसी भी कार्यक्षेत्र में, किसी भी रूप में अस्पृश्यता अथवा भेदभाव न बरता जाए। प्रत्येक कार्यकर्ता यह प्रतिज्ञा ले कि आगामी एक वर्ष में उसके मोहल्ले के प्रत्येक निरक्षर व्यक्ति को काम लायक साक्षर बना दिया जाएगा। आइए, हम सब यह पक्का निश्चय कर लें कि हमारी पार्टी इकाइयों के क्षेत्र में आनेवाले इलाके में दहेज के लिए किसी महिला को परेशान न किया जाएगा। हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे कार्यक्षेत्र में कोई वृद्ध व्यक्ति परिवार एवं समाज की उपेक्षा का शिकार बनकर असहाय न रहे। मैं समझता हूँ कि यह काम हमारे विस्तृत एजेंडा का एक भाग होना चाहिए।

इस विस्तृत एजेंडा को कार्यान्वित करने में हमारे मोरचे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। एक साल के अंदर लोग यह कहने लगें कि स्थानीय भाजपा इकाई के रचनात्मक हस्तक्षेप के कारण उनके गाँव में कोई अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करता; उनके मोहल्ले में एक भी अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, एक भी ऐसा वृद्ध नहीं है जिसका ध्यान नहीं रखा जाता; एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें दहेज के लिए परेशान किया गया हो। यदि हमारे कार्यकर्ता एक सप्ताह में कुछ घंटे, एक महीने में कुछ दिन बचाकर यह काम करें तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है।

ऐसा करके हम अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए जो सद्भावना पैदा करते हैं वह राजनीतिक काररवाई से पैदा होने वाली सद्भावना से कहीं अधिक चिरस्थायी होती है। यह हमारे कार्यकर्ताओं में आदर्शवादिता एवं समाज-सेवा की भावनाओं को भी पैदा करती है और उनका पोषण करती है। साथी प्रतिनिधियों, मैं आप सबको ऐसे विचार और सुझाव देने का आमंत्रण देता हूँ कि हम संरचना को पार्टी के समग्र ढाँचे के एक अविभाज्य अंग के रूप में इस प्रकार से कारगर बना सकते हैं, ताकि समाज परिवर्तन के महान् कार्य में हमारा सक्रिय योगदान हो सके।

हमारा सपना : भारतीय जनता पार्टी—सूक्ष्म भारत का स्वरूप

मित्रो, हमारी पार्टी एक पीढ़ीगत संक्रांति से गुजर रही है। नए-नए और विशेष

रूप से युवा सदस्य बड़ी संख्या में हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नौजवान सक्रिय कार्यकर्ता संगठन में अधिकाधिक जिम्मेदारियों को सँभाल भी रहे हैं। हमें नई शताब्दी में अपनी पार्टी की गौरवशाली परंपराओं को जारी रखने के लिए वरिष्ठ नेताओं के आदर्शवाद और अनुभव तथा नए युवा सदस्यों की ऊर्जा दोनों का समन्वय करना होगा।

अगले तीन वर्षों में हमें बड़ी मेहनत से काम करना होगा, जिससे हमारी पार्टी का संदेश इस विशाल एवं महान् देश के घर-घर तक पहुँच सके। हमें प्रत्येक पंचायत में एक गतिशील इकाई स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए तथा और भी बहुत सी महिलाओं को अपनी पार्टी का सदस्य बनाना होगा तथा संगठन में जिम्मेदारी सौंपनी होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमें अपनी पार्टी और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच विद्यमान दूरी को खत्म करने का विशेष प्रयास करना होगा।

हमारी पार्टी को हमारे देश की सामाजिक, क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक विविधता का सच्चा प्रतिबिंब बनना चाहिए। हमारे समाज का कोई भी ऐसा वर्ग न हो जो अपने आपको हमारी पार्टी से अलग-थलग और विमुख अनुभव करे। प्रत्येक वर्ग को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि उनके सच्चे हित भाजपा के हाथों मे सुरक्षित हैं और हमारा राजनीतिक कार्यक्रम ईमानदारी से उनकी ओर ध्यान देता है।

संक्षेप में, भारतीय जनता पार्टी भारत का एक सूक्ष्म रूप होनी चाहिए।

निष्कर्ष

प्रिय साथियो एवं मित्रो, इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूँ, पार्टी के सर्वोच्च पद पर मुझे चुनने के लिए मैं हृदय से आप सबको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं आपकी आशाओं के अनुरूप उतरने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखूँगा। मैं इस भारी जिम्मेदारी को इस निश्चय के साथ स्वीकार कर रहा हूँ कि मुझे अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का निर्बाध मार्गदर्शन और आप सबका समर्थन तथा सहयोग प्राप्त होगा।

हमारी पार्टी एक युवा पार्टी है, जिसने अभी-अभी 20 वर्ष पूरे किए हैं। इस युवा अवस्था में बड़े-बड़े सपने देखना स्वाभाविक है और अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ-संकल्प के साथ परिश्रम से काम करना होगा। इसमें हम भारत माँ के गौरव को छोड़कर अन्य कोई पारितोषिक प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस सबकुछ इस महान् राष्ट्र की महान् जनता के लिए चाहिए।

हमारे इस प्राचीन राष्ट्र ने अभी नई शताब्दी में यात्रा शुरू की। हमारा देश खुशहाल था, यहाँ खुशियाँ भरी थी, यहाँ सामाजिक शांति थी, जब कलेंडर शुरू

नहीं हुआ था तब यह देश सांस्कृतिक प्रसिद्धि के शिखर पर था। यह इतिहास ने राष्ट्र की यात्रा के दौरान पराजय के कुछ घाव दिए हैं तो हम अब पराजय को पलटकर भारत की महानता के मील के पत्थर को प्रतिष्ठित कर डालेंगे।

'चरैवेति-चरैवेति' यही हमारा आदर्श हो। हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हममें से प्रत्येक इस पवित्र कार्य में अपना पूरा योगदान नहीं कर लेगा। आइए, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन प्रेरक शब्दों को स्मरण करें जिन्हें उन्होंने एकात्म मानववाद के सिद्धांत के प्रतिपादन के अंत में कहे हैं।

"हमें अपने राष्ट्र के विराट् को जाग्रत् करने का काम करना है। अपने प्राचीन के प्रति गौरव का भाव लेकर, वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर और भविष्य की महत्त्वाकांक्षा लेकर हम इस कार्य में जुट जाएँ। हम भारत को न तो किसी पुराने जमाने की प्रतिच्छाया बनाना चाहते हैं और न रूस या अमेरिका की तसवीर।

"विश्व का ज्ञान और आज तक की अपनी संपूर्ण परंपरा के आधार पर हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से अधिक गौरवशाली होगा। जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ संपूर्ण मानव ही नहीं अपितु सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार कर 'नर से नारायण' बनने में समर्थ हो सकेगा। यह हमारी संस्कृति का शाश्वत, दैवी और प्रवाहमान रूप है। चौराहे पर खड़े विश्व-मानव के लिए यही हमारा संदेश है। भगवान् हमें शक्ति दे कि हम इस कार्य में सफल हों, यही प्रार्थना है।"

धन्यवाद।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली 1 अक्तूबर, 2000

प्रिय बंधुओ,

मित्रो, मैं नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में आपका स्वागत करता हूँ।

नागपुर संदेश का प्रभाव

आज भी अभी देश में नागपुर संदेश की चर्चा है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों मीडिया में इसपर विश्लेषण जारी है और विवेचनात्मक टिप्पणियाँ चल रही हैं, जिनमें न जाने अथाह न्यूज प्रिंट और न जाने कितने घंटों का समय खर्च हो गया है।

हमारे राजनीतिक विरोधी—प्रमुख रूप से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियाँ—स्पष्ट है कि निर्मम और अशिष्ट रहे हैं। दरअसल, उनकी टिप्पणियों से उनके अंदर छाया आतंक दिखाई पड़ता है। संभवतः वे दीवार पर लिखी इबारत पढ़ पा रहे हैं कि भाजपा की राष्ट्रीय परिषद् के नागपुर अधिवेशन के कारण वोट बैंक की उनकी हताशाप्रद राजनीति के लिए मौत की घंटी बज गई है।

किंतु भारत के लोगों में नागपुर संदेश से बड़ा उत्साह भर गया है, जो हमारी आशाओं से भी कहीं अधिक है। विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों ने हमारी पार्टी के संदेश के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की है। पिछले एक महीने में जो हजारों पत्र और संदेश मुझे मिले हैं, वह इन वर्गों का हमारी पार्टी के प्रति बढ़ती जा रही सद्भावना का स्पष्ट प्रमाण है।

मैं व्यक्तिशः असंख्य मुसलिमों, दलितों और पिछड़े वर्गों से मिला हूँ। वे मुझसे विशेष रूप से यह कहने के लिए मिलने आए कि वे हमारी पार्टी के नागपुर संदेश का स्वागत करते हैं। पिछले कई सप्ताहों में मैंने अपने दौरों में आयोजित जनसभाओं

में लोगों में जिस तरह का उत्साह देखा है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि उनमें से अनेक वर्गों और हमारे बीच जो झूठे प्रचार की दीवार इतने वर्षों से खड़ी की गई थी, वे उसे तोड़ देने को तैयार हैं।

हमें निरंतर अपने समर्थन का विस्तार करने और इसे सुदृढ़ करने का प्रयास जारी रखना होगा, ताकि भाजपा के उम्मीदवार सतत आधार पर एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के रूप में विकास की ओर बढ़ते रहें। मैं चाहूँगा कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में मैंने नागपुर में अपने अध्यक्षीय भाषण में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ाने के लिए जिस 10-सूत्री कार्य योजना का उल्लेख किया था, पार्टी के कार्यकर्ता इसका जोर-शोर से प्रचार करें।

मैं आपसे यह भी चाहूँगा कि अभी तक हमारी अपील के प्रति जो अल्पसंख्यक वर्ग उदासीन रहे हैं, उनमें अब जो सद्‌भावना हमारे प्रति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, हम उसे सुदृढ़ बनाने के लिए विचार-विमर्श करें और व्यावहारिक उपाय तैयार करें। मुझे पक्का विश्वास है कि आपसी लाभ और इससे भी बढ़कर भारत के लाभ की खातिर हमारे सच्चे और सतत प्रयास हमारी पार्टी और भारतीय मुसलिमों के बीच संबंधों में परिवर्तन लाने में सफल होंगे।

प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा

हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका की हाल की यात्रा के बारे में मैं अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक प्रशंसा अभिव्यक्त करना चाहता हूँ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दि शिखर सम्मेलन में अटलजी ने समान और संघर्ष-मुक्त विश्व की स्थापना का आह्वान किया, जिसमें स्पष्ट और निश्चित रूप से नई शताब्दी में विश्व की यही आकांक्षा अभिव्यक्त होती थी। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, विशेष रूप से राज्य-प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद पर अंतरराष्ट्रीय राय जुटाने के पक्ष में बड़ी समझदारी से वकालत की, जिससे उन अनिष्टकारी शक्तियों को सही चेतावनी मिली है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही हैं।

भारत के सतत राजनयिक प्रयासों का ही फल है कि आज विश्व में यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि आतंकवाद शांतिपूर्ण और सभ्य विश्व व्यवस्था के लिए खतरा है और प्रभावकारी ढंग से इसका मुकाबला विश्व में सामूहिक रूप से ही किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री की वाशिंगटन यात्रा से अमरीकी नेतृत्व भारत के दृष्टिकोण और चिंताओं को कहीं अधिक बेहतर ढंग से समझा है। इससे हमारे देश में अमेरिका द्वारा पर्याप्त निवेश, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि और सामाजिक तथा वैज्ञानिक

अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएँ कहीं अधिक बढ़ गई हैं। भारत के खिलाफ लगे सभी प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से उठाए जाने का मार्ग साफ हो गया है।

रूसी राष्ट्रपति की यात्रा

कल से शुरू हो रही रूसी राष्ट्रपति की यात्रा से भारत और रूस के बीच पारंपरिक मित्रता और भी मजबूत होगी। दोनों देशों के बीच जिस सामरिक सहभागिता समझौते (स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर होंगे, वह हमारे दोनों देशों के लिए दीर्घावधि के लिए महत्त्वपूर्ण है।

कांग्रेस अप-संस्कृति प्रमाणित

झारखंड मुक्ति मोरचा की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव को अविश्वास मत जीतने के लिए अपनी सरकार के पक्ष में वोट देने के वास्ते घूस देने का दोषी पाया है, सम्भव है कि इससे कांग्रेस पार्टी की नैतिकता को जो धक्का लगा है, उसे ठीक करने के लिए वह श्री राव को नकारे या उनसे दूरी रखे; परंतु इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता है कि इस अदालती निर्णय ने केवल एक व्यक्ति मात्र को दोषी करार नहीं दिया है बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को सत्ता से चिपके रहने के लिए हर तरह के भ्रष्ट साधनों का सहारा लेने का दोषी पाया है। देश को इस निर्णय के महत्त्वपूर्ण फलितार्थ को अपनी आँखों से ओझल नहीं करना चाहिए।

आइए, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हों

मित्रो पार्टी को अनेक राज्यों में विधानसभा के निर्णायक चुनावों का सामना करना है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पंजाब में लगभग एक वर्ष के अंदर चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा नवगठित तीन नए राज्यों—उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में विधान सभाओं के चुनाव होंगे।

इन सभी राज्यों के चुनावों में हमें अकेले या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर विजयी होना ही चाहिए। हमारे पास जरा सा भी समय गँवाने के लिए नहीं है। हमें अभी से तुरंत अपनी तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए इन राज्यों में हमें अपना संगठनात्मक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। संबंधित प्रदेश इकाइयों को जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। हमें पिछले लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन की अच्छी तरह समीक्षा करनी चाहिए और अपनी पिछली गलतियों से निःसंकोच सबक लेना चाहिए।

स्थिति हमारे अनुकूल है। लोगों में हमारी पार्टी के प्रति काफी सद्भावना

है, केंद्र में हमारी सरकार ने अटलजी के कुशल नेतृत्व में सफलता का एक नया आयाम स्थापित किया है। हमारी पार्टी के पास विकास का बहुत स्पष्ट तथा व्यापक कार्यक्रम है। हमें अपने कार्यों तथा उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए अपने पार्टी तंत्र को कसकर तैयार करना होगा और इस चुनावी जंग को जीतने के पक्के इरादे के साथ लड़ना होगा। हमारे मन में किसी भी तरह की हिचकिचाहट और अन्यमनस्कता नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी भी स्तर पर हमारी एकता और दृढ़ संकल्प कमजोर पड़े।

उत्तर प्रदेश : आइए, हम पुनः जनादेश प्राप्त करने के लिए कार्य करें

मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में हमें इस प्रकार का अपना सकारात्मक रवैया रखने से भरपूर लाभ होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज्य में इस समय विपक्षी दल पूर्णतया बँटे हुए हैं और बिखरे हुए हैं। इसके विपरीत हमारी पार्टी के समर्थकों की समाज के सभी वर्गों और राज्य में सभी धर्मों में पैठ है।

हाल में मेरी कानपुर यात्रा के दौरान मेरा जिस उत्साह के साथ स्वागत किया गया, उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि राज्य की आम जनता भाजपा के साथ है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री कलराज मिश्र की जन-संपर्क यात्रा ने भी बहुत ही सकारात्मक वातावरण बनाया है, जिससे हमें एक बार फिर यह याद रखना होगा कि निम्नतम स्तर पर कठोर परिश्रम तथा राजनीतिक रूप में जनता को अपने साथ लाने का प्रयास करना होगा और इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

अतः आइए, हम सब मिलकर इस तथाकथित 'शासन विरोधी मनःस्थिति' के तत्त्व को मिटाने के लिए डटकर कार्य करें और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जनादेश को नए सिरे से हासिल करें।

पश्चिम बंगाल की स्थिति

पश्चिम बंगाल में हाल की बाढ़ में जिन लोगों के निकट संबंधी मारे गए हैं तथा जिन्हें अन्य प्रकार से हानि उठानी पड़ी है, उन सबके प्रति मैं पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूँ।

राज्य में बाढ़ ने जो भारी विनाशलीला की है उसने एक बार फिर वाम मोरचे की सरकार के कुशासन को उजागर कर दिया है। यद्यपि बाढ़ प्रकृति के प्रकोप के परिणामस्वरूप आई है, किंतु हर साल राज्य सरकार द्वारा बाढ़-नियंत्रण के उपायों की अपराधपूर्ण उपेक्षा के कारण बहुत अधिक क्षति हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं को राहत तथा पुनर्वास के कार्यों में भरपूर सहायता करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें लोगों को वाम मोरचे की सरकार की गलतियों के बारे में भी जानकारी देनी होगी। उन्हें लोगों को यह भी बताना होगा कि केंद्र सरकार ने विकास संबंधी कार्यों के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई, राज्य सरकार उसका

भी पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकी; क्योंकि राज्य सरकार का अपना खजाना एकदम खाली होने के कारण वह बराबर के संसाधनों को उपलब्ध नहीं करा सकी।

कुछ महीनों में इस राज्य में चुनाव होने वाले हैं। जनता उस दिन का बेताबी से इंतजार कर रही है जब वह अपने आपको कम्युनिस्ट कुशासन से मुक्त करा सकेगी। जनता तृणमूल कांगेस-भाजपा गठबंधन को जनादेश देने के लिए तैयार है। चूँकि कम्युनिस्टों को अपनी अपमानजनक पराजय साफ दिखाई दे रही है, इसलिए वे भयभीत और निराश होकर उचित या अनुचित सभी तरीकों से सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक एवं कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी भयावह है। विपक्षी दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं की सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हत्याएँ की जा रही है। यहाँ तक कि जनसाधारण में वे लोग जो माकपा के स्थानीय अधिकारियों का कहना नहीं मानते हैं, उनपर जानलेवा हमले किए जाते हैं और उन्हें परेशान किया जाता है। मैं अपनी पार्टी की ओर से उन सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ जिनको कम्युनिस्ट गुंडों के हाथों अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि वाम मोरचा अपने कुशासन के बढ़ते हुए विरोध को काबू करने में विफल रहा है। लोगों ने पिछले सभी चुनावों में वाम मोरचे द्वारा अपनाए गए 'वैज्ञानिक ढंग से धाँधली' करने के सभी तौर-तरीकों को देखा है, अतः सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही बीभत्स हिंसा अपने समर्थन के आधार के निरंतर कम होने को रोकने का एक आखिरी प्रयास है।

गत पखवाड़े में इस राज्य में अपनी यात्रा के दौरान मैं ऐसे अनेक लोगों से मिला हूँ जो अपने ही गाँवों में शरणार्थी बन गए हैं। उनकी दशा बड़ी करुणाजनक है। वे यह चाहते हैं कि राज्य में कानून का शासन पुनः स्थापित करने के लिए संघ सरकार उपयुक्त रूप से हस्तक्षेप करे। वे संघ सरकार की सहायता चाहते हैं।

असम में परिवर्तन की हवा

गत पखवाड़े में मैं असम गया था। लोगों में परिवर्तन की भूख स्पष्ट रूप से राज्य में दिखाई दे रही है। अगपा की सरकार से उनका पूर्णतया मोह भंग हो चुका है। अगपा नेतृत्व की अवसरवादिता की पूरी तरह पोल खुल चुकी है। न केवल यह उल्फा तथा अन्य उग्रवादी शक्तियों को काबू में करने में विफल रही है, अपितु लोगों में इस संदेह का पक्का आधार है कि यह उल्फा के कुकृत्यों के प्रति नरम है। राज्य के लोग कांग्रेस की अवसरवादिता और अंदरूनी कलह से

भी अच्छी तरह परिचित हैं।

इस प्रकार असम में हमारे लिए नए दरवाजे खुल गए हैं। लोगों को हमारी पार्टी से बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं। पार्टी की प्रदेश इकाई से मेरा अनुरोध है कि वे अपने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संगठित करके आगामी चुनावी-समर में इस अवसर से लाभ उठाएँ।

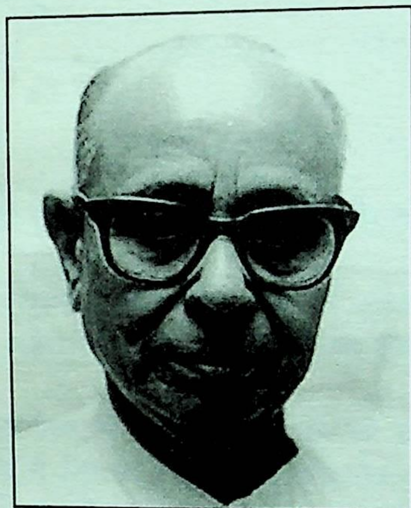
प्रधानमंत्री के प्रति शुभकामनाएँ

मित्रो, हमारे प्रिय श्री अटलजी 10 अक्तूबर को मुंबई में अपने घुटने की शल्य चिकित्सा करा रहे हैं, मैं अपनी ओर से तथा आप सबकी ओर से उनके प्रति अपनी शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह और भी अधिक स्वस्थ होकर वापस आएँगे तथा देश को चहुँमुखी प्रगति पर ले जाने के लिए अपना नेतृत्व जारी रखेंगे।

धन्यवाद,

वंदेमातरम्





अध्यक्षीय भाषण

श्री कुशाभाऊ ठाकरे

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली 15-17 अप्रैल, 2000

प्रिय मित्रो,

मैं भारतीय जनता पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

हम अपनी पार्टी के गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण के अवसर पर हम रहे हैं। इस मास के प्रारंभ में, 6 अप्रैल को हमने भाजपा के स्थापना-दिवस की 20वीं वर्षगाँठ मनाई।

जनता को एक राष्ट्रीय विकल्प देने तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ ने जिसके, राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में हम उभरे, 1977 में 'जनता पार्टी' बनाने के लिए अन्य विरोधी दलों से हाथ मिलाया। दुर्भाग्यवश वह प्रयोग असफल रहा और 1980 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन करने के लिए हम बाहर आ गए।

भाजपा की मुंबई में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय परिषद् में श्री वाजपेयीजी के ये प्रेरणादायक शब्द मुझे इस समय याद आ रहे हैं—

"हम जनता को तब ही संगठित कर सकते हैं जब हम उनके मन पर अपनी विश्वसनीयता अंकित कर सकें। लोगों को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि यह एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति के मंच पर आ जमे स्वार्थी लोगों की भीड़ से कुछ अलग है, इसका उद्देश्य येन-केन प्रकारेण सत्ता हथियाना नहीं है, इसकी राजनीति कुछ जीवन मूल्यों एवं सिद्धांतों पर आधारित है। आज पश्चिमी घाट से घिरे अरब सागर तट पर, मैं भविष्य के विषय में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनजीवन से अंधकार हटेगा, सूरज चमकेगा और कमल खिलेगा।"

प्रारंभिक दिनों में जब हमने बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे, उपर्युक्त शब्दों ने हमें संबल एवं प्रेरणा प्रदान की है। किसी भी स्तर पर हमने हौसला नहीं खोया। उलटे हमने क्रमशः अपना संगठन खड़ा कर लिया और जनता का

विश्वास एवं भरोसा जीत लिया।

आज हम दो करोड़ से भी अधिक सदस्यों वाली देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। संसद् में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। शासक दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हम अग्रणी सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष एवं देश के मूर्धन्यतम नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हैं।

इस सभी का अधिकतर श्रेय जाता है अपने कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम एवं समर्पण भाव को, अपने मित्रों से प्राप्त समर्थन एवं सहायता को एवं उस विश्वास को जो जनता ने हममें दिखाया है।

पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व की ओर से मैं उनके प्रति गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

निःसंदेह, यह एक आनंद मनाने का क्षण है, किंतु यह गए वक्त का लेखा-जोखा लेने एवं भविष्य के लिए तैयारी करने का भी अवसर है। संक्षेप में, यह क्षण आत्म-निरीक्षण का भी है, ताकि हमें आनेवाले समय में किए जाने वाले कामों के लिए समुचित शक्ति मिल सके और हम आगामी कार्यों के लिए सन्नद्ध हो सकें।

इस संदर्भ में मैं एक व्यापक चर्चा की परिकल्पना करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें और इस बात पर भी, कि किस प्रकार हम गत बीस वर्षों, विशेष रूप से गत दो वर्षों की उपलब्धियों का दृढ़ीकरण करते हुए अपने संगठन को और भी शक्तिशाली बनाएँ।

गत तीन आम चुनावों में भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन परिलक्षित हुआ है, जिसमें कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में अपनी प्रमुखता छोड़नी पड़ी और उसकी चुनावी शक्ति का निरंतर क्षरण होता गया। आज जो द्वि-ध्रुवीय राजनीति उभरी है उसमें एक ध्रुव शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी है एवं दूसरा ध्रुव दुर्बल होती जा रही कांग्रेस।

आज जिस राजनीतिक व्यवस्था को उभरता देख रहे है, इसकी तीन धुरी कही जा सकती हैं। अर्थात् संयुक्त सरकारें, सामंजस्य और सहयोग। इससे पूर्व का राजनीकि काल मुठभेड़ का था। वह युग अब समाप्त हो गया है। खेदजनक है कि फिर भी अभी भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने को समझा नहीं पा रहे हैं कि उनकी ब्रांड की राजनीति समाप्त हो चुकी है।

इस नई राजनीतिक धारा ने निश्चित रूप से हमारे कंधों पर महत्तर उत्तरदायित्व डाला है। केवल इसीलिए नहीं कि हम सबसे बड़ा राजनीतिक दल हैं और सत्ता में हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम एक महान् उद्देश्य में विश्वास करते हैं। वह उद्देश्य है राष्ट्र एवं जनता की सेवा करना।

राजग के हमारे सहयोगी दल इस महान् उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें समर्थ

बना रहे हैं। उनके क्षेत्रीय परिदृश्य राजग सरकार के लिए बहुआयामीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण का ताना-बाना प्रदान करते हैं। यह एक ऐसी सरकार है जो सच्चे अर्थों में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और इसी बात में निहित है इसकी शक्ति।

'चेन्नई घोषणा-पत्र', जो गत वर्ष दिसंबर मास में संपन्न राष्ट्रीय परिषद् के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, हमारे आदर्शों एवं जीवन मूल्यों के साँचे में नई शताब्दी के लिए हमारे नए चिंतन का स्पष्ट निरूपण है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सफलता अधिकांशतः इस बात पर निर्भर करेगी कि हम राजनीति की इस नई दिशा में अपने उत्तरदायित्वों को कितना भलीभाँति निभाने में सक्षम हैं। वह सफलता निर्भर होगी इस बात पर कि कितनी सक्रियता से हम 'चेन्नई-घोषणा पत्र' को यथार्थ में परिणत करते हैं।

विधानसभाओं के चुनाव : प्रथम परीक्षा

हमारे चेन्नई अधिवेशन के पश्चात् अति महत्त्वपूर्ण घटनाचक्र रहा उड़ीसा, बिहार, मणिपुर तथा हरियाणा की विधानसभाओं के चुनाव। पहले तीन प्रदेशों में हमें उल्लेखनीय सफलता मिली। उड़ीसा में हमारी शक्ति चार गुना बढ़ी, बिहार में दोगुना और मणिपुर में हमें छह स्थान प्राप्त हुए।

उड़ीसा में हम नई सरकार में साझीदार हैं। दुर्भाग्यवश, अनेक कारणों से, जिनकी चर्चा हम इस बैठक में करेंगे, बिहार में राजग को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लालू-राबड़ी के भ्रष्ट, आपराधिक तथा जातिवादी शासन के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी जारी है। बिहार के जंगलराज से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। हरियाणा में हमारी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय नहीं रहीं, हमें इसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए।

इन चुनावों में कांग्रेस को वास्तव में एक बार फिर बड़ी असफलताएँ झेलनी पड़ीं, परंतु जिस तरह इसने बिहार में सत्ता के कुछ टुकड़ों के लिए राजद से समझौता किया है, उससे जाहिर होता है कि उसने अपनी असफलताओं से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। यह कोई चुनावी रणनीति नहीं, सदाचार और नैतिकता का पूरी तरह सफाया होने का भोंडा प्रदर्शन है।

विधानसभाओं के चुनावों में हमारी सफलता ने अभी हाल में संपन्न द्विवार्षिक राज्य सभा चुनावों पर अच्छा प्रभाव डाला। राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है और उस सीमा तक संसद् में सरकार का काम थोड़ा आसान हो गया है।

यहाँ राज्यसभा के चुनाव जीतने के लिए कुछ ऐसे लोगों द्वारा जिनको धन सुलभ रहा, अपनाए गए घृणित तरीकों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। क्रॉसवोटिंग का प्रभाव चाहे जिस पार्टी पर पड़े यह हमारे प्रजातंत्र पर एक

धब्बा है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए गुप्त मतदान प्रणाली का दुरुपयोग है। यह लोकतंत्र की विकृति है।

हमें गुप्त मतदान की पद्धति के इन घृणित कृत्यों और दुरुपयोग को रोकना होगा। चुनाव आयुक्त को भी यह चाहिए कि वह इस घृणास्पद विषय पर भी ध्यान दें तथा उन्हें सभी राजनीतिक दलों की राय लेकर इस रोग का इलाज खोजना चाहिए।

राष्ट्रपति क्लिंटन की यात्रा : एक नवीन अध्याय का प्रारंभ

विश्व के सबसे बड़े दो लोकतांत्रिक देशों, भारत तथा अमेरिका, के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत-यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में एक नवीन अध्याय का श्रीगणेश हुआ है। इससे अमेरिका में भारत की चिंताओं के महत्त्व को समझने की एक नई इच्छा पैदा हुई है, जो पहले नहीं थी और जिन्हें अभी तक नजरअंदाज किया जाता रहा है।

यह एक संतोष का विषय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ निकटता के एवं गुणात्मक दृष्टि से नवीन संबंधों का वरण किया है। यह स्वाभाविक ही है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शांति एवं लोकतंत्र जैसे साझे जीवन-मूल्यों की प्रोन्नति में भागीदारी करें। 'विजन स्टेटमेंट' इस प्रकार की भागीदारी में निहित संभावित अनंत अंतःशक्ति की अभिपुष्टि है, विशेष रूप से क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने एवं बढ़े हुए सहयोग के क्षेत्रों में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जिनका 'नई अर्थव्यवस्था' से सूत्रपात होता है।

राष्ट्रपति क्लिंटन की यात्रा के परिणाम अपने आप में राजग सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सतत अभिरुचि-पालन तथा विदेशनीति के सफल आचरण के ज्वलंत उदाहरण हैं।

पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति को नियंत्रित रखने की आवश्यकता पर भारत की स्थिति को विश्व के सभी देशों से निरंतर समर्थन मिला है। दूसरी ओर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय जमात से अलग-थलग पड़ता जा रहा है। गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की कार्टीजेना में संपन्न हुई बैठक में जो दस्तावेज स्वीकृत हुआ वह इस बात का एक और प्रमाण है कि आज के विश्व में सैनिक-सरकारों का कोई भी समर्थक नहीं है।

जैसे भी हो, पाकिस्तान के प्रति हमें अपनी निरंतर सजगता बनाए रखनी होगी तथा सीमा पार आतंकवादी दुष्टनीति के प्रति सदैव सचेत रहना ही होगा। कश्मीर में 35 सिक्खों की हत्या यह दिखाती है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी कितने अधिक निराश हो गए हैं तथा अपनी आतंकवादी गतिविधियों में किस प्रकार हत्याएँ कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में खास मजहब के लोगों

का सफाया करने का नया दौर रोकने के लिए वहाँ और भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है।

सरकार ने इस बात पर बल देकर अच्छा किया है कि पाकिस्तान से कोई भी सार्थक वार्त्ता तब तक संभव नहीं है जब तक पाकिस्तान अपनी सीमा पार आतंकवाद की उस नीति का परित्याग नहीं करता जिससे न केवल भारत वरन् संपूर्ण क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। दरअसल, सीमा पार आतंकवाद विश्व के सभी खुले एवं स्वतंत्र समाजों के लिए एक खतरा बना हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ योजनापूर्ण ढंग से संयुक्त राष्ट्र संघ की क्रियाविधि द्वारा निर्धारित काररवाई की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी पहल का मैं स्वागत करता हूँ।

बजट 2000 : अर्थव्यवस्था की स्थिति

सार्वजनिक रियायतों में कटौती के कारण इस वर्ष के केंद्रीय बजट की कुछ आलोचना की गई है। हमें इस बजट तथा इसके प्रावधानों को आज की अर्थव्यवस्था की समग्रता के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

रियायतों के बोझ को एक निर्धारित सीमा के बाद ढोना वास्तव में किसी भी सरकार के लिए असंभव है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी धनराशि मुख्यतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग पर व्यय हो और यह तभी संभव होगा जब सामान्य मदों पर खर्च हो रही विशाल राशि में कटौती की जाएगी।

जनता को यह समझाने की जरूरत है कि आज दी जाने वाली सब्सिडी का खामियाजा कल उन्हें बढ़े हुए खर्चों के बोझ के रूप में भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज जो सब्सिडी दी जाएगी, कल उसका बोझ उनके बच्चों पर ही पड़ेगा। यह एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा।

सरकारी नीति-निर्धारण को प्रभावित करनेवाले कई दूसरे पहलू भी हैं, जिन पर देश का कोई नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि दुनिया में तेल मूल्यों में वृद्धि होती है तो हमारे यहाँ भी तेल मूल्यों में स्वयमेव वृद्धि होगी। सरकार से यह आशा रखना ठीक नहीं होगा कि वह इन कीमतों के बोझ को सहे।

हमारा कार्य द्विस्तरीय है। पहला यह कि हमको जनता को यह समझाना होगा कि कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, ताकि बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सके। यह वैसे ही है जिस प्रकार एक मरीज को अधिक शक्ति वाली दवाएँ दी जाएँ, ताकि वह बीमारी से छुटकारा पा सके और पूरी तरह स्वस्थ हो सके।

दूसरा यह कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामों को पूरे

जोर-शोर से प्रचारित किया जाए। ऐसे बहुत से कदम हैं जिनका यहाँ उल्लेख करना संभव नहीं है; परंतु सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह यह है कि मुद्रास्फीति की दर में अत्यधिक कमी आई है और जिसे गत दो वर्षों से वैसा ही सँभालकर रखा गया है। हमें ग्रामीण विकास से संबंधित सरकारी प्रयत्नों को भी प्रचारित करना चाहिए और यह भी कि अब मानव विकास संबंधी मदों पर पहले से कहीं अधिक खर्च किया जा रहा है।

भावी कार्य

आजकल पार्टी के संगठनात्मक चुनाव चालू हैं, जो मई माह तक संपन्न हो जाएँगे। हमने एक बार पुनः पार्टी के अंदर समय से चुनाव करवाकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। मैं इन चुनावों की तुलना कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने संगठन चुनाव कराने में किए जा रहे संकोच से कर सकता हूँ, जिसके कारण सभी को इतने अधिक स्पष्ट हैं कि यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

अब, जब हम 21वीं शताब्दी में और साथ ही अपनी पार्टी के 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चार कार्यों का उल्लेख करना चाहूँगा—

- अपने राजनीतिक, संगठनात्मक तथा चुनावी आधार को और बढ़ाएँ, ताकि भारतीय जनता पार्टी देश में एक सर्वाधिक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में उभर सके। हमें भाजपा को सही मायनों में आम जनता की पार्टी बनाना है; हर इकाई और कार्यकर्ता को अपनी गुणवत्ता, समर्पण भाव, दूरदृष्टि और सक्रियता को अधिक गहरा और व्यापक बनाना होगा;
- बदल रहे राजनीतिक परिदृश्य को समझिए और इस संदर्भ में राजग के अपने मित्रों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाइए, ताकि विरोधी दलों के दुष्टतापूर्ण इरादों को विफल किया जा सके;
- केंद्र और जिन राज्यों में हम सत्तापक्ष हैं वहाँ सरकार के जनहितकारी उद्यमों और कार्यों के प्रति जनसमर्थन जुटाएँ। आम जनता को समझाएँ कि अपनी सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों की कठिनाइयों भरी पृष्ठभूमि में जनता द्वारा झेली जा रही समस्याओं के निराकरण हेतु क्या-क्या कदम उठाए हैं; और
- अपने देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद के संदेश को समस्त भारत रूपी बड़े परिवार के हर सदस्य तक पहुँचाइए, विशेष रूप से अपने समाज के उन वर्गों तक जिन तक हम अभी नहीं पहुँचे हैं।

अपनी बात समाप्त करने के पूर्व मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि भविष्य की ओर आत्मविश्वास एवं भरोसा रखकर देखिए। अपने कार्यकर्ताओं तथा शुभचिंतकों की शक्ति एवं धारणा में विश्वास रखिए, उस जनता में विश्वास रखिए जिन के समर्थन ने हमें, हमारी पार्टी को इस ऐतिहासिक बिंदु पर पहुँचाया है।

जनता को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने के लिए हमने जिस मार्ग का अपने लिए स्वयं वरण किया है, यदि हम उस पर निरंतर बढ़ते चलें तो निश्चय ही भविष्य हमारा है।

वंदेमातरम् !



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नागपुर

26 अगस्त, 2000

मित्रो,

अपनी कार्यसमिति की यह आज अंतिम बैठक है। अपने संगठन के चुनाव पूर्ण होकर, हमारे नए अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण अपना अध्यक्ष पद कल ग्रहण करेंगे। और स्वाभाविक रूप से नई कार्यसमिति और नए पदाधिकारी भी बनेंगे।

अपनी कार्यसमिति का कार्यकाल एक चुनौती भरा कार्यकाल रहा है। अभी तक कुछ-कुछ प्रांतों में हमारी प्रादेशिक सरकारें बनीं। लेकिन केंद्र में सरकार की बागडोर पहली बार हमारे नेतृत्व में बनी। हमारे वरिष्ठ नेता मान्यवर अटलजी हमारे प्रधानमंत्री बने। केंद्र की सरकार का नेतृत्व करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार देश की आंतरिक, बाह्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी, आर्थिक परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई थीं, सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से हमारा परावलंबन बढ़ता जा रहा था, सारे देश में एक आत्मविश्वासहीनता का भाव घर कर गया था, सारे शासन को भ्रष्टाचार निगलता जा रहा था, और इन्हीं समस्याओं से देश को मुक्ति दिलाने के लिए, जनता ने हमारे ऊपर आस्था प्रकट करते हुए, हमारे हाथ में बागडोर सौंपी। हमारे नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वह अनेक दलों की एक मिली-जुली सरकार बनी है। सरकार चलाने की दृष्टि से सभी साथियों के साथ बैठकर सामूहिक कार्यक्रम बनाना जरूरी था जो देश के सम्मुख उपस्थित इन विकराल समस्याओं से जूझने के लिए समर्थ हो। इसी से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना और उसकी सरकार चलाने की एक कार्ययोजना भी बनी।

पिछली मिली-जुली सरकारें इस दृष्टि से आपसी विवादों में ही उलझी रहीं और देश की राजनीति को स्थायित्व मिलना चाहिए, वह भी न दे पाईं। प्रारंभ में हमको भी अपना कार्यक्रम चलाते समय कुछ दलों की स्वार्थ

भावना के कारण अस्थिरता का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे गठबंधन को बाँधने वाला एक कार्यक्रम होने के कारण और एकाध को छोड़कर बाकी दल भी गठबंधन के कार्यक्रम के साथ निष्ठा से बँधे हुए होने के कारण, हम इस चुनौती का भी सामना करते हुए आज विश्वास से कह सकते हैं, कि भारत की राजनीति को न केवल हमने एक स्थायित्व दिया बल्कि दिशा और कार्यक्रमबद्धता भी दी।

पोखरण दो, कारगिल की जीत, आर्थिक क्षेत्र में प्रतिबंधों के बावजूद हम आगे बढ़े, देश में आत्मविश्वास का भाव बढ़ा, अंतरराष्ट्रीय जगत् में भी हमने एक सम्मान का स्थान पाया। आज भारत को अंतरराष्ट्रीय जगत् में एक सम्मान का स्थान प्राप्त है।

प्रजातंत्र को अक्षुण्ण रखते हुए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दृढ़निश्चय की वजह से आज भारत की बात को लोग सम्मान से देखते हैं।

अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन, जापानी प्रधानमंत्री आदि की भारत यात्रा ये उसी के परिणाम हैं। यह बड़े गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हमने मान्यवर अटलजी के रूप में जो प्रधानमंत्री दिया है, आज अटलजी हमारे ही नहीं, देश के ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय जगत् में भी एक सम्माननीय नेता हैं। और इस बात पर केवल हमको हर्ष ही नहीं गर्व भी है। संगठन की दृष्टि से भी हम आगे बढ़े। हमारी सदस्य संख्या दो करोड़ से ऊपर पहुँच गई। भारत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुँची। लेकिन इसी में संतोष मानकर रहने से काम नहीं चलेगा। चुनौतियाँ बड़ी हैं। हम सबको मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना है। यह उत्तरदायित्व का भाव और उसके लिए उसको पूरा करने की दृष्टि से कमर कसने की आवश्यकता है।

आज यह हमारा अधिवेशन नागपुर में हो रहा है। संघ की हमको हमेशा शिक्षा रही है कि समाज की समस्याएँ सुलझाने के लिए समाज को ही सशक्त करना पड़ेगा। समाज के एक-एक व्यक्ति को कर्तव्य-बोध से अवगत कराना होगा। आत्मनिर्भरता से ही देश और समाज आगे बढेगा, परावलंबन से नहीं। इसी रास्ते पर हम चलते रहे और आगे बढ़ते रहें, आगे का रास्ता भी इसी मार्ग से निकलेगा।

यह हमारा सारा कार्य करते समय हम सब लोग एक टीम के रूप में काम करते रहे। अटलजी, आडवाणीजी का अद्वितीय नेतृत्व हमको उपलब्ध रहा और आज भी है।

नए अध्यक्ष के रूप में, हमने श्री बंगारूजी के हाथ में संगठन की बागडोर दी। मुझे विश्वास है, हमारे नए अध्यक्ष के नेतृत्व में एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ हम आने वाली समस्याओं को हल

करेंगे। अपने कार्यकाल में, आप सब लोगों के सहयोग के लिए, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

इस समय यदि कोई कमी रह गई होगी, मेरी वाणी अथवा कृति से किसी को कष्ट हुआ होगा तो आप उदारतापूर्वक मुझे क्षमा करेंगे, इसी आशा के साथ आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

बंगलौर 2–3 जनवरी, 1999

मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

अभी परसों ही वर्ष 1998 समाप्त हुआ है और इस प्रकार राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं के गहमागहमी वाले वर्ष का पटापेक्ष हो गया है। गत वर्ष में भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार देश में सही अर्थों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक गैर–कांग्रेसी सरकार चुनकर आई। जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय राजनीति में यह एक अभूतपूर्व परिवर्तन था, वहीं साथ ही मई में परमाणु परीक्षणों के होने के बाद भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में सामने आ गया जिसकी वैज्ञानिक उपलब्धि विश्व में किसी विकसित देश से किसी तरह कम नहीं थी।

पहले तो हमारे आलोचकों ने केंद्र में हमारी सरकार बनने की संभावनाओं से इनकार किया। जब उन्होंने देखा कि अब तो सरकार बनकर रहेगी तो फिर उन्होंने कहा कि यह सरकार चल नहीं सकेगी। न केवल हमारी सरकार चल रही है, बल्कि एक साझा सरकार की सीमाओं और बाध्यताओं को देखते हुए सरकार ने अपने कार्यों के माध्यम से अपनी क्षमता भी सिद्ध कर दी है।

हम सभी के लिए 1998 का वर्ष एक अविस्मरणीय वर्ष रहेगा। मुझे निश्चित विश्वास है कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पूर्व का अंतिम वर्ष 1999 राष्ट्र और पार्टी दोनों के लिए और अधिक फलदायी सिद्ध होगा।

विधानसभा चुनाव : एक धक्का, परंतु हम विजयी होंगे

हम पिछली बार अगस्त के अंत में जयपुर में मिले थे। तव से राजनीतिक स्थिति में बड़ा भारी बदलाव आया है। नवंबर में विधानसभा चुनावों में हमें आशा थी कि हम राजस्थान और दिल्ली में अपनी सत्ता बनाए रखेंगे, मध्य प्रदेश में

कांग्रेस से सत्ता छीन लेंगे और यदि अधिक नहीं तो पहली बार कम-से-कम हमारा एक विधायक मिजोरम विधानसभा में होगा।

किंतु विधानसभा चुनावों के परिणाम हमारी आशा के प्रतिकूल निकले। हमें जितने वोट मिले हैं, उसकी सूक्ष्म जाँच करने पर हम देखते हैं कि भाजपा के आधार में कोई बहुत कमी नहीं हुई है, उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में मतों का प्रतिशत अंतर 1.3 रहा। दरअसल कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में तो हम बहुत ही कम, कुछेक सौ वोटों के अंतर से हारे हैं; परंतु अंततः सच्चाई यही है कि विजय हाथ से निकल गई।

चुनाव में हार एक कष्टदायी अनुभव हो सकता है, विशेष रूप से जबकि हमें अपनी सरकारों से हाथ धोना पड़े। परंतु मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि चाहे कोई चुनावी धक्का कितना ही जोरदार क्यों न हो, वह पूर्ण विराम नहीं बन सकता है। अधिक-से-अधिक यह अल्प विराम है, जिससे हमें अपनी पराजय से सबक सीखने और चुनौती को अवसर में बदलने का मौका मिलता है। किसी एक दौर के चुनावों के परिणाम अंतिम निर्णय की परिणति नहीं होते हैं; दरअसल राजनीति में 'अंतिम' शब्द ही नहीं होता है।

आदर्श ध्येय के प्रति समर्पणशील भावना

इस प्रसंग में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 21 अक्तूबर, 1951 को भारतीय जनसंघ की बैठक में दिए गए प्रथम अध्यक्षीय भाषण का स्मरण करना उचित होगा : "निःसंदेह चुनावों का अपना महत्त्व है..... (परंतु) चुनावों के चाहे जो परिणाम हों, हमारी पार्टी को इसके बाद भी अपना कार्य जारी रखना चाहिए, सभी वर्गों के लोगों के पास आशा और सद्भावना का संदेश लेकर पहुँचना चाहिए और प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी लोग पहले से अधिक खुशहाल एवं समृद्ध भारत के पुनर्निर्माण के लिए अधिक-से-अधिक प्रयास करें।"

हमें अपने संगठन में पुनः शक्ति संचार करना होगा, फिर से हमें अपने महान् उद्देश्य की पूर्ति में स्वयं को समर्पित करना होगा और खोए आधार को पुनः प्राप्त करना होगा। इस बैठक में हमें अवसर मिला है कि हम पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों पर चर्चा करें। हम अगले दो दिनों में अपनी हार से सबक सीखने और आगे बढ़ने तथा अगले दौर के चुनावों में विजय का संकल्प लेने के इरादे से चर्चा करेंगे।

कुछ स्पष्ट कारण

यदि मैं इतने खराब प्रदर्शन के प्रमुख कारणों को गिनाऊँ तो उनमें मतदाताओं के सामने खड़ी तात्कालिक समस्याएँ रही हैं, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की कमरतोड़ मूल्यवृद्धि की समस्या रही है और यह माना जाता है कि सरकार ने

मूल्यवृद्धि रोकने में देर की, साथ ही शासन-विरोधी तत्त्व ने उन दो राज्यों में प्रतिकूल प्रभाव डाला, जहाँ हम सत्ता में थे।

व्यक्तिगत हित

इनके साथ-साथ संगठनात्मक कमजोरियाँ और हममें से कुछ लोगों की यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति रही कि उन्होंने पार्टी के हित से अपने हित को ऊपर रखा। वस्तुतः यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारी यह लंबी परंपरा रही है कि पार्टी के हितों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा जाए। हमें इस चुनौती का सामना करना होगा तथा इस बुराई को दूर करना होगा।

अलग पहचान की पार्टी

हम यह न भूलें कि भाजपा एक अलग किस्म की पार्टी है और रहेगी। हम अपनी इस पहचान को नहीं खो सकते हैं। यदि हमें एक और पार्टी बनकर रह जाना है और चुनाव भर जीतना है तो इस प्रकार की विजयों का कोई मतलब नहीं रह जाता है और उन करोड़ों लोगों के लिए तो और भी सांत्वना की बात नहीं होगी, जिन्होंने पिछले अनेक दशकों में हमसे आशाएँ और आकांक्षाएँ बना रखी हैं तथा हमें अपना पूर्ण समर्थन दिया है।

उभरता राजनीतिक परिदृश्य

विधानसभा चुनावों के इस दौर के तीन राजनीतिक प्रभाव पड़े हैं। एक, वह कांग्रेस जो पिछले दो आम चुनावों में निरंतर पराजित होने के कारण बहुत कमजोर हो गई थी, अब पहले से अधिक शक्तिशाली दिखाई पड़ने लगी है। दो, कांग्रेस के पुनर्जीवित होने से मार्क्सवादियों का गैर-भाजपा पार्टियों का एक विशाल छत्र बनाने का सपना टूट गया है। तीन, भाजपा और कांग्रेस भारतीय राजनीति के दो प्रमुख ध्रुव दिखाई पड़ने लगे हैं।

कांग्रेस के नकारात्मक वोट

निःसंदेह राज्यों और आम चुनावों मे खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की विजय ने इस पार्टी को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है। परंतु यहाँ यह बताना उचित होगा कि कांग्रेस वोटिंग पैटर्न के बारे में चाहे जो व्याख्या करे; किंतु निश्चित ही कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक वोट नहीं पड़ा है। जिन तत्त्वों का मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, उसके प्रभाव के कारण उसे नकारात्मक वोट का लाभ मिला है। समग्र रूप से निश्चित ही यह हमारे एजेंडा या नीतियों के खिलाफ जनादेश नहीं है।

कांग्रेस के पुनर्जीवन के साथ ही हमें फिर से उसमें वही लक्षण दिखाई पड़ने

लगे हैं, जिनके कारण उसका पतन हुआ था। एक बार फिर कांग्रेस लोकतंत्र के ऊपर उसी 'खानदान' तंत्र को निःसंकोच बढ़ावा देने तथा 'कांग्रेस को ही शासन करने का स्वाभाविक अधिकार' जैसे नारों के आस-पास मँडराने लगी है। तीन विधानसभा चुनावों में विजयी होने से कांग्रेस के पाप धुल नहीं जाते हैं, न ही पार्टी नेतृत्व पर लगे भ्रष्टाचार के काले धब्बे मिट सकते हैं।

वामपंथियों की संदिग्ध भूमिका

विधानसभा चुनावों से पहले, इन चुनावों के दौरान और बाद में भी मार्क्सवादियों और कम्युनिस्टों के रवैये से भारतीय राजनीति में वामपंथियों की संदिग्ध भूमिका खुलकर सामने आ गई है। उनकी इस संदिग्ध भूमिका का प्रकट हो जाना देश के भविष्य के लिए शुभ संकेत है।

उभर रहे राजनीतिक परिदृश्य का यह आखिरी हिस्सा स्वागत योग्य घटना है। राजनीतिक पार्टियों का छद्म वेश धारण कर नितांत जातिवादी और सांप्रदायिक संगठनों के उभरने से हमारा समाज और राजनीति, दोनों ही खंडित हुए हैं। अब लगता है कि उनकी अपील बेकार जा रही है। यदि अंततः भाजपा और कांग्रेस दो मुख्य ध्रुव बनकर उभरते हैं तो निश्चित ही राजनीति में स्थिरता आएगी और विखंडन की प्रक्रिया रुकेगी।

लोगों की नब्ज महसूस करना

मैंने पहले उल्लेख किया है कि लोगों में यह भावना व्याप्त रही है कि सरकार ने उनकी तात्कालिक समस्याओं को, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि के मामले को सुलझाने में तत्परता और शीघ्रता नहीं दिखाई। तथ्यों के आधार पर यह भाव भले ही ठीक न हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल के चुनावों में मतदाताओं के मन में यह भाव छाया रहा।

एक तरह से यह पार्टी और सरकार दोनों की सामूहिक विफलता थी। हम इसके पीछे के कारणों और अस्थायी प्रकार की मूल्यवृद्धि की बात को प्रभावकारी ढंग से लोगों तक नहीं पहुँचा पाए। सरकार लोगों की नब्ज को ठीक तरह से महसूस नहीं कर सकी।

गांधीनगर में मैंने कहा था कि पार्टी सरकार और लोगों को जोड़ने के लिए एक सेतु का काम करे और लोगों की नब्ज निरंतर महसूस करे। इस प्रकार के सेतु-निर्माण के लिए सरकार और पार्टी के बीच अधिक विचार-विमर्श और समन्वय की आवश्यकता है; निःसंदेह दोनों की अलग-अलग पहचान है और पार्टी को सरकार का हिस्सा नहीं बनना है, परंतु दोनों को एक-दूसरे के लिए पूरक भूमिका का निर्वाह करना है।

एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी बड़ी समस्याएँ सुलझाकर एक अलग पहचान बना लेती है। परंतु इसकी विशिष्ट शक्ति छोटी समस्याओं को सुलझाने में निहित होती है। मुझे आशा है कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करेगी।

सार यह है कि हम सत्ता में हों या न हों, हमें निरंतर यह प्रयास करना होगा कि हमारी पहचान आम जनता के साथ हो। पार्टी इस काम को सरकार को सौंपकर आराम से नहीं बैठ सकती है।

जब मैं पार्टी और सरकार के साथ और अधिक विचार-विमर्श, समन्वय और सहयोग की बात करता हूँ तो मेरा कहना यह है कि सक्रिय समन्वय एक ऐसा व्यावहारिक साधन है, जिसके द्वारा लागों की आकांक्षाओं और अनुभूतियों को शीघ्र और ठीक रूप में सरकार तक पहुँचाया जा सकता है। यह एक ऐसा काम है जिसे नौकरशाही कभी नहीं कर सकती है। यह सरकार के कामकाज और उन बाध्यताओं को भी लोगों तक कारगर ढंग से पहुँचाने का साधन है, जिनमें रहकर सरकार को कार्य करना पड़ता है। मुझे लेशमात्र भी संदेह नहीं है दोनों के मिलने से हमें असीम लाभ हो सकता है—इससे न केवल वोटों के रूप में लाभ होगा अपितु हमारी सद्भावना के आधार का भी विस्तार होगा।

पार्टी और सरकार के बीच प्रभावशाली संचार आवश्यक

निस्संदेह, एक और बात भी है कि सक्रिय समन्वय एवं कारगर परामर्श से सरकार और पार्टी दोनों ही परेशानी और भ्रम की स्थिति से बच सकती हैं। हाल के दो उदाहरण मेरे ध्यान में आते हैं—बीमा नियमन प्राधिकरण विधेयक तथा पेटेंट विधेयक।

इन दोनों मुद्दों पर सरकार के निर्णय के बारे में कुछ भ्रम पैदा हो गया था, जो पार्टी के दृष्टिकोण और शासन के राष्ट्रीय एजेंडा से मेल नहीं खाता था। बाद में जब सरकार ने सांसदों के सामने स्थिति स्पष्ट की तो उन्होंने स्थिति को बेहतर ढंग से समझा और विधेयक के पारण को सुविधानजक बनाया जा सका। इससे पता चलता है कि प्रभावी संप्रेषण होने पर भ्रम और गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है।

गुमराह पंथ निरपेक्षतावादी और उनकी राजनीति

हाल के महीनों में घटी दो घटनाओं पर टिप्पणी करने की आवश्यकता है। पहली घटना शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में खड़े किए गए विवाद से संबंधित है जिसमें कांग्रेस, वामपंथी तथा कुछ अन्य भाजपा दलों ने 'पंथ निरपेक्षता' का ढकोसला खड़ा करके सरस्वती वंदना गायन का विरोध किया।

सरस्वती वंदना

इस तथ्य को देखते हुए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में और अभी हाल में भी 1997 में एक सरकारी समारोह में, जिसमें राष्ट्रपति तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्रकुमार गुजराल ने भी भाग लिया था, सरस्वती वंदना गायन हुआ था, स्पष्ट है कि पिछले वर्ष शिक्षा सम्मेलन में हाय-तौबा मचाने का सही कारण एक मात्र भाजपा-विरोधवाद है।

वंदेमातरम्

दूसरी घटना का संबंध ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वंदेमातरम् गान पर आपत्ति है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वंदेमातरम् एक गान, एक युद्ध घोष था, जिसने लोगों को अपने प्राणों की आहूति देने तक और मातृभूमि के लिए कठोर कारावास में जाने की प्रेरणा दी। आज पचास वर्ष बाद यहाँ ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जो राष्ट्रगान से भी आहत अनुभव करते हैं। कितना पतन हो गया है आज!

ईसाई समुदाय

एक असंबद्ध घटना का उल्लेख करता हूँ, हालाँकि यह पंथ निरपेक्षता के मुद्दे से जुड़ी है, आरोप है कि भारत के ईसाई समुदाय के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता है। कुछ छुटपुट घटनाएँ हुई हैं, जो निंदनीय हैं। इस संबंध में मैं भाजपा-नीत सरकार द्वारा की गई काररवाई का स्वागत करता हूँ।

बहुत समय से हमारे बारे में गलत बातों को फैलाकर अल्पसंख्यक समुदायों और भाजपा के बीच खाई पैदा करने का प्रयास किया जाता रहा है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम इन प्रयासों को विफल कर दें और चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग और भाषा के लोग हों, सभी को संगठित करें।

अंतरराष्ट्रीय घटनाएँ और विदेश नीति में पहल

पिछले दस वर्षों में भाजपा-नीत सरकार ने विदेश नीति से संबंधित मुद्दों और पोखरण द्वितीय के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति का सफल संचालन किया। यह खेद की बात है कि कुछ ताकतें परमाणु परीक्षणों की युक्तिसंगतता को अब भी नहीं समझ रही हैं। सरकार ने परमाणु मुद्दे की सही तसवीर पेश करने के लिए और विश्व में सामूहिक विनाश के हथियारों को एक समयबद्ध अवधि में समाप्त करने के लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही माँग पर जोर देने के लिए अनेक देशों के साथ एक जोरदार राजनयिक अभियान चलाकर बहुत अच्छा काम किया है।

मुझे विश्वास है कि सरकार सी टी बी टी के संबंध में बातचीत करते हुए वैध राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का ध्यान रखेगी। इस संबंध में कोई भी निर्णय पार्टी और संसद् को विश्वास में लेने के बाद ही किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री पहले ही इस बारे में आश्वासन दे चुके हैं।

इराक के खिलाफ हवाई हमले

इराक के खिलाफ ब्रिटेन-अमरीकी काररवाई एकदम अनावश्यक और पूर्णतः अनुचित थी। पार्टी की ओर से मैं इनकी निंदा करता हूँ। न तो अमेरिका को और न ही ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र का दायित्व अपने ऊपर लेने का कोई अधिकार था। यह विशेषाधिकार संयुक्त राष्ट्र का था और रहेगा कि वह कैसे इस मुद्दे के साथ अच्छे-से-अच्छे ढंग से निपटे : जो अपने को 'एक मात्र शक्ति' मानते हैं, उन्हें बहुपक्षीय प्रणाली को छोटे रास्ते में बदलने का अधिकार नहीं मिल सकता है।

रूस और श्रीलंका

रूस का सामरिक गठबंधन का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है और सरकार इसपर सक्रिय रूप से काररवाई करे। मुक्त व्यापार पर भारत-श्रीलंका समझौता एक शानदार उपलब्धि है, जिसका श्रेय इस सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा निजी रूप से की गई पहल को जाता है।

पाकिस्तान

भारत-पाक द्विपक्षीय वार्त्ता भी उपमहाद्वीप में सुख-शांति के लिए शुभ संकेत है। किंतु यदि पाकिस्तान आई. एस. आई. और इसके एजेंटों के माध्यम से भारत-विरोधी गतिविधियाँ जारी रखता है तो यह प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है। सरकार को सीमा पार से इन तोड़-फोड़ की गतिविधियों को पूरी तरह रोक देने की माँग करनी चाहिए।

आगे क्या करना है

हमारे सामने चार काम हैं। प्रथम, पार्टी तात्कालिक मजबूरियों के शिंकजे में जकड़ी नहीं रह सकती—हमें आगे की तरफ देखना है और भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करना है। दूसरे, हमें न केवल खोए आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है, अपितु समाज के वंचित एवं दुर्बल वर्गों पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने समर्थन आधार को बढ़ाना भी है—हमें किसी भी प्रकार की जातिवादी राजनीति में पड़े बिना इन लोगों की चिंताओं एवं आकांक्षाओं को अपनी चिंता और आकांक्षा बनाना है। तीसरे, चाहे

केंद्र में अथवा राज्यों में, जहाँ कहीं भी हमारी सरकारें हैं उनके साथ अधिकतम सहयोग करके लोगों की तात्कालिक समस्याओं का समाधान कर उन्हें अधिक-से-अधिक राहत पहुँचानी है। चौथे, हम सबको मिलकर यह संकल्प करना है कि हाल के चुनावों में हमें जो पराजय का मुँह देखना पड़ा है—उसे हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और सिक्किम के आगामी विधानसभा चुनावों में अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन करके विजय में बदल देंगे, यदि हम व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें तो हम अवश्य सफल हो सकते हैं।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

पणजी (गोवा) 2-4 अप्रैल, 1999

मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम ऐसे समय मिल रहे हैं जो तीन कारणों से महत्त्वपूर्ण है—

- श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुयोग्य नेतृत्व में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने अपने शासन का प्रथम वर्ष अभी-अभी पूरा किया है।
- अगले चार दिनों में पार्टी अपने महत्त्वपूर्ण 19 वर्ष पूरे करनेवाली है। इस अवधि में हम भारत की सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस का एकमात्र विकल्प बनकर उभरे हैं तथा अब पार्टी 20वें वर्ष में प्रवेश करनेवाली है।
- हमारे प्राचीन राष्ट्र ने अभी एक नई शताब्दी-कलियुग की 52वीं शताब्दी में प्रवेश किया है जो विश्व में सबसे आगे है, जबकि विश्व अभी तीसरी सहस्राब्दि में ही प्रवेश कर रहा है।

सफलता का संतोषजनक वर्ष

एक वर्ष पूर्व, जब भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यभार सँभाला था तो हमारे राजनीतिक विरोधियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह सरकार एक वर्ष से पूर्व ही गिर जाएगी। हमने अपने विरोधियों को गलत साबित कर दिया है। यह बड़े गौरव और संतोष की बात है कि हम इस सरकार के शासन की प्रथम जयंती मना रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उथल-पुथल का वर्ष रहा। श्री वाजपेयी को विपक्षी दलों द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं में से गुजरते हुए शासन चलाना पड़ा, क्योंकि विपक्ष शासन को ठप्प करने पर तुला रहा। मई 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के कारण लागू प्रतिबंधों से भी कठिनाइयाँ पैदा हुईं।

इन बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद हम बीते वर्ष पर संतोष अनुभव कर सकते हैं। न केवल सरकार का कार्य-प्रदर्शन शानदार रहा है, उसने विभिन्न

प्रकार के मुद्दों पर अनेक नई पहल भी की हैं। यही नहीं, इसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सँभालकर उसे स्वस्थ बनाया है, जो कांग्रेस और संयुक्त मोरचा सरकारों के कारण बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गई थी। जहाँ एक तरफ पिछले वर्ष एशिया और लैटिन अमरीकी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गई, वहाँ दूसरी तरफ, विपरीत विचार व्यक्त किए जाने के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था की, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई।

प्रयोजनशील बजट

इस वर्ष के बजट में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की यह प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है कि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में अभी तक जिन बातों पर बल दिया जाता था, वह उनमें परिवर्तन करेगी, ताकि यह भी सुनिश्चित हो सके कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि से उच्च स्तरीय मानव विकास और रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों। मुझे विश्वास है कि इस बजट से भारत सामाजिक और आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत होगा।

भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के शासन के प्रथम वर्ष में सफलता के पीछे तीन तत्त्वों का योगदान रहा है :

- प्रथम तत्त्व श्री वाजपेयी का नेतृत्व है : सरकार का भलीभाँति नेतृत्व करते हुए उन्होंने परिकल्पना और कार्य दोनों में ही सिद्धहस्तता दिखाई है।
- दूसरा तत्त्व सत्य निष्ठा है, जिससे इस सरकार के प्रत्येक मंत्री ने शासन के राष्ट्रीय एजेंडा के कार्यान्वयन में से अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया है।
- तीसरा तत्त्व हमारे सहयोगी दलों की प्रतिबद्धता है, जिसके कारण यह सरकार सफल रही और कांग्रेस तथा वामपंथियों के इरादे सफल नहीं हो पाए हैं।

ऐसे अवसर आए हैं जब हमारे सहयोगी दलों में सोच के अंतर के कारण सुचारू रूप से कामकाज करने में कुछ बाधा आई; परंतु पिछले 12 महीनों में हमने अपने सहयोगी दलों के साथ बेहतर समझ-बूझ विकसित की है, जिससे हमारा गठबंधन मजबूत हुआ है। प्रथम वर्ष की रुकावटें पीछे रह गई हैं। मैं सरकार के अंदर और बाहर अपने सभी सहयोगी दलों और मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सुशासन के हमारे स्वप्न को साकार किया।

प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक लाहौर यात्रा

मित्रो, हम दो बड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाओं के तुरंत बाद की पृष्ठभूमि में मिल रहे हैं—एक घटना बाहरी है और दूसरी आंतरिक। दोनों घटनाओं का राष्ट्र पर तथा राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

श्री वाजपेयी ने लाहौर-यात्रा कर साहसिक राजमर्मज्ञता प्रदर्शित की है और भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नया अध्याय शुरू किया है तथा उपमहाद्वीप में एक शांति-युग का मार्ग प्रशस्त किया है। लाहौर के ऐतिहासिक घोषणा-पत्र और इस यात्रा से उत्पन्न सद्भावना के लिए श्री वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियाँ नवाज शरीफ का नेतृत्व श्लाघनीय है। आइए, हम उन्हें बधाई दें।

किंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि कमजोर राष्ट्र इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते हैं। केवल मजबूत राष्ट्र ही शांति ला सकते हैं। मई 1998 पोखरन में परमाणु परीक्षण इस बात का प्रतीक है कि भारत का अभ्युदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ है जो अपने हितों की रक्षा कर सकता है और अपनी सुरक्षा की देखभाल कर सकता है। शक्ति की इस स्थिति से अब हम अपने समय की शांति-यात्रा पर अग्रसर हो सकते हैं। मुझे चर्चिल की वह प्रसिद्ध पंक्ति स्मरण आती है : "युद्ध में दृढ़ संकल्प··· शांति में सद्भावना।"

अब अच्छा होगा कि भारत और पाकिस्तान पिछले पाँच दशकों की कटुता को छोड़ दें और आपसी सद्भावना के आधार पर भविष्य में सहयोग और मित्रता के लिए काम करें।

पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियाँ रोके

इस प्रसंग में मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उपमहाद्वीप में शांति के प्रति अपनी वचनबद्धता दिखाने के लिए आवश्यक है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर अथवा भारत के अन्य किसी राज्य में भी आई. एस. आई. के माध्यम से दी जा रही सहायता तुरंत बंद करे। हाल में भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार ने जो शांति स्थापित की है, वह जम्मू क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में इसलामी अलगाववादियों द्वारा किए गए हिंदुओं के नरसंहार से दूषित हुई है।

मैं सरकार से इस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने का आह्वान करता हूँ। जम्मू में आतंकवादियों ने जिस तरह की चालें चली हैं, वे उसी प्रकार की चालें हैं जैसी उन्होंने कश्मीर में अपनाई थीं। उनका लक्ष्य भी वही है कि हिंदुओं को अपने घरों से भागने के लिए विवश किया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ऐसे उपाय तुरंत करने चाहिए ताकि राजौरी, ऊधमपुर तथा जम्मू के अन्य क्षेत्रों से सामूहिक रूप से घरबार छोड़कर जाने के लिए हिंदू बाध्य न हों और आतंकवादियों की छल योजना सफल न हो पाए।

पंचमढ़ी प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में

पिछले वर्ष पंचमढ़ी में अपनी बैठक में कांग्रेस ने बड़े जोर-शोर से घोषणा की थी कि वह किसी जातिवादी या सांप्रदायिक पार्टी के साथ नहीं मिलेगी। उसने

यह भी संकल्प किया था कि वह विपक्ष में बैठेगी तथा सत्ता में आने के लिए बिना जनादेश के किसी तरह के गलत रास्ते नहीं अपनाएगी।

राबड़ी सरकार को कांग्रेसी समर्थन

अब मैं एक और घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाऊँ, जिसका राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह वह तरीका है जिसके द्वारा कांग्रेस और वापमंथियों ने भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को किसी भी तरीके से अस्थिर करने के अपने प्रयास में सभी राजनीतिक नैतिकता और आचार-नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। परंतु नैतिकता और कांग्रेस तेल और पानी की तरह बिलकुल भिन्न हैं। नैतिकता की राजनीति के प्रति अपनी बचनबद्धता का ढिंढ़ोरा पीटने के बावजूद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व का असली चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस नेतृत्व ने सरकार को परेशान करने की अपनी निर्लज्ज उत्सुकता में पंचमढ़ी की घोषणाओं को कूड़ेदान में फेंक दिया है।

अवैध और अनैतिक लालू-राबड़ी सरकार

सभी जानते हैं कि बिहार की वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई वैध और नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। यह भी सभी लोग जानते हैं कि बिहार में कानून का शासन नहीं चलता है-राज्य के लोग लालू-राबड़ी सरकार द्वारा प्रायोजित अपराधियों के आंतक के साए में रह रहे हैं और राज्य सरकार वहाँ आए दिन हो रही हत्याओं और नरसंहारों का मजा लेते हुए मात्र दर्शक बनी बैठी है, जबकि इन नरसंहारों में भारी संख्या में लोगों के प्राणों की बलि चढ़ रही है।

इस स्थिति में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के सामने ऐसी अक्षम और भ्रष्ट लालू-राबड़ी सरकार को बरखास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, ताकि बिहार के निर्दोष नागरिकों की रक्षा की जा सके। केंद्र सरकार ने किसी अपने हित में नहीं, बल्कि राज्य के असहाय लोगों के हित में इस आशा से काररवाई की थी कि कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में दलगत राजनीति से ऊपर उठेगी और सरकार के निर्णय का समर्थन करेगी।

बिहार में कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति शासन का विरोध

किंतु इस प्रसंग में भी कांग्रेस ऐसे क्षुद्र राजनीतिज्ञों का समूह मात्र निकली, जो अपनी क्षुद्र महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्षुद्र साधन अपनाने को तैयार रहते हैं। लोगों का भारी बहुमत लालू-राबड़ी जोड़ी के जंगलराज से मुक्ति पाने के पक्ष में था; परंतु कांग्रेस ने इस जनमत का तिरस्कार करते हुए लालू प्रसाद

यादव से हाथ मिलाया। बिहार के लोगों, विशेष रूप से दलितों का साथ देने की बजाय कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे हाथ मिलाया जो बिहार में नृशंस रक्तपात के लिए जिम्मेदार थे। ठीक मध्यरात्रि में पूरे गाँव-के-गाँव खत्म होते गए और कांग्रेस-समर्थित लालू-राबड़ी सरकार चुपचाप उसी तरह तमाशा देखती रही जैसे रोम को जलते हुए देख नीरो मजा लेता रहा था।

…बिहार की बर्बर सरकार के साथ वामपंथी भी जुड़े

वामपंथी, जिन्होंने बहुत पहले ही नैतिकता और आचार-नियमों को तिलांजलि दे रखी है, बिहार में जंगलराज के लिए उतने ही दोषी हैं। पटना की भ्रष्ट, जातिवादी और आपराधिक सरकार को गिराने में मददगार होने के बजाय उन्होंने इसके साथ हाथ मिलाया। उनके लोकतंत्र विरोधी और दलित विरोधी चरित्र ने उन्हें नैतिक रूप से भ्रष्ट कांग्रेस और लालू-राबड़ी सरकार के साथ एक जन-विरोधी समान मंच पर ला खड़ा किया है।

यह हास्यास्पद है कि पश्चिम बंगाल के वयोवृद्ध मुख्यमंत्री को, जो हमें 'बर्बर' कहने का कोई मौका नहीं चूकते हैं, इस बात का जरा भी संताप नहीं है कि सी. पी. आई. (एम) ने उस लालू-राबड़ी का साथ दिया जो बिहार में बर्बरता फैलाने में भागीदार है। यह दोगलापन तब और भी निकृष्टतम रूप धारण कर लेता है जब सी. पी. आई. (एम) एक तरफ तो नैतिकता के प्रति वचनबद्धता की बात करती है और दूसरी तरफ उस सरकार से हाथ मिला लेती है जिसमें जरा सी भी नैतिकता नहीं है और जो आज देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है।

कांग्रेस के लिए नैतिकता निरर्थक

कांग्रेस नेतृत्व में न्याय की नाम मात्र भी भावना नहीं रह गई है। स्पष्ट है कि वह नैतिकता, मूल्यों और आचार-नियमों का बुरी तरह तिरस्कार करती है। सत्ता की दुर्दम्य चाह में कांग्रेस नेतृत्व किसी भी स्तर तक नीचे गिरने और कोई भी साधन अपनाने को तैयार है। जो पार्टी लोकतंत्र के मुकाबले खानदानी तंत्र को बढ़ावा देती है, वह लोगों की दुर्दशा से मुँह मोड़ने के अलावा और कर भी क्या सकती है, जैसा कि उसने बिहार में किया है।

कांग्रेस द्वारा बिहार में राष्ट्रपति उद्घोषणा का समर्थन करने से इनकार करने के बाद सरकार के पास इस उद्घोषणा को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। यह अत्यंत खेद की बात है कि बिहार के लोगों को फिर एक बार अपराधियों और हुड़दंगियों की दया पर रहना पड़ रहा है। इसके लिए एकमात्र कांग्रेस और वामपंथी दोषी हैं। हमें इस बात से संतोष है कि हम बिहार के लोगों के साथ खड़े रहे और अब भी हम पटना की जन-विरोधी सरकार के खिलाफ उनके संघर्ष में बराबर साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे।

परंतु हर बुराई से कुछ अच्छाई भी निकलती है—लोकसभा में बिहार संबंधी राष्ट्रपति उद्घोषणा पर मतदान होने पर हमने यह सिद्ध कर दिया कि लोकसभा में हमें बहुमत का समर्थन जारी है। इतना ही नहीं, हमने यह भी दिखा दिया कि जब एक वर्ष पूर्व केंद्र में हमने सत्ता का कार्यभार सँभाला था, उस समय विश्वास मत पाने के अवसर पर सरकार को जितना समर्थन प्राप्त था, आज उसकी तुलना में लोकसभा में हमारा समर्थन बढ़ा है।

कांग्रेस शासन के विपरीत, हमारी सरकार की छवि स्वच्छ है

बजट सत्र के पूर्वार्ध के आखिरी कुछ दिनों में हमने देखा है कि कांग्रेस, वामपंथियों और अन्य पार्टियों ने अत्यंत क्षुद्र आधारों पर संसदीय कार्यवाही रोकी है। निःसंदेह भ्रष्टाचार का उनका आरोप सर्वथा उपहासास्पद है। यह आरोप नागरिक शासनाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर बरखास्त एक नौसेना प्रमुख द्वारा बिना बात आग उगलने के आधार पर लगाया गया है।

परंतु मुझे इससे हैरानी नहीं होती है। जब कभी भी कांग्रेस सत्ता में रही, शर्मनाक भ्रष्टाचार में लिप्त रही। वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती है कि स्वच्छ और पारदर्शी शासन नाम की कोई चीज भी हो सकती है।

हमें इस बात पर गर्व है कि इंदिरा गांधी के समय से लेकर, जिसने यह तर्क देते हुए भ्रष्टाचार को वैध करार दिया था कि कोई भी सरकार भ्रष्ट आचरणों से मुक्त नहीं होती है, हमारी सरकार अब तक की सबसे अधिक बेदाग सरकार है। हमने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत में एक भ्रष्टाचार-मुक्त सरकार संभव है।

सच्चाई यह है कि सत्ता का भूखा, हताश कांग्रेसी नेतृत्व इस गलतफहमी में भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए प्राणपण से जुटा हुआ है कि वह अपने दुःसाहस में सफल हो जाएगा। परंतु उसे यह गलतफहमी ही है, क्योंकि पिछली सरकारों के विपरीत, जिन्हें कांग्रेस ने गिराया था, हमारी सरकार कांग्रेस के समर्थन पर नहीं टिकी है। हम और हमारे सहयोगी दल एकजुट हैं, अपनी ही ताकत और भारत के लोगों के समर्थन पर जीवित हैं।

छद्म-सेक्युलरवादियों से सतर्क रहने की आवश्यकता

मित्रो, हाल की घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि हम छद्म-सेक्युलरवादियों की चालबाजियों से अपने को सतर्क रखने में ढ़ील नहीं दे सकते हैं। हमें बदनाम करने के उद्‌देश्यपूर्ण अभियान के जरिए अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ईसाइयों की हालत के बारे में जिस प्रकार से गुमराह करने वाली तसवीर पेश की जा रही है, उसके पीछे शरारतपूर्ण मंशा है। बाह्य और आंतरिक, दोनों शक्तियाँ इस अभियान को चलाने में लगी हैं।

ईसाइयों पर अत्याचार की तथाकथित घटनाओं के बारे में बहुत हंगामा मचाया गया है। इनमें से अधिकांश मामलों में यह स्थापित हो गया है कि इन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है या ये एकदम झूठी बातें हैं—उदाहरण के लिए इलाहाबाद में एक पादरी पर तथाकथित हमला और केरल में बाइबिल की घटनाएँ सामने हैं। हमारे राजनीतिक विरोधी कुछ ऐसी बाह्य शक्तियों के बहकावे में आकर हमें 'सांप्रदायिक' रूप में पेश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो चाहती हैं कि नई दिल्ली में एक दब्बू सरकार स्थापित हो जाए जो उनके इशारे पर चले। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनके इस प्रकार के व्यवहार से विदेशों में भारत की छवि खराब होती है।

भाजपा-सेक्युलरवाद के प्रति वचनबद्ध

हमारी पार्टी और हमारी सरकार अपने राष्ट्र और अपने समाज के सच्चे सेक्युलर मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। भारत एक बहुधर्मी मान्यता वाला देश है और भारत का संविधान सभी धर्मों के मानने वालों को समान अधिकार और समान सुरक्षा प्रदान करता है। हम इस गारंटी को बनाए रखेंगे।

जब कभी और जहाँ कहीं इसका उल्लंघन हुआ है, हमारी सरकार ने न्यायोचित और कड़ी काररवाई की है। सरकार ने एक मिशनरी और उसके दो पुत्रों को जलाए जाने के बीभत्स अपराध की जाँच के लिए एक न्यायिक जाँच स्थापित की है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि वे अफवाहें फैलाने वालों और शरारती तत्त्वों से बचें।

संगठनात्मक मामले

मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि हम जल्द ही 19 वर्ष पूरे करनेवाले हैं। 6 अप्रैल 1980 से, जब से भाजपा की स्थापना हुई है, हमारी पार्टी अपने आकार और भौगोलिक विस्तार में आगे बढ़ती चली गई है। परिवर्तित परिस्थितियों के साथ कदम-से-कदम मिलाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में हमने महसूस किया है कि हमारे पार्टी संविधान में कतिपय संशोधन करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए एक समिति स्थापित की गई है।

मैं राज्य स्तर पर संगठनात्मक मामलों से जुड़े सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि वे व्यक्तियों के हितों को नहीं बल्कि पार्टी के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर अपने सुझाव इस समिति को भेजें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी संशोधन किए जाएँ, वे व्यापक हों।

मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहूँगा। हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम लोगों के बीच और अधिक वर्गों तक अपनी पहुँच बनाएँ। इस प्रयोजन के

लिए हमारे पास पहले ही छह मोरचे और विभिन्न प्रकोष्ठ हैं। हमारे समाज के जो वर्ग अभी तक हमारे परिवार में शामिल नहीं हैं, उन तक अपनी पहुँच का विस्तार करने के लिए और भी प्रकोष्ठों की स्थापना पर विचार किया जा सकता है।

मितव्ययता और सादगी

हम सदैव स्मरण रखें कि हमारी पार्टी मितव्ययता, सादगी, सेवा और समर्पणशील भावना के लिए प्रसिद्ध है। ये वे गुण हैं, जिनके कारण भाजपा अन्य पार्टियों से भिन्न पार्टी है। हम सदैव ध्यान रखें कि हमारी यह अद्‌भुत पहचान कभी समाप्त न हो।

पिछली बार बंगलौर में हमारी बैठक हुई थी। उसके बाद से पार्टी और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने का एक समुचित तंत्र स्थापित किया जा चुका है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इससे पार्टी ओर सरकार के बीच बेहतर सहमति सुनिश्चित हुई है।

आजीवन सहयोग निधि

हमने पार्टी कार्य के लिए धन इकट्‌ठा करने के लिए एकदम नवीन प्रकार की आजीवन सहयोग निधि योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना की सफलता संतोषजनक है। परंतु इस योजना को जबरदस्त सफल बनाने के लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, ताकि हम पूरे विश्व को दिखा दें कि बड़े उद्योग-धंधों से धन प्राप्त किए बिना भी राजनीतिक गतिविधियाँ चलाने के लिए धन-संग्रह किया जा सकता है।

विधानसभा चुनावों की तैयारी

अगले कुछ महीनों में कई राज्यों के लोग, जिनमें गोवा भी शामिल है, अपनी नई सरकारों का चुनाव करेंगे। हमें इस चुनावी संघर्ष के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी है और पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़नी है। हमारे लिए यह चुनौती है, परंतु यह लोगों का विश्वास प्राप्त करने का अवसर भी है, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें।

पिछले दौर के विधानसभा चुनावों में हमें अपनी कुछ संगठनात्मक कमजोरियों के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हमें इकट्‌ठे मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि इस बार हम इन कमजोरियों से बचेंगे और पार्टी की विजय के लिए अपने संगठन की अपार शक्ति लगा देंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा प्रदर्शन कैसा रहता है, उसकी प्रतिच्छाया केंद्र की भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार पर पड़ेगी।

अतः हमें लोगों के पास सिर उठाकर गर्व से जाना है—हमें अपनी सरकार की अनेक शानदार उपलब्धियों और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता पर गर्व होना चाहिए। आइए, हम आगामी चुनावी संघर्ष की तैयारी में जुट जाएँ। और हम संकल्प कर लें कि आगामी विधानसभा चुनावों में किसी बाधा को आड़े नहीं आने देंगे और हम विजयी होकर रहेंगे।

एक नई शताब्दी, एक महान् भविष्य

मैंने पहले इस बात का उल्लेख किया है कि हमने अभी कलियुग की 52वीं शताब्दी में प्रवेश किया है। अगले नौ महीनों बाद हम सन 2000 में प्रवेश कर जाएँगे। मैं श्री अरविंद के लिखे पत्र को पढ़ता हूँ जिसमें हमारे लिए ऐसे समय में एक अत्यंत उपयुक्त संदेश है, जब हम एक नए युग के द्वार पर खड़े हैं :

"पुरानी परंपराएँ अपने स्थान पर, भूतकाल में बहुत महान् हैं, परंतु मैं नहीं समझता कि हम इन्हें दोहराते ही रहें और आगे न बढ़ें। इस पृथ्वी पर चेतना के आध्यात्मिक विकास के लिए महान् भूत के बाद उससे भी महान् भविष्य का आगमन होना चाहिए···"

मुझे कोई संदेह नहीं है कि भारत और सभी भारतीयों के लिए एक महान् भविष्य सामने है।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली

1-2 मई, 1999

मैं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

गोवा में हमारी बैठक होने के ठीक एक महीने बाद हम मिल रहे हैं। पिछले माह में अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटीं, जिनके कारण यह बैठक बुलाना आवश्यक हो गया।

गठबंधन धर्म का उल्लंघन

जब हम गोवा में बैठक कर रहे थे, तभी हमें भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार से ए आई ए डी एम के के बाहर निकल जाने का कुछ आभास हो गया था। हमने ए आई ए डी एम के को पूरी तरह समझाने का प्रयास किया कि वह नाता न तोड़े और इस ढंग से काम न करे जो 1998 के जनादेश के विरुद्ध हो। किंतु ए आई ए डी एम के किसी दलील या तर्क को मानने को तैयार नहीं थी, उसने साँझा राजनीति के धर्म का उल्लंघन करना ही ठीक समझा। इससे भी बुरी बात यह रही कि वह अपनी सर्वथा अनुचित और न मानी जा सकने वाली माँगों पर अड़ी रही। सरकार ने दृढ़ता दिखाकर बिलकुल ठीक किया और वह अपने स्थान से एक इंच भी नहीं हटी।

विपक्ष का नकारात्मक आचरण

बाद की घटनाओं के बारे में सभी को मालूम है। किंतु कुछ बातों का स्मरण करना अच्छा होगा, जिनसे विपक्ष के नकारात्मक और विध्वंसात्मक आचरण का पता चलता है। जब विपक्ष से पूछा गया था कि वे किस प्रकार की वैकल्पिक सरकार देना चाहते हैं और अनुरोध किया था कि इस बारे में वे राष्ट्र को विश्वास में ले तो विपक्ष ने बड़ी लापरवाही से ऐसे सभी आग्रहों का मखौल उड़ाया था; इसी से उसके वास्तविक इरादे का पता चल गया था कि वह किसी-न-किसी तरह

सरकार को गिराना चाहता है, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पास विकल्प के रूप में देने को कुछ नहीं है। उन्होंने दावा किया था कि वे पाँच मिनट में सरकार बना लेंगे : वे एक सप्ताह से भी अधिक समय में नाम मात्र का भी विकल्प तैयार नहीं कर सके।

कांग्रेस और वामपंथियों की चालें विफल

विडंबना यह है कि जहाँ अस्थिर करनेवाले लोग अपने विध्वंसात्मक एजेण्डे और गैर-लोकतांत्रिक चालबाजियों से सरकार को गिराने के अपने इरादे को लेकर एकजुट थे, वहाँ दूसरी तरफ जब उन्हें वैकल्पिक सरकार बनाने का मौका मिला तो वे पूरी तरह से विभाजित थे। पहले कांग्रेस ने दावा किया कि वह 48 घंटे में बहुमत का समर्थन प्राप्त कर लेगी। परंतु जब उसने देखा कि न केवल भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सांसदों को तोड़ना असंभव है, बल्कि उसने विपक्ष के जिन सदस्यों से कांग्रेस सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहा था, वे भी समर्थन देने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो उसका दावा धरा का धरा रह गया। अंत में सरकार को अस्थिर करने और जनादेश को तहस-नहस करने का पूरा प्रयास ही कांग्रेस के प्रमुख अस्थिरकर्ता पर उलटा गले पड़ गया—और प्रमुख रूप से उकसाने वाले वामपंथियों का भी भंडाफोड़ हो गया। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी, राजद और 1998 के जनादेश की भावना का उल्लंघन करनेवाले अन्य लोगों की भी कलई खुल गई, जिन्होंने देश के सिर पर एक महँगा मध्यावधि चुनाव डाल दिया।

कांग्रेस : मुख्य दोषी

12वीं लोकसभा के भंग किए जाने और देश पर एक महँगा मध्यावधि चुनाव जबरदस्ती लादने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस और उन लोगों पर आती है, जिन्होंने भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार को बिना किसी विकल्प को ध्यान में रखे गिराने में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया।

इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में दो बातें दोहराना आवश्यक लगता है। एक तो यह है कि कांग्रेस ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया है कि वह एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के बिना जिंदा नहीं रह सकती है। जब भी लोगों ने उसे सत्ता से बाहर किया है, तो उसने फिर पलटकर वही अपना जाना-माना वार किया है कि तत्कालीन सरकार को गिराया जाए, अपने को किसी तरह सत्ता में लाने की जुगत भिड़ाई जाए, और सफल न होने पर मध्यावधि चुनाव थोपा जाए।

जनादेश प्राप्त किए बिना सत्ता हथियाने का प्रयास

विश्वास मत पर बहस से ही पता चलता था कि कांग्रेस और विपक्ष की अन्य पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं था। कुछ था तो बस इतना ही कि किसी भी युक्ति

से सत्ता में आने की उनकी अदम्य इच्छा थी। उनके लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती थी कि इस प्रकार के शर्मनाक कार्य करने के लिए उनके पास जनादेश नहीं है।। कांग्रेस या सरकार को अस्थिर करने वाली अन्य पार्टियों पर ऐसी किसी भी बात का असर दिखाई नहीं पड़ा कि उनके ऐसे कृत्य से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहल के उपाय रुक जाएँगे, या फिर एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि विकृत होगी। उनका एक मात्र उद्देश्य मिटाना रहा, निर्माण करना नहीं।

दूसरे, वामपंथी निरंतर अपनी निरर्थक विचारधारा के आधार पर नैतिकता की बढ़-चढ़कर बात करते रहे हैं, उनकी भी पोल खुल गई है कि उनकी पार्टी भी ऐसे व्यक्तियों का गिरोह है जो घटिया किस्म का षड्यंत्र, दुरभिसंधि और जोड़-तोड़ करते रहते हैं। भले ही वामपंथी भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, राजनीति के अपराधीकरण और जातिवादी राजनीति की जोर-शोर से भर्त्सना करते रहे हों, असल में वामपंथियों ने निःसंकोच उन्हीं ताकतों के साथ हाथ मिलाया, जिन्होंने 1998 के जनादेश को ध्वस्त किया।

जनता के साथ विश्वासघात

किंतु कांग्रेस, वामपंथियों तथा अन्य सभी के पूरे प्रयास करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वे झगड़ने लगे, उनमें आपस में कटुतापूर्ण तू-तू मैं-मैं हुई, हरेक दूसरे को विश्वासघात का दोषी ठहरा रहा था। सच बात यह है कि इन सभी ने सामूहिक रूप से मिलकर लोगों के साथ विश्वासघात किया है, जिसके लिए उन्हें जून या सितंबर में होने वाले चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग उन्हें राष्ट्र को नीचा दिखाने के लिए माफ नहीं करेंगे।

सहयोगी दल संगठित : विपक्ष विभाजित

इस तरह हमारे सामने एक ऐसा दृश्य है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे विरोधी बिखरे पड़े हैं और उनमें कुछ भी समानता नहीं है। दूसरी तरफ हम और हमारे सहयोगी दल संगठित खड़े हैं और इकट्ठे ही आगामी चुनाव का सामना करेंगे। भारत को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के प्रति हमारी समान वचनबद्धता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारा समान कार्यक्रम-शासन का राष्ट्रीय एजेंडा है। भाजपा और इसके सहयोगी दल इस एजेंडा पर सहमत हैं तथा अपने नए सहयोगी दलों एवं मित्रों के साथ मिलकर हम इसे अद्यतन बनाएँगे, ताकि नई चुनौतियों का सामना कर सकें तथा नए अवसरों को प्राप्त कर सकें। चुनाव प्रचार के दौरान यह हमारा समान, साँझा मंच होगा।

मित्रो, हम यह चुनाव अत्यंत स्पृहणीय शक्ति की स्थिति में रहकर लड़ रहे हैं :

- सरकार ने अपने 14 महीने के अल्पकाल में बहुत शानदार तथा राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया है;
- हमारे नए मित्र और सहयोगी बने हैं जो हमारी पार्टी के लिए इस रूप में सराहनीय है कि हमारी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है;
- ऐसा कोई नेता नहीं है जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कद और योग्यता के मामले में उनके आस-पास भी पहुँच सके।

पूर्ण जनादेश प्राप्त करने का संकल्प करें

12वीं लोकसभा के खंडित स्वरूप के बावजूद सरकार बहुत सी उपलब्धियाँ प्राप्त करने में सफल रही। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को निर्णायक जनादेश मिलने पर आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी और कितनी अधिक उपलब्धियाँ हो सकती हैं। आइए, हम इस बैठक के बाद अपने-अपने राज्यों में इस दृढ़ संकल्प के साथ लौटें कि हम यह जनादेश प्राप्त करके ही रहेंगे और वाजपेयी सरकार को फिर से भारी बहुमत से सत्ता में लाकर रहेंगे।

पार्टी के अंदर और हमारे सहयोगी दलों के साथ हमारी एकता के कारण ही हमें विपक्ष की विध्वंसात्मक राजनीति का सामना करने की शक्ति मिल सकी। यह एकता हमें आगामी चुनावों को जीतने और शानदार ढंग से जीतने की शक्ति देगी। इसलिए हमें इस एकता के बंधनों को मजबूत करने में जुट जाना है, यही हमारी सफलता की कुंजी रही है और आगे भी रहेगी।

हम सभी जानते हैं कि पिछले महीने देश और विदेश की अस्थिर करने वाली शक्तियों की भूमिका के कारण बहुत से लोग अत्यंत क्षुब्ध रहे हैं। हमारे राष्ट्र, हमारे लोकतंत्र के हित में है कि इन ताकतों को बुरी तरह से हराया जाए। अतः मैं उन सभी से जो भारत को प्यार करते हैं, आग्रह करता हूँ कि वे इन ताकतों को हराने में हमारे साथ आ मिलें। आगामी चुनाव में लड़ाई अस्थिरता पैदा करनेवालों के विरुद्ध होगी और हमें यह लड़ाई जीतनी होगी।

अतः आइए, हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ने के लिए कदम उठाएँ और एक निश्चित विजय, एक निर्णायक जनादेश प्राप्त करने में जुट जाएँ। हमने पहले ही मध्यावधि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। श्री लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय चुनाव प्रचार तथा प्रबंधन समिति के प्रमुख होंगे और मुझे कोई संदेह नहीं है कि जिस आज की स्थिति को चुनाव सर्वेक्षक 'भाजपा के पक्ष में लाभद्व की कह रहे हैं, हम उसे 'भाजपा की शानदार विजय' में बदल सकते हैं।

वर्तमान चुनौती को अवसर में बदलें

मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और हितैषियों से कंधे-से-कंधा मिलाकर काम करने का आह्वान करता हूँ, ताकि हम वर्तमान चुनौती को अवसर में बदल दें। इससे भी बढ़कर मैं भारत के लोगों से अपील करता हूँ कि जिन्हें लोकतंत्र प्रिय है और भारतीय होने पर गर्व है, वे अब हमारे साथ खड़े हो जाएँ। हम सभी साथ मिलकर सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत श्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ अगली शताब्दी में प्रवेश करेगा।

वंदेमातरम् !



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली

3-4 नवंबर, 1999

मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में आपका स्वागत करता हूँ।

हम इस समय एक गौरवपूर्ण क्षण में मिल रहे हैं, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास और हमारी महान् पार्टी के इतिहास में सदैव स्मरण रहेगा।

मुझे श्री लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण के समापन पर उनके वह शब्द याद आते है, जो उन्होंने 1995 में मुंबई में राष्ट्रीय परिषद् की बैठक को संबोधित करते हुए कहे थे—"निश्चित ही भारत उन शक्तिशाली राष्ट्रवादी शक्तियों के नेतृत्व में अगली शताब्दी में प्रवेश करेगा जो एक सौ करोड़ लोगों के इस महान् राष्ट्र में हर स्तर पर उभर रही हैं।"

भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक ऐसी पार्टी के निर्माण का वह सपना भी साकार हो गया है, जो एक स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के आदर्श पर चलेगी और भारत को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले लाने का सत्कार्य अपने हाथ में लेगी। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास और बलिदान आखिर रंग लाया।

एक सकारात्मक जनादेश

भाजपा ने निरंतर तीसरी बार भारत में शासन करने का जनादेश लोगों से प्राप्त किया है :

- 1996 का, खंडित जनादेश होते हुए भी, वह जनादेश भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में था। उस समय कांग्रेस-समर्थित संयुक्त मोरचा ने जनादेश चुरा लिया था। हमें 13 दिनों के बाद सत्ता से हटना पड़ा था।

- 1998 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को स्पष्ट जनादेश मिला, हालाँकि उसका अपना बहुमत कुछ थोड़ा सा कम रहा। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने हमारे एक सहयोगी दल को प्रलोभन देकर खींच लिया और हमारी सरकार 13 महीने बाद गिर गई।
- 1999 में अब भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भारी बहुमत से जनादेश प्राप्त हुआ है। फिर से श्री अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के शासन-प्रमुख बने हैं। पं. जवाहर लाल नेहरू के बाद उन्हीं को निरंतर तीन बार प्रधानमंत्री बनने का श्रेय प्राप्त हुआ है।

हमने यह चुनाव तीन मुद्दों के आधार पर लड़ा—हमारा प्रधानमंत्री का प्रत्याशी, हमारी सरकार का अच्छा काम-काज और हमारा कार्यक्रम। हमने सकारात्मक वोट की माँग की। हमने भाजपा और राजग में सहयोगी दलों के पक्ष में सकारात्मक वोट माँगे थे। हम दोनों मोरचों पर सफल रहे।

1999 का जनादेश हमारे इन तीनों मुद्दों पर सकारात्मक जनादेश है। 1984 के बाद पहली बार भारत के लोगों ने पदासीन प्रधानमंत्री और उसकी सरकार के पक्ष में वोट दिया।

नकारात्मक राजनीति की अस्वीकृति

'99 के जनादेश ने नकारात्मकता और अस्थिरता की राजनीति को भी नकारा है, जिसे हमारे विरोधी अब तक इस आशा में चलाते रहे हैं कि वह लोकतांत्रिक मार्ग को लाँघकर छोटे रास्ते से सत्ता में बैठ जाएँगे। इस प्रकार, इस वर्ष का जनादेश हमारे अच्छे काम-काज का पुरस्कार है और उन लोगों को दंड मिला है जिन्होंने इस काम-काज को तबाह करने की जी-तोड़ कोशिश की।

पार्टी की ओर से मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अपना जनादेश दिया।

मैं लोगों को लोकतंत्र में अपना विश्वास पुनः प्रगट करने के लिए भी बधाई देता हूँ। जहाँ उनका वोट हमें शासन करने के लिए जनादेश है, वहाँ उनका वोट उतना ही लोकतंत्र के पक्ष में जनादेश भी है। जबकि कुछ देशों में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, ऐसे समय में लोकतंत्र के प्रति अपनी वचनबद्धता दिखाकर आज भारत के लोग विश्व में भाजपा की शक्ति बढ़ी, कांग्रेस अप्रासंगिक बनी।

भाजपा की निरंतर बढ़ती शक्ति

मित्रो, 1996 और 1999 के बीच हमारी ताकत निरंतर बढ़ती चली गई है। अंडमान से कश्मीर तक, गुजरात से असम तक, हर तरफ हमारे प्रत्याशी चुने गए हैं। इसके विपरीत, संसद् में कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को मात्र 112 सीटें मिलीं, इतनी कम सीटें उसे इससे पहले कभी नहीं मिली थीं।

अब ऐसा विश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि कांग्रेस आगे भी इस गिरावट को रोक पाएगी।

कांग्रेस और वामपंथियों की प्रासंगिकता समाप्त

अतः कांग्रेस की, और वामपंथियों की भी, प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। वामपंथियों की 'ऐतिहासिक भूल' यह नहीं थी कि उन्होंने 1996 में ज्योति बसु को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उनकी ऐतिहासिक भूल तो यह थी कि वे कांग्रेस के पालकी-वाहक बने। इस हालत में अब वे इतिहास में मात्र एक पाद-टिप्पणी बनकर रह गए हैं।

द्विध्रुवीय राजनीति का मार्ग प्रशस्त

इस चुनाव में द्विध्रुवीय राजव्यवस्था उभरकर आई है। प्रमुख ध्रुव भाजपा है; दूसरा ध्रुव कांग्रेस है।

इस चुनाव में यह भी स्पष्ट हो गया है कि इन पिछले दशकों में हमारे विरोधी अपने लाभ के लिए जिस अस्पृश्यता की राजनीति का इस्तेमाल करते आ रहे थे, वह धराशायी हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण और चुनावों में उसकी विजय इस बात का प्रमाण है कि हम विरोधियों के शत्रुवत् प्रचार के सामने भी सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे। इसके लिए हमारे लाखों कार्यकर्ता और समर्थक प्रशंसा के पात्र हैं, जो मजबूती से जमे रहे और उनका यह विश्वास दृढ़ रहा कि एक दिन अवश्य हमारी विजय होगी।

आत्म-विवेचन का क्षण

हमने एक लंबा रास्ता तय किया है। 1980 में मात्र दो सीटों की स्थिति में रह जाने के बाद अब हम संसद् में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर आए हैं। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। दरअसल यह हमारे लिए हर्षोल्लास का क्षण है, यह गौरव महसूस करने का क्षण है; परंतु यह आत्म-विवेचन का क्षण भी है।

हमें विजय आसानी से नहीं मिली है-इसके पीछे अपार बलिदान और हमारे न जाने कितने अज्ञात लोगों का निरंतर निःस्वार्थ परिश्रम है, जिससे हम आज इस विजय तक पहुँचे हैं। हम उनका समर्पण सदैव स्मरण रखें, ताकि हम सदैव उनसे प्रेरणा लेते रहें और सही मार्ग पर चलते रहें।

नई स्थिति को मजबूत करें

हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि '99 का जनादेश लोगों और हमारे बीच विश्वास का प्रतिज्ञा-पत्र है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे इस विश्वास

को कोई क्षति पहुँचे। इसके विपरीत हमें इस विश्वास में वृद्धि करनी चाहिए तथा अपने लाभ को और अधिक मजबूत करना चाहिए।

आज की स्थिति में हमें अत्यधिक समझदारी से काम लेना होगा। इस समय हम पर अपने कार्यों और शब्दों, दोनों में संयमित रहने की कठिन जिम्मेदारी है। इस समय हमारे सामने अवसर है कि हम लोगों के विश्वास पर खरे उतरकर दिखाएँ। आइए, हम इस अवसर का अच्छे-से-अच्छा उपयोग करें।

पार्टी और सरकार की पूरक भूमिका

इसके लिए हमें निरंतर यह ध्यान रखना होगा कि हम एक जिम्मेदार सत्ताधारी पार्टी हैं, जो समाज के हर वर्ग के हितों के प्रति जागरूक है, जो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, या भाषा के प्रति भेदभाव नहीं करती है। इस कार्य में पार्टी और सरकार, दोनों को एक-दूसरे के लिए पूरक की भूमिका का निर्वाह करना है।

सरकार का काम किसी तरह आसान नहीं है।

- कांग्रेस द्वारा दशकों से सत्ता का गलत ढंग से प्रयोग किए जाने के कारण हमारे वे संस्थान बुरी तरह कमजोर बना दिए गए हैं जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं।
- दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों और लोक लुभावन अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाई है।
- समाज के कल्याण के नाम पर अपार धनराशि लुटाई गई और फिर भी हमारी एक तिहाई जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे रहती है।
- वर्षों से राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं की उपेक्षा की गई और विघटनकारी तथा अलगाववादी शक्तियों के प्रति नरमी दिखाई गई।
- अपराधियों को बचकर भाग जाने दिया गया और मुकदमे न्यायालयों में लटके रहने दिए गए।

45 वर्षों से कांग्रेस के कुशासन में चले आ रहे ये केवल कुछ नमूने हैं।

कुछ कठोर निर्णय आवश्यक

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योग्य नेतृत्व में पिछली सरकार ने इन गलतियों को सुधारने के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। अभी बहुत कुछ करना शेष है। श्री वाजपेयी के निरंतर नेतृत्व में सरकार ने तुरंत ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया है; आइए, हम उन्हें अपने संगठन का पूर्ण समर्थन दें।

•मित्रो, निःसंदेह इस सरकार से आम लोगों को अत्यधिक आशाएँ हैं; परंतु आज जो वास्तविक स्थिति है, उसमें सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। लोग इन अल्पकालीन निर्णयों की मजबूरी को भलीभाँति समझते हैं और जानते हैं कि दीर्घावधि में निश्चित ही ये निर्णय लाभप्रद सिद्ध होंगे।

जनता निर्णयों की विवशता समझे

परंतु इससे हमारा कार्य कम नहीं हो जाता है। हमें लोगों को इन निर्णयों को लेने की आवश्यकता के बारे में समझाने के लिए अपने संगठन की पूरी कुशलता और संसाधनों को लगा देना होगा, ताकि वे समझ लें कि यदि दरवाजे पर दस्तक दे रही नई शताब्दी की चुनौतियों का सामना करना है तो राष्ट्र को स्वयं को तैयार करना ही होगा। हमें लोगों को यह अच्छी तरह समझाना होगा कि मात्र नारेबाजी से अच्छा शासन नहीं चल सकता है। हमें अपने विरोधियों द्वारा निरंतर चलाए जा रहे शत्रुतापूर्ण अभियान के खिलाफ लड़ना होगा।

और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम एकजुट रहें और अपने मार्ग में क्षुद्र विचारों को न आने दें। हमारी एकता और हमारा अनुशासन हमारी धरोहर है। हमें इसका पूरा उपयोग करना होगा और जो सद्‌भावना एवं विश्वास हममें व्यक्त किया गया है, उसे बनाए रखना होगा।

पिछले अनुभवों से सबक

पार्टी और सरकार, दोनों संयुक्त प्रयास कर लोगों को अच्छा प्रशासन प्रदान कर सकते हैं। यदि हम इस प्रयास में विफल हो गए तो हमें स्वयं को ही दोषी ठहराना पड़ेगा। इस प्रसंग में हमें उन राज्यों के अपने अनुभवों से सबक सीखना होगा जहाँ इस चुनाव में हमारा प्रदर्शन आशा के अनुकूल नहीं रहा है।

पार्टी का आधार विस्तार करने की आवश्यकता

संगठन के सामने एक और कार्य है। हमें अपने आधार का और विस्तार करना है और अन्य अनेक वर्गों के पास पहुँचना है। यह हमारा अथक प्रयास रहना चाहिए। हमारे लिए यह चुनौती है और हमें इस चुनौती का मुकाबला करना है तथा सफल होकर बाहर आना है। हमें देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपने संगठन को मजबूत करना है और इस प्रकार समाज के सभी वर्गों के लोगों को निरंतर अधिकाधिक अपने पक्ष में करना है। हमारे एजेंडा में यह कार्य सर्वोपरि होना चाहिए।

तटवर्ती उड़ीसा के लिए धन संग्रह

पिछले महीने तटवर्ती उड़ीसा में दो बार जल्दी-जल्दी चक्रवाती तूफान आए, जिनके कारण भारी तबाही हुई है। तुरंत बचाव और राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार 550 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर चुकी है। परंतु चक्रवात-पीड़ित लोगों के पुनर्वास में बहुत प्रयास करने की जरूरत होगी और इसमें पूरे राष्ट्र की भागीदारी आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से अपील करना चाहता हूँ। हमारा विचार है कि इस कार्य के लिए

धन इकट्ठा किया जाए और मुझे पक्का भरोसा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता और शुभचिंतक इस कार्य में सहायता करेंगे और हम पर्याप्त धन इकट्ठा कर पाएँगे।

मित्रो, हमारे हाथों में एक शक्तिशाली शस्त्र है—भारत सरकार।

किंतु सत्ता हमारे लिए कभी साध्य नहीं रही है, यह तो साध्य तक पहुँचने का साधन मात्र रहा है। हमें सदैव स्मरण रखना होगा कि हमारे लिए सत्ता भारत के राष्ट्रीय हितों को साधने और लोगों का कल्याण करने का साधन मात्र है। यदि हम ऐसा कर सके तो कोई भी ताकत भाजपा को इतिहास में ऐसी शक्ति के रूप में अपना उचित स्थान स्थापित करने से नहीं रोक सकती है, जो एक नवजाग्रत् भारत का निर्माण करके दिखाएगी।

इसलिए आइए, हम इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पुनः अनुप्राणित होकर अपने घर जाएँ।

आइए, हम अपनी पार्टी के प्रिय आदर्शों और राष्ट्र निर्माण के पुनीत कार्य में स्वयं को पुनः समर्पित कर दें।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय परिषद्

चेन्नई 27–29 दिसंबर, 1999

मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

हम चेन्नई के इस सुंदर शहर में अपनी पार्टी के इतिहास में एक गौरवमय क्षण में मिल रहे हैं। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं तमिलनाडु के लागों को, विशेष रूप से चेन्नई के लोगों को, उनके द्वारा दिए गए स्नेह और आतिथ्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक लगभग डेढ़ वर्ष के बाद हो रही है। पिछली बार हम मई 1998 में गांधीनगर में, मध्यावधि चुनाव तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार बनने के तुरंत बाद मिले थे।

संयोग है कि इस बार भी एक और मध्यावधि आम चुनाव तथा फिर से श्री वाजपेयी के नेतृत्व में बनी नई सरकार के बनने के बाद मिल रहे हैं।

फिर भी एक महत्त्वपूर्ण अंतर है। 1998 में चुनाव के बाद हम अपने बहुमत के बिना साँझा सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण चुनाव से पहले हो गया था और हमारा पर्याप्त बहुमत है।

मैं कुछ क्षणों में इस विस्तार के महत्त्व पर बात करूँगा।

1998 और 1999 के बीच

मित्रो, 1998 में सरकार बनने और 1999 में सरकार गिरने के बीच जो कुछ हुआ, उससे आप सभी परिचित हैं, जिसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

हमारा एक सहयोगी दल, ए आई ए डी एम निरंतर ऐसी माँगें करता रहा, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता था, अंततः उससे अलग होना पड़ा, फिर यह पार्टी और कांग्रेस आपस में मिल गई और इसके फलस्वरूप सदन में हमें पराजय का मुँह देखना पड़ा—यह सभी बातें अब इतिहास का भाग बन चुकी हैं।

हमने अपने अनुभव से कुछ सीखा है। इस बार हमने चुनाव-पूर्व गठबंधन किया और एक साँझा घोषणा-पत्र स्वीकार किया; चूँकि राजग के सभी सदस्य दल इस घोषणा-पत्र के प्रति वचनबद्ध हैं, इसलिए इसके कार्यान्वयन के बारे में कोई मतभेद होने की गुंजाइश नहीं है।

1998 और 1999 के बीच यह पहला अंतर है।

दूसरा अंतर यह है कि 1998 के विपरीत इस बार हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। लोगों ने निर्णायक रूप से मत दिया है और राजग को पूरे पाँच वर्ष तक शासन करने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है।

राजग को पूर्ण जनादेश

यह जनादेश तीन कारणों से मिला है :

एक, लोग हमारे विरोधियों की अस्थिरीकरण की राजनीति से तंग आ गए थे, अतः मतदाताओं ने अस्थिरता पैदा करनेवालों को उनकी राजनीतिक स्वार्थपरता की सजा देने का निर्णय किया।

दो, लोगों ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि भाजपा और इसके सहयोगी दलों पर उनके द्वारा किए गए वायदे निभाने पर विश्वास किया जा सकता है, अतः मतदाताओं ने हमारे 13 महीने के शासनकाल के प्रदर्शन को देखकर पुरस्कृत करने का निर्णय लिया।

तीसरे, लोगों ने आज भारत के सर्वश्रेष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में मत दिया।

इन सबसे बढ़कर '99 का जनादेश सकारात्मक है। यह बात इस तथ्य से और महत्त्वपूर्ण बन जाती है कि लोगों ने पिछले दशक में पहली बार किसी सत्तारूढ़ सरकार को चुना है।

अपनी संपूर्ण पार्टी की ओर से मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ।

मैं अपनी पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अथक परिश्रम किया और बिना कोई आशा किए उन्होंने केंद्र में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने तथा श्री वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के स्वप्न को साकार किया।

प्रफुल्लता का अनुभव

यदि मैं 1998-99 में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार तथा वर्तमान सत्तारूढ़ राजग सरकार की उपलब्धि को सारांश रूप में आपके सामने रखूँ तो मैं कहूँगा कि इसके कारण इस सरकार ने हमारे राष्ट्रीय जीवन में प्रफुल्लता भरने का मार्ग प्रशस्त किया।

दशकों से भारत में उथल-पुथल की स्थिति थी, सामाजिक वैमनस्य था, सांप्रदायिक असामंजस्य था और आर्थिक स्थिति गिरती जा रही थी। भारत में नेतृत्व के संकट ने लोगों को हताश कर दिया था। हर तरफ निराशा ही निराशा थी।

दो वर्षों से भी कम समय में स्थिति में अद्‌भुत बदलाव आया है।

सामाजिक तनाव कम हुए हैं, सांप्रदायिक सौहार्दता फिर से कायम हुई है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हुआ है और समृद्धि उन लोगों तक भी पहुँची है, जो अभी तक इसका स्वप्न ही देखते थे। लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि अब देश का कामकाज सुरक्षित हाथों में है और वे अब बिना घबराहट अपना जीवन बिता सकते हैं। लोगों में जितना जोश-खरोश आज है, उतना पहले कभी नहीं रहा।

सरकार में पूर्ण विश्वास

इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण इन गरमियों में कारगिल युद्ध के दौरान देखने को मिला। लोगों को सरकार की योग्यता पर पूरा भरोसा था कि वह इस संकट पर काबू पा लेगी और दुश्मन को मुँह की खानी पड़ेगी इसीलिए किसी को भी यह महसूस नहीं हुआ कि कश्मीर में एक पूरा युद्ध लड़ा जा रहा है। बल्कि, हमारे शेयर बाजार में उस गति से उछाल बना रहा, जिस गति से सीमा पर तोपें दागी जा रही थीं।

लोगों का विश्वास गलत नहीं था।

पाकिस्तान की करारी हार

पाकिस्तान को युद्ध क्षेत्र में जबरदस्त मात खानी पड़ी। राजनीतिक रूप से वह अलग-थलग पड़ गया। पहले कभी भी अंतरराष्ट्रीय जनमत इस कदर भारत के पक्ष में नहीं रहा, कम-से-कम युद्ध के समय में तो कभी नहीं रहा।

कारगिल के बाद की स्थिति को भी अद्‌भुत ढंग से सँभाला गया। अर्थव्यवस्था को टूटने नहीं दिया गया और न ही सैनिक काररवाई का बोझ लोगों पर डाला गया।

चुनाव परिणामों और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए नए कदमों ने प्रफुल्लता को और बढ़ाया है।

तीव्र विकास के लिए तीव्र काररवाई

जहाँ 13वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों से पता चलता है कि लोगों ने केंद्र सरकार के कार्य प्रदर्शन पर अपनी मोहर लगाई है, वहीं कुछ राज्यों में अलग-अलग सरकारों का कार्यप्रदर्शन ठीक न होने के कारण उन राज्यों में जोरदार शासन-विरोधी

तत्त्व काम करता दिखाई पड़ा है।

कांग्रेस राज के दौरान पाँच दशकों तक सरकार की निष्क्रियता की मार के बाद लोग आशा करते हैं कि अब कुछ अलग ढंग की बात हो। सबसे अधिक तो वे बेहतर जीवन बिताने की इच्छा रखते हैं। और वह चाहते हैं कि यह अभी संभव हो जाए।

लोगों की आकांक्षाएँ पूरी तरह न्यायोचित हैं। आखिर नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रभावशाली सरकार वही है जो यथासंभव अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँच सके और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, आवास और सुरक्षा की पूर्ति कर सके।

सरकार ने सामाजिक-विकास के इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता की सूची में रखकर ठीक ही किया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इनपर तत्काल ही कार्य करे।

समता आधारित समाज विकास

हम जहाँ भी सत्ता में हैं वहाँ हमारे दो मार्गनिर्देशी सिद्धांत होने चाहिए, कि तेजी से आर्थिक परिवर्तन लाया जाए, तेजी से समाज विकास का कार्य संपन्न हो। जब तक हम सब में बराबर विकास को सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक हम आशा नहीं कर सकते हैं कि हमारे लिए लोगों का समर्थन जारी रहेगा। हम लोगों की आशा पूरी करेंगे—इस बारे में उन्हें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए।

दो मुद्दे लंबे समय से लटके पड़े हैं; यदि राष्ट्रीय कार्यक्रम को अर्थपूर्ण और वास्तव में कारगर बनाना है तो इनका समाधान करना आवश्यक है।

पहला मुद्दा क्षेत्रीय असमानताओं और अलग-अलग राज्यों में असमान विकास से जुड़ा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास स्तरों में भी असमानता है। अतः ऐसे उपाय और साधन जुटाने होंगे जिनसे विकास स्तरों पर समानता आ सके, ताकि कोई क्षेत्रीय या राज्य यह महसूस न करे कि वह पीछे रह गया या उसे सुविधाओं से वंचित रखा गया।

इससे उत्तर-पूर्व जैसे कम विकसित क्षेत्रों के लोगों की शिकायतें नहीं रह जाएँगी और राष्ट्रीय अखंडता की दिशा में योगदान मिलेगा।

जनसंख्या वृद्धि का स्थिरीकरण

दूसरा वर्तमान ज्वलनशील मुद्दा यह है कि भारत की जनसंख्या को स्थिर करने की आवश्यकता है। निरंतर बढ़ती जा रही जनसंख्या की आवश्यकताओं को निश्चल राष्ट्रीय संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता है। भारत को अविलंब ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की आवश्यकता है।

पोखरण और उसके बाद

रूसी क्रांति को 'दस दिन में विश्व को हिला देने' वाली क्रांति के नाम से जाना जाता है। मई 1998 में सरकार द्वारा पोखरण में किए गए पाँच परमाणु परीक्षणों को भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है—'पाँच विस्फोट, जिन्होंने विश्व को हिला दिया।'

अचानक ही बड़ी शक्तियाँ इस तथ्य के बारे में नींद से जाग उठीं कि भारत कोई ऐसा विकासशील देश नहीं है, जिसकी उपेक्षा की जा सकती है। उन्होंने बड़ी तेजी से काररवाई करते हुए प्रतिबंध लगा दिए और सहायता रोक ली। परंतु फिर एक बार सरकार ने अपनी योग्यता प्रदर्शित की कि वह इन महाशक्तियों का मुकाबला कर सकती है।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी

पोखरण-2 के एक वर्ष के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि विकसित देशों के रवैये में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया है। अब भारत की सुरक्षा चिंता को बेहतर ढंग से समझा जाने लगा है। आज हम राष्ट्रों के समुदाय में सिर ऊँचा करके खड़े हुए हैं।

विश्व में तेजी से बदलते परिदृश्य में सभी देश एक-दूसरे पर निर्भर हैं; ऐसी स्थिति में एक ध्रुवीय विश्व न तो वांछनीय है और न ही स्वीकार्य हो सकता है। चाहे कोई देश आर्थिक और सैन्य रूप में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, किसी अन्य देश पर अपनी शर्त थोप नहीं सकता है।

भारत ने हाल में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में इस स्थिति को बहुत सही और जोरदार ढंग से स्पष्ट कर दिया है। बैठक विफल सिद्ध हुई जो इस बात का प्रमाण है कि एकध्रुवीय विश्व की परिकल्पना मान्य नहीं हो सकती है।

बाह्य और आंतरिक सुरक्षा

मैंने पहले ही कारगिल संघर्ष और पाकिस्तान के दुःसाहस का उल्लेख किया है। हालाँकि पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया गया और उसे भारत की तरफ की नियंत्रण रेखा से वापस जाना पड़ा, फिर भी पाकिस्तान ने भारत विरोधी अपने इरादों को छोड़ा नहीं है।

पाकिस्तान अभी भी सीमा पार से आतंकवाद और भारत-विरोधी शत्रुतापूर्ण प्रचार चला रहा है। इस शत्रुता के साथ पाकिस्तान में सैन्य विद्रोह के कारण एक नया आयाम जुड़ गया है।

पाकिस्तान में घटी घटनाएँ : चिंता का विषय

पाकिस्तान में घटी घटनाएँ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में महत्त्व रखती

हैं। सत्ता हथियाने के तुरंत बाद पाकिस्तान के सैन्य शासकों ने आतंकवादी संगठनों को एक सम्मेलन करने दिया, जिसमें भारत के खिलाफ 'जेहाद' के नारे लगाए गए। इनमें से अनेक संगठन, विशेष रूप से लश्कर-ए-तोयबा, भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ चलाने के लिए विख्यात हैं।

सरकार को सीमा पार के आतंकवाद से निपटने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए। प्रधानमंत्री पहले ही राष्ट्र को वचन दे चुके हैं कि सरकार आतंकवाद को जरा भी सहन नहीं करेगी और इसके खिलाफ काररवाई करने की नीति अपनाएगी। अब हमें मानवता के खिलाफ इस अपराध के प्रति दृढ़ता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

कुछ और भी पहलू हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में वामपंथी उग्रवादियों ने जिस तरह का रक्तरंजित आतंक फैलाया हुआ है, उससे भी कठोरता और समन्वित रूप से जवाबी-काररवाई कर निपटाना आवश्यक है।

इसी प्रकार उत्तर-पूर्व राज्यों में विशेष रूप से त्रिपुरा और मणिपुर में विद्रोही गतिविधियों से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। किसी भी भारतीय नागरिक पर आतंक की छाया पड़ने नहीं दी जा सकती है।

राजनीतिक स्थिति

आप जानते ही हैं कि पिछले आम चुनाव में भाजपा प्रमुख पार्टी बनकर उभरी है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस इतनी तेजी से रसातल की ओर जा रही है कि राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका नगण्य बनकर रह गई है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से कोई सबक सीखने को तैयार है और वह अपनी खोई प्रतिष्ठा का पुनः प्राप्त करने को तैयार है। इसके विपरीत गोवा में कांग्रेस सरकार के पतन से लगता है कि पार्टी की वर्तमान स्थिति कितनी कमजोर है और पार्टी पर उसके नेतृत्व का अधिकार कितना क्षीण हो गया है। उड़ीसा में कांग्रेस सरकार के अत्यंत दयनीय प्रदर्शन और राज्य में महाचक्रवात से उत्पन्न लोगों पर आए संकट से निपटने में उसकी नितांत अक्षमता को माफ नहीं किया जा सकता है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उड़ीसा के लोग कांग्रेस को दंड देकर रहेंगे।

कांग्रेस का गिरता आधार

कांग्रेस ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने का वायदा किया था। परंतु उसने बोफोर्स मामले में सी बी आई के आरोप पत्र में राजीव गांधी के नाम को हटाने की माँग पर तूफान खड़ा कर दिया। इस मुद्दे पर अब सरकार का दृष्टिकोण सही साबित हुआ है। कांग्रेस ने इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य की बात

की थी; अब दिखाई पड़ रहा है कि वास्तव में यह कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा था।

इस बीच कांग्रेस ने आम चुनाव से पूर्व जो भी जोड़-तोड़ कर कमजोर सा गठबंधन किया था वह भी समाप्त हो गया है।

वामपंथी और बुरी हालत में

वामपंथी आज की वास्तविकताओं से बड़ी तेजी से नाता तोड़ते जा रहे हैं और उनका आधार उन राज्यों में भी घटता जा रहा है, जहाँ पहले वह शक्तिशाली थे। पिछले दौर के चुनावों में अपने खराब प्रदर्शन के बाद सी. पी. आई. (एम) राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना दर्जा खो सकती है।

सी. पी. आई. (एम) की इस माँग को यह देखकर हैरत होती है कि वह राजनीतिक पार्टियों के दर्जे से संबंधित नियमों में संशोधन कराना चाहती है, ताकि मार्क्सवादी 'राष्ट्रीय पार्टी' के रूप में अपने दर्जे को कायम रख सकें।

बिहार में राजद अपनी अंतिम साँसें गिन रहा है। बिहार के 'सत्ताधारी परिवार' की पक्षपातपूर्ण हरकतें याद दिलाती हैं—'रोम जल रहा था और नीरो तमाशा देख रहा था।' उड़ीसा की तरह बिहार में भी पदासीन सरकार लोगों के क्रोध से नहीं बच सकती है।

इन दोनों राज्यों में हमें चुनाव की तैयारी करनी है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाना है, ताकि लोगों के सामने इस बारे में स्पष्ट विकल्प हो कि किन लोगों ने उन्हें बेहाल किया है और कौन उनके हित में कार्य कर उन्हें वर्तमान दुर्दशा से निकाल सकते हैं।

एक आखिरी बात, हमारे विरोधी वही पुरानी 'सांप्रदायिकता' की दुहाई देते थकते नहीं हैं, हालाँकि उनकी मिथ्या बातों पर अब कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। जिस कुत्सित ढंग से उन्होंने अयोध्या मुद्दे पर संसद् की काररवाई ठप्प की और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, उसकी चाहे जितने कड़े-से-कड़े शब्दों में निंदा की जाए, फिर भी कम ही होगी।

जो तर्क वह देते हैं, उसमें कहीं कोई तुक और तर्क नहीं है। उदाहरण के लिए, वे दावा करते हैं कि एक समुदाय विशेष उस स्थान पर पूजा-अर्चना स्थल का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ दूसरे समुदाय की संख्या अधिक है। इस तरह के विकृत तर्क का एक ही प्रयोजन हो सकता है : वैरभाव पैदा कर सांप्रदायिक सौहार्द को भंग किया जाए। हमें ऐसे कुत्सित इरादों से सावधान रहना होगा।

संगठनात्मक कार्य

मित्रो, अगले वर्ष हमारी पार्टी के संगठनात्मक चुनाव होने वाले हैं। जनवरी से हमारा सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा।

मैं आप से आग्रह करूँगा कि आप इस अवसर का लाभ उठाकर पार्टी के आधार का विस्तार करें, अधिक-से-अधिक समाज के जितने वर्गों तक पहुँचा जा सकता है, उनके पास पहुँचा जाए और पार्टी में ईमानदार पुरुषों और महिलाओं को शामिल करें, जो हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी निःस्वार्थ सेवाएँ देना चाहते हैं।

भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषी देश है। अपनी विचारधारा के अनुरूप हमें सदैव सबको साथ लेकर चलने के सिद्धांत पर कायम रहना चाहिए तथा किसी भी प्रकार से अपवर्जन से बचना चाहिए।

सभी भारतीयों के कल्याण के प्रति वचनबद्धता

इस अवसर पर पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं पार्टी के सामूहिक विश्वास को फिर दोहराता हूँ : भाजपा चाहे सत्ता में हो या न हो, सभी भारतीयों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है, चाहे वह किसी लिंग, जाति, धर्म या भाषा से संबद्ध क्यों न हो। हम साथ-साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मातृभूमि को सुदृढ़, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए काम कर सकते हैं।

मित्रो, मैं पार्टी अनुशासन के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। हमें अवश्य ही स्मरण रखना चाहिए कि उन व्यक्तियों ने ही इस पार्टी का निर्माण किया है जिन्होंने संगठन को हर चीज से ऊपर रखा। हम आज जो कुछ भी हैं, वह केवल इसलिए हैं, क्योंकि संगठन के हितों को सदैव व्यक्ति के हितों और आकांक्षाओं से ऊपर रखा गया।

किंतु हाल में कुछ व्यक्तियों में पार्टी से ऊपर स्वयं को रखने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति देखी गई है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

भाजपा एक अलग किस्म की विशिष्ट पार्टी होने के लिए विख्यात थी, यह वह पार्टी है जो अनुशासन और पार्टी के सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों के प्रति परम निष्ठा को अत्यंत महत्त्व देती है। ऐसे कुछ व्यक्तियों के कार्यों से पार्टी की छवि धूमिल हुई है, जिन्होंने पार्टी को हानि पहुँचाकर अपने हितों को साधना चाहा।

हाँ, मतभेद हो सकते हैं और समस्याएँ भी हो सकती हैं; परंतु पार्टी के अंदर और समुचित मंच पर ही इनका समाधान होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के बीच फूट पैदा करना और अनुशासन का उल्लंघन करने का अर्थ पार्टी का परित्याग करना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए संगठन में न तो कभी स्थान रहा है और न ही रहेगा।

पार्टी अनुशासन पर दृढ़

हमें अप्रिय और दुखद अनुभवों से बचने और भाजपा की एक विशिष्ट प्रकार की पार्टी होने की छवि को पुनः स्थापित करने के लिए उपाय करना आवश्यक है; मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूँ :

- निर्णय लेने की प्रक्रिया और कार्यक्रमों तथा नीतियों के कार्यान्वयन, दोनों में ही कार्यकर्ताओं को सहभागी बनाया जाए।
- सभी स्तरों पर इकाइयों तथा मोरचों के बीच केंद्र और राज्य दोनों में पार्टी तथा इसके विधायी अंगों के बीच और अधिक तालमेल सुनिश्चित किया जाए।
- मतभेदों और शिकायतों का शीघ्रता से समाधान किया जाए, अनुशासनात्मक काररवाई लटकाई न रखी जाए, बल्कि तुरंत की जाए।
- सभी स्तरों पर हमारे नए प्रवेश करनेवाले तथा वर्तमान दोनों कार्यकर्ताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएँ।
- आधारभूत स्तर से पार्टी इकाइयों को सक्रिय और कारगर बनाया जाए। केवल मंडल स्तर इकाइयाँ स्थापित करना काफी नहीं है; हमें सुनिश्चित करना होगा कि वे हर समय सक्रिय रहें और कार्य करती रहें।

हमारा उत्तरदायित्व

मैं इस राष्ट्रीय परिषद् के माध्यम से सभी पार्टी सदस्यों और विधायकों का आह्वान करता हूँ कि वह यह सोचें कि इन परिवर्तित परिस्थितियों में उनसे क्या अपेक्षा हो सकती है। अब हम विपक्षी पार्टी नहीं हैं, बल्कि हमारी पार्टी सत्ता में है।

दो कारणों से हम पर विशाल उत्तरदायित्व आता है।

आज भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, संसद् में जिसके सबसे अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। और, देश में शासन कर रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम सबसे बड़े सहभागी हैं।

राजग का एजेंडा–हमारा एजेंडा

ऐसा कुछ भी नहीं कहना और करना चाहिए जिससे हमारे बारे में जरा सी भी उत्तरदायित्वहीनता का संकेत मिले। राजग का एजेंडा हमारा एजेंडा है : न इससे अधिक, न इससे कम।

हमारा प्रमुख उत्तरदायित्व सुशासन सुनिश्चित करना है और आमूलचूल सामाजिक–आर्थिक कायाकल्प करना है। हमारे विरोधी इस उत्तरदायित्व की ओर से हमारा ध्यान बँटाने की कोशिश करेंगे और यदि हम विभ्रमित हो गए तो हम उनके जाल में फँस जाएँगे।

हम यह न भूलें कि लोगों ने हम पर यह जिम्मेदारी डाली है और यदि हम अपने कर्तव्य में असफल रहे तो हम लोगों के विश्वास को तोड़ेंगे।

यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगियों पर बड़ी जिम्मेदारी आती है। उन्हें अपने काम और शब्दों से कार्यकर्ताओं को राह दिखानी है। उन्हें ऐसा कुछ कहना या करना नहीं चाहिए जिससे विवाद खड़ा हो और हमारे विरोधियों को आलोचना करने का मौका मिले।

हमारा लक्ष्य

आइए, हम इस बैठक से नैतिक मूल्यों की राजनीति करते हुए लोगों की सेवा करने का भाव भरकर अपने-अपने घरों को लौटें।

हमारे लिए राजनीति सदैव उच्च मिशन रही है, हमने इसे एक महान् लक्ष्य को साधने के लिए छोटे से साधन के रूप में अपनाया है : एक समृद्ध समाज, जो भेदभाव से मुक्त हो, एक ऐसा समाज, जहाँ प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना योगदान दे; और एक ऐसा समाज, जिसमें जातिवाद और धार्मिक उन्माद की बुराइयाँ न हों।

सचमुच ही हमारी पार्टी राष्ट्रवादी है क्योंकि हम राष्ट्र को किसी भी चीज के ऊपर रखते हैं। यदि हम अपनी पार्टी के संस्थापकों—डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिखाए मार्ग से विचलित न हों तो उनके सपनों को साकार कर सकते हैं।

वंदेमातरम् !



राष्ट्रीय परिषद्

गांधीनगर 3-4 मई, 1998

आदरणीय स्वागताध्यक्षजी, प्रतिनिधि भाइयो और बहनो

मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के इस ऐतिहासिक सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ।

अत्यधिक विनम्रता एवं कृतज्ञता की भावना और अपनी पार्टी तथा राष्ट्र के महान् भविष्य के प्रति अपार विश्वास के साथ मैं आपको संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

यह सत्र अनेक अर्थों में ऐतिहासिक है।

यह पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् का प्रथम सत्र है, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और हमारी पार्टी के संस्थापक-अध्यक्ष एवं हमारे वरिष्ठतम नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस महान् राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। हमने इसी घड़ी का सपना देखा था। यही वह घड़ी है जिसकी करोड़ों देशभक्त उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे और जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे।

अतः यह हमारे लिए जनता-जनार्दन तथा अपने प्रिय नेता श्री वाजपेयी को धन्यवाद देने का सत्र है। आज वे देश की जनाकांक्षाओं एवं स्वप्नों की सजीव एवं साकार प्रतिम हैं और देश के अनन्यतम नेता हैं।

जनता से भारी समर्थन

किसी भी संसदीय चुनाव में हमारी पार्टी को मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् का यह प्रथम सत्र है। हम 1989 में कहा करते थे कि "यदि 1984 का चुनाव हमारी चुनावी सफलता का निम्नतम बिंदु था तो 1989 के चुनाव उसका उच्चतम बिंदु है।" अगले चुनावों में हमने यही बात दोहराई, केवल 1989 का स्थान 1991 ने ले लिया। अगले पाँच वर्ष बाद जो चुनाव हुआ उसके बाद

हमने और अधिक गर्व के साथ एक बार फिर वही बात दोहराई, केवल 1991 का स्थान 1996 ने ले लिया।

परंतु भारत की जनता प्रत्यक्ष एवं गूढ़ रूप से सदा हमें यह सूचित करती रही, "आप अभी से इतना क्यों इतरा रहे हैं, जब आपकी सर्वोत्तम सफलता को और अधिक ऊँचे शिखर तक पहुँचाने का हमारा दृढ़ निश्चय है।" और उन्होंने वस्तुतः ऐसा करके दिखा दिया। भाजपा को 1998 में 1996 की अपेक्षा कहीं अधिक सीटें मिलीं और उसका मत-प्रतिशत भी बहुत अधिक बढ़ गया। जनता-जनार्दन का समर्थन प्रचुर मात्रा में सदा विद्यमान था; हमें उसे केवल संगठित करना और जुटाना था। हमारे लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं सहयोगियों के अथक संघर्ष तथा सहर्ष बलिदान के बिना यह संभव नहीं था।

किंतु कार्यकर्ताओं का संघर्ष एवं बलिदान तथा 1984 की 2 सीटों से आरंभ करके 1998 में 181 सीटें प्राप्त करने की हमारी यात्रा श्री लालकृष्ण आडवाणी के सुदृढ़ एवं दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व के बिना सफल नहीं हो सकती थी। अतः यह हमारे कार्यकर्ताओं—आप सबको—और हमारे आदरणीय नेता श्री आडवाणी को धन्यवाद देने का सत्र है।

मित्रों, मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपना सारा जीवन पार्टी के संगठन, निर्माण एवं इसके विस्तार के लिए अर्पित कर दिया है। हमारे शीर्षस्थ नेता अब सरकार चलाने में संलग्न हैं। संपूर्ण राष्ट्र की यह उत्कट अभिलाषा है कि यह सरकार सुचारू रूप से चले। पार्टी के हम सब सदस्यों की भी यही कामना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे दिग्गजों को सरकार की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सँभालना होगा।

पार्टी में आत्मविश्वास

इसके साथ ही पार्टी के संगठन को भी सुचारू रूप से चलाना होगा। आखिरकार यही तो वह वाहन है जिसने हमें अपनी यात्रा के वर्तमान पड़ाव तक पहुँचाया है। यदि इस वाहन को अच्छी तरह ईंधन से परिपूर्ण रखा जाएगा, अच्छी तरह इसमें तेल डाला जाएगा और सदा इसका यथासंभव रख-रखाव किया जाएगा तो यह आशा की जा सकती है कि हम आगे की कठिन डगर अधिक तेजी और आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकेंगे।

हमें यह स्मरण करना आवश्यक है कि जब पार्टी केंद्र में सत्ता में हो तब पार्टी का संगठन भी उतना ही अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है। मेरे विचार में इसी बात को ध्यान में रखकर मुझ जैसे कार्यकर्ता को इस घड़ी में पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

लक्ष्य सदैव साध्य रहे

मुझे सर्वसम्मति से निर्वाचित करने के लिए मैं पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रो, मुझे अपनी क्षमता एवं सीमाओं का ज्ञान है। हमारी पार्टी ने सदा ही सामूहिक रूप से निर्णय करने में गर्व अनुभव किया है। अतः आजकल की आवश्यकताओं के अनुसार पार्टी को चलाने में मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती।

इसके साथ ही, मैं पार्टी के प्रत्येक सदस्य को सावधान कर देना चाहता हूँ कि गौरव की इस घड़ी में हमें ऐसा कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। लोगों को हमसे बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं। उनकी समस्याएँ और राष्ट्र की समस्याएँ बड़ी गंभीर हैं। लोग यह चाहते हैं कि हम इन समस्याओं को साहस, दृढ़निश्चय और सूझ-बूझ से हल करें। हमारे लिए भी यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है कि हम शीघ्रताशीघ्र इन समस्याओं के सार्थक एवं स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करना आरंभ करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, जिसका अथक एवं लगन से परिश्रम करना स्वभाव है, कभी भी आत्मसंतुष्ट न होने का संकल्प करें और कभी भी अपने लक्ष्य को अपनी आँखों से ओझल न होने दें।

मैं जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे प्रेरणास्रोत एवं वैचारिक मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यस्मृति को प्रणाम करके इस पद को ग्रहण करता हूँ। मुझे इन दोनों को निकट से जानने तथा इनके साथ काम करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके आदर्शों ने ही, जिनकी वे अपने व्यक्तिगत जीवन में साक्षात् प्रतिमूर्ति थे, इस संगठन के साथ मेरे संपूर्ण 47 वर्षों के संबंध में मेरा मार्गदर्शन किया है—पहले भारतीय जनसंघ के साथ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहण करते समय उनके आदर्श मेरे लिए प्रकाशस्तंभ का कार्य करेंगे।

सत्ता का असली प्रयोजन

मित्रो, जैसा कि मैंने कहा, यह बैठक भाजपा के सत्तारूढ़ होने के साथ-साथ हो रही है। हमारे लिए सत्ता कभी एकमात्र लक्ष्य नहीं रही; हमने सदा ही सत्ता को लक्ष्य की प्राप्ति का साधन समझा है और वह लक्ष्य जन-कल्याण का है। हमारी सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध है। यदि सत्ता का जन-कल्याण के लिए न्यायसंगत उपयोग किया जाए तो यह एक उदात्त अनुभव हो सकता है। व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने के लिए सत्ता का उपयोग भ्रष्टकारी प्रभाव डालता है। हमें इससे सावधान रहना चाहिए।

हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हमारी यात्रा, जो 1951 में भारतीय

जनसंघ की स्थापना के साथ आरंभ हुई थी, हमारे सत्तारूढ़ हो जाने के बाद समाप्त नहीं हो गई है। निस्संदेह, हम बहुत दूर चले आए हैं, किंतु हमें अभी और आगे जाना है, और हम यह केवल तभी कर सकते हैं जब पार्टी का संगठन और अधिक शक्तिशाली हो तथा हमारे कार्यकर्ता अपने वायदों पर दृढ़ता से कायम रहें।

राजनीति : एक उच्च ध्येय

हमारी बैठक गांधीनगर में हो रही है। इस स्थल का अपना महत्त्व है। गुजरात के दो महान् सपूतों महात्मा गांधी और सरदार पटेल का स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राजनीति में योगदान दो बातों के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। प्रथम, उन्होंने नैतिकता एवं आचारनीति को समाविष्ट करके राजनीति का स्तर ऊँचा किया; और दूसरे, उन्होंने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति एक उत्कृष्ट महान् ध्येय की प्राप्ति का साधन है।

राजनीति के नैतिक आधार की संपुष्टि

हम जो भाजपा में हैं, उनके लिए आचारनीति तथा नैतिकता के आधार से रहित राजनीति केवल व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि का माध्यम हो सकती है; किंतु इससे राष्ट्र का हित तो निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए हम राजनीति के नैतिक आधार को और अधिक संपुष्ट करने का आग्रह करते हैं। आइए, हम सब इस उच्च ध्येय की प्राप्ति के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करें और उन राजनीतिज्ञों के हाथों, जो अपने आपको राष्ट्र से ऊपर समझते हैं, राजनीति के अधःपतन को रोकने के लिए अपने संकल्प को और सुदृढ़ बनाएँ।

राजनीति के अधःपतन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विकृति के विरुद्ध हमारी लड़ाई गुजरात से आरंभ हुई थी। मुझे याद है कि एक दशक या इससे कुछ पहले हमने नगरपालिका में 26 सीटें जीती थीं और कांग्रेस के 25 सदस्य थे। कांग्रेस ने हमारे एक सदस्य से दलबदल करवा लिया और इस प्रकार हमें बहुमत से वंचित कर दिया। हमारी पार्टी ने इसके जवाब में अभियान चलाया जिससे भारी जनमत कांग्रेस पार्टी और उस दलबदलू के खिलाफ हो गया और उसे अपनी सीट से त्यागपत्र देना पड़ा। जब बाद में इस सीट के लिए चुनाव हुआ तो हम जीत गए और हमें फिर से बहुमत मिल गया।

लगभग एक दशक बाद, हमने जनादेश का उल्लंघन करने की वैसी ही अनैतिक राजनीति का दृश्य एक बार फिर देखा। इस बार यह अधिक बड़े पैमाने पर किया गया था, जब हमारे अपने ही कुछ लोगों ने, पदलोलुपता में, केशुभाई पटेल की सरकार को अस्थिर कर दिया था। परंतु अंत में उन्हें अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ी।

हमारा ध्येय : जनता की सेवा

जनता ने उन्हें उनकी अनैतिकता का दंड दिया। हम एक बार फिर गुजरात में सत्तारूढ़ हो गए हैं। जनता ने हमारा साथ दिया, क्योंकि हमने अपने सिद्धांतों का परित्याग नहीं किया। किंतु हमें अधिक सतर्क रहना होगा। भाजपा की 'अपनी एक अलग पहचान' है। हम अपनी इस पहचान को आँखों से ओझल नहीं कर सकते जो हमें ऐसे लोगों से अलग करती है जो अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए आचारहीन तरीकों से सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं। हमें इस बात को अपनी नजरों से ओझल नहीं करना चाहिये कि हमारा संगठन इस महान् राष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए ही बनाया गया है।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए तथा अब और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा संगठन बहुत बड़ा हो गया है। केवल गत वर्ष में ही हमारी सदस्य-संख्या लगभग 100 प्रतिशत बढ़ गई है। अब यह 70 लाख से बढ़कर डेढ़ करोड़ तक पहुँच गई है। किंतु केवल विस्तार काफी नहीं है। हमें प्रत्येक को अपने साथ लेकर भी चलना है। हममें से प्रत्येक को नीचे से आरंभ करके एक ऐसे समाज के निर्माण के निःस्वार्थ काम में जुट जाना है, जो सबका ध्यान रखता हो, न्यायसंगत और अधिक दयालु हो। यदि हम एक मजबूत नींव रख सकें; ऐसी नींव, जो आदर्शवाद और विचारधारा पर आधारित हों, तो उस नींव पर हम जो ढाँचा बनाएँगे वह अधिक मजबूत और चिरस्थायी होगा।

पार्टी की भूमिका

जब से नई सरकार बनी है तब से मुझसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह यह है कि बदली हुई परिस्थितियों में पार्टी की भूमिका क्या होगी? अब तक एक विपक्षी राजनीतिक दल के रूप में हम सरकार की विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करके व्यवस्था के विरुद्ध मुख्यतया जनमत संगठित करने का काम किया करते थे। किंतु अब चूँकि भाजपा व्यवस्था का एक अंग है, अतः हमें पार्टी की भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा।

हमारा मुख्य प्रयास दोतरफा होना चाहिएः प्रथम, सरकार को दिशानिर्देश और परिप्रेक्ष्य प्रदान करना; और दूसरे, सरकार को आम जनता के साथ जोड़ने वाले सेतु का काम करना। इन दोनों कामों के लिए हमें निरंतर लोगों की नब्ज पहचाननी होगी।

हमें अपने संगठन का विस्तार ऊर्ध्व एवं समतल दोनों दिशाओं में करना होगा, क्योंकि केवल तभी हम अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँच सकेंगे। इस प्रकार से हम लोगों की जरूरतें जान सकेंगे और सरकार को नीति-निर्माण में सही दिशानिर्देश दे सकेंगे।

पार्टी को एक ऐसा वाहन बनना चाहिए जो सरकार तक विश्वसनीय

जानकारी पहुँचा सके। सरकार एक अत्युत्तम नीति तैयार कर सकती है, परंतु उस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने की आवश्यकता होगी और यह काम अकेली नौकरशाही पर नहीं छोड़ा जा सकता। यदि सत्तासीन मंत्रिगण पार्टी संगठन को जानकारी के वैकल्पिक स्रोत के रूप में प्रयोग करें तो उन्हें एक ऐसा आयाम मिलेगा जो नौकरशाही द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वरूप से भिन्न होगा। इससे नौकरशाह भी अधिक चुस्ती से काम करेंगे।

हमें निरंतर इस बात का ध्यान रखना होगा कि सरकार हमारे लिए जनता की सेवा का एक साधन है, हमारा लक्ष्य नहीं है। अब चूँकि हम सत्ता में आ गए हैं, इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा काम खत्म हो गया है। इससे संगठन नष्ट हो जाएगा। हमारे सामने कांग्रेस संगठन का उदाहरण है जो इस प्रकार के रवैए के कारण खत्म होता जा रहा है।

सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नई परिस्थितियों में पार्टी संगठन के सदस्यों को और अधिक समर्पित भाव से काम करना चाहिए और सर्वथा ईमानदार रहना चाहिए, जिससे कि उनकी ईमानदारी पर कोई उँगली न उठा सके। किसी भी हालत में संगठन को व्यवस्था का एक हिस्सा नहीं बन जाने देना चाहिए।

हमारी विचारधारा ही हमारी शक्ति है

एक राजनीतिक पार्टी का जन्म एक राजनीतिक विचार से होता है। भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनसंघ की उत्तराधिकारी है, राष्ट्रवाद के विचार से उत्पन्न हुई है। यह हमारी विचारधारा का मूलमंत्र है। हमारे लिए भारत एक राष्ट्र एक जन और एक संस्कृति है। हमारा यह दृष्टिकोण है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी परिभाषा इसकी अद्वितीय एवं एक सूत्र में पिरोने वाली सांस्कृतिक पहचान द्वारा की गई है। यह मार्क्सवादियों के उस भारत से भिन्न है जो इसे अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रों का समुच्चय मानते हैं। यह कांग्रेस के उस दृष्टिकोण से भी भिन्न है, जिसके अनुसार भारत का जन्म एक भौगोलिक इकाई के रूप में 1947 में हुआ।

हमारी सभ्यता 5000 से भी अधिक वर्ष पुरानी है। इन सब शताब्दियों में इस भूमि के जन-जन के एक समान मूल्य, विश्वास और रीति-रिवाज रहे हैं, चाहे उनका प्रदेश अथवा पंथ, जाति या भाषा कोई भी हो। अपनी अनेक विविधताओं के होते हुए भी, सहस्रों वर्षों से हमारे इस राष्ट्र ने एक ऐसी साझी जीवन-शैली स्थापित की है जिसकी जड़ सबकी साझी सांस्कृतिक विरासत में निहित है। यही साझी जीवन-शैली भारत की अद्वितीय देन है, जिसे हम हिंदुत्व अथवा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। आप इसका कोई भी अन्य नाम—भारतीयता या इंडियननेस—रख सकते हैं, किंतु मूल वही रहता है।

राष्ट्रवाद के प्रति वचनबद्धता

भाजपा के आलोचकों के अनुसार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अलगाववादी और सांप्रदायिक है। परंतु इस आक्षेप का कोई आधार नहीं है। हिंदुत्व की परिभाषा के अनुसार यह सर्वव्यापी धारणा है और पंथ निरपेक्षता के सच्चे अर्थ-सर्वपंथसमभाव से पूर्णतया मेल खाती है। इसका अर्थ सभी नागरिकों के साथ न्याय है। हिंदुत्व की इसी आंतरिक शक्ति ने छद्म पंथ निरपेक्षतावादियों की वोट-बैंक की राजनीति को रोकने में सहायता की है।

अटल राष्ट्रवाद के प्रति हमारी वचनबद्धता ने ही हमें इतने वर्षों तक जीवित रखा है तथा अनेक विघ्न-बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता की है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को अपनी अन्य प्रतिबद्धताओं और अपने मूलभूत दर्शन, एकात्म मानववाद के बारे में भी स्मरण करा देना चाहता हूँ। हमारी विचारधारा हमारी असली शक्ति है। हम इसे अपनी आँखों से ओझल नहीं कर सकते और न ही इससे विचलित हो सकते हैं।

किंतु विचारधारा कठमुल्लापन से भिन्न होती है। विचारधारा उन्नति की दिशा में ले जाती है, किंतु कठमुल्लापन हमें पीछे रोके रखता है। विचारधारा एक परिमाप होती है जिसमें अपने मूलभूत सिद्धांतों से समझौता किए बिना समसामयिक मुद्दों को निरंतर बैठाना पड़ता है।

समन्वय : प्रगति का सर्वव्यापी सिद्धांत

मित्रो, यह हमारे राष्ट्र एवं हमारी पार्टी के जीवन में ऐतिहासिक संक्रमण का क्षण है। यह तथ्य कि सात मास से भी कम समय में हम इस शताब्दी तथा इस सहस्राब्दि के अंतिम वर्ष में प्रवेश करनेवाले हैं, वर्तमान समय के संक्रमणकाल के स्वरूप को उजागर करता है। अतः यह उपयुक्त ही है कि हमारा ध्यान सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर केंद्रित हो : हमारा राष्ट्र किस ओर जा रहा है? हमारी भारतीय जनता पार्टी किस ओर जा रही है? हम कहाँ जाना चाहते हैं? और हम कैसे वहाँ जा सकते हैं?

मेरा दृढ़ विश्वास है—और यह विश्वास मेरे दीर्घकालीन अनुभव एवं चिंतन के बाद मेरे अंदर पैदा हुआ है—कि जो सिद्धांत भारत तथा हमारी पार्टी की उन्नति में सहायक सिद्ध हुआ है और जो भविष्य में भी उनकी उन्नति में सहायक सिद्ध होगा वह केवल एक ही सिद्धांत है और वह है समन्वय का सिद्धांत।

भारतीय जनता पार्टी अब जब विस्तार एवं उन्नति के नए क्षितिज में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है तो उसके सामने जो वैचारिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्य हैं, उनके संदर्भ में इस सिद्धांत को समझना हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। वस्तुतः समन्वय ही सर्वव्यापी दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है, जो जीवन एवं राजनीति में हमारे सभी प्रश्नों का सही उत्तर ढूँढने में सहायक सिद्ध होगा।

यह परिप्रेक्ष्य हमें अपनी संस्कृति से ही उत्तराधिकार में मिला है। इसे प्रत्येक नए युग में हमारी सभ्यता के महान् ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, गीता आदि, बुद्ध, महावीर और गुरु नानक की शिक्षाओं, हमारे भक्तिकाल और सूफी संतों की सुंदर वाणी, संत रविदास, बासवेश्वर नारायण गुरु तथा असंख्य अन्य महान् समाज-सुधारकों की कृतियों और निस्संदेह आधुनिक युग के हमारे नेताओं जैसे स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी के जीवन तथा उनके उपदेशों द्वारा निरंतर संस्कारित तथा पुनः शक्तिशाली बनाया गया है।

इसी परिप्रेक्ष्य को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद विषयक निबंध में अत्यधिक संस्कारित एवं स्फटिक मणि सदृश स्पष्ट अभिव्यक्ति मिली। उदाहरणार्थ, पंडित दीनदयालजी लिखते हैं :

"विविधता में एकता और विभिन्न स्वरूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र रहा है। यदि इस सत्य को शुद्ध हृदय से स्वीकार कर लिया जाए तो विभिन्न शक्तियों से संघर्ष का कोई कारण ही शेष नहीं रह जाएगा। संघर्ष संस्कृति अथवा प्रकृति का द्योतक नहीं है, यह तो उनके अधःपतन की निशानी है।"

आज देश और हमारे संगठन के सामने जो ठोस चुनौतियाँ हैं, उनका सामना करने के लिए हमें भाजपा की विचारधारा के मूलमंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करते समय हमें अपने मन से ऐसी गलत धारणा को निकाल देना चाहिए कि समन्वय केवल एक समझौते का नुस्खा है, और इसलिए यह दुर्बल लोगों का मार्ग है। नहीं, यह शक्तिशाली लोगों का मार्ग है। वस्तुतः यह नेतृत्व का एक प्रमुख अंग है।

विविधता में एकता, एकता में विविधता

हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में महत्त्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका अदा करने के लिए कहा गया है। जैसे एक किसान किसी फसल को उगाने से पहले मिट्टी की किस्म और पर्यावरण का अध्ययन करता है, उसी प्रकार हमारी पार्टी को अनिवार्य रूप से उस समाज के स्वभाव को पूरी तरह समझना होगा जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। इस विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरी दीर्घकालीन शिकायत भी है कि हमारे राजनीतिक टिप्पणीकारों ने, कुछ अपवादों को छोड़कर, भारत के सामाजिक स्वभाव को पूरी तरह समझा नहीं हैं।

हमारा समाज बहुत विविधतापूर्ण है। वस्तुतः विश्व में ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जो भारत की अपेक्षा अधिक समृद्ध और सामाजिक-सांस्कृतिक-भाषाई विविधता से भरपूर हो। यहाँ भाषा, वेशभूषा, सामाजिक रीति-रिवाज, आध्यात्मिक परंपराएँ, भौगोलिक तथा पारिस्थितिक दशाएँ, आर्थिक यथार्थताएँ न केवल एक

राज्य से दूसरे राज्य में बदल जाती हैं, अपितु एक जिले से दूसरे जिले में भी भिन्न-भिन्न होती हैं। जब आप एक जिले के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो आपको ये परिवर्तन दिखाई देते हैं।

अधिकांश राजनीतिक टीकाकार भारत के सामाजिक मुद्दों को या तो हिंदू-मुसलिम 'प्रिज्म' के माध्यम से देखते हैं अथवा वर्ग तथा जाति के कठोर ढाँचे में रखकर देखते हैं, और ऐसा करते समय वे न केवल अन्य सामाजिक विशेषताओं को नजरअंदाज कर देते हैं अपितु इन विविधताओं में अंतर्निहित एकत्व और सामंजस्य को भी नहीं देख पाते। यदि असलियत इतनी सरल होती जैसा कि राजनीतिक एवं मीडिया क्षेत्रों में कल्पना की जा रही है, तो हमारी समस्याएँ बहुत पहले सुलझा ली गई होतीं।

विविधता शक्ति का स्रोत है; किंतु शक्ति तभी प्राप्त होती है यदि उसमें निहित एकता को पहचान लिया जाए, सुरक्षित रखा जाए और बढ़ाया जाए, यह भी उतना महत्त्वपूर्ण है कि कोई भी वर्ग न करेंगे, न करने देंगे की उक्ति चरितार्थ न करे।

एकता के इस जादुई धागे के बारे में, जो संपूर्ण संपन्न विविधता में से होकर गुजरता है, प्राचीन ऋषि-मुनियों, समाज-सुधारकों, आधुनिक काल के चिंतकों तथा राष्ट्रीय नेताओं ने लोगों को उपदेश दिया है। वस्तुतः उन्होंने एकता की इस अवधारणा को केवल भारतीय राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु इसे संपूर्ण मानवता पर लागू कर दिया जैसा कि इस वैदिक सूक्त 'वसुधैवकुटुम्बकम्' से स्पष्ट होता है।

मानव परिवार में यह एकता की भावना, विविधता को स्वीकार करने और सम्मान देने के लिए सदा उद्यत रहने की भावना, 'जियो और जीने दो' की प्रथा, यह कोई कानून अथवा संविधान की उपज नहीं है, अपितु हमारी संस्कृति की ही देन है। इसी कारण से भारत के गाँव में भी 'विश्व शांति' जैसे मुद्दों के लिए तत्काल समर्थन मिलता है।

घृणा नहीं, अपितु प्रगाढ़ स्नेह हमारी जीवन-शैली है। चीर-फाड़ नहीं, अपितु सामंजस्य हमारी संस्कृति है।

न केवल टकराव, अपितु हितों का सामंजस्य भी

हमारे समाज का ढाँचा ऐसा है कि आप चाहे जो भी क्षेत्र अथवा मुद्दा चुनें-चाहे वह कृषि, उद्योग, ग्रामीण—शहरी संबंध या अन्य कुछ भी हो—आपको हितों का टकराव और हितों का समायोजन दोनों ही दिखाई देंगे। उदाहरणार्थ, भारतीय कृषि की समस्याओं को ही लें, खेतिहर मजदूरों और भूस्वामियों के बीच कुछ टकराव हैं; किंतु यदि हम केवल टकराव को ही देखेंगे तो यह बात हमें दिखाई नहीं देगी कि उन दोनों को एक-दूसरे की जरूरत भी है।

इसी प्रकार से, ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच एक स्पष्ट विषमता है; किंतु यदि हम इसे गहराई से देखें तो हम इस बात को महसूस करेंगे कि न तो ग्रामीण भारत की समस्याएँ और न ही शहरी भारत की समस्याएँ अलग-थलग रूप से सुलझाई जा सकती है एक बार फिर इस मुद्दे को निपटाने का एक ही उपाय है : समन्वय।

न तो डंडा और न ही कानून अपितु अपनत्व की भावना ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करेगी

कोई भी पार्टी भारत जैसे विशाल तथा विविधतापूर्ण और जटिल समस्याओं से घिरे हुए देश को शासन डंडे के बल पर नहीं चला सकती। यहाँ तक कि देश की एकता और अखंडता को भी डंडे का प्रयोग करके कायम नहीं रखा जा सकता अथवा मजबूत नहीं किया जा सकता। केवल कानून और संविधान ही एकता की भावना पैदा नहीं कर सकते। यह केवल तभी पैदा की जा सकती है जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क और हृदय में यह अनुभव करे कि यह राष्ट्र उसका अपना है और यह अपनत्व की भावना तभी पैदा होती है—जब प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी जाति, धर्म या श्रेणी कुछ भी हो, यह अनुभव करे कि उसकी देखभाल की जा रही है।

राष्ट्र की एक विशाल, विस्तृत परिवार के रूप में संकल्पना ही देश की एकता और प्रगति की सबसे बड़ी गारंटी है। अर्थात् जब राष्ट्र के सभी घटक इस सत्य को अनुभव करें कि भारत मात्र एक भौगोलिक इकाई नहीं है, अपितु एक सजीव तथा प्राचीन सभ्य समाज है जो सबके योगदान से समृद्ध हुआ है और यदि राष्ट्र प्रगति करेगा तो उसका प्रत्येक सदस्य प्रगति करेगा।

पार्टी कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को समझें

मैंने अपने इस विश्वास को बताने का प्रयास किया है कि भारत की समस्याएँ केवल तभी हल की जा सकती हैं, जब हम भारत को समझें। यदि हम बाहर गाँवों में, शहरी मलिन बस्तियों में, आदिवासी क्षेत्रों में और ऐसे स्थानों में, जहाँ अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, न जाएँ तो हम भारत को कैसे समझ सकते हैं? यदि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सभी प्रदेशों और समाज के सभी वर्गों में फैल नहीं जाते हैं, यदि हम उनके विशिष्ट इतिहास तथा रीति-रिवाजों और समस्याओं तथा शक्तियों की ठोस जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं तो हम उन्हें अपनी पार्टी के अधिक निकट कैसे ला सकते हैं?

अतः मेरी सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से यह प्रार्थना है : अपने आपको सभी भारतीय चीजों से तादात्म्य स्थापित करने के लिए, प्रत्येक भारतीय की पीड़ा को अनुभव करने के लिए और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से समाज के हर वर्ग की समस्याओं

को हल करने के लिए अपनी संकल्प शक्ति को जाग्रत् कीजिए। हमारे समाज की सामाजिक संरचना हमारी पार्टी के संगठन में पूर्णतया प्रतिबिंबित होनी चाहिए। जब कोई प्रेक्षक सभी स्तरों पर भाजपा के संगठनात्मक ढाँचे पर दृष्टिपात करे, तो उसे भारत माता का पूर्ण एवं व्यापक दर्शन होना चाहिए।

अंकगणित या वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी

इस संदर्भ में, हमें यह भी जानना होगा कि अंकगणित के आधार पर किसी भी समुदाय की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता, अर्थात् यह हिसाब लगाना कि उसकी संख्या के आधार पर प्रत्येक समुदाय का कितना चुनावी अथवा राजनीतिक महत्त्व है। हमारे यहाँ कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से छोटे हैं। उनका संसद् में प्रतिनिधित्व भी न्यूनतम है। लेकिन क्या यह कोई कारण है कि हम उनके साथ बड़े राज्यों जैसा बरताव न करें? जैसे अरुणाचल प्रदेश को लें, इसकी जनसंख्या मात्र आठ लाख है और यह संसद् में केवल दो संसद् सदस्य भेजता है। लेकिन यहाँ पर 131 जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें से कुछ की संख्या तो 1000 से भी कम है। क्या यह न्यायसंगत होगा कि छोटी जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर हम उनकी उपेक्षा करें। अगर हम कांग्रेस की नीतियों के आधार पर कहें तो उत्तर होगा 'हाँ'। लेकिन यदि हम राष्ट्रवाद के आधार पर बात करें तो उत्तर होगा 'बिलकुल नहीं'।

संवेदनशील और एकीकृत नीति को अपनाकर आप इस योग्य हो जाएँगे कि अनुसूचित जाति के लोग यह महसूस करेंगे कि आपकी पार्टी उनके लिए है। आप 'वनवासी' लोगों को यह महसूस करा सकेंगे कि आपकी पार्टी उनके लिए है। आप उत्तर-पूर्व के मिजो, नागा और कुकी लोगों को यह महसूस करा सकेंगे कि आपकी पार्टी उनके लिए है। आप मुसलिमों और ईसाइयों को भी यह महसूस करा सकेंगे कि आपकी पार्टी उनकी है। इस प्रक्रिया में अनेक समस्याएँ और विरोधाभास, जो एक जाति से दूसरी जाति के साथ या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के साथ होंगे, सामने आएँगे। लेकिन यदि हम समन्वय के सिद्धांत पर कायम रहें तो हम देखेंगे कि समस्याओं के साथ उनके समाधान भी निकल आते हैं।

अल्पसंख्यक, भाजपा और पंथ निरपेक्षता

भाजपा सकारात्मक पंथ निरपेक्षता के प्रति अपनी वचनबद्धता पर दृढ़ हैं, जो पंथीय-राजतंत्र (थियोक्रेसी) को अस्वीकृत करते हुए 'सब के साथ न्याय, किसी का तुष्टीकरण नहीं' के सिद्धांत पर बल देता है। हमारा यह दृष्टिकोण है कि राज्य इस अर्थ में धर्मविहीन नहीं हो सकता कि इसका कोई धार्मिक आधार नहीं होगा, किंतु यह न तो किसी पंथ के पक्ष में पक्षपातपूर्ण दिखाई देना चाहिए और न ही

किसी पंथ के विरू)। इसके विपरीत हमारे विरोधियों ने पंथ निरपेक्षता के अर्थ को बिगाड़ दिया है जिससे कि वे अपनी धारणा के अनुरूप राज्य को धर्मविहीन बनाने अथवा अपनी वोट-बैंक की राजनीति पर परदा डालने के लिए उसका मनमाना अर्थ निकाल सकें।

प्रथम श्रेणी के छद्म-सेक्युलरवादियों के लिए मैं 'हिंद स्वराज' से महात्मा गांधी को उद्धृत करूँगा : 'धर्म मुझे प्यारा है, और मेरी पहली शिकायत यह है कि भारत धर्मविहीन होता जा रहा है'। गांधीजी विशेष पंथ का उल्लेख नहीं कर रहे थे अपितु वे उस धर्म का उल्लेख कर रहे थे जो सब पंथों में विद्यमान है। दूसरे छद्म-सेक्युलरवादियों से मुझे सिर्फ यह कहना हैं—जिन्हें आप इतने वर्षों तक गुमराह करते रहे हैं वे यह महसूस करने लगे हैं कि उनकी भलाई झूठे वायदों में नहीं है, अपितु सरकार के न्यायसंगत और निष्पक्ष कार्यों में है। मेरा अल्पसंख्यक समुदायों से अनुरोध है कि वे इन बातों से हमारे बारे में कोई फैसला न करें कि हमारे विरोधी हमारे बारे में क्या कहते हैं, परंतु हमारे कार्यों और काम को देखकर फैसला करें।

मेरा छद्म-सेक्युलरवादियों से यह भी अनुरोध है कि वे जम्मू और कश्मीर तथा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के अल्पसंख्यक समुदाय की हालत के बारे में अपनी आँखें खोलें। यदि उन्हें सच्चे मन से अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में चिंता है तो उन्हें वोट-बैंक की राजनीति के रंगीन चश्मे से इस मुद्दे को नहीं देखना चाहिए, अपितु देश के प्रत्येक क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में एक ही पैमाना इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे उनकी पंथीय पहचान कुछ भी हो। जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे, उनकी चिंता पर लोग संदेह प्रकट करते रहेंगे।

जब कभी हम सत्ता में आए हैं तो हमने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित किया है। अब चूँकि केंद्र में भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार है इसलिए हम अपने विरोधियों को एक बार फिर झूठा साबित कर देंगे। इस आम चुनाव में लालच और हमारे विरोधियों की भविष्यवाणियों की परवाह न करते हुए बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हमें वोट दिए हैं। मुझे इसमें रत्ती भर शक नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकाधिक सदस्य हम को चुनेंगे और वोट-बैंक की राजनीति करनेवालों से अपने आपको आजाद कर लेंगे।

क्या भाजपा की नकेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में है? जी नहीं

हमारी प्रगति को जैसे-तैसे रोकने के लिए हमारे विरोधियों ने एक और झूठा प्रचार कर रखा है और हमारे ऊपर यह आरोप लगाया है कि भाजपा स्वयं अपनी स्वामी नहीं है अपितु इसकी 'नकेल' वस्तुतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में है। यह आरोप लगाना कि भाजपा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नियंत्रण है न

केवल असली सच्चाई को तोड़-मरोड़कर पेश करना है, अपितु संघ के नेतृत्व के स्वभाव और चिंतन के बारे में पूर्णतया गलत धारणा भी फैलाना है।

सच तो यह है कि राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ से प्रेरित सभी संस्थाएँ अपना निर्णय लेने में पूर्णतया स्वतंत्र हैं। इसका कारण यह है कि केंद्रीयकृत नियंत्रण का विचार ही गैर-हिंदू है।

एक दर्शन और व्यवहार के नमूने के रूप में अत्यधिक केंद्रीयकरण वास्तव में साम्यवादियों और कांग्रेसियों की विशेषता है। आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास में राजनीतिक समर्थन तथा संगठन के दो भिन्न-भिन्न नमूने देखे जा सकते हैं। एक है साम्यवादी नमूना, जिसके अंतर्गत एक मजबूत केंद्र के अधीन सभी एकक आते हैं और इन्हें सेवक एकक के रूप में सहयोजित किया जाता है। कांग्रेस ने भी केंद्रीयकृत नियंत्रण के एक राजवंश के हाथों में आ जाने के बाद से इसी नमूने का पालन किया है।

परंतु जिस प्रकार से भाजपा को संगठित किया गया है और भारतीय जनसंघ के दिनों से पिछले 47 वर्षों के दौरान इसने कार्य किया है उससे यह बात पूरी तरह से मिथ्या साबित होती है कि एक बाहरी केंद्र भाजपा को 'रिमोट' से नियंत्रित कर रहा है। जब हमारे विरोधी यह कहकर हमारी आलोचना करते हैं तो वे अपना नमूना हम पर थोपने का प्रयास करते हैं।

रा. स्वं. सं. को भाजपा को रिमोट से नियंत्रित करने में कोई रुचि नहीं है; परंतु भाजपा उसे अपने नैतिक दिग्दर्शक के रूप में देखता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमसे यह आशा करता है कि हम अपने आपको राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दें। वह हमसे उम्मीद करता है कि हम विलासपूर्ण जीवन की अपेक्षा सादा जीवन व्यतीत करें। वह हमसे यह भी अपेक्षा रखता है कि हम सादगीपूर्ण एवं सदाचारी बनें। संघ की हमसे केवल यही आशा है।

1998 के चुनाव का तात्पर्य

1998 के आम चुनाव भारत के चुनावी इतिहास में निर्णायक साबित हुए हैं। हमने 'स्थायी सरकार और योग्य नेतृत्व' के संकल्प पर चुनाव लड़ा। लोगों का जनादेश यह बताता है कि वे केवल भारतीय जनता पार्टी को ऐसे दल के रूप में पहचानते हैं जो देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता ला सकता है और देश को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों की जीत इन मध्यावधि चुनावों का एक मात्र परिणाम है। इस चुनाव ने लोगों पर थोपे गए संयुक्त मोरचा और कांग्रेस पार्टी के बीच हुए पूर्णतः अवसरवादी गठजोड़ को समाप्त कर दिया। देश के चुनावी इतिहास में एक और ऐतिहासिक, निर्णायक तथा समान रूप से महत्त्वपूर्ण परिणाम यह निकला है कि भाजपा उस कांग्रेस पार्टी के विकल्प के रूप

में एक वास्तविक राष्ट्रीय विकल्प बनकर उभरी है जिसने पिछले 50 वर्षों में से लगभग 45 वर्षों तक भारत में शासन की बागडोर सँभाल रखी और अभी हाल तक वही राष्ट्रीय विकल्प बनी हुई थी।

प्रथम वास्तविक गैर-कांग्रेसी सरकार

हमने 1951 में भारतीय राजनीति का एक प्रमुख ध्रुव बनकर उभरने का स्वप्न देखा था। 1998 में हमने वह स्वप्न साकार कर दिखाया है। भारत की प्रथम वास्तविक गैर-कांग्रेसी सरकार ने श्री वाजपेयीजी के सुयोग्य नेतृत्व में राष्ट्र के कामों का दायित्व सँभाला है।

हमारे विरोधियों ने वहीं पुराना मिथ्या प्रचार कर एक बार फिर से हमें अलग-थलग करने की कोशिश की। परंतु इस बार उनकी कोशिशें बेकार हो गई हैं। हमारे चुनाव पूर्व के सहयोगियों ने हमारा साथ दिया और चुनावों के बाद नए सहयोगी दल हमारे समर्थन के लिए आगे आए हैं। आज किसी और दल की तुलना में भाजपा के अधिक मित्र हैं इससे लोगों और राजनीतिक वर्ग के बीच हमारी बढ़ती हुई स्वीकार्यता का पता चलता है। विडंबना तो इस बात की है कि जिन लोगों ने हमें 1996 में अलग-थलग करने का प्रयास किया था और जो अपने उद्देश्य में सफल भी हुए थे, आज वही लोग अलग-थलग और परित्यक्त बन गए हैं।

हमने महत्त्वपूर्ण 25 प्रतिशत लोकप्रिय मत के अवरोध को पार कर लिया है और संसद् में अपनी संख्या बढ़ा ली है। अन्य विकल्प अर्थात् कांग्रेस पार्टी के मत आधार में और कमी आई है।

जहाँ तक संयुक्त मोरचा का प्रश्न है, उसमें जो कुछ भी टूट-फूट के बाद शेष बचा है, वह अपनी पहचान खोने के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। वह मूलतः केवल वाम मोरचा बन कर रह गया है। स्वयं वामपंथी दलों में कांग्रेस के साथ अपने संबंधों के मुद्दे को लेकर खलबली मचने की संभावना है।

वामपंथी असंगत बने

यहाँ राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान अवमूल्यन हेतु वामपंथी दलों के दुर्भावनापूर्ण योगदान के बारे में विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है। इतिहास द्वारा साम्यवाद और मार्क्सवाद को बार-बार अस्वीकार दिए जाने के बावजूद इन्होंने भारत में अपने चिंतन को सुधारा नहीं हैं।

वामपंथियों ने सदैव भाजपावाद-विरोधी राजनीति पर विचारधारा का मुलम्मा चढ़ाया है जिससे कांग्रेस और इसके प्रतिरूप दलों को भाजपा तथा इसके पूर्व जनसंघ की राष्ट्रवाद की राजनीति का विरोध करने की बौद्धिक शक्ति मिली है।

ऐसा नहीं कि इससे वामपंथियों को कोई लाभ हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि इन्हें अपने अप्रासंगिक हो जाने का भय सता रहा है और इसी वजह से वामपंथी 'सांप्रदाकिता' का विरोध करने के नाम पर भाजपा के विरोध में और अधिक तीखे तथा विषाक्त प्रहार कर रहे हैं।

पार्टी के भौगोलिक और सामाजिक समर्थन आधार का विस्तार

इन चुनाव परिणामों से तीसरा संकेत यह मिला है कि भाजपा के समर्थन आधार में भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से वृद्धि हुई है। पार्टी ने दक्षिण तथा पूर्व में उल्लेखनीय प्रगति की है और पूर्वोत्तर में भी सफलता प्राप्त की है। यद्यपि हमने अपने अनुसूचित जनजाति के सांसदों की संख्या में वृद्धि की है; परंतु महाराष्ट्र और राजस्थान में अपनी आकांक्षाओं पर खरा न उतरने के कारण हमारे अनुसूचित जाति के सांसदों की संख्या में कमी हुई है। इन दोनों राज्यों में मेरे सहयोगी इसके कारणों की समीक्षा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमें अगले चुनावों में अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

हमारी पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनावों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया है कि हम गुजरात में पुनः सत्तासीन हो गए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाई है तथा हम मेघालय की सरकार में भी शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर इन चुनावों में हमारी उपलब्धि कोई कम नहीं है।

तथापि, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी सफलता कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ हमारे गठबंधन के कारण है। हमने मिलकर काम किया और इससे हमें काफी सफलता मिली है। मुझे अब आशा है कि भाजपा और इसके सहयोगी दल भविष्य में सरकार में भी सामंजस्यपूर्वक मिलजुलकर काम करेंगे। कभी-कभार कुछ अड़चनें आना अवश्यंभावी है, परंतु हममें उनसे जूझने और उनपर काबू पाने की क्षमता है।

और आगे बढ़ना-हमारा लक्ष्य

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अब आप हमें प्राप्त हुए राजनीतिक समर्थन को मजबूत करें और आधार में वृद्धि करें। मैंने पहले भी कहा है कि हमने लंबी दूरी तय कर ली है, परंतु मैं एक बार फिर यह बात दोहराना चाहूँगा कि हमें अभी बहुत आगे जाना है। हमें उच्च लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और आनेवाले समय में उन लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि आप कांग्रेस और वामपंथी दलों के नापाक इरादों से सतर्क रहें। वे 1998 के जनादेश को पलटने का प्रयास कर सकते हैं। चूँकि कांग्रेस और वामपंथी दलों में घोर आंतरिक विरोधाभास हैं, अतः प्रत्यक्ष

और लोकतांत्रिक तरीकों से हमारी सरकार को चुनौती देना उनके लिए कठिन होगा। परंतु वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिकतम षड्यंत्रकारी तरीकों का सहारा अवश्य लेंगे। कुल मिलाकर इस प्रकरण में वामपंथियों की भूमिका महाभारत के शकुनि जैसी होगी जिसकी गलत मंत्रणा से कौरवों को पराजय और शर्म का सामना करना पड़ा था।

गठबंधन की राजनीति : चुनौती और अवसर

हमने केंद्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन बनाया है, उसे एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में देखना चाहिए। यह एक चुनौती इसलिए है, क्योंकि यह गठबंधन के प्रयोजन की एकता और संयोजनशीलता को मजबूत बनाने और उसे कायम रखने की हमारे दल की क्षमता की कसौटी होगा। चूँकि इस गठबंधन में हमारा दल सबसे बड़ा घटक है और वास्तव में इस गठबंधन का मूल उत्तरदायित्व न केवल नई दिल्ली में बैठे दल के नेताओं का है, बल्कि समान रूप से सभी स्तरों पर सभी कार्यकर्ताओं का भी है।

परंतु केंद्र में सत्तारूढ़ हमारा गठबंधन इस प्रकार एक अवसर भी है क्योंकि भारत की एक महान् उपलब्धि अर्थात् इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने पहली बार भाजपा को एक संस्थागत संदर्भ उपलब्ध कराया है, जिसमें इसे अनेक राजनीतिक दलों से संपर्क करने का अवसर मिला है। ये दल हमारे समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

समान राष्ट्रीय उद्देश्य

अब हम गठबंधन सरकार में भागीदार बनकर उन्हें अपने विश्वास, परंपराओं और अपने लोगों की अधिक अच्छी तरह जानकारी दे सकते हैं। साथ ही अपने भागीदारों और जिन लोगों का प्रतिनिधित्व ये दल करते हैं, उनको समझने का भी यह एक अवसर है। यह साँझी आवश्यकता पर आधारित संपर्क के आधार पर एक शक्तिशाली और साँझा राष्ट्रीय प्रयोजन उभरकर सामने आएगा।

यहाँ सावधानी का एक शब्द कहना उचित होगा। मैंने पहले ही भाजपा के नेतृत्ववाली गठबंधन सरकार की कुछ आरंभिक अड़चनों का जिक्र किया है। इससे इस बात के जोर पकड़ने का खतरा है कि यह तो एक झगड़ा करनेवाला गठबंधन है जिसके कुछ घटक दल अन्य दलों के साथ सहमत नहीं है। यदि इस प्रकार की बात जोर पकड़ती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

शासन का राष्ट्रीय एजेंडा

गठबंधन सरकार के प्रत्येक घटक दल ने अपने-अपने चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर आम चुनावों में भाग लिया था। परंतु चुनावों के बाद सरकार को

सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमने विचार-विमर्श करके एक समान कार्यक्रम तैयार किया है। हमने इसे 'शासन का राष्ट्रीय एजेंडा' की संज्ञा दी है। यह उन मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम है जिसके बारे में सभी दल सहमत हैं। इसमें कुल मिलाकर वह कार्यक्रम शामिल है जिसका उल्लेख हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में किया है।

इस एजेंडा का मूलभूत सिद्धांत पूर्ववर्ती सरकारों की टकराव की नीति के विपरीत आम सहमति तथा सहयोग के साथ काम करना है। चूँकि हम सब की इस एजेंडे पर सहमति है, अतएव इसकी क्रियान्विति के बारे में मुझे विवाद की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। फिर भी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि श्री वाजपेयी और श्री आडवाणी सफलतापूर्वक यह कार्य संपन्न करेंगे।

हमारे कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए कि एक गठबंधन की सरकार को अनेक मजबूरियों के अंतर्गत कार्य करना होता है। हमें परिस्थिति के प्रति वास्तविकता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि हम एक संयुक्त सरकार के भाग हैं तथा भाजपा इतना ही कर सकती है, इससे अधिक नहीं।

इसके साथ ही, अपनी मजबूरियों के कारण हम अपने मूल सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकते। और यह हमने सिद्ध भी कर दिया है—उदाहरण के लिए, सार्वजनिक जीवन में शुचिता एवं ईमानदारी के विषय में हम दृढ़ हैं। न ही हम कभी राष्ट्र तथा जनता की सुरक्षा से कोई समझौता करेंगे।

राष्ट्रीय एजेंडा का महत्त्व

इस प्रकार के स्वरूप और संरचना की गठबंधन की सरकार चलाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। परंतु इस कार्य को हम शासन के राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में एक साँझा आधार बनाकर सरकार के सभी घटकों के सहयोग से पूरा कर रहे हैं।

समन्वय की राजनीति

हमारे कई सहयोगियों की विचारधारा संबंधी तथा राजनीति पृष्ठभूमियाँ भिन्न हैं। हमारे विरोधियों ने प्रयत्न किया—और कुछ समय के लिए वे सफल भी हुए—कि हमें भारतीय राजनीति में अलग-थलग कर दें और किसी भी प्रकार यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दल हमारा समर्थन करने और हमें सहयोग देने को तैयार न हो। परंतु हमने उनकी यह निंदनीय योजना चकनाचूर कर दी और ऐसे दल के रूप में उभरकर सामने आए जो भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल सकता है।

वास्तव में राष्ट्रीय एजेंडा—जो केवल आठ पृष्ठों का एक संक्षिप्त दस्तावेज है, समन्वय की राजनीति का एक उत्कृष्ट नमूना है।

भाजपा के अतिरिक्त किसी भी अन्य दल ने इतने दृढ़ विश्वास के साथ नहीं कहा कि भारत की समस्याएँ इतनी जटिल और अधिक हैं कि उनका हल किसी एक दल द्वारा किया जाना संभव नहीं हैं। किसी भी अन्य दल ने भाजपा की तरह इतना उत्कट अनुरोध नहीं किया कि राष्ट्र के सभी बड़े मुद्दों के हल के लिए राष्ट्रीय आम सहमति स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

तो फिर हमने ऐसा क्यों किया? हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि अपने राष्ट्रीय एजेंडा में समाविष्ट समन्वय के आधार पर अपनी नीतियों का नव-निर्माण करके ही भारत एक महान् देश बन सकता है। यह कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। परंतु हमारी शक्ति हमें इन संकटों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। हमारा व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य हमें विविध हितों को एकीकृत तथा समन्वित करने और हमारी शक्ति को और भी ऊँचाइयों पर ले जाने का काम करेगा।

आंतरिक सुरक्षा

भारत की एकता एवं निर्दोष नागरिकों के जीवन को खतरा पहुँचानेवाली आतंकवादी, विघटनकारी तथा अलगाववादी कार्यवाहियों के प्रति वर्षों तक सहिष्णुता का रुख अपनाए जाने के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। राज्य का एक सबसे महत्त्वपूर्ण दायित्व देश के सामान्य नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। पूर्व की सरकारें चुनाव की राजनीति तक सीमित अपने संकुचित दृष्टिकोण के कारण यह उत्तरदायित्व निभाने में असफल रही हैं।

आई. एस. आई. की घुसपैठ

परिणामस्वरूप, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई. एस. आई. हमारे देश में दूर-दूर तक घुसपैठ कर गई है। कश्मीर से उत्तर-पूर्व तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक, आई. एस. आई. ने आंतक फैलाने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित कर लिया है। कुछ ही समय पूर्व, तमिलनाडु और केरल में आई. एस. आई. समर्थित इसलामी कट्टरपंथी संगठनों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों का फैलाव हमने देखा। इन संगठनों के षड्यंत्रों ने श्री आडवाणी को भी अपना लक्ष्य बनाया। कोयम्बतूर में उनका जीवन लेने का जो कायरतापूर्ण प्रयास किया गया, वह भगवान् की दया से असफल हो गया। दुर्भाग्य से इस घटना में 50 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हाल ही में मदुरई में कट्टरपंथियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के एक वरिष्ठ नेता की हत्या कर दी। तमिलनाडु सरकार इस

समस्या का मुकाबला करने में असफल प्रतीत होती है और दिन-प्रतिदिन यह समस्य बढ़ती ही जा रही है।

अब निश्चित प्रमाण सामने आए हैं कि उत्तर-पूर्व में अलगाववादी हिंसा फैलाने में आई. एस. आई. का हाथ है। इस बात का प्रमाण है कि आई. एस. आई. ने उत्तर प्रदेश में घुसपैठ की है। लगभग दस वर्ष से आई. एस. आई. का जम्मू और कश्मीर के खून-खराबे में हाथ चल रहा है। दिल्ली में आई. एस. आई. द्वारा नियोजित कई बम विस्फोट हुए हैं।

भारत की नरम राष्ट्र की छवि

हमारे देश के शत्रु इसलिए अधिकाधिक ढीठ हो गए हैं, क्योंकि भारत को एक ऐसे नरम राष्ट्र के रूप में देखा जाता है जो कठोर निर्णय लेने में असफल है। पुरुलिया में गिराए गए हथियार उन लोगों की बढ़ती हुई उद्दंडता का प्रमाण हैं जो भारत की एकता और अखंडता को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। हाल में, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह के निकट हथियारों व बारूद से लदा एक जहाज पकड़ा गया था। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, सरकार को अपराधियों की पहचान करनी चाहिए और जनता के समक्ष सारे तथ्य रखने चाहिए। मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार यह कार्य करेगी।

नक्सलवादी ग्रुप

चिंता का एक और विषय आंध्र प्रदेश, बिहार तथा कुछ अन्य राज्यों में विभिन्न नक्सलवादी दलों की हत्याकारी कार्रवाइयाँ हैं। 'वर्ग संघर्ष' के नाम पर वे केवल ऐसी हिंसा फैलाने में ही सफल हुए हैं जो अपने आप बढ़ती जाती है। समस्याओं को सुलझाने के स्थान पर उन्होंने अपने कार्य-क्षेत्र के राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्याएँ और भी बढ़ा दी हैं।

अवैध घुसपैठ

हमारी पूर्वी सीमा के पार से लगातार बड़े पैमाने पर होने वाली गैर-कानूनी घुसपैठ से हमारी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और अधिक खराब हो गई है। सीमा-पार की इस लगातार घुसपैठ के लिए मुख्यतः कांग्रेस तथा हमारे अन्य विरोधियों की वोट की राजनीति उत्तरदायी है। कुछ समय पूर्व, सरकारी आँकड़ों के अनुसार इन घुसपैठियों की संख्या 1.7 करोड़ तक पहुँच गई थी। उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल और बिहार में आर्थिक और सामाजिक तनाव पैदा करने के अतिरिक्त, बेरोक-टोक घुसपैठ से आंतरिक सुरक्षा को भी भारी खतरा पैदा हो गया है। इसपर समुचित ध्यान न देना आपदा को आमंत्रित करना होगा।

सरकार के उपयुक्त कदम

मुझे यह कहने में प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक तत्त्वों एवं आई. एस. आई. के खतरे का मुकाबला करने तथा जनता में सुरक्षा की भावना पुनः पैदा करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। गृहमंत्री श्री आडवाणी ने बहु-प्रयोजनीय पहचान-पत्र का वादा किया है। उन्होंने गुप्तचर सूचना प्रणाली को सक्षम बनाने और सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए कदम उठाए हैं।

इस संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "हम देश के सभी भागों में सब नागरिको की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम एक दंगा-मुक्त व्यवस्था तथा आतंकवाद रहित भारत बनाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाएँगे।" आतंकवाद से लड़ने के लिए यदि राजनीतिक साहस जुटाने की आवश्यकता पड़ी, तो भूतपूर्व सरकारों के विपरीत हमारा शासन इसमें खरा उतरेगा।

आंतरिक सुरक्षा के एक और पहलू पर ध्यान देने की अतीव आवश्यकता है, और वह है कानून तथा व्यवस्था की स्थिति। देश के विभिन्न भागों में समाज-विरोधी तत्त्वों और भूमिगत माफिया की कार्रवाइयों के कारण मानव जीवन और संपत्ति को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस स्थिति से निपटने, कानून और व्यवस्था तंत्र को सुधारने तथा निर्दोष नागरिकों की रक्षा में होनेवाली त्रुटियों के लिए उसे जिम्मेदार बनाने की आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर : एकीकरण की समस्याएँ

पूर्वोत्तर के सात राज्यों की, जो 'सात बहनों' के नाम से जाने जाते हैं, बहुत अरसे से उपेक्षा की जाती रही है। मैं आर्थिक उपेक्षा की बात नहीं कर रहा। वास्तव में, वहाँ के विकास के लिए केंद्र ने हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं; परंतु इसमें से बहुत कम पैसा उन लोगों की भलाई के लिए खर्च हुआ है जिनके लिए यह भेजा गया था। अधिकतर पैसा भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और बेईमान नौकरशाह हड़प गए हैं।

पूर्वोत्तर की वर्तमान विभाजनकारी और उपद्रवग्रस्त स्थिति की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो अंग्रेजों के और उनसे भी पहले के दिनों से चली आ रही है। यह क्षेत्र छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था जो विभिन्न स्थानों पर शासन करते थे। जब अंग्रेजों ने अपनी उपनिवेशी जकड़ बढ़ानी प्रारंभ की तो टकराव हुआ और केंद्रीय सत्ता से ये लोग विमुख हो गए।

भारत के स्वतंत्र होने पर आशा जगी कि प्रजातंत्र से स्व-शासन की संस्थाओं का प्रादुर्भाव होगा तथा पूर्वोत्तर के लोगों और राष्ट्रीय मुख्य धारा के बीच संपर्क एवं नए सेतु बनेंगे। यदि नई दिल्ली ने उन्हें समझने और उनकी परवाह करने का

अविचल प्रयत्न किया होता तो शेष भारत के साथ पूर्वोत्तर का कहीं अधिक विकासात्मक और भावात्मक विलय हो गया होता। परंतु दुख की बात है कि ऐसा नहीं हुआ।

आधारभूत समस्याएँ

पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की समस्याएँ अन्य राज्यों के लोगों की समस्याओं से भिन्न हैं और यही शेष भारत से उनके अलगाव की भावना का कारण है। एक ओर तो विकास की समस्याएँ हैं जो मूलतः आर्थिक स्वरूप की हैं। इन राज्यों की भारत के अंतःस्थल से भौगोलिक दूरी तथा इस दूरी को पाटनेवाले साधनों का अभाव इसका एक और कारण है।

आर्थिक वंचना से शासन के विरुद्ध क्रोध उत्पन्न होता है। भौगोलिक दूरी एक प्रकार का मानसिक विलगाव पैदा करती है। दोनों मिलकर पृथकतावादियों और आंतकवादियों का शिकारगाह बन जाते हैं। अतएव, सरकार को दोनों ही पहलुओं पर ध्यान देना होगा। विकास की गति भी बढ़ानी होगी और भौगोलिक दूरी कम करने के लिए संचार आदि सांधनों का प्रबंध भी करना होगा। तभी शेष भारत से उनकी मानसिक दूरी भी कम होगी। हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि ये सब राज्य हमारे सीमावर्ती राज्य हैं और इसलिए इनका सामरिक महत्त्व है। एक तीसरा पहलू जो एकीकरण को सुदृढ़ कर सकता हैं, वह इस क्षेत्र की प्रजातंत्रीय व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

सामाजिक–आर्थिक समस्याओं को उच्च प्राथमिकता

हमारे घोषणा–पत्र में इस क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक समस्याओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाएगी। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन राज्यों के लोग भी भारतीय हैं और जब तक सरकार उनकी उचित देखभाल नहीं करती, उनमें देश के लिए उनके महत्त्व की भावना नहीं भरती और भारतीय समाज की मुख्यधारा के साथ उन्हें नहीं जोड़ती, हम उनसे सरकार के प्रति निष्ठा की आशा नहीं कर सकते। सरकार के लिए यह एक चुनौती है।

अपनी ओर से पार्टी ने पूर्वोत्तर में एक राज्य को छोड़कर अपने संगठनात्मक ढाँचे का विस्तार किया है। इस बार, सभी स्थानों पर हमने सब जगह संगठनात्मक चुनाव कराए हैं। निर्वाचनों की दृष्टि से भी हमारी स्थिति सुधरी है। अब हमें एकीकरण की प्रक्रिया में अधिक भूमिका निभानी है।

जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान

जैसा कि हाल की घटनाओं से ज्ञात होता है कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति

काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और वहाँ अभी शांति के लिए कोई आधार नहीं है। वहाँ पर कार्यरत चुनी हुई सरकार की मदद से आतंकवादी गतिविधियों पर कुछ अंकुश लगा है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ आतंक फैलाने के लिए आर्थिक सहायता और अस्त्र-शस्त्र देना जारी रखे हुए है।

विशेष चिंता यह है कि वहाँ हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार जारी है। जनवरी में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर श्रीनगर के निकट 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। 17 अप्रैल की रात ऊधमपुर जिले के प्राणकोट गाँव में 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। इस नरसंहार और आक्रमण का मुख्य उद्देश्य राज्य में आतंक कायम कर वहाँ से हिंदुओं को पलायन के लिए विवश करना है। पहले ही 2.5 लाख हिंदू घाटी से पलायन कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। भारी संख्या में निर्दोष मुसलमान भी इन आतंकवादियों के शिकार हुए हैं।

आतंकवाद की समाप्ति—प्रथम लक्ष्य

सदा के लिए यह स्थिति रहने नहीं दी जा सकती। जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से खून-खराबा होता आ रहा है। अब वहाँ स्थायी शांति कायम करने का समय आ गया है। राज्य सरकार, सुरक्षा बलों तथा केंद्रीय सरकार के सक्रिय सहयोग से ही इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि भावी पीढ़ियों का गत दशकों की असहाय वेदना से बचाना है तो इस राज्य से आतंकवाद को निकाल बाहर करना होगा।

कश्मीरी हिंदू

मैं केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का आह्वान करता हूँ कि वे एक ऐसा पैकेज तैयार करें जिससे कश्मीरी हिंदू पूरे आदर, सम्मान तथा सुरक्षा से अपने पूर्वजों की भूमि को लौट सकें। जब तक ऐसा संभव न हो उनके कल्याण की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।

पाकिस्तान के साथ सख्त रवैया अपनाना होगा

हमें पाकिस्तान के साथ भी सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि वही सीमा-पार से विदेशी भाड़े के सैनिक तथा हथियार भेजकर जम्मू-कश्मीर में निरंतर आतंक फैला रहा है। भारत और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध तभी संभव हैं जब पाकिस्तान भारत में हिंसा फैलाने की अपनी नीति त्याग दे। स्थिति पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान को समझाने में विलंब नहीं करना चाहिए।

पाकिस्तान और भारत का विदेशी सुरक्षा परिदृश्य

आई. एस. आई. के माध्यम से भारत में सीमा-पार से आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने पर भी संतुष्ट न होकर पाकिस्तान ने अब मध्यम दूरी की सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को गौरी नाम दिया है तथा यह दावा किया है कि यह मिसाइल 1500 कि.मी. तक मार कर सकती है तथा इसकी लोड क्षमता 700 कि.ग्रा. है।

यह केवल धमकी देने या बाज़ी मारने की बात नहीं है। पाकिस्तान के इसमें दो उद्देश्य हैं—पहला यह कि उसने विश्व को यह दिखाया है कि इसके पास परमाणु 'वार हेड' सहित भारतीय लक्ष्यों पर मार करने की क्षमता हैं; तथा दूसरा यह कि इस्लामाबाद ने दिल्ली को एक राजनीतिक संदेश भेजा है जिसकी इतिहास में जड़ें हैं।

शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी पहला मुसलमान हमलावर था जिसने 1191 में दिल्ली पर हमला किया था। पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा तो दिया लेकिन उसे जीवन दान दे दिया। गौरी एक वर्ष बाद फिर लौट आया तथा धोखे से पृथ्वीराज चौहान का हरा दिया, और भारत में विदेशी शासन की नींव डाली। गौरी मिलाइल का परीक्षण करके पाकिस्तान ने हमें यह याद दिलाया है कि इतिहास दोहराया जा सकता है।

हम इस धमकी को नजरअंदाज करके देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब हम अपने सुरक्षा-हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। 1962 की करारी हार की दुःखद स्मृतियाँ अभी भी ताजा हैं। हमें अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में भी सचेत रहना है।

हमारे सुरक्षा हित

शीत युद्ध के बाद की दुनिया में हमें अपने सुरक्षा हितों को स्वयं ध्यान रखना होगा तथा शत्रु का मुकाबला करने में किसी भी तरह उससे पीछे नहीं रहना होगा। इस क्षेत्र में तथाकथित शांति बहाल करने के हामी भरने वाले वे देश जो व्यापक परमाणु निषेध संधि (सी टी बी टी) तथा परमाणु अप्रसार संधि (ए पी टी) जैसी भेदभावजनक संधियों को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आक्रामक रुख सदैव अनदेखा किया है।

यह एक वास्तविकता है तथा हमें इसका डटकर मुकाबला करना है। हमारी सरकार ने एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के गठन के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। यह उचित होगा कि हमें 'अग्नि' और 'पृथ्वी' मिसाइलों के निर्माण और तैनाती के मामले में पश्चिमी देशों के दबाव में हर्गिज नहीं आना चाहिए। हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए और गौरी मिसाइल के झाँसे में नहीं आना चाहिए।

मित्रो, भाजपा ने हमेशा अन्य देशों की शांति और खुशहाली में विश्वास किया है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे तथा सार्थक संबंध रखने में विश्वास करते हैं। किंतु देश के हितों और सुरक्षा की कीमत पर कोई स्थायी संबंध कायम नहीं किए जा सकते। वास्तव में यह हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय झाँसे में नहीं आना चाहिए।

लोकतंत्र की संस्थाएँ तथा हमारा संविधान

कोई भी लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब उसकी संस्थाएँ शाक्तिशाली हों। पिछले लगभग तीन दशकों में हमारे देश में इन संस्थाओं-कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका ने अपना महत्त्व खो दिया है तथा उनमें काफी गिरावट आई है। हाल के वर्षों में कार्यपालिका के उच्च पदों में भ्रष्टाचार तथा इन संस्थाओं में आपसी लड़ाई के कारण स्थिति काफी खराब हुई है। राजनीति का अपराधीकरण तथा चुनावों में बाहुबल तथा धन के बढ़ते इस्तेमाल से हमारे विधानमंडलों की काफी हानि हुई है। हमें अपनी राजनीति में से दलबदल की कुप्रथा को समाप्त करने की भी आवश्यकता है।

हमारे लोकतंत्र के तीनों स्तंभों की सुपरिभाषित भूमिका है। लेकिन साथ ही अपरिभाषित क्षेत्र एवं शक्तियाँ भी हैं। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए इन्हें अपने कार्यकरण में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि इनमें आपस में सतत संघर्ष रहेगा अथवा वे अन्य की अपेक्षा स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के प्रयास करती रहेंगी तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। इससे भी बुरी बात यह होगी कि इससे इन संस्थाओं की गरिमा कम होगी तथा इनके प्रति जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा।

चुनाव सुधारों की तत्काल आवश्यकता

कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका हमारी प्रतिष्ठित संस्थाएँ हैं तथा इनकी गरिमा को बहाल किया जाना आवश्यक है। ऐसा किसी एक दल द्वारा नहीं किया जा सकता; इसके लिए सर्वदलीय प्रयास किए जाने की जरूरत है। पिछले कई वर्षों से हम व्यापक चुनाव सुधारों के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल नाम मात्र के ही परिवर्तन किए गए हैं।

वर्तमान सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस दिशा में त्वरित कारंरवाई करे, ताकि गोस्वामी समिति की रिपोर्ट को आदेश-दस्तावेज समझें। उक्त सुधार ईमानदार तथा योग्य पुरुषों एवं महिलाओं को विधानमंडलों में भेजने में मील का पत्थर साबित होंगे।

राज्यपाल का पद भी एक ऐसी संस्था है जिसकी विश्वसनीयता में कमी आई है। पूर्ववर्ती सरकारों ने राज भवनों को केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विस्तार-महलों

में परिवर्तित कर दिया था तथा विधिवत् रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों को अपदस्थ करने के लिए अनुच्छेद 356 का खुलकर दुरुपयोग किया था। उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के मामले तो इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं। हमने राज्यपालों को कतिपय मुख्यमंत्रियों के भ्रष्ट तरीकों का समर्थन करते हुए भी देखा है।

इनमें से अधिकांश राज्यपालों के स्थान पर अब निर्विवाद रूप से ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया है और मुझे विश्वास है कि ये लोग संवैधानिक औचित्य के अनुरूप कार्य करेंगे। आइए, हम राज्यपाल के पद को उसका यथोचित सम्मान बहाल करने का तरीका सुझाएँ।

संविधान समीक्षा

हमने विशेषज्ञों का एक ऐसा आयोग गठित करने का वचन दिया है जो संविधान के ऐसे कतिपय प्रावधानों की पुनरीक्षा करेगा जिनकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है या जिन प्रावधानों में परिवर्तित समय के अनुरूप संशोधन की आवश्यकता है। संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप एक जीवंत दस्तावेज बनाया जाना परमावश्यक है। कई पक्षों द्वारा इन परिवर्तनों के रूपारूप के बारे में आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं। मुझे इन आशंकाओं का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि संविधान के 'आधारभूत ढाँचे' में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है।

हमें एक ऐसे संविधान की जरूरत है जो सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था एवं साधन, दोनों ही हो। इसलिए, पिछले पाँच दशकों के अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय प्रावधानों की नई सिरे से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है।

केंद्र-राज्य संबंध और छोटे राज्य

केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद का युग समाप्त हो चुका है। हम एक नए युग के प्रवेश द्वारा पर खड़े हैं, जिसमें मजबूत केंद्र तथा मजबूत राज्य एक साथ मिलकर सुदृढ़ भारत के निर्माण की दिशा में एकजुट होकर कार्य करेंगे।

सरकारिया आयोग रिपोर्ट का कार्यान्वयन

हमने सदैव सौहार्दपूर्ण केंद्र-राज्य संबंधों, राज्य सरकारों के लिए और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता तथा सबसे निचले स्तर तक विकेंद्रीकरण की वकालत की है। अब इन्हें मूर्तरूप देने का समय आ गया है। हमारे समक्ष सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पहले से ही है परंतु इन वर्षों में इसपर कोई काररवाई नहीं की गई। इस दिशा में पहला कदम इस रिपोर्ट को लागू करना तथा कालातीत अंशों को अद्यतन बनाया जाना है।

हमारे लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि हम मुख्यमंत्रियों के लिए छोटी-से-छोटी स्वीकृतियों तथा मंजूरियों के लिए दिल्ली भागने की पुरानी प्रथा को समाप्त करें। श्री वाजपेयी राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में मुख्यमंत्रियों के लिए विशेष रूप से आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निर्णय लेने के संबंध में और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की बात पहले ही कह चुके हैं। अब इसे अंतर-राज्य परिषद् के मंच के माध्यम से एक ठोस रूप प्रदान किया जाना जरूरी है।

नए राज्यों का गठन

मैं इस बात का उल्लेख भी करना चाहूँगा कि उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ के गठन में अब और अधिक विलंब नहीं किया जा सकता। छोटे राज्यों से संतुलित विकास, प्रभावी प्रशासन और जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र तथा 'शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा' दोनों में ही इन नए राज्यों के गठन के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई है। आशा है कि इन कदमों से इन क्षेत्रों की जनता बहुत लाभान्वित होगी और इन सभी दशकों के दौरान वे जिस विकास से वंचित रहे हैं, अंततः वे अब इसका लाभ उठा पाएँगे।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहु-आयामी अभियान की आवश्यकता

सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार भारत के त्वरित एवं समानतावादी आर्थिक विकास के मार्ग में एक प्रमुख समस्या है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब तक के संघर्ष से यह पता चलता है कि यह मामला मुख्यतः विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष के एक भाग के रूप में ही उठाया गया है। इस संघर्ष को कभी-कभार व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हो जाता है और यह एक जन अभियान बन जाता है। इसकी परिणति सरकारों के परिवर्तन में भी हो जाती है।

परंतु क्या इससे इस समस्या को हल करने में कोई मदद मिली है? नहीं। उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार अपनी सभी सीमाएँ पार कर गया है और निचले स्तर पर चिंताजनक रूप में फैल गया है। ऐसा क्यों हुआ है? इसका कारण यह है कि राजनीतिक स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान, चार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए एक सुव्यवस्थित तरीके से चलाये जाने की आवश्यकता है—

- सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था में कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है। जब तक हमारी अर्थव्यवस्था अभावों और कमियोंवाली अर्थव्यवस्था रहेगी तब तक भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ भी बनी रहेंगी।
- दूसरे, किसी भी कार्य में विलंब से लोग भ्रष्ट तरीके अपनाने लिए बाध्य हो जाते हैं, हालाँकि कई बार वह उनकी इच्छाओं के विरुद्ध होता है। हमें

सभी स्तरों पर उपयुक्त प्रशासनिक और न्यायिक सुधार करके विलंब के अवसर उत्पन्न नहीं होने देने चाहिए। निर्णय लेनेवाले निकायों में ऐसी प्रक्रियाएँ बनाई जानी चाहिए, जिनमें पारदर्शिता हो और निर्णय लेनेवालों की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए।

- तीसरे, जब तक नैतिकता की पुनः प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी और किसी भी गलत कार्य का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिरोध नहीं होगा तब तक हम चाहे कितने भी कानून बना लें और प्रशासनिक कदम क्यों न उठा लें, हम भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते हैं। आज से पचास वर्ष पूर्व किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति की उसके संगठन समुदाय और समाज द्वारा भर्त्सना की जाती थी, परंतु आज स्थिति यह है कि समाज स्वयं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है।
- चौथा, सरकार को शीघ्र और पूर्वग्रह रहित जाँच, तुरंत मुकदमा चलाए जाने और कठोर दंड को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जा सके।

अर्थव्यवस्था की स्थिति और स्वदेशी तथा स्वावलंबन का महत्त्व

मित्रो, हमारी सरकार को जो अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है उसकी स्थिति अत्याधिक चिंताजनक है। लंबे समय से अर्थव्यवस्था में मंदी चली आ रही है। कृषि के विकास में ठहराव आ गया है। औद्योगिक उत्पादन में शिथिलता आई है। निर्यात में भी गिरावट आई है। हमारे बैंकों के पास 60,000 करोड़ रुपए के ऋण संसाधन होने के बावजूद हमारे किसान और उद्यमी, विशेषकर छोटे किसान और लघु उद्यमी, बैंकों से समय पर पर्याप्त वित्त प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

ब्याज की ऊँची दरों के साथ-साथ ऋण प्रदान करने की उचित व्यवस्था और बाजार सुविधाओं के अभाव में सेवाओं और पारंपरिक व्यवसायों के गैर-निगमित क्षेत्र अथवा 'भागीदारी क्षेत्र' को अपना इंतजाम स्वयं करने को मजबूर होना पड़ता है। यहाँ यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि कृषि और स्व-रोजगार के क्षेत्र, जिनमें अधिकतम उत्पादन रोजगार का सृजन करने के साथ-साथ एक समानतावादी आय वितरण की क्षमता है, लंबे समय तक नीतिगत उपेक्षा और संस्थागत उदासीनता के शिकार रहे हैं।

बीमार अथवा आवधिक रूप में ऋण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें हजारों करोड़ रुपए का सरकारी निवेश हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अपवहन और बाधक सिद्ध हुए हैं। निगमित क्षेत्र की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं रही है। सस्ता और आसान आयात, जिनमें से कुछ नए डब्ल्यू.टी.ओ. नियमों के कारण मजबूरन करने पड़े हैं, कई भारतीय उद्योगों के लिए एक खतरा बनकर सामने आए हैं। बासमती चावल और हल्दी के संबंध में हाल ही में उठे विवादों

से यह बात सामने आई है कि पेटेंट की नई उभरती हुई सत्ता हमारे कृषि और जैव-विविधतावाली संपदा के लिए एक खतरा है।

पिछली सरकार से मिली विरासत

स्थिति का डटकर मुकाबला करने और एक राष्ट्रीय मानस तैयार करने तथा हमारे समक्ष चुनौतियों के लिए राष्ट्र की अपनी आर्थिक स्थितियों के अनुरूप नीतियाँ बनाने के बजाय पूर्व कांग्रेस और संयुक्त मोरचा सरकारों ने एक मिथ्या और खतरनाक धारणा उत्पन्न कर दी कि भारत की समस्याओं का एकमात्र हल हमारी अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय निगमों, विदेशी निवेश, अनियंत्रित उपभोक्तावाद और डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा निर्धारित वैश्वीकरण एजेंडा के लिए मुक्त करने में ही है।

पूर्व सरकारों द्वारा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के अत्यधिक खराब प्रबंधन का एक उदाहरण भारत के ऊपर पहाड़ सा विदेशी कर्जे का होना है। हमारी परिश्रमपूर्वक कमाई गई विदेशी मुद्रा का पाँचवाँ भाग वार्षिक ऋण-सेवा में चला जाता है। यदि हम अनियंत्रित वैश्वीकरण के संभावित परिणामों को इसमें जोड़कर देखें तो हमें यह स्पष्ट नजर आ जाएगा कि मेक्सिको, कोरिया, थाईलैंड और अन्य देशों को हाल ही में जिन प्रमुख वाह्य-आरोपित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उनका सामना हमें भी करना पड़ेगा।

राष्ट्रीय स्वाभिमान का अभाव

इस भयावह स्थिति का मूल कारण यही है कि हमारे पिछले शासकों ने स्वदेशी (आर्थिक राष्ट्रवादिता) और स्वावलंबन (आत्मनिर्भरता) के मूल्यों का—जिन्होंने 1947 से पूर्व ब्रिटिश राज को चुनौती देने के लिए प्रत्येक देशभक्त भारतीय में शक्ति का संचार कर दिया था—परित्याग कर दिया। राष्ट्रीय आत्मविश्वास इस हद तक क्षीण हो गया है कि स्वाधीनता के 50 वर्ष बाद भी हम अपना राज-काज अपनी राष्ट्र भाषा हिंदी अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा में नहीं चला सकते हैं।

स्वावलंबन का महत्त्व

यह दृष्टिकोण भारत को गंभीर अव्यवस्था की ओर धकेल देगा। इसलिए इसे बदलना ही होगा। इसे सरकार के निर्णय लेनेवाले सभी अंगों, उद्योग और समाज में स्वदेशी और स्वावलंबन की भावना को आत्मसात् करके ही बदला जा सकता है। हमें फिर से यह जताना है कि भारत का निर्माण भारतीय ही कर सकते हैं। विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी का स्वागत है, पर हमारी राष्ट्र निर्माण आयोजना में वह सहयोगी और अनुषंगी भूमिका ही निभा सकते हैं। जहाँ इनकी जरूरत भी हो वहाँ राष्ट्रहित पूर्णतः सुनिश्चित करना होगा।

किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना

हमारे देश की लगभग तीन-चौथाई जनता गाँवों में रहती है और अभी भी कृषि ही भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड हैं। परंतु सरकारें इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा करती आई हैं। यहाँ तक कि हम खाद्य भंडार की दृष्टि से भी स्वयं को सुरक्षित नहीं मान सकते हैं।

हमारा लक्ष्य दोहरा होना चाहिए : हमें कृषि को अर्थव्यवस्था में उपयुक्त स्थान देना है और किसान-विरोधी प्रवृत्ति, जो अब तक सरकार की नीति के मूल में रही है, को बदलना है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाए और किसानों की समस्याओं पर अविलंब ध्यान दे।

विगत कुछ महीनों में हमने किसानों पर पड़ी आपदा देखी है कि किस तरह प्रकृति के प्रकोप के कारण उनकी फसलें नष्ट हुई हैं। किसानों को प्रभावी और व्यापक बीमा पॉलिसियों द्वारा बरबाद होने से बचाया जा सकता है। सरकार को इसपर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए, इसलिए भी कि हम देश के लाखों लोगों को अन्न पहुँचाने के लिए मेहनत करनेवाले इस वर्ग की सुरक्षा का पहले ही वचन दे चुके हैं।

कृषि उपज की अधिक लाभकारी कीमत देने की निरंतर माँग की जाती रही है। खाद्यानों की लागत बढ़ने से किसान निस्संदेह अधिक कीमत पाने के हकदार हैं। मुझे खुशी है कि सरकार गेहूँ की कीमतों में वृद्धि की पहले ही घोषणा कर चुकी है।

परंतु हमें भूमिहीन किसानों और कृषि मजदूरों की जरूरतों और उनके हितों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह भूमि सुधार और भूमि के पुनर्वितरण के काम में तेजी लाये क्योंकि स्वाधीन भारत का यह दायित्व अभी भी अधूरा पड़ा है।

कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया था कि हम निर्बल से निर्बल व्यक्ति तक पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी का यह एक राजनीतिक नारा मात्र नहीं है। यह हमारे सामाजिक दर्शन, जो पूर्ण मानवतावाद के मूल में हैं, में रचा-बसा है। हमने राजनीति का उपयोग सामाजिक बदलाव और हमारे समाज की सभी बुराइयों का उन्मूलन करने के साधन के रूप में करने का सदैव प्रयास किया है। हमारा प्रयास समाज के प्रत्येक वर्ग को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने का रहा है।

सामाजिक समरसता का मार्ग

परंतु हमने सामाजिक संघर्ष और टकराव का रास्ता नहीं बल्कि सामाजिक

समरसता का रास्ता चुना है। हमारा उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों में समरसता लाकर उन्हें एक ऐसे संयुक्त समाज का रूप देना है जो शोषण और किसी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त हो। अलगाववाद और बहिष्करण की नीति अपनाने के बजाय हम मेल मिलाप का दृष्टिकोण अपनाकर समाज के विभिन्न घटकों को एकजुट करने की अनवरत माँग करते रहे हैं।

यह कुछ राजनीतिक दलों की जातिगत राजनीति के सर्वथा प्रतिकूल है। ये दल विशाल भारतीय कुल की एकता में नहीं बल्कि उसे टुकड़ों में बाँटने में विश्वास रखते हैं। ये दल मतभेद दूर करने में विश्वास नहीं करते बल्कि संघर्ष और टकराव को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं। उनकी नजर चुनाव जीतने तक सीमित रहती है। हमारा लक्ष्य जाति-विसंगतियों से मुक्त एक पुनरुत्थानशील भारतीय समाज की स्थापना है।

स्वामी विवेकानंद ने भारत के उत्पीड़ित वर्गों के बारे में कहा था, "इन आम व्यक्तियों ने हजारों वर्षों से उत्पीड़न भोगा है…उन्हें असीम पीड़ाएँ झेलनी पड़ी हैं।" स्वतंत्रता के पाँच दशकों के पश्चात् भी इनमें से अधिकतर लोग स्वतंत्रता के लाभ से वंचित हैं, उनमें से अधिकतर इस पीड़ा को चुपचाप सहते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका कोई दखल नहीं है।

यह सही है कि काफी परिवर्तन हुआ है। साथ ही यह भी सही है कि अभी भी हमारे समाज से व्यक्तिगत विकृति तथा भेदभाव के कलंक को मिटाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। नारायण गुरु महात्मा फुले और डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे महान् व्यक्तियों ने अपने जीवन से हमें जातिगत विकृति और विभेद से लड़ने का रास्ता दिखाया।

वंचित वर्गों को शक्ति-संपन्न बनाना

मित्रो, सरकारें इस बुराई से लड़ने के लिए कानून पारित कर सकती हैं। ऐसे कानूनों को कोई कमी नहीं है। वास्तव में, अमेरिका द्वारा नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में बनाए गए विधानों से बहुत पहले भारत में अस्पृश्यता और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक कानून बना था। परंतु कानून ही पर्याप्त नहीं है। जागरूकता बढ़ाने तथा वंचित वर्गों को शक्तियाँ प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यह कार्य हमारे जैसे राजनीतिक संगठन द्वारा ही किया जा सकता है।

हमने दस वर्ष पहले आगरा में अनुसूचित जाति की समस्याओं के संबंध में एक नीति अपनाई थी। उसके बाद हमने बंगलौर में एक सामाजिक घोषणा-पत्र पारित किया। विगत वर्षों में, हमने विधानमंडलों में, राज्य विधानसभाओं और संसद् में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया है।

इसी प्रकार, हम अनुसूचित जन-जातियों को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की माँग करने में सबसे आगे रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ

अलग-अलग तरह की हैं तथा इनसे अधिक गंभीरता से निपटना चाहिए। उन्होंने हमें वोट देकर भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पार्टी उन्हें निराश नहीं कर सकती।

कमजोर वर्गों में पार्टी का आधार-विस्तार

अब हमें समाज के इन कमजोर वर्गों में अपना आधार बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचना चाहिए तथा उन्हें उस बड़े और समतावादी भारतीय परिवार में शामिल करना चाहिए, जिसमें जातीय तथा जनजातीय वर्ग पूर्ण सद्भाव के साथ मिलकर रहें तथा वे एक-दूसरे से न झगड़ें।

सरकार ने अपनी तरफ से राष्ट्रीय एजेंडा के जरिए इन वर्गों को शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। मात्र संकेत से काम नहीं चलेगा, उनको अधिकार दिया जाना है, उनके मर्यादा के अधिकार की रक्षा की जानी है तथा उन्हें राष्ट्र की समृद्धि में बराबर का भागीदार बनाया जाना है।

नारी शक्ति के प्रति हमारी सुस्पष्ट वचनबद्धता

हम महिलाओं के अधिकारों को प्रोत्साहित करने तथा लिंग-भेद से मुक्त न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था की माँग करने में अग्रणी रहे हैं। वास्तविक विकास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से वास्तव में शक्तियाँ प्रदान नहीं की जातीं।

यद्यपि कानूनों से लिंग-भेद दूर करने में काफी हद तक मदद मिली है, फिर भी कानून लागू करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा तथा महिलाओं, जो देश की आधी आबादी हैं, की व्यापक क्षमता का सदुपयोग करने के लिए तंत्र विकसित करने होंगे।

परिवार और राष्ट्र, दोनों के लिए बालिका एक वरदान हैं, हमें उसे एक बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसका पालन-पोषण करना चाहिए तथा उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक योगदान देना चाहिए। यह समाज और राष्ट्र की संयुक्त जिम्मेदारी है। इस आदर्श को अपनाकर कई अल्प-विकसित और विकासशील देशों ने अत्यधिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

भारतीय जनता पार्टी ही पहली पार्टी थी जिसने सभी निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की माँग करके आधिकारिक रूप में एक औपचारिक संकल्प पारित किया था। यद्यपि 11वीं लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया था, किंतु इसपर कतिपय दलों की हठधर्मिता के कारण मतदान नहीं हो सका। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे शीघ्रातिशीघ्र

इस विधेयक पर चर्चा करवाए और इस मुद्दे पर सभी दलों की सहमति प्राप्त करे।

राष्ट्र के द्वार पर नवयुग की दस्तक

आक्रमणकारियों एवं औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा किए गए शताब्दियों के जन और धन के शोषण ने हमें विपन्न तो किया, किंतु इस राष्ट्र की आत्मशक्ति को नहीं तोड़ सके।

गरीबी और दरिद्रता

आज हमारे देश की एक-तिहाई से अधिक आबादी अत्यधिक गरीबी और दरिद्रता में रह रही है। करोड़ों लोग जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे हैं, जिनमें छत नहीं है। हजारों गाँवों में महिलाओं और बालिकाओं को एक बर्तन पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। अधिकांश लोग निरक्षरता, रोग, कुपोषण और भुखमरी से ग्रस्त हैं। नगरों में बेराजगार युवाओं की भरमार है। बच्चे स्कूल में जाने के बजाय खेतों तथा खतरनाक औद्योगिक एककों में कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा और पोषाहार की कमी के कारण प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे असमय मर जाते हैं। विश्व में हमारे यहाँ मातृत्व मृत्यु-दर सबसे अधिक है।

यह वह देश नहीं है जिसकी हमने आकांक्षा की थी। यह निश्चित रूप से वह देश नहीं है, जो हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए छोड़ जाना चाहते हैं।

आम आदमी पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता

संभव है कि स्वतंत्र भारत की राजनीति से तत्कालीन दलों तथा उनके नेताओं का हित साधन हुआ हो, परंतु आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं की ओर, जो उसकी जिंदगी से ही जुड़ी हुई है, किसी का ध्यान नहीं गया है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें भारतीय राजनीति के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन लाना होगा। टकराव की राजनीति को रचनात्मक मोड़ देना होगा। सभी दलों की मनोवृत्ति को बदलना होगा। यदि आम आदमी की हालत सुधारनी है तो हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा।

इसी भावना को ध्यान में रखकर तथा राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए आम सहमति के मार्ग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शासन का 'राष्ट्रीय एजेंडा' स्वीकार किया गया है, जिसका परिप्रेक्ष्य तात्कालिक राजनीतिक लाभ से आबद्ध नहीं है, अपितु राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कुछ मुद्दों के बारे में मोटे रूप में आम सहमति विद्यमान है और उन्हीं को लेकर कार्य आरंभ कर दिया गया है। आइए, अब हम अन्य मुद्दों पर भी आम सहमति जुटाएँ। हमने अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है, अब हमें प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा

है। देश की जनता ने बहुत दुःख उठाए हैं। आइए, हम सब मिलकर उनकी दशा सुधारने के लिए कार्य करें। यही मेरी प्रार्थना है।

पार्टी पर भारी उत्तरदायित्व

मेरे पूर्वाधिकारी ने मुंबई के पुणे अधिवेशन में यह भविष्यवाणी की थी कि भारत के भाग्य में यह लिखा है कि वह शक्तिशाली राष्ट्रवादी शक्तियों के नेतृत्व में 21वीं सदी में प्रवेश करेगा। वह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है; किंतु इससे हमारे ऊपर और हमारे मित्रों पर भारी जिम्मेदारी भी आन पड़ी है।

हम आशावाद और अवसर के नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, जो भारत को बुला रहा है। यदि हम इस अवसर से लाभ उठाकर और आशावाद पर अपना भवन बनाएँगे तो हम भारत को एक ऐसे नए युग में प्रवेश कराएँगे जो इस महान् राष्ट्र की खोई हुई कीर्ति को पुनः स्थापित कर देगा। यदि हम दृढ़ता से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहण करेंगे तो मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि 21वीं सदी भारत को एक बार फिर मानव प्रकाश के पुंज, मानव सभ्यता के उत्तुंग शिखर, साहस एवं मानवता के अनुकरणीय उदाहरण तथा एक सुस्थापित समाज के रूप में उदीयमान होते हुए देखेगी।

आइए, हम सब भविष्य के इस महान् एवं पुनीत कार्य के प्रति अपने आपको समर्पित करें।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

जयपुर 21-23 अगस्त, 1998

मैं पार्टी की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस प्रथम बैठक में आप सब का स्वागत करता हूँ।

मैंने मई में गांधीनगर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार असाधारण परिस्थितियों में सँभाला था।

भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वास्तविक प्रथम गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन किया था। स्वाभाविक है कि हमारे अनेक प्रतिभाशाली नेताओं को सरकार में कार्यभार सँभालने के लिए भेजा गया। परंतु इसके कारण हमें कोई अड़चन नहीं पड़ी, क्योंकि पार्टी में प्रतिभावान लोगों का भंडार है।

हम इस समय जयपुर के ऐतिहासिक नगर में बैठक कर रहे हैं, जबकि इस वर्ष बाद में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उचित ही होगा कि पिछले पाँच महीनों का लेखा-जोखा किया जाए और अपने अनुभव के आधार पर हम आनेवाले महीनों में अपने को तथा अपने कार्यकर्ता वर्ग को तैयार करें।

सरकार द्वारा उठाए गए महत्त्वूपर्ण कदम

मई और अगस्त के बीच बहुत सी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के गतिशील नेतृत्व में सरकार साँझा राजनीति की दुर्गम स्थितियों का प्रबंध करने की कड़ी कसौटी पर खरी उतरी है। पाँच परमाणु परीक्षणों के रूप में हमने निर्णायक कदम आगे बढ़ाए हैं। स्वदेशी आधारित जन-समर्थक बजट प्रस्तुत किया गया और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में यह पारित हुआ। सरकार ने आर्थिक प्रतिबंधों के प्रत्याशित प्रभावों से देश को कठिनाइयों से निकाला है। नई नीतियाँ और योजनाएँ अपनाई गई हैं, जो कमजोर और गरीब लोगों के लिए

लाभप्रद हैं। सामाजिक क्षेत्र में कम होते गए सरकारी निवेश की दिशा को उलट दिया गया है।

लगभग एक दशक की निष्क्रियता और आलस्य के कारण देश भर में हर तरफ आतंकवाद का नासूर फैल गया था; अब भारत की आंतरिक सुरक्षा की इस गंभीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक नया संकल्प और दृढ़ विश्वास पैदा हुआ है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पूर्वोत्तर-परिषद् को प्रभावकारी निकाय बना दिया गया है और इस क्षेत्र में धन का निवेश करने, विकास की गतिविधियाँ चलाने का एक नया पैटर्न तैयार किया गया है। नगालैंड में एक और वर्ष के लिए युद्ध विराम बढ़ा दिया गया, हालाँकि असम में आतंकवाद में तीव्रता और जातिगत संघर्ष देखने में आया है, परंतु समग्र रूप से इस क्षेत्र की स्थिति में सुधार हुआ है।

हमारे अनेक आलोचकों ने पिछले पाँच महीनों की बड़ी धुँधली तसवीर पेश की है। परंतु पिछले पाँच महीनों की सफलताएँ पिछले पाँच दशकों की असफलताओं से कहीं अधिक उज्ज्वल हैं। इस सरकार को विरासत में पिछले 50 वर्षों का कुशासन, खोए अवसर और गलतियाँ ही मिली थीं। केवल कोई अव्यावहारिक व्यक्ति ही 50 वर्ष की गलतियों को मात्र पाँच महीने में ठीक करने की आशा कर सकता है।

गठबंधन की सीमाओं के अंदर रहते हुए कार्य करना

निःसंदेह लोगों को इस सरकार से बहुत अधिक आशाएँ थीं और ये आशाएँ जारी रहेंगी। परंतु वास्तविकता यह है कि हमें सांझा राजनीति की विवशताओं की सीमा में रहकर कर कार्य करना पड़ा है—और इसी प्रकार करते रहना पड़ेगा—साथ ही सदन में बहुमत भी नाजुक हैं तथा सदन में हमारे विरोधी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय रोड़े अटकाने पर तुले हुए हैं।

मैंने गांधीनगर में आपका ध्यान इस वास्तविकता की ओर दिलाया था। अब उन पिछली बातों को याद कर, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम पर हावी अनेकानेक सीमाओं के बावजूद हमने बहुत-कुछ उपलब्ध किया है।

साथ ही, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूँगा कि हमारे कुछ सहयोगी दलों में पारस्परिक सहयोग की भावना का स्पष्ट ही अभाव है, जिस पर चिंता करना उचित ही है। भाजपा-नेतृत्व गठबंधन में हम और हमारे सहयोगी दलों को सदैव यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि हम सब 'शासन के राष्ट्रीय एजेंडा' के आधार पर मिलकर कार्य करने के लिए सहमत हुए थे। एक तरह से यह सरकार जितनी हमारी है, उतनी ही हमारे सहयोगी दलों की भी है—सहयोगी

दलों में से प्रत्येक दल शासन में भागीदार है और वह सरकार की असफलताओं और सफलताओं में बराबर का जिम्मेदार है।

मैं अपने सभी सहयोगी दलों से आग्रह करूँगा कि वे जो शिकायतें अनुभव करते हैं या विचारों में कहीं मतभेद हैं तो इन्हें मीडिया के माध्यम से उजागर न करें, अपितु इसके लिए समन्वय समिति को एक कारगर तंत्र बनाएँ। मैं प्रत्येक सहयोगी दल से यह भी आग्रह करता हूँ कि वृहद् लक्ष्य की खातिर छोटे-मोटे मुद्दों का त्याग करें। आखिर हमने भी अपने प्रमुख मुद्दों को एक तरफ रख दिया है, ताकि इनके कारण कटुता पैदा न हो; हालाँकि इनके बारे में हमने चुनाव अभियान में प्रचार भी किया था।

राष्ट्रीय हित में गठबंधन की सफलता आवश्यक

इस गठबंधन को सफल होना ही चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि हम इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि राष्ट्रीय हित दाँव पर लगे हैं। इस वृहद् हित को ध्यान में रखकर ही हमने श्री वाजपेयी के नेतृत्व में सदैव विचारों में मतभेदों को दूर करने और सभी को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की है। हम सभी को पारस्परिक सहमति और आपसी तालमेल की आवश्यकता को दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए। हमारी मार्ग-निर्देशी भावना में व्यक्ति का हित नहीं, अपितु राष्ट्र का हित ही सामने रहना चाहिए।

सरकार के कार्य-प्रदर्शन का लेखा-जोखा लेते समय कुछ मित्र कहते हैं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जिस सरकार का कम-से-कम पाँच वर्ष का कार्यकाल होता है उसके जीवन में पाँच महीने का समय बहुत कम होता है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से अधीर न होने का आग्रह करता हूँ—उन्हें समझना चाहिए कि यह भाजपा की सरकार नहीं है, बल्कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार है। उन्हें यह लथ्य भी समझ लेना चाहिए कि हमने राजनीतिक दृढ़ संकल्प को लेकर भ्रष्टाचार, आतंकवाद और गिरती जा रही अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौती का मुकाबला किया है। हम धैर्य रखें और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामों की प्रतीक्षा करें।

कावेरी जल-विवाद का समाधान

इस प्रसंग में मैं आपका ध्यान कावेरी जल-विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से हुए समाधान की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो निश्चित ही इस सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता है। दो दशकों से भी अधिक समय से चार दक्षिण राज्यों के बीच कावेरी जल बँटवारे का पुराना विवाद एक चुनौती भी था और एक अवसर भी था—चुनौती इस रूप में था कि हम इनका समाधान बातचीत और चर्चा के

माध्यम से करने के लिए प्रतिबद्ध थे; दूसरी तरफ आम सहमति की राजनीति में अपने विश्वास को कसौटी पर कसना—हमारे लिए एक अवसर था।

मुझे विश्वास है कि हम यहाँ सभी एकत्रित लोगों को इस तथ्य पर गर्व है कि सरकार ने इस चुनौती पर विजय प्राप्त की और पिछले वर्षों से टकराव की राजनीति के विपरीत आम सहमति की राजनीति को व्यवहार में लाने के अवसर का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप जो कुछ दो दशकों से भी अधिक समय में प्राप्त नहीं किया जा सका था, उसे आधे वर्ष से भी कम समय में प्राप्त कर लिया।

बढ़ती कीमतें चिंता का विषय

परंतु यदि हम इस सरकार की कमियों को नजअंदाज करते हैं तो प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी कमी, जो सामने दिखाई पड़ती है, वह मूल्यों के मोरचे पर दिखाई पड़ती है। जहाँ यह ठीक है कि लगातार बढ़ते जा रहे मूल्य-सूचकांक के लिए सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, वहीं लोगों में फैली भावना की पूरी तरह अनदेखी नहीं की जा सकती है। सच्चाई यह है कि वर्तमान मूल्य-वृद्धि आंशिक रूप से पिछली सरकारों की नीतियों तथा प्राकृतिक आपदाओं दोनों ही कारणों से हुई है। जमाखोरों और कालाबाजारियों ने कृत्रिम संकट पैदा कर स्थिति का लाभ उठाया है तथा मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि को बढ़ावा दिया है।

इन सभी कारणों से सरकार मूल्य रेखा को नियंत्रण में लाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती है। इसके विपरीत मैं सरकार से तुरंत उपचारी उपाय करने का आह्वान करता हूँ, ताकि आम आदमी को बढ़ते जा रहे बोझ से राहत मिल सके। मैं आप सब से भी जमाखोरों और कालाबाजारियों पर और अधिक नजर रखने का आह्वान करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जमाखोरों और मुनाफाखारों के खिलाफ कड़ी काररवाई करने का वायदा किया है। हमारे कार्यकर्ता सरकार द्वारा उन लोगों के खिलाफ काररवाई करने में सरकार की मदद करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जो लोगों पर पड़ी इस विपदा से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। हम इस प्रयोजन के लिए अपने पार्टी संगठन, विशेष रूप से युवा मोरचा और महिला मोरचा का कारगर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं।

पार्टी और सरकार के बीच तालमेल

गांधीनगर में एक सुझाव दिया गया था कि पार्टी संगठन और सरकार के बीच और अधिक तालमेल स्थापित करने के लिए एक तंत्र बनाया जाए, जिससे कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के बीच सेतु और साथ ही सरकार और लोगों के बीच

दलों में से प्रत्येक दल शासन में भागीदार है और वह सरकार की असफलताओं और सफलताओं में बराबर का जिम्मेदार है।

मैं अपने सभी सहयोगी दलों से आग्रह करूँगा कि वे जो शिकायतें अनुभव करते हैं या विचारों में कहीं मतभेद हैं तो इन्हें मीडिया के माध्यम से उजागर न करें, अपितु इसके लिए समन्वय समिति को एक कारगर तंत्र बनाएँ। मैं प्रत्येक सहयोगी दल से यह भी आग्रह करता हूँ कि वृहद् लक्ष्य की खातिर छोटे-मोटे मुद्दों का त्याग करें। आखिर हमने भी अपने प्रमुख मुद्दों को एक तरफ रख दिया है, ताकि इनके कारण कटुता पैदा न हो; हालाँकि इनके बारे में हमने चुनाव अभियान में प्रचार भी किया था।

राष्ट्रीय हित में गठबंधन की सफलता आवश्यक

इस गठबंधन को सफल होना ही चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि हम इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि राष्ट्रीय हित दाँव पर लगे हैं। इस वृहद् हित को ध्यान में रखकर ही हमने श्री वाजपेयी के नेतृत्व में सदैव विचारों में मतभेदों को दूर करने और सभी को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की है। हम सभी को पारस्परिक सहमति और आपसी तालमेल की आवश्यकता को दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए। हमारी मार्ग-निर्देशी भावना में व्यक्ति का हित नहीं, अपितु राष्ट्र का हित ही सामने रहना चाहिए।

सरकार के कार्य-प्रदर्शन का लेखा-जोखा लेते समय कुछ मित्र कहते हैं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जिस सरकार का कम-से-कम पाँच वर्ष का कार्यकाल होता है उसके जीवन में पाँच महीने का समय बहुत कम होता है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से अधीर न होने का आग्रह करता हूँ—उन्हें समझना चाहिए कि यह भाजपा की सरकार नहीं है, बल्कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार है। उन्हें यह लथ्य भी समझ लेना चाहिए कि हमने राजनीतिक दृढ़ संकल्प को लेकर भ्रष्टाचार, आतंकवाद और गिरती जा रही अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौती का मुकाबला किया है। हम धैर्य रखें और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामों की प्रतीक्षा करें।

कावेरी जल-विवाद का समाधान

इस प्रसंग में मैं आपका ध्यान कावेरी जल-विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से हुए समाधान की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो निश्चित ही इस सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता है। दो दशकों से भी अधिक समय से चार दक्षिण राज्यों के बीच कावेरी जल बँटवारे का पुराना विवाद एक चुनौती भी था और एक अवसर भी था—चुनौती इस रूप में था कि हम इनका समाधान बातचीत और चर्चा के

माध्यम से करने के लिए प्रतिबद्ध थे; दूसरी तरफ आम सहमति की राजनीति में अपने विश्वास को कसौटी पर कसना—हमारे लिए एक अवसर था।

मुझे विश्वास है कि हम यहाँ सभी एकत्रित लोगों को इस तथ्य पर गर्व है कि सरकार ने इस चुनौती पर विजय प्राप्त की और पिछले वर्षों से टकराव की राजनीति के विपरीत आम सहमति की राजनीति को व्यवहार में लाने के अवसर का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप जो कुछ दो दशकों से भी अधिक समय में प्राप्त नहीं किया जा सका था, उसे आधे वर्ष से भी कम समय में प्राप्त कर लिया।

बढ़ती कीमतें चिंता का विषय

परंतु यदि हम इस सरकार की कमियों को नजअंदाज करते हैं तो प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी कमी, जो सामने दिखाई पड़ती है, वह मूल्यों के मोरचे पर दिखाई पड़ती है। जहाँ यह ठीक है कि लगातार बढ़ते जा रहे मूल्य-सूचकांक के लिए सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, वहीं लोगों में फैली भावना की पूरी तरह अनदेखी नहीं की जा सकती है। सच्चाई यह है कि वर्तमान मूल्य-वृद्धि आंशिक रूप से पिछली सरकारों की नीतियों तथा प्राकृतिक आपदाओं दोनों ही कारणों से हुई है। जमाखोरों और कालाबाजारियों ने कृत्रिम संकट पैदा कर स्थिति का लाभ उठाया है तथा मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि को बढ़ावा दिया है।

इन सभी कारणों से सरकार मूल्य रेखा को नियंत्रण में लाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती है। इसके विपरीत मैं सरकार से तुरंत उपचारी उपाय करने का आह्वान करता हूँ, ताकि आम आदमी को बढ़ते जा रहे बोझ से राहत मिल सके। मैं आप सब से भी जमाखोरों और कालाबाजारियों पर और अधिक नजर रखने का आह्वान करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जमाखोरों और मुनाफाखारों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने का वायदा किया है। हमारे कार्यकर्ता सरकार द्वारा उन लोगों के खिलाफ कारवाई करने में सरकार की मदद करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जो लोगों पर पड़ी इस विपदा से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। हम इस प्रयोजन के लिए अपने पार्टी संगठन, विशेष रूप से युवा मोरचा और महिला मोरचा का कारगर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं।

पार्टी और सरकार के बीच तालमेल

गांधीनगर में एक सुझाव दिया गया था कि पार्टी संगठन और सरकार के बीच और अधिक तालमेल स्थापित करने के लिए एक तंत्र बनाया जाए, जिससे कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के बीच सेतु और साथ ही सरकार और लोगों के बीच

एक सेतु का निर्माण करने के दोनों प्रयोजन सिद्ध हो सकें। इस प्रयोजन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और हम केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर जल्द ही एक तंत्र स्थापित कर लेंगे।

एक और नापाक-गठबंधन की शुरुआत

पिछले कुछ सप्ताहों में 'सेक्युलर शक्तियों' के झंडे तले भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों का तेजी से बनता जा रहा जमावड़ा देखने में आया है। सत्ता के लिए हो रहे अधीर तथा लोगों के फैसले के प्रति तिरस्कार की भावना रखते हुए ये पार्टियाँ एक और नापाक गठबंधन बनाने का प्रयास कर रही हैं—केवल एक बात, जो उन्हें एक जुट करती है, वह है अत्यंत निकृष्ट प्रकार की अवसरवादिता। वामपंथी हमेशा की तरह निर्लज्जतापूर्वक निजी स्वार्थ के लिए इन कठिन परिस्थितियों से लाभ उठाने को लालायित हैं।

यदि सरकार को अस्थिर करने तथा राजनीतिक प्रक्रिया को तोड़ने की उनकी साजिश को कुटिलतापूर्ण ढंग से सहारा नहीं दिया गया होता तो लोकसभा में दशांश भाग भी न रखनेवाले इन छुटभैये नेताओं और छोटी-छोटी पार्टियों की उच्चाकांक्षाओं का मखौल ही उड़ता।

विघटनकारी तत्त्वों का षड्यंत्र

सी.पी.आई (एम) और कांग्रेस को एक-दूसरे को स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखकर हमारे सामने एक विचित्र दृश्य उपस्थित होता है; कल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करनेवाले कुछ लोग अत्यंत घूसखोर राजनीतिज्ञों के साथ हाथ मिला रहे हैं; घोर जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति को 'सेक्युलरवाद' की आड़ में सही माना जा रहा है।

हमें निरंतर सतर्क रहना होगा और कुछ विघटनकारी ताकतों के षड्यंत्रों से अपने को बचाना होगा, जिन्हें न तो संवैधानिक औचित्यों पर आस्था है और न ही लोगों के जनादेश का सम्मान करते हैं।

हमें लोगों को बताना होगा और इन राजनीतिक अवसरवादियों के बुरे इरादों के खिलाफ जनमत इकट्ठा करना होगा। देश एक और राजनीतिक अनिश्चितता तथा नेतृत्व संकट के दौर को वहन नहीं कर सकता है। आज हाथ-पर-हाथ धरकर बैठना बाद में बहुत महँगा पड़ सकता है—यह हमारे लिए और देश, दोनों के लिए भारी पड़ेगा।

कमजोर वर्गों को शक्ति-संपन्न बनाना और भाजपा

जब से हमने भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक चेहरे को बदल देने

को अपना राजनीतिक मिशन बनाया है तभी से उन लोगों के हित हमें प्रिय रहे हैं जिन्हें उनके दाय-अधिकारों से वंचित किया गया, जिनके साथ भेदभाव किया गया और जिन्हें लाभों से वंचित रखा गया है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अपने में कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी प्राप्त न हो।

महिलाओं के लिए आरक्षण

हमने संसद् और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वायदा कई वर्षों पहले किया था जब किसी अन्य दल ने महिलाओं को शक्ति-संपन्न बनाने के लिए इन नए उपायों के बारे में सोचा तक नहीं था। सरकार सदन में विधेयक रखने की कोशिश कर इस वायदे पर कायम रही। दुर्भाग्य से कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने इस प्रगतिशील, दूरदृष्टिवाले विधान का समर्थन करने की बजाय ऐसी शर्तें रख दीं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

मैं यहाँ यह साफ कर देना चाहता हूँ कि हम सदैव मानते रहे हैं और ठीक मानते रहे हैं कि महिलाओं को जाति और संप्रदाय के आधार पर विभाजित करना समाज के हितों के खिलाफ है। भारत न तो एक और जातिवादी संघर्ष वहन कर सकता है और न ही एक और संप्रदाय-आधारित विभाजन।

पार्टी की ओर से मैं महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई अनेक घोषणाओं का स्वागत करता हूँ, जिनमें लड़कियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करने का नया मार्ग प्रशस्त करनेवाला निर्णय और महिलाओं तथा कन्याओं के लिए कम प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी शुरू करना भी शामिल है।

सरकार द्वारा किए गए प्रोत्साहनकारी उपाय

मैं ग्रामीण विकास मोरचे पर प्रोत्साहनों का भी स्वागत करता हूँ; विशेष रूप से किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए फसल बीमा योजना को विस्तृत आधार देने और कालाहाँडी क्षेत्र के उन लोगों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का निर्णय स्वागत योग्य है, जो शायद हमारे गरीब और वंचित लोगों में सर्वाधिक कष्टभोगी गिने जाते हैं।

इसी प्रकार, सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया में तेजी लाए। इसे प्राथमिक कार्य के रूप में हाथ में लिया जाए। मैं उन राज्यों की सरकारों से भी आग्रह करता हूँ, जहाँ हम सत्ता में हैं, कि वे केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के कार्यान्वयन में अग्रणी बनें।

जम्मू और कश्मीर तथा आतंकवाद का खतरा

इस सरकार को पिछली सरकारों से जो अनेक दायित्व विरासत में मिले, उनमें से पाकिस्तान द्वारा प्रेरित, उसकी मदद और उकसाहट पर चलाए जा रहे आतंकवाद से लड़ने का साहसी कार्य भी शामिल है। जहाँ कांग्रेस और संयुक्त मोरचा की पिछली सरकारें, जिनमें राजनीतिक इच्छा जुटाने की ताकत ही नहीं थी, कम-से-कम प्रतिरोध करने का मार्ग अपनाकर संतुष्ट रह गईं और इस प्रकार उन्होंने आतंकवाद को फलने-फूलने दिया, वहाँ इस सरकार ने राजनीतिक इच्छा का परिचय दिया है और आतंकवाद को कुचल देने का अपना निश्चय साफ कर दिया है।

आतंकवाद के संबंध में भाजपा के रवैये को देखते हुए और लोगों की बड़ी-बड़ी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया गया कि इस विभीषिका से तुरंत निबटा जाए; किंतु इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिस समस्या को इतने वर्षों तक एक जख्म की तरह बढ़ने दिया गया, उसे कुछ महीनों में हल नहीं किया जा सकता है। इस विभीषिका को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि आगामी महीनों में हमें इन प्रयासों के परिणाम दिखाई देने लगेंगे।

जम्मू और कश्मीर में कुछ सकारात्मक घटनाएँ देखने में आई हैं, जिनमें से एक यह है कि आतंकवाद से जिन लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित हुई है, वे आतंकवादियों के खिलाफ होने लगे हैं। लोगों का समर्थन मिलने पर सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को तार्किक परिणति तक पहुँचा सकेगी।

जो निराशावादी हैं, उनसे मुझे केवल इतना ही कहना है : याद रखिए, जब दीये की लौ बुझनेवाली होती है—तो यह हमेशा के लिए बुझने से पहले एक बार पूरे जोर-शोर से चमकती है। आतंकवाद की भी यही हालत है। हमने पंजाब में भी यही नमूना देखा था जहाँ आतंकवाद की समाप्ति से पूर्व के महीनों में आतंकवादियों ने अंधाधुंध, हताशापूर्ण क्रोध में, आसान ठिकानों को चुनकर बार-बार हमले किए थे।

आइए, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किए गए उच्चतम बलिदान से प्रेरणा लें तथा दृढ़ निश्चय से इस विश्वास के साथ खड़े हों कि हम आतंकवाद के निर्दयी चेहरे को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि इस सरकार में आतंकवाद तथा इससे जुड़ी बुराइयों का सामना करने के लिए—चाहे ये जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, केरल अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहीं भी हो—अपेक्षित राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं दृढ़ निश्चय विद्यमान है।

छद्म-सेक्युलरवाद और वोट-बैंक की राजनीति

एक ऐसे समय में जब हम आशा करते थे कि हमने अपने अतीत के

द्वेषभाव को पीछे छोड़ दिया है, तब कांग्रेस तथा अन्य छद्म-सेक्युलरवादी पार्टियाँ सांप्रदायिकता का हौआ खड़ा करने और वोट-बैंक तथा अल्पसंख्यकवाद की निंदनीय राजनीति को फिर से जीवित करने की जोर-शोर से कोशिश कर रही हैं।

हमने इस बात को तब महसूस किया जब कांग्रेस ने अयोध्या में मंदिर निर्माण का हौआ खड़ा करने की कोशिश की और इस तथ्य की अनदेखी कर दी कि बहुत पहले अनेक वर्षों से कारीगर अयोध्या से दूर के स्थानों पर देश के किसी कानून का उल्लंघन किए बिना कार्य कर रहे हैं। एक और बात देखिए, जब संसद् में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की कोशिश की गई तो उसने सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की बेतुकी माँग उठा दी। हाल के दिनों में हम ने देखा है कि गुजरात में घटी मामूली सी घटनाओं को तिल का ताड़ बनाकर दिखाने की कोशिश की गई और इसके लिए सर्वथा असत्य और झूठी बातों के जरिए लोगों को बरगलाने का प्रयास किया गया।

कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना

अब हम श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट के बारे में एक भ्रामक एवं अत्यधिक खतरनाक अभियान देख रहे हैं; इस रिपोर्ट में कही गई बातें एक निष्पक्ष न्यायिक जाँच के निष्कर्षों से सर्वथा भिन्न हैं। जो भी हो, 1993 में हिंसा और बम विस्फोटों के लिए भाजपा-शिव सेना पर दोष मढ़ने में कोई तुक नहीं है। उस समय केंद्र और महाराष्ट्र दोनों स्थानों पर कांग्रेस ही सत्ता में थी, जो पहले हिंसा रोकने में असफल रही और फिर हिंसा पर अंकुश नहीं लगा सकी।

मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि इस सब का उद्देश्य सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना है, ताकि नए सिरे से वैमनस्य पैदा किया जाए और पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया जाए। इस शरारत को आरंभ में ही दबा देने की जरूरत है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि छद्म-सेक्युलरवादियों के इस अभियान के पीछे उनके वास्तविक इरादों से लोगों को आगाह कर दिया जाए और ऐसे काम किए जाएँ, जिससे लोगों में भरोसा पैदा हो। हमें उन राज्यों में, जहाँ हम सत्तारूढ़ हैं, सांप्रदायिक शांति एवं व्यवस्था कायम रखने की ओर ध्यान देना चाहिए। भाजपा ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह एक दंगामुक्त समाज को सुनिश्चित कर सकती है। हमारे विरोधियों के दुस्साहसपूर्ण कृत्यों से हमारी यह उपलब्धि धूमिल न होने पाए।

भावी कार्य

पिछले कुछ महीनों में मुझे अनेक राज्यों का दौरा करने तथा स्थानीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपस में यह बातचीत अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध हुई है। मुझे यह बताते हुए भी

प्रसन्नता हो रही है कि जिन थोड़े से प्रदेशों में संगठनात्मक चुनाव अधूरे पड़े हुए थे, वहाँ भी ये चुनाव बिना किसी कठिनाई के संपन्न हो गए हैं। वस्तुतः इस वर्ष के संगठनात्मक चुनाव आंतरिक पार्टी लोकतंत्र एवं आंतरिक पार्टी अनुशासन का उज्ज्वल उदाहरण है। इसका श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है।

गांधीनगर में मैंने कहा था कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बन जाने से हमारा काम खत्म नहीं हो गया है। मैं उस बात को फिर दोहराता हूँ कि हमारे सत्तारूढ़ होने के बाद, संगठन का काम और अधिक कठिन तथा महत्त्वूपर्ण हो गया है। मुख्य विपक्षी दल से मुख्य सत्तारूढ़ दल बनने का संक्रमणकाल आसान नहीं होता—और न ही यह समाप्त हो गया है। यह एक कठिन संक्रमणकाल है और हम इसमें से तभी सफलतापूर्वक निकल सकते हैं, यदि हम पार्टी के हितों को निजी स्वार्थों से ऊपर रख सकें।

पार्टी सरकार का भाग नहीं

यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि पार्टी संगठन कभी भी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता और न ही कभी ऐसा आभास होना चाहिए कि यह सरकार का हिस्सा बन गया है। सरकार को अपना काम करना है और हमें अपना काम करना है। इसमें संदेह नहीं कि दोनों को एक-दूसरे का पूरक बनना होगा; किंतु दोनों को कभी एक नहीं हो जाना चाहिए।

अभी भी देश के ऐसे बहुत से विशाल क्षेत्र हैं, कुछ दूर-दराज के और अन्य पास के, जहाँ हमें अभी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। लोगों के बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके पास हमें पहुँचना है और विश्व के बारे में उन्हें अपने सार्वभौमिक विचारों के बारे में विश्वस्त करना है। अनेक ऐसे काम हैं, जिनमें समाज सुधार के काम भी शामिल हैं, जो अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। राष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक संगठन के रूप में हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है, इसका क्षय नहीं करना है।

पार्टी के समक्ष अनेक चुनौतियाँ

राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं; हमें चुनावों की इन नई चुनौतियों का भी सामना करना है। न केवल राजस्थान और दिल्ली में हमें अपनी स्थिति सुधारनी है, जहाँ हम सत्तारूढ़ हैं, अपितु मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के हाथों से सत्ता को छीनना है।

हम अपने इन दोनों ही उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं

हमें केवल इतना ही करना है कि हम एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और अपने प्रयासों में जुट जाएँ। यदि हम वह उपलब्धि प्राप्त

कर सके हैं, जिसे पिछले आम चुनावों में हमारे विरोधी असंभव बताते थे तो कोई कारण नहीं कि हम आगामी विधानसभा चुनावों में जो संभव है, उसे क्यों न प्राप्त कर सकें।

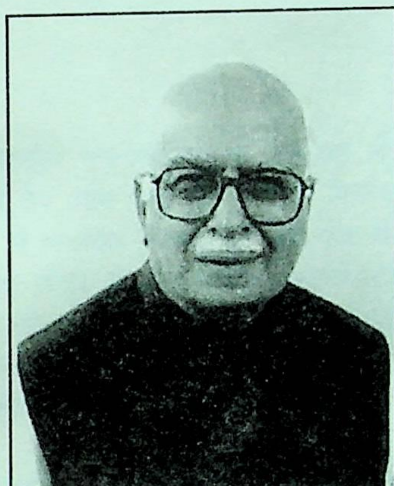
लोग हमारी ओर आशा भरी निगाहों से निहार रहे हैं; न तो पार्टी और न ही सरकार उन्हें निराश कर सकती है।

आइए, मैं आप से विदा लेते हुए पूज्य माताजी के प्रेरणादायक विचारों को रखें :

जो आप नहीं है, वह बनने का दावा मत करिए।
वायदे नहीं, काम करिए।
स्वप्न मत देखिए, उन्हें साकार कीजिए।

वंदेमातरम् !





अध्यक्षीय भाषण

श्री लालकृष्ण आडवाणी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली

11-12 अप्रैल, 1998

मुझे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष है। आप सभी इस सत्र के विशेष महत्त्व से परिचित हैं। बारहवें आम चुनावों में जनादेश मिलने के बाद केंद्र में सहयोगी दलों के साथ मिलकर हमारी सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह प्रथम बैठक है। यह संयोग है कि मेरे पार्टी-अध्यक्ष के कार्यकाल की यह अंतिम पूर्ण बैठक है। अतः इस समय पार्टी के जीवन में एक संक्रमणकाल की स्थिति है, जिसमें एक नए युग का शुभारंभ और पुराना युग समाप्ति पर है।

अटलजी का करिश्माई व्यक्तित्व और लोकप्रियता

मैं अपने दो आदरणीय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस नए युग का स्वागत करता हूँ, जो इसका आदर्श प्रस्तुत करते हैं। निःसंदेह, भाजपा को सत्तारूढ़ पार्टी बनाने में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभाव रहा है और वही इसके प्रतीक भी हैं; वह हमारे संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। हाल के चुनावों में भाजपा के सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रदर्शन में अनेक तत्त्वों का योगदान रहा है। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और हमारी विचारधारा से जुड़े करोड़ों लोगों ने भाजपा को वर्तमान स्थल तक पहुँचाने में वर्षों से अथक परिश्रम किया है। परंतु किसी को लेशमात्र भी इसमें संदेह नहीं है कि इस चुनाव में राष्ट्रीय जीवन में श्री अटलजी की ऊँचाई, उनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता तथा हमारे समाज में उनका जो करिश्माई व्यक्तित्व है, इन सभी कारणों ने भाजपा को शासन के इस नए युग में प्रवेश कराया है।

मुझे गौरव है कि मैंने उनके साथ चार दशकों से भी अधिक समय तक काम करने का अवसर पाया है। इसमें उनके साथ मेरे दीर्घकालीन और प्रगाढ़ दोनों तरह के सहचर्य से मुझे सफलता की इस घड़ी में पार्टी को प्रसन्नता के साथ हर्षित होने

का विशेष हक है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि अब हमें श्री अटलजी हमारे राष्ट्रीय इतिहास के कठिन मोड़ पर भारत में एक स्थिर, सुदृढ़ और ईमानदार सरकार प्रदान कर और अधिक ऊँचाइयों पर ले जाएँगे। हमारी पार्टी ने इस समय जो एक और अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य हाथ में लिया है, आइए, हम सब उन्हें अपना संपूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करने की प्रतिज्ञा करें।

नए युग में भाजपा के प्रवेश का शुभारंभ पार्टी के नए अध्यक्ष से भी होगा, जिनको मैं जल्द ही अपना दायित्व सौंप दूँगा। नए अध्यक्ष के चुनाव की सभी औपचारिकताएँ पूरी हो गई हैं। अगले सप्ताह पार्टी की सर्वसम्मत—परंतु किसी भी तरह अज्ञात नहीं—पसंद की घोषणा हो जाएगी। वह भी एक पुराने और सम्माननीय साथी हैं, जिनके साथ मेरा दीर्घकालीन और निकट का साहचर्य रहा है। यदि श्री अटलजी भाजपा गठबंधन की सरकार के अध्यक्ष हैं तो हमारे नए अध्यक्ष सत्तारूढ़ भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। मैं निवर्तमान अध्यक्ष हूँ, मैं अपने उत्तराधिकारी को संपूर्ण समर्थन और सहयोग देने का वचन देता हूँ।

भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक की यात्रा

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक 19-21 दिसंबर, 1997 को भुवनेश्वर में हुई थी। यद्यपि लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं हुई थी, फिर भी अनौपचारिक रूप से भुवनेश्वर की बैठक में हमारी पार्टी का चुनाव-अभियान उड़ीसा की राजधानी में एक ऐतिहासिक रैली के साथ आरंभ हो गया था। वास्तव में उस रैली से संकेत मिल गया था कि देश में और उड़ीसा में भी भविष्य में क्या कुछ होनेवाला है।

'स्थायी सरकार और योग्य प्रधानमंत्री' के लिए मतदान करने के आह्वान से प्रेरित होकर भारत की जनता ने फरवरी-मार्च 1998 में चुनाव में एक चुनावी इतिहास की रचना कर दी। मई 1996 की भाँति, भाजपा एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उदय हुई, परंतु 1996 से भिन्न स्थिति यह रही कि 1998 में केंद्र में साझा सरकार का नेतृत्व करने के लिए अन्य कोई मैदान में नहीं था। यह भी कि पहली बार भारत के गणतंत्र में वास्तव में एक गैर-कांग्रेसी नेता देश का प्रधानमंत्री बना, जिससे 113 वर्ष पुरानी पार्टी के अंतिम पतन का संकेत मिल गया।

भाजपा की प्रभावशाली उपलब्धि

इस चुनाव में हमारी पार्टी ने न केवल अपनी प्राप्त सीटों पर सन् 1996 में 162 से 1998 में 180 सीटें-वृद्धि की, बल्कि उसके वोट भी 20.3 प्रतिशत से बढ़कर 25.46 प्रतिशत हो गए। कांग्रेस ने श्रीमती सोनिया गांधी के प्रचार का बढ़-चढ़कर शोर मचाया, परंतु वह मुश्किल से 1996 की अपनी 140 सीटों की

संख्या कायम रख सकीं। वास्तव में उसके वोटों की भागीदारी गिरकर 28.8 प्रतिशत से 25.68 प्रतिशत तक पहुँच गई। यहाँ हम यह ध्यान रखें कि हाल के चुनाव में कांग्रेस 471 सीटों पर लड़ी, जबकि भाजपा ने 388 निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रत्याशी खड़े किए। सबसे बड़ा धक्का संयुक्त मोरचा को लगा, जिसकी सीटों की संख्या 183 से घटकर 86 रह गई, जो आधे से भी कम है।

लोकसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन के तथ्यपरक अध्ययन करने पर पता चलता है कि जहाँ कई राज्यों में भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली वहाँ कुछ राज्यों में चिंताजनक विफलता भी हाथ लगी। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अपनी स्थिति में सुधार किया। हमने कर्नाटक, गुजरात और पंजाब में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमने उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में श्रीगणेश कर दिया। इनमें से कई राज्यों में जहाँ चुनाव पूर्ण गठबंधन कर हमारी पार्टी को लाभ हुआ तो हमने भी अपने सहयोगी दलों की सफलता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रतिकूल स्थिति के रूप में महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा के चुनाव परिणामों से अत्यंत निराशा हुई और इसी के कारण सरकार बनाने में बाद में हमारे सामने काफी कठिनाइयाँ खड़ी हुईं। चुनाव परिणामों में सफलताओं और विफलताओं दोनों का शांत चित्त से विश्लेषण करना आवश्यक है। दरअसल, यह पहले ही शुरू कर दिया गया है। मेरा केवल इतना आग्रह है—न तो स्वयं को दंड भावना से ग्रसित करें और न ही आत्मश्लाघा में संलिप्त हों; आरोपों-प्रत्यारोपों से बचें; और कष्टप्रद तत्त्वों को तोड़-मरोड़कर रखने की प्रवृत्ति भी न अपनाएँ।

गुजरात में पुनः जनादेश प्राप्त करना

केंद्र में हमारी चुनावी सफलता से गुजरात विधानसभा के चुनाव में प्राप्त जनादेश पुनः प्राप्त कर लेने की हमारी अभूतपूर्व उपलब्धि को किसी तरह कम नहीं किया जा सकता है। यह सफलता और भी मधुर हो गई हैं, क्योंकि हमने यह सफलता सत्ता के मद में चूर उन राजनीतिज्ञों को समुचित फटकार-त्रताकर हासिल की है, जिन्होंने सन् 1995 में पार्टी के साथ विश्वासघात कर उसे कलंकित किया था। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अनुरोध करता हूँ कि गुजरात के उन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति करतलध्वनि कर प्रशंसा व्यक्त करें, जिन्होंने पार्टी के चेहरे से इस कलंक को मिटा दिया। आइए, हम हिमाचल प्रदेश में अपने साथियों की सफलता पर करतलध्वनि करें, जहाँ पार्टी पाँच वर्षों से कुछ अधिक अंतराल के बाद फिर से सत्ता में लौटी है।

उत्तर-पूर्व में उज्ज्वल भविष्य

अब उत्तर-पूर्व में भी हमारा पाँव जमा है। पहली बार भाजपा इस क्षेत्र में

साझा सरकार में भागीदार बनी है—मैं मेघालय सरकार की बात कर रहा हूँ। बाहरी मणिपुर में हमारा प्रत्याशी अपनी सीट जीतने के बहुत नजदीक पहुँच गया था। हमने असम में एक सीट जीती और 10 सीटों पर दूसरे स्थान पर भी पहुँच गए। इस पूरी स्थिति से पता चलता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भविष्य उज्ज्वल है; यह वह क्षेत्र है, जो भारत की सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अनुरोध करता हूँ कि उत्तर-पूर्व के अपने इन साथियों का जोर-शोर से स्वागत करें।

अलग-थलग करनेवाले स्वयं अकेले पड़ गए

संख्या की दृष्टि से हुई वृद्धि से भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण लाभ उत्कृष्टता की दृष्टि से हुआ है कि भाजपा राजनीतिक अस्पृश्यता की बेड़ियाँ तोड़ने में सफल हो गई है। जिन्होंने हम पर सांप्रदायिकता का ठप्पा लगाकर देश की राजनीति से निकाल बाहर करने और अलग-थलग करने का प्रयास किया, आज वह स्वयं अलग-थलग पड़ गए हैं। जैसा कि मैंने नवंबर 1996 में जयपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में परिकल्पना की थी कि दरअसल भाजपा रूपी शेर पिंजरे से बाहर निकल आया है।

आज लगभग सभी राज्यों में भाजपा के मित्र और समर्थक हैं। वस्तुतः हमने नए सिरे से भारत के नए राजनीतिक मानचित्र की रेखाएँ खींचने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। अतः हम आज बड़े गौरव से घोषणा करते हैं कि भाजपा ने 6 अप्रैल को अपने 18 वर्ष पूरा करते हुए अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है। जैसे-जैसे हम इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों की ओर बढ़ेंगे वैसे-वैसे आनेवाले समय में तेजी से प्रगति, साहसपूर्ण आक्रमण, विशाल उपलब्धियों और बड़े-बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बढ़ना होगा।

किंतु पुरानी आदतें मुश्किल से ही जाती हैं। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और हमारी पार्टी के प्रति पूर्वग्रह रखनेवाले अन्य विरोधी भाजपा का विरोध करने की अपनी रणनीति पर गंभीरतापूर्वक आत्मावलोकन करने के न तो योग्य हैं और न ही इच्छुक हैं और वे वही पुराने झूठ तोते की तरह रटे जा रहे हैं। वे सफल नहीं होंगे।

भाजपा का कोई 'प्रच्छन्न एजेंडा' नहीं

मित्रों, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह आखिरी पूर्ण सत्र है, जिसकी मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ, अतः मैं आपसे एक-दूसरे से जुड़े दो प्रश्नों पर गहराई से विचार करने का अनुरोध करना चाहता हूँ—कैसे भाजपा बढ़ते-बढ़ते सत्तारूढ़ पार्टी बनी? और कैसे अब इसके बाद यह पार्टी आगे बढ़े कि सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में यह अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सके?

जीवन के मूलभूत नियमों में एक नियम यह है कि किसी भी जीवित प्राणी

का विकास तभी होता है जब अपनी निर्धारित प्रकृति के अनुरूप चलता है। यही बात आदमी पर भी लागू होती है और मानवीय संगठनों पर भी सही बैठती है। हमारी पार्टी का जन्म उस राष्ट्रवाद के मूल्यों को बनाए रखने के लिए हुआ था, जिसे एकात्म मानववाद के बृहद् परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। राष्ट्रवाद भाजपा की प्रकृति और पहचान-चिह्न है। यह हमारी निश्चित विशेषता है।

राष्ट्रवाद के प्रति अटूट प्रतिबद्धता

हमने अपने 18 वर्षों के जीवनकाल में, बल्कि इससे पूर्व भारतीय जनसंघ के अवतार और जनता पार्टी के साथ विलय होकर बिताए दो वर्षों को मिलाकर बने 26 वर्षों में कोई भी बात जो हमें प्रिय रही है और जो कुछ भी हमने प्रतिपादित किया है, उसमें राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति विशिष्ट रूप से हुई है। इस प्रकार, लोकतंत्र, सेक्युलरवाद, सुशासन, समान न्याय, सामाजिक न्याय, लिंग-सम्मत न्याय, राज्यों और पंचायतों को अधिक शक्ति प्रदान करना—यह सभी अन्य ऐसे विषय हैं, जिनका अर्थ हमारे लिए अलग सिद्धांतों के रूप में प्रगट नहीं होता है बल्कि हमारे यह सिद्धांत राष्ट्रवाद के प्रति सर्वग्राही प्रतिबद्धता में परिणत हुए हैं।

राष्ट्रवाद के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता से यह संभव हुआ है कि सन् 1951 में एक छोटी सी पार्टी धीरे-धीरे एक-एक कदम बढ़ाते हुए 1998 में एक मुख्यधारा की पार्टी बन सकी है। विडंबना है कि जब कभी भी हम अपनी यात्रा में पिछड़े हैं तो उसका कारण राष्ट्रवाद के प्रति हमारी अटल निष्ठा ही रहा है। हमें सन् 1979 में धक्का लगा, जब हमें दोहरी सदस्यता के बहाने जनता पार्टी से निकाल दिया गया था। हमें 1984 के चुनावों में फिर एक बार झटका लगा, क्योंकि हमने हिंदू-सिख एकता के बारे में अपने विश्वास से हटने से इनकार कर दिया। इन दोनों ही अवसरों पर हमारी पराजय ने हमारी भावी सफलता के लिए पायदान का काम किया। हमारी पराजय फिर से विजय में केवल इसीलिए परिवर्तित हो सकी, क्योंकि हमारे कार्य राष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से पृथक् नहीं हुए।

मैं आपको यह ऐतिहासिक उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुरंत ही आजकल चल रहे विवाद के महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर आना चाहता हूँ। हाल में हमारे विरोधियों ने भाजपा के तथाकथित 'प्रच्छन्न एजेंडे' पर बहुत विवाद खड़ा किया है और शोर मचाया है। यह विवाद इसलिए खड़ा करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र के तीन मुद्दों—अयोध्या, संविधान के अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता—को भाजपा गठबंधन द्वारा स्वीकृत शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल नहीं किया है।

भाजपा चुनाव घोषणा-पत्र और राष्ट्रीय एजेंडा

सदन के अंदर प्रधानमंत्री ने पहले ही बड़े कारगर ढंग से छद्मपूर्ण आरोप

का खंडन कर दिया है। परंतु क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक पार्टी मंच है और यह भी कि हमने उन तीन मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल नहीं किया है, जो हमारी वैचारिक पहचान के विशेष महत्त्व रखनेवाले हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि इस प्रश्न का उत्तर दूँ और स्पष्ट करूँ कि किस प्रकार से यह भी राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

मैं ऊपर पहले ही कह चुका हूँ कि अलग-अलग सिद्धांतों का अपने आप में सारभूत अर्थ नहीं होता है। बल्कि इनका महत्त्व और सापेक्ष महत्ता संपूर्ण योजना के अंतर्गत राष्ट्रवाद के उच्चतर अनिवार्य सिद्धांत से निश्चित होती है। आज की विशिष्ट स्थिति में राष्ट्रवाद का अनिवार्य सिद्धांत यह है कि भारत को स्थिर, सुदृढ़ और ईमानदार सरकार मिले। बारहवें आम चुनावों में खंडित जनादेश के प्रसंग में, जिसमें भाजपा को लगभग जनादेश प्राप्त हुआ, परंतु स्पष्ट जनादेश नहीं मिला, एक स्थिर सरकार तभी मिल सकती थी जब भाजपा, इसके चुनाव पूर्व सहयोगी दल और चुनाव के बाद के कुछ समर्थक आपस में मिल जाते।

राष्ट्रीय शासन एजेंडा में केवल सहमत मुद्दे

शासन चलाने के लिए जो गठबंधन बना, उसमें इसके घटक दलों के लिए स्वाभाविक था कि शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में आम सहमति के मुद्दों पर सहमत होते। परंतु इससे वे उपर्युक्त तीन मुद्दे, जो हमारी वैचारिक पहचान का भाग रहे हैं, कहाँ हट जाते हैं? क्या हमने अवसरवादी और सिद्धांतों से हटकर कोई कार्य किया है?

यहाँ दो बातें कहना आवश्यक है—एक, बहुत हद तक शासन करने में विचारधारा का—किसी भी विचारधारा का—हाथ कम ही रहता है, सिवाए इस बात के कि राष्ट्रीय हितों का सिद्धांत ही सर्वोपरि हो। वास्तव में, राष्ट्रीय जीवन की अधिकांश परिधियों में सुशासन तभी संभव हो पाता है जब हम इसमें विचारधारा और राजनीति का समावेश न होने दें। इस प्रकार, यदि कोई ऐसा मुद्दा है, जिसकी चाहे अंतर्निहित वैधता हो, परंतु जब उसका अत्यधिक वैचारिक स्वरूप बन जाता है—दरअसल इतना सुदृढ़ वैचारिक स्वरूप बन जाए कि साझा सरकार और इसलिए स्थायी सरकार चलाने में कठिनाई पैदा करे तो फिर यही उचित होगा कि इसे छोड़ दिया जाए। ठीक यही हमने राष्ट्रीय एजेंडा में किया है।

परंतु, फिर अब हमारा इन तीनों मुद्दों पर क्या रुख है, जो राष्ट्रीय एजेंडा के भाव और भाषा के अनुरूप हो और राष्ट्रीय आम सहमति की हमारी जोरदार वकालत से भी मेल खाए? निश्चित ही हमारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मस्तिष्क में यह प्रश्न सर्वाधिक छाया हुआ है और यह उचित ही होगा कि हम इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण मामले को समझ लें। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विचारार्थ एक नया साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

हमारी प्राथमिकता राष्ट्र मंदिर का निर्माण है

जहाँ तक सरकार का संबंध है, उसके लिए राष्ट्रीय एजेंडा मार्गदर्शक है। किंतु जहाँ तक राष्ट्र का संबंध है, मैं समझता हूँ कि सही दृष्टिकोण यही होगा कि इन तीनों मुद्दों पर शांतिपूर्ण, बिना टकराव पैदा किए और रचनात्मक ढंग से बहस तथा बातचीत जारी रखी जाए।

विशेष रूप से, अयोध्या के मामले में मेरा कहना है कि इस मुद्दे को न्यायपालिका और विधायी दोनों क्षेत्रों से अलग कर लिया जाए और इसे सभी पक्षों से बातचीत कर एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने, तलाश करने तक सीमित कर दिया जाए। आइए, हम आनेवाले दशक को पूरी तरह राष्ट्र-निर्माण के लिए लगा दें। दूसरे शब्दों में एक भव्य राष्ट्र मंदिर निर्माण में लग जाएँ, जिसमें भारतमाता के सभी बच्चे शांति, समृद्धि और सुरक्षा से रह सकें, चाहे उनकी कोई जाति, कोई धर्म या कोई क्षेत्र हो। यही बात हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के प्रति वचनबद्धता दिखाते हुए भी कहती आई है।

दस-सूत्री चार्टर

दरअसल, हमारे चुनाव की मुख्य बात थी कि इसमें अगले दस वर्षों में एक मात्र नए भारत के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके लिए आजादी का एक दस-सूत्री चार्टर पेश किया गया। इस चार्टर में हमने पार्टी की प्रतिबद्धता का वचन दिया है—(1) प्रतिवर्ष एक करोड़ नौकरियों का सृजन करके बेरोजगारी से आजादी; (2) प्रतिवर्ष 20 लाख नए मकान बनाकर बेघरबारी से आजादी; (3) वर्ष 2010 तक खाद्य उत्पादन को दुगुना करके भूख से आजादी; (4) वर्ष 2010 तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर निरक्षरता से आजादी; (5) भारत को दंगा-मुक्त एवं आतंकवाद-मुक्त बनाकर भय से आजादी; (6) सभी समुदायों में समरसता स्थापित करके सामाजिक टकराव से आजादी; (7) राज्यों को शक्तियों का मौलिक रूप से हस्तांतरण कर केंद्र-राज्य संबंधों की कटुता से आजादी; (8) स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करके तथा संसद् एवं राज्यविधान सभाओं में 33 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण के लिए कानून बनाकर महिलाओं की आजादी; (9) बिजली, ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार, सूचना टेक्नोलॉजी तथा अन्य क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण करके ढाँचागत सुविधाओं के अभाव से आजादी; (10) प्रत्येक भारतीय का भारत में विश्वास जाग्रत् करके मानसिक दासता से आजादी।

पार्टी की भावी प्रगति का नया मार्ग

मित्रो, अब चूँकि केंद्र में हमारी सरकार है, अतः आइए हम इन दसों दिशाओं में सारगर्भित और प्रत्यक्ष प्रगति करने का संकल्प करें। हमें अपने आपको तथा

आनेवाली पीढ़ी को यह सिद्ध करके दिखा देना है कि हम पार्टी के आजादी के घोषणा-पत्र में निहित उच्च आदर्शों के प्रति पूर्णतया निष्ठावान् हैं, जिनमें से अधिकांश राष्ट्रीय एजेंडा में भी सम्मिलित किए गए हैं। और चूँकि इस एजेंडा को कार्यान्वित करने के लिए एक समर्थनकारी और स्थायी सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण की आवश्यकता है, अतः हमारी पार्टी के लिए यह नया मार्ग अपनाना, जो मैंने बताया है, न केवल वांछनीय है अपितु आवश्यक भी है।

सुशासन और योग्य नेतृत्व

यदि हम सन् 1980 के बाद से अपनी पार्टी की प्रगति का सर्वेक्षण करें तो देखते हैं कि सन् 1989-96 की अवधि के दौरान हमने जो बहुत तेजी से प्रगति की उसका मुख्य कारण हमारी विचारधारा थी। किंतु 1996 के चुनावों के बाद से केवल उसी विचारधारा के कारणों से ही हमारी प्रगति की रफ्तार कायम नहीं रही है। इसके साथ ही इन्हीं विचारधारा के कारणों से ही विभिन्न राज्यों से हमारे नए राजनीतिक सहयोगी हम से नहीं जुड़े हैं। बल्कि लोगों में यह खयाल बढ़ता गया कि एकमात्र भाजपा ही एक स्थायी विकल्प है और वही सुशासन प्रदान कर सकती है और इसके साथ श्री वाजपेयी के नेतृत्व में उनकी अटूट आस्था हमें अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बहुमत प्राप्त करने की ओर अधिकाधिक निकट लाती गई है।

इससे हमारी पार्टी को यह सशक्त संदेश मिलता है कि हमें बदनाम, हताश और वंशवादी कांग्रेस का स्थान लेने के लिए देश की मुख्यधारा की पार्टी के रूप में अपनी नवार्जित स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ यह है कि भाजपा को समाज के सभी वर्गों तथा भारत के सभी क्षेत्रों की स्वीकार्य पार्टी बनाने के लिए सोच-समझकर और नियमित रूप से अपने को बदलना होगा। प्रत्येक भारतीय को चाहे उसकी जाति, धर्म, प्रदेश, नस्ल और भाषा कुछ भी हो हमारे वैयक्तिक एवं सामूहिक चिंतन में एक ही स्थान मिलना चाहिए। हमें दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से अपनी पार्टी के अधिक निकट लाने का प्रयास करना चाहिए और हमें यह शृंखलाबद्ध तरीके से अपनी नीतियों, विकास के कार्यक्रमों, संगठित करने की रणनीतियों तथा सच्चे मन से संवाद द्वारा करना चाहिए।

यह मार्ग हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वकालत करने के पूर्णतया अनुरूप है, चूँकि हमने हिंदुत्व को कभी भी एक संकुचित, अन्यापवर्जित अथवा भेदभावजनक अवधारणा के रूप में नहीं लिया है।

शासक दल के रूप में अच्छा प्रदर्शन दिखाना

वस्तुतः उक्त नया मार्ग उस दूसरे प्रश्न का आंशिक उत्तर है, जो कि मैंने

अपने उद्बोधन के पहले भाग में उठाया था। भाजपा को शासन चलानेवाली पार्टी के रूप में अपनी कुशलता का परिचय देते हुए अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए?

इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए प्रथम अपेक्षा यह है कि पार्टी में सर्वोच्च पद पर आसीन पदाधिकारी से लेकर निम्नतम इकाई के कार्यकर्ता तक हम में से प्रत्येक के कंधों पर, जो जिम्मेदारी आन पड़ी है, उसकी महानता और उसके ऐतिहासिक स्वरूप को पूरी तरह से समझना होगा। जब तक हम शासन की जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे तब तक उसके बाद आनेवाली अन्य प्रवृत्ति संबंधी एवं संचालन संबंधी अपेक्षाओं को हम अपने अंदर ला नहीं पाएँगे। जैसा कि एक के बाद दूसरे तथा हाल के चुनाव से पता लगा है कि जो लोग सत्ता में होते हैं, उनके काम का मूल्यांकन करते समय लोग उन्हें बख्शते नहीं हैं और यदि वे अपने वायदों को पूरा करने में असफल रहते हैं तो उन्हें गद्दी से हटाने में जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। हमें इस सरकार-विरोधी प्रवृत्ति का अंत करना होगा।

भाजपा पर भारी उत्तरदायित्व

सदन में अपनी संरचना तथा समर्थन की संख्या के आधार को देखते हुए, हमारी सरकार पर काम करके दिखाने की चुनौती और भी अधिक भारी है। सत्तारूढ़ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते या यूँ कहिए कि सत्तारूढ़ गठबंधन का मस्तिष्क तथा हृदय और उसकी आत्मा होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी को अत्यधिक जिम्मेदारी की भावना, दूरदर्शिता तथा यदि मैं कहूँ कि एक मिशन की भावना से काम करना होगा।

इस बात को महसूस करने के फलस्वरूप प्रवृत्ति संबंधी एवं संचालन संबंधी जिन अपेक्षाओं की आवश्यकता है, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

1. एकता और अनुशासन को सुदृढ़ करना

हमें पार्टी में सभी स्तरों पर, विशेषरूप से केंद्र में तथा राज्यों में उच्चतम स्तरों पर एकता, समन्वय एवं अनुशासन को और अधिक सुदृढ़ बनाना होगा।

2. भाजपा मूलभूत परिवर्तन का विशिष्ट साधन

मीडिया, हमारे सहयोगी, हमारे विरोधी और जनसाधारण भी हमारे पदाधिकारियों, हमारे मंत्रियों, हमारे सांसदों तथा हमारे कार्यकर्ताओं की उक्तियों एवं कार्यों पर कड़ी नजर रखेंगे। इस संबंध में हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सके और लोगों में राजनीति और शासन की एक नई संस्कृति की आशा का संचार कर सके। हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हमारे शासन के राष्ट्रीय एजेंडा की यह भी एक गंभीर प्रतिबद्धता है। सत्ता के घमंड और व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राज्य के तंत्र का प्रयोग करने के लालच पर अंकुश

लगाना अत्यावश्यक है, क्योंकि इन्हीं बुराइयों के कारण कांग्रेस पार्टी इतनी अधिक बदनाम हुई। इस प्रकरण में हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उन बातों को याद करना चाहिए, जो उन्होंने हमें उस समय कही थीं, जब हम सत्ता के द्वार के कहीं आस-पास भी नहीं थे। उन्होंने कहा था—"जनसंघ एक ऐसी पार्टी नहीं है, जो केवल चुनाव जीतने और सत्ता को हथियाने के लिए बनाई गई हो। नहीं, यह राजनीति तथा राष्ट्रीय जीवन में एक मौलिक परिवर्तन लाने का साधन मात्र है।"

3. आम सहमति की दिशा में सतत प्रयास

हमारी गठबंधन की सरकार है। स्वाभाविक है कि इससे कतिपय दायित्व तथा जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आन पड़ी है, जिसे हम गठबंधन की राजनीति का धर्म कह सकते हैं, यह गठबंधन के सभी भागीदारों पर लागू होती हैं। जहाँ तक भाजपा का संबंध है, मैं यह चाहता हूँ कि हमारे सभी सहयोगी विशेषरूप से, जो राज्य इकाइयों में जिम्मेदार पदों पर हैं, इस बात को हृदयंगम कर लें कि केंद्र की गठबंधन सरकार के हित सर्वोपरि हैं। राज्यों में पार्टी की रणनीतियाँ इसकी राष्ट्रीय रणनीति के अनुकूल होनी चाहिए। एक मोटी सी नीति के रूप में हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि साझे हितों के क्षेत्र को निरंतर बढ़ाकर तथा मतभेदों के क्षेत्र को संकुचित अथवा हर हालत में निष्क्रिय करके गठबंधन के सही रसायन को विकसित किया जाए।

4. पार्टी का महत्त्व

अधिकांश लोकतंत्रों में सत्तारूढ़ दल तथा सरकार के बीच बड़ा पेचीदा और नाजुक संबंध होता है। साम्यवादी देशों ने दोनों संरचनाओं को आपस में मिलाकर इसे सुलझाने की कोशिश की है—और बहुतों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दलों ने एक बार सरकार में जाकर जब पार्टी के काम की उपेक्षा की है तो लोकतंत्रों को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। चूँकि भाजपा ने केंद्र में पहली बार सत्ता की बागडोर सँभाली है, अतः हमें पार्टी के महत्त्व को कम न करने के बारे में बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पार्टी को विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के काम पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और उनकी निगरानी करनी चाहिए तथा प्रधानमंत्री को तुरंत इसके बारे में सूचित करते रहना चाहिए।

विशेषरूप से, सरकार तथा पार्टी के बीच समुचित संबंध स्थापित करने के लिए शीघ्र ढाँचा, तंत्र एवं मार्ग के निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता है। यह काम और भी अधिक जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे सर्वोच्च पदाधिकारियों में से काफी लोगों को सरकार की जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्टी के विचार, सुझाव एवं उसकी सूचना नियमित

रूप से एवं शीघ्रता से सरकार में सही लोगों के पास पहुँचती रहे और उनपर उचित ध्यान भी दिया जाए।

5. जनता की समस्याओं के प्रति सचेत

अंत में, अब चूँकि भाजपा एक शासक दल है, अतः निम्नतम कार्यकर्ता तक हमारे सभी पदाधिकारियों को अपना समय और ध्यान लोगों के मुद्दों अथवा बड़े-बड़े मुद्दों की ओर लगाना चाहिए और व्यक्तिगत मामलों अथवा छोटे-मोटे मुद्दों की ओर नहीं। जनता के मुद्दों की ओर ध्यान देने से सामाजिक एवं राजनीतिक लाभ होता है। व्यक्तिगत मुद्दों को उठाने से पार्टी के पदाधिकारियों तथा सरकारी अफसरों के समय का अकसर अनुचित उपयोग होता है और उससे कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

नए युग की नई भाजपा

मैंने पहले जो दो प्रश्न उठाए थे, उनका उत्तर देते हुए मैंने जो कुछ कहा है, उन सबका मतलब यह है कि भाजपा को अब एक नई भाजपा बनना चाहिए। भारत और हमारी पार्टी के सामने जो एक नया युग आ रहा है, उसकी जिम्मेदारियों को केवल एक नई भाजपा ही सँभाल सकती है। नई भाजपा बीते हुए कल के मुद्दों से नहीं, बल्कि आनेवाले कल के एजेंडे से दिग्दर्शित होगी। नई भाजपा बदलते हुए विश्व-परिदृश्य से पूर्णतः अवगत है और यह स्वयं को तथा भारत को इन चुनौतियों का मुकाबला करने के योग्य बनाने को तैयार है और इक्कीसवीं शताब्दी के गर्भ में पल रहे अवसरों से भी लाभ उठाना होगा। नई भाजपा केवल सत्तारूढ़ पार्टी नहीं होगी, बल्कि शासन करनेवाली स्वाभाविक पार्टी होगी।

यह एक ऐतिहासिक चुनौती है, एक बड़ी भारी चुनौती है। हमें इसका मुकाबला करना है और हम इसका सामना करेंगे तथा सफल होंगे। जैसा कि एक दार्शनिक ने कहा है—"बड़े-बड़े कामों में प्रायः दृढ़ निश्चय लेकर चलने से काम बन जाता है।" हमारे मामले में, हमारे पास न केवल दृढ़ निश्चय है, अपितु राष्ट्रवाद की सही दिशा भी है, जिसने हमारे इतिहास की हर कठिन घड़ी में हमारा साथ दिया है।

अपने इस महान् उद्देश्य की सफलता में पूर्ण विश्वास की इस अभिव्यक्ति के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस महत्त्वपूर्ण बैठक में मैं अपना उद्घाटन भाषण समाप्त करता हूँ।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

गांधीनगर — 2 मई, 1998

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी,

नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे तथा आदरणीय बंधुओ,

कल से आरंभ होनेवाली भाजपा राष्ट्रीय परिषद् के ऐतिहासिक अधिवेशन की पूर्व संध्या पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष है।

इस अधिवेशन को तीन कारणों से ऐतिहासिक कहा जा सकता है। एक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में केंद्र में भाजपा नेतृत्व की सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय परिषद् की यह प्रथम बैठक है। अभी तक हम केवल विपक्ष की एक पार्टी के रूप में राष्ट्रीय परिषद् की बैठक के लिए एकत्र होते थे। कल हम शासन की पार्टी के रूप में एकत्र होंगे।

दो, राष्ट्रीय परिषद् के गांधीनगर अधिवेशन में एक नए अध्यक्ष, श्री कुशाभाऊ ठाकरे अपना कार्यभार सँभालेंगे, जिन्हें इस पद पर सर्वसम्मति से चुना गया है और वे पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर अगली शताब्दी में ले जाएँगे।

आखिर में, मेरे अपने जीवनकाल में कल का दिन महत्त्वपूर्ण दिवस है। जब मैं कल श्री कुशाभाऊ ठाकरे जो को अध्यक्ष का पदभार सौंप दूँगा तो मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अध्याय समाप्त हो जाएगा। ऐसा अवसर निश्चय ही भावना और स्मृतियों तथा संपन्न किए गए कार्यों तथा अनेक ऐसे अन्य कार्यों के विचारों से ओत-प्रोत रहता है, जो अभी विषय में संपन्न किए जाने हैं।

आज मेरे मन में सबसे अधिक शक्तिशाली भावना और विचार कृतज्ञता से परिपूर्ण हैं। पार्टी और पूरे संघ परिवार के प्रति मेरे मन में कृतज्ञता है। आप सभी ने मेरी इच्छा से कहीं अधिक मुझे स्नेह, शक्ति और सहयोग प्रदान किया है। अतः यदि कोई कार्य पूरा हो पाया तो यह आप सभी के सहयोग और उन सभी के समर्थन से पूरा हो पाया है, जिनसे यह प्रबल राष्ट्रीय शक्ति निर्मित हुई है और

जिसने आज हमारे वैचारिक अभियान का रूप ग्रहण कर लिया है। जो कुछ भी अधूरा रह गया है, अध्यक्ष के नाते मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ।

भाजपा—एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी शक्ति

आज जब मैं अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तरदायित्व छोड़ रहा हूँ तो मुझे जहाँ एक तरफ जनसंघ के समय की पुरानी स्मृतियों का स्मरण होता है तो दूसरी तरफ अगली सहस्राब्दी की परिकल्पना भी होती है। भूतकाल की अपनी स्मृति और भविष्य की परिकल्पना के बीच पार्टी का विकास निहित है, जब पार्टी के छोटे से समूह से बढ़ते-बढ़ते अगली सहस्राब्दी में भारत को ले जानेवाली राष्ट्रव्यापी शक्तिशाली ताकत बन गई है।

जनसंघ का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ था। उसका जन्म बलिदानों के बीच हुआ। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शताब्दियों के बाद बनी एकमात्र राष्ट्रीय सरकार में अपने गौरवपूर्ण पद से त्याग-पत्र दिया और एक छोटी सी विरोधी पार्टी 'जनसंघ' की स्थापना की। आज जो कुछ होता है, वह ठीक इसका उलटा है। आज पार्टियाँ इसलिए बनती हैं, क्योंकि किसी नेता विशेष को सरकार में शामिल नहीं किया जाता है। जनसंघ का अस्तित्व इससे भी अधिक बलिदान करता हुआ बना रहा। डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या रहस्यमय परिस्थितियों में हुई।

मातृभूति के प्रति अगाध आदर्शवाद और प्रेम से आप्लावित होकर सैकड़ों युवा नर-नारी जनसंघ में शामिल हुए, जिनमें से अनेक को रा.स्व.सं. से प्रेरणा मिली थी और प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आज हममें से अनेक लोग, जिनके बाल उड़ गए हैं और सफेद हो गए हैं, उन्हीं में से हैं। ऐसी अनेक राजनीतिक पार्टियों के विपरीत, इनका पुनर्निर्माण पहले से गढ़े-गढ़ाए विचारों और ढाँचों पर हुआ, जनसंघ और इसकी वैचारिक धारा से प्रेरित होकर पुनः अवतरित भाजपा ने एक सामंजस्यपूर्ण, सुदृढ़ और स्पंदनशील राष्ट्रीय शक्ति बनने के लिए जबरदस्त परिश्रम किया और आज भाजपा केवल केंद्र में एक साझा सरकार का नेतृत्व ही नहीं करती है, अपितु आज भारतीय राजनीति के केंद्र में छाई हुई है।

भाजपा असाधारण प्रगति में विचारधारा और आदर्शवाद का योगदान

आज जब मैं मुड़कर इस महान् पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपने बीते वर्षों को देखता हूँ तो मेरे सामने एक गतिमान, निरंतर आगे बढ़ती पार्टी का चित्र आता है। यदि लोकतंत्र में किसी राजनीतिक पार्टी के आगे बढ़ने का सूचक चुनावों में उसका प्रदर्शन है तो भाजपा सन् 1984 में अपने प्रदर्शन ग्राफ से सबसे निचले बिंदु से उभरती हुई 1998 में सर्वोच्च बिंदु पर जा पहुँची है। हम सभी के लिए यह बड़े संतोष का विषय है। हमारी इस असाधारण प्रगति के मुख्य कारण विचारधारा और

आदर्शवाद का वह अभूतपूर्व मिश्रण है, जिसके कारण भाजपा शेष राजनीतिक पार्टियों से अलग दिखाई पड़ती है।

हमारा विकास इसी कारण होता गया, क्योंकि हमने राष्ट्रवाद की जिस विचारधारा को अपनाया, उसकी विजय पूर्व निश्चित बन जाती है और भाजपा राजनीतिक क्षेत्र में केवल एक साधन है, जिसने अपनी विजय प्राप्ति के लिए जिस विचारधारा को संस्थापित किया है हमने अपनी राजनीतिक यात्रा के हर मोड़ पर राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति निष्ठा प्रकट की है। राजनीतिक पार्टी के रूप में सन् 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में और 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में आरंभ में जन्म से ही राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति हमारी अपनी प्रतिबद्धता ने इसका प्रमाण प्रस्तुत किया है।

मूल्य-आधारित राजनीति में विश्वास

इसके दौरान हमारी पार्टी ने जिस मुद्दे को उठाया और प्रत्येक मुद्दे ने, जिससे हमारी पार्टी चुनाव में और लोगों की दृष्टि में सम्माननीय बने, दोनों ही रूपों में इस बात को सिद्ध कर दिया कि हमारी आस्था मूल्य आधारित राजनीति में है।

इस प्रकार, आपातकालीन शासन के विरुद्ध हमारे संघर्ष ने लोकतंत्र के मूल्य के प्रति हमारी वचनबद्धता को प्रमाणित किया, जिसके बिना भारतीय राष्ट्रवाद की कोई पहचान ही नहीं रह जाती है।

इसी प्रकार, अयोध्या में राम मंदिर के लिए हमारे अभियान से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के प्रति हमारी वचनबद्धता प्रमाणित होती है, जिसके बिना न केवल सेक्युलरवाद के अर्थ की परिभाषा नहीं हो पाती है, अपितु भारत की पहचान भी नहीं हो पाती है।

कश्मीर के पूर्ण विलय का हमारा अभियान राष्ट्रीय एकता के आदर्श के प्रति हमारी वचनबद्धता को प्रमाणित करता है, जो स्वराज की अवधारणा का केंद्र बिंदु है।

सामाजिक समरसता के प्रति हमारी आस्था इसी प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है कि हम सामाजिक न्याय की उच्च भावना के समर्थक हैं, जिसके बिना हमारे समाज की एकजुटता सुनिश्चित नहीं हो सकती है।

स्वदेशी पर हमारा बल आर्थिक राष्ट्रवाद के मूल्यों को प्रमाणित करता है, जिसके बिना भारत वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ, विशेषरूप से उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा अनवरत संघर्ष शुचिता के आदर्श के प्रति हमारी वचनबद्धता को प्रमाणित करता है, जो सुशासन की अवधारणा का केंद्र बिंदु है।

इसी प्रकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, वनवासियों, युवाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे समुदायों की वैध आकांक्षाओं और भारत के धर्मों के लिए हमारी आवाज उठाने का अथक प्रयास सभी भारतीयों के संतुलित कल्याण

के प्रति हमारी वचनबद्धता को दरशाता है, जिसके बिना एकात्म मानववाद के आदर्शों से प्रेरित समतावादी भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्त मुद्दों में से प्रत्येक मुद्दे ने हमारी पार्टी का विकास करने में सहायता की है। यह तर्क दिया जा सकता है कि देश की मुख्यधारा की पार्टी के रूप में भाजपा का विकास मुख्य रूप से कांग्रेस के पतन के कारण हुआ है, जो अभी हाल तक देश में प्रमुख स्थान पर विद्यमान थी। यह तर्क कुछ हद तक ठीक है। परंतु यह तर्क भाजपा की अपार प्रगति को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करता है। इससे इस आलोच्य का उत्तर नहीं मिलता कि 'क्यों भाजपा ही कांग्रेस द्वारा रिक्त स्थान को भर पाई और अन्य कोई पार्टी क्यों नहीं?'

भाजपा : राष्ट्रवाद की प्रतीक

इसका सही उत्तर एक बार फिर राष्ट्रवाद है, क्योंकि यही एक राजनीतिक पार्टी की स्थिरता और उन्नति की गारंटी देनेवाला है। जब तक भारत की जनता कांग्रेस को राष्ट्रीय मूल्यों की धरोहर और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देनेवाली समझती रही तब तक भारतीय राजनीति पर इसका एकच्छत्र राज्य बना रहा। यह वस्तुतः स्वाभाविक शासक दल था। जब लोग यह देखने लगे कि कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रयोजन खत्म होता जा रहा है तो उनका इस दल से मोह-भंग आरंभ हो गया। जब तक कोई स्पष्ट विकल्प उभरकर नहीं आया तो लोगों ने कांग्रेस सरकारों की तरह के कई परीक्षण किए।

परंतु इसके साथ ही जब एक बार कांग्रेस और दूसरी बार कांग्रेसी सरकार की तरह के अनुभव से तंग आ गए तो वे भाजपा को स्पष्ट रूप से अपनी एक पसंद की पार्टी के रूप में भी देखने लगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी पार्टी थी, जो उनकी दृष्टि में राष्ट्रवाद की कसौटी पर खरी उतरती थी। इसी कारण सन् 1989 के बाद से ही हमें संसद् में, शनैः-शनैः अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देने के पश्चात् लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सन् 1998 में शासक दल बना दिया।

किंतु इस जनादेश के पूर्ण न होने का स्पष्ट रूप से यह भी अर्थ है कि हमने अभी तक भारत की जनता का विश्वास पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया है। इस बात को मानना पड़ेगा कि जितनी तेजी से कांग्रेस का अधःपतन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का उतनी तेजी से उत्थान नहीं हुआ है। यद्यपि यह उन्नति काफी अद्‌भुत रही है। अतः संगठनात्मक रूप में भौगोलिक एवं सामाजिक दोनों ही रूप से नए-नए क्षेत्रों में पहुँचने का काम निर्बाध रूप से निरंतर चलता रहना चाहिए।

आज जो स्थिति है, उसको देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि लोगों ने हमें अभी अपनी नई नौकरी पर परिवीक्षाधीन रखा है। हम इस परीक्षा में कैसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होंगे? मेरे विचार में आज जो हमारी नई परीक्षा ली जा रही

है, वह भी एक बार फिर राष्ट्रवाद के बारे में हमारी परीक्षा है। आज राष्ट्रीय हित में सर्वप्रथम और सबसे अधिक आवश्यक अनिवार्यता सुराज की है। हम जिस हद तक सुराज के आदर्शों का अनुगमन और पालन कर सकेंगे, उसी हद तक राष्ट्रवाद में अपनी आस्था की कसौटी पर खरा उतर सकेंगे।

एक चुनौतीपूर्ण स्थिति

मित्रो, इस परीक्षा में सफल होने की प्रथम अपेक्षा इस बात को स्वीकार करना है कि आज के इरादे चाहे कितने ही नेक क्यों न हों, यह काम आसान नहीं है। हमें इस कठोर यथार्थता को स्वीकार करना होगा ताकि हम अपनी जिम्मेदारी के पूरे बोझ को समझ सकें। प्रथम छह सप्ताह तक सत्ता में रहने के बाद हमने काफी अच्छी तरह इस बात को जान लिया है कि हमारे सामने जो स्थिति है, उसमें सामान्यतया, एक नई सरकार को मधुमास का आनंद उठाने दिया जाता है। हमें यह आनंद लेने का भी अवसर नहीं मिला। सच तो यह है कि यह समय बहुत ही कष्टप्रद रहा है। पुराने गर्भाशय से नवजात शिशु का जन्म काफी पीड़ाप्रद है।

परंतु हमें शायद सर्वशक्तिमान भगवान् का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने शैशवकाल में ही हमारे धैर्य की परीक्षा ले ली और हमारे जीवन के आरंभ में ही हमें सतर्कता एवं जीवित रहने का पाठ पढ़ा दिया। प्रथम छह सप्ताह की परीक्षा एवं कष्टों ने हमें स्थिरचित्त और अपने आपको शक्तिशाली बनाने के हमारे संकल्प को और लोहे जैसा दृढ़ बना दिया है। हम विजयी होंगे, हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुयोग्य नेतृत्व में सरकार में अपने कामों से यह सफलता प्राप्त करेंगे।

भविष्य की ओर दृष्टि

नई स्थिति में गुणात्मकता और संख्या दोनों ही दृष्टियों से पार्टी की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। आज भाजपा के अध्यक्ष पद से निवृत्त होते समय मेरा पार्टी से यह अनुरोध है कि हम अतीत की अपनी सफलताओं के सहारे हाथ-पर-हाथ धरे न बैठे रहें, अपितु भविष्य की चुनौतियों का सीना तानकर मुकाबला करें और अवसरों से लाभ उठाएँ।

आज यदि हमारी पार्टी को स्वाभाविक रूप से शासन करनेवाली पार्टी बनना है तो मेरे विचार से उसे चार बड़े-बड़े क्षेत्रों में पार्टी को क्या करना चाहिए, इसकी ओर ध्यान देना होगा। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं—

1. शासन की अपनी क्षमताओं को बढ़ाना

भाजपा को अपनी शासन की क्षमताओं को बढ़ाना एवं समृद्ध बनाना होगा, जो राजनीतिक क्षमताओं से भिन्न होती है। हमें न केवल पिछली कांग्रेसी तथा अन्य कांग्रेसी सरकारों की तरह के कुशासनजनित गड़बड़झाले की सफाई करनी

होगी, अपितु यह और भी महत्त्वपूर्ण है कि हमारे राष्ट्रवाद के उच्च स्वप्नों के अनुसार उसका पुनर्नवीकरण और पुनर्निर्माण करना होगा।

इसका अर्थ है कि उन सबको जिन्हें केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों के लिए जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, राजनीतिक मुद्दों की ओर अधिक ध्यान देने की बजाए शासन संबंधी मुद्दों को निपटाने में अधिकाधिक समय लगाना होगा और छोटे-मोटे तथा भौंडी राजनीति करने के मुद्दों की ओर तो बहुत कम ध्यान देना होगा। इसके साथ ही हमें पार्टी के नवयुवकों तथा नए लोगों को विभिन्न शासन संबंधी कामों के लिए प्रशिक्षित करना होगा। हमने गत वर्ष प्रशिक्षण शिविरों की जो श्रृंखला आरंभ की थी तदनुसार उसका पुनर्नवीकरण करना होगा।

2. जनता और सरकार के बीच की कड़ी

जो राजनीतिक पार्टी अपने समर्थन के आधार का विस्तार और उसे समेकित करना चाहती है, उसके पास जनता-जनार्दन के साथ निकट, निरंतर एवं सीधा संपर्क स्थापित करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। यह किसी विपक्षी दल के लिए सत्य है तो यह किसी शासक दल के लिए भी उतना ही सत्य है। हम सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाने के लिए नौकरशाही अथवा मीडिया पर निर्भर नहीं रह सकते। न हम उनपर इस बात के लिए निर्भर रह सकते हैं कि वे लोगों की समस्याओं तथा मुद्दों को सरकार तक पहुँचाएँगे। जनता और सरकार के बीच दोनों तरफ से संपर्क सूत्र का महत्त्वपूर्ण कार्य तो पार्टी संगठन ही कर सकता है।

3. पार्टी में युवा शक्ति को बढ़ावा देना

शासक दल के नाते भाजपा को अपनी चिंताओं के क्षितिज को अधिक गहरा तथा व्यापक बनाना होगा। हमारे चारों ओर की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। सतही तौर पर संभवतः केवल अथवा मुख्य रूप से नकारात्मक परिवर्तन ही दिखाई दें। परंतु यदि संतुलित रूप से देखा जाए तो दुनिया में बड़ी सकारात्मक दिशा में परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे अधिक ठोस और आह्लादजनक विशेषता हमारे स्वप्नदृष्टा नवयुवकों की गतिशीलता है। वे ऊर्जा एवं विचारों और यहाँ तक कि आदर्शों से भी भरपूर हैं। भाजपा को अपने निरंतर नवीकरण के लिए इस युवाशक्ति के जलाशय का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए। विशेषरूप से हमें अधिकाधिक शिक्षित, विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित कुशल व्यवसायियों को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करना चाहिए तथा उन्हें खास-खास जिम्मेदारियाँ सौंपनी चाहिए।

4. ठोस विचारधारा और उच्च आदर्शवाद

अंतिम, किंतु जो कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको चेतावनी का एक शब्द

कहना चाहता हूँ। संपूर्ण विश्व का अनुभव हमें यह बताता है कि सत्ता अत्यधिक प्रतिबद्ध तथा सुसंगठित दलों को भी भ्रष्ट कर देती है। हमने देखा है कि हमारे देश में राजनीतिक दलों, जिनमें कभी महान् रही कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, का क्या हश्र हुआ। जो पार्टी सत्ता के ताम-झाम से अभिभूत हो जाती है, अनिवार्य रूप से अपनी दिशा और प्रयोजन को खो बैठती है। ऐसी पार्टी लंबे समय तक आपस में सामंजस्य नहीं रख सकती और इस कारण शासन को सुचारु रूप से चलाने का ऐतिहासिक कार्य उसके बस में नहीं रहता।

अभी तक भाजपा इस समस्या से अधिकांशतया मुक्त रही है। किंतु हम आत्मसंतुष्ट नहीं रह सकते। यह आवश्यक है कि हम अपने आपको निरंतर यह याद कराते रहें कि विचारधारा को आदर्शवाद से अलग नहीं किया जा सकता। उच्च आदर्शवाद के बिना विचारधारा थोथी है और ठोस विचारधारा के बिना आदर्शवाद महत्त्वहीन है।

ठोस विचारधारा और उच्च आदर्शवाद के इस मिश्रण को, जो भारतीय जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी की जन्मजात पहचान है, हमें आगामी वर्षों तथा दशकों में भाजपा में सोच-समझकर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे ही 'भारतीय राजनीतिज्ञ की भौंडी' छवि मिटाई जा सकती है, जो आजकल आम जनता में प्रचलित है।

ठाकरेजी के नेतृत्व में पार्टी का भविष्य उज्ज्वल

आज जब मैं आपसे पार्टी अध्यक्ष के रूप में विदाई ले रहा हूँ तो मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरी कामना है कि वे इस कठिन घड़ी में पार्टी को नेतृत्व प्रदान करें। वस्तुतः हमें ठाकरेजी से अधिक समर्पित, निस्वार्थ एवं सरल स्वभाव का व्यक्ति अपने में से ही नहीं मिल सकता। उनमें पार्टी को प्रेरणा, उदाहरण एवं नेतृत्व प्रदान करने की अद्वितीय योग्यता है। ठाकरेजी जानते हैं कि एक सही स्वरूप वाली पार्टी ही सरकार बना सकती है किंतु सरकारें पार्टियाँ नहीं बना सकती। मुझे पूरा निश्चय है कि ठाकरेजी जैसे पूर्णतया संगठन को समर्पित व्यक्ति ही अपने संयम एवं सादगी के अद्भुत उदाहरण से आगे आनेवाले कठिन वर्षों में हमारी नैया पार लगाएँगे।

मित्रो, इतिहास ने हमें अपने प्रिय राष्ट्र की सेवा करने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। इसके साथ ही इतिहास को हम से बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं इस पद से मुक्त होते समय मेरा हृदय आशा एवं विश्वास से परिपूर्ण है कि हमारी पार्टी अपने ध्येय में सफल होगी। इस निरंतर प्रयास में मैं अपना विनम्र योगदान करता रहूँगा।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली 26-27 जुलाई, 1997

संयुक्त मोरचा सरकार का पतन अवश्यंभावी

मैं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में आए सभी का स्वागत करता हूँ।

आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि आज केंद्र में जिस प्रकार की अत्यंत अराजकतापूर्ण राजनीतिक स्थिति चल रही है, उसके संदर्भ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक का अत्यधिक महत्त्व है। पिछली बार जब 6-7 अप्रैल, 1997 को इसी सभागार में हम मिले थे, तब से देश के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा नाटकीय परिवर्तन हुआ है, हालाँकि यह परिवर्तन पूर्वानुमान के अनुरूप ही रहा है।

संयुक्त मोरचा सरकार का हास्यास्पद स्वरूप उसके अंदर के विभाजनकारी रूप से पूरी तरह मेल खाता है। जब हम अप्रैल में मिले थे, उस समय इस अवसरवादी संगठन ने अपनी ही समर्थनकारी कांग्रेस पार्टी के घातक हमले के सामने खुद अपना सिर काटकर कांग्रेस के कदमों में चुपचाप रखकर अपनी जान बचाई थी। सचमुच तब किसी को यह विश्वास नहीं था कि संयुक्त मोरचा सरकार के 'शिरच्छेदन' के इस चमत्कारिक कारनामे के बाद उसकी कालावधि और लंबी हो जाएगी। परंतु अब इस अस्वाभाविक मोरचे के जिस तरह से तेजी से टुकड़े हो रहे हैं, उससे सभी को यह पक्का विश्वास हो गया है कि श्री इंद्र कुमार गुजराल की सरकार की आखिरी घड़ियों की उल्टी गिनती सचमुच शुरू हो गई है।

इस अंतराल में जनता दल में बड़ा भारी विभाजन देखने को मिला है, संयुक्त मोरचा की प्रमुख पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी तोड़कर प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय जनता दल बना लिया है। इस विभाजन के साथ-साथ लालू प्रसाद यादव का जैसा शोचनीय व्यवहार रहा है और प्रधानमंत्री ने आखिरी क्षणों तक अपनी कुरसी बचाने के लिए जिस प्रकार की लगभग सह-अपराधी की भूमिका अदा की, उससे देश का शासन चलाने के लिए संयुक्त मोरचा की जो थोड़ी वैधता थी, वह भी

समाप्त हो गई। इन दोनों घटनाओं ने संयुक्त मोरचा के अंदर जो भी भ्रम और अस्त-व्यस्तता की हालत थी, उसे और बदतर बना दिया तथा अब संयुक्त मोरचा ने अनेकानेक जबानों से उलटी-पुलटी बातें करना शुरू कर दिया है।

संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति का अपमान

बिहार में कल जो कुत्सित घटनाचक्र चला है, वह संयुक्त मोरचा-कांग्रेस गठबंधन की अनैतिकता का चरम उदाहरण प्रस्तुत करता है। महीनों तक आरोपित श्री लालू प्रसाद यादव त्याग-पत्र देने से इनकार करने पर अड़े रहे। इससे भी खराब बात यह रही कि कांग्रेस और संयुक्त मोरचा के घटकों ने सक्रिय या निष्क्रिय रूप से उन्हें अपने पर पर बने रहने में मदद की। अंततः उन्होंने त्याग-पत्र दिया, परंतु यह त्याग-पत्र तब दिया जब उन्होंने देख लिया कि वह न्यायपालिका के लंबे हाथों से अब बच नहीं सकते हैं। अब भी उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठाकर त्याग-पत्र दिया। उनकी पत्नी से बड़ा कोई राजनेता ढूँढ़ना मुश्किल है। साथ ही संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति के इससे बड़े अपमान की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

लोकतांत्रिक संस्कृति का भी पतन

पटना के इस घटनाचक्र से यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है कि श्री लालू प्रसाद यादव का त्याग-पत्र एक ढोंग है, स्पष्ट रूप से धोखा है, जिससे वह किसी को भी मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इन परिस्थितियों में त्यागपत्र का मतलब अपने अपराध के प्रति जवाबदेही का दायित्व होना है। परंतु श्री यादव के व्यवहार से पता चलता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को और इस पद से प्राप्त पाप की कमाई को अपने परिवार में ही रखने का दुराग्रह बना रखा है। जब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में गिरतार होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में त्याग-पत्र देना और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना, मात्र पाखंड ही नहीं है, अपितु यह सरासर धोखा है। इससे पता चलता है कि श्री यादव को अपनी पार्टी के किसी सहयोगी पर जरा सा विश्वास नहीं है, जिससे यह बात भी खुलकर सामने आती है कि विकृत-सामाजिक न्याय और छद्म-पंथनिरपेक्षता की राजनीति करनेवाले हमारे विरोधियों में लोकतांत्रिक संस्कृति का किस हद तक पतन हो गया है।

संयुक्त मोरचा और कांग्रेस के बीच अनैतिक समझौता फॉर्मूला

बिहार में जो कुछ हुआ है, वह कोई संयोग मात्र नहीं है, बल्कि संयुक्त मोरचा और कांग्रेस जिस प्रकार की अनैतिक राजनीति चला रहे हैं, यह उसी का संपूर्ण तार्किक उपसंहार है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि श्री लालू प्रसाद ने जिस

प्रकार का धूर्ततापूर्ण रास्ता अपनाया है, वह उसके सभी संरक्षकों सर्वश्री सीताराम केसरी, इंद्र कुमार गुजराल और हरकिशन सिंह सुरजीत के हितों के लिए फलदायी है। न तो वह, न ही उनके हितैषी बिहार सरकार को बरखास्त करने और विधानसभा को भंग करना चाहते थे। संयुक्त मोरचा-कांग्रेस गठबंधन ने, जिन्होंने पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश और गुजरात में गलत ढंग से दो बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने में जरा भी नहीं सोचा, षड्यंत्र रचकर देश में सर्वाधिक दागदार राजनीतिज्ञ को आखिरी दम तक, बल्कि उसके बाद तक भी अपनी मनमानी करने दी। ऐसा लगता है कि दरअसल यह वह 'समझौता-फॉर्मूला' था जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से संयुक्त मोरचा-कांग्रेस बात कर रही थी।

इस प्रकार अब केवल इसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि भारत के गणतंत्रीय इतिहास में इस सरकार जैसी कभी कोई इतनी सिद्धांतहीन, इतनी कमजोर, इतनी प्रतिनिधित्वहीन और इतनी आत्मविश्वास से वंचित सरकार नहीं रही—और यह एक ऐसी सरकार है जो बिलकुल भी सरकार कहलाने लायक नहीं है।

पिछले साढ़े तीन महीनों में प्रधानमंत्री पूरी तरह हमारे इस पुर्वानुमान पर खरे उतरे हैं कि उनके कार्यकाल की अवधि ठीक ही लंबी होती जाएगी, जितनी उनमें अपनी और अपने उच्च पद की बेइज्जती सहने की क्षमता होगी। एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जब प्रधानमंत्री स्वयं को उपहास का पात्र न बनाते हों और विश्व में भारत की बदनामी न कराते हों।

प्रधानमंत्री की सत्ता-लिप्सा

आरंभ में उनके साथ सहानुभूति रखने वाले और जाने-माने आलोचकों ने भले ही उनकी विवशता की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें संदेह का लाभ दिया हो। परंतु जैसे-जैसे समय गुजरता गया और उन्होंने बिना कोई विरोध किए अपने पार्टीजनों तथा मोरचा के सहभागियों, दोनों का अपमान सहा तथा कपटी कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए एक के बाद एक अपमान को सहना जारी रखा तो स्पष्ट हो गया है कि श्री गुजराल विवशता के उतने शिकार नहीं हैं जितना कि उनमें ढोंग करने और कुरसी के साथ चिपके रहने की व्यक्तिगत लालसा है। जिस ढंग से उन्होंने सी बी आई के पद से अचानक ही श्री जोगिंदर सिंह को हटाकर या बिहार के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के मामले में ढुलमुल नीति अपनाकर अपना दो-मुँही चेहरा दिखाया या जिस तरह से उन्होंने अलग हुए राष्ट्रीय जनता दल के अपने मंत्रिमंडल के तीन मंत्रियों को हटाने से इनकार कर दिया, इन सबसे यही पता चलता है कि उन्होंने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर रखा है।

अब मुद्दा यह नहीं रह गया है कि स्पष्ट ही जो असंवैधानिक स्थिति सामने है, उसे देखते हुए श्री लालू प्रसाद की पत्नी के नेतृत्व वाली परोक्षी सरकार को क्यों सत्ता में रहने दिया जाए। अब मुद्दा यह है कि गुजराल सरकार में पूरी तरह

नैतिकता का दिवाला पिट जाने के बाद उनकी यह सरकार सत्ता में क्यों बनी रहे?

वस्तुतः इस लड़खड़ाती सरकार के गिरने की अटकलें इस बात पर नहीं घूम रही हैं कि सरकार गिरने वाली है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि यह सरकार कब गिर रही है और कितनी जल्दी। अब कांग्रेस और संयुक्त मोरचा के घटकों ने भी इस बात को समझ लिया है। इसी कारण कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त मोरचा में उनके विरोधी (विशेष रूप से दो वामपंथी पार्टियाँ) अपने को चुनाव और चुनाव के बाद की स्थिति में रखकर देख रहे हैं। इनमें विरोधाभास और अंतर्द्वंद्व के बावजूद दोनों ही एक समान लक्ष्य से प्रेरित हैं: 'भाजपा को रोको'।

फिर भी कांग्रेस और संयुक्त मोरचा में हमारे विरोधियों ने भी यह अच्छी तरह समझ लिया है कि इस बार भाजपा के निरंतर बढ़ते कदमों को शीर्ष स्थान पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकेगा। इससे उनमें ऐसा भय और हताशा छा गई है कि वे भाजपा के बढ़ते कदमों को रोकने या उसकी गति धीमी करने के लिए किसी भी हद तक और कैसे-कैसे बेतुके कार्य करने पर उतारू हैं।

अन्यथा मुंबई में हाल में दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना पर महाराष्ट्र की भाजपा-शिव सेना सरकार की बरखास्तगी की हास्यास्पद माँग को और क्या कहा जा सकता है, जबकि इस घटना के पीछे भी कांग्रेस का षड्यंत्रकारी हाथ दिखाई पड़ता है। और जैसा कि स्वयं गृहमंत्री ने लोकसभा में बुधवार को कहा था कि कांग्रेस का भी मुंबई के एक अपराध जगत् के जाने-माने सरगना के साथ मेलजोल है, और वह भाजपा-शिव सेना के खिलाफ हाल में चलाए गए उसके राजनीतिक अभियान में उसे प्रच्छन्न रूप से समर्थन दे रही है।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा के मध्यावधि चुनाव होने से पहले बसपा के साथ हमारे गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करने के अलावा राज्य के बदनाम राज्यपाल के पद का इस्तेमाल कर भाजपा-बसपा गठबंधन सरकार को अस्थिर करने में लगी है। बिहार में वह हाल के भारतीय इतिहास में सबसे अधिक दागदार राजनेता का खुला बचाव इस उम्मीद में कर रही है कि शायद कांग्रेस को फिर से वहाँ राज्य में सत्ता में लाया जा सके।

अत्यंत सतर्कता आवश्यक

आनेवाले कुछ महीनों में कांग्रेस और संयुक्त मोरचा में इसके सहयोगी दलों द्वारा भाजपा-शासित राज्यों को अस्थिर करने के षड्यंत्रों को देखते हुए हमारी पार्टी को अत्यंत सतर्क रहना होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे सहयोगी दल भी इस खतरे को महसूस करेंगे और लोकतंत्र के हित में तथा कांग्रेस और संयुक्त मोरचा का एक स्थायी और विश्वसनीय विकल्प बनने के लिए उपयुक्त प्रत्युत्तर देंगे।

देश छद्म पंथ निरपेक्षवादी गठबंधन से दुःखी

प्रिय बंधुओ, कांग्रेस और संयुक्त मोरचा की कपटपूर्ण राजनीति के दिन पूरे हो गए हैं। कोई चमत्कार भी न तो गुजराल सरकार को बचा सकता है और न ही भ्रष्ट और सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञों की इस चौकड़ी की खोई विश्वसनीयता को बहाल कर सकता है। यहाँ तक कि 11वीं लोकसभा के चुनावों में मतदाताओं के जिन वर्गों ने हमें वोट नहीं दिया था, वे भी संयुक्त मोरचा और कांग्रेस के छल-बल को समझ गए हैं अर्थात् 'सांप्रदायिक ताकतों' से लड़ने के नाम पर भाजपा को सत्ता से बाहर रखने का तीव्र अभियान केवल एक बहाना है, ताकि वे बैठे-बिठाए सत्ता में बने रहें। पूरा राष्ट्र कांग्रेस, कम्युनिस्टों, लालू प्रसाद यादवों और छद्म-पंथनिरपेक्षवादी गठबंधन में उनके साथियों के निकृष्ट आचरण से दुखी है।

जनता भाजपा के पक्ष में

समय बदल रहा है। भारत के राजनीतिक भू-दृश्य पर नई हवा बहने लगी है। लोगों ने पहले ही मन बना लिया है कि जब कभी भी चुनाव होंगे वे भाजपा और उनके सहयोगी दलों को केंद्र सत्ता में लाकर ही रहेंगे। मेरा तो विचार है कि आज पूरी तरह ऐसी यथार्थ स्थितियाँ बन गई हैं कि यह भाजपा और इसके सहयोगी दल के पक्ष में लहर का रूप लेती जा रही है। यदि हमारी अपेक्षित तैयारियाँ इन यथार्थ स्थितियों के अनुरूप बनाई जा सकें तो यह संभावना निश्चितता में बदल सकती है।

मेरा यह विश्वास अनेक तत्त्वों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि हाल में संपन्न स्वर्ण जयंती रथ यात्रा के संबंध में मेरे अनुमान और विश्लेषण के आधार पर होती है। इस यात्रा के कारण मुझे और मेरे सहयोगियों को लोगों के मनोभाव जानने का अवसर मिला। एक के बाद एक राज्यों में रथयात्रा के स्वागत में लोगों के चेहरों पर जो मुसकान देखी, उन्होंने जैसा स्वागत किया, जिस प्रकार से हाथ-हिलाकर, तालियाँ बजाकर और नारे लगाकर उत्साह प्रगट किया, उससे एक संदेश जोर-शोर से मुखरित हुआ : "हम भारत के लोग नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। हम एक स्थायी सरकार चाहते हैं और हमें दृढ़ विश्वास हो गया है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ही एक स्थायी और अच्छी सरकार बन सकती हैं।"

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को स्मरण होगा कि भाजपा की 13 दिन के शासन के समाप्त होने के तुरंत बाद जुलाई में हमारे भोपाल अधिवेशन में हमने अपनी पार्टी के प्रभाव को और नए सामाजिक तथा भौगोलिक क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में फैलाने का संकल्प किया था। केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रथयात्रा का जो भव्य स्वागत हुआ है, उससे मेरा विश्वास दृढ़ हुआ है कि इन क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। यदि इन राज्यों

में हम अपना संगठनात्मक आधार मजबूत कर सकें तो हम निश्चय ही अगले चुनावों में ही लाभ उठाने में सफल होंगे।

प्रिय बंधुओ, आज देश में भाजपा के समर्थन में जो वातावरण बनता जा रहा है, उसमें हमारे विरोधियों की सिद्धांतहीन राजनीति और उनमें आपसी असहमति का आचरण बहुत हद तक एक कारण है। इससे भाजपा का 'नकारात्मक वोट' तैयार होता है; किंतु मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि भाजपा के समर्थन में जो वातावरण बना हैं, उसके 'सकारात्मक' पहलू को बड़े स्तर पर विस्तार देने की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि अब तुरंत ही और पूरी ईमानदारी से संपूर्ण पार्टी के तंत्र को लामबंद किया जाए, जिससे निम्नलिखित 'सकारात्मक' संदेश पर लोगों का ध्यान केंद्रित कर निर्णायक चुनावी लड़ाई लड़ी जाए :

स्थायित्व का तुरुप कार्ड भाजपा के हाथ में

1. अनेक दशकों से कांग्रेस पार्टी चुनावों में स्थायित्व के कार्ड को तुरूप कार्ड बनाकर चलती रही है। जब से कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोरचा की सरकार बनी है, जिसमें आरंभ से ही स्थायी रूप से अस्थिरता और पूरी तरह अनिश्चितता रही है, तब से स्थायित्व कार्ड कांग्रेस के हाथों से निकल गया है और भाजपा के पास आ गया है अब तो लोगों को पूरा यकीन हो गया है कि केवल भाजपा ही एक स्थायी और ईमानदार सरकार दे सकती है; परंतु हमारे अभियान में जिस बात पर बल देना आवश्यक है, वह यह है कि लोंगों को पता चले कि अस्थिरता की कितनी अधिक सामाजिक-आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है और इसलिए भाजपा और इसके सहयोगियों के लिए लोकसभा में भाजपा को एक पर्याप्त बहुमत दिलाना अनिवार्य है।
2. भाजपा को अपने चुनावी संदेश में 'भय, भूख और भ्रष्टाचार' को उखाड़ फेंकने का चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए।

पंथ निरपेक्षता की जड़ें हिंदुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में

3. भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्रवाद की भावना को पुनर्जीवित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। भाजपा को दृढ़ होकर इस बात का समर्थन जारी रखना चाहिए कि वास्तविक पंथनिरपेक्षता की जड़ें हिंदुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में ही जमी हैं, जो शुरू से ही हमारी पार्टी का प्रमाण-चिह्न है। खुशी की बात है कि अल्पसंख्यक समुदायों के एक महत्त्वपूर्ण वर्ग ने हमारे इस विचार के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया प्रगट करनी आरंभ कर दी है। हैदराबाद के आर्क बिशप 'अलप्पा' ने सार्वजनिक रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हमारी संकल्पना से सहमति व्यक्त की है और पुष्टि की है : "मैं धर्म से ईसाई हूँ, परंतु मेरी संस्कृति हिंदू है।"

भाजपा एकता की शक्ति

4. आज के दूषित सामाजिक–राजनीतिक वातावरण में भाजपा को यह एक बड़ा लाभ है कि उसने एक ऐसी पार्टी के रूप में बड़ी मेहनत से यह प्रतिष्ठा प्राप्त की है कि वह एक पार्टी है जो लोगों को एक सुदृढ़ राष्ट्रीय नींव पर संगठित करती है, जबकि इसके ठीक विपरीत, हमारी विरोधी पार्टियाँ भारतीय समाज को जाति, समुदाय और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित करने के कुत्सित प्रयास करती हैं। हमें चुनाव के दौरान इस महत्त्वपूर्ण लाभ को और ठोस रूप देना चाहिए। पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों और इन प्रयासों में मिली सफलता को अच्छी तरह उजागर करने की आवश्यकता है।

भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री

5. 25 जून को जयपुर में भाजपा शासित राज्यों का सफल सम्मेलन हर लिहाज से केंद्र–राज्य संबंधों के बारे में एक अभूतपूर्व सम्मेलन रहा। एक जवाबदेह प्रशासन और जनता के हित में सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सत्ता के विकेंद्रीयकरण के प्रति हमारी पार्टी की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता के प्रसंग मे यह मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हमें अपने चुनाव से पूर्व और चुनाव के एजेंडे में केंद्र–राज्य संबंधों की पुनः संरचना तथा राज्यों को और अधिक वित्तीय एवं प्रशासकीय शक्तियाँ प्रदान करने तथा इसके बाद इन्हें जिलों और ग्राम पंचायतों तक प्रदान करने को एक प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए।

प्रिय साथियो, इस समय भाजपा के समर्थन में बने वातावरण में 'सकारात्मक' तत्त्व को अधिक–से–अधिक महत्त्व दिया जाए, इसकी आवश्यकता के बारे में अधिक कहने की जरूरत नहीं है। यह हमारे लिए लोकसभा में अच्छा बहुमत प्राप्त करने के लिए अपने वोट प्रतिशत में पर्याप्त रूप में वृद्धि करने के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि सत्ता में आने के बाद भाजपा देश को अच्छा शासन प्रदान कर सके। संक्षेप में, आनेवाले संघर्षपूर्ण महीनों में हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए :

आइए, हम शासन सँभालने के लिए तैयार हों;
आइए, हम भारत को सुशासन देने का संकल्प करें।

पार्टी ने इस वर्ष जनवरी में अपने वरिष्ठ नेताओं की एक चिंतन बैठक की थी। संगठन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर पर्याप्त गहन चर्चा करने के बाद 1997 को 'संगठन–वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।

राष्ट्रवादी विचारधारा और आदर्श

प्रिय बंधुओ, आइए, हम आज की स्थिति पर शांतचित होकर विचार करें और संपूर्ण रूप से अपने संगठन की शक्तियों और कमजोरियों का ही जायजा लें। जहाँ एक तरफ सबसे बड़ी शक्ति हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा और आदर्श रहे हैं जो पिछले साढ़े चार वर्षों में भारतीय राजनीति में हर तरह की झंझावाती स्थितियों में भी हमारी शक्ति बन कर हमारे काम आते रहे हैं वहीं दूसरी तरफ पार्टी के दो महान् मार्गदर्शी प्रकाश स्तंभ–डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय–हमारी शक्ति बने रहे हैं, जो इस विचारधारा और इन आदर्शों के प्रणेता थे। आइए, हम इस शक्ति को स्थायित्व प्रदान करें जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर पार्टी के नेतृत्व को चाहिए कि वह समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी विचारधारा तथा आदर्शों को समर्थन देना जारी रखे।

निःसंदेह यह सत्य है कि हमारी बहुत सी समस्याओं (जैसे अत्यधिक महत्त्वाकांक्षा, राजनीति में व्यक्तिगत लाभ का विचार, गुटबंदी आदि) के पीछे दो तत्त्व कहे जा सकते हैं। पिछले एक दशक में हमारी पार्टी की अथाह श्रीवृद्धि और देश में विद्यमान प्रदूषित वातावरण, जिसमें पार्टी को रहना पड़ रहा है। हमने कई वर्ष पहले ही इस बीमारी के लक्षणों को पहचान लिया था। किंतु हमें इस रोग का उपचार तुरंत शुरू करना होगा, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में यह और भी जरूरी है जबकि हम केंद्र में सता सँभालने के नजदीक खड़े हैं।

भाजपा पर भारी जिम्मेदारी

हमारे द्विवर्षीय संगठन चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं। कितने सुचारू ढंग से और सद्भावपूर्वक हम इन चुनावों को संपन्न करते हैं, यही हमारे लिए एक खरी कसौटी सिद्ध होगी कि हम विरार निर्णयों के कार्यान्वयन करने में कहाँ तक सफल हुए हैं।

इतिहास भाजपा पर एक भारी जिम्मेदारी डालने जा रहा है। जब नियति इस महान् राष्ट्र का शासन चलाने और कभी महान् रही कांग्रेस तथा इसके सहयोगी संगठनों ने देश को जिस भ्रष्टाचार तथा कुशासन की दलदल में डाल दिया है उससे देश को बाहर निकालने का भार हम पर डाले तो हम इसे वहन करने में अशक्त न पाए जाएँ।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

भुवनेश्वर

19–21 दिसंबर, 1997

प्रिय बंधुओ, मैं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस महत्त्वपूर्ण बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह बैठक देश के राजनीतिक इतिहास के असाधारण अवसर पर हो रही है। उथल-पुथल का एक वर्ष समाप्त हुआ है। एक नए विजय-वर्ष की शुरुआत होने वाली है।

भाजपा सरकार : अटलजी का नेतृत्व

1997 में संयुक्त मोरचा सरकारों के पतन की इबारत भाजपा ने नहीं लिखी; परंतु निश्चय ही वह भारतीय राजनीति का बिलकुल एक नया अध्याय लिखेगी। आइए, आगे बढ़ें और हम देखेंगे कि भारत में मार्च में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी।

सामान्य रूप से अब तक एक नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और एक नए अध्यक्ष के अधीन पदाधिकारियों की एक नई टीम बन जानी चाहिए थी। कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में संगठन चुनाव संपन्न हो चुके हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पार्टी का पूर्ण अधिवेशन भी नवंबर में कानपुर में संपन्न हो जाना था, जहाँ मुझे अध्यक्ष का कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को सौंप देना था।

परंतु लोकसभा के मध्यावधि चुनावों के बारे में पहले तो पूर्वानुमान और बाद में यह चुनाव निश्चित हो जाने के कारण पार्टी के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष का चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया और मुझसे इस पद पर तब तक बने रहने को कहा जब तक निर्णायक चुनाव समाप्त नहीं हो जाते हैं। पार्टी ने मुझमें जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उसका आभारी हूँ।

घटनाचक्र ने हमारे विश्लेषण को सही ठहराया

26–27 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली

बैठक में हमने भविष्यवाणी की थी : "गुजराल सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है।" हमने विस्तार से इसकी व्याख्या करते हुए कहा था : "पिछले साढ़े तीन महीनों में प्रधानमंत्री श्री इंद्रकुमार गुजराल हमारी भविष्यवाणी पर पूरी तरह खरे उतरे हैं कि उनके कार्यकाल की अवधि ठीक उतनी ही लंबी होती जाएगी जितनी उनमें अपनी और अपने उच्च पद की बेइज्जती सहने की क्षमता होगी। एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जब प्रधानमंत्री स्वयं को उपहास का पात्र न बनाते हों और विश्व में भारत की बदनामी न कराते हों।"

देश के शासन में भाग्य से बने प्रधानमंत्रियों का प्रवेश उतना ही आश्चर्यजनक है, जितना उनका निष्कासन अपमानपूर्ण होता है। किंतु यह कोई दैवयोग नहीं है, यह तो अस्वाभाविक, नकारात्मक और विकृत राजनीति का अनिवार्य परिणाम है। हाल के वर्षों में जिसका सहारा हमारे विरोधी केवल भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के उद्‌देश्य से लेते रहे हैं।

नकारात्मक राजनीति

नकारात्मक राजनीति से लोकतंत्र विकृत होता है। और जब लोकतंत्र में धोखाधड़ी के नियम चलने लगते हैं तो सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाता है और अहम टकराते हैं, जिसके प्रतिफल को इसके बिगाड़ने वाले भी एक निश्चित समय के बाद नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। न तो श्री इंद्र कुमार गुजराल और न ही श्री केसरी ने इस षड्‌यंत्र की इबारत लिखी थी, जिसके कारण संयुक्त मोरचा की दूसरी सरकार का पतन हुआ और मध्यावधि चुनावों की आवश्यकता पड़ गई; परंतु भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के एक बड़े षड्‌यंत्र में मुख्य रूप से लाभ उठाने वाले और सह-अपराधी महँगे दुष्परिणामों से बच नहीं सके।

'स्थायी सरकार, सुयोग्य प्रधानमंत्री'

संयुक्त रूप से कांग्रेस-संयुक्त मोरचा के नेताओं की अत्यंत निम्न किस्म की चालबाजियों ने दो मुद्‌दों पर खास ध्यान केंद्रित किया है, जिनसे चुनाव अभियान की दिशा और परिणाम तय होगा : सरकार का स्थायित्व और प्रधानमंत्री की योग्यता। इन दोनों मामलों में हमारी पार्टी अन्य सभी विरोधी पार्टियों से हर प्रकार से सर्वोपरि है।

भाजपा के पास श्री अटल बिहारी जैसे नेता हैं, जो न केवल पार्टी की अपनी पसंद हैं, बल्कि वह राष्ट्र की स्वाभाविक पसंद हैं। जब कांग्रेस और अन्य पार्टियों के अपने सितारे गगन में चमक रहे थे, उस समय भी अटलजी की दमक उन सबसे कहीं अधिक उज्ज्वल थी। आज जब हमारी विरोधी पार्टियों का नेतृत्व बौने लोग कर रहे हैं और वे प्रधानमंत्री पद के लिए अपना कोई उम्मीदवार भी प्रस्तुत

करने की स्थिति में नहीं हैं तब भारत की जनता द्वारा श्री अटलजी के नेतृत्व की स्वीकृति पूर्व-निर्धारित निष्कर्ष है।

स्थायित्व का कार्ड भाजपा की झोली में

स्थायित्व के मामले में भी भाजपा ही भारत में एक स्वाभाविक विकल्प है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जुलाई की बैठक में मैंने कहा था : "अनेक दशकों से कांग्रेस पार्टी चुनावों में स्थायित्व के कार्ड को तुरूप कार्ड बनाकर चलती रही है। जब से कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोरचा की सरकार बनी है, जिसमें आरंभ से ही स्थायी रूप से अस्थिरता और पूरी तरह अनिश्चितता रही है, तब से स्थायित्व का कार्ड कांग्रेस के हाथों से निकल गया है और भाजपा की झोली में आन पड़ा है।"

बाद की घटनाओं ने इस विश्लेषण को मूलतः सही सिद्ध कर इसकी और अधिक पुष्टि की है। 17 महीनों की अवधि में संयुक्त मोरचा की दो सरकारों के पतन ने विशाल स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि संवैधानिक रूप में बहुत क्षति की है। देश में हर वर्ग के लोगों ने माना है कि केंद्र में सरकार की अस्थिरता से होने वाले विशाल खर्च को भारत किसी तरह वहन नहीं कर सकता है।

इस बार भाजपा

ठीक इसी कारण से प्रत्येक वर्ग के लोग उसी पार्टी और गठबंधन के समर्थन में मतदान करेंगे, जिसके द्वारा स्थिर सरकार बनाने की संभावना सबसे अधिक होगी। विघटित कांग्रेस और बदनाम तथा विभाजित संयुक्त मोरचा की जमीनी वास्तविकता के संदर्भ में आज की स्थिति को देखें तो इसका अर्थ यही निकलता है कि भाजपा और इसके सहयोगी दलों को समर्थन मिलेगा।

स्थायित्व के तत्त्व के साथ-साथ एक और कारण है, जो भाजपा के लिए समर्थन का और बड़ा आधार बनता है। भारतीय मतदाता के अंदर स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक चेतना है, जो आज अधिकांशतः भारतीयों के मस्तिष्क और मुख से स्वतः इस प्रकार प्रस्फुटित हो रही है : "हमने नई दिल्ली में अन्य सभी पार्टियों को सत्ता में देख लिया है। इस बार हमें भाजपा को मौका देना चाहिए।"

भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में भाजपा कांग्रेस का स्थान ले लेगी।

ऊपर दिए गए दो कारणों से भाजपा के लिए एक ऐसी यथार्थ स्थिति पैदा हो गई है, जिससे पिछले दो चुनावों में हमें मिले 20 प्रतिशत मतों से कहीं अधिक मत प्राप्त होंगे। भौगोलिक और सामाजिक, दोनों रूपों में भारत के अनेकानेक वर्गों के जो लोग परंपरागत रूप से हमारी पार्टी के समर्थक नहीं थे, आज मतदान करने में उनका भी झुकाव हमारी ओर है।

के लिए तैयार खड़ी है। किंतु हमने बार-बार इस बात की प्रतिज्ञा की है कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है। यह तो शासन में फर्क लाने और इसके द्वारा अर्थव्यवस्था, समाज, संस्थाओं तथा विश्व में भारत की स्थिति में एक ठोस फर्क लाने का एक आवश्यक साधन मात्र है।

भाजपा समर्थन लहर

शासन में ठोस फर्क लाने के लिए हमें अपने अभियान को ही एक सुदृढ़ ठोस आधार पर रखकर इस की शुरुआत करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य न केवल कांग्रेस व संयुक्त मोरचे के अपमानजनक आचरण के फलस्वरूप, जिसने राष्ट्र पर एक खर्चीला और अनावश्यक मध्यावधि चुनाव थोप दिया है, नकारात्मक वोट के आधार पर, अपितु प्रेरणा के द्वारा अर्जित सकारात्मक वोट के आधार पर भी भाजपा के पक्ष में एक हवा बाँध देना होना चाहिए। हमें केवल और यहाँ तक कि कांग्रेस तथा संयुक्त मोरचे के कुकृत्यों और कुशासन पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। लोगों को इस पहलू का पहले से ही ज्ञान है और इसी ज्ञान की वजह से ही उन्होंने भाजपा को इस बार मौका देने का पहले से ही मन बना लिया है।

सकारात्मक कार्यक्रमों की प्रस्तुति

अभियान के दौरान तो मतदाता यही जानना चाहेगा कि सत्तारूढ़ होने पर भाजपा क्या करेगी। अतः इस चुनाव में मुद्दों तथा नीतियों और कार्यक्रमों को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में स्थिरता हमारा एक तुरूप का पत्ता है, जो पहले ही हमारे हाथ में हैं, हमें स्थिरता के संबंध में ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

हमारा सीधा-सादा स्पष्ट उत्तर यह होना चाहिए कि अच्छे शासन की पहली शर्त स्थिरता है। और सुशासन, जो शुचिता (सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता), सुरक्षा (देश तथा जनसाधारण की सुरक्षा), समरसता (सामाजिक सौहार्द) तथा स्वदेशी (आर्थिक राष्ट्रवाद) इन चार सिद्धांतों पर आधारित हो, इसकी दूसरी शर्त है जिससे भारत एक सुदृढ़, समृद्ध तथा स्वाभिमानी राष्ट्र बन जाए, जिससे विश्व के राष्ट्रों में उसका समुचित स्थान प्राप्त हो।

स्थिरता की खातिर स्थिरता नहीं

भाजपा को केवल स्थिरता के लिए स्थिरता में रुचि नहीं है। आखिर भारत ने ऐसी कांग्रेस सरकारें देखी हैं, जिन्हें संसद् में संख्यासुर का बहुमत प्राप्त था और फिर भी उसने राष्ट्र को भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद और सांप्रदायिकता के मार्ग पर धकेल दिया। भाजपा जो चाहती है और जिसका वायदा करती है वह

प्रगतिशील, सोद्देश्य स्थिरता है। तो हमारे सामने यह चुनौती है कि हम अपने आपको और राष्ट्र को यह साबित करके दिखा दें कि हम यथास्थितिवादी नहीं हैं, अपितु परिवर्तनवादी हैं, जो स्थिरता को राष्ट्र-निर्माण का एक अवसर और पहली शर्त समझते हैं।

दीनदयालजी के बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शक शब्दों को स्मरण कराना

उपरोक्त चुनौती के मद्देनजर चुनाव घोषणा-पत्र की सुसंगतता और उपयोगिता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। सामान्यतया अब तक चुनावों में चुनाव घोषणा-पत्र को तैयार करना एक कर्मकांड सा बन गया है और अभियान में इसकी विषयवस्तु को या तो नजरंदाज कर दिया जाता है अथवा पूर्णतया इसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थता को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक अद्वितीय स्थिति बन गई है, जिससे '98 के चुनाव एक सुदृढ़, ठोस और मुद्दा आधारित बन गए हैं। अतीत में जो बहुत से चुनाव हुए है उनकी अपेक्षा आगामी चुनाव अधिक शिक्षाप्रद होंगे और भाग लेने की दृष्टि से इनका महत्त्व बढ़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से, इससे सत्तारूढ़ होने पर इस पार्टी की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाएगी।

आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण

पार्टी की नीतियाँ और वायदे तैयार करते समय हमें आदर्शों तथा यथार्थता का अच्छा सम्मिश्रण करना चाहिए। इस प्रसंग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सन् 1962 के संसदीय चुनावों से ऐन पहले दिसंबर 1961 में 'आपका मत' शीर्षक से जो सुप्रसिद्ध निबंध लिखा था उसे स्मरण कराना बहुत शिक्षाप्रद होगा। यह निबंध उस समय लिखा गया था जब भारतीय राजनीति में भाजपा हाशिए पर थी, हम राजनीति में क्यों हैं, लोकतंत्र में चुनावों का क्या महत्त्व हैं, राजनीतिक नेताओं के व्यवहार का मानदंड क्या होना चाहिए और अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करते समय हमें किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, इन सब बातों को समझने के लिए अपनी याददाश्त ताजा करने हेतु आज भी उस निबंध को गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है।

पंडित दीनदयालजी लिखते हैं—"एक अच्छे दल का (तीसरा) गुण यह है कि इसके कुछ आदर्श होने चाहिए तथा इसकी सारी नीतियाँ इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए बनाई जानी चाहिए। यह सच है कि स्थिति का सैद्धांतिक विश्लेषण करके प्रशासन के व्यावहारिक कृत्यों को निश्चित रूप से सूत्रबद्ध नहीं किया जा सकता। परंतु कार्यसाधन तथा अवसरवादिता को यथार्थता का रूप नहीं देना चाहिए। यथार्थता आदर्शवादी, सिद्धांतयुक्त पुरुष, सोद्देश्य कार्यकर्ता का एक गुण है; यह उस व्यक्ति का लक्षण नहीं है, जिसकी आत्मा शीघ्र बदल जाए, जो

अवसरवादी हो और धर्मभ्रष्ट हो। राजनीतिक दल और उनके नेता अपने व्यवहार के द्वारा राजनीतिक जीवन के मूल्यों को निर्धारित करते हैं। वे नियम बनाते हैं। स्वाभाविक रूप से, उनकी नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए, जो किसी भी अवस्था में सार्वजनिक व्यवहार के इन नियमों का उल्लंघन न करें। लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है। इसके लिए सुसंगठित लोगों, सुसज्जित दलों और राजनीतिक व्यवहार की सुस्थापित परंपराओं की आवश्यकता होती है।

"एक अच्छे दल के पास, जिसके पास अच्छे उम्मीदवारों का समुच्चय हो, अच्छा यथार्थवादी कार्यक्रम भी होना चाहिए। आखिर कार्यक्रम को ही तो कार्यान्वित करना होगा। अच्छे लोग, जिनके पास खराब कार्यक्रम हो अथवा अव्यवहार्य कार्यक्रम हो, वे लोगों के कष्टों को दूर करने में मदद नहीं कर सकते। इसके विपरीत वे और अधिक कठिनाइयाँ पैदा कर देंगे।"

चुनाव घोषणा-पत्र तथा अभियान के लिए कुछ विचार

चुनाव घोषणा-पत्र समिति तथा अभियान समिति, जिनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इसी बैठक में गठन किया जाएगा, निस्संदेह, शीघ्र ही अपना काम शुरू कर देंगी। परंतु चर्चा और दिशा-निर्देश के लिए मोटे रूप में कुछ पथ-प्रदर्शक सिद्धांत मैं यहाँ अपने सहयोगियों के समक्ष रखना चाहता हूँ—

1. सुशासन

हमें सुशासन के लिए एक व्यापक योजना और इसकी प्राप्ति के अनिवार्य साधनों को प्रस्तुत करना चाहिए। इन अनिवार्य चीजों में यथासंभव अधिक-से-अधिक राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने का मार्ग है।

हमें लोगों को यह बताने में हिचकिचाना नहीं चाहिए कि राष्ट्र के समक्ष बड़ी पेचीदा समस्याएँ हैं और कोई सरकार उनका समाधान आसानी से नहीं निकाल सकती। इस कठोर सत्य के आधार पर हमें लोगों तथा अन्य दलों से अपील करनी चाहिए कि वे राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में उच्च स्तर पर साझेदार बनकर इसमें भाग लें।

2. चुनाव-सुधार

स्थिरता एवं सुशासन को संस्थागत रूप देने के लिए दूरगामी राजनीतिक तथा चुनावी सुधारों को करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को हमें बताना चाहिए।

3. लोगों की बुनियादी आवश्यकताएँ

हमारे समाज के सभी वर्गों को आर्थिक तथा विकास संबंधी मुद्दों की चिंता सता रही है। इसी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अंततोगत्वा किसी सरकार की कार्यकुशलता

की परीक्षा होती है। शासन करनेवाली स्वाभाविक पार्टी के रूप में भाजपा को लोगों में यह विश्वास पैदा करना होगा कि हम इन मुद्दों को अत्यधिक महत्त्व देते हैं और उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास निश्चित नीतियाँ और कार्यक्रम हैं।

दुर्भाग्य से, हमारे देश की आर्थिक नीति के बारे में मीडिया तथा राजनीतिक क्षेत्रों में और वस्तुतः संपूर्ण जगत् में जो बहुत सारी बहस चल रही है वह 'केंद्रीकरण अथवा खुला बाजार', 'स्वदेशी उद्योग अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ' आदि जैसे विवादास्पद सवालों पर केंद्रित है। मेरा यह तर्क नहीं है कि यह बहस असंगत अथवा व्यर्थ है। हमारी अपनी पार्टी के विचार इनके बारे में बिलकुल स्पष्ट है। परंतु भारत जैसे देश में आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य हमारे निर्धन एवं वंचित भाइयों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना होना चाहिए। भारत की राजनीतिक पार्टियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पीने के पानी, मकान, बाल एवं मातृ कल्याण तथा वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों की देखभाल जैसे मुद्दों के बारे में अधिक चिंता होनी चाहिए।

4. महान् भविष्य की परिकल्पना

हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में इन मुद्दों के बारे में मोटे रूप में सामान्य रूप से नहीं, अपितु स्पष्ट, परिणामोन्मुख, प्रेरणादायक और संगठित किए जाने योग्य शब्दों में अटल प्रतिबद्धता पूरी तरह दिखाई देनी चाहिए। मैं उदाहरण के रूप में यह सुझाव देना चाहता हूँ कि हमें 'बच्चों' के बारे में एक अलग और महत्त्वपूर्ण विभाग खोलना चाहिए। वे हमारे वोटर नहीं हैं, किंतु इनके संबंध में हम जो भी निवेश करेंगे—जो यह निवेश वित्तीय, बौद्धिक, सांस्कृतिक अथवा भावनात्मक संसाधनों के रूप में हो सकता है—यह निवेश भारत के भविष्य में होगा। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी इक्कीसवीं सदी में भारत में शासन करने की तैयारी कर रही है, इसलिए हमारे स्वप्न की विशालता भी हमारे महान् भविष्य के स्वप्न के समान होनी चाहिए, बल्कि जैसा कि दीनदयालजी कहा करते थे कि यह हमारे महान् अतीत से भी ज्यादा विशाल होना चाहिए।

5. केंद्र-राज्य संबंधों का पुनर्निर्माण

केंद्र-राज्य संबंधों का पुनर्निर्माण, सभी स्तरों पर सत्ता का विकेंद्रीकरण और जनता की भलाई के लिए प्रशासनिक सुधारों के बारे में सुदृढ़ प्रतिबद्धता का उल्लेख हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में होना चाहिए। यह न केवल भाजपा का प्रमुख विश्वास है, अपितु सभी प्रादेशिक दलों को भी इसके प्रति बड़ा आकर्षण है।

6. सामाजिक न्याय

देश की मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी होने की संभावना से हमारे चुनाव घोषण-पत्र पर यह अनिवार्य जिम्मेदारी पड़ गई है कि उसमें भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग—विशेष रूप से दलितों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की चिंताओं तथा आकांक्षाओं को परिलक्षित किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी बिना किसी हिचकिचाहट के यह माँग करती है कि सत्ता, संपत्ति और सम्मान में हमारे राष्ट्रीय परिवार के हर वर्ग को उसका समुचित हिस्सा मिले। भाजपा दर्शन में ये चिंताएँ सदा केंद्र बिंदु पर रही हैं। किंतु अतीत में पहले कभी ऐसी अनुकूल स्थिति नहीं रही जितनी कि अब यह हमारे पक्ष में है। अब हम अपने विरोधियों की 'सामाजिक न्याय' की वकालत की परिसीमाओं की पोल खोल सकते हैं और लोगों को यह बता सकते हैं कि सामाजिक समरसता का हमारा नारा इसी ऊँची विचारधारा को प्रकट करने का कितना उत्तम अधिक ईमानदारी पूर्ण तरीका है।

7. अल्पसंख्यक मतदाता की बदलती मनोदशा

हमारे उम्मीदवारों की सूची भारतीय समाज की सामाजिक संरचना की अच्छी तरह द्योतक होनी चाहिए। हमें धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषरूप से मुसलमानों में से पात्र एवं जीतनेवाले उम्मीदवारों का पता लगाने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। शायद भाजपा के प्रति मुसलमान मतदाताओं की बदलती हुई मनोदशा सन् 1998 के चुनावों की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समाजशास्त्रीय विशेषता है।

8. महिला–आरक्षण

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के कारण हमारा यह दायित्व हो गया है कि उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं की संख्या अधिक हो।

नए इतिहास की रचना

प्रिय सहयोगियो, हमारी विजय निश्चित है। किंतु हमें अपनी इस विजय के ऐतिहासिक महत्त्व को समझ लेना चाहिए। यह केवल एक और संसदीय चुनाव में केवल एक और राजनीतिक दल की मात्र विजय नहीं होगी। जी नहीं, यह हमारी विचारधारा तथा हमारे राष्ट्रवाद के आदर्शों की विजय होगी। इसका अर्थ राजनीति एवं शासन के क्षेत्र में राष्ट्र की चिति की पुनः स्थापना होगी। इसके साथ राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंधों में पुनः समरसता स्थापित करने की चुनौती का सामना करना, जिसके द्वारा ही भारत अपने पूर्व–निर्धारित गौरवशाली मार्ग पर अग्रसर होने में सफल होगा।

इस बार हम इतिहास की रचना करनेवाले हैं। हमारी अनेक दशाब्दियों की तपस्या फलीभूत होनेवाली है। निस्संदेह, फल अपने आप नहीं मिलेगा। हमें इसके लिए कठोर परिश्रम करना होगा और इसमें आत्मतुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं है। यह और भी जरूरी है चूँकि हमारे असफल और हताश विरोधी सत्ता को इतनी आसानी से छोड़नेवाले नहीं है। किंतु सत्ता को आसन्न देखकर हमें अपनी तपस्या को नहीं भुला देना चाहिए। हमारे लिए सत्ता मातृभूमि की सेवा का एक साधन मात्र है और कुछ भी नहीं। अतः हमारे लिए शासन चलाना मात्र भारतमाता की अनवरत सेवा को जारी रखना है। हमारी सेवा के परिणामस्वरूप और सेवा-कार्य में रत रहकर ही हमें तपस्या का सच्चा फल प्राप्त होगा।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली 22–23 फरवरी, 1996

मैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप सबका स्वागत करता हूँ।

हमारी पिछली बैठक 23 और 24 दिसंबर, 1995 को संसद् के शीतकालीन अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद हुई थी।

पिछली बैठक और वर्तमान बैठक के बीच दो महीने के अंतराल में अत्यंत स्तब्धकारी घटनाएँ देश की राजनीति पर गहरा तथा चिरस्थायी प्रभाव डालेंगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

मैं इस अवधि की प्रमुख चार घटनाओं का संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ।

1. पुरुलिया में विमान से गिराए गए हथियारों की घटना देश के लिए अत्यंत क्षोभकारी घटना थी। इससे एक बात स्पष्ट होकर सामने आई कि वर्तमान शासन के अधीन हमारे देश की सीमाएँ और वायुमार्ग पूरी तरह से असुरक्षित हैं। आज तक सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई है कि देश की सुरक्षा का यह अतिक्रमण किस प्रकार संभव हुआ।

   अभी पुरुलिया में गिराए गए हथियारों की घटना का रहस्य सुलझ नहीं पाया है कि हम देखते हैं कि इसी सप्ताह पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों का एक दूसरा भंडार दिल्ली में पकड़ा गया है। इन घटनाओं से स्पष्ट पता चलता है कि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई. एस. आई. पूरे भारत में व्यापक रूप से गड़बड़ी फैलाने का अनर्थकारी इरादा रखती है। यह तथ्य अपने आप में अत्यंत चिंताजनक है कि पाकिस्तान हमारे देश में इतनी आसानी से हथियारों का विशाल भंडार भेज रहा है। आज देश की सुरक्षा को जितना गंभीर खतरा है उतना इससे पहले कभी नहीं रहा।

भाजपा पर नेताओं के विरुद्ध हवाला का षड्यंत्र

2. 16 जनवरी को सरकार ने भाजपा के अध्यक्ष समेत अनेक राजनेताओं के विरुद्ध हवाला मामले में आरोप पत्र दायर किया। यह मामला पिछले पाँच वर्षों से सरकार के पास पड़ा रहा है और उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार कोंचने के बाद भी इसपर कुछ नहीं किया गया।

मैं समझता हूँ कि चारों तरफ से घिरे प्रधानमंत्री ने हताश होकर हवाला कांड से भाजपा पर प्रहार करने का आखिरी जुआ खेला है। इस निर्णय के पीछे निहित उद्देश्य एकदम साफ है कि भाजपा द्वारा राव सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे युद्ध की धार को कुंद किया जाए। लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि ठीक है, "यदि हम भ्रष्ट हैं तो हमारे सभी प्रमुख विरोधी भी ऐसे ही हैं।"

राव सरकार पर चाल उलटी पड़ी

किंतु राव सरकार को अपनी इस हवाला चाल की प्रतिक्रिया में भाजपा के शक्तिशाली और सिद्धांताधारित उत्तर का अंदाजा नहीं था। पार्टी द्वारा इस मुद्दे पर अपने अध्यक्ष को संसद् से त्यागपत्र देने और जब तक वह इस आरोप से मुक्त नहीं हो जाते तब तक चुनाव न लड़ने की घोषणा से ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश निश्चित है। इस समय कांग्रेस की पूरी इमारत ताश के पत्तों के महल की तरह गिरती दिखाई पड़ती है। भाजपा के विरुद्ध चली गई यह चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई है। लोगों की दृष्टि में कांग्रेस पार्टी इच्छा-मृत्यु से ग्रस्त है।

उच्च न्यायालय द्वारा मुलायम सिंह की भर्त्सना

3. पिछली बार की कार्यकारिणी की बैठक के बाद न्यायालय का अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है जिसमें 2 अक्तूबर, 1994 को उत्तरांचल कार्यकर्ताओं पर बरपा किए गए आतंक के लिए मुलायम सिंह सरकार की तीव्र भर्त्सना की गई है। एक पृथक् उत्तरांचल पर्वतीय राज्य की माँग को लेकर नई दिल्ली में होनेवाली एक रैली में भाग लेने जा रहे शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं को मुजफ्फरनगर में रोक दिया गया। इसके बाद जो कुछ घटा वह मुलायम सिंह के शासन के तौर-तरीके के अनुरूप था। पुलिस ने गोली चलाकर कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की, महिलाओं को खेतों में जबरदस्ती घसीटकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और अनेक लोग स्थायी रूप से विकलांग हो गए।

भाजपा उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है जिसमें श्री यादव के प्रशासन को मानवाधिकारों का हनन कर पूरी तरह से दुरुपयोग करने

का दोषी पाया है तथा इस घटना में शिकार हुए लोगों को मुआवजा दिया है तथा उत्तरांचल क्षेत्र को ठीक-ठाक किया जाए। दोषी अधिकारियों को तुरंत दंड दिया जाए। हम समझते हैं कि श्री यादव भी दोषी हैं, क्योंकि सरकार का नेतृत्व करने के नाते वह अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। दो कारणों से उन्हें दंड मिलना चाहिए। एक, पहले तो उन्होंने अत्याचार किए जाने की सच्चाई को ही निराधार आरोप कहकर नकारा और दूसरे, बाद में उन्होंने अपने अधिकारियों की कार्रवाइयों से अपने को अलग कर लिया। अयोध्या में 6 दिसंबर की घटनाओं में तत्कालीन अधिकारियों की काररवाई के प्रतिफल श्री कल्याण सिंह के आचरण की तुलना में उनका (मुलायम सिंह) आचरण एकदम विपरीत है।

भाजपा उत्तरांचल राज्य के निर्माण के प्रति वचनबद्ध है। श्री कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व के समय में पारित प्रस्ताव के रूप में जो इस दिशा में पहला कदम उठाया गया था, केंद्र में भाजपा की सरकार होने पर इसकी पूर्ण परिणति की जाएगी।

चारा घोटाला

4. बिहार में हमारी पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा लगातार जोर देने पर छुपा हुआ घोटाला उजागर हुआ है कि किस प्रकार लालू यादव की सरकार पिछले पाँच वर्षों से राज्य को लूटती रही है। अब चारा घोटाले के नाम से विख्यात इस घोटाले से पता चला है कि पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए का गबन हुआ। इसी प्रकार शिक्षा तथा लोक निर्माण विभाग में करोड़ों रुपए का गबन हुआ। हमारी छान-बीन ने स्पष्ट कर दिया है कि इसी प्रकार जनता दल ने राज्य विधानसभा चुनावों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए इस धन का प्रयोग किया और पार्टी के कुछ जाने-माने लोगों को लाभ पहुँचाया।

भ्रष्टाचार का मुद्दा—सर्वोच्च महत्त्वपूर्ण

पिछले वर्ष हमने सुरक्षा, शुचिता और समरसता मुद्दों के रूप में पहचान की थी, जो आगामी चुनावों में जनमानस को प्रभावित करेंगे। हाल की घटनाओं ने हमारे इस मूल्यांकन की पुष्टि की है। सामान्यतया कांग्रेस पहले भ्रष्टाचार को विश्वजनीन तत्त्व कह कर इसे दबाने में सफल रही है। केवल 1989 में बोफोर्स के कारण भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा बना, जिससे उस वर्ष के चुनाव परिणाम सुनिश्चित हुए। चुनाव सन्निकट हवाला अभियोजन के मामले शुरू कर राव सरकार ने इस विषय को इस वर्ष की चुनाव विषय सूची में सबसे ऊपर रख दिया है, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

जनता सत्ता-परिवर्तन की इच्छुक

1946 में पं. नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई थी। तब से इस वर्ष 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं। चार वर्षों को छोड़कर इन 50 वर्षों में केंद्र में कांग्रेस ही शासन करती रही है। उसके शासन काल का रिकॉर्ड अत्यंत निराशापूर्ण है। देश परिवर्तन के लिए बेताब है।

दिल्ली चलो

यह वर्ष हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान् अधिनायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी का है। 25 अगस्त 1943 को नेताजी ने औपचारिक रूप से आजाद हिंद फौज की कमान सँभालते हुए कहा था—

"आइए, 'दिल्ली चलो' का नारा लेकर हम तब तक जुटे रहें और संघर्ष करते रहें जब तक नई दिल्ली में वाइसराय हाउस पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने लग जाए।"

उस समय सभी देशभक्तों के लिए 'दिल्ली चलो' प्रेरणादायी नारा बन गया था, जिसका उद्‌देश्य 'स्वराज' प्राप्त करना था। यद्यपि हमें 'स्वराज' प्राप्त हुए 50 वर्ष हो गए, 'सुराज' हमसे कोसों दूर है। आइए, भाजपा को 'सुराज' लाने का साधन बनाएँ।

मार्च में होली त्यौहार के बाद 'स्वराज से सुराज तक की दिल्ली चलो रथयात्रा' आरंभ करने का मेरा विचार है, जिसमें देश के सभी भागों में सुरक्षा, शुचिता, समरसता और स्वदेशी का संदेश तथा भाजपा की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (हिंदुत्व) की विचारधारा जन-जन तक पहुँचाई जाएगी।

मूल्य-आधारित व्यवस्था का संकल्प

चीनी लिपि में 'संकट' शब्द को दो विशेष तत्त्वों के यौगिक रूप में लिखा जाता है, जिसमें एक 'खतरे' और दूसरे 'अवसर' का द्योतक है।

आज भाजपा को देश में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में देखा जाता है जो भारतीय राजनीति में उस नैतिक आधार की पुनःप्रतिस्थापना के लिए कटिबद्ध है, जिसके लिए गांधी जी, दीनदयालजी और जयप्रकाशजी ने प्रयास किया था। सरकार ने भाजपा पर नवीनतम प्रहार इस लोकप्रिय विचार को क्षत-विक्षत करने के इरादे से किया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस चुनौती को एक विलक्षण अवसर में बदल दें।

हमारा संघर्ष केवल सरकार बदलना नहीं है, अपितु शासन पद्धति में परिवर्तन करना है; एक ऐसी मूल्य आधारित व्यवस्था लाना है, जो ऐसी शासन पद्धति को स्वरूप प्रदान करती है।

वंदेमातरम् ! 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

भोपाल 21 जून, 1996

भाजपा सबसे बड़ी पार्टी

आज से छह मास पूर्व मुंबई में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के महाधिवेशन में पार्टी ने भविष्यवाणी की थी कि—

"यह भारत की नियति है कि वह 21वीं शताब्दी में मजबूत राष्ट्रवादी शक्तियों के नेतृत्व में प्रवेश करेगा, जो इस शत-कोटि नागरिकों के महान् राष्ट्र में हर स्तर पर उभर रही है। यह भाजपा के लिए ऐतिहासिक कार्य है कि ऐसी घड़ी में इन शक्तियों के केंद्रबिंदु के रूप में उठ खड़ी हो और धीरे-धीरे भारत को उसकी प्रतीक्षारत गौरवशाली नियति की ओर ले चले।"

1996 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विरोधियों को पछाड़ कर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सांसदों की दलीय सूची देखने पर संतोष होता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला सांसदों की संख्या (14) सबसे अधिक है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 120 स्थान आरक्षित हैं। यहाँ भी 42 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सांसद जिताकर भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर है। अपने 'ऐतिहासिक कार्य' के निर्वाह की दिशा में उल्लेखनीय सफलता भारतीय जनता पार्टी का प्रथम दृढ़ कदम है।

अगले दौर की तैयारी

परंतु 11वीं लोकसभा के वर्तमान स्वरूप में अस्थिरता इस प्रकार अंतर्निहित है कि लगता है, अगला चुनाव शीघ्र होना अनिवार्य है। सामान्य रूप से लोकसभा का अगला चुनाव सन् 2001 में होना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सभी इकाइयों को इस संभावना के प्रति सचेत रहना चाहिए कि 21वीं लोकसभा का चुनाव उससे बहुत पहले, और संभवतः 1997 में ही, हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच ही वह एक सुनहरा

अवसर होगा जब 'प्रतीक्षारत 21वीं शताब्दी की ओर धीरे-धीरे ले जाने' के पार्टी के मुंबई के पूर्वानुमान को हम शब्दशः सत्य प्रमाणित कर सकेंगे।

कांग्रेस दो बार पहले भी लोकसभा चुनाव हार चुकी है—पहली बार 1977 में और दुबारा 1989 में। लेकिन इस बार जैसा घोर पराभव पहले कभी नहीं हुआ।

लोगों का ध्यान लोकसभा चुनावों पर केंद्रित होने के कारण आम तौर पर इस बात की उपेक्षा हो गई कि 1996 के चुनावों में कांग्रेस न केवल दिल्ली में सत्ताच्युत हो गई वरन् साथ-ही-साथ असम, केरल और हरियाणा में भी अपनी सरकारें खो बैठी। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. को भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा।

भ्रष्टाचार--लिप्त कांग्रेस पार्टी का पतन

कांग्रेस की इस बुरी पराजय के लिए कई मुद्दे कारण बने। किंतु उसके इस अपकीर्तिक पतन का सबसे बड़ा कारण निश्चय ही भ्रष्टाचार रहा है। प्रशासन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा 'सुशासन' का प्रथम और प्रमुख अंग है। इस पृष्ठभूमि में संसद् में संयुक्त मोरचा के प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा को भ्रष्टाचार की विभीषिका को कमतर बताने का प्रयास करते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। बहुत से शीर्ष राजनीतिज्ञों, जिनमें वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं, की यह धारणा है कि भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों का कुछ भी लेना-देना नहीं है। उनकी यह मान्यता पूर्णतया गलत है।

औसत भारतीय जहाँ भी जाता है, भ्रष्टाचार की पीड़ा का अनुभव करता है। वह इसका अनुभव तब करता है जब वह अपने बच्चे को विद्यालय में भरती कराने के लिए घूस देता है। वह अनुभव करता है जब उसे गाड़ी में स्थान पाने के लिए स्टेशन पर रेलवे के दलाल को पैसा देना पड़ता है। वह इस वेदना का तब भी अनुभव करता है जब वह टेलीफोन के लिए आवेदन करने जाता है। वह तब भी इसका अनुभव करता है जब राशन की दुकान पर उसे अनाज और कंकड़-पत्थर के मिश्रण के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा देना पड़ता है।

यह स्थिति बदलनी ही चाहिए। और यह बदल सकती है। लेकिन लोक-जीवन और प्रशासन में ईमानदारी शिखर से आरंभ होनी चाहिए। यदि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ निर्लज्ज होकर घोटाले और महाघोटाले करते रहेंगे तो आम जनता के लिए कोई आशा नहीं।

श्री देवगौड़ा ने संसद् में बिना किसी संकोच के यह घोषित किया कि भ्रष्टाचार से निपटना सरकार के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। उनकी इस घोषणा से इस संदेह को बल मिलता है कि संयुक्त सरकार के लिए कांग्रेस का समर्थन भारी कीमत चुकाकर प्राप्त किया है—वह कीमत है राव सरकार के भ्रष्टाचार और दुष्कृत्यों पर परदा डालना।

संयुक्त मोरचा सरकार को समर्थन और फिर धोखा

इस प्रकार कांग्रेस-समर्थित संयुक्त मोरचा सरकार सही मायने में सरकार कम और कांग्रेस के लिए एक सुरक्षा कवच अधिक है।

जब संसद् में देवगौड़ा सरकार के प्रति विश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने उस समय जोरदार हर्ष-ध्वनि की जब श्री नरसिंह राव ने उद्घोषणा की कि "श्री देवगौड़ा के साथ हमारा समझौता है कि हमारी पार्टी उनकी सरकार को किसी भी स्थिति में गिरने नहीं देगी। इतिहास को यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि देवगौड़ा सरकार कांग्रेस पार्टी के कारण गिर गई।"

इस असंदिग्ध और निर्बंध आश्वासन के आठ के दिन के भीतर ही जो परिवर्तन हुआ है वह विचारणीय है। अपने संसदीय क्षेत्र बहरामपुर (उड़ीसा) में 19 जून को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री नरसिंह राव ने संयुक्त मोरचा सरकार को चेतावनी दी कि उसे यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि कांग्रेस का समर्थन हर स्थिति में मिलता रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारा समर्थन अंध समर्थन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि संयुक्त सरकार ने कांग्रेस की मूलभूत नीतियों के विरुद्ध आचरण करने की भयंकर भूल की तो हमें सरकार के समर्थन पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

मन में सहज आशंका जन्म लेती है कि पिछले कुछ दिनों में सी.बी.आई. ने यूरिया घोटाले में जो कदम उठाये हैं क्या उनका बहरामपुर में दी गई धमकी से कुछ संबंध है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय

दो विश्वास प्रस्तावों—एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रवर्तित और दूसरा श्री एच.डी. देवगौड़ा द्वारा प्रवर्तित, पर संसद् में हुई का एक स्वागत योग्य पहलू यह भी रहा है कि इसने पंथनिरपेक्षता पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।

मुझे प्रसन्नता है कि एक बार श्री पी.वी. नरसिंह राव ने भी अपना सामान्य मौन तोड़ा और पंथनिरपेक्षता के विषय पर अपने विचार रखे।

श्री राव ने हिंदू मंदिरों के प्रशासन पर सर्वोच्च न्यायलय के उस निर्णय का उल्लेख किया जिसमें सरकार को मंदिरों के प्रबंधन के कुछ क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे भारतीय पंथनिरपेक्षता के एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।

मैं नहीं समझता कि किसी ने इस निर्णय पर कोई आपत्ति की। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि वे जहाँ हिंदू मंदिरों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हैं वहीं समान नागरिक संहिता के विषय में उच्चतम न्यायालय द्वारा कांग्रेस सरकार की बार-बार भर्त्सना की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता। इतना ही नहीं, भाजपा द्वारा इसके समर्थन का उल्लेख श्री राव पंथनिरपेक्ष विरोधी स्वरूप

के उदाहरण के रूप में करते हैं।

वास्तव में श्री राव ने अपने भाषण में भाजपा के चुनाव घोषणा-पत्र के दो पहलुओं का ही उल्लेख यह सिद्ध करने के लिए किया कि क्यों भाजपा को वह पंथनिरपेक्षता का विरोधी मानते हैं। वे दो पहलू हैं :

(क) भाजपा समान नागरिक संहिता की वकालत करती है, और

(ख) भाजपा धारा 370 को समाप्त करना चाहती है।

भाजपा इन दोनों मुद्दों पर वचनबद्ध है। हम मानते हैं कि इन मुद्दों का विरोध शुद्ध रूप से वोट-बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है। इन मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस के लिए हम अपने विरोधियों को चुनौती देते हैं।

समान नागरिक संहिता

"भारत समान नागरिक संहिता स्वीकार करे या नहीं, यह विधिक प्रश्न है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 44 में 'राज्य' को दिया गया आदेश है और संविधान देश की सर्वोच्च विधि है।"

"किंतु दुर्भाग्य से विधिक प्रश्नों का प्रायः राजनीतीकरण हो जाता है और इस प्रकार भ्रम पैदा कर दिया जाता है—विशेष रूप से यह भ्रम की अवस्था ऐसे मुद्दों पर फैलाई जाती है, जिनसे प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए चुनावी लाभ प्राप्त करने की संभावनाएँ बनती हैं, और विशेष रूप से जब कि मुसलिम वोट-बैंक प्रभावित हो जाता है, जिन पर अधिकांश दलों को निर्भर रहना पड़ता है।"

'इसी कारणवश, इस प्रकार के संविधान के प्रावधानों पर लिखने वाले किसी भी विद्वान् लेखक को निहित स्वार्थ वाले राजनेताओं द्वारा 'सांप्रदायिक' घोषित किए जाने का जोखिम उठाना पड़ता है। इस संदर्भ में 'समान नागरिक संहिता' जैसे महत्त्वपूर्ण विषय का उदाहरण सर्वविदित है।

भाजपा के लिए बहुमत की प्रबल संभावना

'इंडियन एक्सप्रेस' के 14.6.96 के अंक में प्रकाशित अपने लेख में हाल के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने लिखा है कि भाजपा की उपलब्धि मुख्य रूप से 'हिंदी भाषी और पश्चिमी भारत' से रही है; किंतु उनका यह मानना है कि

"उसकी (भाजपा की) सीटों की संख्या वास्तव मे प्रभावशाली है। उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है भाजपा की 12 वर्षों से असाधारण प्रगति—1984 में दो सदस्यों की संख्या से 1996 में 160 तक पहुँच जाना। यदि भाजपा और उसके सहयोगियों की सीटें जोड़ लें तो कुल सीटों की संख्या उतनी हो जाती है, जितनी कांग्रेस को 1989 में मिली थी।"

"अगला चुनाव जब भी होगा तब 'संघ परिवार' द्वारा अकेले ही पूर्ण बहुमत

प्राप्त करने की संभावना है, इस तथ्य को मेरी पार्टी सहित सभी राजनीतिक पार्टियों को ध्यान में रखना चाहिए।"

इसमें संदेह नहीं कि पिछले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी की प्रगति असाधारण रही है। लेकिन विचारणीय विषय यह है कि कांग्रेस का अधःपतन जिस तीव्रता से होता जा रहा है उस तेजी से भारतीय जनता पार्टी की प्रगति नहीं हो रही।

आगामी महीनों और वर्षों में भाजपा का युद्ध-घोष होना चाहिए—हमें नए भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ना है और कांग्रेस के विखराव से उत्पन्न शून्य को भरना है।

हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं उनके अनुरूप पार्टी के संगठनात्मक तंत्र को चुस्त करने की भी आवश्यकता है। आज की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अत्यधिक अनुकूल है। सत्ता में 13 दिन का हमारा कार्यकाल सुगठित और सुनिर्मित 'ट्रेलर' सिद्ध हुआ है, जिसे देखने के बाद दर्शकों में पूरी फिल्म देखने की चाहत पैदा हुई है। राष्ट्र श्री वाजपेयी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और चाहता है कि उनकी सरकार पूरे 5 वर्ष शासन करे।

इस अनुकूल परिस्थिति की पूरी संभाव्यता का अनुभव तभी किया जा सकता है जब पार्टी संगठन के सभी स्तरों पर एकता का दृढ़ निश्चय और अनुशासन की पुनःस्थापना हो।

भाजपा के सामने तीन कार्य

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक के समक्ष मुख्यतः तीन विषय विचारणीय हैं—

1. चुनाव परिणामों की समीक्षा करना और आवश्यक ग्रहण करना।
2. चुनाव बाद की राजनीतिक गतिविधियों का आकलन करना और यह अनुमान लगाना कि इसने पार्टी को कहाँ तक प्रभावित किया है।
3. उत्तर प्रदेश विधानसभा के आसन्न चुनावों के लिए योजना बनाना और तैयारी करना।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

जयपुर 15-17 नवंबर, 1996

जयपुर में पार्टी की इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आप सबका हार्दिक स्वागत है।

यद्यपि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रत्येक बैठक ही उल्लेखनीय होती है, परंतु यह बैठक जो अभी प्रारंभ हुई है, दो कारणों से विशेष महत्त्वपूर्ण है। गत 21 से 23 जून तक भोपाल में हमारी बैठक के बाद राष्ट्रीय पटल पर ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिनका हमारे देश और पार्टी, दोनों पर गहरा असर हुआ है। इस जयपुर बैठक का आह्वान है कि हम बाह्य राजनीतिक परिस्थिति के साथ-साथ पार्टी के आंतरिक संगठनात्मक स्वास्थ्य के प्रति एक दृढ़ और सिद्धांतनिष्ठ रुख निर्धारित करें।

दिशाहीन सरकार

भोपाल बैठक के समय श्री एच.डी. देवगौड़ा की सरकार बने मात्र बने 15 दिन ही हुए थे। जब से पाँच महीने बीते हैं और इस सरकार के बारे में हमारा आकलन इतना अधिक सही सिद्ध हुआ है कि हमें स्वयं को आश्चर्य हुआ है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसी सरकार नहीं रही, जो न केवल इतने अधिक दिशा-भ्रम और बिखराव से ग्रस्त हो, बल्कि जिसके पास वास्तविकता में कोई लोकतांत्रिक जनादेश भी न हो।

आज देश का प्रधानमंत्री ऐसी पार्टी से है, जिसके संसद् में कुल 45 सदस्य हैं। उस पार्टी का अध्यक्ष बिहार का मुख्यमंत्री है, जो स्वयं अपनी ही सरकार से सैकड़ों करोड़ रुपए की जालसाजी की सबसे अनोखी घोटाला प्रणाली का आविष्कार करने के बाद अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।

सत्तारूढ़ गठजोड़ को संयुक्त मोरचा कहा जाता है। पर वह चाहे और जो कुछ भी हो, संयुक्त तो नहीं ही है। प्रधानमंत्री ने पृथक् उत्तराखंड राज्य बनाने संबंधी अपनी सरकार का संकल्प जैसे ही घोषित किया, संयुक्त मोरचे के भीतर

ही वाम मोरचा दाँत पीसने लगा। हाल ही में असम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अवैध प्रवासी (पंचाट द्वारा निर्धारण) अधिनियम 1983 खत्म कर देगी तो वाम दलों ने ऐसे बयान के लिए पुनः उनसे डाँट-डपट की।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश की अवहेलना

देश में समान नागरिक कानून बनाने की दिशा में सरकार ने क्या प्रयास किया है, इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अगस्त से पूर्व तक एक शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन सरकार ने जो विवरण दाखिल किया, उससे सर्वोच्च न्यायालय अप्रसन्न ही हुआ है, क्योंकि उसमें यह दोहराया गया था कि सरकार न अभी, न भविष्य में कभी, समान नागरिक कानून बनाने की इच्छुक है। विडंबना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल यह विवरण उस विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किया था, जिसके मंत्री श्री रमाकांत खलप के अपने गृह राज्य गोवा में आजादी के बाद से एक समान नागरिक कानून लागू हैं, जिस पर न कभी विवाद उठा, न जिसे लेकर किसी को समस्या हुई। यह दिखाने के लिए कई और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं कि श्री देवगौड़ा की सरकार कितनी भ्रमित, बेतरतीब और भीतरी तौर पर विभाजित है।

दुर्दशापूर्ण आर्थिक स्थिति

देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। जिम्मेदार मंत्रियों में से कोई एक भी यह बताने को इच्छुक नहीं है कि भारत एक भयानक मंदी के कगार पर आ खड़ा हुआ है।

निर्यात दर में लगातार गहरी गिरावट के फलस्वरूप सन् 1996-97 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जो गत वर्ष 19.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक घट गया है जिसके कारण भुगतान संकट के काले बादल घिर आए हैं। सरकार कहेगी कि मंदी, भ्रष्टाचार की तरह, वैश्विक-घटनाक्रम है। पर यह सच नहीं है। इन्हीं 12 महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का भंडार 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

परंतु अब मैं उन 'उपलब्धियों' की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, जो सीधे-सीधे आम आदमी को प्रभावित करती हैं। कोयले का मूल्य 28 प्रतिशत बढ़ गया है, जिसमें से 8 प्रतिशत की वृद्धि केवल अक्तूबर में ही हुई है। जुलाई से ईंधन का मूल्य 30 प्रतिशत बढ़ गया है। डीजल का मूल्य 25 प्रतिशत बढ़ा है। माल ढुलाई और रेलवे किरायों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

परंतु इसमें से कुछ भी हमारे 'साधारण किसान' प्रधानमंत्री पर असर नहीं डालता, जो कहते हैं कि वे अपने परिवार के 15 सदस्यों को अफ्रीका ले जाने

का विमान किराया देने में समर्थ हैं। परंतु यह उस कामगार व्यक्ति को जरूर प्रभावित करता है, जो देखता है कि उसका बस भाड़ा दुगुना हो गया है।

यथार्थता से दूर

इसके बावजूद हमारे वित्त मंत्री को कोई चिंता नहीं और वह मस्ती के आलम में हैं कि वे मुंबई में माइकल जैक्सन के कार्यक्रम के लिए 5-5 हजार रुपए के टिकट खरीदनेवाले अति धनिक युवाओं का उदाहरण देते हुए कहते हैं, 'देखो भारतीयों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है। मैं तो उन्हें और ज्यादा-से-ज्यादा खर्च करते हुए देखना चाहता हूँ।' यह वाक्य उस झुग्गी बस्ती के वासी को कितना क्रूर प्रतीत होगा, जिसे अपने बच्चों के स्कूल की फीस देने की भी चिंता सताती है या गाँव के उस गरीब किसान को यह सुनकर कैसा लगेगा, जो अपने बीमार बच्चों के इलाज के लिए भी पैसे-पैसे का मोहताज है।

13-पार्टी का तमाशा

जिन्होंने मई में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 13 दिन का चमत्कार कह कर निंदा की थी, वे अब यह तथ्य नहीं छिपा सकते कि केंद्र में जो कुछ भी सरकार के नाम पर चल रहा है, वह देश के हितों की दृष्टि से तेरह पार्टियों का एक महँगा मिथ्याचार है। पिछले 5 महीनों का अनुभव असंदिग्ध शब्दों में यही संदेश देता है कि देश को इस संयुक्त मोरचा सरकार के नाम से चल रहे मिथ्याचार तमाशे से जल्दी-से-जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए।

सरकार का लड़खड़ाता ढाँचा दो खपच्चियों पर टिका है। कांग्रेस, जो संयुक्त मोरचे के बाहर है और दूसरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो मोरचे के भीतर है। दोनों ही सरकार के काम-काज पर तीव्र आघात कर रही हैं। हालाँकि निश्चित तौर पर हम उनकी आलोचना को ईमानदार नहीं मान सकते, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के नेता एक ही वक्त में दो बातें करना चाहते हैं। एक, पिछली सीट पर बैठकर सरकार की गाड़ी चलाना और दूसरा, आम आदमी को दिखाने के लिए उसके काम-काज की आलोचना करना। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि विपक्ष के संपूर्ण मंच पर ही भाजपा का एकाधिकार हो गया है, इसलिए वे इस फेर में उलझ गए हैं कि गुड़ खा भी लें और बचा भी लें।

आतंरिक विरोधाभास और विवशताएँ

इस प्रक्रिया में संयुक्त मोरचा तथा कांग्रेस के आंतरिक विरोधाभास और दबाव हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस समय तो संयुक्त मोरचा और कांग्रेस दोनों ही एक-दूसरे को खा जानेवाली साजिशों में व्यस्त है। संयुक्त मोरचा कांग्रेसियों को मंत्री पद का लालच देकर कांग्रेस तोड़ना चाहता है तो दूसरी और कांग्रेस का

खेल है कि वह संयुक्त मोरचा से तिवारी कांग्रेस, तमिल मनीला कांग्रेस और बंगारप्पा जैसे पुराने कांग्रेसियों को वापस अपने दल में शामिल कर ले तथा उसके बाद देवगौड़ा सरकार से भी समर्थन खींच ले। आनेवाले महीनों में केंद्र में इस प्रकार की अस्थिरता और जोड़-तोड़ का तमाशा देखने को मिलेगा। हमारी पार्टी को सजग और सचेत रहते हुए किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तत्पर रहना होगा।

माफिया को संरक्षण

भोपाल में अपने उद्घाटन भाषण में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि भ्रष्टाचार जैसी भयानक बीमारी की गंभीरता को प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा ने संसद् में किस प्रकार हल्के ढंग से लिया था। बिना किसी शर्म और संकोच के उन्होंने संसद् में घोषित किया कि भ्रष्टाचार का विषय उनकी सरकार की वरीयता में नहीं है। "इस घोषणा से उन्होंने इस संदेह को ही पुष्ट किया कि संयुक्त मोरचा सरकार को कांग्रेस का समर्थन काफी भारी कीमत देकर खरीदा गया है और यह कीमत है कि पिछली राव सरकार के जितने भी भ्रष्टाचार के कांड हुए उनसे बचाव के लिए कार्यपालिका जिस हद तक जा सके, जाएगी। कांग्रेस समर्थक संयुक्त मोरचा सरकार इस प्रकार एक समुचित शासकीय ढाँचे के बजाय हफ्ता वसूलने का तंत्र है।" (जो माफिया गिरोह के लोग किन्हीं खास लोगों को संरक्षण देने के नाम पर वसूलते हैं)।

कितना सही चित्रण किया गया है यह। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब राव मंत्रिमंडल के सदस्य भ्रष्टाचार के किसी नए कांड के रहस्योद्घाटन से अखबारों में सुर्खियाँ न बनाते हों या न्यायिक व्यवस्था द्वारा उसके महाघोटालों की छानबीन के संबंध में हर मोड़ पर थप्पड़ न रसीद किया जाता हो। यहीं नहीं, ऐसा भी कोई एक दिन नहीं जाता जब देवगौड़ा, बहुधा उन तरीकों से कि हर बार समाचार पत्रों में उनके कारनामे उजागर न हो जाएँ, राव और उनके भ्रष्ट सहयोगियों को बचाने की कोशिश न करते हों। यह हफ्ता वसूली गिरोह न ज्यादा चलेगा, न ही उसे चलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

न्यायपालिका का एक वर्ग कार्यपालिका की भूलचूक के गलत कार्यों को कड़ाई से लेकर इस हफ्ता वसूली के गिरोह की साजिशें विफल करने में प्रशंसनीय भूमिका निभा रहा है। इस प्रक्रिया में संभव है कि कुछ अतिरेक भी हुआ हो। पर इस बात को समझना जरूरी है कि न्यायिक सक्रियता के वर्तमान दौर का जन्म कार्यपालिका की पंगुता में से हुआ है। इसलिए कुछ क्षेत्रों में जिस प्रकार न्यायपालिका की भूमिका की सामान्यीकृत आलोचना हो रही है, वह उचित नहीं है। बहरहाल, भाजपा को भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त जनयुद्ध छेड़ने हेतु स्वतंत्र रूप से अपनी सक्रिय राजनीतिक भूमिका के लिए सिद्धता बढ़ानी होगी।

कम्युनिस्ट पार्टियों की संदिग्ध भूमिका

हमारे वैचारिक आक्रमण के एक भाग के रूप में संयुक्त मोरचे के दो प्रमुख रचयिताओं-दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों, के घोर अवसरवाद, नग्न पाखंड तथा दोहरेपन के विरुद्ध सतत अभियान छेड़ने की आवश्यकता है।

गुजरात और उत्तर प्रदेश में संविधान की धारा 356 के दुरुपयोग को मुखर समर्थन देने से कम्युनिस्टों का पाखंड और उजागर हुआ है। उत्तर प्रदेश में जालसाजीपूर्वक धारा 356 लागू करने से एक दिन पहले ही ज्योति बसु इस प्रावधान के विरुद्ध बोलते सुने गए थे जब उन्होंने इसे पूरी तरह रद्द करने की माँग की थी। उनका यह पांखड 7 नवंबर को पटना में तथाकथित 'बिहार बचाओ रैली' में भी खुलकर प्रदर्शित हुआ। खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले और देश के हितों की रक्षा करनेवाले जेसे खोखले दावे जो करते हैं, वे माकपा और उसकी जेबी भाकपा के नेताओं ने एक शब्द भी लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार पर नहीं कहा, जिनके साथ ये महानुभाव गत वर्ष गरीब रैली में भी एक मंच पर बैठे थे। वैसे भी, लालू को वे कैसे निशाना बना सकते हैं, जो अभी भी संयुक्त मोरचे के प्रमुख घटक के अध्यक्ष हैं। क्योंकि ऐसा करने पर इस तमाशे, जिसे संयुक्त मोरचा कहा जाता है, का पूरा तंबू ही धराशायी नहीं हो जाएगा।

इस मामले का सच तो यह है कि भले ही कम्युनिस्ट कहें कि उनकी दिलचस्पी बिहार बचाने में हैं, वस्तुतः वे लालू को ही बचाने में लगे हैं। और लालू को बचाने के पीछे उनका उद्देश्य भारतीय राजनीति में अपनी तेजी से खत्म होती साख को बचाने की कोशिश ही है।

अपने दकियानूसीपन को छिपाने की कोशिश में भारतीय राजनीति के ये दानासुर कितनी बेहूदगी तक उतर आते हैं। हमारे इन कम्युनिस्टों ने, जो पिछले सात दशकों से अपनी पितृभूमि में बारिश होने पर अपने कर्तव्य के नाते यहाँ भी छाता तान लिया करते थे, पटना की उक्त रैली में 'महान' रूसी क्रांति की 79वीं वर्षगाँठ भी मना ली, भले ही रूसी उसे पीठ पीछे छोड़ बैठे हैं।

सरकार के पीछे अब कम्युनिस्टों का दिमाग

इनकी गिरती हुई ताकत को देखते हुए ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ सामान्यतया ज्यादा ध्यान देने की पात्रता नहीं रखतीं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में एक खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। इन कम्युनिस्टों ने 1947 में भारत की आजादी को झूठी आजादी बताया था; उन्होंने भारत के विभाजन का समर्थन किया तथा 90 के दशक के आरंभ तक, जब तक सोवियत संघ अचानक बिखर नहीं गया, उसे राष्ट्रीय एकता का आदर्श उदाहरण बताते रहे; जो आज भी लेनिन और स्टालिन का जैसा सम्मान करते हैं वह सम्मान गांधी और सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण या किसी भी अन्य भारतीय महानायक को नहीं देते; ऐसे

कम्युनिस्ट आज भारत के सत्ता प्रतिष्ठान को संचालित करनेवाला मस्तिष्क बन बैठे हैं। चूँकि इतिहास (न केवल भारतीय इतिहास, बल्कि विश्व इतिहास) ने उनके तमाम वैचारिक वस्त्र उतार फेंके हैं, फिर चाहे वह पूँजीवाद विरोध का हो, साम्राज्यवाद विरोध का, सर्वहारा की तानाशही का या ऐसी ही अन्य बेहूदगियों का, इसलिए अब उन्होंने अपनी संदर्भहीनता को छिपाने की अंतिम कोशिश में 'भाजपा विरोध' को खोज निकाला है। केरल में भाजपा, संघ व विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मार्क्सवादी हिंसाचार इसी कमजोरी से पैदा बौखलाहट का प्रमाण है।

विडंबना यह है कि सत्ता तथा निर्णय लेने वाले प्रतिष्ठानों में उनका दबदबा इस हद तक बढ़ गया है कि जो उनके ठहरे हुए या सिकुड़ते जा रहे चुनावी आधार की तुलना में एकदम विलोमानुपाती है। ऐसी परिस्थिति में भाजपा जैसी एक राष्ट्रवादी पार्टी का कर्तव्य है कि वह कम्युनिस्टों के विनाशकारी प्रभाव के विरुद्ध शक्तिशाली तथा अथक वैचारिक संघर्ष छेड़े।

भारतीय राजनीति पर कम्युनिस्टों का सबसे विनाशकारी प्रभाव आज सांप्रदायिकता से लड़ने के नाम पर भाजपा को अलग-थलग किए जाने के रूप में प्रकट हो रहा है। कम्युनिस्ट और उनके अवसरवादी सहयोगी सत्ता हड़पने और उसे बनाए रखने की कोशिश में किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं—और मैं इसे दोहरा रहा हूँ कि किसी भी सीमा तक। और यह वे तब भी करते रहेंगे यदि इस प्रक्रिया में संविधान के शब्दों और भावनाओं को भी विखंडित किया जाए या सभी सुस्थापित परंपराओं और मर्यादाओं की धज्जियाँ उड़ा दी जाएँ या इसके लिए भाजपा को अवैध रूप से ही क्यों न हो, गला घोंटकर अस्तित्वहीन करना पड़े। हमने इस उन्मादी भाजपा विरोध के शर्मनाक उदाहरण गुजरात और उत्तर प्रदेश में देखे ही हैं। संयुक्त मोरचा संचालन समिति ने तो यह औपचारिक प्रस्ताव तक पारित किया कि वह उत्तर प्रदेश में तब तक राष्ट्रपति शासन जारी रखेगी जब तक वहाँ 'सेकुलर' सरकार नहीं बन जाती। यह भाजपा पर यथार्थरूपेण एक प्रतिबंध लगाने के सिवाय और कुछ नहीं है।

भाजपा-विरोध की घेराबंदी : हमारे लिए चिंता की बात नहीं

बहुत से राजनीतिक समीक्षकों और हमारे समर्थकों ने भी हमारे विरोधियों द्वारा भाजपा को अलग-थलग किए जाने को पार्टी के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि हम अपनी विकास यात्रा में अधिकतम ऊँचाई तक पहुँच चुके हैं या यह भी कि हमें गंभीर पराजय के झटके लगे हैं।

लेकिन तथ्यों का वस्तुगत निरपेक्ष और ठंडे दिमाग से किया गया विश्लेषण कुछ और ही बताता है और यह सिद्ध होता है कि 70 के दशक के अंतिम काल

में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद भारत में जो नई राजनीतिक गतिज ऊर्जा पैदा हुई, उसका प्रमुख लाभ स्वाभाविक रूप से भाजपा को ही मिला है। फिर भी असंदिग्ध रूप से गुजरात और उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम के विश्लेषण में आत्मालोचन करते समय पूर्णतः कठोरता और वस्तु निरपेक्षता बरतनी चाहिए तथा उससे सही सबक सीखना चाहिए। लेकिन भाजपा विरोधी गिरोहबंदी से अतिरंजित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

हम निकट अतीत की ओर मुड़कर देखें कि किस प्रकार हम चुनावी गणित में तथा राष्ट्र के लिए वैचारिक कार्यक्रम निर्धारित करने के संदर्भ में कितना आगे बढ़े हैं। भाजपा के जन्म का उत्स उस जनता पार्टी के हिंदुत्व विरोधी (जिसे रा. स्व. संघ विरोध का मुखैटा पहनाया गया) रवैये में है जिस जनता पार्टी से हमें कृतघ्नतापूर्वक बाहर किया गया था। तब तक और यहाँ तक कि 1979 तक एक भिन्न स्वरूप में राजनीतिक दलीय व्यवस्था की गतिजता में परिवर्तन को प्रभावित करनेवाला मुख्य पहलू कांग्रेस विरोधवाद ही था। लेकिन भाजपा के गत 16 वर्षों के अस्तित्व में हमारी पार्टी 1989 तक मंद गति से, लेकिन अनवरत बढ़ी, और उसके बाद तेजी से बढ़ते हुए न केवल भारतीय राजनीति की गतिजता को बल्कि उसकी धारा को भी परिवर्तित कर दिया। अब कांग्रेस विरोधवाद नहीं, लेकिन भाजपा विरोधवाद है, जो पार्टियों के गठजोड़, तालमेल और पुनः गठजोड़ को उत्प्रेरित कर रहा है। 1996 का लोकसभा चुनाव वस्तुतः इस गतिजता में एक बहुत बड़ा मोड़ सिद्ध हुआ।

भाजपा का तीव्र विकास

लेकिन ऐसी कौन सी पार्टी है जो इस राजनीतिक गतिजता के कारण आगे बढ़ी? अगर हम 1986 के बाद के 10 वर्षों के कालखंड में 5 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की विधानसभाओं में शक्ति की तुलनात्मक स्थिति पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि जहाँ 1986 में सभी राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायकों की संख्या कुल मिलाकर 1874 थी, वहीं वह 1083 तक गिर गई है। माकपा की विधानसभा में सदस्य संख्या थोड़ी कम हुई है जबकि भाकपा और जनता दल नगण्य रूप से बढ़त दिखाते हैं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने इस कालखंड में असाधारण और उल्लेखनीय बढ़त दिखाई है। उसकी विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 10 वर्ष पहले जहाँ 201 थी, वहीं आज 714 तक पहुँच गई है।

उपर्युक्त आँकड़ों का महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि इन पाँच पार्टियों में केवल भाजपा और कांग्रेस ही यथार्थतः राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। जनता पार्टी तो बिखराव के कगार पर है और दो राष्ट्रीय पार्टियों में भी कांग्रेस की विधानसभा में शक्ति 1986 से 96 के दशक में 42.2 प्रतिशत घट गई है, जबकि भाजपा की

शक्ति 250.2 प्रतिशत बढ़ी है। दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की गिरावट और विकास का यह चित्र इस दशक में दोनों की संसदीय शक्ति की तुलना करने से और स्पष्ट हो उठता है। 1986 में कांग्रेस के 415 सदस्य थे आज केवल 146 हैं। दस वर्ष पूर्व लोकसभा में हमारे सदस्यों की संख्या 2 थी और आज 161 हैं।

लोगों का समर्थन बढ़ता गया

इसलिए भाजपा के विरुद्ध बहुत व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा यह प्रचार कि उसे इन दिनों काफी झटके लगे हैं पूर्णतः खोखला है। हमें इस प्रकार के प्रचार को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि वह तथ्यात्मक रूप से गलत है। वस्तुतः हम यह समझ लें कि हमारे विरोधी हमें जितना अलग-थलग करने की कोशिश करेंगे उतनी ही अधिक तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। जितनी निर्लज्जता से संयुक्त मोरचा और कांग्रेस हमें अलग करने की कोशिश में संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को विखंडित करेगी, उतनी ही अधिक तीव्र भावना तथा विस्तार के साथ हमें जन-समर्थन मिलेगा। केंद्र में जितना अधिक संयुक्त मोरचा शासन व्यवस्था की दुर्गति करेगा, जो कि वह पहले ही कर रहा है, उतना ही अधिक और असंदिग्ध रूप से जनता श्री वाजपेयीजी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लाने हेतु उत्कंठित होगी। इसलिए हमारे विरोधी हमारे प्रति जो कर रहे हैं उसके बारे में बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

संगठनात्मक समस्याओं का समाधान

मुझे प्रायः ऐसा लगता है कि भाजपा ऐसे सिंह का दृश्य प्रस्तुत कर रही है जिसने अपने आपको स्वयं ही पिंजरे में बंद किया हुआ है। उसके पास वह सबकुछ है जो भारतीय राजनीति में सिंह की स्थिति में राजतिलक हेतु होना चाहिए। पिछले 45 वर्षों के हमारे अस्तित्व में, पहले भारतीय जनसंघ और फिर भाजपा के रूप में, हमारी पार्टी के लिए स्वयं को स्थायित्व सकारात्मकता और दूर दृष्टि के साथ भारत पर शासन करने में समर्थ राजनीतिक शक्ति के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित करने हेतु बाहरी वातावरण इतना अधिक अनुकूल कभी नहीं रहा। फिर भी यदि निश्चित स्थिति कई बार अनिश्चित और अप्राप्य प्रतीत होती है तो इसका मुख्य कारण हमारी भीतरी समस्याएँ ही हैं। और ये समस्याएँ वैचारिक नहीं हैं जैसा कि हमारे कुछ आलोचक, जो गंभीर तथा अर्थपूर्ण आलोचक हैं, जोर देकर कहते हैं। सत्य यह है कि ये समस्याएँ संगठनात्मक या व्यवहार से संबंधित हैं।

पार्टी ने अपने लिए जो उच्च आदर्श नियत किए हैं—और ये उच्च आदर्श पार्टी की अपनी विचारधारा से अभिषिक्त है, जो उसे अन्य सभी से विशिष्ट और पृथक् करती हैं, उनके आलोक में हमें संगठनात्मक तथा व्यवहार संबंधी

समस्याओं का समाधान करना होगा, जो हम आनेवाले महीनों में अत्यंत गंभीरता से करेंगे।

भविष्य की चुनौतियाँ

आनेवाले महीनों में, जैसा कि भाजपा पुनः केंद्र सरकार बनाने के नजदीक आती जाएगी, चाहे वह जल्दी आनेवाले मध्यावधि चुनाव के माध्यम से हो या अन्य प्रकार से, हमसे सुशासन स्थापित करने की अपेक्षा होगी जो कि जनता को हमारा वायदा भी है और हमारा पवित्र आत्म-संकल्प भी, बल्कि यही तो वह उद्देश्य है जिसके लिए हमारा अस्तित्व है। अतः मेरा आह्वान है कि हम सब पार्टी को इस चुनौती का सफलतापूर्वक निर्वाह करने के लिए सिद्ध करें।

जैसाकि मैंने पहले कहा कि हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध शक्तिशाली जनमत आंदोलित करने के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक पहल करनी होगी। मेरे विचार में अब समय आ गया है कि हम भ्रष्टाचार के विनाशकारी रोग को समाप्त करने के लिए स्पष्ट और सधे हुए कदम उठाएँ, क्योंकि यह रोग न केवल राजनीति को ग्रस्त कर रहा है, बल्कि समाज के सभी वर्गों पर दुष्प्रभाव छोड़ रहा है। कानून के भय के लोप, वैधानिक एवं कानून लागू करनेवाले तंत्र के दोषपूर्ण कामकाज और सबसे बढ़कर स्वयं कार्यपालिका द्वारा सिल-सिलेवार ढंग से कानून के राज का विखंडन किए जाने से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए विनाश का सूचक है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान

इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मेरा आह्वान है कि वह उच्च स्थानों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अथक राष्ट्रव्यापी अभियान की एक योजना बनाएँ। इस अभियान में तीन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

पारदर्शिता और जवाबदेही

प्रथम, इस अभियान को सत्ता प्रतिष्ठान में जवाबदेही और अधिकतम पारदर्शिता के प्रावधानों को संस्थागत रूप प्रदान करने तथा मंत्रियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, सांसदों और विधायकों के लिए न्यूनतम विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करने पर जोर देना चाहिए। यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक, राजनीतिक तथा कानूनी सुधार करने पड़ेंगे तथा विकेंद्रीकरण हेतु कदम उठाने पड़ेंगे। इस संबंध में दो मुख्य आधार चुनाव खर्च हेतु सरकारी अनुदान पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए चुनाव सुधार और काले धन की उत्पत्ति को रोकने के होने चाहिए।

कठोर दंड

द्वितीय, जो अपने व्यक्तिगत समृद्धि के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते पाए जाएँ, न केवल उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा कड़ा दंड मिले बल्कि इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि उनके विरुद्ध उनके अपने राजनीतिक दल द्वारा भी कठोर काररवाई की जाए। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत समृद्धि हासिल करने के आसान रास्ते के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय जो लोग संसद् या विधानसभा की सदस्यता अथवा मंत्रिमंडल में स्थान पाने के लिए लालायित रहते हैं, उनके लिए प्रोत्साहन के पहलू कम करते हुए उन्हें निरुत्साहित करनेवाले पहलू बढ़ाने होंगे।

धन संग्रह—हमारी पारदर्शी पद्धति

तृतीय, जहाँ तक पार्टी के लिए धन संकलन का संदर्भ है, भाजपा को नई पद्धति अपनानी होगी। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के कुछ आवश्यक और अपरिहार्य खर्च होते ही हैं और यह सभी खर्च सादगी के सभी उपाय करने के बावजूद निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि धन संग्रह और उसके खर्च का हिसाब-किताब पारदर्शितापूर्वक रखा जाए तथा जिसका नियमित अंकेक्षण भी होता रहे तो पार्टियों द्वारा राजनीतिक चंदा स्वीकार किए जाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। राजनीतिक चंदों में पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए हमें कर कानूनों, कंपनी कानूनों तथा चुनाव संबंधी कानूनों में महत्त्वपूर्ण सुधार करने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध रचनात्मक अभियान के संदर्भ में जिन बिंदुओं का मैंने ऊपर उल्लेख किया है वे केवल पार्टी व पार्टी के लिए ही सत्य नहीं हैं, बल्कि समग्रतः समूचे राजनीतिक वर्ग के लिए औचित्यपूर्ण तथा सत्य हैं। भाजपा को इन सुधारों को लाने के लिए समयबद्ध ठोस कदम उठाने की दिशा में एक सर्वदलीय चर्चा आरंभ करने हेतु पहल करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में हम केंद्र तथा राज्य दोनों ही जगह पार्टी के लिए धन संकलन की पूर्णतः पारदर्शी पद्धति को शीघ्र ही प्रभावी बनाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं।

भाजपा को और अधिक समर्थन की संभावना

जहाँ तक इस चर्चा का प्रश्न है कि भाजपा का जनसमर्थन अपने चरम बिंदु पर आकर ठहर गया है, मैं अपने विरोधियों को यह याद दिला दूँ कि यही बात हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, वास्तव में 1967 से ही जबकि जनसंघ को अपनी प्रारंभिक सफलताएँ मिली थीं, जिनके फलस्वरूप वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में संयुक्त विधायक दल सरकारों में सहभागी बना था। अतः ऐसी टिप्पणियों से परेशान न हों। हमारे अपने अनुभव ने यह दरशाया है कि केवल वहीं संगठन निरंतर शक्ति के नए स्तर और कीर्तिमान प्राप्त करते

चलते हैं जिनकी स्वयं में आस्था होती है, जिनके पास एक आदर्श स्वप्न होता है, दृढ़ इच्छाशक्ति, अनुशासन और आगे बढ़ने का संकल्प होता है, जो आदर्श और विचारधारा के अमिट ऊर्जा स्रोत से प्राणशक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और जिनकी विचारधारा अनिवार्यतः राष्ट्र और उसके जन-कल्याण से जुड़ी होती है।

और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही एक संगठन है। अन्यथा आज हताशा और आत्म-दैन्य की स्थिति में जिस प्रकार वह आशा की किरण बनी हैं, वह संभव नहीं होता। यह उन कर्मशील लोगों के तप और निष्ठा से पुष्पित, पल्लवित वह संगठन है जिनकी आँखों में भारत के परम वैभव के स्वप्न हैं और जिनके हृदय में आगे बढ़ने का संकल्प तथा आत्मविश्वास है। डॉ. हेडगेवार, डॉ. मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान् राष्ट्रनायकों से प्रेरणा पाते हुए हमारे पास आदर्शवाद की एक समृद्ध परंपरा है। आइए, हम हिंदुत्व (सांस्कृतिक राष्ट्रवाद), स्वदेशी (आर्थिक राष्ट्रवाद) और सुराज (सुशासन) के आदर्शों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें तथा सत्ता में हों या सत्ता से बाहर, अपनी इस महान् मातृभूमि की सेवा में जुटे रहें।

वंदेमातरम् !



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

पणजी (गोवा) 2 अप्रैल, 1995

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गोवा के प्रतिनिधि काफी समय से गोवा में कार्यकारिणी बैठक आयोजित करने का आग्रह कर रहे थे। परंतु किसी-न-किसी कारण से अभी तक उनके आमंत्रण का लाभ उठा पाना संभव न हो सका था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अंततः हम पणजी में मिल रहे हैं तथा गोवा की जनता के स्नेहिल आतिथ्य का आनंद ले रहे हैं। इस तीन दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारिणी के सभी सदस्यों तथा विशेष आमंत्रितों का मैं स्वागत करता हूँ।

जिस समय यह गोवा बैठक हो रही है, उसका महत्त्व है। 6 अप्रैल, 1980 को भाजपा का उदय हुआ। इस प्रकार इस सप्ताह भाजपा ठीक पंद्रह वर्ष की हो जाएगी।

इस सप्ताह दो त्यौहार भी हैं और अनोखा संयोग है कि न केवल ईसाइयत के इतिहास में बल्कि भाजपा के लिए भी उनका महत्त्व है।

जनता पार्टी के नेताओं ने पूर्व जनसंघ के सदस्यों को पार्टी से निष्कासित करने के लिए जो कुख्यात दोहरी सदस्यता का प्रस्ताव बनाया था, वह 4 अप्रैल, 1980 को पारित किया गया और वह दिन था गुड फ्राइडे का। इस वर्ष भी अगले शुक्रवार को गुड फ्राइडे है। ईसाइयों का विश्वास है कि यही वह दिन है जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के दो दिन बाद भाजपा का औपचारिक श्रीगणेश हुआ और वह दिन था संडे का, जिस दिन माना जाता है कि ईसा मसीह फिर से जी उठे थे। इस वर्ष भी अगला रविवार ईस्टर संडे है।

हिंदुत्व की विचारधारा का पुनर्जन्म

1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन यथार्थ में एक विचारधारा का

पुनर्जन्म ही था—जातिवाद, सांप्रदायिकता और छद्म-सेक्यूलरवाद की शक्तियाँ हिंदुत्व की विचारधारा का गला घोंटना और निकाल बाहर करना चाहती थीं।

अयोध्या में 6 दिसंबर की घटनाओं के अवसर पर इन शक्तियों ने हमारी विचारधारा के विरुद्ध कीचड़ उछालने और मिथ्या आक्षेप करने का सरकार-प्रायोजित अभियान छेड़ दिया और उसे अवैध ठहराने की कोशिश की। धर्म-विधेयक इसी दिशा में उठा कदम था।

जब 1993 के विधानसभा चुनावों में भाजपा अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम न ला सकी तो हमारे इन विरोधियों ने हर्षित होकर घोषित कर दिया कि देश ने हिंदुत्व को नकार दिया है। उन्होंने इस कठोर सत्य को मानने से इनकार कर दिया कि यद्यपि भाजपा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल की सत्ता में नहीं रही, लेकिन आम जनता के समर्थन के पैमाने पर वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से कहीं आगे थी और अपनी प्रमुख विरोधी कांग्रेस की तुलना में उसे एक करोड़ वोट अधिक मिले थे। बहरहाल, हाल में विधानसभा चुनावों के जो दो दौर हुए, पहला गत वर्ष अक्तूबर-नवंबर और दूसरा फरवरी-मार्च में, उन्होंने परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है।

भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनरांकन

भारत का राजनीतिक मानचित्र यथार्थतः नए सिरे से अंकित हुआ है। भाजपा को अपने प्रदर्शन पर गौरवान्वित होने का उचित कारण है। देश के दो सबसे अग्रणी औद्योगिक प्रदेशों में हम सत्ता में हैं। गुजरात में अपने बलबूते पर और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन में। हमने दक्षिण में पार्टी को मजबूत आधार दिया है और कांग्रेस को तीसरी स्थिति में गिराते हुए कर्नाटक में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल बने हैं। उड़ीसा में हमने अपने सामर्थ्य को बढ़ाया है और बिहार में अपनी स्थिति बनाए रखी है। मणिपुर में हमने अपना खाता खोला और उससे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि गोवा के इस सुंदर प्रदेश में हमारी चार सदस्यों की टीम एक ऊर्जस्वी तथा सचेत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। 1993 में ही हमने राजस्थान और दिल्ली विजित किया है।

परंतु स्पष्ट कहा जाए तो इन तमाम उत्साहवर्द्धक समाचारों के बावजूद किसी हर्षोन्माद का कोई कारण नहीं है। गत कुछ महीनों में निश्चय ही हमें गौरव-पुष्प मिले हैं। परंतु उन्होंने हमें एक ऐसी भूमिका में भी डाल दिया है जो न केवल हमें अधिक विनम्र बल्कि अधिक कठोर भी बनाने वाली होगी।

निस्संदेह भाजपा बढ़ रही है, लेकिन चिंताजनक स्थिति यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वस्त होने की गति हमारे बढ़ने की गति से तीव्र है।

राष्ट्रीय शक्तियों की एकजुटता हमारा लक्ष्य

जो खतरनाक शक्तियाँ रिक्त स्थान भरने की कोशिश में हैं वे हैं जातिवाद, सांप्रदायिकता और साम्यवाद। भ्रष्टाचार के साथ-साथ बौखलाई हुई और असमान शक्तियाँ हमारे अस्तित्व और अस्मिता के लिए खतरा है। हमारे सामने अब सवाल कांग्रेस पार्टी का विकल्प होने का नहीं रह गया है। वह तो भाजपा को आज दूर-दूर तक समझा जाता ही है। भाजपा के सामने एक वृहत्तर कार्य है, क्योंकि हमारी ही वह एकमात्र पार्टी है जो भारत को एकजुट बनाए रखने के लिए केंद्रीय शक्ति प्रदान कर सकती है। हमारे सामने चुनावों में मात्र विजय प्राप्त करने का नहीं, देश को अखंड बनाए रखने का काम है।

परिवर्तनशील रुझानवाले हिंदी भाषी क्षेत्रों में हमें कुछ अजीब दृश्य दिखते हैं। लखनऊ जहाँ कांग्रेस समर्थित जातिवाद का नजारा है तो पटना में कम्युनिस्टों द्वारा समर्थित जातिवाद है। भोपाल में बुरी तरह विभाजित कांग्रेस आखिरी साँस तक लड़ने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर इन तीन राज्यों में प्रायः एक-तिहाई भारतीय जनता रहती है और इन तीनों राज्यों में केवल भाजपा की ही एकसूत्र केंद्रीय शक्ति है। तीनों राज्यों में मिलाकर भाजपा सबसे बड़ी अकेली पार्टी है। यही वह क्षेत्र है जहाँ अगली बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी।

कांग्रेस पतन की ओर

देश में कांग्रेस की स्थिति वास्तव में अस्पृहणीय हो गई है। यह तो सच है कि वह किसी तरह लोकसभा की आधी शक्ति जुटा पाई है, लेकिन यह चुनाव के माध्यम से नहीं, दल-बदल द्वारा हासिल की गई है। तो भी राज्यसभा में सदन की कुल संख्या का मात्र एक तिहाई ही उसके पास है। आप संसद् से बाहर आएँ और राज्य विधान मंडलों पर नजर दौड़ाएँ तो पाएँगे कि कांग्रेस का नियंत्रण जनसंख्या के मात्र पाँचवें हिस्से तक सिकुड़ गया है।

विधानसभा चुनावों के अंतिम दो दौर राव सरकार के पूरे देश की ओर से बोलने और काम करने के अधिकार को गंभीर रूप से क्षति कर गए हैं। आज राव सरकार साखहीन लँगड़ी सरकार की हालत में पहुँच चुकी है। ऐसी सरकार को पूरे साल भर चलना एक ऐसा आरोपण होगा जो देश सहन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय हितों को गंभीर क्षति पहुँचेगी।

नया जनादेश आवश्यक

इसलिए मैं आज भाजपा की इस माँग को पुनः दोहराता हूँ कि राव सरकार को फिर से नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए।

आपसी झगड़ों में व्यस्त उच्च कमान अपने लड़खड़ाते, कम होते जा रहे सिपाहियों का नेतृत्व करते हुए वस्तुतः महाभारत के दृष्टिहीन धृतराष्ट्र की भाँति

व्यवहार कर रहा है। वे अपने नाते-रिश्तेदारों द्वारा भारत की लूट को प्रोत्साहित करते हैं और उन्होंने इंद्रप्रस्थ अर्थात् आज की दिल्ली को भ्रमों से भरी मायानगरी में बदल दिया है।

सबसे बड़ा भ्रमजाल राव के आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप आ रही समृद्धि और खुशहाली में 'चमत्कार' से संबंधित है। दसियों वर्षों तक कांग्रेस भारत को आर्थिक विकास के सोवियत नमूने की राह पर ले जाती रही। उदारीकरण, विनियंत्रण, खुले बाजार जैसे शब्द उसके कानों को सुनने तक पसंद नहीं थे। उसका नतीजा एक ऐसे लाइसेंस-परमिट-कोटा राज के रूप में निकला, जिसने इस देश की असीम आर्थिक क्षमता को नष्ट कर दिया। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निरंतर इस लाइसेंस-परमिट-कोटा राज के विरुद्ध रही है और सदा से नियंत्रण, लाइसेंस और अफसरशाही के फंदे खत्म करने की वकालत करती रही है।

आइए, हम यह बात भी स्वीकार करें कि कांग्रेस पार्टी में उदारीकरण के लिए पैदा हुआ नया-नया उत्साह आर्थिक स्वार्थपूर्ति से प्रेरित था, न कि किसी सैद्धांतिकता से और इसका कारण यह खोज भी रही कि इस पद्धति में ज्यादा धन छिपा है।

उदारीकरण : लूट का एक और अवसर

स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लिए उदारीकरण लूट का एक और मौका है, ठीक उसी तरह जैसे धन-संपदा एकत्र करने के लिए लाइसेंस और परमिट राज था।

लंदन 'इकोनॉमिस्ट' ने हाल ही में भारत के बारे में एक सर्वेक्षण किया है। उसकी लेखिका एमा डंकन ने कानपुर से कन्या कुमारी तक काल्पनिक रेखा खींची और ध्यान रहे, वह अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा कर रही थीं, न कि राजनीति के बारे में। उन्होंने पाया कि इस रेखा के पश्चिम भाग में शांति, कानून-व्यवस्था और अधिक आर्थिक प्रगति है। परंतु उन्होंने इस रेखा के पूर्वी भाग में अराजकता ही पाई।

यह कोई संयोग नहीं है कि आज भाजपा देश के अधिकांश पश्चिमी भाग—दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ है। कर्नाटक और गोवा में भाजपा प्रमुख विपक्षी दल है।

अत्यंत प्रभावशाली! बहुत संतोषजनक! परंतु जरा पूर्वी भाग पर भी नजर डालें। लखनऊ, पटना, कलकत्ता और भोपाल। एक राजनीतिक दल के नाते हम अपने विरोधियों की परेशानी पर खुश हो सकते हैं। परंतु सच्चे भारतीय के नाते क्या हम अपने भाइयों की दुर्दशा पर हर्षित हो सकेंगे?

भाजपा : सबसे शक्तिशाली पार्टी के रूप में

भाजपा आज देश में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल बन ही चुका है। पिछले कुछ महीनों में यही एक सबसे महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। परंतु हमारे सामने और अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उससे हमारा संकल्प अधिक मजबूत और हमारा व्यवहार अधिक विनयी बनना चाहिए।

सबसे ताजा चुनावी मुकाबले के परिणाम का सर्वाधिक संतोषजनक पहलू यह रहा कि इसने हमारे उन आलोचकों का मुँह बंद कर दिया जो तरह-तरह की सामान्यीकृत व्याख्याएँ देकर हमारी प्रगति की खिल्ली उड़ाने में ही दिलचस्पी रखते थे।

1989 में इन आलोचकों ने तर्क दिया कि कांग्रेस विरोधवाद ने हमें लोकसभा में 86 सीटें दिलाईं। इनके अनुसार 1991 में सिर्फ अयोध्या ही मुद्दा था। उन्होंने चपलता से कहा भाजपा तो सिर्फ एक ही मुद्देवाली पार्टी है। परंतु इस बार वे सच में उलझन महसूस कर रहे हैं।

अल्पसंख्यकवाद गले पड़ा

एक बिंदु पर सभी चुनाव विश्लेषक सहमत हैं कि इस बार कांग्रेस की पराजय का एक प्रमुख कारण मुसलिम मतदाताओं का कांग्रेस-विरोधी रुख रहा। कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकवाद की जन्मदात्री ही नहीं, उसकी सबसे प्रमुख प्रोत्साहक भी रही है और अब यह उस पर ही उलटा वार साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने ही जाल में फँसकर भस्मासुर की स्थिति में आ पहुँची है।

कश्मीर पर तवलीन सिंह की हाल ही में छपी एक पुस्तक में हिजबुल मुजाहिदीन के एक वरिष्ठ नेता अब्दुल माजिद दर्दी के साथ लेखिका के एक रोचक वार्त्तालाप को उद्धृत किया है। इस वार्त्तालाप में दर्दी ने कहा था, "हम अब महसूस करते हैं कि कश्मीर समस्या का समाधान तभी मिलेगा जब दिल्ली में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ होगी। कम-से-कम वे बिना लाग-लपेट के बात करते हैं…मुखालफत भी करेंगे तो खुल के करेंगे।"

कांग्रेस और हमारे अन्य विरोधियों द्वारा जिस प्रकार के सेक्यूलरिज्म का व्यवहार किया जाता है वह मात्र छलावा है। वह पाखंड है। इसी को हम छद्म सेकुलरवाद कहते हैं, जो वोट बैंक राजनीति के लिए मुखौटा मात्र है। अधिक-से-अधिक मुसलमान अब यह महसूस करने लगे हैं कि भाजपा एक ईमानदार और स्पष्ट पारदर्शी रुखवाली पार्टी है जो वास्तविक अर्थों में सेक्यूलरिज्म के प्रति प्रतिबद्ध है, जब वह 'इसके लिए न्याय और किसी का तुष्टीकरण नहीं' के रूप में सेक्यूलरिज्म की व्याख्या करती है। इसका अर्थ है कि वह जो कहती है और जो वायदा करती है उसे पूरा करती है। मुसलमानों के इस वर्ग ने गुजरात और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों में बहुत मूल्यवान् योगदान दिया है।

आगे चुनौतियाँ-ही-चुनौतियाँ

इस चुनाव में भाजपा ने तीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था—भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और वोट बैंक राजनीति।

जबकि पहले दो मुद्दों ने हमें सार्वजनिक जीवन में पतन और गिरावट के लिए कांग्रेस पर आघात करने का अवसर दिया, वहीं तीसरे मुद्दे ने हमें अपनी विशिष्ट विचारधारा का दृष्टिकोण प्रकट करने में सहायता दी।

जो कश्मीर, अयोध्या, बँगलादेशी घुसपैठ, आई.एस.आई. की गतिविधियों इत्यादि पर अपने स्पष्ट रुख के कारण हमें सांप्रदायिक कहकर हमारी भर्त्सना करते हैं वे आज स्वयं सांप्रदायिक वोट बैंक के दबावों में काम कर रहे हैं।

जिस ढंग से कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों ने बँगलादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर न केवल महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में, बल्कि संसद् में भी शोर मचाने की कोशिश की है, उससे लगता है कि अभी तक जनादेश का अर्थ नहीं समझे हैं। भाजपा द्वारा उक्त वर्णित तीनों व्याधियों पर पहले की ही भाँति उग्र आघात जारी रहेंगे।

भाजपा को अयोध्या आंदोलन में अपने योगदान के प्रति गर्व है। परंतु वह एक मुद्दे वाली पार्टी नहीं है। देश की समस्याओं के प्रति उसकी दृष्टि समग्र है और यह भी कि हमारा दृष्टिकोण एकात्मवादी और समावेशक है, विभाजक नहीं। आनेवाले महीने चुनौतीपूर्ण हैं और वे हमें एक ऐसा अवसर भी दे रहे हैं जिसे हमें गँवाना नहीं है।

वंदेमातरम् !



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली

15-16 जुलाई, 1995

भाजपा दौड़ में सबसे आगे

आज हम विरार सम्मेलन के तीन महीने बाद और गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होने के साढ़े तीन महीने बाद मिल रहे हैं।

गोवा और विरार में भाजपा की बैठकें फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनावों में हमारी शानदार विजय के परिप्रेक्ष्य में हुई थी। हमने महाराष्ट्र में (शिवसेना के साथ मिलकर) और गुजरात में (अपने बल पर) शानदार विजय प्राप्त की थी। बिहार में हमने कांग्रेस को तीसरे स्थान पर छोड़ दिया और जनता दल सरकार के सामने प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभर कर आए।

इस प्रकार फरवरी-मार्च में हुए विधानसभा चुनावों ने दिखा दिया कि आगामी लोकसभा चुनावों की दौड़ में भाजपा सबसे आगे है।

कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल

हमारी विरार बैठक और आज की बैठक के बीच तीन महीने के अंतराल में अनेक राजनीतिक घटनाएँ और स्थितियों में परिवर्तन हुआ जिसके कारण देश की राजनीति में भाजपा की स्थिति और मजबूत हुई है। हाल की एक घटना ने हमारी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को बुरी तरह से धूमिल किया है। मैं इनमें से पाँच और महत्त्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विशिष्ट रूप से उल्लेख करना चाहूँगा—

हाल में उच्चतम न्यायालय ने सरला मुद्गल बनाम संघ मामले में भारत सरकार को संविधान के अनुच्छेद 44 की उपेक्षा करने के लिए सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता न बनाने के लिए भारत सरकार की भर्त्सना की है।

रामामूर्ति अधिकरण ने विश्व हिंदू परिषद् पर लगाए गए प्रतिबंध को अवैध

करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस अधिकरण ने निर्णय दिया है कि सरकार का निर्णय असंगत प्रयोजनों से लिया गया था और इसके प्रमाण में जो प्रणाली प्रस्तुत की गई वह जाली और मिथ्या थी।

चरार-ए-शरीफ में भारत सरकार की विफलता ने उसकी कश्मीर नीति के दिवालिएपन को पूरी तरह से खोलकर रख दिया है। चरार-ए-शरीफ पर हुई संसदीय बहस में प्रधानमंत्री का यह बयान सुनकर अतीव क्षोभ हुआ कि भारत सरकार, आजादी से कम, सब प्रकार की स्वायत्तता उग्रवादियों को देने के लिए तैयार है।

पिछले तीन महीनों में सबसे महत्त्वपूर्ण घटना उत्तर प्रदेश में सरकार में हुए परिवर्तन की है।

भाजपा का 'ऑपरेशन मुलायम सिंह' सफल

हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा राजनीति के अपराधीकरण को एक केंद्रीय मुद्दा बनाने में सफल रही है। इस बुराई ने देश में कानून और व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुँचाया है और एक आम नागरिक के जीवन को खतरे में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को मुलायम सिंह के शासन काल के दौरान इसका कटु अनुभव हुआ था। वास्तव में मुलायम सिंह सरकार के उसी कृत्य ने बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी से अलग किया और उसे भाजपा के साथ मिलने पर प्रेरित किया।

'ऑपरेशन मुलायम सिंह' बड़ी कुशलता से कार्यान्वित किया गया। इससे एक साथ दो उद्देश्यों की पूर्ति हुई। प्रथम, एक राजनीतिक उद्देश्य पूरा हुआ— मुलायम सिंह सरकार को सत्ता से हटाया गया। द्वितीय, एक सामाजिक उद्देश्य पूरा हुआ— मायावती सरकार को भाजपा के समर्थन से स्थापित किया गया और इससे दलितों में गर्व एवं संतोष का भाव पैदा हुआ तथा वे फिर से आश्वस्त हो सके, जिससे हिंदू समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला।

राजनीति में अपराध-भाव

पिछले सप्ताह नई दिल्ली में तंदूर हत्याकांड ने बड़े नाटकीय ढंग से यह बात उजागर की है कि किस प्रकार से स्वयं कांग्रेस पार्टी ने राजनीति में अपराधियों और अपराधिता को निर्लज्जतापूर्वक बढ़ावा दिया है।

यह मामला किसी एक व्यक्ति या मात्र किसी एक अपराधपूर्ण कृत्य से नहीं जुटा है। इस प्रकार के पाशव आचरणवाला एक व्यक्ति इतने लंबे समय से सत्ताधारी पार्टी से संबद्ध अनेक 'अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी.)' का संरक्षण प्राप्त करता रहा और उदारतापूर्वक लाभ प्राप्त करता रहा, यही एक बात उस पार्टी पर एक बहुत बड़ा धब्बा है।

तंदूर कांड

जब पिछले मई मास में कांग्रेस पार्टी का औपचारिक रूप से विभाजन हो गया तो अलग हुए दल को सरकार ने बड़े तिरस्कृत रूप से 'तिनका' कांग्रेस का नाम दिया था। अब स्वयं सरकारी कांग्रेस 'तंदूरी कांग्रेस' के कलंक से विभूषित हो गई है। इस घिनौनी हत्या के बारे में प्रकाशित रिपोर्टों से पूरे देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा हुई है। यह अपराध कभी भी भुलाया या माफ नहीं किया जा सकेगा।

ऐसे समाचार मिले हैं कि प्रधानमंत्री ने गुप्तचर ब्यूरो से एक रिपोर्ट माँगी है कि वह कौन से मंत्री हैं और पूर्व मंत्री हैं जो इस घिनौने प्रकरण से जुड़े हुए हैं। यह रिपोर्ट तुरंत लोगों के सामने रखी जानी चाहिए। न्यायालय तो कथित हत्यारे या हत्यारों के बारे में कार्यवाही करेगी ही परंतु लोग निश्चित ही जानना चाहेंगे कि वे कौन से कांग्रेसी राजनीतिज्ञ हैं जो सीधे राष्ट्रीय राजनीति को पतन की स्थिति तक पहुँचाने और उसे भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में दलीय पद्धति में जबरदस्त कायापलट हुई है।

कांग्रेस के स्थान पर भाजपा राष्ट्रीय विकल्प के रूप में

अनेक दशकों से भारत में दलीय ढाँचा ऐसा था जिसमें एक ही पार्टी का प्रभुत्व स्वीकार किया जाता था। कांग्रेस के प्रभुत्व का कुछ इस ढंग से बखान किया जाता था कि सामान्यतया विपक्षी दलों को यह विश्वास करना पड़ता था कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। सरकार को हटाने के लिए सभी विपक्षी दलों की गतिविधियों का उद्देश्य कांग्रेस विरोधी गठजोड़, बनाना और मिली-जुली गैर कांग्रेस सरकारें बनाना होता था। इस प्रकार कांग्रेस विरोध सत्ता-परिवर्तन का एक प्रमुख उपकरण बना हुआ था। पार्टी के कार्यक्रमों और उसकी विचारधारा का चुनाव के परिणामों पर कम ही प्रभाव पड़ता था।

भाजपा इस धारणा को हटाने में सफल हुई कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। 1991 से अब व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि वह कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

पिछले कुछ वर्षों में भाजपा की एक और सफलता यह रही है कि मतदाताओं में विचारधारा को संगत मुद्दा बना सकी है। हम देश भर में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम छद्म-सेक्यूलरवाद पर बहस कराने में सफल हुए हैं। अब अधिक-से-अधिक लोग महसूस करने लगे हैं कि सेक्यूलरवाद के नाम पर हमारे विरोधी चाहते हैं कि राष्ट्र अपनी अस्मिता जिसे हिंदुत्व कहते हैं, उसे नकार दे। इस राष्ट्रीय अस्मिता को भी भारतीयता का नाम दिया जा सकता है। परंतु इसका अंतर्निहित सार एक ही है।

भारतीय सेक्यूलरवाद के बारे में एक विशद अध्ययन में डोनाल्ड यूजीन ने लिखा था—'भारतीय संस्कृति एक मिली-जुली संस्कृति होने के बावजूद उसमें हिंदुत्व ही अत्यधिक शक्तिशाली और व्यापक बन रहा है। वे लोग जो बार-बार भारतीय संस्कृति के इस मिले-जुले स्वरूप के बारे में बहुत बल देते हैं, इस बुनियादी तत्त्व के महत्त्व को कम कर देते हैं।' हिंदुत्व ने ही वास्तव में भारतीय संस्कृति को आवश्यक विशिष्टता प्रदान की है।

एक ओर भाजपा की शक्ति बढ़ती गई और दूसरी ओर कांग्रेस का विकल्प ढूँढ़ने या बनाने की बात नहीं सोच रहा है। इस समय भाजपा का विकल्प ढूँढ़ा जा रहा है।

दिल्ली में भाजपा शासन

अभी हाल में ही अगले लोकसभा चुनावों के संभावित परिणामों पर टिप्पणी करते हुए जनता दल के नेता श्री रामकृष्ण हेगड़े ने भविष्यवाणी की थी कि केंद्र में भाजपा का सत्ता में आना निश्चित है। उनके अनुसार केवल एक ही तरीका है जिससे इस स्थिति को टाला जा सकता है और वह यह है कि राष्ट्रीय मोरचे और वाम मोरचे की सभी पार्टियाँ चुनावों से पहले ही कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर लें, श्री नरसिंह राव के अधीन मिली-जुली सरकार बनाने को तैयार हों और एकजुट होकर भाजपा के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए जोर लगाएँ।

श्री हेगड़े का प्रस्ताव धरा-का-धरा रह गया। परंतु इससे निश्चित ही दो तथ्य सामने आते हैं—कांग्रेस पार्टी अब देश की प्रमुख पार्टी नहीं रह गई है; भाजपा अब भारतीय राजनीति का प्रमुख ध्रुव बन गई है।

भाजपा—विजय की ओर

आज भाजपा तेजी से आगे बढ़ने को उद्यत है। कोई भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं करता है। फिर भी राजनीतिक क्षेत्रों में भ्रम फैला रखा है कि संभवतः 1996 की लोकसभा त्रिशंकु होगी, भाजपा सबसे बड़ी एक पार्टी होगी, परंतु उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा।

भाजपा इस संदेश को गलत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। आगामी महीनों में सुनियोजित ढंग से चुनावी योजना तैयार कर और अथक परिश्रम करके हम निश्चित ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसे दो राज्य थे जिनके बारे में सभी प्रेक्षकों ने त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की थी। परंतु मतदाताओं ने स्पष्ट निर्णय देना उचित समझा और अंततः यही हुआ।

सामूहिक रूप से मतदाताओं का मन त्रिशंकु विधानमंडल बनाने के पक्ष में नहीं है। यदि मतदाता स्पष्ट रूप से पहचान जाता है कि कौन सा दल दौड़ में सर्वप्रथम है तो मतदाता का झुकाव पूरी तरह से उस दल के पक्ष में होता है, ताकि

स्पष्ट निर्णय निकल सके।

मुझे पूरी आशा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में भी देश में ऐसा ही होगा।

कांग्रेस विरोधवाद का जन्म तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। यह लगभग सरकार के खिलाफ विरोध की भावना जैसा ही था। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि भाजपा विरोधवाद भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए किया जा रहा है, हालाँकि अभी भाजपा सत्ता में है नहीं, अब वैचारिक दृष्टिकोण की शक्ति को स्वीकार किया जा रहा है।

केवल नकारात्मक आधार पर बनी सरकारें नहीं चलती हैं। कोई कांग्रेस-विरोधी गठबंधन अधिक समय तक नहीं चल सका। भाजपा-विरोधी गठबंधनों का इससे भी कहीं बुरा हश्र होगा।

राष्ट्रवाद और आदर्शवाद

भाजपा की बढ़ती हुई गति विचारधारा और आदर्शवाद दोनों का सम्मिलित सुफल है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के तेजी से विकास का कारण कश्मीर, अयोध्या, समान नागरिक संहिता, गोरक्षा, अवैध घुसपैठ, भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण आदि पर हमारा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण तो है ही। साथ ही यह आम भावना पैदा हुई है कि भाजपा एक अलग प्रकार की पार्टी है। हमारी पार्टी विपक्ष में हो या सत्ता में, वह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के प्रति वचनबद्ध है और हम ईमानदारी से भारतीय राजनीति को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है।

भाजपा-शासित राज्यों में भाजपा से ऊँची आशाएँ

हमें सतत प्रयास करना होगा कि अधिकाधिक लोग इस सत्य को पहचानें कि भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना एक उदार और प्रबुद्ध संकल्पना है और यह भी कि हिंदुत्व मजहबी राज्य, धर्मांधता और संकीर्णता को स्वीकार नहीं करता है। दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत व्यवहार में बहुत ईमानदार और सार्वजनिक क्षेत्र में अपने आचरण को बहुत खरा बनाकर भी रखना होगा।

इस समय भाजपा देश के चार राज्यों में शासन कर रही है। विशेष रूप से हमें इन राज्यों में लोगों की आशाओं की तुलना पर खरा उतरना होगा।

वंदेमातरम् !



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

पुणे 7-8, नवंबर, 1995

भाजपा—सबसे आगे

इस कार्यकारिणी की यह अंतिम बैठक है। जून 1993 में बंगलौर में हुए अधिवेशन के बाद इस कार्यकारिणी का गठन हुआ था। आपके इस सवा दो वर्ष के कार्यकाल में 15 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। परिणाम पार्टी के लिए काफी सुखद रहे हैं। चार प्रदेशों में हम यशस्वी हुए और सरकार बना पाए। दिल्ली, राजस्थान व गुजरात में अपने बलबूते पर और महाराष्ट्र में शिवसेना से मिलकर। कर्नाटक व बिहार में, हम कांग्रेस को पछाड़ कर विधानसभा में प्रमुख विरोधी दल का स्थान प्राप्त कर पाए।

कुल मिलाकर 1993, 1994 और 1995 में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी को न केवल कांग्रेस के प्रमुख प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित किया है वरन् यह भी सिद्ध कर दिया है कि लोकसभा के लिए चल रही दौड़ में भाजपा ही सब से आगे है।

मुंबई अधिवेशन के बाद बननेवाली नई कार्यकारिणी में कुछ अनिवार्य परिवर्तन करने होंगे। पार्टी के संविधान में हाल में हुए संशोधन के अनुसार कम-से-कम 25 प्रतिशत सदस्य नए होने चाहिए।

पुणे की इस बैठक के सामने प्रमुख कार्य हैं—मुंबई महाधिवेशन के लिए प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करना। महाधिवेशन का आकार बहुत विराट् होने वाला है। संभवतः वहाँ दो ही प्रमुख प्रस्ताव लिये जा सकेंगे। यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी उपयुक्त समझे तो कुछ विषयों पर अपनी ओर से प्रस्ताव जारी करे।

बार-बार चुनाव की स्थिति समाप्त हो

मुंबई का महाधिवेशन लोकसभा के 11वें आम चुनाव से कुछ ही महीने पहले हो रहा है। इन्हीं चुनावों के समय हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु,

पांडिचेरी व केरल विधानसभाओं के भी चुनाव होने हैं। हाल में इस सूची में उत्तर प्रदेश भी जुड़ गया है। भाजपा की माँग है कि वे सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए।

वास्तव में, राजनीतिक दलों को मिलकर ऐसी उपाय-योजना पर विचार करना चाहिए कि क्या लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव फिर एक साथ नहीं हो सकते जैसे चौथे आम चुनाव अर्थात् 1967 तक हुआ करते थे। 1971 से ही इसमें विलगाव आ गया। उससे चुनाव पर होनेवाला व्यय बहुत बढ़ गया है। अब प्रायः हर वर्ष या एक वर्ष छोड़ दूसरे वर्ष एक लघु आम चुनाव होता रहता है। यह स्थिति न लोकतंत्र के लिए और न ही प्रशासन के लिए स्वस्थ है।

साधारणतः एक लोकसभा चुनाव जनता के सामने विगत 5 वर्षों के कार्यकलापों का लेखा-जोखा लेने क़ा अवसर प्रस्तुत करता है। 1996 का चुनाव भी नरसिंह राव की सरकार के कार्यकाल का विवेचन करने का अवसर होगा। इन 5 वर्षों में भ्रष्टाचार व अपराधीकरण भयंकर रूप से बढ़ा है। राष्ट्र की एकता व सुरक्षा पूरी तरह से संकटग्रस्त हो गई है।

किंतु 1996 के लोकसभा चुनावों का एक विशेष महत्त्व भी है। 15 अगस्त, 1997 को भारत अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएगा। लोकसभा के 12वें चुनाव सामान्यतः सन् 2001 में होंगे। 1996 के चुनाव संभवतः इस शताब्दी के अंतिम लोकसभा चुनाव होंगे।

अतएव इस आनेवाले अभियान में हम केवल इन 5 वर्षों पर ही अपना ध्यान केंद्रित न करें। देश की आजादी के बाद की पूरी अर्ध-शताब्दी का मूल्यांकन करने के लिए जनता को प्रेरित करें। 1947 के बाद के 48 वर्षों में से 44 वर्षों तक कांग्रेस का ही राज रहा है। देश की आज की दुर्दशा के लिए यदि किसी पार्टी को दोष दिया जा सकता है तो मात्र कांग्रेस को।

कांग्रेस के खोखले वायदे

14 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान सभा में दिए अपने उस ऐतिहासिक भाषण 'नियति से मुलाकात' में कहा था कि राष्ट्र के सामने प्रमुख कार्य है 'गरीबी और अज्ञान और बीमारी और अवसर की असमानता का अंत।'

भारत के पास ऐसे अतुल मानवीय और भौतिक संसाधन हैं जिनसे पश्चिम के विकसित देश भी ईर्ष्या करें। परंतु इन सबके बावजूद आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी 'गरीबी और अज्ञान और बीमारी और अवसर की असमानता के अंत' का दूर-दूर तक कोई निशान नहीं।

भारत आज भी विश्व के सर्वाधिक अभावग्रस्त देशों में से एक बना हुआ है। न केवल पश्चिमी राष्ट्रों की तुलना में अपितु विकासशील संसार के अधिकांश देशों के मुकाबले में भी।

भाजपा सुशासन के प्रति वचनबद्ध

यह स्थिति बदलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यह परिवर्तन लाने के लिए कृत-संकल्प है। विगत कुछ वर्षों में भाजपा राष्ट्रीय राजनीतिक मंच के केंद्र में पहुँच गई है। करोड़ों देशवासियों को आज की अति निराशाजनक स्थिति में भाजपा ही आशा की किरण के रूप में दिखाई दे रही है। हमें इन करोड़ों लोगों की आशा-आकांक्षाओं के अनुरूप खरा सिद्ध होना है और लोकसभा के आगामी चुनाव से पूर्व देश के सामने 'भारत 2001' की अपनी कल्पना प्रस्तुत करनी है। चुनाव के लिए हमारा घोषणा-पत्र यह निरूपित करेगा कि हम इस कल्पना को कैसे साकार करेंगे।

इस कार्यकारिणी के 11 सदस्यों को मैं घोषणा-पत्र समिति के रूप में आज नामांकित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि अपने अन्य सहयोगियों से सलाह कर, हमारे मुख्यमंत्रियों से परामर्श कर, उन सभी बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, सैनिकों, शिक्षा-शास्त्रियों आदि से जो पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के साथ जुड़े हैं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से राय लेकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार करेंगे जो एक आदर्श प्रशासन के माध्यम से भारत को वास्तविक अर्थों में राम राज्य बना देगा।

वंदेमातरम् !



राष्ट्रीय परिषद्

मुंबई 10-12 नवंबर, 1995

स्वागत समिति के अध्यक्ष जी, प्रतिनिधि भाइयो और बहनो!

सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस महान् पार्टी का एक और कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना।

पार्टी के पास आज जो कार्य हैं वे पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। लोगों की अपेक्षाएँ भी बहुत बढ़ गई हैं। फिर भी मुझे कोई संदेह नहीं कि भाजपा के 80 लाख सदस्यों और देश भर में फैले हुए करोड़ों समर्थकों और हितचिंतकों के सहयोग से हम राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ सिद्ध होंगे।

बंबई से मुंबई तक

1980 में बंबई में भारतीय जनता पार्टी का पहला महाधिवेशन संपन्न हुआ था। पार्टी के उस प्रथम अखिल भारतीय एकत्रीकरण ने सभी को बहुत अधिक प्रभावित किया। अधिवेशन में अतिथि वक्ता के रूप में विशेष रूप से आमंत्रित दिवंगत श्री मोहम्मद करीम छागला ने एकत्रित प्रतिनिधियों का इन शब्दों में आह्वान किया था—

"यह कहना कि भाजपा सांप्रदायिक है, पूर्णतः बेहूदा और निराधार है····। मैं आपके अनुशासन, आपकी ईमानदारी और आपके समर्पण का प्रशंसक हूँ। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपने भविष्य को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में प्रकट करें। पूरे देश में जाइए और लोगों को बताइए कि आप कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं, बल्कि जैसा कि वाजपेयीजी ने ठीक ही कहा है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और अकेली ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस का विकल्प बन सकती है।"

15 वर्ष पश्चात् जब हम पुनः इस महानगर में एक और महाधिवेशन के निमित्त मिल रहे हैं, हमें यह महसूस करते हुए संतोष होता है कि हमारे प्रयासों ने छागलाजी की अभिलाषा को साकार कर दिया है। भाजपा अब किसी क्षेत्र

विशेष तक सीमित पार्टी नहीं मानी जाती है। उसका राष्ट्रव्यापी आधार है और उसे राष्ट्रव्यापी समर्थन प्राप्त है।

आज बंबई का अधिकृत रूप से 'मुंबई' नामकरण कर दिया गया है। भाजपा के लिए बंबई से मुंबई तक की यह 15 वर्षीय यात्रा एक कठिन लेकिन रोमांचक यात्रा रही है। यह काफी संतोषप्रद भी है। निश्चित रूप से रास्ते में कई उतार-चढ़ाव भी मिले। लेकिन इन सबके अंत में भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा स्थान अर्जित कर लिया है जो आजादी के बाद कोई भी गैर-कांग्रेस पार्टी प्राप्त नहीं कर सकी थी।

भारतीय राजनीति का रूपांतरण

वस्तुतः गत 15 वर्षों में भारतीय राजनीति एक समग्र परिवर्तन के दौर से गुजरी है। यह भाजपा के कारण ही हुआ है। प्रारंभिक वर्षों के विपरीत अब एक पार्टी की विचारधारा और दृष्टिकोण ने चुनावों को अधिक-से-अधिक प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यह भी हुआ है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण का चरित्र बदल गया है।

कई दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति दो शिविरों में ध्रुवीकृत रही—एक कांग्रेस शिविर और दूसरा गैर कांग्रेस शिविर। चुनाव अनिवार्यतः राजनीतिक श्रेष्ठियों और राजनीतिक वंचितों के बीच का एक संघर्ष बनकर रह गए थे। गैर कांग्रेस शिविर के घटकों की सफलता मुख्यतः सरकार विरोधी भावनाओं पर अवलंबित रहती थी। इस प्रकार राजनीतिक परिवर्तन को मुख्यतः गैर कांग्रेसवाद से ही गति मिलती थी। विचारधारा और यहाँ तक कि पार्टी कार्यक्रम भी चुनाव परिणामों से नितांत संदर्भहीन बने हुए थे।

राष्ट्रवाद के बारे में भाजपा अटल

'80 के दशक के उत्तरार्द्ध और; '90 के दशक में भाजपा की अभूतपूर्व प्रगति का श्रेय जम्मू-कश्मीर, अयोध्या, बँगलादेश से अवैध घुसपैठ, आई.एस.आई. की गतिविधियों तथा समान नागरिक संहिता पर भाजपा के राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के प्रति सकारात्मक सोच पर आधारित दृष्टिकोण को मिले जनता के उत्साहजनक समर्थन को दिया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर भाजपा का दृढ़ राष्ट्रवादी रवैया ही है जिसने उसके विरोधियों को इकट्ठा होने तथा भाजपा को 'सांप्रदायिक' और 'सेकुलर विरोधी' कहने को उद्यत किया।

इसका कुल परिणाम यह निकला है कि हालाँकि अभी तक भाजपा सत्ता-प्रतिष्ठान नहीं बनी है, फिर भी आज जिन दो नए राजनीतिक शिविरों में राष्ट्रीय राजनीति ध्रुवीकृत हो गई है वे हैं एक भाजपा शिविर और दूसरा गैर भाजपा शिविर।

वास्तविक पंथ निरपेक्षता

छद्म सेकुलरवादियों द्वारा भाजपा के विरुद्ध एक निंदा अभियान छेड़ दिया गया है कि भाजपा मुसलिम-विरोधी है और यदि हम सत्ता में आए तो भारत को एक हिंदू धर्म-राज्य बना देंगे।

इस प्रकार के आक्षेपों का हम अपनी पूरी ताकत से विरोध करते हैं और इन आलोचकों की सेकुलर-साख को प्रश्नांकित करते हैं। हम उन्हें छद्म सेकुलर मानते हैं।

फिर भी यह समझ लेना चाहिए कि छद्म सेकुलरवादी दो छाप के हैं। पहली छाप वाले वे हैं जो मूलतः यह मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानते हैं कि धर्म जनता की अफीम है उनके लिए एक निधार्मिक राज्य ही सच्चा सेकुलर हो सकता है। दूसरी छाप का और एक ज्यादा बड़ा गुट मुख्यतः राजनीतिज्ञों का है, जिनके लिए सेकुलरवाद वोट बैंक की राजनीति का मात्र एक मुखौटा है। हवा के रुख का उनका जैसा आकलन हो, उसके अनुसार ये राजनेता एक समय जिस जगह पर बाबरी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए उत्साहित हो सकते हैं, दूसरे समय उसी जगह पर राम-मंदिर बनाने के लिए एक रामालय ट्रस्ट की रचना के प्रति भी उत्साह दिखा सकते हैं।

भाजपा असंदिग्ध रूप से वास्तविक सेकुलरवाद, जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अभिकल्पित किया, से प्रतिबद्ध है। उनकी अवधारणा के तीन तत्त्व थे और उन सभी को संविधान में अंकित किया गया है। ये हैं—

(क) मजहबी राज्य का अस्वीकार।

(ख) सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी आस्था को मानने वाले हों, समान हैं और

(ग) प्रत्येक नागरिक को अपने पंथ या मजहब के व्यवहार और प्रचार की पूरी स्वतंत्रता की गारंटी है।

1947 में यद्यपि देश का विभाजन मजहब पर आधारित था और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी स्वयं को इसलामी राज्य घोषित किया था, भारत ने पंथनिरपेक्षता को चुना। यह इसलिए हुआ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद का मूल इस देश की युगों पुरानी संस्कृति में निहित है जो कि अनिवार्यतः हिंदू है। मजहबी राज्य हिंदू राजनीति, इतिहास तथा संस्कृति के लिए अनजाना है। यह महत्त्वपूर्ण राज्य हिंदू राजनीति, इतिहास तथा संस्कृति के लिए अनजाना है। यह महत्त्वपूर्ण है कि बँगलादेश जो 1971 में भारत की सहायता से स्वतंत्र हुआ, प्रारंभ में सेकुलर देश रहा, लेकिन कालांतर में वह सेकुलरवाद को खत्म कर पाकिस्तान की तरह ही इसलामी देश बन गया।

हम यह मानते हैं कि राष्ट्रीय मुख्यधारा के अंग के रूप में मुसलमानों का भारत में महान् भविष्य है। उनके लिए मेरे तीन सुझाव हैं—

(क) शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें।

(ख) हिंदुओं पर विश्वास करें, जिन्होंने भारत को एक पंथनिरपेक्ष देश बनाया है और

(ग) स्वयं को वोट बैंक दलालों के शिकंजे से मुक्त करें।

उनकी चिंता इन तथाकथित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नहीं है। उनका एकमात्र स्वार्थ है—अल्पसंख्यक वोट

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम छद्म सेकुलरवाद

देश में इस समय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम छद्म सेकुलरवाद पर जो जबरदस्त राष्ट्रीय बहस छिड़ी हुई है उसका श्रेय भाजपा को ही है।

'हिंद स्वराज' में महात्मा गांधी ने लिखा था—

'अंग्रेजों ने हमें यह सिखाया है कि पहले हम एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में अभी हमें शताब्दियाँ लगेंगी। यह बात निराधार है। उनके भारत आने से पहले से ही हम एक राष्ट्र थे। एक ही विचार हमें प्रेरित करते थे। हमारी जीवन शैली एक समान थी। चूँकि हम एक राष्ट्र थे, इसलिए वे एक साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए।'

भारत का राष्ट्रत्व न तो ब्रिटिश शासन की देन है, न ही उस स्थिति में स्वतंत्रता आंदोलन की। न ही वह भारत के संविधान से उपजा है। वास्तव में तो स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन स्वराज के लिए संघर्ष की अग्नि प्रदीप्त करने हेतु जाग्रत् हुई राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति था। भारत के संविधान ने वस्तुतः उस प्राचीन राष्ट्र को मान्य किया है जो इस भूमि में हजारों वर्षों से विद्यमान रहा है। जब संविधान में गोरक्षा को निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया गया तो यह उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्वीकारोक्ति ही थी जो उस राष्ट्र के जीवन का प्राण है।

यथार्थतः आजादी के बाद के राजनीतिक नेतृत्व ने भारत और भारतीय राष्ट्रवाद के ब्रिटिश दृष्टिकोण को आत्मसात् कर लिया है। सेकुलरिज्म के नाम पर वे देश को अपना अनिवार्य व्यक्तित्व ही छोड़ देने पर जोर दे रहे हैं। इसी ने आजादी के बाद विखंडनवादी प्रवृत्तियों और अलगाववादी राजनीति के उभार में सबसे ज्यादा योगदान दिया है।

भाजपा का यह दृढ़ विश्वास है कि केवल भारतीय राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक आधारशिलाओं में निहित अनंत शक्ति को मान्य करके ही अलगाववादी ताकतें खत्म कर राष्ट्र को एकजुट किया जा सकता है। यह बात गौण है कि आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की इस अवधारणा को कैसे बताते हैं—हिंदुत्व के रूप में या भारतीयता के रूप में। मूल तत्त्व तो एक ही है। अयोध्या में राम-मंदिर के निर्माण हेतु भाजपा का संघर्ष उन्हीं सांस्कृतिक आधारशिलाओं को मजबूत करने के लिए है, ताकि भारत माता का एक भव्य राष्ट्र-मंदिर बनाया जा सके।

हिंदुत्व : एकात्मवादी सिद्धांत

इस प्रकार हिंदुत्व एक एकात्मवादी सिद्धांत है। यह भारत की आत्मा की रक्षा और उसे पुनः ऊर्जावान् बनाने का सामूहिक उद्यम है। यह एक ऐसा सकारात्मक प्रयास है जो इस महान् भूमि की रचनात्मक शक्ति का प्रस्फुटन करता है और किसी भी एक वर्ग को दूसरे की कीमत पर लाभ उठाने की शर्मनाक कोशिशों को रोकता है। हिंदुत्व है अनुशासन और आत्मानुशासन और इसके अनुयायियों के लिए यह एक तपस्या है, न कि विधान मंडलों या ऊँचे पदों पर पहुँचने का एक टिकट।

समान नागरिक संहिता

सरला मुद्गल तथा अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह, जो इस किस्म का तीसरा निर्णय था, केंद्र में आई सरकारों के विरुद्ध इस बात के लिए तीव्र अभियोग से कम नहीं था कि वे समान नागरिक कानून लागू करने में असफल रहीं तथा उन्होंने संविधान की धारा 44 के प्रावधानों की उपेक्षा की।

राव सरकार ने मुसलिम निजी कानून के बचाव की युगों पुरानी बातें ही दोहराना चुना, जो बचाव इस गलत धारणा पर टिका है कि यह कानून छेड़ा नहीं जा सकता तथा इसमें बदलाव की कोई भी बात मुसलिम समुदाय के भीतर से ही उठनी चाहिए। यह धारणा इसलिए दोषपूर्ण है, क्योंकि मुसलिम निजी कानून न तो अपरिवर्तनीय है, न ही यह ऐसी वैधानिक संहिता है जिसका मुसलमान प्राचीन काल से पालन करते आ रहे हों। इसे मात्र 1937 में ही वैधानिक मान्यता दी गई थी, जब अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के दमन के लिए मुसलिम लीग को इस्तेमाल करने की नीति को पक्का किया था।

पृथक् निजी कानून स्त्री-पुरुष असमानता को ही बढ़ावा देते हैं, जबकि भाजपा विरोधी प्रत्येक राजनीतिक दल महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए मात्र शब्द-विलास करते हुए नहीं थकता, उन्होंने निजी कानूनों के जरिए महिलाओं पर थोपी गई सबसे बड़ी असमानता दूर करने के लिए कुछ भी किया नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि संविधान की धारा 44 पर पुनः दृष्टिपात करे, ताकि पूरे देश के नागरिकों पर समान नागरिक कानून लागू किया जा सके। परंतु नरसिंह राव सरकार ने अपनी खासियत के अनुरूप दूसरी दिशा में ही देखना पसंद किया है। प्रधानमंत्री ने तो धारा 44 के विरोध की कसम खाने और उनसे मिलने आए मुसलिम प्रतिनिधिमंडलों को वैसा ही आश्वासन देने के लिए बरेली की यात्रा तक कर डाली।

महाराष्ट्र सरकार के सराहनीय कदम

मैं महाराष्ट्र सरकार को इस बात की बधाई देता हूँ कि उसने कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने और निजी कानूनों के विकृत प्रभाव दूर करने के लिए पहला कदम उठाया है। यहाँ राज्य सरकार ने नवीन मार्ग प्रशस्त करनेवाले दो ऐसे विधेयक बनाए हैं जो सम्मिलित रूप से महाराष्ट्र के नागरिकों पर, उनके मजहब, नस्ल या जाति के भेद से परे हटकर, समान नागरिक कानून लागू होने की दिशा में पहला कदम है। पहले विधेयक का लक्ष्य बहुपत्नी विवाह रोककर एक पत्नी-विवाह की सर्वमान्य व्यवस्था हासिल करना है। दूसरा विधेयक भी, जो धारा 44 के कथ्य और भाव के अनुरूप है, गोद लेने के लिए समान नागरिक कानून सभी व्यक्तियों पर मजहब, जाति, नस्ल या स्त्री-पुरुष भेद से परे हटकर, लागू करने से संबंधित है।

भ्रष्टाचार और अपराधीकरण

ऐसे तीन प्रमुख मुद्दे हैं जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और इसलिए हमारे शासन-तंत्र को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ये तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं और एक- दूसरे से शक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से भी काम करते हैं। ये तीन पहलू हैं—धन और शासन, अपराध और शासन तथा तीसरा भ्रष्टाचार और शासन।

राजनीति में धन-बल

शासन में धन की भूमिका कांग्रेसी संस्कृति की हमारी राजनीति में सीधी देन है। इसके अब बहुत हानिकारक पहलू हो गए हैं। क्योंकि इस देश के सर्वोच्च पदस्थ द्वारा इसे वैधानिकता प्रदान कर दी गई है। गत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार धन-शक्ति ने हमारी निर्वाचित संसद् तक का गणितीय समीकरण बदल दिया। धन के निर्लज्ज उपयोग द्वारा अनेक पार्टियाँ तोड़ी गईं और संसद् में थोक में दल-बदल करवाए गए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस में दल-बदल कर आनेवाले सांसदों को स्वीकार करने का निर्णय 'राजनीतिक, नैतिक और मर्यादा की दृष्टि से उचित निर्णय' कहकर न्यायसंगत ठहराया।

मैं देश को यह चेतावनी देना चाहूँगा कि चुनाव-परिणाम विकृत करने के लिए धनशक्ति की वीभत्स भूमिका एक अत्यंत हानिकारक घटनाक्रम है। यदि हम स्वयं को उसी तरह उदासीन होने दें, जैसे कि प्रधानमंत्री हुए हैं या इसके प्रति उपेक्षा-भाव भी अपना लें तो हमारे देश का समूचा लोकतांत्रिक उद्यम बिखर जाएगा। हम यह होने नहीं दे सकते। हमारी राजनीति के इस नैतिक पतन को रोकने के लिए भाजपा पुनः स्वयं को प्रतिबद्ध करती है।

कांग्रेस नेता प्रायः भ्रष्टाचार को अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम बताकर इसे टालने

की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ सारे विश्व के देशों में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। भारत में यह विष-बीज फल-फूल रहा है।

हर साल भ्रष्टाचार का व्याप बढ़ता जा रहा है। बोफोर्स लगभग 65 करोड़ का मामला था। सिक्योरिटी घोटाला इस राशि से सौ गुने से भी ज्यादा का निकला। इस बीच छोटे घोटाले हुए, जैसे चीनी घोटाला जिसमें कतिपय मंत्री शामिल थे। तस्कर, नशीले पदार्थों के मुखिया, अपराधियों के गुट और संरक्षण देने के नाम पर चलनेवाले गिरोह—ये सभी कांग्रेस के मुख्य संरक्षक बन गए हैं। इतने सब का तो उस वोहरा समिति की रपट से संकेत मिलता ही है जिसने सिर्फ इस बड़े हिमखंड का छोटा सा कोना ही स्पर्श किया है।

राजनीति और अपराध के बीच सह-संबंध निंदनीय

हाल ही में विधानसभा चुनावों में वह मुख्य मुद्दा राजनीति और अपराध के बीच गठजोड़ का ही था जिसने जनता को कांग्रेस अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। वोहरा समिति की रपट में यह प्रमुखता से कहा गया है कि किस प्रकार 'माफिया संगठन' प्रायः 'एक समानांतर सरकार' चलाने लग गए हैं। इस सरकार के कार्यकलाप उस समिति की रपट से जो कि गृह मंत्रालय की ही अपनी रपट है, कठघरे में आ खड़े हुए हैं। यह रपट दो वर्ष से पूर्व दे दी गई थी। फिर भी आज तक सरकार इस समिति की सिफारिशें लागू करने की दिशा में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। यह तथ्य कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह जरूरी समझा कि वह वोहरा समिति की रपट पर सरकार से स्पष्टीकरण माँगे, स्वयं में इस सरकार के विरुद्ध एक और अभियोग ही है।

और जैसे कि यह सब पर्याप्त नहीं था, स्वयंभू तांत्रिकों-पुजारियों की देश के सर्वोच्च व्यक्ति तक सीधी पहुँच के मामले भी अब दबाए जा रहे हैं। मैं इन समाचारों पर अपनी गंभीर चिंता प्रकट करना चाहूँगा कि मुंबई विस्फोट कांड के मुख्य भगोड़े दाऊद इब्राहिम पर अब भारत के विरुद्ध उस भीषण अपराध का आरोप भी नहीं लगाया जाएगा!

अपराध जगत् के आर्थिक ताने बाने पर काबू पाने के वित्तमंत्री के लंबे-चौड़े दावों के बावजूद यह आकलन किया गया है कि भारत की कुल मुद्रा-आपूर्ति का 50 प्रतिशत काला धन है। 'फॉर्च्यून' पत्रिका ने भारत और चीन को एशिया में सर्वाधिक भ्रष्ट अर्थतंत्र घोषित किया है और विदेशी कंपनियों को इस ढाँचे में काम करने के नुक्ते सुझाए हैं। अधिकांश पश्चिमी विश्लेषकों के लिए घूस का पैसा वह चिकनाई पैदा करता है, जिससे भारत में काम हो जाते हैं।

सरकारी कोष से चुनाव-व्यय

काफी पहले 1971 में लोकसभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर चुनाव सुधारों के बारे में सुझाव देने के उद्देश्य से एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। उसने अपने विषय पर अध्ययन के दौरान राजनीति में धनशक्ति की भूमिका पर विचार किया और सिद्धांततः यह स्वीकार किया कि राज्य को ही समस्त चुनावी खर्चों का दायित्व लेना चाहिए। उसने सिफारिश की थी कि आजकल जो चुनाव खर्च उम्मीदवार या पार्टी द्वारा वहन किए जा रहे हैं वे शनैः-शनैः राज्य को स्थानांतरित किए जाने चाहिए।

कुछ वर्ष बाद सरकार द्वारा काले धन की वृद्धि रोकने के साधन और मार्ग खोज निकालने के लिए न्यायमूर्ति वांचू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। वांचू समिति ने भी वैसी ही सिफारिश की तथा सरकार से आग्रह किया कि वह पश्चिमी जर्मनी के नमूने के अनुसार राजनीतिक पार्टियों को चुनाव-अनुदान दे।

मैं मानता हूँ कि अब इस मामले में और देरी नहीं करनी चाहिए। चुनाव खर्च के लिए सरकारी कोष की योजना तुरंत बनाकर क्रियान्वित करनी चाहिए। इसी के साथ चुनाव सुधार के बारे में दिनेश गोस्वामी की सिफारिशें भी बिना और विलंब किए लागू की जानी चाहिए।

आंतरिक सुरक्षा

भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और वोट बैंक राजनीति ने मिलकर भारत को एक निर्बंध राज्य बना दिया है जो देश की सुरक्षा, अखंडता तथा सामान्य व्यक्ति के जीवन की रक्षा का प्राथमिक दायित्व निभाने में भी असमर्थ है।

आम आदमी सुरक्षा-हीनता के बढ़ते जा रहे वातावरण में जी रहा है। कानून और व्यवस्था का तंत्र वस्तुतः ध्वस्त हो चुका है तथा देश की आधारशिलाओं को चुनौती दी जा रही है।

आई.एस.आई. ने देश के ओर-छोर तक अपना ताना-बाना फैला लिया है चाहे वह कश्मीर हो या तमिलनाडु, आई.एस.आई. विद्रोहात्मक गतिविधियों में संलग्न है।

दुर्भाग्यपूर्ण निरंतरता के साथ हो रहे विस्फोटों ने, चाहे जम्मू में गणतंत्र दिवस की परेड हो या वह जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह मारे गए, भारतीय एजेंसियों को सूत्रहीन और किंकर्तव्यविमूढ़ बना दिया है। गुप्तचर ब्यूरो कांग्रेस का शरारती दस्ता बना दिया गया है जो शासक दल के संकेतों पर उठ-बैठ कर रहा है। गृह मंत्रालय में मंत्री आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समान रणनीति पर ही फैसला नहीं ले पाते।

आतंकवादी एवं विध्वंसक अधिनियम (टाडा) का छद्म सेकुलरवादियों के

दबाव तथा कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति के हिस्से के तहत खत्म होने दिया गया। जब कि आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए यही अकेला निरोधक कानून था। उस पर तुर्रा यह है कि आतंकवाद तथा आंतरिक सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए कोई स्थानापन्न कानून बनाए बिना 'टाडा' खत्म होने दिया।

अधिकांश समस्याएँ कांग्रेस की देन

आंतरिक सुरक्षा से संबंधित देश की अधिकांश समस्याओं का मूल कांग्रेस पार्टी की क्षुद्र दलीय नीतियों में निहित है।

यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने कश्मीर को शेष देश से अलग रखा है, जो दशकों तक राज्य पर एक भ्रष्ट सामंती परिवार थोपे रखने की अपराधी है और जिसे उस राज्य में एक के बाद एक हुए चुनावों में घोटाले करने से भी कोई संकोच नहीं हुआ। 1953 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान न होता तो हम बहुत पहले ही हम यह जम्मू-कश्मीर खो चुके होते।

और यह भी हुआ कि पंजाब में अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अकालियों को नीचा दिखाने की इच्छा से ही नई दिल्ली ने भिंडरावाले को उभारा। पुनः तमिलनाडु में वोट बैंकों के लालच में ही श्री राजीव गांधी ने श्रीलंका से संबंध बिगाड़े।

उत्तर-पूर्वांचल गंभीर संकट में

पंडित नेहरू ने अपनी विरासत में हमें कश्मीर समस्या सौंपी। श्रीमती गांधी ने अपने पीछे पंजाब छोड़ा। राजीवजी ने समस्याओं का वह पुलिंदा दिया जिसे लिट्टे कहते हैं और अब प्रधानमंत्री राव कश्मीर समस्या और जटिल करने के अलावा उत्तर पूर्वांचल में अपना योगदान दे रहे हैं।

गत कुछ वर्षों में उत्तर-पूर्वांचल में जो हो रहा है वह अजीब और अविश्वसनीय भले ही प्रतीत हो, पर वह सच है और प्रधानमंत्री इसे जानते हैं।

उत्तर पूर्वांचल के एक राज्य के राज्यपाल ने लिखित रूप में नई दिल्ली को सूचित किया कि राज्य के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। लेकिन अपनी ही पार्टी का होने के कारण उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस राज्यपाल ने, जो एक उच्च स्तरीय सम्मान से अलंकृत पूर्व सैनिक अधिकारी थे, त्यागपत्र दे दिया।

गुप्तचर एजेंसियों ने एक और उत्तर पूर्वांचलीय राज्य के बारे में सूचित किया कि जब सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है तो उसी समय लगभग 10 प्रतिशत राशि काट कर आतंकवादियों को भेजी जाती है। एक अन्य राज्य में आतंकवादियों के लिए हथियार मुख्यमंत्री की कार में छुपाकर लाए गए।

यह सब सच में अभूतपूर्व है— सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा आतंकवाद का संरक्षण। एक ओर हम आतंकवाद से लड़ने के लिए सुरक्षा बलों पर धन खर्च करते हैं। धन से भी अधिक हम अपने नौजवानों की जान आतंकवाद से लड़ने के लिए जोखिम में डालते हैं। दूसरी ओर आतंकवादियों को सरकारी कोष से आर्थिक मदद देते हैं। सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी है। गुप्तचर एजेंसियों को भी इसका पता है। वे केंद्र को सूचित करते हैं। पर कुछ नहीं होता।

जब हम अपराधी–राजनीतिज्ञ गठजोड़ की बात करें तब सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश, मुंबई या गुजरात या दिल्ली के बारे में ही न सोचें। उत्तर पूर्वांचल में ज्यादा बड़ा खतरा है, राष्ट्रीय अखंडता को खतरा।

जम्मू–कश्मीर में दुर्दशा

राष्ट्रीय सुरक्षा बहु–आयामी चुनौती है। इसके कई अंग होते हैं। प्राथमिक आवश्यकता, राष्ट्रीय आकांक्षाओं और एक राष्ट्रीय इच्छा–शक्ति के निर्माण की होती है। यही वस्तुतः वे अनिवार्य तत्त्व हैं जिनका गत दशकों में कांग्रेस के कुशासन में क्षरण हुआ है। राष्ट्र में उसकी अपनी नियति को बोध पुनः प्रतिष्ठित करना और फिर से यह मान्य करना कि राष्ट्रवाद, संप्रभुता और महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के संरक्षण को हमारे आंतरिक एवं वैदेशिक दोनों मामलों के संचालन में प्रमुखता मिलती रहनी चाहिए, आवश्यक है।

हमें भारत के महत्त्वपूर्ण हितों की पहचान और परिभाषा करने में समर्थ होना चाहिए—अपनी राष्ट्रीय श्रेष्ठता और कल्याण के वे पहलू जिनके विरुद्ध किसी आघात या उनकी विरलता की हम अनुमति नहीं देंगे—चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैं इसपर इसलिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ही अवधारणा के अभाव ने गत वर्षों में हमारे राष्ट्रीय हितों को इस सीमा तक चोट पहुँचाई है कि हमारी सरकार अब दबाव के पहले झटके में ही उनसे समझौता कर लेती है।

वस्तुतः जम्मू–कश्मीर राज्य में भारत को मिल रही चुनौती का जिस भीरुता से भारत सरकार सामना कर रही है, वह देखकर देश स्तंभित है।

गत वर्ष संसद् के दोनों सदनों ने जम्मू–कश्मीर राज्य में आतंकवाद को जड़ से मिटाने तथा पाकिस्तानी कब्जे में स्थिर कश्मीर भी वापस लेने का राष्ट्र का संकल्प व्यक्त करते हुए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किए थे। लेकिन इस वर्ष प्रधानमंत्री ने इस रुख से एकदम पलटते हुए सबको स्तब्ध कर दिया जब उन्होंने संसद् में घोषित किया कि उनकी सरकार आतंकवादियों को 'आजादी से कुछ कम' सबकुछ देने को तैयार है। इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की 1953 से पूर्व की स्थिति बहाल करने संबंधी माँग पर गंभीर विचार किया जा रहा है।

1953 के पूर्व की स्थिति बहाल नहीं होगी

भाजपा न केवल एकता की प्रक्रिया विपरीत दिशा में मोड़ने की विरोधी है, बल्कि इस मत की है कि धारा 370, जो जम्मू-कश्मीर राज्य और शेष भारत के बीच एक बड़ी मानसिक और संवैधानिक दीवार है, खत्म कर देनी चाहिए।

भाजपा का आग्रह है कि राज्यों को और अधिकार दिए जाएँ—विशेषकर वित्तीय अधिकार। तुरंत हम यह भी मानते हैं कि इस समय केवल विशेषतः जम्मू-कश्मीर के पक्ष में अधिक सत्ता का हस्तांतरण विद्रोह को बढ़ावा देनेवाला सिद्ध होगा और इसलिए ऐसा कदम खतरनाक होगा। इससे पूरे देश में विखंडनवादी ताकतें फूट निकलेंगी।

कांग्रेस सरकार द्वारा कश्मीर मुद्दे पर दिखाए गए पूर्ण निकम्मेपन ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है। इसके अलावा जिस प्रकार सरकार इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण होने दे रही है, जो कि मूलतः एक आंतरिक मामला है उससे यह सरकार एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय गलती करने की आरोपी सिद्ध होती है। इस सरकार ने जम्मू-कश्मीर की जो दुर्दशा की है वह राष्ट्रीय सुरक्षा की दोनों प्रमुख भुजाओं—रक्षा तथा विदेश नीति पर उसकी असफलता प्रकट करती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

भले ही प्रधानमंत्री इसके विपरीत दावे करें, हम तीव्रता से इस दृष्टिकोण के हैं कि देश की रक्षा का प्रबंधन अंशकालिक काम नहीं है। 1993 से किसी पूर्णकालिक (स्वतंत्र) रक्षामंत्री का न होना देश को बहुत महँगा पड़ा है।

देश की सशस्त्र सेनाओं में जो गंभीर स्थिति विद्यमान है उसे उजागर करना मैं उचित समझता हूँ। उनकी कुल युद्धक-क्षमता में स्पष्ट गिरावट आई है। रक्षा के क्षेत्र में बजट के आवंटन में लगातार की जानेवाली कटौतियों के परिणामस्वरूप हमारी सशस्त्र सेनाओं के लड़ने के सामर्थ्य में कमी आई है। दो सेनाध्यक्षों ने, एक—नौसेना और दूसरे—थल सेना के, अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सार्वजनिक रूप से इस चिंता को व्यक्त किया है।

समय पर निर्णय लेने में असफलता और उसके बाद बजट का आवश्यक संबल देने और फिर शीघ्र क्रियान्वयन में असफलता के कारण हमारी सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताएँ जमा होती गई हैं। यह जरूर है कि धन का दबाव भी होता है। पर यही वह बिंदु है जहाँ नियोजन और नेतृत्व की भूमिका होती है और सरकार इसी बिंदु पर असफल हुई है। एक के बाद एक पंचवर्षीय रक्षा योजनाएँ सिर्फ कागजी कसरत बनकर रह गई हैं।

हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का वस्तुपरक विश्लेषण यह उद्घाटित करता है कि पाकिस्तान से किसी संभावित खतरे का सामना करने के लिए स्वयं को सैन्य

क्षेत्र में पर्याप्त सशक्त बनाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। व्यावहारिक तौर पर इसका अर्थ है कि हमें थल, नभ और नौशक्ति में पाकिस्तान की तुलना में बेहतर क्षमता हासिल करनी होगी।

धीरे-धीरे हिंद महासागर न केवल पश्चिमी बेड़ों के लिए, जो वहाँ अपनी स्थायी उपस्थिति बनाए रखते हैं, बल्कि चीन के लिए भी आकर्षक होता जा रहा है जिसने यहाँ स्थायी अड्डे हासिल करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमारी नौसेना को वह विस्तार और व्याप चाहिए जिससे वह न केवल नौ-सीमाओं की रक्षा कर सके बल्कि सागर-मार्ग निष्कंटक भी बनाए रखे।

भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास तथा परिष्कृत हथियारों के निर्माण हेतु औद्योगिक क्षमता पिछले दशक में प्राप्त बहुत क्षीण माँग के बावजूद काफी आगे बढ़ चुकी है। इस संदर्भ में इस्राइल के साथ और अधिक सहयोग बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।

विदेश नीति

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक पहचान योग्य विश्व-व्यवस्था खोजने को संघर्षरत है और जैसे विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच संबंध परिवर्तनशील बने हैं, भारतीय विदेश नीति विचार और नेतृत्वहीनता के तमाम दुष्प्रभाव प्रकट कर रही है। इस सरकार के नेतृत्व में भारत की वैश्विक साख राष्ट्रों के समुदाय में गिरती ही गई है।

विचार के अभाव में हमारी नीति में स्थिरता नहीं है। तदर्थवाद ने हमारे राष्ट्रीय हितों को बहुत क्षति पहुँचाई है। कश्मीर के अंतरराष्ट्रीयकरण का उल्लेख हो चुका है। भारत की अफगानिस्तान नीति में बिखराव एक दूसरा उदाहरण है। उस पड़ोसी देश में जो भी होता है, उसका भारत के राष्ट्रीय कुशल-क्षेम पर सीधा असर पड़ता है। हमें इस तथ्य के प्रति सजग होना चाहिए कि अफगानिस्तान और कश्मीर घाटी के घटनाक्रमों में एक संबंध है।

एक निष्फल विदेश यात्रा

निकट अतीत में हमारी विदेश नीति के लक्ष्यों पर दो तात्कालिक उद्देश्यों का वर्चस्व रहा है। पहला था पाकिस्तान को अमरीकी तथा अन्य पश्चिमी ताकतों जैसे फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा सैन्य आपूर्ति फिर से शुरू होने देना और दूसरा था संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए व्यापक समर्थन हासिल करना। प्रधानमंत्री की हाल ही में कोलंबिया और अमेरिका की यात्रा इन दोनों धुरियों पर ही प्रत्यक्षतः टिकी थी और यह भी उतना ही प्रत्यक्ष है कि हम दोनों ही उद्देश्यों में विफल रहे। एक कल्पनाशील व्यंग्य चित्रकार ने विदेश यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री को कस्टम अधिकारियों के सामने खाली सूटकेस

रखते हुए और दोनों हाथ ऊपर उठाकर यह कहते हुए दिखाया, 'बिलकुल कुछ भी घोषित करने के लिए नहीं है।'

वाशिंगटन ने तो घाव पर नमक ही छिड़का, जब उन्होंने ब्राउन संशोधन उस समय पारित किया जब कि प्रधानमंत्री राव अमेरिका में ही थे। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् में हमारी सदस्यता का प्रश्न है, एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष जिसने खुले तौर पर हमारा समर्थन किया राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ही थे। हमारे नेतृत्व और जनमत बनानेवालों ने गरिमा, सहिष्णुता और निर्णायक क्षमता की जगह चापलूसी भरी याचनाओं और मरमराते विरोधों को अपना लिया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विश्व रंगमंच पर हमारी प्रभावहीनता अतल तक पहुँच गई है।

चूँकि हमें अपने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, इस सरकार ने कुछ और भी अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते होने दिए हैं। मेरा संकेत हमारे आणविक तथा प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की ओर है।

भारत राष्ट्र को यह माँग करने का अधिकार है कि प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम बिना किसी कमी या विलंब के आगे बढ़ाया जाए। पश्चिमी क्षेत्र में 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती को भी क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

भारत को आणविक भेदभाव अस्वीकार

हम यह अवधारणा स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि जहाँ कुछ देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परमाणु परीक्षण जारी रखने का निर्देशन कर सकती है और वह भी परमाणु अप्रसार संधि के बावजूद, वहीं भारत की सुरक्षा आवश्यकताएँ ऐसी मानी जाएँ कि जिन्हें हमेशा महत्त्वहीनता की स्थिति में धकेला जाता रहे।

हम परमाणु अप्रसार संधि और हाल ही में किए गए उसके विस्तार तथा पुष्टि को एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था मानते हैं। हमारा विश्वास है कि एक समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि हो सकती है। किंतु आणविक भेदभाव के जरिए नहीं। हम उस अवधारणा को मान्य नहीं कर सकते जो किसी एक के राष्ट्रीय हितों के लिए एक व्यवहार करे और दूसरों के लिए उससे नितांत भिन्न पैमाना अपनाए।

जबकि भाजपा जन-विनाश के सभी हथियारों की संपूर्ण और वैश्विक समाप्ति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, जब तक वह समय आए कि ऐसी व्यवस्था संतोषजनक ढंग से लागू की जा सके, भारत को राष्ट्रहित में सभी प्रकार के निर्णय करने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए हम इस सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी संसद् के संप्रभुता-संपन्न मंच से ठीक इसी विचार को अभिव्यक्त करने में हमारे साथ आए।

जहाँ तक भाजपा का संबंध है, यह अपने इस दृष्टिकोण को दोहराना चाहेगी कि चीन और पाकिस्तान के परमाणु शक्ति-संपन्न होने की पृष्ठभूमि देखते हुए

राष्ट्रीय सुरक्षा की यह माँग है कि भारत भी अपना एक परमाणु-प्रतिरोधक विकसित करे।

संविधान पर एक और दृष्टि

इस वर्ष के प्रारंभ में अनेक प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमण और वर्तमान लोकसभाध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल भी थे, सार्वजनिक तौर पर भारतीय संविधान की आमूलाग्र पुनः रचना की माँग की। जहाँ कुछ राजनीतिक चिंतक लंबे समय से वर्तमान संसदीय प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रपति प्रणाली की शासन व्यवस्था के लिए समर्थन जुटाते रहे हैं, उक्त दो नेता संसदीय प्रणाली के भीतर ही मूलभूत परिवर्तन के पक्षधर प्रतीत हुए—ऐसे परिवर्तन जो मुख्य कार्यकारी को महज बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता से कहीं अधिक बड़ा बना देंगे।

मैंने यह देखा है कि हर कुछ वर्ष के अंतराल पर विधानसभा में मौलिक सुधारों के बारे में यह बहस एक निश्चित नियमितता के साथ उठती रहती है और जो सुझाव आते हैं, उनपर विशेष रूप से ऐसे समय में ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं जब जनता राजनीति और राजनेताओं को विशेषकर गिरा हुआ समझने लगे।

काश, यह महसूस किया जाता कि आज जिन समस्याओं का देश सामना कर रहा है वे व्यवस्था के कारण कम और उन लोगों की प्रकृति के कारण अधिक उपजी हैं जो व्यवस्था चला रहे हैं। मुझे स्मरण है कि संविधान सभा में संविधान को अंतिम तौर पर अपनाए जाते समय डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने जो कहा था। उन्होंने कहा था—

"अगर निर्वाचित लोग सक्षम हैं और चरित्रवान् तथा ईमानदार हैं तो वे एक दोषपूर्ण संविधान का भी सर्वोत्तम उपयोग कर पाएँगे। यदि उनमें इन गुणों का अभाव होगा तो संविधान देश की मदद नहीं कर सकेगा। आखिरकार संविधान एक यंत्र की भाँति निष्प्राण वस्तु है। वह उसे नियंत्रित और संचालित करनेवाले व्यक्तियों के कारण ही जीवंत होता है और भारत को आज ऐसे कुछ ईमानदार लोगों के अलावा और अधिक कुछ नहीं चाहिए जो देश का हित अपने सामने रखेंगे।"

फिर भी इस संविधान को प्रायः आधी शताब्दी तक चलाने के बाद संभवतः उस पर एक व्यवस्थित ढंग से पुनः एक दृष्टि डालना सार्थक रहेगा।

संविधान की व्यापक समीक्षा के लिए आयोग गठित हो।

मेरा सुझाव है कि संविधान पर एक आयोग का गठन किया जाए जो गत प्रायः 50 वर्षों में संविधान के काम की व्यापक समीक्षा करे और इसी सिलसिले में जाँचे कि—

1. क्या वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाओं में आमूलाग्र पुनः रचना की आवश्यकता है और यदि है तो किस दिशा में?
2. बहुमत पर आधारित जिस चुनाव प्रणाली को हमने स्वीकार किया है उसके राजनीतिक परिणाम क्या हुए और निर्वाचन की सूची प्रणाली या मिश्र प्रणाली अपनाने का भारत को एक वास्तविक सहभागी लोकतंत्र बनाने पर क्या असर होगा?
3. विकास और प्रशासन की आवश्यकताओं को प्रमुख विषय मानते हुए भारत का राजनीतिक मानचित्र पुनः अंकित करने की आवश्यकता; विभिन्न आंदोलनों के प्रति तदर्थ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने राज्य पर 5 लाख से लेकर 1 करोड़ की जनसंख्या तक के हैं। कुछ बड़े राज्य तो मुख्यतः अपने को न सँभाल पानेवाले बड़े आकार के कारण ही ठहराव के शिकार हो रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा ने दो बार एक पर्वतीय प्रदेश उत्तरांचल बनाने की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव पारित किए, लेकिन नई दिल्ली ने इस बारे में कुछ भी करने से इनकार कर दिया।
4. न्यायिक व्यवस्था की आमूलाग्र पुनः रचना की आवश्यकता, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री भगवती सहित अनेक प्रमुख न्यायविदों के अनुसार, 'ध्वस्त होने के कगार पर है।'

न्यायिक निर्णयों में होनेवाली असाधारण देरी के कारण आम आदमी की न्याय तंत्र में आस्था बुरी तरह हिल गई है। न्यायालय में मामला ले जाने में जो कीमत चुकानी पड़ती है वह आम आदमी के लिए बहुत भारी है।

न्यायिक सुधार

न्यायिक प्रक्रियाएँ जटिल और धीमी हैं। न्यायपालिका भी दोषपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया और अनाकर्षक सेवा शर्तों के कारण सर्वोत्तम विधि प्रतिभाएँ आकृष्ट नहीं कर पा रही हैं।

भाजपा एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की पक्षधर है, जिसे न्यायिक नियुक्तियों में निर्णायक एवं अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। आयोग को न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अभी आपराधिक शिकायतों से निबटने का भी अधिकार मिलना चाहिए। भाजपा न्यायिक प्रक्रिया के सरलीकरण तथा राष्ट्रव्यापी कानूनी सहायता कार्यक्रम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम आदमी को न्यायिक समाधान उपलब्ध कराएगा।

आर्थिक सुधार

देश के राजनीतिक स्वास्थ्य में गिरावट के साथ ही राष्ट्र की बिगड़ती जा रही आर्थिक स्थिति द्रष्टव्य है। तथाकथित सुधारों के पिछले चार वर्ष भारत की

विशाल बहुसंख्या के लिए त्रासदीपूर्ण रहे हैं। कीमतें ऊँची उठीं, गरीबी बढ़ी, रुपया गिरा और राष्ट्रीय ऋण अभूतपूर्व चरम तक पहुँचा है। यह जरूर है कि सरकार इसके विपरीत दावा करती है, लेकिन उसके अनोखे दावों और भयावह वास्तविकता के बीच की खाई सबके सामने स्पष्ट है। जनता अब झूठे दावों और विदेशियों द्वारा समय-समय पर छोटी-छोटी तारीफों से मूर्ख नहीं बनाई जा सकती। जहाँ कहीं और जब कभी उन्हें अवसर मिला है, लोगों ने खुलकर सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध मत दिए हैं।

जब सुधारों की घोषणा हुई थी, भाजपा ने उनका सावधानीपूर्वक स्वागत किया था, क्योंकि उसे कांग्रेस सरकार की साधारण-से-साधारण सुधार को भी बिगाड़ने की प्रसिद्ध क्षमता के बारे में अच्छी तरह पता था। स्वागत इसलिए भी किया था, क्योंकि वह चाहती थी कि सत्तारूढ़ पार्टी एक नया अध्याय शुरू करे तथा विनाशकारी नेहरू-महालनोबीस नमूने से दूर हटे जिसने देश को इस स्थिति तक पहुँचाया। यह भाजपा ही है जो लगातार लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, जिस पर भारी शीर्षवाला ढाँचा बनाया गया था, कूड़ेदान में फेंकने की माँग करती रही है।

यह सुधार करते समय कांग्रेस समाजवाद के नाम पर पिछली अर्द्ध शताब्दी में आर्थिक स्थिति की दुर्गति करने के बाद केवल समय के साथ चलने की ही कोशिश में थी। भाजपा के लिए अफसरशाही-रहित और अतिरेकी नियंत्रणों से मुक्त अर्थतंत्र निष्ठा की बात थी। जबकि कांग्रेस के लिए सुधार अनिवार्यतः भुगतान संतुलन के तीव्र संकट का प्रत्युत्तर मात्र थे।

लेकिन सरकार सीमित सुधारों में भी, जो उसने 1991 में धूम-धड़ाके से शुरू किए थे, विफल रही और वह भी बुरी तरह से विफल।

गलत प्राथमिकताएँ

उसकी प्राथमिकताएँ पूरी तरह से गलत हैं। प्रत्येक तीन भारतीयों में से दो गाँवो में रहते हैं और खेतों पर काम करते हैं। लेकिन सुधारों में किसानों के लिए कुछ नहीं है और अब कुछ समय से सरकार यह मानने को बाध्य हुई है कि किसान पूर्णतः उपेक्षित रह गए। 1980 और 1990 के बीच कृषि में वास्तविक निवेश आधा रह गया और इस रुख को पलटा जाना चाहिए था। पर न तो ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं, न ही लघु उद्योगों की हालत सुधरी है जो औद्योगिक रोजगार का बहुत बड़ा हिस्सा है। सुधार कार्यक्रम की यही मूलभूत असफलता है और यही कारण भी है कि वह आम आदमी को लाभान्वित करने में असफल रहा।

भारत में बेरोजगारी समस्या बढ़ानेवाली कोई भी आर्थिक रणनीति ठोस नहीं मानी जा सकती। यही कारण है कि भाजपा वैश्वीकरण में वर्तमान सरकार की ऊँची छलाँग की विरोधी है। गहरे सागर में मछलियाँ पकड़ने के लिए बहुराष्ट्रीय

कंपनियों को दिए गए लाइसेंस लाखों छोटे मछुआरों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए।

बढ़ती कीमतें

कीमतों और मुद्रास्फीति के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। आम आदमी ने पहले कभी भी महीने-दर-महीने, साल-दर-साल कीमतों में होती जा रही ऐसी कमरतोड़ वृद्धि का सामना नहीं किया था। आलू 12 रुपए किलो बिक रहे हैं, जो चार वर्ष की कीमतों में पाँच गुना ज्यादा हैं। दूध और सब्जियाँ मध्यम वर्ग के लिए भी विलास की वस्तुओं जैसी हो गई है। फिर भी सरकार, आम आदमी और उसके परिवार के सामने भोजन के समय टुकुर-टुकुर देखती खाली थालियों के बजाय विदेशी खाद्य पदार्थों जैसे भुने हुए चिकन और हैमबर्गरों के लिए ज्यादा चिंतित हैं।

अवमूल्यन के भीषण परिणाम

पिछले चार वर्षों में रुपए की कीमत में विनाशकारी गिरावट आई है। जून 1991 में डॉलर सिर्फ 21.05 रुपए का था, जो आज 35 रुपए से अधिक का है। इसका अर्थ है कि राव राज के प्रत्येक दिन में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 1 पैसा कम होती रही। रुपए के डूबने का देश के कर्ज पर जो भीषण असर होगा उसे भी महसूस करें। आज भारत पर 92 अरब डॉलर का विदेशी ऋण है। हमारा 92 करोड़ लोगों का देश है। अगर यह कर्ज बराबर बाँटा जाए तो हर स्त्री-पुरुष और बच्चा 100 डॉलर का कर्जदार हुआ। इसका अर्थ 1991 में 2100 रुपए था, लेकिन 1995 में यह हुआ 3500 रुपए।

सिर्फ अवमूल्यन के कारण (डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में प्रतिदिन एक पैसे की गिरावट), रुपए में भारत का विदेशी ऋण 92 करोड़ रुपए प्रति दिन की दर से बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि 1 भी डॉलर और उधार लिये बिना रुपयों में हमारा कर्ज 2700 करोड़ प्रति माह या 32,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है।

तो यह हाल है अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए का। अब हम देखें कि भारत के भीतर ही रुपए की क्या स्थिति रही है।

जून 1991 में जब राव ने शपथ ली थी, औद्योगिक कामगारों के लिए सूचकांक (आधार वर्ष 1982) 209 था। दूसरे शब्दों में, 1992 से तुलना करें तो रुपए की कीमत सिर्फ 48 पैसे थी। चार वर्ष बाद जुलाई 1995 में सूचकांक है 313, इस प्रकार 1982 से तुलना करने पर रुपए की कीमत सिर्फ 32 पैसे रह गई है।

चलिए इसे दूसरी तरह से रखते हैं। जून 1991 में आप कुछ आवश्यक वस्तुएँ 100 रुपए में खरीद सकते थे। अब वही वस्तुएँ उसी परिमाण में यदि आज आप

खरीदना चाहें तो आपको 150 रुपए देने होंगे। चार वर्ष और कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि देश के भीतर ही हुई है।

इसी के साथ विदेशी को भी देखें। चार वर्ष पूर्व उसे किसी वस्तु को खरीदने के लिए यदि 1 डॉलर देने पड़ते थे तो उसी वस्तु के लिए अब उसे सिर्फ 43 सेंट (1 डॉलर 100 सेंट) देने होंगे।

वर्तमान शासन में हमारे आर्थिक प्रबंधन का यही वास्तविक लेखा-जोखा है—अवमूल्यन का उदारीकरण, कर्ज का वैश्वीकरण। भारत के इतिहास में इस समृद्ध और महान् राष्ट्र में हम कभी इतने गहरे कर्ज में नहीं फँसे थे।

निरंतर बढ़ती असमानताएँ

गरीबी बढ़ी है, बढ़ रही है और आय में बढ़ रही असमानताओं के साथ तो वह और बढ़ेगी। नई नीतियों ने ऊपर की बारीक सतह के वर्ग को विशाल बहुसंख्या में रह रहे लोगों की कीमत पर खासकर जो गाँवों में हैं, जहाँ अधिकांश भारत बसता है और जिसे दरिद्र बनाया जा रहा है, अधिक समृद्ध होने में मदद दी है। इससे ऐसे सामाजिक तनाव पैदा हो रहे हैं जो जल्दी ही असहनीय हो सकते हैं।

भाजपा सदा से ही एक उदार अर्थतंत्र की समर्थक रही है। लेकिन वह आम आदमी के लिए लाभकारी होना चाहिए। भारत में विकास का कोई भी नमूना, और निश्चित रूप से बाहर से आयातित नमूना तो कतई नहीं, तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह गरीबों में सबसे गरीब और कमजोरों में सबसे कमजोर की आवश्यकताओं और हितों पर केंद्रित न हो। हम उदारीकरण पर पीछे नहीं लौटना चाहते, लेकिन हम उन क्षेत्रों और खंडों पर वरीयताएँ पुनः केंद्रित करना चाहते हैं जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं।

किसान और कामगार की देखभाल

कीमतें बढ़ने के बजाय घटनी चाहिए, राष्ट्रीय कर्ज चढ़ते रहने के बजाय नीचे आए और रोजगार के अधिक अवसर मिलें। इसके लिए कृषि और लघु उद्योग क्षेत्र में अधिक पूँजी निवेश होना चाहिए, क्योंकि किसान और कामगार भारतीय समाज की रीढ़ हैं। हमें नीचे से निर्माण का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यही एकमात्र वह मार्ग है जिससे हम विकास का स्थायी भवन निर्मित कर सकेंगे और जिसके फलों में सबका हिस्सा होगा।

सुधारों को उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर चलाया जा रहा है। हम वैश्वीकरण के विरोधी नहीं हैं। हम इस विशाल व्यापक विश्व में भारत को अलग-थलग नहीं रखना चाहते, यद्यपि भारत स्वयं इतना बड़ा है कि उसे अलग-थलग किया नहीं जा सकता। लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि भारत

पर बाहरी ताकतें—आर्थिक या अन्य छा जाएँ। वैश्वीकरण भारत को शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाने और साथ-साथ इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र के नाते उसकी स्थिति बनाए रखने में सहायक हो। अन्यथा वह प्रतिकूल परिणाम देनेवाला होगा।

चार वर्षों में विदेशी ऋण दुगुना

वैश्वीकरण एकतरफा मामला नहीं होना चाहिए। अभी तक जहाँ इसने समृद्ध देशों के लिए आकर्षक बाजारों के द्वार खोले हैं, वहीं उससे भारत सहित गरीब देशों में मुद्रास्फीति और भारी कर्ज भी बढ़ा है। भारत अब एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया में तीसरा बड़ा कर्जदार देश है, हालाँकि वह सबसे गरीब देशों में भी गिना जा रहा है। पिछले चार वर्षों में भारत का विदेशी ऋण प्रायः दुगुना हो गया है-जो कि एकतरफा सुधारों का एक सीधा और विकृत परिणाम ही है।

आर्थिक राष्ट्रवाद का कोई विकल्प नहीं

ऋण एक विश्वव्यापी समस्या है। तीसरे विश्व का बढ़ता जा रहा ऋण एक अंतरराष्ट्रीय व्याधि है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रहार होना चाहिए। भाजपा धनी और गरीब देशों और विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का आह्वान करती है कि वे एक साथ मिल-बैठकर सोचें और इससे पहले कि ऋण-संकट उनके दुर्बल अर्थतंत्रों को घेरकर दबा दे, इसका समाधान ढूँढ़ निकालें।

और यहीं स्वदेशी या आर्थिक राष्ट्रवाद की भूमिका आती है। भाजपा ने राष्ट्रीय विकास नीतियों के संदर्भ में दो प्रमुख पहलुओं पर हमेशा जोर दिया है—स्वराज और स्वदेशी। वे अवधारणाएँ जिनकी जड़ें राजनीतिक और आर्थिक राष्ट्रवाद में हैं। वे परस्पर जुड़ी हुई हैं। यदि स्वराज का अर्थ है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन तो स्वदेशी है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए अर्थतंत्र। भारत जैसे देश में स्वदेशी का कोई विकल्प नहीं है।

आर्थिक राष्ट्रवाद का अर्थ है—भारत की आर्थिक नियति भारतीयों द्वारा तय की जाएगी, विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विदेशी पूँजी निवेशकों द्वारा नहीं, यद्यपि अर्थतंत्र के निर्माण में उनके सहयोग का स्वागत है। भारत उनसे समान शर्तों पर व्यवहार करेगा—ऐसी शर्तें जो परस्पर लाभकारी हों।

चूँकि हमें महसूस हुआ कि शर्तें परस्पर लाभकारी नहीं, एनरॉन करार रद्द करना पड़ा। भारत और भारतीय आक्रांत नहीं किए जा सकते। यदि एक बार हम खुद को आक्रांत हो जाने देंगे तो हमेश आघात सहते रहेंगे और न केवल अपनी आर्थिक संप्रभुता बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता भी खो बैठेंगे।

आइए, कमजोर वर्ग की सहायता करें

भाजपा इस देश पर कांग्रेस द्वारा थोपे गए लाइसेंस-परमिट-कोटा राज की तीव्र आलोचक रही है। लेकिन हम इस सीधे-सादे विचार से भी सहमत नहीं हैं कि भारत गरीब और पिछड़ा सिर्फ इसलिए रहा, क्योंकि यहाँ बाजार के उप्रेरक तत्त्व नहीं थे।

काश, भारत की प्रगति के बारे में यह बहस सरकारी नियंत्रण बनाम बाजार-उप्रेरक की राजनीति की परिधि से आगे जाए। हमारी सबसे महत्त्वपूर्ण असफलताएँ तो वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मोरचों पर हुई हैं। यही वे असफलताएँ हैं जो विकासशील देशों में भारत को सबसे वंचित राष्ट्र बनाए रखने का मुख्य कारण है।

आर्थिक विकास पर सबसे संकीर्ण अर्थ के अनुरूप अत्यधिक जोर ने उनकी कल्पनाओं को धुँधला दिया है जिन पर भारत को अगली शताब्दी में ले जाने का दायित्व है। हमें अपना मार्ग नए सिरे से तय करने की आवश्यकता है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सामाजिक, सांस्कृतिक, मर्यादा संबंधी और राष्ट्रीय पहलू नजरअंदाज न ही हों, हमें मर्यादा और नैतिकता की पुनःप्रतिष्ठा को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की आधारशिला बनाने की आवश्यकता है।

द्विमुखी प्रयास

हमारे प्रयास दोतरफा होने चाहिए—राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ करना और सामाजिक विकास के लक्ष्य पूरे करना। भाजपा सचेत रूप से इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रही है।

कमजोर वर्गों का कल्याण

1988 में आगरा में भाजपा ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक समग्र और भली प्रकार निर्मित घोषणा-पत्र बनाया था। हमारे विरोधियों ने भी उसको साहसिक किंतु यथार्थवादी दस्तावेज के रूप में मान्य किया। दो वर्ष बंगलौर में हमने सामाजिक घोषणा-पत्र अंगीकार किया जिसने सामाजिक दृष्टि से सभी कमजोर वर्गों के लिए पार्टी की दृष्टि को स्पष्ट किया। जनता को उन दोनों दस्तावेजों के बारे में जानकारी देने और उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

महिला आरक्षण

गत वर्ष वडोदरा में भाजपा ने माँग की थी कि जिस प्रकार स्थानीय निकायों के मामले में किया गया, उसी प्रकार राज्य विधानसभाओं और संसद् में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार किया जाना चाहिए।

मैं भाजपा की राज्य सरकारों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वे शिशु

कन्याओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में शैशव अवस्था से वयस्क होने तक बड़ी मात्रा में पूँजी निवेश करें। वे एक ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को बढ़ावा दें, जो किसी भी रूप में शिशु कन्या के विरुद्ध भेदभाव खत्म करने के लिए बना हो और जन्म पूर्व लिंग-परीक्षण तथा कन्या भ्रूण हत्याओं की अनैतिकता में लिप्त लोगों को कठोर सजा दें।

राजनीति—पावन उद्देश्य या व्यापार

भारत में 1947 से पहले राजनीति में सहभाग का अर्थ था स्वतंत्रता के महान् राष्ट्रीय संघर्ष में सहभाग लेना। वह महान् बलिदानों का आह्वान करनेवाला एक पावन उद्देश्य था। वह असाधारण क्षमता और अप्रतिम भावनाओं और बुद्धि से युक्त व्यक्तियों को आकृष्ट करती थी। लोकमान्य तिलक, सावरकर और गांधी जैसे नेता किसी भी देश के गौरव कहे जा सकते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीति किसी भी दूसरे व्यवसाय की तरह ही है। जैसे कि अन्य व्यवसायों में होता है, जैसे चिकित्सा और कानून, बौद्धिक क्षमता के अलावा व्यावसायिक ईमानदारी के गुण का भी बहुत बड़ा मूल्य माना जाता है।

दुर्भाग्य से भारत में राजनीति बुरी तरह गिर चुकी है। आजादी से पूर्व राजनीति को जिस प्रकार पावन उद्देश्य माना जाता था उसका पाखंड तो जारी है, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में राजनीति विशुद्ध व्यापार के रूप में पतित हो चुकी है। ईमानदारी, राजनीतिक या वित्तीय, अब कोई फलदायक प्रतीत नहीं होती।

भाजपा को विशिष्ट स्थान प्राप्त

हाल ही के वर्षों में भाजपा के विकास का श्रेय दो पहलुओं को है— प्रथम भाजपा की प्रखर राष्ट्रीय विचारधारा और दूसरी, वह बहु व्याप्त विश्वास कि यह पार्टी मूल्यों में कांग्रेस और कांग्रेस से निकली दूसरी पार्टियों से भिन्न है।

पिछले कुछ समय से गुजरात की घटनाओं ने अनेक को विषादग्रस्त किया है। निस्संदेह यह संतोष की बात है कि वहाँ हमारी सरकार अपने सामने आए संकट को पार कर पाई। लेकिन इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह तथ्य है कि हमारे कटुतम आलोचकों ने भी सामान्यतः अपनी टिप्पणी इस प्रश्न के साथ समाप्त की—क्या भाजपा कांग्रेस के मार्ग पर जा रही है?

भाजपा से आशाएँ

यह प्रश्न एक साथ दो बातें प्रकट करता है— पहली कि कांग्रेस पतनोन्मुख है और इसलिए जनता को उससे कोई आशाएँ नहीं हैं और दूसरी जनता भाजपा को एक अलग किस्म की पार्टी मानती है और उससे भारी आशाएँ रखती है। ऐसे

कैसे हो सकता है, आलोचकों ने पूछा कि भाजपा भी कांग्रेस के पतन जैसे चिह्न दिखाने लग गई?

जब 1993 में दिल्ली विधानसभा के लिए भाजपा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा रहे थे, पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के सामने कुछ अशोभनीय घटनाएँ हुईं। पहले कभी ऐसी घटनाओं का सामना न करने के कारण हममें से अधिकांश इन घटनाओं से काफी अधिक विचलित हो गए थे, जिनके समाचार-पत्रों में व्यापक समाचार छपे। फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि मतदाताओं ने इन घटनाओं को एक अपवाद ही माना और उनकी उपेक्षा कर दिल्ली के चुनावों में भाजपा को भारी विजय दिलाई।

मुझे कोई संदेह नहीं कि गुजरात की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का आगामी लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। परंतु आंतरिक तौर पर हमें इन मामलों पर विचार करना ही होगा। हमारा उद्देश्य केवल चुनाव जीतने में सफल होना ही नहीं है। हमारा लक्ष्य राजनीति में उस पावन उद्देश्य तथा आदर्शवाद के बोध को प्रतिष्ठापित करना है जो स्वतंत्रता संघर्ष में उसके साथ रहा था।

नवोदित भारत की हमारी कल्पना

जैसे-जैसे 20वीं शताब्दी का सूर्यास्त हो रहा है और हम एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने उदय की 50वीं जयंती की ओर बढ़ रहे हैं, एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत, ऐसे लोकतंत्र, जिसकी राजनीति का मूल धर्म में निहित हो जिसने स्वातंत्र्य-संघर्ष के दौरान करोड़ों लोगों के भाव-जगत् को धधका दिया था की कल्पना मात्र एक सुदूरस्थ मृग-मरीचिका बन गई है।

नैतिकता और मर्यादा का सार्वजनिक जीवन से लोप हो गया है तथा हमारे नेता अब राष्ट्र-चेता के रक्षक नहीं रह गए हैं। सरकार की मुक्त बाजार की नीतियों के फलस्वरूप एक वर्ग के लोगों के लिए तुरंत उपजी किंतु अल्पकालिक समृद्धि हमारे समाज को विवेकहीन उपभोक्तावाद की ओर ले जा रही है, जिसने हमारी सामाजिक अस्मिता की आधार-शिलाओं को कुरेदना शुरू कर दिया है। विकास और सामाजिक नीतियाँ बाजार से निर्देशित हो रही हैं और बाजार के संप्रदाय ने धर्म के सिद्धांतों की जगह ले ली है।

हमारे सम्मुख महान् कार्य

भाजपा यह देखने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है कि अगली शताब्दी, जो अब सिर्फ पाँच वर्ष दूर है—भारत की शताब्दी बने। यह भारत की नियति है कि वह 21वीं शताब्दी में सामर्थ्यवान् राष्ट्रवादी शक्तियों के नेतृत्व में प्रवेश करेगा, जो इस शत-कोटि नागरिकों के महान् राष्ट्र में हर स्तर पर उभर रही हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक कार्य है कि वह ऐसी घड़ी में इन शक्तियों के

केंद्र-बिंदु के रूप में उठ खड़ी हो और सौम्यता से भारत को उसकी प्रतीक्षारत गौरवशाली नियति की ओर ले चले।

यह काम आसान नहीं होगा। कोई देश महान् नहीं हो सकता, यदि उसके लोग गरीब रहें। इसलिए हमारे सामने—भाजपा के सामने और राष्ट्र के सामने—सबसे पहला काम है सदियों से हमारे करोड़ों देशवासियों के जीवन को तमसावृत्त करनेवाली गरीबी के अभिशाप को समाप्त करना। आनेवाले वर्षों में यह भाजपा का सर्वप्रमुख उद्‌देश्य रहने वाला है।

इसके लिए हम इस संपूर्ण व्यापक विश्व के साथ धनी देशों और गरीब देशों, बड़े देशों और छोटे देशों, उन देशों के साथ जो पूँजी या तकनालॉजी दे सकते हैं और उन देशों के साथ जो कच्चे माल और तैयार उत्पादनों से व्यापार कर सकते हैं, सहयोग के लिए तैयार है। लेकिन 99 प्रतिशत ध्यान इस ओर लगाना होगा कि देश के भीतर क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए, क्योंकि केवल भारतीय ही भारत का निर्माण कर सकते हैं, बाहरी लोग नहीं।

यह हमें पुकार रही एक नई शताब्दी की देहरी पर नवोदित हो रहे भारत की कल्पना, है एक ऐसी कल्पना जो भारत और भाजपा को उस नियति के बंधन में बाँधती है जो पावन निष्ठा भी है और एक पवित्र संकल्प भी।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली

23-24 दिसंबर, 1995

मैं पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

दो दिन की इस बैठक में पार्टी के संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति और अनुशासन काररवाई समिति के गठन के बारे में कुछ संवैधानिक दायित्व पूरे किए जाने हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी को आगामी लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के बारे में पार्टी की योजनाओं और राजनीति की व्यापक रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श करना है। यहाँ बैठक में उपस्थित विभिन्न राज्यों के पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और विधान दल के नेता हमारी इस चर्चा और निर्णयों के लिए मूल्यवान् विचार दे सकेंगे।

दूरसंचार सौदे

संसद् के शीतकालीन अधिवेशन में लगभग तीन सप्ताह तक गतिरोध बना रहा, क्योंकि सरकार दूरसंचार सौदों के बारे में संसदीय समिति द्वारा छानबीन करने की विरोधी पक्ष की माँग को स्वीकार न करने पर अड़ी रही।

जिस ढंग से संचार मंत्री ने दूरसंचार की बुनियादी सेवाओं के टेंडरों पर काररवाई की, उससे एक फर्म विशेष को बहुत लाभ हुआ तथा सरकारी खजाने को बहुत भारी नुकसान पहुँचा।

प्रथम दृष्टया यह एक अनावश्यक और अवांछित पक्षपात का स्पष्ट मामला है।

इस सरकार के कार्यकाल की एक विशेष बात यह है कि इसकी शुरुआत सोलंकी घोटाले से (डेवास से बोफोर्स पर परदा डालने के प्रयास) हुई और सुखराम घोटाले के साथ अंत हो रहा है।

चुनाव कराने का समय

राव सरकार के पाँच वर्ष का समय जुलाई 1995 में समाप्त होगा। कुछ समय

पूर्व निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी कि 1996 में होनेवाले लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव कब कराए जाएँ।

भाजपा ने फरवरी-मार्च 1996 में चुनाव कराने के पक्ष में सम्मति दी थी। अधिकांशतः अन्य विरोधी दलों ने भी ऐसी माँग की थी। किंतु कांग्रेस पार्टी का मत था कि ये चुनाव अप्रैल में कराए जाएँ।

मैं सरकार तथा निर्वाचन आयोग से आग्रह करूँगा कि वे आपस में परामर्श कर इस बारे में शीघ्र घोषणा करें। वर्तमान अनिश्चितता अविलंब दूर होनी चाहिए।

मुझे मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी दयनीय हालत को अच्छी तरह जानती है, इसलिए सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन और 6 महीने बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। भाजपा ऐसे किसी भी विचार का तीव्र विरोध करती है। ऐसा करने का कोई भी औचित्य नहीं है।

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और हरियाणा राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ कराने की घोषणा कर बहुत ठीक किया है। उत्तर प्रदेश को इन राज्यों की सूची में इसलिए शामिल नहीं किया गया, क्योंकि स्पष्ट ही उस समय जब उक्त घोषणा की गई, तब तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद् ने स्वीकृति नहीं दी थी। अनुच्छेद 356 (4) के अनुसार उक्त घोषणा का कार्यान्वयन 17 अप्रैल, 1996 को समाप्त हो जाएगा। निर्वाचन आयोग को उत्तर प्रदेश में भी साथ-साथ चुनाव कराने की घोषणा कर देनी चाहिए।

चुनाव के नतीजों पर पूर्व चुनाव वर्ष की घटनाओं का प्रभाव भी निश्चित पड़ता है। इस दृष्टि से तीन राज्यों के चुनावों और न्यायालयों के तीन निर्णयों के कारण 1995 का वर्ष भाजपा के लिए बड़ा शुभ वर्ष रहा है।

गुजरात और महाराष्ट्र में विजय

वर्ष का आरंभ देश में चार प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनावों से हुआ। भाजपा ने गुजरात और महाराष्ट्र में शानदार विजय हासिल की, बिहार में मुख्य विरोधी दल बनकर तथा उड़ीसा में अपनी तीन गुना शक्ति बढ़ाकर भी उसने बड़ी छलाँग लगाई।

वर्ष के मध्य में गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। पार्टी का प्रदर्शन वस्तुतः अभूतपूर्व रहा।

वर्ष की अंतिम तिमाही में उत्तर प्रदेश में स्थानीय चुनावों के रूप में तीसरी बार चुनावी शक्ति परीक्षण का मौका आया। इसमें कांग्रेस लगभग समाप्त हो गई है।

न्यायालयों के निर्णय

मैं यहाँ न्यायालयों के तीन निर्णयों का उल्लेख करूँगा जो हमारे दृष्टिकोण से एक प्रकार से वरदान रहे हैं। पहला, ट्रिब्युनल का निर्णय आया, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार का विश्व हिंदू परिषद् पर प्रतिबंध लगाना अवैध और शून्यकृत था तथा यह निहित स्वार्थ से प्रेरित था।

इसके तुरंत बाद उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया जिसमें सरकार की सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को न निभाने पर सरकार की भर्त्सना हुई। और अब वर्ष समाप्त होते-होते उच्चतम न्यायालय का 'हिंदुत्व' के बारे में निर्णय आया। इस निर्णय से भारत में राष्ट्रवाद के पीछे अनिवार्यतः सांस्कृतिक अवधारणा के हमारे वैचारिक दृष्टिकोण को पूरी तरह पुष्ट किया गया।

उक्त तीन चुनावी नतीजों और न्यायालयों के निर्णयों से अगले वर्ष होनेवाले लोकसभा चुनावों में भाजपा की स्थिति पर्याप्त रूप से मजबूत हुई है।

कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता को क्षति

तदनुरूप, 1995 में इन तीन घटनाओं ने लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता को अत्यंत क्षति पहुँचाई है।

ये तीन घटनाएँ अपने आप में तीन बुराइयाँ हैं, अर्थात् भ्रष्टाचारी, अपराधीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा करने में अक्षमता; सत्ताधारी पार्टी पर ये तीनों बुराइयाँ हावी है।

दूरसंचार घोटाले से भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से उभरकर आया; बीभत्स तंदूर कांड अपराधीकरण का उदाहरण था, और जिस प्रकार से इस विशाल देश पर विदेशी विमान ने उड़ान भरकर हमारे देश में विद्रोही गतिविधियों के लिए रॉकेट लांचर और अन्य परिष्कृत हथियारों को गिराया, वह अत्यंत क्षोभजनक है, जिससे पता चलता है कि देश की सुरक्षा इस सरकार के हाथों में सुरक्षित नहीं है।

उस समय भी जब भाजपा भारतीय राजनीति में कुछ कम महत्त्व और हाशिए की पार्टी थी तब भी वह अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अपनी वैचारिक अवधारणा के कारण लगातार आलोचना का मुख्य बिंदु बनी रहती थी।

भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार

परंतु जब से हम केंद्र बिंदु बन गए हैं और कांग्रेस पार्टी को प्रमुख रूप से चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं, तब से पार्टी के रूप में भाजपा के विरुद्ध तथा अवधारणा के रूप में हिंदुत्व के विरुद्ध इस आलोचना ने मिथ्या अभियान का रूप ले लिया है। हिंदुत्व को मजहबी कट्टरवाद कह कर अपदृष्टि से देखा जाता रहा है। कुछ हलकों में हिंदू को बुरा कहना एक फैशन बन गया है। मुझे आशा है कि पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय से मिथ्या

और निंदात्मक प्रचार समाप्त हो जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ के अपने पहले निर्णयों से व्यापक रूप से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और टिप्पणी की है कि हिंदुवाद या हिंदुत्व को 'केवल धर्म की संकीर्ण सीमाओं' तक 'सीमित करना' गलत है। इस निर्णय में आगे कहा है कि "···· उपमहाद्वीप में 'हिंदुत्व' शब्द का लोगों की जीवन शैली से अधिक संबंध है। यह समझना मुश्किल है कि इन निर्णयों को देखते हुए किस प्रकार सार रूप में 'हिंदुत्व' या 'हिंदूवाद' के अर्थ को संकीर्ण कट्टर हिंदू धार्मिक धर्मान्धता के रूप में और इसके समरूप ग्रहण किया जा सकता है।"

लगभग अपमानजनक स्थिति तक किए जा रहे निराधार दुष्प्रचार के अलावा हमारे विरोधी एक प्रमुख गलती करने के दोषी हैं। उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण तथ्य को नहीं पहचाना है कि भाजपा मात्र एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह भारत के पुनरुज्जीवन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन अंतरंग भाग है। भाजपा की परिकल्पना केवल शासन कला तक सीमित नहीं है; इसमें संपूर्ण नागरिक समाज समाहित है।

इतना समझ लिया जाय कि जब हम हिंदुत्व या भारतीयता की बात करते हैं तो हमारा मतलब केवल राजनीति से नहीं होता है। हमारा केंद्र बिंदु एक ऐसे भारत के निर्माण से होता है, जहाँ वर्तमान, भूत और भविष्य में शांति रहे; एक ऐसा भारत जो अपने भविष्य के प्रति सजग है; और एक ऐसा भारत जिसके नागरिक कहीं भी विश्व में गौरव से सिर ऊँचा कर जा सकें।

ऐसे मिशन के समक्ष राजनीति इसका एक छोटा सा भाग मात्र है। परंतु यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग है। आज विश्व में भारत को महत्त्वहीन मान लिया जाता है और मान लिया जाता है कि उससे जो कुछ कहा जाएगा, वह करेगा, इसका कारण यह है कि हमारा राजनीतिक चेहरा विकृत और विद्रूप हो गया है।

भारत का पुनरुत्थान : भाजपा की योजना

भाजपा का लक्ष्य इस राजनीतिक चेहरे को बदल देना है और सार्वजनिक जीवन में फिर से सम्मान और गौरव को प्रतिस्थापित करना है। यह कार्य सरल नहीं है और हमें कभी-कभी झटके लग सकते हैं। परंतु भारत का पुनरुत्थान कभी भी ऐसी सरकार के रहते नहीं हो सकता, जिसकी दोष-दृष्टि ही राष्ट्रीय दर्शन का रूप बन जाए।

यदि हमने अपने नैतिक आधार, अपनी विरासत और अपने धर्म को छोड़ दिया तो दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और बहुराष्ट्रिकों के प्रयास भी भारत को 'सर्वोन्नत देश' नहीं बना सकते।

हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो भारत की सृजनशील भावनाओं के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हटा देगी और जिसमें इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा करने का संकल्प होगा जिससे भौतिक तथा नैतिक सभी क्षेत्रों में भारत

शक्तिशाली बन सके।

हमारे विरोधियों में इसी संकल्पना की कमी है। वे सत्ता की आराधना करते रहें, परंतु हमें भारत को देवत्व की स्थिति तक ले जाना है।

जैसे-जैसे आम चुनाव निकट आ रहे हैं, हमारे लिए महत्त्वपूर्ण है कि भाजपा की इस विशिष्ट छवि को लोगों के सामने रखा जाय। हमें अपने विरोधियों के निम्न स्तर तक पहुँचना है। हमें अपने राजनीतिक संभाषण को राजनीति से भी कहीं आगे ले जाना है। अच्छा होगा कि लोग उनके चुनाव घोषणा-पत्र और हमारी परिदृष्टि के बीच अंतर कर सकें।

स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद यह चुनाव वास्तव में एक अलग ढंग का होगा। आइए, हम इस प्रश्न से कहीं ऊपर उठ जाएँ कि आपको किस प्रकार की सरकार चाहिए? आइए, लोगों के सामने भाजपा का यह प्रश्न हो कि आपको किस प्रकार का भारत चाहिए?

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

हैदराबाद

20-22 मार्च, 1994

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अप्रैल 1980 में हुई थी। पार्टी की स्थापना के प्रथम वर्ष में ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सत्र अक्तूबर 1980 में हैदराबाद में हुआ था। आज चौदह वर्ष बाद फिर यहाँ मिल रहे हैं। इस अवधि में पार्टी का अभूतपूर्व विकास हुआ है और हमने अपने आप को निश्चित और अविवादरूपेण कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्थापित कर लिया है।

भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ-साथ सभी अन्य राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, जनता दल और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों की शक्ति का ह्रास भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगत है।

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का लोप हो गया है तथा जनता दल, जो तीन वर्ष पहले केंद्र में तथा छह से अधिक राज्यों में सत्तारूढ़ था, आज वह विखंडन की कष्टप्रद प्रक्रिया से गुजर रहा है।

विश्व भर में साम्यवाद की समाप्ति से दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ दिशाहीन होकर रह गई हैं। पार्टी में लोगों का शामिल होना पूरी तरह बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य में जाति समर्थक सत्तारूढ़ संगठन के साथ मिल रहे हैं। ऐसा लगता है, वामपंथियों के लिए भाजपा का विरोध ही उनके अस्तित्व के लिए एक मात्र सहारा रह गया है।

भारतीय जनता पार्टी के उसके अपने अद्वितीय विकास से भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि उसने देश में राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा में गुणात्मक परिवर्तन का सूत्रपात किया है।

भाजपा द्वारा वैचारिक आयाम स्थापित

भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुकाबले और राजनीतिक खंडन-मंडन में वैचारिक आयाम स्थापित करने में सफल रही है। यह एक तरह से उस बहस की

फिर से शुरुआत है जिसमें कभी स्वतंत्रता के आरंभिक दिनों में कांग्रेस फँसी हुई थी और यह बहस राष्ट्रीय एकता से संबंधित समस्याओं के बारे में पंडित नेहरू और सरकार पटेल के दृष्टिकोण पर चलती रही।

वास्तव में यदि हैदराबाद राज्य के बारे में पंडित नेहरू का दृष्टिकोण सरदार के दृष्टिकोण पर हावी हो जाता है, जैसा कि जम्मू और कश्मीर के मामले में हुआ, तो शायद आज हैदराबाद की समस्या भी बिना समाधान के पड़ी रहती।

भारतीय स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्षों तक भारतीय राजनीति में केवल एक पार्टी—कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। सभी चुनावों में मुकाबला कांग्रेस कैंप और गैर-कांग्रेसी कैंप के बीच होता था। दूसरे शब्दों में, चुनावों में शक्ति-द्वंद्व उनके बीच होता था, एक वह जिनके पास राजनीतिक सत्ता है और दूसरे वे जिनके पास यह नहीं है। इस टकराव में वैचारिक पक्ष का महत्त्व नहीं था।

हिंदुत्व की अवधारणा

अयोध्या आंदोलन ने इस पूरी स्थिति को बदल दिया। इस आंदोलन ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है कि भारतीय राष्ट्रवाद क्या है तथा भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जिस रूप में पंथनिरपेक्षता (सेक्यूलरिज्म) की परिकल्पना की थी, उसके सही अर्थ क्या हैं।

भारतीय जनता पार्टी का विचार है कि भारत एक देश है और सभी भारतीय एक जन हैं, परंतु उसका यह विश्वास है कि भारत के एकत्व का आधार उसकी युगों पुरानी संस्कृति में निहित है।

हमारे इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का सहज स्वरूप हिंदुत्व बन गया है। हिंदुत्व हमारे लिए मात्र नारा नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मूलमंत्र है जिसमें उसकी पहचान और दृष्टि अत्यंत विशिष्ट रूप से प्रकट होती है। अयोध्या से बहुत पहले पार्टी का यही प्रमाण चिह्न था और अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के वास्तविक निर्माण के बाद भी बना रहेगा।

भारतीय जनता पार्टी का यह भी विश्वास है कि भारतीय पंथनिरपेक्षता हिंदुत्व की जड़ों में ही समाई हुई है। भारत सरकार सेक्यूलर है, क्योंकि अनिवार्य रूप से वह हिंदू है। हिंदू परंपरा और इतिहास में धर्मतंत्र का स्थान नहीं है।

सांस्कृतिक एकता

भारतीय राष्ट्रवाद का आधार हमारी युगों पुरानी संस्कृति है—इस बात को न्यायालयों ने अनेक निर्णयों में स्वीकार किया गया है।

प्रदीप जैन बनाम भारत संघ (1984) मामले में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस अमरेंद्रनाथ

सेन तथा जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने कहा था—

"यह इतिहास का रोचक तथ्य है कि भारत का राष्ट्र के रूप में अस्तित्व बनाए रखने का कारण एक समान भाषा या इस क्षेत्र में एक ही राजनीतिक शासन का जारी रहना नहीं है बल्कि सदियों पुरानी चली आ रही एक समान संस्कृति है। यह सांस्कृतिक एकता है, जो किसी भी बंधन से अधिक मूलभूत और टिकाऊ है, जो किसी देश के लोगों को एकजुट रखने में सक्षम है और जिसने इस देश को एक राष्ट्र के सूत्र में बाँध रखा है।"

हाल के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी 'हिंदुत्व की पराजय' के बारे में बहुत खुश होकर चर्चा करते हैं। निस्संदेह इन चुनावों के परिणाम हमारे समर्थकों या वस्तुतः हमारे विरोधियों को जितना भय था उनकी आशा के अनुकूल नहीं रहे। परंतु इन परिणामों से हमारी विचारधारा को कोई धक्का नहीं लगा है।

हिंदुत्व के प्रति बढ़ती आस्था

इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थन आधार का पर्याप्त विस्तार किया है। हमें कांग्रेस से एक करोड़ से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वैचारिक संघर्ष सबसे अधिक गहन था, वहाँ हमें 1991 से कहीं अधिक समर्थन मिला है, जबकि उस समय अयोध्या की 1990 की भयावह घटनाओं के कारण राम का मुद्दा असाधारण रूप से भावनाप्रद मुद्दा बना हुआ था। उससे यही सिद्ध होता है कि हिंदुत्व लोगों के मन में पहले से कहीं अधिक घर कर गया है।

छद्म पंथनिरपेक्षता के कारण अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति का उद्भव हुआ है। जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह विलय करने का अपना आंदोलन शुरू किया था, तब से हमने छद्म पंथनिरपेक्षता के खिलाफ अनवरत संघर्ष छेड़ा हुआ है। अयोध्या आंदोलन ने हमारे प्रयासों को महत्त्वपूर्ण सफलता प्रदान की है। राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण हम छद्म पंथ निरपेक्षता के विकल्प के रूप में हिंदुत्व की तरफ ध्यान आकर्षित कर सके हैं।

इस सफलता को हमें सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना होगा। हमने जो संघर्ष छेड़ा है, उसमें शिथिलता नहीं आने दी जानी चाहिए। वास्तविक पंथनिरपेक्षता क्या है, इस बारे में राष्ट्रीय बहस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार इसका अर्थ है—

"सबके लिए न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं", यह बहस जारी रहनी चाहिए और लोगों को इस तथ्य के प्रति अधिकाधिक सचेत किया जाना आवश्यक है। हमारे विरोधियों द्वारा अपनाई जा रही अल्पसंख्यकवाद की राजनीति से देश

की एकता को क्षति पहुँचती है और साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुँचा है।

अयोध्या आंदोलन का प्रभाव

अयोध्या आंदोलन का लोगों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि हमारे कट्टर-से-कट्टर विरोधी को भी इस बारे में कुछ पुनः विचार करने पर विवश होना पड़ा। तथाकथित सेक्यूलरवादियों में भाजपा का विरोध करने की आम सहमति बनी रहेगी, परंतु उनमें भी चाहे हिचकिचाते हुए ही सही, हिंदू भावना को समाहित करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। अब कोई भी पार्टी उसी स्थल पर बाबरी ढाँचे के पुनर्निर्माण की बात नहीं करती।

भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच सुखद आश्चर्य रहा कि सरकार और अन्य दलों ने भी हमारे इस सुझाव के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया कि संसद् एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करे जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पता चले कि जहाँ तक जम्मू-कश्मीर का संबंध है, उसके बारे में राष्ट्र की मूलधारा क्या है!

अंतिम रूप से पारित प्रस्ताव में काफी ऐसे पहलू शामिल हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी अनेक वर्षों से अब तक जोर देती रही है।

जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद

भाजपा के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि जेनेवा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए श्री वाजपेयी को कहा गया। श्री वाजपेयी को, उनके श्रेष्ठतम नेतृत्व प्रदान करने के लिए और जिस ढंग से उनकी टीम ने पाकिस्तान द्वारा बदनाम करने के प्रयास को विफल किया है, पूरे राष्ट्र से सराहना मिल रही है।

किंतु देश को सावधान रहना होगा, क्योंकि जेनेवा प्रकरण से हमें केवल कुछ देर के लिए राहत मिली है। पाकिस्तान हमें नीचा दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करने की अपनी चाल नहीं छोड़ेगा। यह तभी समाप्त हो सकता है जब हम वस्तुतः उग्रवाद को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकें।

इस प्रसंग में जम्मू कश्मीर से प्राप्त खबरें बड़ी चौंकानेवाली हैं। उग्रवाद ने जम्मू क्षेत्र को भी प्रभावित कर लिया है और सरकार मात्र इतना कर रही है कि वह गाहे-बगाहे चुनाव कराने तथा राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा करती रहती है। देश ने घरेलू मामलों के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं मानी।

भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि राजनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू करने की यह सारी बात ही बेकार है। आज सबसे पहली आवश्यकता प्रशासन को बहाल करने और विद्रोह को मजबूती से दबाने की है। यदि पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे इस अप्रत्यक्ष युद्ध में उसे पराजित करना है तो कठोर कदम उठाकर

प्रशासन में उसके एजेंटों को बाहर करना होगा।

कार्यकारिणी के समक्ष चार महत्त्वपूर्ण कार्य हैं—

- डंकल प्रस्तावों के संदर्भ में आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण।
- अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से लघु उद्योगों पर बजट के प्रभाव का विश्लेषण।
- 6 अप्रैल को होनेवाली डंकल विरोधी रैली के समर्थन में लोगों को एकत्र करने के बारे में किए गए कार्य की समीक्षा। संयोगतः 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है।
- अगले बारह महीनों में जिन 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनके बारे में राज्यों से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों पर विचार करना।

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अन्य विभिन्न राज्यों की, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश की; राजनीतिक स्थिति की संक्षिप्त रिपोर्ट की जानकारी भी लेना चाहेगी।

वंदेमातरम्



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

वडोदरा

8-9 जून, 1994

मैं वडोदरा में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूँ। यह बैठक परसों हो रहे राष्ट्रीय परिषद् के अधिवेशन के प्रस्तावों के प्रारूप तैयार करने के लिए आयोजित की जा रही है।

गुजरात में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक चौथी बार हो रही है। 1992 में एक अधिवेशन हुआ था। गांधी नगर में परिषद् की बैठकें दो बार वर्ष 1986 और फिर 1992 में हुई। आज हम वडोदरा में मिल रहे हैं। इस नगर का संबंध आधुनिक युग की दो अद्वितीय प्रतिभाओं—श्री अरविंद घोष और श्री भीमराव अंबेडकर की स्मृति के साथ जुड़ा है। श्री अरविंद एक क्रांतिकारी, देशभक्त और संत थे, जिन्होंने देशवासियों से राष्ट्रवाद को अपना धर्म मानने के लिए कहा था। डॉ. अंबेडकर एक विद्वान् और राजनेता थे, जो दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे।

चुनाव-सुधार

राष्ट्रीय परिषद् के अधिवेशन की तारीखें हमने यह ध्यान में रखकर निश्चित की थीं कि यह सम्मेलन संसद् के बजट अधिवेशन और मानसून अधिवेशन के अंतराल की अवधि के मध्य में आसानी से रखा जा सकता है। किंतु बजट सत्र के अंत में अचानक ही सरकार इस बात का मान कर जाग उठी कि चुनाव सुधारों का मुद्दा ऐसा है जिसमें और देर नहीं की जा सकती और इसलिए सामान्यतया जुलाई मास में मानसून सत्र की बैठक होने की बजाय संसद् का सत्र कुछ दिनों के लिए जून मास में ही रखा जाए, क्योंकि यह सत्र 13 तारीख को बुलाया गया है। अतः संसद् सदस्यों को इसमें भाग लेने के लिए वडोदरा से सीधे नई दिल्ली रवाना होना पड़ेगा।

जनसंघ के समय से ही हम चुनाव सुधारों के लिए जन अभियान के मामले

में अग्रणी रहे हैं। इस विषय पर हमारे अभियान का कालक्रमानुसार वृत्तांत कुछ समय पहले तैयार किया गया था जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है।

सरकार की नीयत साफ नहीं

पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने 1967 में जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में इस मुद्दे को उठाया था। श्री वाजपेयी ने सर्वप्रथम इस मामले को संसद् में 1969 में उठाया था। किंतु हमें यह कहते हुए दुःख होता है कि इस बार इन दो बिलों को पेश करने में सरकार का इरादा बिलकुल सदाशयतापूर्ण नहीं है।

दो बिलों में से एक संविधान संशोधन बिल है। निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने के नाम पर (जिसके लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है) इस बिल का उद्देश्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को अवरुद्ध करना है।

दूसरे बिल में पहचान पत्रों के बारे में चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को अकृत्य और शून्य करार देना है। जब तक कि सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न हो जाए एक और प्रावधान के जरिए धर्म को चुनावी दायरे से निष्कासित कर देना चाहिए।

निर्वाचन आयोग और भाजपा के प्रति दुराग्रह

इस प्रकार इन दोनों बिलों का लक्ष्य चुनाव में भ्रष्ट आचरणों को दूर करना नहीं है। उनका प्रथम लक्ष्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरा निशाना भाजपा है। निस्संदेह बिलों में से अनेक खंड हैं, जैसे—परिसीया निर्धारण आदि, जिन पर हमारी सहमति है; परंतु क्योंकि सरकार के इरादे बुरे हैं, इसलिए भाजपा इन बिलों का विरोध करने पर दृढ़ निश्चयी है।

चुनाव ऐसा मामला है, जो लोकतंत्र के स्वास्थ्य से जुड़ा है। यदि इस बारे में पेश किए जानेवाले बिल में देश के लोगों की एक व्यापक सहमति की झलक दिखाई दे तो वह देश के हित में होगा। वर्तमान बिलों ने देश में विभाजन पैदा कर दिया है और आम सहमति दिखाई नहीं पड़ती है। पिछले कुछ दिनों की रिपोर्टों से पता चलता है कि गैर-कांग्रेस दल, जो पहले इन बिलों का समर्थन कर रहे थे, अब इस मुद्दे पर पुनः विचार कर रहे हैं।

संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता

ब्रिटेन में प्रत्येक चुनाव के बाद हाउस ऑफ कॉमंस का स्पीकर पिछले चुनावों के अनुभवों की पृष्ठभूमि में चुनाव संबंधी कानूनों के सुधार के प्रश्नों पर चर्चा के लिए सामान्यतया सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया करता है। 1969 में जब श्री

वाजपेयी ने पहली बार इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया तो उन्होंने इसी प्रकार का सुझाव दिया था। मेरा विचार है कि यही समय है जब इस बारे में संस्थागत व्यवस्था की जाए ताकि चुनाव सुधार एक अनवरत प्रक्रिया बन जाए और इन सुधारों को किसी राजनीतिक विवशताओं के कारण या अनियमित ढंग से न किया जाए।

दिनेश गोस्वामी समिति ने इस बारे में ठोस सुझाव दिए थे। उसने समय-समय पर सभी चुनाव मामलों पर विचार करने के लिए संसद् की एक स्थायी समिति गठित करने की सिफारिश की थी। मैं लोकसभा अध्यक्ष से इस बारे में पहले करने का आग्रह करता हूँ।

वंदेमातरम्



राष्ट्रीय परिषद्

वडोदरा 10–12 जून, 1994

स्वागताध्यक्ष महोदय, बहनो एवं भाइयो !

मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद् के इस 15वें अधिवेशन में आपका स्वागत करता हूँ। हम इस बार गुजरात में मिल रहे हैं और वह भी जून मास में। अधिवेशन का स्थल और समय दोनों ही भारत के हाल के राजनीतिक इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

महात्मा गांधी और सरदार पटेल की इस भूमि गुजरात में पहली बार राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया गया था। श्री जयप्रकाश नारायण और श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गुजरात के लोगों ने कांग्रेस की भ्रष्ट राज्य सरकार को सत्ता से हटा दिया था। यह घटना ठीक 19 वर्ष पूर्व जून 1975 में हुई थी। भारतीय राजनीति में यह महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर था। इससे भारतीय राजनीति में एक ही पार्टी की प्रमुखता का युग समाप्त हो गया था।

द्वि–दलीय प्रणाली की ओर

उसके बाद के दो दशकों से भारतीय राजनीति एक गहन उथल–पुथल के दौर से गुजरती रही है। तब से लोकसभा के पाँच आम चुनावों में कांग्रेस ने दो में विजय प्राप्त की, दो में हारी और पाँचवें में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर आई। निस्संदेह इस समय भी यह देश की प्रमुख पार्टी है, परंतु एक ही पार्टी की प्रधानता समाप्त हो गई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसका लगभग लोप ही हो गया है।

इस काल का सर्वाधिक सकारात्मक पक्ष यह है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार अब संसद् के दोनों सदनों में एक अकेली गैर–कांग्रेसी पार्टी भाजपा मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के रूप में स्वीकृत हुई है। दरअसल लोकसभा के दसवें आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीति को मोटे तौर पर एक ऐसी द्वि–दलीय प्रणाली के रूप

में प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में लोकतंत्र के हितैषी बहुत समय से इच्छा कर रहे हैं।

आज वडोदरा में आयोजित इस बैठक का महत्त्व इसलिए भी है कि इस नगर से भारत माँ के दो महान् सपूतों—योगी अरविंद और डॉ. भीमराव अंबेडकर की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। सौ वर्ष पूर्व महाराजा गायकवाड़ के अनुरोध पर श्री अरविंद घोष ने बड़ौदा आकर इस नगर को अपनी कर्मभूमि बनाया था और वे 1813 से 1906 तक यहाँ रहे थे। इस काल में न केवल उनके जीवन में, अपितु राष्ट्र के जीवन में भी नया मोड़ आया।

अरविंद और अंबेडकर

बड़ौदा में श्री अरविंद ने 'आध्यात्मिक राष्ट्रवाद' के आधार पर भारत के पुनर्निर्माण के लिए देशवासियों का आह्वान किया था। यहीं पर अरविंद ने पूरे देश में भवानी भारती मंदिरों (भारत माता मंदिरों) के निर्माण की अवधारणा को लोगों के सामने रखा था। अरविंद ने कहा था—भवानी भारती की शक्ति तीस करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति की एकता है, परंतु वह तमस के सम्मोहनशील दायरे में फँसी और अपने बेटों की नादानी के कारण निष्क्रिय पड़ी है।' अरविंद ने राष्ट्रवाद को सनातन धर्म कहा था। राष्ट्रवाद के विषय में योगी अरविंद के विचार आज उन्हें धर्म व राजनीति को मिलानेवाले 'अपराधियों' के कठघरे में खड़ा कर देते।

1917 में महाराजा बड़ौदा ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर को राज्य का सैनिक सचिव नियुक्त किया। तब बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. की उपाधि लेकर अमेरिका से लौटे ही थे। जब वे बड़ौदा पहुँचे तो महाराजा के अधिकारियों में से उन्हें स्टेशन पर कोई भी लेने नहीं आया। आखिर वह एक 'अछूत' महार थे। इसी कारण कुछ समय तक उन्हें रहने का भी कहीं कोई स्थान नहीं मिला। किसी तरह उन्होंने एक पारसी धर्मशाला में जगह का इंतजाम किया। परंतु उन्हें वहाँ से भी 'अछूत' घर में जन्म लेने के 'अपराध' के कारण बहुत जल्दी निकाल दिया गया।

बड़ौदा के इन्हीं भयानक अनुभवों के कारण इस महान् व्यक्ति में दृढ़ निश्चय पैदा हुआ और उन्होंने दृढ़-प्रतिज्ञ होकर दलितों के हितों के लिए जेहाद छेड़ दिया। किंतु दलितों के प्रति उनकी इस चिंता के कारण भारत की एकता और लोकतंत्र इन दोनों के प्रति उनकी संपूर्ण प्रतिबद्धता पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी ये प्रतिबद्धताएँ डॉ. अंबेडकर द्वारा देश के लिए तैयार किए गए महान् संविधान में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं।

जून मास का एक और आसन्न महत्त्व भी है। इस महीने नरसिंह राव सरकार के तीन वर्ष पूरे हो जाएँगे। इस अवधि में इस सरकार के कार्य-प्रदर्शन पर दृष्टि

डालते हुए मुझे वास्तव में बहुत संकोच अनुभव हो रहा है, जब याद करता हूँ कि एक बार मैंने वर्तमान प्रधानमंत्री की तुलना श्री लाल बहादुर शास्त्री से की थी। श्री शास्त्री सार्वजनिक जीवन में सत्य, निष्ठा और ईमानदारी की साक्षात् प्रतिमूर्ति थे। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि राव राज के ये तीन वर्ष हाल के समय में सर्वाधिक नैतिकता-शून्य रहे हैं।

नैतिक अधःपतन

निस्संदेह अब तक भारत में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद, अपराध और हिंसा अच्छी तरह पनप चुकी है। परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ, जब कि स्वयं शीर्ष सत्ताधिकारियों ने इन बुराइयों को इस हद तक संरक्षण प्रदान किया हो, जैसा अब देखने में आ रहा है। स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस स्थिति को देखा होता तो यही कहते—'गंगोत्री स्वयं मैली हो गई है।'

स्वतंत्र भारत में किसी शहर को तहस-नहस कर देनेवाले सबसे बड़े उपद्रव 1984 में हुए। किसी छोटे-मोटे जिले में नहीं, अपितु भारत की राजधानी में हुए। हजारों सिक्खों की हत्या कर दी गई—अधिकांश को जिंदा जला दिया और यह सब कुछ भारत सरकार की आँखों के सामने हुआ। उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री गृह विभाग सँभाले हुए थे।

तब से दस वर्ष बीत गए। एक भी अपराधी को दंड नहीं दिया गया। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली की भाजपा सरकार ने इन अपराधियों को न्याय के कठघरे में खड़े करने का हरसंभव प्रयास किया है, परंतु राव सरकार बाधाएँ डालती रही है। राव सरकार के राज में हत्यारों को विशेष संरक्षण दिया जाता है और संतप्त परिवांरों को दुःख झेलने के लिए छोड़ दिया जाता है।

नैतिकता का विघटन वस्तुतः नांदयाल में शुरू हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव प्रचार-प्रबंधक अपना नाम विश्व रिकॉर्ड की गिनीज बुक में दर्ज करा लेना चाहते थे। इस प्रकार के प्रयास के लिए उन्हें पूरे नंबर मिलने भी चाहिए। नांदयाल में डाले गए मतों में से श्री राव को 90 प्रतिशत से कुछ ही कम मत मिले। प्रबंधकों ने इस 90 प्रतिशत से नीचे की संख्या पर अपने को रोक लिया, जिसका स्पष्ट कारण यही था कि यदि किसी उम्मीदवार को 90 प्रतिशत या इससे अधिक मत मिलते हैं तो चुनाव आयोग इसे प्रत्यक्षतः धाँधली का प्रमाण मान लेता है। आजकल जब वर्तमान सरकार गला फाड़-फाड़कर चुनाव सुधारों के बारे में चिल्ला रही है तो नवंबर 1991 के नांदयाल को भूल नहीं जाना चाहिए।

दल-बदल का दौर-दौरा

वर्तमान व्यवस्था में चुनावों के दौरान सत्ताधारी पार्टी ने जो कुछ किया है, वह काफी खराब है। चुनावों के बाद जो कुछ करती रही है वह उससे भी खराब

है। अल्पमत की सरकार को बहुमत की सरकार में बदलने के लिए राव सरकार ने किसी तरह की झिझक या नैतिक वर्जना की परवाह नहीं की। वस्तुतः दल-बदल कराने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित हो गई है। प्रधानमंत्री के दूतों ने बार-बार जनता दल, तेलुगु देशम, झारखंड मुक्ति मोरचा और शिवसेना में विभाजन कराया और फिर इन दलों के बचे-खुचे सदस्यों को समुचित प्रलोभन देकर सत्ताधारी पार्टी में मिलने के लिए आकर्षित किया। विपक्षी पार्टियों की तो बात ही क्या, राव सरकार ने अपनी ही मित्र पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. को भी तोड़ने की कोशिश की।

वर्तमान सरकार द्वारा दल-बदल के प्रति उत्साह के अलावा केवल एक और बात में उत्साह दिखाई पड़ता है और वह है भ्रष्टाचार के प्रति उत्साह। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही कभी पहले इतने थोड़े से लोगों ने इतने अधिक लोगों को इतना अधिक लूटा हो।

जब दो वर्ष पहले नरसिम्हा राव सरकार में विदेश मंत्री ने डेवास की यात्रा की और स्वीडन के विदेश मंत्री को एक नोट सौंपा, जिसमें स्वीडन के अधिकारियों से बोफोर्स मामले में धीमी गति से कार्यवाही करने का अनुरोध किया, तभी श्री राव की पोल खुल गई थी कि वे भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के इच्छुक नहीं हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार, उन्हें किसी ऐसी घटना का पता नहीं था। मंत्री महोदय का कहना था कि वे नहीं जानते कि यह पत्र किसने लिखा और इसपर भी वे दोनों चाहते थे कि जो कुछ उन्होंने कहा, उस पर देश विश्वास कर ले।

असीम घोटाला

परंतु बोफोर्स सौदे में जिन्हें दलाली मिली थी, वे शेयर घोटाले के धाँधलीबाजों के मुकाबले नौसिखिए थे। बोफोर्स घोटाले में देश के खजाने को लगभग 60 से 100 करोड़ रुपए तक की हानि उठानी पड़ी होगी, परंतु जब हम प्रतिभूति घोटाले की बात करते हैं तो यह अरबों खरबों की लूट की बात है और इसमें लाभ उठानेवाले केवल दलाल ही नहीं हैं, गोल्डस्टार जैसे उद्योगपति भी हैं।

घोटालेबाजों और प्रधानमंत्री के विरोधाभासी कथन

घोटाले की इन घटनाओं के कारण प्रधानमंत्री के उच्च पद को भी कलंकित किया गया था। सचमुच वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब मत संग्रहकर्ता लोगों के पास उनकी राय जानने के लिए गए कि वे किसकी बात पर विश्वास करते हैं—घोटालेबाजों की बात पर जिन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं या प्रधानमंत्री के कथन पर? लोगों को जो बात उलझन में डालती है वह यह है कि ये घोटालेबाज झूठ बोल रहे थे तो फिर वे अभी तक कैसे स्वच्छंद घूम रहे हैं।

संयुक्त संसदीय समिति ने 6 मंत्रालयों को दोषी ठहराया। सरकार ने उनके

विरुद्ध कार्यवाही करने और जे.पी.सी. की जाँच पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी संसद् को तीन महीने में पेश करने का वायदा किया था। 6 महीने गुजर गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

विनिवेश घोटाला

शेयर बाजार घोटाले से भी पहले सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों के विनिवेश का घोटाला भी चला। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों के विनिवेश के कारण भारत के लोगों को कम-से-कम 3000 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी। ये मेरे आँकड़े नहीं हैं—ये अनुमान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने लगाया है। निश्चित ही यह बहुत बड़ी राशि है जो बोफोर्स सौदे की दलाली से भी पचास गुना अधिक है। परंतु इसके लिए कौन उत्तरदायी है? किसी को कुछ मालूम नहीं। अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई? कुछ नहीं।

देश में चीनी की वर्तमान स्थिति के कारण सर्वोच्च स्तर पर व्यापक अकुशलता और सरकार में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार दोनों दुराचरणों की दुर्गंध फैली हुई है। एक तरफ आम आदमी बेतहाशा बढ़ी कीमतों के बोझ तले पिस रहा है, दूसरी तरफ तानाशाह और राजनीतिज्ञ खुले आम आपस में झगड़ा करने में लगे हैं।

जब बात अपराधी की होती है तो राव सरकार 'स्फिंक्स' की तरह चुप्पी साध लेती है। संयोगतः 'स्फिंक्स' एक वित्त कंपनी का नाम भी है जो वर्तमान शासन के निकट है।

1984 में नई दिल्ली में आयोजित एक विचार गोष्ठी में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर.के. त्रिवेदी ने चेतावनी दी थी कि "जब तक चुनावों में अंधाधुंध खर्च पर रोक लगाने के उपाय नहीं किए जाएँगे और इस प्रकार धन शक्ति की निर्भरता को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता ही जाएगा।"

धन-शक्ति और बाहुबल

भाजपा का बहुत समय से यही दृष्टिकोण है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जड़ें राजनीतिक भ्रष्टाचार में जमी हैं और फिर राजनीतिक भ्रष्टाचार चुनावी भ्रष्टाचार से पैदा होता है। सबसे पहले श्री वाजपेयी ने ही 1969 में संसद् में जनसंघ के नेता के रूप में चुनाव-सुधार का मुद्दा उठाया था और सरकार से एक संसदीय समिति की स्थापना कराई थी। इस समिति ने 1972 में एक बहुमूल्य रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद अनेक रिपोर्टें आईं परंतु सरकार इस मामले में एक इंच आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई। अब 20 वर्षों के बाद और वह भी दलगत व कुत्सित कारणों से उसने कार्यवाही करने का इरादा किया है। इसी बीच देश के चुनावों

में इस हद तक गिरावट देखने को मिली है कि कहीं-कहीं चुनाव पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच मात्र इस बात पर मुकाबला हुआ कि कौन कितनी अधिक धन-शक्ति और माफिया-शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

जब राजनीतिज्ञ चुनाव जीतने के लिए ताकत और अपराधियों को इस्तेमाल करने लगते हैं तो वे अपराध के सहभागी बन जाते हैं। इसी बीच होने यह लगा है कि स्वयं पुराने अपराधी ही राजनीतिक अखाड़े में उतरने लगे हैं और उन्हें विधानसभाओं में स्थान मिल गया है। इस प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन का एक भाग भी अपराध प्रवृत्ति में लिप्त हो गया है। वर्ष-प्रति वर्ष यह विघटन अधिक ही बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक राज्य में हम गुंडों की मित्र सरकारों को सत्ता में आते देख रहे हैं। यह जानकर क्षोभ होता है कि पिछले वर्ष बंबई में बम विस्फोटों की भयानक घटना में वे कट्टर अपराधी शामिल थे जिनका राज्य के वर्तमान शासन के साथ निकट का संबंध था। जहाँ कुछ राज्यों में अपराधी-राजनीतिज्ञों के बीच संबंधों के कारण सामाजिक सद्भाव और कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य राज्यों में इन संबंधों ने खतरनाक ढंग से राष्ट्र-विरोधी आयाम ले लिया है। आश्चर्य नहीं, जब से श्री टी.एन. शेषन ने चुनावों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरह से जेहाद छेड़ दिया है, वह तभी से लोगों की आँखों का तारा और कांग्रेस की आँखों का काँटा बन गए हैं।

निशाना : मुख्य चुनाव आयुक्त और भाजपा

अगले सोमवार को होनेवाले संसद् अधिवेशन में जिन दो प्रस्तावों पर चर्चा की जानी है, उनका उद्देश्य चुनाव-भ्रष्टाचार को समाप्त करना नहीं है। वास्तविक निशाने हैं—प्रथम, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे, संसद् में प्रमुख विपक्षी दल।

भाजपा ने सदैव बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का समर्थन किया है। 1972 में संयुक्त संसदीय समिति, 1974 में तारकुंडे समिति और 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्टों में बहुसदस्यीय आयोग की सिफारिश है। परंतु इनमें से किसी भी समिति ने अनुच्छेद 324 की वर्तमान व्यवस्था को बदलकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा देने की बात पर विचार तक नहीं किया, सिफारिश करने की बात तो दूर रही, क्योंकि वास्तव में इससे निर्वाचन आयोग की शक्तियों और स्वायत्तता पर गंभीर आँच आती है।

1993 के मध्य में सरकार ने संसद् में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें कहा कि यदि कोई पार्टी चुनाव में धर्म, जाति, भाषा या वंश का प्रयोग इस ढंग से करती है, जिससे विभिन्न वर्गों में फूट पड़ती है तो उस पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाए। बाद में इस विधेयक में परिवर्तन करके जाति, भाषा और वंश को हटा दिया तथा इसे धर्म तक सीमित रखा, जिससे स्पष्ट हो गया कि इस प्रावधान का प्रयोजन केवल भाजपा के विरुद्ध था जो सत्ताधारी पार्टी के लिए जबरदस्त चुनौती बन गई थी।

धर्म-विरोधी विधेयक

1993 में धर्म को राजनीति से अलग करने के नाम पर प्रस्तुत किए गए दो विधेयक पारित नहीं हो सकें। अब धर्म-विरोधी विधेयक के पंजीकरण को रद्द करने के प्रावधान को अगले सप्ताह पेश किए जानेवाले चुनाव सुधार विधेयक में डालने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा इन दोनों विधेयकों का विरोध करने के लिए कृतसंकल्प है। धर्म-विरोधी प्रावधान को हमारे विरोध के पीछे मूलाधार बताना उचित होगा, भाजपा सदस्यों ने धर्म-विरोधी दो विधेयकों पर संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट के संबंध में अपनी विसम्मत टिप्पणी में कहा था—

धर्म की गलत व्याख्या

"चालीस वर्ष पहले डॉ. संपूर्णानंद ने अपने एक मित्र से कहा था कि कभी-कभी मात्र एक शब्द के गलत अनुवाद से देश की विचार प्रक्रिया बुरी तरह छिन्न-भिन्न हो सकती है। इस संबंध में उन्होंने 'धर्म' शब्द को 'रिलिजन' शब्द के अनुवाद के रूप में लिये जाने का उल्लेख किया है।

धर्म को राजनीति से अलग करने के नाम पर दो विधेयकों को पारित करने की माँग डॉ. संपूर्णानंद के इस पूर्वाभास को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है। विधेयकों के हिंदी रूपांतरण में सर्वत्र 'रिलिजन' शब्द के लिए 'धर्म' शब्द रखा गया है। सार्वजनिक जीवन से पांथिक मान्यता का निष्कासन भी कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु सार्वजनिक जीवन से धर्म को निकाल देने की अवधारणा मात्र हमारे देश के औसत नागरिक के लिए क्षोभकारी होगी।

"फिर भी प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से धर्म के किसी भी आह्वान पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और महाभारत तथा रामायण, यहाँ तक कि राम राज्य, का संकेत मात्र करने को चुनावी अपराध बनाया जा सकता है। यदि महात्मा गांधी और श्री अरविंद—लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय की तो बात ही क्या है—जीवित होते तो उन्हें भी राजनीतिक रूप से अपराधी बना दिया जाता, क्योंकि सरकार और इनके मित्र सहयोगी भारत को आधारहीन बनाने की बात ही नहीं सोच रहे हैं बल्कि वे भारत को एक सदाचार-विहीन और आचरणहीन भारत बना रहे हैं।"

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

"निस्संदेह उनके भय के मूल में अल्पसंख्यकवाद पर आधारित छद्म पंथनिरपेक्षता की राजनीति के कारण उत्पन्न जनक्षोभ भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।

"इस राष्ट्रवाद का आधार हमारी संस्कृति और विरासत है। हमारे लिए ऐसे राष्ट्रवाद का कोई अर्थ नहीं है जो हमें वेदों, रामायण, महाभारत, गौतमबुद्ध, भगवान् महावीर, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी,

रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी दयानंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और असंख्य अन्य राष्ट्रीय अधिनायकों से अलग करता हो। यह राष्ट्रवाद ही हमारा धर्म है।"

कश्मीर में संकट

'सेक्यूलरवाद' और 'धर्म' के बारे में कांग्रेस पार्टी की विकृत धारणा का सबसे अधिक दुष्परिणाम यह हुआ है कि कश्मीर का मुद्दा गड़बड़ घोटाले में पड़ गया है। पार्टी में उग्रवादियों की गतिविधियाँ निर्बाध रूप से जारी हैं और जैसा कि भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री को बताया था कि जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्से में आतंकवादियों की गतिविधियाँ बढ़ने के कारण इस क्षेत्र से भी लोगों का पलायन शुरू हो गया है। यह एक अत्यंत विक्षोभकारी घटना है। घाटी से निकलकर आए हुए तीन लाख विस्थापितों की दयनीय स्थिति वस्तुतः भारत सरकार के लिए शर्म की बात है। जम्मू में भी इसी प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए।

भारतीय संस्कृति का स्थल—कश्मीर

सरकार के लिए और देश में अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के लिए जम्मू कश्मीर की समस्याओं को केवल एक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि यह एक मुसलिम बहुल राज्य है। हम अकसर भूल जाते हैं कि कश्मीर प्राचीन भारतीय सभ्यता, दर्शन और रीति-रिवाजों का सबसे बड़ा स्थल रहा है और यह भी कि कश्मीर और शेष भारत के बीच सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति के बंधन हैं। भारत के लोग इस मुद्दे पर कभी कोई समझौता नहीं करने देंगे। इस मामले में किसी भी तरह का समझौता करने से देश की एकता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।

संसद् में प्रस्ताव

इसी कारण भाजपा ने कुछ समय पूर्व सार्वजनिक रूप से पहल कर के संसद् को इस बारे में वचनबद्ध किया था कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमें खुशी है कि हमें इस पहल में सफलता मिली। हम विशेष रूप से इस बात पर संतोष अनुभव करते हैं कि संसद् द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य पर पाकिस्तान का हमला तथा राज्य के एक-तिहाई भाग पर उसका अवैध कब्जा है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अभी तक सरकार ने कश्मीर के मुद्दे पर कभी स्वीकार तक नहीं किया था।

सामंजस्यपूर्ण नीति का अभाव

जम्मू कश्मीर राज्य से उग्रवाद को उखाड़ फेंकने में भारत सरकार की विफलता का मुख्य कारण यह है कि सरकार की कोई एक सामंजस्यपूर्ण नीति नहीं है और न ही इस विषय में नेतृत्व की कोई एकसूत्रता है। इस अधिवेशन में हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जो उपाय इस बारे में किए जाने चाहिए उनका उल्लेख करेंगे।

पहले 1950 के दशक में कश्मीर मुद्दे पर जनसंघ के आंदोलन तथा 1990 के दशक में अयोध्या के मामले में भाजपा के आंदोलन में एक ही प्रकार का दृष्टिकोण रहा है कि पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति वचनबद्ध है और वह विकृत सेक्यूलरवाद को स्वीकार नहीं करती है।

भारत के साथ एकात्मकता

इन दोनों आंदोलनों के सकारात्मक परिणाम निकले हैं। 1953 में आंदोलन के कारण और विशेषतः डॉ. मुखर्जी के बलिदान के फलस्वरूप जम्मू और कश्मीर को शेष देश के साथ जोड़ने के लिए अनेक कदम उठाने पर सरकार बाध्य हो गई। परमिट प्रणाली समाप्त की गई, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधिकारों को जम्मू–कश्मीर राज्य पर लागू किया गया। राष्ट्रीय तिरंगा, जो उस समय तक राज्य में नहीं फहराया जा सकता था, अब उसे वहाँ सम्मानजनक स्थान मिल गया। इस प्रकार 1953 का वर्ष जम्मू और कश्मीर के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। जो लोग 1953 से पूर्व की स्थिति में लौटने की बात करते हैं वे दरअसल इस सबको मिटा देना चाहते हैं।

अयोध्या आंदोलन

जहाँ तक अयोध्या आंदोलन का प्रश्न है, यह देखकर संतोष होता है कि 1993 व 1994 में अयोध्या आंदोलन के विरोधियों ने भी यह मान लिया कि राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि पर ही होगा। अब कोई भी 'बाबरी ढाँचे' के पुनर्निर्माण की चर्चा नहीं करता है। पिछले कुछ महीनों में हमारे विरोधियों ने इस मुद्दे के केवल एक पहलू की चर्चा की है कि मंदिर का निर्माण सरकारी न्यास द्वारा किया जाना चाहिए, न कि राम जन्मभूमि न्यास द्वारा। लोग ऐसा नहीं होने देंगे।

आर्थिक स्थिति

अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। जिस नई आर्थिक नीति का प्रवर्तन तीन वर्ष पहले बड़े धूमधाम से किया गया था, वह ठप्प होकर रह गई है। कीमतों को छोड़कर शेष सभी संकेतक बताते हैं कि अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही

है। इसका सबसे खराब पक्ष यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का अपनी वित्त व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो किसी भी अर्थपूर्ण विकास के लिए प्रथम आवश्यकता है। उद्योग मंदी से घिरे हुए हैं। पूर्ण अर्थव्यवस्था चाहे इसका संबंध पूँजी बाजार, विद्युत् संयंत्र की स्थापना से हो या चीनी के आयात से हो—भ्रष्टाचार, धाँधली, दलाली और घोटालों से कलंकित है। एक ओर सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्वागत पलक पाँवड़े बिछाकर कर रही है, तो दूसरी ओर भारतीय प्रतिभा और उद्यम कालातीत कानूनों और नीतियों की बेड़ियों में अब भी जकड़े हुए हैं।

कीमतें और रोजगार

भारत में आम आदमी को सबसे अधिक दो बातों की चिंता है—कीमतें और रोजगार। सत्ताधारी पार्टी ने 1991 के अपने घोषणापत्र में कीमतों को 100 दिन के अंदर 1990 के स्तरों पर लाने तथा 10 लाख नए रोजगारों का सृजन करने का वायदा किया था। इसकी बजाय पिछले 3 वर्षों में कीमतें 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई हैं और कई मामलों में तो, जैसे चीनी, दुगुनी हो गई है।

मुद्रास्फीति बढ़कर दो अंकों में

देश में मुद्रास्फीति का प्रसार पहले ही दो अंकों तक पहुँच गया है। इससे भी खराब स्थिति यह है कि पिछले कुछ सप्ताहों में अनाज, चीनी, कपास, पेट्रोलियम पदार्थों और बिजली जैसी मदों पर कीमतें 26 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं। 11 मदें ऐसी हैं जिनके कारण कुल मिलाकर मुद्रास्फीति में 57 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

बेरोजगारी

जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है, जितना कम कहें बेहतर होगा। अनेक उद्योगों को, जिनमें अधिकांश लघु क्षेत्र में आते हैं, बंद होना पड़ा है जिससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। सरकार के पास नए उद्योगों अथवा नई परियोजनाओं के लिए धन नहीं है और धन की कमी इतनी विकट है कि योजना आयोग ने विकास लक्ष्य 5.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।

बढ़ते विदेशी ऋण

इस सभी का शुद्ध परिणाम यह हुआ है कि विदेशी ऋण बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में अनुमान है कि अब यह 85 बिलियन डॉलर या 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक है। तीन वर्ष पूर्व जब सरकार ने सत्ता सँभाली थी तो यह ऋण 1,24,000 करोड़ रुपए था या यों कहें कि वर्तमान ऋण का आधे से भी कम था। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में जितना अधिक ऋण लिया उस ऋण का क्या

किया? यह पैसा कहाँ चला गया? इसका प्रयोग उद्योग में नहीं हुआ, क्योंकि उद्योग डाँवाँडोल हालत में है। इसका उपयोग कृषि में नहीं हुआ, क्योंकि वस्तुतः कृषि में निवेश कम होता जा रहा है। यह धन मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के काम में आया है और पिछले तीन वर्षों की लंबी अवधि में कीमतें बढ़ती रही हैं।

उदारीकरण हो, भूमंडलीकरण नहीं

जब से नई नीति आरंभ की गई है तभी से भाजपा इस बात पर बल देती रही है कि सरकार की रुचि अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और इसे पुनः व्यवस्थित करने की अपेक्षा भूमंडलीकरण के प्रति अधिक रही है।

उदारीकरण का अर्थ होता है—नियंत्रण, विनिमयों और नौकरशाही से मुक्ति पाना। परंतु हम चाहते हैं कि अनेक वर्षों की गलत नीतियों से जर्जर हमारी अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण किए जाने से पहले यह वस्तुतः सुदृढ़ बने। जिस प्रकार से सरकार आज हड़बड़ी में भूमंडलीकरण के पीछे पड़ी है, हम उसके विरुद्ध हैं।

भाजपा को डंकल प्रस्ताव स्वीकार नहीं

यही कारण है कि भाजपा ने डंकल प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। राजनीतिक अथवा आर्थिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है, इन प्रस्तावों में निहित सिद्धांत उस दृष्टिकोण से जरा भी मेल नहीं खाते। निस्संदेह विश्व का रूप लघु से लघुतर होता जा रहा है तथा कोई भी देश अलग-थलग रहकर नहीं चलना चाहेगा अथवा अलग नहीं पड़ना चाहेगा। परंतु राजनीतिक अथवा आर्थिक दोनों मामलों में ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, वस्तुतः यह एक ही सिक्के—संप्रभुता के सिक्के—के दो पहलू हैं।

राष्ट्रीय संप्रभुता

आगामी वर्षों में यह एक प्रमुख मुद्दा बना रहेगा तथा यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी उपेक्षा आसानी से नहीं की जा सकती और निश्चित ही भाजपा तो उपेक्षा कर ही नहीं सकती क्योंकि भाजपा के लिए संप्रभुता ही उसके दर्शन का सत्त्व है। डंकल मुद्दा, बहुराष्ट्रिकों का मुद्दा मात्र आर्थिक अथवा वाणिज्यिक मुद्दे नहीं हैं, यह केवल आयात और निर्यात की छोटी-मोटी बात भी नहीं है और न ही यह वित्तीय सौदेबाजी की बात है। ये तो भारत के करोड़ों लोगों के जीवन और मृत्यु के मुद्दे हैं। ये वे मुद्दे हैं जो आनेवाले वर्षों में यह निर्णय करेंगे कि हम अपना सिर ऊँचा कर के स्वतंत्र लोगों की तरह रह सकेंगे। या सिर्फ जिंदा रहने की खातिर अंतरराष्ट्रीय धोखेबाजों के दबाव में आकर झुक जाएँगे।

भारतीय स्थिति के मूल तत्त्व भूमंडलीकरण की आधारभूत मान्यताओं से भिन्न है। रोजगार, उत्पादन और निर्यात के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का तीन-चौथाई भाग भारतीय कृषि, कुटीर और लघु उद्योगों में निहित है; जबकि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं का मूल आधार बड़े उद्योग और अधिक वित्त है। भारत अभी तक अपने आंतरिक बाजार का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाया है, पश्चिमी राष्ट्रों का अपना बाजार लगभग पूरी तरह भर गया है और वे विदेशी व्यापार के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं।

गलत प्राथमिकताएँ

अतः औद्योगिक रूप से विकसित देशों के लिए विदेश व्यापार और विदेशी निवेश जीवन-रक्त ही है, परंतु भारत के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश उसके राष्ट्रीय प्रयास का केवल एक संपूरक हो सकता है। एक बात और, अरब देशों, ब्राजील या क्यूबा की तरह भारत ऐसा देश नहीं है जिसके पास बेचने के लिए केवल एक ही वस्तु हो, इसलिए उसके लिए विदेशी व्यापार केवल एक अतिरिक्त साधन है, उसके लिए विदेशी व्यापार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु नहीं है।

हमारा कृषि उत्पादन वर्तमान उत्पादन से दुगुना हो सकता है। यह स्वीकृत तथ्य है कि भारत में जहाँ भी पानी उपलब्ध है वह क्षेत्र समृद्ध है और फिर भी हम अपने आधे से अधिक ग्रामवासियों को पानी से वंचित रखे हैं। हमारे वर्तमान आर्थिक नीति-निर्माता पानी न मिलने से दुःखी इन लाखों लोगों के बारे में सोचते तक नहीं। वे तो इसी बहस में व्यस्त हैं कि पेप्सी कोला या कोका कोला से डॉलरों का अधिक निवेश होगा या केंटुकी मेक्डॉनल्ड से।

उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ बहुत ही ऊपरी सतहों को क्रियाशील बनाने का प्रयास होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के 90 प्रतिशत भाग तक इसके प्रभाव तक पहुँचने की प्रतीक्षा करनी होती है। किंतु भारत को इससे विपरीत स्थिति की आवश्यकता है भारत की प्रमुख रूप से अपने ही विचारों पर आधारित समाधानों के द्वारा भारतीय नींव को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस स्थिति में भारतीय व्यवस्था मूलाधार है और पश्चिमी अर्थव्यवस्था अतिरिक्त पूरक का काम करती है। आधुनिक व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था की अनुपूरक बनती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल देने की आवश्यकता

अतः भारत को अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने की जरूरत है। आज प्रमुखतः शहरी उद्योगों पर जोर दिया जाता है और कृषि पर ध्यान गौण रहता है। इस दृष्टिकोण को बदलना होगा—ग्रामीण कृषि तथा कृषि प्रधान उद्योगों के

सम्मिलित रूप पर प्रमुख बल देना होगा। यही हमारे स्वदेशी अर्थशास्त्र की नींव है, जिसमें सभ्यता, राजनीति और अर्थ के आयाम शामिल हैं और यह केवल विदेशों में तैयार किए गए माल के मुकाबले भारत में तैयार माल का मुद्दा नहीं है, जैसा कि हमारे कुछ आलोचक बताने का प्रयास कर रहे हैं।

विश्व बाजार का मिथक

विश्व बाजार एक भ्रम है, वस्तुतः यह शक्तिशाली देशों का खेल है। यही कारण है कि जापान एक शक्तिशाली देश होते हुए भी लगातार और कठोरता से अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया है। यही बात अमेरिका के बारे में भी सही है जो बाहर से और यूरोपीय समुदाय के देशों से प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए विशेष कानून बनाता है, यूरोपीय समुदाय के देश भी बहुतंत्रीय व्यवस्था तथा इसी प्रकार के अन्य तरीके अमल में लाते हैं। सभी देश विश्व के बाजार में माल बेचना चाहते हैं, खरीदना नहीं चाहते। विकास से जुड़े जापान के प्रख्यात अर्थशास्त्री श्री ओकीता ने बताया था कि किस तरह जापान ने आंतरिक उदारीकरण अपनाते हुए अपने विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा—संरक्षण प्रदान किए बिना जापान में न 'होंडा' होता, न 'निशान'। उन्होंने भारत को भी पूरी तरह से आंतरिक उदारीकरण किए बिना भूमंडलीकरण न करने का परामर्श दिया।

मराकेश समझौते में व्यापार समभाव का नियम नहीं है। इसमें भविष्य में लगातार व्यापार संघर्ष चलते रहने के आधारभूत नियम हैं। गैट के महासचिव पीटर सदरलैंड ने कहा है कि डंकल समझौता 'व्यापार संघर्ष की शुरुआत है, अंत नहीं।' जापान, कोरिया और ताइवान के शासन प्रमुखों ने इस समझौते को स्वीकार करने के लिए अपने लोगों से क्षमा याचना की है। यदि गैट सभी के लिए अच्छा है तो उन्हें अफसोस क्यों होता? परंतु भारत में प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक और वाणिज्य मंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक हमारे ये नेता भारत के लिए जैसे इस महान् संधि पर हस्ताक्षर कर अपने को शाबाशी दे रहे हैं।

भूमंडलीकरण गलत क्यों है

इसलिए भाजपा वर्तमान सरकार की भूमंडलीकरण नीतियों का विरोध करती है और जिस तेजी से एवं बिना सोचे-समझे वह ऐसे कार्य कर रही जैसे कि वह किसी के हुकुम पर चल रही हो, भाजपा इसका भी विरोध करती है। भाजपा की आपत्तियाँ जिस तर्क पर आधारित हैं उनका कोई उत्तर उनके पास नहीं है।

एक : भूमंडलीकरण सार रूप में विश्व स्तरों पर विपणन की व्यवस्था है जिसमें सभ्यता, समाज और अर्थव्यवस्था के रूप में भारत में जो मूल तत्त्व भिन्न है उनकी उपेक्षा की गई है। इसमें ऐसे तत्त्व हैं जो भारत की सभ्यता, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थापनाओं के प्रतिकूल है।

दो : इसमें उन समस्याओं का समाधान नहीं है जो विश्व बाजार से बाहर की समस्याएँ हैं, इसलिए इसमें भारत की भूख, गरीबी और बेरोजगारी की सर्वप्रधान समस्याओं का कोई समाधान नहीं है।

तीन : समाजवाद से उदारीकरण की तरफ अचानक बढ़ने के कारण एक तकनीकी आर्थिक आघात पहुँचेगा, जिसे इस देश की राजनीतिक और आर्थिक संप्रभुता को खोए बिना वहन नहीं किया जा सकता।

चार : इसका आधार व्यय-प्रमुख जीवन शैली है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत की भूमिका प्रमुख है और संरक्षण पर आधारित है। भारत में गृहस्वामी उपभोक्ता की अपेक्षा गृहस्थ अधिक हैं और खर्च की बजाय बचत करना अधिक पसंद करता है—इस कारण विश्व बाजार की आवश्यकताओं तथा भारत की बचत की स्वस्थ आदतों और संरक्षण की मानसिकता के बीच मेल नहीं बैठता है।

पाँच : इसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों और भागों को सक्रिय नहीं किया जा सकता है—वस्तुतः इसमें इनकी जानबूझकर उपेक्षा की गई है।

छह : इसने यह भ्रम पैदा किया है और बना रखा है कि भारत में विकास पूर्णतः और एकमात्र विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से ही किया जा सकता है—इस प्रकार विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को मूल मुद्दा बनाने से राष्ट्रीय प्रयासों की संपूर्ण बात ही जड़ से समाप्त हो जाती है, अपितु उपहासास्पद बन जाती है। इस तरह से देश का अपना विश्वास ही समाप्त होकर रह जाता है।

भूमंडलीकरण से उत्पन्न खतरा केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में नरसिंह राव सरकार ने भारत के 'अलग-थलग' होने की दुहाई देकर कुछ ऐसे निकृष्ट समझौते किए हैं जिनमें भारत की अर्थव्यवस्था और उसके सुरक्षा हितों पर ही बुरा प्रभाव पड़ा है।

प्रधानमंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा का अवसर ऐसा था जब भारत को अमेरिका का प्रिय बनने की खातिर अनेक राष्ट्रीय हितों की बलि दे दी गई। घटनाओं का क्रम इसका पर्दाफाश करता है।

लंदन में विफल वार्त्ता

पहले तो अमेरिकी विदेश विभाग की एक कनिष्ठ अधिकारी का जोर-शोर से स्वागत किया, जिसने जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय पर प्रश्नचिह्न लगाने की धृष्टता की। इनकी उपस्थिति इनती अप्रियकर थी कि गृहमंत्री को खुल्लमखुल्ला स्वीकार करना पड़ा कि यदि ऊपर से आदेश न होते तो वह उनसे नहीं मिलते।

दूसरे जब विदेश विभाग के उप सचिव स्ट्रोब टेलबाट प्रधानमंत्री से आमने-सामने बैठकर मिलने आए तो उन्होंने खबरदार कर दिया कि भारत को वाशिंगटन द्वारा

तैयार क्षेत्रीय अप्रसार समझौते के लिए सहमत होना पड़ेगा। सरकार ने लगभग मौन स्वीकृति दे दी। संसद् में रक्षा राज्यमंत्री ने स्वीकार किया कि भावी 'अग्नि' मिसाइल परीक्षण को रोक दिया गया है। सभी प्रकार की विखंडज सामग्री के उत्पादन को समाप्त करने के लिए शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय अधिकारियों को गुप्त रूप से लंदन भेजा गया। यह अलग बात है कि हमारे सतर्क प्रेस ने इस गोपनीयता का पर्दाफाश कर दिया और बातचीत विफल कर दी। इस बारे में प्रमुख मुद्दा यही है कि राव सरकार इस कार्यक्रम पर अमेरिका से बातचीत करने के लिए सहमत हुई।

अमेरिका के दबाव में मिसाइल परीक्षण स्थगित

लंदन में वार्त्ता असफल होने तथा इसके प्रति जन-आक्रोश के बावजूद सरकार अमेरिका के सामने झुकती रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अमेरिका के साथ सद्भावना के रूप में 'पृथ्वी' मिसाइल के परीक्षण को स्थगित करने का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री ने जरा भी परेशान हुए बिना लोकसभा में इस बात को स्वीकार किया।

भारत को निरीह अवस्था में डाल दिया

प्रश्न यह है कि यदि हमें निरीह और निर्बल अवस्था में देखा जाता है तो क्या अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हम सम्मान पा सकेंगे? और सरकार भारत को इसी निरीह अवस्था की ओर धकेल रही है। कहा जाता है कि हमारे पास कोई सार्थक विकल्प नहीं है। यदि हम इसी प्रकार आत्मसंशय और निराशा की स्थिति में रहेंगे तो हमारे पास कभी भी सार्थक विकल्प होगा ही नहीं।

राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहें

निस्संदेह अंतरराष्ट्रीय सम्मति का महत्त्व है। परंतु भारत को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के बारे में कभी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मति उपयोगी नहीं रही है। यदि सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय सम्मति और अलग-थलग पड़ने के भय से ग्रस्त होकर नीति-निर्धारण करते तो क्या वे 1948 में हैदराबाद में 'पुलिस कार्यवाही' का आदेश दे सकते थे? यदि अंतरराष्ट्रीय सम्मति के कारण हम भीरु बन जाते तो क्या हम 1960 में पुर्तगालियों से पुनः गोवा वापस ले सकते थे? उस समय कोई हमारे पक्ष में नहीं था। जब बीस वर्ष पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने पोखरण में अणु बम का परीक्षण करने की स्वीकृति दी थी तब भी हमारे साथ कोई नहीं था। जब सिक्किम ने स्वेच्छा से भारत में विलय का निर्णय लिया तो पूरे विश्व में हमारे विरुद्ध आक्रोश फैल गया था।

अलग-थलग पड़ जाने और अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार की थोथी दलील के पीछे

केवल प्रतिरोध न करने की नीति को स्वीकार करना है। यह केवल राष्ट्रीय भावना को चोट पहुँचाने का नुस्खा है और घुटने टेकने की सहज स्वीकृति है। यदि भारत स्वयं ही खड़ा नहीं होना चाहता तो बाकी दुनिया को उसे उठाने की क्या जरूरत पड़ी है। हमने स्पष्ट शब्दों में दुनिया को जाहिर कर दिया है कि हम निरीह और निर्बल हैं और वे मान लें कि यह वही भारत है जिसने 1962 में आर्डनेंस फैक्टरियों में काफी परकुलेटरों का निर्माण कर के जवानों को नीचा दिखाने के लिए कृष्ण मेनन को फटकारा था, तो क्या इस प्रकार के तुष्टीकरण से कुछ भला होने वाला है? मुझे संदेह है कि अपने डिलीवरी सिस्टम को टेक्नोलॉजी डेमांस्ट्रेटर बताने से हमारा कोई आत्मसम्मान बढ़ेगा।

हमें इस अवसाद और आत्मसमर्पण की मानसिकता से बाहर निकलने का रास्ता ढूँढ़ने की जरूरत है। हमें अलग-थलग पड़ जाने के निरर्थक भय से मुक्त होने की जरूरत है।

यह भी महसूस करना जरूरी है कि जब से पाकिस्तान को 1971 में शर्मनाक पराजय का मुँह देखना पड़ा है तब से वह बड़े तरीके से एक बार फिर मुकाबला करने की तैयारी और योजना बनाता रहा है। आतंकवादियों की हिंसा, बम विस्फोटों आदि के रूप में आई.एस.आई. के माध्यम से उसने जो एक छोटा सा युद्ध हमारे खिलाफ छेड़ रखा है, लगता है कि वह इससे कहीं गंभीर स्थिति पैदा करने की पूर्व भूमिका है। यह स्थिति विशेष रूप से और भी गंभीर बन जाती है जब हम देखते हैं कि सरकार की प्रतिक्रिया उतनी ही दुर्बल है जितनी स्वयं सरकार दुर्बल है।

भारत को परमाणु शक्ति बनना चाहिए

भाजपा ने लगातार आरंभ से ही परमाणु विकल्प का उपयोग करने की बात कही है। इसका कारण यह नहीं है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को डराना या धमकाना चाहता है, अपितु इसलिए कि हमारा विश्वास यह है कि हमारे पड़ोसी देश और महाशक्तिशाली देश हमें कभी डरा-धमका न सकें।

आज तो एक और बाध्यता भी है : लगता है कि एक दंभी और निरंकुश सुपर पावर ने भारत को अपने रक्षा आवरण के नीचे लाने का संकल्प किया हुआ है। अमेरिका की अप्रसार संधि संबंधी पहल के पीछे बिना कहे ही यह मान्यता है कि भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा वाशिंगटन के हाथों में सौंप देनी चाहिए और भारत को बस इतना करना है कि वह इस महाशक्ति के लिए अपने बाजार के दरवाजे निर्बाध रूप से खोल दे।

परमाणु अस्त्रों और मिसाइल प्रणाली पर चल रही बहस पर बहुत हद तक पश्चिमी देशों का प्रभाव है जिसमें प्रमुख रूप से अमेरिका का प्रभाव है और ये देश भी अपने राष्ट्रीय और सभ्यतामूलक हितों के लिए कार्य कर रहे हैं।

श्वेत विश्व को हावी नहीं होने देंगे

समग्र रूप से श्वेत विश्व अपनी वर्तमान और संभाव्य शक्ति के बारे में ही अधिक चिंतित है। यही कारण है कि वे परमाणु अस्त्रों और मिसाइल कार्यक्रमों के बारे में इतना दुराग्रही बने हुए हैं। भारत की बात छोड़िए, वे तुर्की को भी जो 'नाटो' (NATO) का सदस्य है, ऐसे हथियारों का विकास नहीं करने देना चाहते जिससे वह महाशक्ति बन सके।

परमाणु विकल्प का उपयोग

हमें दृढ़तापूर्वक और निर्भीक बनकर तथा अटल राष्ट्रीय संकल्प के साथ समुचित उत्तर देने की आवश्यकता है। भाजपा का विश्वास है कि परमाणु विकल्प का उपयोग करने के बारे में स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करके ही उन सभी को करारा जवाब दिया जा सकता है जो भारत को संप्रभुता से वंचित करने पर तुले हुए हैं। इस प्रकार की युक्ति से न केवल देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा स्वयं करने के प्रति दृढ़ निश्चयी बन सकेगा बल्कि भारत के आत्मसम्मान का अधिकार तथा उसकी अपनी सभ्यता की पहचान का दावा भी मुखर होगा। भारत को अपना महत्त्व स्थापित करने के लिए तनकर खड़ा होना ही है।

खाड़ी युद्ध के कुछ समय बाद ही भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल के. सुंदरजी ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि 'बड़े देशों द्वारा भारत के प्रति विवश कर देनेवाली नीतियों को हतोत्साहित करने के लिए 'भारत को परमाणु अस्त्र बनाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा था कि खाड़ी युद्ध ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि उन्नत परमाणु शक्ति ही शक्ति का द्योतक होंगे। जनरल सुंदरजी ने इस कटु सत्य को ही सामने रखा है। देश केवल खतरा मोल लेकर ही इसकी अनदेखी कर सकता है।

दक्षिण अफ्रीका का अभिवादन

दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना और रंगभेद के युग की समाप्ति इस वर्ष की अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना है। भाजपा दक्षिण अफ्रीका के लोगों का अभिवादन करती है और उन्हें अपनी शुभकामनाएँ देती है।

आज हम जब गुजरात में मिल रहे हैं तो महात्मा गांधी ने रंगभेद के खिलाफ लंबे और कठिन संघर्ष में जो अद्वितीय योगदान दिया था, उसे स्मरण करते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं। मैंने हैदराबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि हिंदुत्व भाजपा का वैचारिक मूलाधार है जो एक प्रकार से हमारी नीतियों और सिद्धांतों का आधार है। तथ्य यह है कि केवल भाजपा को ही हिंदुत्व

की आवश्यकता नहीं है, अपितु पूरे देश को ही इस वैचारिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

पिछले चार माह अनेक कारणों से त्रासदीपूर्ण रहे हैं। यदि हम दो अंकों में बढ़ी मुद्रास्फीति और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को यह मानकर नजरअंदाज कर भी दें कि ये तो कांग्रेस सरकारों के सामान्य प्रतीक हैं, फिर भी प्रत्येक समझदार भारतीय को भारतीय राष्ट्रत्व की विरोधी शक्तियों द्वारा राजनीति प्रणाली पर किए जा रहे प्रहारों के कारण आघात पहुँचना स्वाभाविक है।

गांधीजी पर आरोपों के पीछे कुत्सित इरादा

मैं विशेष रूप से उन दलों तथा व्यक्तियों द्वारा महात्मा गांधी पर लगाए जा रहे अशोभनीय आरोपों का उल्लेख करना चाहता हूँ जो कांग्रेस के समर्थन से बनी सरकार में भागीदार होने के कारण महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं। जब उत्तर प्रदेश में बसपा-सपा गठबंधन के नेता गांधीजी पर आरोप लगाते हैं और उन्हें जातिवादी समर्थक बताकर उनका अपमान करते हैं तो ऐसा करने के पीछे उनका विशेष प्रयोजन होता है।

गांधीजी एक राजनीतिक मिशनरी थे जिन्होंने बहुत पहले जान लिया था कि राष्ट्र तब तक अपना गौरव कायम नहीं रख सकता जब तक हिंदू समाज छिन्न-भिन्न अवस्था में है और आंतरिक कलह से ग्रस्त है। गांधीजी ने राष्ट्र की कायाकल्प के लिए हिंदुओं को संगठित करना अनिवार्य माना। आज गांधीजी की यही विरासत उन लोगों को बुरी लगती है जो जातिवाद और वर्गगत राजनीति से लाभ उठाना चाहते हैं।

उभरता जातिवाद

सपा-बसपा गठबंधन तथा अन्यत्र उन्हीं की विचारधारा रखनेवाले लोग जो कुछ कर रहे हैं उसे समझने में किंचित् भूल नहीं करनी चाहिए। उनके इरादे कुत्सित हैं। वे हिंदू समाज के ढाँचे को ही उखाड़ देना चाहते हैं, वे भारतीय को भारतीय से लड़ाना चाहते हैं।

इन राजनीतिज्ञों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जातिवाद की भावनाएँ भड़काने से कमजोर वर्ग के लोगों के दुःखों को बढ़ाने में ही मदद मिली है। उत्तर प्रदेश में सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति लगभग समाप्त होने के अलावा पिछले छह महीनों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार कई गुना बढ़ गए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंकुश भूमंडलीकरण से उत्पन्न सांस्कृतिक अव्यवस्था की पृष्ठभूमि में इस स्थिति को देखें तो समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार की विभाजनकारी राजनीति से भारत का नाम केवल भूगोल में रह जाएगा और उसकी

राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रत्व की भावना पूर्णतः मिट जाएगी।

हिंदुत्व के प्रति वचनबद्धता

इसी प्रसंग में हिंदुत्व की समसामयिकता और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि हम भाजपा के लोग निरंतर कहते हैं कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, यह धर्मतांत्रिक राज्य स्थापित करने का नुस्खा भी नहीं है। इसमें राष्ट्रत्व का सत्त्व और मूलाधार समाहित है। यह राष्ट्र को एकजुट करनेवाली सुदृढ़ शक्ति है। हिंदुत्व केवल अयोध्या में मंदिर नहीं है, यह तो हजारों वर्षों के भारतीय अनुभव की सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अक्तूबर 1961 में मदुरई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था—

"भारत पिछले अनेक युगों से तीर्थस्थलों का देश रहा है। पूरे देश में बर्फीली हिमालय पर्वतमाला में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक आपको प्राचीन स्थलों के दर्शन होंगे।

"इन महान् तीर्थयात्राओं में ऐसी क्या बात है जो लोगों को दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण की यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है? यह एक देश और संस्कृति की भावना है और इस भावना ने हम सब को जोड़ रखा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि भारत भूमि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैली हुई है।

"भारत को एक महान् देश समझने की अवधारणा युगों-युगों से चली आ रही है, जिसे लोग पावन भूमि मानते हैं और इसी अवधारणा ने इसे एक सूत्र में बाँध रखा है, हालाँकि यहाँ विभिन्न राजनीतिक स्वरूप के अलग-अलग राज्य रहे हैं और हम विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। फिर भी यह मृदुल बंधन हमें अनेक रूपों में इकट्ठा बाँधे रखता है।"

मृदुल बंधन

नेहरू ने 'हिंदू' शब्द का प्रयोग नहीं किया। परंतु भारत की एकता-संस्कृति के मृदुल बंधन का जो आधार स्पष्ट रूप से उन्होंने सामने रखा वह वही है जिसे भाजपा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व की संज्ञा दी है।

इस प्रकार हिंदुत्व वह आदर्श है जो भूत और भविष्य को वर्तमान से जोड़ता है। सार रूप में यही भारत की पहचान है। 'सेक्यूलरवाद' के नाम पर राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि यह देश अपनी पहचान भूल जाए। हिंदुत्व मात्र सिद्धांत नहीं है, इससे बढ़कर यह भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की वास्तविकता है। प्रतिशोधी कांग्रेसी सरकारों द्वारा कोई भी मनमाना कानून पारित करने से यह वास्तविकता मिट नहीं सकती है।

जब तक भारतीय सभ्यता है, हिंदुत्व का स्थान अटल है और भाजपा यह

सुनिश्चित करेगी कि हिंदुत्व के रूप में भारत की आत्मा ऐसे कठोर लोकतंत्र-विरोधी कानूनों पर हावी रहे। यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, यह हमारा मिशन है। आइए, यहाँ एकत्र हुए सभी प्रतिनिधि इस मिशन को पूरा करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने के लिए संकल्प लें। इससे भारतीय राजनीति में नैतिक और आचार संबंधी आधार फिर से स्थापित हो सकता है जिसे जातिवाद और सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति को चलानेवाले धीरे-धीरे समाप्त करते जा रहे हैं।

वंदेमातरम्



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

पटना 15–17 सितंबर, 1994

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का मैं आज की इस पटना की बैठक में स्वागत करता हूँ। एक और महत्त्वपूर्ण चुनाव–संग्राम होने जा रहा है और उससे तुरंत पूर्व हमारी आज की बैठक हो रही है। यह आगामी संग्राम दो दौर में होगा। पहला दौर दो महीने बाद होगा और दूसरा दौर, जिसमें इस बिहार प्रदेश की जनता भी मतदान करेगी, पाँच या छह महीने बाद होगा।

दस विधानसभाओं के चुनाव

इस बार के शक्ति परीक्षण में दस राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। इन दस राज्यों में से छह राज्य बड़े हैं और इन छह राज्यों का ही लोक सभा में कुल प्रतिनिधित्व 219 सदस्यों का है।

अतः हमारी इस पटना की बैठक के समक्ष एक प्रमुख विचारणीय विषय है—इस होने वाले लघु आम चुनाव के लिए विचार–विमर्श करना व संकल्प करना कि इस चुनाव में पार्टी अपनी प्रगति यात्रा का एक और महत्त्वपूर्ण चरण बनाएगी। विगत कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रगति की है उसने राष्ट्रीय स्तर पर एक द्वि–दलीय राजनीति को विकसित किया है। आगामी चुनावों में विभिन्न प्रदेश इसी दिशा में बढ़ें, इसकी कार्य–योजना बनानी है।

कांग्रेस : आत्मघाती मार्ग पर

कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की कृपा से उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार को एक फिर जीवनदान मिल गया है। वैसे यह सरकार आरंभ से ही सतत संकटग्रस्त रही है। पहले इसके अपने ही प्रत्यक्ष सहयोगी बसपा ने दो बार इस सरकार को पतन के कगार तक पहुँचा दिया था। फिर इसके परोक्ष सहयोगी कांग्रेस ने दुविधा पैदा की। मुलायम सिंह सरकार कुछ समय तक चिंताग्रस्त रही और

प्रदेश की जनता आशान्वित हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बड़े गाजे-बाजे से माँग की कि सरकार से जनता को छुटकारा दिया जाए। पर नई दिल्ली ने माँग को ठुकरा दिया।

विशुद्ध दलगत दृष्टि से देखें तो इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश कांग्रेस को जैसा अपमानित किया गया है वह भाजपा के लिए बहुत हितकारी है। वस्तुतः मेरी मान्यता है कि मुलायम सिंह सरकार को समर्थन जारी रखना राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से आत्महत्या के रास्ते पर चलना है। परंतु इस सरकार के सत्ता में बने रहने से राज्य के लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है तथा सामाजिक सद्भाव को भयंकर क्षति हो रही है। जिस दिन यह सरकार चली जाएगी, लोगों को राहत की साँस मिलेगी।

प्रधानमंत्री की महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

बडोदरा बैठक और इस वर्तमान बैठक के बीच तीन महीने के अंतराल में प्रधानमंत्री ने भाजपा के दृष्टिकोण से दो रोचक वक्तृत्व दिए हैं। यह महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ हैं। लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस को घोषणा की थी कि कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान से केवल इस पहलू पर बात कर सकता है कि पाकिस्तान कश्मीर पर अवैध रूप से जिस एक-तिहाई मार्ग पर से कब्जा किए हुए है, उसे वह कब खाली कर रहा है। सरकार ने इस तरह का दृष्टिकोण पहले कभी नहीं अपनाया था।

उनका दूसरा वक्तव्य जो मेरे ध्यान में आता है, वह उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस रैली को संबोधित करते हुए दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने जान-बूझकर मसजिद का उल्लेख छोड़ दिया था जिसके बारे में वह पहले कहते रहते थे।

यह खुला रहस्य है कि सरकार द्वारा बनाए जा रहे न्यास में शामिल होने के लिए जिन शंकराचार्यों को आमंत्रित किया है, सरकार ने उन्हें स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित राम मंदिर का निर्माण वहीं राम जन्मभूमि पर किया जाएगा जहाँ आज रामलला की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। जब कभी भी ऐसा होता है तो अयोध्या आंदोलन सफल हो जाएगा।

भाजपा की नीतियों की वैधता सिद्ध

आरंभ से ही जनसंघ और भाजपा ने आर्थिक विकास के नेहरू महालोनोबिस मॉडल की तीव्र आलोचना की है और अर्थव्यवस्था को नियंत्रण, विनियमों और नौकरशाहों से मुक्त करने का आग्रह किया है। केवल हमारी पार्टी ही इस्राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के पक्ष में रही है। आज पूरा देश हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार करता है।

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका यही होती है कि वह किसी खास मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण के लिए तब तक लोगों का समर्थन जुटाती रहे जब तक सत्ताधारी पार्टी को तीव्र जनमत के समक्ष अपना दृष्टिकोण बदलने पर विवश न कर दिया जाए। यदि सरकार समुचित प्रतिक्रिया व्यक्त न करें तो फिर स्वयं सरकार को बदल दिया जाए।

भाजपा का आज का एजेंडा कल देश का एजेंडा होगा

भाजपा महसूस करती है कि पाक अधिकृत कश्मीर तथा अयोध्या दोनों मामलों में जनमत सरकार को भाजपा का दृष्टिकोण स्वीकार करने पर विवश कर रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी को समान नागरिक संहिता या अनुच्छेद 370 को समाप्त करने अथवा बँगलादेश की ओर से किए जा रहे जनसांख्यिक आक्रमण या फिर उत्तरांचल, वनांचल और विदर्भ जैसे छोटे राज्यों के निर्माण के बारे में भी हमारे दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा।

इस प्रकार की टिप्पणी पढ़कर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस भाजपा के कार्यक्रम को उड़ा ले जा रही है, जैसे कि यह कोई ऐसी बात हो कि इससे भाजपा की छवि बिगड़ती हो। हमें इतना समझ लेना चाहिए कि यदि भाजपा का आज का कार्यक्रम कल देश का कार्यक्रम बन जाता है तो हमारे लिए यह गर्व और संतोष का विषय होगा।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

बंबई 17-18 दिसंबर, 1994

अगले चुनावों की योजना

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस मास के अंतिम सप्ताह में नागपुर में रखी गई थी, परंतु जब विधानसभा चुनावों के अगले दौर के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई और यह स्पष्ट हो गया कि विभिन्न राज्यों की चुनाव अधिसूचनाएँ जनवरी 1995 के आरंभ में जारी होना शुरू हो जाएँगी तो आवश्यक हो गया कि कार्यकारिणी की बैठक पहले की जाए, ताकि राज्य इकाइयों को पार्टी के उम्मीदवारों की सूची के चयन, सिफारिश और अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए।

अतः राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक स्थल और इसकी तारीखों दोनों को ही बदलना पड़ा। इस कारण कार्यकारिणी के सदस्यों और राज्य इकाइयों, विशेष रूप से नागपुर एवं बंबई शाखाओं को जो असुविधा हुई है, उसके लिए मुझे खेद है।

हाल में प्रमुख चुनावी संघर्ष समाप्त हुआ है। दक्षिण के दो राज्यों में कांग्रेस पार्टी लगभग समाप्त हो गई है, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। 1991 में कांग्रेस दक्षिण राज्यों के कारण ही नई दिल्ली में सत्तासीन हुई थी और अब साढ़े तीन वर्ष बाद आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक इन दो राज्यों में कांग्रेस को स्पष्टतः नकार दिया गया है।

इस संक्षिप्त बैठक में हमारा प्रमुख कार्य इस चुनाव परिणाम के फलितार्थ का मूल्यांकन करना है और इस आधार पर अगली चुनाव लड़ाई के लिए योजना बनानी है।

कांग्रेस में खलबली

आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में कांग्रेस की बुरी तरह पराजय का तुरंत प्रभाव तो यह हुआ है कि कांग्रेस पार्टी में तीव्र हलचल मच गई है और नए सिरे से यह

प्रयास शुरू हो गए हैं कि श्री पी.वी. नरसिंह राव को, यदि सरकार से नहीं तो कम-से-कम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से हटा दिया जाए।

देश को कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह से कोई मतलब नहीं है। भाजपा मानती है कि इस बार चुनाव परिणामों ने केवल कांग्रेस के नेता के विरुद्ध नहीं अपितु पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अविश्वास की अभिव्यक्ति की है।

लगभग इस पूरे सप्ताह में सरकार के चीनी घोटाले के बारे में ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट के निष्कर्षों को उद्घाटित करने से इनकार करते रहने के कारण संसद् का कार्य ठप्प रहा। अंततः सरकार संसद् के पुस्तकालय में रिपोर्ट रखकर इस मुद्दे के समाधान के लिए सहमत हुई। एक प्रकार से उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को फिर से एक बार प्रमुखता देने में सफल हुई है।

किंतु यह दुर्भाग्य ही है कि जो कुछ बैंक घोटाले में हुआ, उसकी फिर से पुनरावृत्ति हुई है। पहले घोटाले में श्री पी. चिदंबरम् को अपनी आहुति देनी पड़ी थी, जबकि मानना होगा कि वे घोटाले से सीधे नहीं जुड़े थे और अब इस बार नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री ए.के. एंटनी हैं, जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, हालाँकि वह इस सरकार के कुछ गिने-चुने ईमानदार मंत्रियों में से एक माने जाते हैं।

तीन गंभीर पाप

भाजपा कांग्रेस को तीन गंभीर पापों का दोषी मानती है, जैसे—

(क) क्षुद्र चुनावी लाभों के लिए राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करना तथा इस प्रक्रिया में देश की सुरक्षा को खतरे में डालना;

(ख) कुत्सित राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि की खातिर सामाजिक हितों की कुर्बानी देना तथा इसके द्वारा जातिवादी एवं सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना; और

(ग) कुछ थोड़े से इने-गिने लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए जनसामान्य के आर्थिक हितों के साथ समझौता करना, जिससे हर तरफ भ्रष्टाचार फैलना।

मैं अपने इन आरोपों के समर्थन में आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ—

नदवा प्रकरण

नदवा प्रकरण सचमुच आघात पहुँचानेवाला प्रकरण है। इस मामले में आई. एस.आई. एजेंटों के खिलाफ पूर्णसिद्ध प्रमाण थे। विदेशियों के अपहरण में गिरफ्तार किए गए कुछ उग्रवादियों से इकट्ठा पुख्ता सबूतों के आधार पर आई. बी. तथा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लखनऊ में नदवा कॉलेज पर छापा मारा। कॉलेज के अधिकारियों द्वारा असहयोग के बावजूद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, किंतु राज्य सरकार ने सुरक्षा अधिकारियों को इन गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ने पर विवश कर दिया। न केवल मुलायम सिंह सरकार बल्कि केंद्र सरकार ने भी इस छापे के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की। इससे भी बढ़कर

तो यह बात है कि आई.बी. और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए दंडित किया गया।

सचमुच यह अत्यंत लज्जा की बात है कि आई. एस. आई. के विरुद्ध की गई वैध कारवाई को अल्पसंख्यकों को परेशान करने का मामला बना दिया गया। यह सब कुछ मात्र वोट बैंक राजनीति की खातिर किया गया। श्री मोइली ने नदवा के कारण कर्नाटक में कांग्रेस की 'पराजय' को खुलेआम स्वीकार किया है। वस्तुतः कांग्रेस पार्टी की यही मानसिकता है जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सकती।

हाल में ही इसरो (ISRO) में एक गंभीर जासूसी षड्यंत्र का पता लगा है। पाकिस्तान की आई.एस.आई. तथा अन्य देशों की कुछ गुप्तचर एजेंसियाँ क्रायोजेनिक इंजन के कुछ हिस्सों और बहुमूल्य मानचित्रों को उड़ाने की कोशिश में लगी रहीं। पिछले वर्ष अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के अनुसंधान विभाग ने विश्व भर में राज्य-प्रायोजित आतंकवादी दस्तावेजों से पुष्ट एक रिपोर्ट में बल दिया है कि भारत में पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद का लक्ष्य मात्र कश्मीर नहीं है; समग्र रूप से इसका लक्ष्य भारत को अस्थिर बनाना है। बंबई में विस्फोटों की क्रमिक घटनाएँ तथा इसके बाद कलकत्ता, मद्रास एवं अन्य स्थानों में बम विस्फोटों की घटनाएँ इस मूल्यांकन की सत्यता को सिद्ध करती हैं।

वर्तमान सरकार की घुटना टेक नीति तथा इन गतिविधियों के प्रति सरकार का ढुलमुल रवैया स्पष्ट करता है कि इस सरकार के सत्ता में रहते हुए राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा बना रहेगा।

उत्तरांचल

उत्तरांचल के लोगों के खिलाफ मुलायम सिंह सरकार की लड़ाई निर्बाध रूप से जारी है। मुजफ्फरनगर में बलात्कार करनेवाले अपराधी देश के सबसे बड़े राज्य में यथावत् सत्ता में बने हुए हैं; राज्य में अपराधी और माफिया गिरोहों की मौज बनी है। सरकार के इस आदेश से न तो न्यायपालिका और न ही विधानसभा के सदस्य बच पाए हैं। सरकार की आलोचना करनेवाले समाचार-पत्रों पर प्रत्यक्षतः आक्रमण किए गए हैं। मुलायम सिंह इन अपराधों के बावजूद केवल इसलिए मजे से चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली में बैठी राव सरकार का संरक्षण और वरदहस्त प्राप्त है।

वस्तुतः उत्तर प्रदेश एक ऐसा मामला है जहाँ राज्य में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू करना न केवल न्यायोचित है, अपितु ऐसा न करने का अर्थ यह है कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत अपना कर्तव्य निर्वाह करने में चूक रही है।

यहाँ ध्यान देने की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गठबंधन के सहयोगी दलों में एक का दावा है कि वह ही पूरी तरह से दलितों के हितों के लिए है और

फिर भी यही राज्य है जहाँ दलित पुरुषों और महिलाओं दोनों पर बुरे-से-बुरे अत्याचार देखने को मिले हैं।

उदारीकरण ठीक है, भूमंडलीकरण गलत है

भाजपा कांग्रेस द्वारा देश पर आरोपित लाइसेंस कोटा राज के सदैव विरुद्ध रही है। अतः हम आंतरिक उदारीकरण के पक्षधर रहे हैं, अर्थात् नियंत्रण और नियम-विनियमों के बंधन हटाए जाएँ।

परंतु उदारीकरण के नाम पर नई दिल्ली की केंद्र सरकार उदारीकरण के मोहपाश में इस तरह बँधी है जिससे हमारे जैसे देश में न केवल बेरोजगारी की समस्या गंभीर हो सकती है बल्कि अमीर और गरीब के बीच की खाई और अधिक चौड़ी हो जाएगी।

उदारीकरण विकासशील देशों के लिए वरदान नहीं

पॉल केनेडी ने अपनी पुस्तक 'द राइज एंड द फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स' में जोर देकर कहा है कि विकसित देशों तक में उदारीकरण बेबाक वरदान नहीं है, किंतु विकासशील देशों में इसके परिणाम निश्चय ही लगभग विनाशकारी हैं।

अपनी नवीनतम पुस्तक 'प्रीपेयरिंग फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी' में केनेडी लिखते हैं—

"मान लें कि कोई सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर स्कूलों, स्वास्थ्य, आवास और सार्वजनिक उपयोगिताएँ प्रदान करने के लिए सजग रूप से प्रयास करती है तो वह इन अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के कान खड़े किए बिना किस प्रकार आवश्यक धन जुटा सकती है, क्योंकि इन देशों को अपने लाभ को छोड़कर उस देश के नागरिकों के कल्याण में जरा भी रुचि नहीं होगी? एक युक्तियुक्त बाजार की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उसका सामाजिक न्याय और औचित्य के साथ कोई सरोकार नहीं रहता है।"

केनेडी आगे कहते हैं—"भूमंडलीकरण का एक और परिणाम यह होगा कि अधिक प्रगतिवाले देशों की कंपनियों द्वारा विकसित नई तकनॉलाजियों से उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों में लाखों नौकरियों के स्थान पर अन्य साधनों के उपलब्ध करा देने के कारण लाखों नौकरियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे अधिक निर्धन वर्ग के समाजों को बहुत हानि हो सकती है।"

2000 मेगावाट की डाभोल विद्युत् परियोजना इसका उदाहरण है कि राष्ट्र के आर्थिक हितों को एक प्रभावशाली बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों गिरवी रख दिया है। कहा जाता है कि वित्तमंत्री ने इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को किसी प्रकार की गारंटी देने के बारे में आपत्ति की, परंतु उनके कथनानुसार इस बारे में संबंधित विभाग के मंत्री और प्रधानमंत्री की राय अंततः हावी रही।

नागपुर त्रासदी

गत मास नागपुर में जो भयावह घटना घटी, जिसमें 110 निर्दोष पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के प्राण चले गए, इससे पता चलता है कि सत्तासीन कांग्रेस कितनी निर्दयी और संवेदनहीन है कि न तो मुख्यमंत्री को और न ही किसी मंत्री को घटनास्थल पर जाने तथा उनसे मिलने का तथा उन 50,000 गवारियों की वैध शिकायतें सुनने का समय मिला, जो विधानसभा के बाहर इकट्ठे हो गए थे।

कांग्रेस समर्थन से शासित उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। परंतु जनता दल शासित बिहार में तो स्थिति इससे भी अधिक खराब है, जहाँ लालू सरकार ने जातिवाद और अपराधीकरण को पूरे प्रदेश में फैला दिया है। सभी वर्ग के लोगों में अराजकता फैली है। शिक्षा पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है। कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता है।

ऊपर दिए गए उदाहरण केवल इस बात के संकेतक हैं कि किस हद तक बिखराव घर कर गया है। वस्तुतः पूरे देश की स्थिति कहीं अधिक खतरनाक है। जो कुछ हो रहा है, उससे आदमी बहुत घबराया हुआ और चिंतित है और बहुत उत्कंठापूर्वक आशा बाँधे बैठा है कि शायद यह थोड़े समय का संक्रांतिकालीन दौर है।

कांग्रेस का पतन अवश्यंभावी

कांग्रेस के इस पतन से पुनः उठने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। वर्तमान चुनावी दौर के बाद पार्टी के नेता जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उससे लगता है कि पतन की गति इससे भी अधिक तेज हो सकती है।

कुछ समय से इस बढ़ते जा रहे शून्य के कारण क्षेत्रीय अर्द्ध-क्षेत्रीय दलों के इकट्ठा होने की बात को बढ़ावा मिला है, जिसके द्वारा इस शून्य को भरने का प्रयास किया जा रहा है। भूतकाल में केंद्र में इसी प्रकार के गठबंधनों की दुर्गति देख कर औसत भारतीय नागरिक इस तरह की संभावना से जरा भी उत्साहित नहीं होता है। जो लोग इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि कुछ विदेशी ताकतें खामख्याली में भूतपूर्व सोवियत संघ के समान भारत का हश्र होने की प्रतीक्षा में हैं और वस्तुतः यही ताकतें इस प्रकार की संभावना का डर दिखाती हैं।

इस स्थिति में भाजपा पर ज़बरदस्त जिम्मेदारी आती है, जो धीरे-धीरे, परंतु निश्चित रूप से कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प बनती जा रही है। कर्नाटक में भाजपा की सफलता इस दिशा में महत्त्वपूर्ण छलाँग है।

अगले वर्ष फरवरी में हो रहे पाँच राज्यों के चुनावों के लिए इस समय भाजपा इकाइयाँ अपने घोषणा पत्र तैयार कर रही हैं, जिनमें वहाँ की विभिन्न स्थानीय और प्रदेशीय समस्याओं के प्रति पार्टी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जाएगा। इस दृष्टिकोण का सामंजस्य पार्टी के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ बिठाना होगा।

इस दृष्टिकोण के प्रमुख तत्त्व इस प्रकार हैं—

1. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति वचनबद्धता

राष्ट्रीय सुरक्षा, कश्मीर, अयोध्या, सेक्यूलरवाद, बँगलादेश से जनसांख्यिकीय घुसपैठ, समान नागरिक संहिता, हुबली इत्यादि के बारे में हमारा दृष्टिकोण इसी वचनबद्धता से उभरकर आते हैं।

2. मूल्य-आधारित राजनीति के प्रति वचनबद्धता

भ्रष्टाचार, जातिवाद, अपराधीकरण और वोट बैंक राजनीति के विरुद्ध हमारा धर्मयुद्ध इसी वचनबद्धता की शाखाएँ हैं।

3. स्वावलंबी अर्थव्यवस्था के प्रति वचनबद्धता :

उदारीकरण के प्रति हमारी सीमित आपत्तियाँ, स्वदेशी के प्रति हमारी आस्था तथा ऋण-मुक्त भारत की ओर बढ़ने के हमारे संकल्प में इसी वचनबद्धता की जड़ें जमी हैं।

4. मित्रो! आइए हम आगामी महीनों में तीन शब्दों को वर्चस्व प्रदान करें—

सुरक्षा, शुचिता, स्वदेशी।

पिछले कुछ वर्षों में भाजपा के दृष्टिकोण के बारे में की गई टिप्पणियाँ दो उक्तियों के बीच घूमती रही हैं।

"वह केवल बस एक मुद्दे 'अयोध्या' पर आश्रित है" और "अब उसने अयोध्या को पीछे डाल दिया है।"

हमें इन उक्तियों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है।

पहली उक्ति के कारण रामजन्म स्थान पर भव्य राममंदिर निर्माण करने के हमारे संकल्प के बारे में हमें कभी भी क्षमा प्रार्थी होने की आवश्यकता नहीं है और दूसरी उक्ति के कारण हमें अपनी उस समग्र दृष्टि का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है जिसे भाजपा ने सदैव राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं के लिए अपनाया है।

वंदेमातरम्!



राष्ट्रीय परिषद्

बंगलौर 18-20 जून, 1993

स्वागत समिति के अध्यक्षजी, प्रतिनिधि भाइयो और बहिनो तथा प्रतिष्ठित अतिथियो!

सर्वप्रथम मैं भाजपा की राष्ट्रीय परिषद् के आप सब सदस्यों का इस बात के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझ में पुनः विश्वास व्यक्त किया तथा इस महान् पार्टी का मुझे पुनः अध्यक्ष चुना। विशेष रूप से मैं डॉ. मुरली मनोहर जोशी का आभारी हूँ जिन्होंने इस उच्च पद के लिए मेरे नाम का प्रस्ताव किया। उनके नेतृत्व में गत ढाई वर्षों में पार्टी ने असीम प्रगति की है।

अविस्मरणीय स्मृतियाँ

हम आज यहाँ बंगलौर में मिल रहे हैं और महीना भी जून का है। इस सभा के स्थान और समय, दोनों ने मेरे मानस में अंकित गहरी स्मृतियों को फिर से ताजा बना दिया है। 18 वर्ष पहले जून 1975 में मैं श्री वाजपेयी के साथ एक संसदीय समिति की दो दिवसीय बैठक में यहाँ आया था। उन दिनों हम यहीं थे जबकि देश पर एक क्रूर वज्रपात हुआ—आपातकाल लागू हो गया। कर्नाटक विधायक निवास में हमारा दो दिवसीय निवास बंगलौर केंद्रीय जेल में 19 महीने की कैद में बदल गया। देश के वरिष्ठ नेता श्री जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी देसाई भी जेल में डाल दिए गए। रा.स्व.संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जनसंघ और रा.स्व.संघ के हजारों कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। 42वें संशोधन द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी ने उस तानाशाही तंत्र को स्थायी बनाना चाहा जिसमें कानून का राज्य अर्थहीन हो चुका था।

निस्संदेह जब जनता को 1977 में एक चुनावी मौका मिला तो लोकतंत्र के विरुद्ध अपराध करनेवाले उन सभी को जनता ने उनके योग्य सबक सिखाया।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस को बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी और नई दिल्ली में सरकार बदली। मुझे यह स्मरण करते हुए गर्व होता है कि लोकतंत्र की बहाली के इस ऐतिहासिक संघर्ष में जनसंघ, रा.स्व.संघ और हमारे सहयोगी संगठनों ने प्रमुख भूमिका निभाई।

मैंने यह सब स्थान और समय के संयोग के कारण ही याद नहीं किया है, बल्कि इसलिए भी, क्योंकि मैं यह बड़ा पाखंडपूर्ण मानता हूँ कि जिस पार्टी ने तब लोकतंत्र को समाप्ति के कगार पर ला खड़ा किया था, अब पिछले कुछ महीनों से वही भाजपा को कानून के राज्य और लोकतंत्र की पवित्रता के बारे में उपदेश दे रही है।

भाजपा विरोध का उन्माद

पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी ढाँचे के विध्वंस के बाद से देश में भारतीय जनता पार्टी, रा.स्व.संघ, वि.हि.प. तथा संघ परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ एक अत्यंत तीखा और प्रायः पागलपन भरा अभियान देख रहा हूँ। हम पर तोड़-फोड़ करनेवाले, लंपट, फासिस्ट और कट्टरपंथी जैसे आरोप लगाए गए हैं। हमारे विरोधियों को हमें बुरा-भला कहने के लिए कोई भी शब्द स्तरहीन नहीं लगता।

पर इस पागलपन से एक उद्देश्य भी पूरा हुआ। देशभक्त संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने, भाजपा सरकारों की बरखास्तगी तथा पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और परेशान करने जैसी घटनाओं से हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है तथा उसने हमें आगामी चुनौतियों के बारे में और सचेत किया है। आपातकाल के काले दिनों की ही तरह हमने इस बार भी गरिमा और दृढ़ संकल्प के साथ दमन तथा झूठे आरोपों को झेला है। इससे निस्संदेह हम सामान्य जनता के और अधिक प्रिय बने हैं, जो कि यह देखकर अचंभित हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू दृष्टिकोण तथा राष्ट्रवाद के विचार लेकर खड़े होना एक अपराध क्यों माना जाना चाहिए?

मंदिर निर्माण रोकना असंभव

हमारे विरोधियों को अयोध्या के बारे में एक बात समझ लेनी चाहिए। अयोध्या में श्रीराम के जन्म-स्थान पर राम मंदिर के निर्माण का अभियान भले ही साधुओं, वि.हि.प. तथा रा.स्व.संघ द्वारा प्रारंभ किया गया है, भाजपा ने उसे अपना पूरा समर्थन दिया है और यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अब यह संपूर्ण राष्ट्र का संकल्प है न कि मात्र किसी संगठन या पार्टी की आकांक्षा।

जनता के संकल्प को विफल करने का कोई भी प्रयास निश्चित रूप से

असफल होगा ही। मुझे आशा है कि अयोध्या में हाल ही में सोम यज्ञ की असफलता ने सभी संबंधित लोगों को इसे पर्याप्त स्पष्ट कर दिया होगा।

निस्संदेह हमारे खिलाफ जहर भरे ढंग से पीछे पड़ने और लोकतांत्रिक व्यवहार की सभी मर्यादाओं को तोड़कर हमारे विरोधियों ने अनजाने ही हमारा बड़ा भला किया है।

पहले तो उन्होंने स्वयं यह उजागर कर दिया है कि वे जन–मानस से कितने अलग–थलग पड़ गए हैं। 'शर्म से कहो हम हिंदू हैं' जैसे नारों ने उन संगठनों और व्यक्तियों से लोगों का मन उचाट करने में ही सहयोग दिया है जो समाज से अपने अलगाव को ही बड़ा गुण मान बैठे हैं। दूसरे, हमारे विरोधियों के अभियान ने इस मान्यता को फिर से दृढ़ किया है कि भाजपा अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट और विशिष्ट है।

एक नया ध्रुवीकरण

हमको अलग–थलग करने की कोशिश में हमारे विरोधियों ने राजनीतिक ध्रुवीकरण की कसौटी स्थापित करने में मदद की है। आज यह विभाजन कांग्रेस और कांग्रेस विरुद्ध विपक्ष में नहीं रह गया है, बल्कि भाजपा और भाजपा–विरोधियों में है। देश के सम्मुख विषयों का निर्धारण हम करते हैं और हमारे विरोधी केवल उनपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

1977 और 1980 के बीच जनता प्रयोग तथा 1989 और 1990 के और भी संक्षिप्त राष्ट्रीय मोरचे के नेतृत्व ने यह स्पष्ट दिखा दिया है कि नकारात्मक पहलू पर नए भारत का निर्माण संभव नहीं है। जिस तरह हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि हम किन बातों का विरोध कर रहे हैं, उसी तरह उन मुद्दों के बारे में भी स्पष्ट होना चाहिए जिनका हम समर्थन कर रहे हैं। भा.ज.पा केवल चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए ही कार्यरत नहीं है। हालाँकि यह भी महत्त्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्त्व की बात यह है कि भाजपा एक नए उभर रहे और आधुनिक भारत के स्वप्नवाली पार्टी है और यही बात हमें अपनी विशिष्टता के मूल बिंदु अर्थात् हिंदुत्व की अवधारणा तक ले जाती है।

आजकल कुछ क्षेत्रों में भाजपा पर गैर–सेकुलर होने और राजनीति में धर्म का मिश्रण करने का आरोप लगाना फैशन की बात हो गई है। इस बात की पड़ताल की जानी चाहिए। हाँ, भाजपा ने जानबूझकर स्वयं को आज के सरकारी वोट बैंक वाले सेकुलरवाद से अलग रखा है। हमने तो उसे छद्म सेकुलरवाद तक कहा है। भाजपा, जैसा कि मार्क्सवादी खुलेआम कहते हैं या मार्क्सवाद से प्रभावित अन्य सेकुलरवादी मानते हैं, इस बात में विश्वास नहीं करती कि धर्म जनता के लिए अफीम है और इसलिए एक निधर्मी समाज की रचना का उद्देश्य ही आदर्श है। हम इस बात पर भी विश्वास नहीं करते कि राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया

बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के लिए दोहरे मापदंड अपनाकर या दूसरे शब्दों में, अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देकर प्रोत्साहित की जा सकती है।

भाजपा धर्मतंत्र की विरोधी

भाजपा भारतीय संविधान के सेकुलर तत्त्वों से प्रतिबद्ध है। पहले, मजहबी राज्य को अस्वीकार करना, दूसरे बिना पंथ या मजहब का भेदभाव किए सभी नागरिकों की समानता और तीसरे, विश्वास और उपासना पद्धति की पूर्ण स्वतंत्रता। हमारा विश्वास है कि मजहबी राज्य हमारी संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। वस्तुतः हम तो यह मानते हैं कि भारत हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण ही सेकुलर है।

सभी राज्यों के कानून में समानता अनिवार्य

लेकिन इतिहास बताता है कि तुष्टीकरण भी विभाजन नहीं रोक पाया। कश्मीर में धारा 370 ने एक ऐसे भावनात्मक पृथक्तावाद को बढ़ाया, जिसने अलगाववाद की और वर्तमान भटकाव की जमीन तैयार की। यदि देश की एकता बचानी है तो इसके लिए सबसे पहले कानून के सामने सबकी पूर्ण समानता अनिवार्य है। यह कोई मध्ययुगीन अवधारणा नहीं है, बल्कि राज्यतंत्र के सबसे आधुनिक आदर्शों से उपजा सिद्धांत है।

बहरहाल, न्यायपूर्ण समाज की रचना के लिए समान कानून आवश्यक तो हैं, परंतु केवल वही पर्याप्त नहीं है। उतना ही महत्त्वपूर्ण है राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करना, जो जनता के ऐतिहासिक अनुभव तथा सांस्कृतिक परंपराओं की अभिव्यक्ति करती हो तथा जो, जैसे कि भारत के मामले में, जनता की भीतरी एकता को प्रतिबिंबित करती हो। यही वह भावना है जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं। किसी विशिष्ट उपासना पद्धति या कर्मकांड से जुड़ाव नहीं, बल्कि भारत के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक अनुभव का कुल योगफल हिंदुत्व है। हमारी दृष्टि में हिंदुत्व इस देश के मूल्यों, नैतिकता बोध तथा आकांक्षाओं अर्थात् भारतवर्ष की सभ्यता के प्रति प्रतिबद्धता का नाम है।

राज्य और समाज के विषम संबंध हानिकारक

हिंदुत्व की रचना भाजपा ने नहीं की, हमने इसे केवल उभार दिया है। यह राष्ट्रीय चेतना तो अनादिकाल से विद्यमान रही है। भाजपा ने तो हिंदुत्व की इस अकाट्य वास्तविकता का मात्र उपयोग उस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए किया है, जो हमेशा बाहर से प्रेरणा लेती रही लेकिन अपने राष्ट्र-जीवन की सांस्कृतिक जड़ों को स्वीकार करने से मना करती रही। वास्तव में छद्म-सेकुलरवादी चाहते हैं कि यह देश अपने व्यक्तित्व को ही नकार दे। यदि देश में हताशा और

उत्साहहीनता है तो उसके लिए बड़ी मात्रा में दोषी वे हैं जो गत चार दशकों से भारत को उसकी स्वाभाविक मूल व्यवस्था से दूर ले जाने का प्रयास करते रहे हैं। इसने हमारी जनता को भ्रमित किया है, राज्य तथा नागरिक समाज के बीच बेमेल संबंध पैदा किया है और परिणामतः आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता को कमजोर किया है।

जिन संकटों ने हमारे समाज को घेरा हुआ है, हिंदुत्व उनकी रामबाण औषधि नहीं है, किंतु वह आत्मविश्वास से उन आघातों का मुकाबला करने का नैतिक आधार तो कम-से-कम बनाता ही है। अपनी जड़ों से कटने और अपनी हर बात पर शक करने की प्रवृत्ति ने भारत में जो भयंकर विनाश किया है, उसे हम देख चुके हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार तथा अवसरवाद को खुलेआम बढ़ावा देकर हमारे समाज की नैतिक जिजीविषा को कमजोर कर पूरे देश का मान घटाया है। उसने जोड़-तोड़ को सार्वजनिक जीवन चलानेवाले नियंत्रक सिद्धांत के दर्जे तक बढ़ा दिया है।

प्रस्तावित कानून

इसलिए आश्चर्य नहीं कि अब कांग्रेस राजनीति से धर्म को बहिष्कृत करने के लिए कानून बनाना चाहती है। मजहबी कठमुल्लापन ऐसा रोग है जो सामाजिक समरसता को तोड़ता है। इसी प्रकार जातिवाद और भाषाई कठमुल्लापन है। चुनावी कानूनों में मजहब, जाति, भाषा आदि के नाम पर वोट लेने के लिए की गई विकृत, संकीर्ण अपीलों के विरुद्ध काररवाई की व्यवस्था पहले से ही है।

हिंदुओं को लांछित करने का प्रयास

प्रस्तावित कानून का चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ करने से कोई लेना-देना नहीं है। अनिवार्यतः वह भाजपा की बाढ़ को रोकने का एक बौखलाहट भरा कदम ही है। आम आदमी को यह विधेयक हिंदुओं को लांछित करने का एक और तथा विकृत उदाहरण ही प्रतीत होगा।

धर्म के प्रति अधिकांश राजनीतिज्ञों का रुख यह प्रकट करता है कि वे यह समझ पाने में असमर्थ रहे हैं कि भारतीय जनता की धर्म में कितनी गहरी आस्था है।

काश, राष्ट्रध्वज के अपमान को प्रतिबंधित करने के लिए कानून होता। एक कानून ऐसा होता जो अनाप-शनाप फतवों पर रोक लगाता और राष्ट्र-विरोधी प्रचार के लिए मजहबी मंच के दुरुपयोग के खिलाफ एक कानून बनता। लेकिन सरकार और सेकुलरवादी इस तरह की गलत बातों के प्रति आँखें बंद रखते हैं। जानबूझकर या अनजाने में उनका निशाना वे ही आचारपरक नैतिक नियम होते हैं जो कि जनता के मानस की रचना करते हैं और जिन्हें हम धर्म के नाम से

पुकारना अधिक उचित समझते हैं। हमारी संस्कृति और हमारा राष्ट्रीय मानस अविभाज्य रूप से इस धर्म से जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता इन्हीं तत्त्वों को हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का प्रयास करते रहे।

वर्तमान राजनीतिक समस्या : धर्मविहीन राजनीति

यह एक दुःखद विडंबना है कि स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक शिकागो वक्तृता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनांदोलन के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में लोकमान्य तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए गणेशोत्सव के शताब्दी वर्ष में आज के शासक गंभीरतापूर्वक एक ऐसा कानून बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो भारत से उसकी आत्मा को छीन लेगा। गांधीजी ने एक बार टिप्पणी की थी–

"मेरे अनेक राजनीतिक मित्र मुझसे इसलिए हताश होते हैं, क्योंकि उनके अनुसार मेरी राजनीति भी धर्म से उद्भूत है और वे ठीक कहते हैं। मेरे लिए धर्म से विहीन राजनीति हमेशा दूर रखने योग्य पूर्णतः गंदगी है।" (द माइंड ऑफ महात्मा गांधी, ले. आर. के. प्रभु और यू. आर. राव)।

आज की राजनीतिक समस्या यह नहीं है कि उसमें बहुत अधिक धर्म विद्यमान है बल्कि यह है कि उसमें बहुत कम धर्म है। इस असंतुलन को दूर करना भाजपा के राम राज्य की कल्पना के मूल में है–एक न्यायपूर्ण राज्य, एक नैतिक राज्य और एक शक्तिशाली राज्य।

अल्पसंख्यक और भाजपा

भाजपा का मत है कि गैर-भाजपा पार्टियों द्वारा की गई अल्पसंख्यकवाद की राजनीति ने केवल राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचाई है। इस नीति से भले ही इन राजनीतिक दलों को कुछ चुनावी फायदा हुआ होगा, कुछ अल्पसंख्यक नेताओं ने राजनीतिक ताकत हासिल कर ली होगी, लेकिन इसने निश्चित रूप से मुसलमानों का तो भला नहीं किया है, जो आजादी के 46 वर्षों के बाद भी एक समुदाय के रूप में आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ही हैं।

भाजपा मुसलिम भाइयों से आग्रह करती है कि वे इस कठोर वास्तविकता पर विचार करें। उनके हित इन दो बातों में ही निहित हैं–एक तो, वे स्वयं को वोट बैंक के हिंदू और मुसलिम दोनों दलालों के शिकंजों से मुक्त करें और दूसरे, जितना अधिक वे दे सकें शिक्षा पर ध्यान दें।

जहाँ तक भाजपा का संबंध है, मैं मुसलमानों से आग्रह करूँगा कि वे हमारे विरोधियों के रंगीन चश्मों से हमें न देखें बल्कि हमारे पिछले कामकाज के आधार पर हमारे बारे में फैसला करें। वे पाएँगे कि भाजपा सरकारें ही हैं जो कि वास्तव

में समाज के सभी वर्गों को, चाहे वे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक, सुरक्षा, न्याय और समानता की गारंटी देने में समर्थ रही है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि वास्तव में आम मुसलमान यही चाहता है।

चुनाव सुधार अनिवार्य

जनसंघ के समय से ही हम भाजपा के लोग चुनाव-सुधारों के लिए सतत अभियान चलाते आ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि जब तक चुनाव-प्रक्रिया शुद्ध नहीं की जाती तब तक जन-जीवन में शुद्धि नहीं आ सकती। राजीव सरकार की प्रथम नीति घोषणा मुझे याद है। जनवरी 1985 में संसद् के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र के समक्ष जन-जीवन को स्वच्छ बनाने की प्रतिज्ञा की गई थी। स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रपति ने संसद् को आश्वस्त किया था कि सरकार शीघ्र ही चुनाव सुधार का कार्य आरंभ करेगी। तब से आठ वर्ष बीत चुके हैं। सरकारें आईं और सरकारें गईं, किंतु वह प्रतिज्ञा अपूर्ण ही रह गई।

1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी तब चुनाव सुधार के आंदोलन को नया प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तत्कालीन विधि मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति बनाई गई। वरिष्ठ दलीय प्रतिनिधियों के अतिरिक्त उस समिति में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री श्यामलाल शकधर भी थे। समिति ने मई 1990 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कई बहुमूल्य सुझाव दिए। दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर—एक तो राज्य कोष द्वारा निर्वाचन व्यय वहन करने पर और दूसरे वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में आमूलचूल संशोधन करने पर जरूर मतभेद थे, किंतु इस समस्या के अन्य विविध महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर 'व्यापक सहमति भी उभरी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उक्त समिति की सिफारिशें अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई हैं।'

गोस्वामी समिति

उक्त समिति की कुछ सिफारिशें, जिनका भाजपा जोरदार समर्थन करती है, निम्नलिखित हैं—

1. चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय निकाय होना चाहिए। नियुक्ति की विधि ऐसी होनी चाहिए कि कार्यपालिका के मनमानेपन पर अंकुश लगाया जा सके। लोकसभा सचिवालय के सदृश इसका अपना स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए।
2. लोकसभा एवं विधायिकाओं के चुनाव क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन होना चाहिए।
3. समस्त मतदाताओं को बहूद्देशीय सचित्र परिचय पत्र अवश्य दिए जाने चाहिए। इसके लिए सारे देश के हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए।

4. अ-गंभीर प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में भाग लेने की संभावना को न्यूनतम बनाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।
5. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित आचार संहिता को वैधानिक कवच प्रदान किया जाना चाहिए। संहिता के उल्लंघन को भ्रष्ट आचरण घोषित करना चाहिए।
6. अविलंब इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रों का प्रयोग शुरू किया जाना चाहिए।
7. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था करनी चाहिए कि केवल किसी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी की मृत्यु पर ही चुनाव स्थगित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
8. कानून में संशोधन कर मतदान दिवस पर लॉरी, ट्रेक्टर, बस सदृश यांत्रिक वाहनों द्वारा मतदान केंद्र तक मतदाताओं को लाना सर्वथा निषिद्ध कर दिया जाना चाहिए।
9. दलबदल-विरोधी कानून को संशोधित किया जाना चाहिए।

चुनाव प्रचार या उसके नाम पर जो कुछ किया जाता है, वही भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार के मूल में है। केंद्र तथा राज्यों की अनेक कांग्रेस सरकारों के कामों तथा ईमानदारी पर गहरे संदेह व्यक्त किए जा चुके हैं, जिन्होंने अपने प्रशासन के स्थायित्व से भयानक खिलवाड़ किया। यही वास्तव में हमारे लिए महत्त्वपूर्ण कारण है कि हम चुनाव को काले धन के कलंक से मुक्त करने का प्रयत्न करें।

मैं माँग करता हूँ कि गोस्वामी समिति की सिफारिशें लागू करने में अब तनिक भी देर नहीं की जानी चाहिए। जिन दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं हो सकी, अर्थात् राज्य कोष द्वारा चुनाव-व्यय का वहन एवं चुनाव प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन, उनके बारे में विविध दलों में तुरंत विचार-विमर्श आरंभ किया जाना चाहिए।

भाजपा लाइसेंस राज के विरुद्ध

कांग्रेस द्वारा उदारीकरण का मंत्र जपना शुरू करने के बहुत पहले से ही भाजपा अर्थव्यवस्था को नियंत्रण, नियमन और नौकरशाही के चंगुल से मुक्त करने की माँग उठाती रही है। नेहरू-मोहालानोविस-प्रतिरूप के द्वारा देश पर थोप दिए गए लाइसेंस-परमिट-कोटा राज के हम कठोर आलोचक रहे हैं। वर्षों से हम अपने प्रस्तावों और नीति वक्तव्यों के द्वारा इसपर जोर देते रहे हैं कि सरकारी खर्च को अनुशासित किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रतिस्पर्धामुखी बनाया जाए और अब भयावह स्तर तक पहुँच जानेवाले राष्ट्रीय ऋण की संवैधानिक उच्चतम सीमा निर्धारित की जाए। हमने बार-बार माँग की है कि हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी के तुल्य किसानों के लिए नई व्यवस्था की जाए एवं

राज्यों के लिए अधिकतर संसाधन जुटाए जाएँ।

यह स्मरण दिलाना भी संगत होगा कि 24 वर्ष पहले इसी नगर में कांग्रेस नेतृत्व ने कुछ ऐसे 'छिटपुट विचार' व्यक्त किए थे जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को वस्तुतः बिलकुल विपथगामी कर दिया।

कांग्रेस की आर्थिक नीतियों का आधार राजनीतिक स्वार्थ

दुर्भाग्यवश कांग्रेस के लिए आर्थिक नीतियाँ मुख्यतः राजनीतिक स्वार्थ-साधन का विषय रही हैं। '70 के दशक में दृष्टिगोचर होनेवाली राष्ट्रीयकरण की सनक के पीछे कोई आर्थिक तर्क नहीं था। यह विशुद्ध राजनीतिक आवश्यकता थी। मुझे यह भी लगता है कि निजीकरण के लिए कांग्रेसी नेताओं की आज की उत्साहपूर्ण घोषणाएँ भी विश्वास से कम और स्वार्थसाधक दृष्टि से अधिक परिचालित हैं।

राष्ट्रीयकरण से निजीकरण के बीच झूलते हुए सत्तारूढ़ दल ने हमारी अर्थव्यवस्था की नींव ही खोद डाली है। उसके लिए यदि राष्ट्रीयकरण जनता को लूटने का लाइसेंस भर था तो निजीकरण अपने चहेतों की जेबें भरने का अवसर मात्र है। एक बार सार्वजनिक क्षेत्र-उपक्रमों के तुलन-पत्रों को देखिए और महालेखापाल एवं वित्त निरीक्षक के प्रतिवेदन में सार्वजनिक क्षेत्र-उपक्रमों के शेयरों के संबंध में टिप्पणी पर गौर कीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसी मद पर हमें 3000 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है। अवश्य ही ये बातें कांग्रेस के लिए तुच्छ हैं, क्योंकि उसके एक प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले ही घोषित किया है कि 'आर्थिक विसंगतियाँ भ्रष्टाचार के अंतर्गत नहीं आतीं।'

भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं

भाजपा का विश्वास है कि भ्रष्टाचार-मुक्त समाज में ही अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है। हमारा यह भी विश्वास है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जड़ें राजनीतिक भ्रष्टाचार में निहित हैं।

हम विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर विश्वास करते हैं। केंद्रीकृत व्यवस्था में सदा भ्रष्टाचार पनपता है। वह व्यवस्था भ्रष्टाचारी राजनेताओं, बेईमान अधिकारियों और सत्ता के दलालों के बहुत अनुकूल होती है।

पिछले दो वर्षों में वस्तुतः बिलकुल वृद्धि नहीं हुई है और आर्थिक प्रगति रुक गई है। मुद्रास्फीति की दर कम हुई है, इसका बहुत ढोल बजाया जाता है, किंतु साधारण जन के लिए पीड़ादायक तथ्य यह है कि पिछले दो वर्षों में कीमतें 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हैं। अनाज की कीमतें तो और भी ज्यादा बढ़ी हैं जिसके कारण गरीबों को अमीरों से कहीं ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। जबकि आम आदमी को अनाज के लिए बहुत अधिक दाम देना पड़ रहा है, किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा रहा है।

हमें यह बताया गया था कि रुपए के अवमूल्यन से निर्यात बहुत बढ़ेगा और भुगतान-शेष की स्थिति सामान्य हो जाएगी। पिछले दो वर्षों में रुपए का अवमूल्यन चार बार किया गया है और नई सरकार बनने के समय से उसकी कीमत करीब आधी रह गई है। तब भी निर्यात में वृद्धि का कोई लक्षण नहीं दिखता। भुगतान-शेष की स्थिति भी उतनी ही खराब है।

साधारण जन के लिए तो नई नीतियों का दृष्टिगोचर होने वाला परिणाम प्रतिभूति घोटाला ही है। सारा देश साँस रोककर आकुलतापूर्वक प्रतिभूति घोटाले के संबंध में संसदीय समिति के जाँच परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है। भाजपा कायल है कि व्यवस्था संबंधी त्रुटि, भ्रष्ट दलाल, अपराधी बैंकर और बेईमान अधिकारी तो इस घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं ही, किंतु इतनी बड़ी घपलेबाजी बिना राजनीतिक संरक्षण के कदापि संभव नहीं थी। जब तक भ्रष्ट राजनेताओं को दंडित नहीं किया जाता तब तक देश संतुष्ट नहीं होगा।

हम अपने भीतर झाँकें

भारत को शिखर तक पहुँचने के लिए अपना लक्ष्य ऊँचा रखना चाहिए। एक राष्ट्र को शिखर तक पहुँचाने लिए आवश्यक समस्त गुण हममें हैं, यदि हम फिर भी आगे नहीं बढ़ पाए तो उसके लिए जिम्मेदार नेतृत्व है, जनता नहीं। हमें आवश्यकता एक नई दृष्टि की है, आत्मानुशासन के बोध की है जिसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।

हम यह सोचकर अपने को मूर्ख न बनने दें कि हमारी समस्याओं का समाधान वाशिंगटन और लंदन में हो सकता है। 90 करोड़ जनता के देश के भाग्य का फैसला देशवासियों को ही करना है, विदेशियों को नहीं और हम अपनी आर्थिक संप्रभुता पर भी किसी प्रकार की आँच नहीं आने दे सकते। भाजपा की आर्थिक नीति का मूलमंत्र है परिश्रमी भारतीय जनता को बंधनमुक्त कर अपने सामर्थ्य को प्रकट करने में सहायता देना और सरकारी भूमिका को वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल आर्थिक परिवेश की सृष्टि तक सीमित रखना।

भारत के समक्ष चार प्रमुख कार्य

हम यदि मिल-जुलकर काम करें और अपनी शक्तियों को निम्नलिखित चार कार्यों को पूर्ण करने के लिए केंद्रित करें तो दस वर्षों में हम इस देश का चेहरा बदल सकते हैं—

1. प्रत्येक ग्राम, कस्बे एवं नगर के लिए पर्याप्त जल,
2. प्रत्येक के लिए पर्याप्त भोजन,
3. प्रत्येक घर एवं कारखाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा, और
4. देश भर के गाँवों, कस्बों, नगरों को जोड़नेवाली तेज, सस्ती एवं आधुनिक

संचार व्यवस्था, जिसमें दूरसंचार व्यवस्था भी सम्मिलित है।

स्वाधीनता के प्रायः पचास वर्षों बाद भी हमारे पास न पर्याप्त जल है, न खाद्यान्न, न ऊर्जा, न सस्ता परिवहन। करोड़ों लोगों को तो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ भोजन, वस्त्र और मकान—भी सुलभ नहीं हैं। इनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। प्रत्येक भारतीय की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की समस्या से ही जनसंख्या की समस्या जुड़ी है और यह समस्या शिक्षा के मुद्दे से संबंधित है। भाजपा एक ऐसी प्रभावी योजना बनाकर उसका कार्यान्वयन करेगी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को अन्य संबंधित कल्याण कार्यक्रमों और साक्षरता अभियान से जोड़ेगी।

भाजपा इसका ध्यान रखेगी कि आगामी दस वर्षों में अर्थात् इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने के तुरंत बाद भारतीयों को ये आधारभूत आवश्यकताएँ सुलभ हो सकें।

आत्मनिर्भरता : हमारा उद्देश्य

निस्संदेह जगत् दिनोदिन छोटा होता जा रहा है। कोई भी देश कूपमंडूक नहीं बना रह सकता। बिना जगत् के दूसरे देशों से तालमेल बनाए रखे कोई देश अग्रसर नहीं हो सकता, किंतु सर्वदा दूसरों पर निर्भर रहनेवाला देश भी आगे नहीं बढ़ सकता।

अतः हमें सुरक्षात्मक ही नहीं रहना चाहिए। सार्वभौमीकरण के लिए की गई सरकार की आवेगपूर्ण वकालत में बहुधा विश्वासहीनता और असहायता झलकती है। यदि जगत् हमें कुछ दे सकता है तो हम भी जगत् को बहुत कुछ दे सकते हैं। भारत के बाहर भारतीयों का कामकाज बहुत अच्छा है। भारत में वे वैसा या उससे भी अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते। हम अपने को अवशिष्ट जगत् से काटकर अलग नहीं रख सकते, किंतु हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि जगत् हम पर छा भी न जाए।

हमारे लिए भारत के हित सर्वोपरि हैं। भारत के बड़े एवं छोटे उद्योगों के हित भी तदनुरूप ही हैं। हम विदेशी कंपनियों का स्वागत उच्च तकनीकी उद्योगों या जिनमें अधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता है उन उद्योगों में करेंगे, किंतु उनके साथ हमारा व्यवहार अपने उद्योगों के समतुल्य ही होगा, उन्हें विशेष अतिरिक्त सुविधाएँ नहीं दी जाएँगी।

सार्वभौमीकरण के पहले उदारीकरण अत्यावश्यक

भा.ज.पा का मत है कि हमें पहले आंतरिक उदारीकरण पर और अब की तुलना में अधिक द्रुत गति से बल देना चाहिए। बाह्य उदारीकरण उसके बाद एवं क्रमशः किया जा सकता है।

भाजपा ऐसी अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है जिसका अभिसूचक उत्पादन है, पूँजी निवेश नहीं। सफलता का निर्णय परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए, संसाधनों के विनियोजन के आधार पर नहीं। आज हम इसकी डींग मारते हैं कि कितने हजार करोड़ रुपए हमने खर्च किए, इसकी नहीं कि उससे उत्पादन कितना हुआ। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था, "नई दिल्ली के द्वारा खर्च किए गए एक रुपए का केवल पंद्रह पैसा जनता तक पहुँचता है।" प्रसंगवश, इसी क्षेत्र में राजनीतिक भ्रष्टाचार सर्वाधिक व्यापक है।

एक ठोस उदाहरण लें। भारत में प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपयों की गैस जल जाती है। केवल 2000 करोड़ रुपयों की लागत से इसे उपयोग में लाया जा सकता है। हम यदि उतनी ही राशि खर्च करें जितनी हम प्रतिवर्ष जला देते हैं तो हमें 100 प्रतिशत लाभ हो सकता है लेकिन हम अनुबंध करने में दो वर्षों तक मोल-तोल करते रहेंगे, प्रत्यक्षतः तो दर में कमी करने के लिए वस्तुतः गँवाने के लिए, हम 4000 करोड़ रुपयों की गैस जलाकर दावा करेंगे कि हमने अनुबंध में 40 करोड़ रुपयों की बचत की है।

प्रबंधक को, चाहे वह राजनेता हो या शासनाधिकारी या शिल्पतांत्रिक, उत्तरदायी होना ही होगा।

लघु उद्योगों की उपेक्षा न की जाए

यह खेदजनक है कि बहु-विज्ञापित 'संपुटित आर्थिक सुधार' की घोषणा में लघु उद्योगों की उपेक्षा स्पष्टतः परिलक्षित होती है। लंदन 'इकोनोमिस्ट' में प्रकाशित एक अध्ययन में यह तथ्य उजागर हुआ है कि दुनिया भर में बड़े उद्योगों से तुलनात्मक रूप से अल्प उत्पादन और कम लाभ हो रहा है। उनके मुकाबले में लघु उद्योग अधिक व्यवहार्य प्रमाणित हो रहे हैं। जर्मन आर्थिक चमत्कार के मेरुदंड सदृश हैं। वे 3,00,000 लघु औद्योगिक इकाइयाँ जो जर्मनी के सकल स्वदेशी उत्पाद (जी.डी.पी.) का दो-तिहाई उत्पादन करती हैं। यही बात जापान के लिए भी सत्य है जो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा अर्थव्यवस्था के लघुरूपीकरण का अद्भुत उदाहरण है और वृहदाकार इकाइयों का प्रतिस्पर्धी है।

भारत में भी लघु उद्योग इकाइयाँ, जिनके अंतर्गत कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग और ग्रामीण उद्योग आते हैं, सकल स्वदेशी उत्पाद (जी.डी.पी.) का 40 प्रतिशत उत्पादन करती हैं एवं 3 करोड़ 25 लाख व्यक्तियों को रोजगार देती हैं, जबकि बड़े उद्योग निजी क्षेत्र में केवल 74 लाख व्यक्तियों को और सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 23 लाख व्यक्तियों को रोजगार दे पाते हैं। 1989-90 में लघु उद्योग इकाइयों ने 30 हजार करोड़ के कुल निर्यात में से 9 हजार करोड़ रुपए का सीधा निर्यात किया था। इन आँकड़ों में विदेश में कार्यरत हमारे बढ़ई, राज-मिस्त्री और दूसरे कुशल कारीगरों द्वारा 1981-90 के दशक में प्रेषित 21 अरब डॉलर की राशि

सम्मिलित नहीं है। भारतीय सुनार विदेशी मुद्रा में भारत के लिए 4 अरब डॉलर की कमाई करते हैं, जो राशि भारत में सभी बड़े उद्योगपतियों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उपार्जन के योगफल से भी अधिक है। यह किसी एक ही वर्ष का आकस्मिक आँकड़ा नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतिवर्ष होता रहता है। यह हमारे अप्रयुक्त शक्ति स्रोतों को उद्घाटित करनेवाला तथ्य है। यदि हम अपनी इन कुशलताओं का उपयोग करें तो हम उत्पादन में, रोजगार उपलब्ध कराने में, निर्यात करने में और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने में सफल हो सकते हैं।

जापान का बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श

तो हम पारंपरिक के साथ आधुनिक का समन्वय कैसे करें? अनेक राष्ट्रों ने, विशेषतः जापान ने अपने इतिहास के महत्त्वपूर्ण मोड़ पर इस समस्या का सामना किया है। जापान ने पारंपरिक कुशलता को आधुनिक क्षेत्र से कैसे जोड़ा? जापान ने जो कुछ किया उसका सारांश जापान के दैतो बुनका विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रो. तोकेशी हयाशी के शब्दों में निम्नलिखित है—

"पारंपरिक शिल्पकार को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता कि वह विश्वविद्यालय में पढ़ा सके क्योंकि उसके शिल्प का वैसा सैद्धांतिक आधार नहीं था। वह अपने अनुभव अगली पीढ़ी को सौंपते चले जाने से ज्यादा संबंधित है, किंतु आधुनिक इंजीनियरों की सहायता से उन्हें इस प्रकार जुटाया जा सका कि वे नई उभरनेवाली उत्पादन प्रक्रिया में अपना सहयोग दे सकें। कोई पारंपरिक को आधुनिक से कैसे समन्वित करता है? अपने क्षेत्र में हम लोग बहुत समझ-बूझकर चुनते रहे हैं कि आधुनिक का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए वस्त्र शिल्प के क्षेत्र में केवल कताई का मशीनीकरण किया गया, बुनाई का नहीं। बुनाई पारंपरिक शिल्पकारों के हाथों में ही छोड़ दी गई। आधुनिक तकनीक पारंपरिक कुशलताओं और पारंपरिक शिल्पकारों का अस्तित्व नहीं मिटा सकती। पारंपरिक और आधुनिक दोनों साथ-साथ काम करते रहे।"

जापान ने जो कुछ किया उसकी तो प्रो. हयाशी ने व्याख्या की ही, अन्य विकसित राष्ट्रों को परामर्श देते समय उन्होंने उस प्रवृत्ति की आलोचना की, जो मानती है कि पश्चिमी नुस्खे सारी दुनिया के लिए समान रूप से कारगर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को अपनी नियति का निर्धारण स्वयं करना चाहिए। वे कहते हैं—

"पश्चिम के प्रशंसक तो बहुतेरे हैं, हमारे यहाँ भी वे हमेशा से रहे हैं। मेरे चिंतन के अनुसार पश्चिम की प्रशंसा इस सीमा तक की जानी चाहिए कि वे अपनी समस्याओं को स्वयं हल करते हैं, किंतु जब वे इन विचारों और नमूनों को दूसरों पर सार्वभौम चिंतन के रूप में थोपते हैं तो बात कुछ और हो जाती है।

"मैं जानता हूँ कि विकासशील देश यह जानने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं

कि जापान ने सफलता कैसे पाई और क्या दूसरे राष्ट्र भी उन्हीं नीतियों का अनुकरण कर उसी प्रकार सफलता पा सकते हैं। यह तो ठीक है कि जापानी प्रयोग से कुछ दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है लेकिन मेरी समझ के अनुसार उसकी नकल करना संभव नहीं, क्योंकि अपने प्रकार में वह बिलकुल अनोखा है। वह जापानी सभ्यता और संस्कृति के साथ ऐतिहासिक परिस्थितियों के संदर्भ में विशिष्ट पहलुओं के कारण सफल हुआ। विकासशील देशों को अपना रास्ता खुद चुनना होगा, जो उनकी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप हो। यह आसान काम नहीं है।"

भारत को अपना रास्ता स्वयं तय करना है। वह पश्चिम की हूबहू नकल नहीं कर सकता। प्रत्येक राष्ट्र और उसकी जनता के जीवन का अपना उद्‌देश्य हुआ करता है।

स्वदेशी की अवधारणा

जिस सीमा तक उद्‌देश्य की समानता होती है उसी सीमा तक जीवन पद्धति, आदतें और आवश्यकताएँ भी समान होंगी और तदनुरूप समान तकनीक का भी प्रयोजन होगा। यह हर राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह विकासशील राष्ट्रों की समानता की सीमा के आधार पर अपना विशिष्ट पथ निर्धारित करे। यह निर्णय और निष्कर्ष ही 'स्वदेशी' है जिसका अर्थ है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क इस बात का विवेकपूर्वक फैसला करे कि अपने लिए उसे क्या चाहिए और उसे पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? साथ ही जिन समानताओं के आधार पर विश्व एक साँझा गाँव बनता जा रहा है, उनका रक्षण और पालन-पोषण भी होना चाहिए।

स्वदेशी की अवधारणा का अर्थ यह नहीं है कि केवल मात्र भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाए। इसका अर्थ है मस्तिष्क के सोच द्वारा मानसिक एवं शारीरिक धरातलों पर स्थानीयता के अनुरूप जीवन जीने पर अधिकाधिक बल देना और पारस्परिक प्रयोजन पर आधारित विदेशी व्यापार भी करते रहना। यह विकसित देशों के सामने किसी हीनता ग्रंथि को प्रकट नहीं करती। भारत की अर्थव्यवस्था को ऋण-मुक्त बनाना भी इसके लक्ष्य में सम्मिलित है।

कर्नाटक के इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए इसका उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि पुराने मैसूर राज्य में ही आधुनिक तकनीक का श्रीगणेश हुआ था। देश में जल-विद्युत् ऊर्जा का सर्वप्रथम आविर्भाव मैसूर में ही हुआ था। मैसूर में 1935 में उद्‌घाटित रेडियो स्टेशन को 'आकाशवाणी' नाम दिया गया, जिसे बाद में पूरे देश ने स्वीकार कर लिया।

बागबानी, कृषि और वनरोपण

वस्तुतः मैसूर आधुनिक भारत के आधुनिकीकरण करनेवालों की प्रथम पंक्ति में आता है। देश का सर्वाधिक सुंदर 'वृंदावन उद्यान' भी यहीं है।

उद्यान की चर्चा करते हुए मैं यह कामना करता हूँ कि हमारे नीति निर्माता बागबानी में निहित निर्यात की अपार संभावना का अनुमान कर पाते। विश्व में फूलों का कुल निर्यात व्यापार 14 अरब रुपयों के आस-पास है। इसमें हमारा हिस्सा नगण्य है, इस तथ्य के बावजूद कि हमारे देश में वर्ष भर धूप रहती है।

भारत की कुल भूमि का क्षेत्रफल 32 करोड़ 9 लाख हैक्टेयर है, जिसमें 6 करोड़ 40 लाख हैक्टेयर वन-भूमि है। वास्तविक वन-आच्छादन तो 3 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही है और अवशिष्ट 2 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर भूमि पर निम्न कोटि के वन हैं, जिनमें शीघ्र पुनः वृक्षारोपण की आवश्यकता है। इसके अलावा 10 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि भी सुलभ है। इस प्रकार हमारे पास वनरोपण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

भाजपा वनरोपण की विस्तृत योजना बनाने के पक्ष में है। इससे लाखों व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी। बंजर भूमि और रेगिस्तान की वृद्धि रोकना संभव होगा और परिवेशगत संतुलन एवं वातावरण में, जो अब विश्वव्यापी चिंता का विषय हो गया है, सुधार हो सकेगा।

अर्थव्यवस्था के संबंध में अपनी टिप्पणी आरंभ करते समय मैंने स्मरण दिलाया था कि 25 वर्ष पहले इसी शहर में 'छिटपुट विचारों' के शीर्षक के अंतर्गत कुछ ऐसी नीतियाँ प्रतिपादित की गई थीं जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को बिलकुल चौपट कर दिया। बंगलौर में हमारी पार्टी का यह विचार-विमर्श भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा का निर्देश कर सकेगा।

जम्मू-कश्मीर में खतरनाक स्थिति

जम्मू-कश्मीर राज्य में सरकार उस घृणित 'नस्ल समाप्तीकरण' (नस्लकुशी) की मूकदर्शक बनी रही जिसके फलस्वरूप करीब ढाई लाख हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बना दिए गए।

उभरती हुई वास्तविकता यह है कि भारत क्रमशः एक इसलामी कट्टरपंथी घेरे में घिरता चला जा रहा है, जो सुरक्षा के लिए खतरा होने के साथ-साथ सभ्यतामूलक चुनौती भी है। कश्मीर में अलगाववादी विद्रोह केवल '1947 के अधूरे काम' को पूरा करने का पाकिस्तानी हथकंडा ही नहीं है, यह कट्टरपंथी शक्तियों द्वारा छेड़े गए व्यापक हमले का एक पहलू भी है। उदाहरण के लिए यह कोई आकस्मिक स्थिति नहीं है कि कश्मीर घाटी के तथाकथित मुजाहिदीन आतंकवादियों में पाकिस्तानी, अफगानी और सूडानी भी शामिल हैं। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि वह हाल ही में पारित इसलामी देशों के उन प्रस्तावों पर विचार

करे जिनमें कश्मीर में अशांति की तुलना फिलिस्तीन और बोस्निया की घटनाओं से की गई है।

यह समझना चाहिए कि कश्मीर की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए पहले की तरह सोचे जा रहे सभी उपाय नाकारा साबित होंगे, जैसे कठपुतली सरकारों को खड़ा करना, या अधिक स्वायत्तता देना या पृथक्तावादियों को तुष्ट करना। यह ख्याली पुलाव ही है कि पाकिस्तान को समझा-बुझाकर घाटी के आतंकवादियों का समर्थन करने से किसी तरह विरत किया जा सकता है। पाकिस्तान को लगता है कि उसकी जीत होने वाली है, अतः उससे किसी प्रकार के संयम की अपेक्षा व्यर्थ है।

आवश्यक है कि विश्व में इस सवाल पर अनुकूल अभिमत जुटाया जाए। इस्राइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूँ। कट्टरतावाद एवं आतंकवाद से सफलतापूर्वक संघर्ष करने का इस्राइल का लंबा अनुभव है और भारत उससे लाभ उठा सकता है।

धारा 370 हटाओ

फिर भी बाहरी समर्थन आंतरिक सुव्यवस्था का स्थान नहीं ले सकता। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अदूरदर्शी सरकार द्वारा श्री जगमोहन को राज्यपाल के पद से हठधर्मितापूर्वक हटाए जाने के बाद जो सरकारें बनीं उन्होंने घाटी की स्थिति को बिगड़ने दिया और अब हाल इतना खराब हो गया है कि डोडा जिले से हिंदुओं के नए निष्क्रमण का खतरा पैदा हो गया है। केंद्रीय गृहमंत्री और उनके राज्यमंत्री के बीच दलगत संघर्ष का दंड देश को भोगना पड़ रहा है।

हमारा दल संविधान में अस्थायी व्यवस्था के रूप में स्वीकृत धारा 370 को हटाने की लगातार माँग करता रहा है। घटनाओं ने हमारे इस विश्वास को सत्य प्रमाणित किया है कि जम्मू-कश्मीर के तथाकथित विशेष दर्जे से एकीकरण को आगे बढ़ाने के स्थान पर राष्ट्रीय एकता में भावात्मक एवं कानूनी बाधाओं की ही सृष्टि हुई है।

भाजपा माँग करती है कि अपने घर में सभी विस्थापितों को पुनः बसाने के तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएँ। सरकार इस मुद्दे की इसीलिए निर्दयतापूर्वक उपेक्षा करती रही है, क्योंकि ये विपत्तिग्रस्त विस्थापित मुख्यतः हिंदू हैं। परिस्थिति की माँग है कि पूर्व सैनिकों को घाटी में विशेष रूप से बसाकर एक नए भारतीय सुरक्षा क्षेत्र का निर्माण किया जाए। हमारे लिए अर्थहीन हो गई, पुरानी पड़ गई धारा 370 की तुलना में भारत माता की अखंडता अधिक महत्त्वपूर्ण है।

जनसंख्या का आक्रमण

स्वामी विवेकानंद ने एक स्थान पर 'धैर्यशाली हिंदू, मृदुल हिंदू' की चर्चा की

है। उनका संकेत देश के असीम लचीलेपन और विपत्तियों को झेलने की असीम क्षमता की ओर था। कांग्रेस को ये विशेषताएँ वांछित गुणों के स्थान पर दुर्बलताएँ प्रतीत होती हैं। इसीलिए वह हिंदुओं की परवाह नहीं करती, समाज की परवाह नहीं करती, राष्ट्र की परवाह नहीं करती। हमने उसके इस मनोभाव को कश्मीर में देखा, हमने इसे परिलक्षित किया है, उसके उस अनुमतिबोधक रुख में जिसके कारण बाढ़ के सदृश एक करोड़ बँगलादेशी भारत में घुसकर मौन जनसांख्यिकी रूपांतरण घटित कर रहे हैं। हम इसे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार के अवज्ञापरक रुख में भी परिलक्षित कर रहे हैं।

राजनीति का अपराधीकरण

12 मार्च, 1993 को बंबई में हुए बम-विस्फोटों की शृंखला—जिसके कारण करीब 500 निर्दोष नागरिक मारे गए—राष्ट्रीय लज्जा का विषय है। इससे न केवल हमारी आंतरिक सुरक्षा की दुर्बलता प्रकट हुई है, बल्कि पाकिस्तान के पूरे सक्रिय एवं गुप्त सहयोग से देश में कार्यरत गुप्तचरों की गतिविधियों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता भी उजागर हो गई है। तीन महीने बीत जाने के बाद भी सरकार मुख्य अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

स्थिति के इतना संगीन बन जाने का एक बड़ा कारण राजनीति का अपराधीकरण है, जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी किंतु जिसने पिछले दशक में भयावह रूप धारण कर लिया है। जब तक राजनेताओं और माफिया नेताओं के गठबंधन को तोड़ा नहीं जाता तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

बंबई और कलकत्ता में हुए विस्फोटों के संदर्भ में जो तथ्य उजागर हुए हैं, उनसे यह साफ है कि कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों गले-गले तक इस कूट योजना के दलदल में धँसी हुई हैं और इसीलिए इस समस्या का समाधान करने की न उनमें क्षमता है, न इच्छा ही है।

अराजकता की ओर झुकाव

स्थिति सचमुच गंभीर है क्योंकि देश और नागरिकों की सुरक्षा परस्पर जुड़ी है। 1984 ई. में कांग्रेस ने अपने कुख्यात प्रचार-अभियान में जनसाधारण से पूछा था कि क्या वे देश की सीमाओं का अपने द्वारों तक सिमट आना पसंद करेंगे। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कांग्रेस को प्रचंड जनादेश प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस सद्भावना को न केवल निःशेष कर दिया है बल्कि देश की सीमाओं को सचमुच औसत नागरिक के द्वार तक ले आने का अपराध भी किया है। अपनी शिथिलता और मर्यादाहीनता के कारण उन्होंने सारे भारत को सीमांत सदृश बना दिया है। नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा की गंभीर जिम्मेदारी अब कांग्रेस

निभा सकती है, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता।

जनता का धीरज चुकता जा रहा है और सरकार पूरी तरह निष्क्रिय बनी हुई है। मुसलिम संस्थाओं की 'मिल्ली पार्लियामेंट' द्वारा जब मुसलमानों से हथियार उठाने का आह्वान किया जाता है तब उस संकट के प्रति भी वह मूकदर्शक ही बनी रहती है। जब ईद के दिन हजरतबल मसजिद के मंच से एक आतंकवादी नेता देश से कश्मीर को अलग करने के लिए भड़काऊ भाषण देता है तो सरकार मुँह फेरकर दूसरी ओर देखती रहती है। उसका बहुमूल्य वोट बैंक उसके हाथ से निकल न जाए, इस भय से वह केरल के विद्यालयों में शुक्रवार को छुट्टी की घोषणा करती है। यह सब केवल लज्जाजनक ही नहीं है, अश्लील है।

कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शत्रु हम पर हँसते हैं। वे जानते हैं कि सरकार ने भारत को नपुंसक बना रखा है क्योंकि इसका एक सूत्री कार्यक्रम है, किसी भी कीमत पर अपनी गद्दी बचाए रखना।

अराजकता की ओर देश के इस खतरनाक भटकाव के प्रति जनता की चिंता में भाजपा शामिल है। हम देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को अपने लिए सर्वोपरि महत्त्व का विषय बनाना चाहते हैं। हम भारत को महत्त्वहीन बना दिया जाना हर्गिज नहीं सहेंगे।

शीत युद्ध का अंत

भारत की विदेश नीति का ढाँचा मुख्यतः इन तीन तथ्यों पर आधारित था—अमेरिका और रूस के बीच का शीत-युद्ध; रूस के साथ दीर्घकालिक मैत्री, जो दोनों पक्षों के लिए अनुकूल थी और कम्युनिज़्म के प्रचार के विरुद्ध पाकिस्तान को निर्भर योग्य सहयोगी मानने वाले अमेरिका के साथ बनते-बिगड़ते संबंध।

बहरहाल यह स्थिति अब बिलकुल बदल चुकी है। 1989 से द्रुत गति से समाप्त होते हुए शीत-युद्ध और एक महाशक्ति के विलोप ने अंतरराष्ट्रीय स्थिति को और भी अधिक जटिल बना दिया है। पहलेवाली स्थिति में एक संयम और भविष्य का अनुमान लगा पाना अंतर्निहित था। उनके स्थान पर अब अनिश्चितताएँ और पर्याप्त मात्रा में भ्रम हैं। विश्व शांति के नवयुग का उदय नहीं हो पाया है किंतु गंभीर असमानताएँ और भयंकर आंचलिक संघर्ष विद्यमान है। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के विघटन, यूगोस्लाविया में लड़े जा रहे नस्ली युद्ध, स्वाधीन देशों के राष्ट्रकुल को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया में रह गए अनिर्णीत पहलू, अफगानिस्तान में विद्यमान गृह युद्ध जैसी स्थिति, सोमालिया और कंबोडिया में लंबे समय से चल रही लड़ाई और पश्चिमी एशिया की विषादग्रस्त अस्थिरता आदि के कारण स्थिति सचमुच बहुत जटिल हो गई है।

भारतीय नीति-निर्धारण में चुनौतियाँ

अंतरराष्ट्रीय मामलों के क्षेत्र में भारतीय नीति-निर्धारण के समक्ष त्रिमुखी चुनौती है—

क. आज की बदली हुई वास्तविकताओं की त्वरित पहचान और शताब्दी के इस संकटापन्न मोड़ के अनुरूप भारत की परराष्ट्र नीति को पुनः क्रमबद्ध करना।

ख. हमारी कूटनीति की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों, उक्तियों एवं कृतियों को सामंजस्यपूर्ण बनाकर राष्ट्रमंडल में भारत के लिए उपयुक्त स्थान एवं भूमिका प्राप्त करना।

ग. दक्षिण एशिया में ऐसी महत्त्वपूर्ण पहलें करना जिनसे अपने सभी पड़ोसियों से हमारे लाभजनक द्विपक्षीय संबंध विकसित हों ताकि इसमें रहनेवाली विशाल जनसंख्या को दरिद्रता और अभावों की अपंगकारी दासता से मुक्त किया जा सके।

चीन और पाकिस्तान से संबंध

भाजपा देश के सभी पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय लाभजनक एवं पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंधों के पक्ष में है, अतः चीनी गणराज्य के साथ स्थायी मैत्री और सहयोग की राह में उत्तराधिकार में प्राप्त सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हम उपयुक्त कदम उठाएँगे। हम जानते हैं कि यह कार्य सरल नहीं है, विशेषतः तीन कारणों से—एक तो विवादग्रस्त सीमा समस्या के कारण, दूसरे चीन द्वारा पाकिस्तान को सैनिक तकनीक और हथियारों की लगातार मदद देते रहने के कारण और तीसरे भारतीय जनता की तिब्बत के बौद्धों की खत्म होती जाती पहचान के बारे में चिंता का कारण। तथापि हम मानते हैं कि चीन से संबंध सुधारने के लिए सचेत रूप से प्रयास करना आवश्यक है जिससे या तो हम विवादों को हल कर सकें या कम-से-कम उन्हें और आगे न बढ़ने दें।

अंग्रेजों द्वारा 1947 में भारत और पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही पाकिस्तान से हमारा क्षेत्रीय संघर्ष चला आ रहा है। यह इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि अतीत में दो बार जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारी सेनाओं के सामने उसे मुँह की खानी पड़ी तब हमने कश्मीर समस्या के अंतिम समाधान के लिए उसे राज़ी होने को बाध्य किए बिना एवं अपनी विजयों के आधार पर स्थायी शांति स्थापित किए बिना ही इन अवसरों को गँवा दिया।

पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान हमारे देश की एकता को खंडित करने के लिए योजनाबद्ध रूप से भारत के विविध प्रदेशों में विशेषतः पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को सहायता देकर विद्रोह भड़काने की चेष्टा करता रहा है। हम यह जानते हैं कि इस उपमहादेश की जनता की भलाई को पड़ोसियों के स्थायी वैमनस्य के हाथ बंधक नहीं रखा जा सकता, किंतु शांति

तो तभी स्थापित हो सकती है जब हम अपने देश में पाकिस्तान की शरारत को प्रभावी ढंग से व्यर्थ कर सकें और उसे यह अनुभव करा सकें कि उसका दुस्साहस उसके लिए महँगा पड़ेगा।

विश्व लोकतंत्र

हम उभरती हुई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिका के विशिष्ट निर्णायक महत्त्व को स्वीकार करते हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि उत्तराधिकार में प्राप्त विगत पारस्परिक पूर्वग्रहों को दूर कर, उभयपक्षों द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों एवं बोधों पर आधारित परस्पर लाभजनक संबंधों को हम अमेरिका के साथ विकसित करें।

भाजपा विश्वव्यापी परिवेशगत सहमति और संपोष्य विकास पर आधारित न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को स्वीकार करती है, किंतु इसके लिए संपन्न एवं विपन्न, साधन एवं उत्पादन, दारिद्र्य एवं प्राचुर्य के बीच विद्यमान विश्वव्यापी खाई को पाटना होगा। यही है वह नया विश्वव्यापी लोकतंत्र जिसके प्रति हम अपना दायित्व निभाएँगे। इस उद्देश्य से सामंजस्य रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए कार्य करने की भी आवश्यकता है।

आणविक नीति

शीत-युद्ध की समाप्ति के द्वारा न आणविक अस्त्र ही खत्म हुए और न राष्ट्रों के बीच आणविक युद्ध का खतरा ही दूर हुआ। विश्वव्यापी स्तर पर कुछ स्वागत योग्य अग्रगति हुई है, किंतु क्षेत्रीय स्तर पर आणविक अस्त्रों के विस्तार की समस्या और संगीन हो गई है। स्वघोषित रूप से पाकिस्तान की आणविक शस्त्र-संपन्नता, चीनी गणराज्य की आणविक वस्तुस्थिति, खाड़ी के कुछ राष्ट्रों की महत्त्वाकांक्षा और स्वाधीन राज्यों के राष्ट्रकुल में व्याप्त उथल-पुथल एवं अनिश्चयता के संदर्भ में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानतः बल देते हुए ही भारत इस प्रश्न का हल खोजने की चेष्टा करेगा।

भारत की प्रगति को रोकने के किसी भी प्रयास से हम सहमत नहीं हो सकते। इस संबंध में हमारी नीति निरंतरता और उससे भी अधिक आक्रमण-निवारण की आवश्यकता से परिचालित है।

भाजपा का 4 सूत्री प्रस्ताव

अतः मैं पार्टी की आणविक नीति के आधार के रूप में चार-सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ—

1. भा.ज.पा राष्ट्रीय संप्रभुता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में कोई समझौता नहीं करेगी।
2. भा.ज.पा आणविक अस्त्रों के विस्तार को रोकने के लिए समावेशकारी

विश्वव्यापी निर्विभेदकारी संधि का सिद्धांततः समर्थन करती है। जैव-रासायनिक युद्ध के संबंध में किया गया समझौता इसके लिए अनुकरणीय उपयोगी नमूना है। विश्व स्तर पर आणविक अस्त्रों के और भी परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाने को पार्टी प्रोत्साहित करेगी।

3. 'पहले प्रयोग न करने' की घोषणा की संभावना की जाँच-पड़ताल करने के पक्ष में भा.ज.पा है। साथ ही हम सहकारी सुरक्षा के सभी पक्षों का रचनात्मक रूप से परीक्षण, विश्वास-निर्माण के अन्य उपायों के विस्तार और मध्य, दक्षिण, पश्चिम एवं पूर्व एशिया के सभी क्षेत्रों में आणविक संयम के सराहनीय प्रयासों का समर्थन भी करते रहेंगे।
4. हमारा मत है कि भारत अपने शांतिपूर्ण प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को त्याग नहीं सकता।

इस संदर्भ में भाजपा यह महसूस करती है कि सरकार को भारत की आणविक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल के. सुंदरजी ने पहले ही इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है।

पाँच प्रधानमंत्री और पाँच कारण

पिछले 16 वर्षो में हमारे देश में 5 प्रधानमंत्री सत्ता से हटाए गए हैं। उनकी अपदस्थता के पीछे प्रत्येक मामले में एक प्रमुख कारण रहा है—

श्रीमती इंदिरा गांधी को लोकतंत्र को रौंदने के कारण हटना पड़ा। आपातकाल लगाने के कारण जनता उन्हें क्षमा नहीं कर सकी।

जनता पार्टी की भयंकर आंतरिक कलह को असह्य मानकर मतदाताओं ने श्री मोरारजी भाई देसाई की सरकार को दंडित किया।

श्री राजीव गांधी को बोफोर्स कांड के कारण हटना पड़ा, जो जनता की दृष्टि में उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार का प्रमुख उदाहरण माना जाने लगा था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अयोध्या आंदोलन का विरोध करने एवं वोट बैंकों की राजनीति में निर्लज्जतापूर्वक लिप्त होने के कारण जन-आक्रोश के शिकार हुए।

श्री चंद्रशेखर का पतन उनके सहयोगी दल कांग्रेस के मन में उनके द्वारा अपने काम में टाँग अड़ाने और अपने ऊपर गुप्तचरी करने के संशय के कारण हुआ।

उपर्युक्त प्रत्येक प्रधानमंत्री के लिए एक ही निमित्त पर्याप्त घातक सिद्ध हुआ।

राव की दुर्बलता

यह दिलचस्प बात है कि केवल दो वर्षों के संक्षिप्त शासनकाल में ही श्री पी.वी. नरसिंह राव पर ये पाँचों आरोप लागू होते हैं।

लोकतंत्र पर हमला

श्री राव ने देश पर विधिवत् आपातकाल भले ही न थोपा हो, किंतु 6 दिसंबर, 1992 के बाद उनकी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम स्वेच्छाचारी, मनमाने और पूर्णतः अलोकतंत्रीय रहे हैं। इनमें से उनके द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम—यथा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को बरखास्त करना, रा.स्व.संघ को प्रतिबंधित करना आदि अदालतों के द्वारा असंवैधानिक होने के कारण रद्द कर दिए गए। अनेकानेक अदालतों ने भाजपा नेताओं एवं सांसदों को गिरफ्तार करने और रा. स्व.संघ और वि.हि.प. के कार्यालयों को सीलबंद करने जैसे गैर-कानूनी कामों के लिए सरकार की भर्त्सना की है।

कांग्रेस के भीतर गृह-युद्ध

आज कांग्रेस दल वस्तुतः गृह-युद्ध की व्यथा से ग्रस्त है। कैबिनेट स्तर के कई मंत्री भी खुलेआम प्रधानमंत्री की निंदा करते रहते हैं। एक ही विभाग के वरिष्ठ और कनिष्ठ मंत्री परस्पर विरोधी कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सूरजकुंड अधिवेशन में शोरगुल भरे विवादों ने तो जनता पार्टी के कलह को भी पीछे छोड़ दिया।

भ्रष्टाचार

इन्हीं दो वर्षों में स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार 'प्रतिभूति घोटाला' देश में घटा। देश के प्रमुख प्रशासकों के रिश्तेदारों के बारे में समाचार-पत्रों में गंभीर अभियोग लगाए जाते रहे हैं। जब कांग्रेस ने 3 न्यायाधीशों की समिति द्वारा दोषी करार दिए गए न्यायाधीश रामस्वामी को लोक सभा में चल रहे महाभियोग से बरी कराने के लिए भ्रष्टाचार से खुल्लमखुल्ला समझौता किया तो वास्तव में सारा देश गंभीर रूप से विक्षुब्ध हो गया।

अयोध्या और वोट बैंक की राजनीति

जहाँ तक अयोध्या का प्रश्न है, श्री नरसिंह राव ने प्रमाणित किया कि वे भी उस आंदोलन के उतने ही विरोधी हैं जितने विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह उनका एकमात्र उद्देश्य इस संदर्भ में वोट बैंक की ही राजनीति करना था। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके शासनकाल में देश में केरल में दी जानेवाली शुक्रवार की छुट्टियों और अयोध्या में किए जानेवाले सोमयज्ञ जैसे निकृष्टतम सुविधावाद के उदाहरण प्रस्तुत किए गए।

सहकर्मियों पर गुप्तचरी

संसद् के इस वर्ष के बजट सत्र में मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह आरोप

लगाया कि उनकी टेलिफोन वार्त्ता सुनी जाती है और उनके कार्यों पर सरकार द्वारा निगरानी रखी जाती है।

जून 1991 में जब श्री पी.वी. नरसिंह राव ने सत्ता संभाली थी तब उनके साथ बहुमत तो नहीं था किंतु जनादेश था। ठीक दो वर्षों के बाद आज उन्होंने जनता दल और तेलुगूदेशम में फूट डालकर छलपूर्वक बहुमत तो प्राप्त कर लिया, परंतु उन्हें प्राप्त जनादेश लुप्त हो गया है। मुझे निश्चय है कि वे इसका अनुभव करते हैं, किंतु मैं चाहता हूँ कि वे इसे स्वीकारें और जनता से नया जनादेश माँगें।

भाजपा सुफल दे सकती है

हमें इस बात का गौरव है कि भाजपा शासित 4 राज्यों में हम माफिया गिरोहों एवं अपराधियों पर नियंत्रण हासिल करने में सफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के सत्तारूढ़ होने के पहले हर वर्ष बीसियों दंगे हुआ करते थे। कल्याण सिंह का 18 महीने का शासनकाल दंगा-मुक्त था। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि इन 4 राज्यों की हमारी सरकारों की आलोचना कई काम नहीं कर सकने के कारण तो हुई किंतु उनपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। सभी मानते हैं कि हमारे मंत्रियों की निष्ठा और ईमानदारी का स्तर बहुत ऊँचा है।

अपने अनुभवों और उपलब्धियों के आधार पर भा.ज.पा आश्वस्त है कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर जनता ने हम में विश्वास व्यक्त किया तो समाज को दंगा-मुक्त, प्रशासन को भ्रष्टाचार-मुक्त, अर्थव्यवस्था को ऋण-मुक्त और निर्वाचनों को हिंसा-मुक्त बना सकेंगे।

विश्व की नजर हम पर है

इस राष्ट्रीय परिषद् के सत्र में सहयोगी प्रतिनिधियो! मुझे विश्वास है कि आप सब महसूस करते होंगे कि पिछले कुछ महीनों में भाजपा से जनता की आशाएँ और अपेक्षाएँ कई गुना बढ़ गई हैं। असंदिग्ध रूप से अपनी सफलताओं के कारण, अकेले सरकार बनाने में समर्थ होने की संभावना के कारण हम जो कुछ कहते और करते हैं उसका बहुत सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण किया जाता है। हमारे कुछ कृपालु मित्रों ने जिस प्रकार सीमा लाँघकर भी हमें बदनाम करना चाहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा आचरण साधारण मानदंडों के आधार पर ही खरा नहीं उतरना चाहिए बल्कि इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई उसकी ओर उँगली उठा ही न सके।

द्रुत विकास का अर्थ ही है विविध पृष्ठभूमियों के व्यक्ति पार्टी की ओर आकृष्ट हुए हैं। यह स्वास्थ्य और तेजस्विता का लक्षण है, किंतु क्योंकि हमारा दावा है कि हमारी पार्टी विशिष्टतायुक्त है, द्रुत विकास के कारण हमें इसका दुगुना

प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह हमारी पार्टी के मानदंड और मूल्य–बोध शिथिल न हो जाएँ।

आत्म–शुद्धीकरण

आनेवाले महीनों में बहुतों को ऐसा लग सकता है कि "पार्टी शीघ्र ही सत्तारूढ़ होने जा रही है, इसलिए मुझे कोई ऐसा अनुकूल पद प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे सत्ता प्राप्त होने पर मैं उसका लाभ उठा सकूँ" यह प्रलोभन घातक सिद्ध होगा। इससे लोगों की निगाह में विशिष्टता का हमारा दावा नष्ट हो जाएगा और सत्तारूढ़ होने पर यदि हमारे सदस्य लाभ उठाने पर जुट जाएँगे तो उससे न केवल हमारी पार्टी को क्षति पहुँचेगी, बल्कि हमारा महान् उद्देश्य भी खतरे में पड़ जाएगा। भाजपा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। नई दिल्ली में सरकार बनाना हमारा वैध लक्ष्य है, किंतु उसका साधन छल–प्रपंच और षड्यंत्र नहीं है। उसका साधन है आत्मशुद्धि। धम्मपद की उक्ति पर ध्यान दें—जिस प्रकार सुनार सोने की अशुद्धियाँ दूर करता है उसी प्रकार विवेकी व्यक्ति पुनः–पुनः प्रयास कर अपने दोषों को एक–एक कर, थोड़ा–थोड़ा कर दूर किया करता है।

आगामी लक्ष्य

भाजपा का उद्देश्य तो भारतीय जनता के सुख और गौरव की वृद्धि करना ही है। इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन ही है राजनीतिक सत्ता। आज कांग्रेस का तेजी से अधःपतन हो रहा है। कम्युनिज्म की विश्वव्यापी विफलता के कारण मार्क्सवादी पार्टियाँ अपनी राह से भटक गई हैं। जनता दल में जबरदस्त बिखराव है, इसपर भी यह नियति का व्यंग्य ही है कि उसमें यदा–कदा भाजपा की प्रेरणा से ही उद्यम परिलक्षित होता है। इस बढ़ती हुई शून्यता में बहुतों के मतानुसार भाजपा ही एकमात्र विकल्प है।

दूसरों की कमियों के कारण ही जनता हमें चुने, यह हमारी कामना नहीं है। आखिर हमारा लक्ष्य केवल चुनावी सफलता नहीं है। हमारा लक्ष्य तो है अभिशासन में सफलता प्राप्त करना। अतः पार्टी का त्रिसूत्री लक्ष्य है—अपने जनाधार को विस्तृत करना, सरकार के लिए युक्तियुक्त एवं समग्रतापरक नीति निर्धारण करना और विपक्ष में रहते हुए भी आचरण के द्वारा जनता के मन में विश्वास जगाना कि यह पार्टी सचमुच विशिष्टतायुक्त है। हमसे जनता को बहुत आशाएँ हैं। आइए, संकल्प करें कि हम उन्हें निराश नहीं करेंगे।

वंदेमातरम्



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

जयपुर — 31 जुलाई से 1 अगस्त, 1993

कांग्रेस पार्टी का भंडाफोड़

संसद् के वर्षाकालीन सत्र का प्रथम सप्ताह कल समाप्त हुआ। यह सप्ताह सदा स्मरणीय रहेगा। इसने सत्ता पक्ष की पूरी कलई खोल दी है। इस सप्ताह के घटनाचक्र ने प्रमाणित किया कि अब कांग्रेस पार्टी एक घटिया किस्म की राजनीतिक जमघट बन चुकी है, जिसके सामने येन-केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य शेष नहीं।

अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में राजधानी में और संसद् में जो वातावरण बना दिया गया वह वास्तव में शर्मनाक था। मंगलवार रात्रि को और बुधवार प्रातः को सांसदों की जैसी खरीद-फरोख्त व सौदेबाजी के किस्से सुने जा रहे थे उनसे लगता था कि अब कांग्रेस ने नैतिकता को पूरी तरह तिलांजलि दे दी है। एक कांग्रेसी को सरकार की जीत पर जब बधाई दी गई तो उसने कहा, "मुझे तो शर्म आती है कि हमारी सरकार इस प्रकार के हथकंडों को अपनाकर जीती है।"

भाजपा के आरोप : परंतु प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं

इस बार के अविश्वास-प्रस्ताव का मुख्य आधार था भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिभूति घोटाले और बोफोर्स कांड के बारे में सरकार से जवाब-तलबी की। हमारे दल ने जम्मू-कश्मीर के विषय में सरकार की घोर विफलता और बंबई-कलकत्ता बम विस्फोटों के अपराधियों को पकड़ने में शासन की नाकामी को भी मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री ने अपने उत्तर में इनमें से किसी विषय का उल्लेख तक नहीं किया। प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बात की मुखर गवाही थी कि इन विषयों पर सरकार दोषी है और उनके पास कोई उत्तर नहीं।

धर्म को राजनीति से अलग करने संबंधी विधेयक

अपने उत्तर में प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए धर्म से राजनीति को अलग करने के बहाने एक विधेयक को लाने की घोषणा की। तदनुसार गृह मंत्री बृहस्पतिवार को संविधान का 80वाँ संशोधन लेकर संसद् में आए। इसके साथ ही विधि मंत्री ने जन-प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करनेवाला एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया जिसके द्वारा राजनीतिक दलों को अपंजीकृत करने का अधिकार या अपंजीकृत करने की व्यवस्था की जा रही है, यदि किसी दल की गतिविधियाँ समाजवाद, सेक्यूलरवाद और लोकतंत्र के अनुरूप नहीं हैं।

विगत महीनों में जब भी सरकार ने राजनीति को धर्म से अलग करने के कानून बनाने की घोषणा की है, गैर-भारतीय जनता पार्टी दलों ने इन घोषणाओं का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। सरकार को इस कारण से आश्चर्य हुआ होगा कि जब गत बृहस्पतिवार को लोकसभा में विधेयक के प्रस्तुत होने पर अन्य विपक्षी दलों ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए इस विधेयक का विरोध किया। सरकार को मजबूर होकर एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन करने की घोषणा करनी पड़ी, साथ ही उसे यह भी घोषणा करनी पड़ी कि इस सत्र के अंत तक वे इसको पारित करना चाहते हैं और विधेयक में धर्म को राजनीति से अलग करनेवाले जो भी प्रावधान हैं उनमें कोई भी परिवर्तन करनेवाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को सरकार के कुत्सित इरादों के बारे में सावधानी बनाए रखनी पड़ेगी।

धर्म गलत नहीं है, धर्म का दुरुपयोग गलत है। इस प्रकार का दुरुपयोग रोकने के लिए चुनाव कानून में पहले ही उपबंध मौजूद हैं। सत्तारूढ़ दल का उद्देश्य चुनाव व्यवस्था का परिष्कार करना नहीं है। वे तो वैचारिक बहस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इस बात का निर्णय जनता जनार्दन ही करे कि कौन धर्म का दुरुपयोग कर रहा है। जो लोग विश्व हिंदू परिषद् के अयोध्या आंदोलन का मुकाबला करने के लिए सोम यज्ञ का आयोजन करते हैं, अथवा अपने चुनाव घोषणापत्र में मिजोरम में एक ईसाई राज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त करते हैं या केरल के स्कूलों में जुम्मे (शुक्रवार) की छुट्टी की घोषणा करते हैं, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि वे इस संदर्भ में काँच के महल में हैं। उनके लिए बुद्धिमानी इसी में है कि वे दूसरों पर पत्थर न फेंकें।

वंदेमातरम्



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

नई दिल्ली — 18–19 दिसंबर, 1993

नवंबर में हुए चुनावों के बाद भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह प्रथम बैठक हो रही है। मुझे दुःख है कि मैं बैठक में भाग नहीं ले पा रहा हूँ। इसी प्रकार डॉ. जोशी और श्री कल्याण सिंह भी इस कार्यकारिणी की बैठक में अनुपस्थित होने पर विवश हैं। इस बैठक में चुनाव परिणामों का जायजा लेना है। शांतभाव से इन परिणामों से पैदा हुए निर्णयों का विश्लेषण करके आवश्यक निष्कर्ष निकालने होंगे, जहाँ आवश्यक है, वहाँ सुधार करने होंगे और तदनुसार पार्टी की भविष्य की कार्ययोजना तैयार करनी होगी।

मुझे विश्वास है कि जैसा 29 नवंबर को पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया था, हमारे महासचिवों ने उन राज्यों का दौरा किया होगा, जहाँ चुनाव थे, वहाँ राज्य के पदाधिकारियों से चर्चा की होगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विचारार्थ एक समेकित रिपोर्ट तैयार की होगी।

इस बात की उत्सुकता सभी में होगी कि इस रिपोर्ट पर कार्यकारिणी में क्या विचार विमर्श होता है, क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या परामर्श दिया जाता है और भविष्य के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की जाती है।

निस्संदेह कार्यकारिणी राज्य इकाइयों द्वारा दिए गए ब्यौरों के आधार पर चुनाव परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण करेगी। किंतु मोटे तौर पर पार्टी का इन चुनावों में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, उसके बारे में मैं अपनी कुछ सहमति कार्यकारिणी को देना चाहूँगा—

भाजपा : राजनीति का प्रमुख ध्रुव

1. नवंबर 1994 के चुनावों ने निश्चित रूप से स्थापित कर दिया है कि भाजपा भारतीय राजनीति का प्रमुख ध्रुव है। स्वतंत्रता से लेकर अब

तक पिछले सभी दशकों में किसी भी प्रमुख चुनाव के परिणाम का मूल्यांकन करने की मुख्य कसौटी यही रही है कि कांग्रेस ने कैसा प्रदर्शन किया है? क्या वह जीती है या हारी है? अब यह कसौटी बदल गई है। आज कसौटी यह है कि भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या वह जीती है या हारी है?

हमारा प्रदर्शन बेहतर हो

2. यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेनी होगी कि भाजपा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। लोगों की राय में यह बात भी संगत नहीं है कि हमने कांग्रेस या अन्य विरोधी दलों के मुकाबले अधिक अच्छा प्रदर्शन किया है।

जिन पाँच राज्यों में पार्टी का भाग्य दाँव पर लगा था, हमें उनमें से हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों में धक्का लगा है।

शेष तीन राज्यों में हमारा समर्थन आधार बढ़ा है। इनमें से दो राज्यों–दिल्ली और राजस्थान में भाजपा की सरकारें बनी हैं। परंतु तीसरे राज्य उत्तर प्रदेश में जन समर्थन बढ़ने के बावजूद सीटों की संख्या नहीं बढ़ी।

वोट अधिक, परंतु सीटें कम

3. यहाँ यह महत्त्वपूर्ण है कि इन सभी राज्यों में कुल मिलाकर 9.8 करोड़ लोगों ने वोट दिया, उनमें से 3.57 करोड़ लोगों ने (36.18%) ने भाजपा को समर्थन दिया। यह कांग्रेस को प्राप्त 2.59 करोड़ (अर्थात् 26.24%) मतों से एक करोड़ अधिक मत हैं और जनता दल द्वारा प्राप्त मतों (89 लाख अर्थात् 9.08%) से चार गुना है।

मुझे स्मरण है कि 1989 में जब लोकसभा में भाजपा मात्र 2 सीटों से बढ़कर शानदार 86 तक पहुँच गई थी तो लंदन से प्रकाशित 'इकोनॉमिस्ट' ने भारतीय चुनावों के बारे में विश्लेषण करते हुए अपने लेख में एक प्रभावशाली शीर्षक 'विनर कम्स सेकंड' (अर्थात् वास्तविक विजेता दूसरे स्थान पर रहा) दिया था। हाल के चुनाव पर तदनुरूप एक उचित टिप्पणी 'लूजर स्टैंड फर्स्ट' अर्थात् (पराजित होकर भी इसका स्थान प्रथम है) कहकर दी जा सकती है।

भाजपा की विचारधारा को प्रबल समर्थन

4. किंतु इस चुनाव में जो धक्का लगा है, उसे समुचित रूप से समझ लेना चाहिए कि यह धक्का पार्टी को लगा है, विचारधारा को नहीं लगा है। पार्टी के जनाधार में हुई पर्याप्त वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि पार्टी की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति अधिकाधिक अनुयायी आकर्षित

होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस तथ्य को देखें, जहाँ अयोध्या आंदोलन का प्रभाव पड़ा है वहाँ भी भाजपा का न केवल मत प्रतिशत बढ़ा है, बल्कि आज सत्ताधीन हुई सपा–बसपा गठबंधन के मुकाबले भाजपा को 40 लाख वोट अधिक मिले हैं, इससे इस बात की ओर भी पुष्टि होती है। देश में राजधानी में भाजपा की जबरदस्त विजय भी इसी बात को सिद्ध करती है।

भाजपा इससे पहले जिन दो राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में सत्ता में थी, वहाँ भी इसकी मत प्रतिशतता में कमी आई है। मेरी मान्यता है कि भाजपा सरकारों ने इन दो राज्यों में काफी अच्छा काम किया, परंतु इन दो राज्यों में हमारी सरकारों की छवि नकारात्मक रही। यह हमें बहुत महँगी पड़ी। लोकतंत्र में प्रायः छवि का भी उतना ही (चाहे अधिक न हो तब भी) महत्त्व है जितना कि वास्तविकता का महत्त्व होता है।

5. हमारे विरोधियों की दुर्दशा तो निस्संदेह दयनीय है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और जनता दल दोनों ही मिट गए हैं। उन्हें एक ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है, जिसके एक प्रमुख नेता ने खुल्लम खुल्ला कांग्रेस अध्यक्ष को 'आखिरी मुगल' कहा था और जनता दल अध्यक्ष को 'घास में छुपा साँप' बताया था।
6. इस चुनाव में हमने अपने आपको ऊँचा रखा था अर्थात् सभी पाँचों राज्यों में सरकारें बनाने का लक्ष्य। यदि हम सचमुच इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते तो भारतीय राजनीति के इतिहास में यह अपने आप में एक प्रकार का कीर्तिमान स्थापित हो जाता। हमारे समर्थकों को आशा थी और हमारे विरोधी डरे हुए थे कि हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। तेज धावक एक और कीर्तिमान बनाने में असफल रहा। उसमें अब भी दौड़ने की क्षमता है, यह बहुत संतोष की बात नहीं है।

हमारे बढ़ते चरण न रुकें

पिछले कुछ वर्षों में पार्टी का प्रगति–ग्राफ अद्वितीय ढंग से तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता गया है। इन चुनावों के परिणाम मात्र को देखने से यह विकास–गति कुछ कम लगने लगती है। स्वाभाविक है कि हमारे समर्थक निराश हुए हैं और हमारे विरोधियों को चैन की साँस मिली है। पार्टी के समक्ष अब यह कार्य है कि हमारी पहुँच और राजनीति ऐसे सुचारु रूप से तैयार की जाए कि उपर्युक्त निराशा या 'चैन की साँस' उड़न–छू हो जाए। हमारी गतिविधियों की तीव्रता को मंथर नहीं होने देना है।

अपनी यह टिप्पणी समाप्त करने से पहले मैं इस अवसर पर कार्यकारिणी

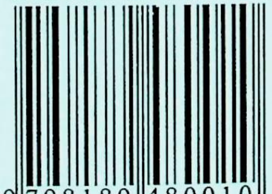
के सदस्यों को और उनके माध्यम से पूरे देश में पार्टी की यूनिटों और कार्यकर्ताओं को, अपने सांसदों, विधायकों और विधान परिषद् के सदस्यों को डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री कल्याण सिंह, श्री विनय कटियार और स्वयं अपनी ओर से इस बात के लिए हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी गिरफ्तारी के विरुद्ध अत्यंत शक्तिशाली ढंग से लोगों को इकट्ठा किया।

वंदेमातरम्

□□□




25
वर्ष
भारतीय जनता पार्टी


ISBN 81-89480-01-4
9798189480010